वार्षिक रिपोर्ट

2018-2019

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 'मन की बात' के लिए अपना सन्देश देते हुए

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

fo"k; lph

	वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां	07
1.	एक झलक	25
2.	मंत्रालय की भूमिका और कार्य	29
3.	मंत्रालय की नई पहल	33
4.	सूचना क्षेत्र की गतिविधियां	39
5.	प्रसारण क्षेत्र की गतिविधियां	89
6.	फ़िल्म क्षेत्र की गतिविधियां	191
7.	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	239
8.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण	243
9.	मंत्रालय की सेवाओं में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व	245
10.	राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग	249
11.	महिला कल्याण संबंधी गतिविधियां	251
12.	सतर्कता संबंधी मामले	253
13.	नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र	255
14.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले	259
15.	लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा	263
16.	लेखा पैरा	277
17.	कैट के फैसलों/आदेशों पर अमल	281
18.	योजना परिव्यय	283
19.	मीडिया इकाई–वार बजट	287
20.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सांगठनिक चार्ट	291

मुंबई में 19 जनवरी, 2019 को भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय में
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं अन्य गणमान्य अतिथि

मुंबई में 19 जनवरी, 2019 को फ़िल्म प्रभाग कार्यालय में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का अवलोकन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

o"k dh ie[k miyfC/k;k

lpuk [kM

- 8 दिसंबर, 2018 को माननीय उप राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के पहले वर्ष के भाषणों का संकलन 'द रिपब्लिकन एथिक' और 'लोकतंत्र के स्वर' का लोकार्पण किया। इस अवसर पर माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज मुख्य अतिथि थीं और माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ सहित कई अन्य वरिष्ठ गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे। ये पुस्तकें प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित की हैं और इनके ई–बुक संस्करण भी इसी अवसर पर जारी किए गए जो अब ई–कॉमर्स प्लेटफार्म्स पर मौजूद हैं। माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने उसी दिन पुस्तकों की एक–एक प्रति माननीय राष्ट्रपति को भी भेंट की। डीपीडी ने पिछले चार वर्षों में विभिन्न अवसरों पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए उद्धरणों से सुसज्जित पुस्तक 'स्वच्छ भारत : संकल्प से सिद्धि' का प्रकाशन किया। इस पुस्तक की परिकल्पना एवं डिजाइन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने तैयार की थी। पुस्तक की पहली प्रति 12 फरवरी, 2019 को कुरुक्षेत्र में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने माननीय प्रधानमंत्री को भेंट की।

नई दिल्ली में 08 दिसंबर, 2018 को प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित भारत के राष्ट्रपति के चुनिंदा भाषणों की पुस्तक 'लोकतंत्र के स्वर' का लोकार्पण माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने किया साथ में हैं माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे एवं अन्य गणमान्य अतिथि

- नई दिल्ली में 8 और 9 मई, 2018 को क्वालालम्पुर मलेशिया के एशिया–पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) के सहयोग से सम्मेलन पूर्व वर्कशॉप्स सहित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (आईआईएमसी) और ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के साथ मिलकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 15वीं एशिया मीडिया समिट की मेजबानी की। सम्मेलन का विषय था 'टेलिंग आवर स्टोरीज–एशिया एंड मोर'।

➢ तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री, श्रीमती स्मृति ईरानी ने आयोजन का उद्घाटन किया और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोद्यौगिकी तथा केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 'मीडिया रेगुलेशन पॉलिसीज : एथिक्स, रूल्स एंड लॉज' के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। सूचना प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने एआईबीडी द्वारा चुने गए विजेताओं को 'वर्ल्ड टेलिविजन अवाड्र्स 2018' प्रदान किए और सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन के माध्यम से क्षेत्र के प्रसारकों को प्रसारण एवं सूचना के क्षेत्र में विभिन्न पक्षों के बीच परस्पर कार्य करने से संबंधित विचार साझा करने का अनूठा मौका मिला था। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 42 देशों के 300 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था।

नई दिल्ली में 11 मई, 2018 को 15वीं एशिया मीडिया समिट के समापन सत्र को संबोधित करते हुए माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

➢ अलग–अलग मंत्रालयों/विभागों से संबंधित समस्या स्टेटमेंट से निपटने के लिए 36 घंटे की प्रतियोगिता 'स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2018' के सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले 30–31 मार्च, 2018 तक देशभर के 28 केंद्रों में आयोजित किया गया था। इस पहल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रमुख भागीदार था। जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और अनुसंधान केंद्र (जेईसीआरसी), जयपुर में, लगभग 400 छात्रों को शामिल करने वाली 50 टीमों ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 16 समस्याओं के लिए सॉफ्टवेयर समाधान विकसित करने के लिए कोडिंग की है। सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन–सॉफ्टवेयर संस्करण 2018 के ग्रांड फिनाले के विजेताओं को सम्मानित किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा शीर्ष 3 टीमों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार स्वरूप विजेता को 1 लाख रुपये, दूसरा स्थान पाने वाले को 75,000 रु. और तीसरा स्थान पाने वाले को 50,000 रु. दिए गए।

➢ माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने 19 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित एक समारोह में 7वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए। पेशेवर श्रेणी के लिए विषय था, ''महिलाओं के नेतृत्व में विकास'', जबकि एमेच्योर श्रेणी का विषय था, ''भारत के मेले और त्योहार''। लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित कुल 13 पुरस्कार दिए गए। विजेताओं की तस्वीरों को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में 3 दिन की फोटो प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया

नई दिल्ली में 19 फरवरी, 2019 को नौवें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करते युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। सूचना एवं प्रसारण सचिव, श्री अमित खरे भी उपस्थित थे

गया। इस अवसर पर 7वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों की विवरणिका भी जारी की गई।

➢ सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फ्लैगशिप योजनाओं और प्रमुख घटनाओं पर विभिन्न संचार और मल्टीमीडिया अभियान शुरू किया, जिसमें शामिल हैं:

• सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर, मंत्रालय की मीडिया इकाइयों द्वारा की गईं पहल –

– ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, बीओसी (विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, डीएवीपी) ने 'सरकार की पहल' विषय पर एक डिजिटल सिनेमा अभियान चलाया और अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में 'ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया–लाइक नेवर बिफोर' की 25 लाख से अधिक प्रतियां भेजीं।

– ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, (डीएवीपी) ने lkQ uh;r lgh fodkl पर एक मल्टीमीडिया (बहुभाषी टीवी और रेडियो) अभियान की संकल्पना की, योजना बनाई तथा क्रियान्वित की और इस विषय पर 4 कलर प्रिंट विज्ञापन जारी किए।

– प्रकाशन विभाग (डीपीडी) की पत्रिकाओं– योजना और d#{k= के जून 2018 के अंक क्रमशः 'गतिशील भारत' और 'ग्रामीण भारत का पुनरुत्थान' विषय पर थे।

– प्रेस सूचना कार्यालय (पीआईबी) के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों ने पिछले 4 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों, पहलों और नीतियों के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए बड़े पैमाने पर देशव्यापी आउटरीच कार्यक्रम चलाया, जिसमें लगभग 40 आयोजन किए गए। इनमें रेडियो जॉकी क्षेत्र के वरिष्ठ संपादकों के साथ बातचीत और क्षेत्रीय मीडिया के साथ संवाददाता सम्मेलन शामिल हैं।

• मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के सिलसिले में कई पहल कीं। माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) द्वारा पालिका पार्क राजीव चौक, नई दिल्ली में 2 से 7 अक्तूबर तक आयोजित 'बापू री–लिव्डः इन वर्ड, डीड एंड एक्शन' नामक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रकाशन विभाग ने महात्मा गांधी के जीवन पर विभिन्न लेखकों की 11 पुस्तकें प्रकाशित कीं। महात्मा गांधी पर बीओसी, दूरदर्शन (डीडी) और फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित एक एनीमेशन फिल्म सहित तीन लघु फिल्में भी दिखाई गईं।

माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने नई दिल्ली में
02 अक्तूबर, 2018 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का दौरा किया

– पीआईबी ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में 18 सितंबर, 2018 को वेब पोर्टल और लोगो की शुरुआत के लिए व्यापक प्रचार किया और जानकारी का प्रसार किया।

– मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों में वेबसाइटों, पत्रों और लेखन सामग्री पर लोगो ब्रांडिंग के लिए सहायता दी जा रही है।

– मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों में 31 अक्तूबर, 2018 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की व्यापक कवरेज और प्रचार के लिए कई गतिविधियां की गईं।

– प्रकाशन विभाग (डीपीडी) ने सरदार पटेल पर 6 पुस्तकों के नए संस्करण प्रकाशित किए।

– बीओसी द्वारा मल्टीमीडिया अभियान में अखिल भारतीय टीवी अभियान, प्रिंट विज्ञापन और लोक सेवा विज्ञापन (पीएसए) के निःशुल्क 120 सेकेंड के स्पॉट के 6604 डिजिटल सिनेमा स्क्रीन पर प्रदर्शन के साथ–साथ निजी एफएम स्टेशनों के माध्यम से अखिल भारतीय आउटडोर अभियान शामिल थे।

– पीआईबी वेबसाइट पर विशेष वेब पेज बनाया गया। पीआईबी ने घटनाओं के त्वरित और व्यापक प्रचार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से फोटो, वीडियो, ट्वीट, साउंड–बाइट्स और लाइव स्ट्रीमिंग पोस्ट करके सोशल मीडिया का उपयोग किया।

– न्यू मीडिया सेल द्वारा सभी ट्वीट्स की ब्रांडिंग के लिए विशेष हैशटैग का उपयोग किया गया था।

– फोटो प्रभाग ने आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों को व्यापक फोटो कवरेज दी।

– सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के सहयोग से, सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह के उपलक्ष्य पर 28 से 30 सितंबर, 2018 तक "पराक्रम पर्व" मनाया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने 28 सितंबर, 2018 को राजस्थान के जोधपुर में एक सैन्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और कोणार्क युद्ध स्मारक का भी दौरा किया।

– राजपथ, नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के समन्वय से बीओसी द्वारा एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी सहित मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। माननीय रक्षा मंत्री ने 28 सितंबर की शाम को राजपथ, इंडिया गेट पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने भी 29 सितंबर को इस कार्यक्रम में भाग लिया।

– देशभर में 50 स्थानों पर इसी तरह के समारोह आयोजित किए गए और मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों ने इनका व्यापक प्रचार किया और कवरेज दी।

– राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के स्वयंसेवकों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

– 29–30 सितंबर, 2018 को राजपथ पर दो दिवसीय संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 30 सितंबर को श्री कैलाश खेर ने प्रख्यात गीतकार श्री प्रसून जोशी द्वारा लिखा गया विशेष गीत ijkØe xhr गाया।

– लोकप्रिय गायक श्री सुखविंदर सिंह, श्री कैलाश खेर और आकाशवाणी (एआईआर) के कलाकारों ने भी देशभक्ति के गीत गाए।

– कार्यक्रम में अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों/गतिविधियों का भी आयोजन किया गया।

नई दिल्ली में 29 सितंबर, 2018 को राजपथ स्थित इंडिया गेट के मैदान में आयोजित 'पराक्रम पर्व' में माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और माननीय गृह राज्यमंत्री, श्री किरन रिजिजु शामिल हुए। साथ में हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे

• बीओसी ने सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न योजनाओं के लाभ के बारे में बताने के लिए मीडिया के कई माध्यमों का उपयोग करते हुए ^ukeedhu vc eefdu g^ विषय पर कई अभियान चलाए थे। ये अभियान प्रिंट विज्ञापन, दृश्य–श्रव्य प्रचार, टीवी और रेडियो, डिजिटल सिनेमा, सोशल मीडिया और आउटडोर प्रचार अभियानों के माध्यम से चलाया गया। बीओसी ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के माध्यम से 'न्यू इंडिया चौपाल' नाम से व्यापक ग्राउंड एक्टिवेशन अभियान और अंतर्वैयक्तिक संवाद कार्यक्रमों की एक परियोजना

शुरू की, जिसका उद्देश्य 15 राज्यों के 318 जिलों में सरकार की विभिन्न योजनाओं पर 8,000 आउटरीच कार्यक्रम चलाना है।

– प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए कुंभ मेला 2019 के लिए मंत्रालय की मीडिया इकाइयों द्वारा पर्याप्त कवरेज की गई। प्रेस सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने इंफोग्राफिक्स की एक श्रृंखला तैयार कर जारी की और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर वास्तविक समय में घटनाओं की तस्वीरें प्राप्त कीं। ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) ने प्रयागराज में ^,d Hkkjr] LoPN vkSj l{ke Hkkjr&ckiw vkSj ljnkj ds liuks dk Hkkjr^ विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया।

• मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों ने 15 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2018 तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर और स्वच्छता से संबंधित मुद्दों और आयोजनों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए LoPNrk gh lsok अभियान चलाया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान शुरू किया गया और 'महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन' में इसका समापन किया गया।

– कई Jenku आयोजित किए गए। शास्त्री भवन में भी एक श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने योगदान किया तथा एक अन्य बीओसी द्वारा सूचना भवन के निकट बारापुला नाला, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आदि के दक्षिणी छोर पर आयोजित किया गया।

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका ;kstuk को LoPNrk% fopkj ls okLrfodrk विषय को समर्पित किया गया और इसमें केंद्रीय मंत्रियों तथा सचिवों के अनेक लेख शामिल किए गए, जिनमें अब तक की प्रगति और सफलता की कहानियों सहित स्वच्छता के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। jkstxkj lekpkj और अन्य पत्रिकाओं में भी स्वच्छ्ता पर लेख प्रकाशित किए गए और LoPNrk gh lsok 2018 vfHk;ku और LoPN lo{k.k xzkeh.k iqjLdkj 2018 के तहत शुरू की गई गतिविधियों पर समाचार प्रकाशित किए।

• 8 मार्च, 2018 को "अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस" से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की व्यापक कवरेज की गई और प्रचार किया गया, जिसमें महिला उद्यमिता मंच, ^mn~e l[kh iksVZy^ की शुरुआत और ^ck;ksMhxzsMscy lSusVjh uSifdu^, ukjh 'kfä iqjLdkj forj.k और cVh cpkvks cVh i<kvks ¼chchchih½ आदि कार्यक्रमों का समूचे भारत में विस्तार शामिल है।

– डीएवीपी ने सरकार द्वारा शुरू की गई महिला केंद्रित योजनाओं के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए अखिल भारतीय अभियान ^efgykvksa ds ubZ Hkkjr ds fodkl^ चलाया।

– पीआईबी ने cVh cpkvks cVh i<kvks के अखिल भारतीय विस्तार और iks"k.k vfHk;ku की शुरुआत के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए झुंझुनू के 2 दिवसीय प्रेस दौरे का आयोजन किया।

– डीपीडी ने प्रमुख लेखकों को शामिल करते हुए एक चर्चा कार्यक्रम– ^Hkkjrh; L=h ijaijk vkSj vk/kqfudrk^ का आयोजन किया।

• vke ctV 2018&19 को व्यापक कवरेज दी गई और प्रचार किया गया।

– प्रेस सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने वित्त मंत्री के बजट के उपरान्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। पीआईबी टीम द्वारा तैयार प्रेस विज्ञप्तियां, इंफोग्राफिक्स और अन्य सोशल मीडिया सामग्री को पीआईबी वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

– डीपीडी की पत्रिकाओं ;kstuk और dq#{ks= के मार्च 2018 के अंक का विषय केंद्रीय बजट 2018–19 था।

– 21 जून, 2018 को चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया और देशभर में आयोजित अन्य विभिन्न कार्यक्रमों का व्यापक कवरेज और प्रचार किया गया।

– ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ने प्रिंट, बाह्य प्रचार/आउटडोर पब्लिसिटी (ओपी), प्राइवेट सी एंड एस चैनलों और प्राइवेट एफएम चैनलों के माध्यम से व्यापक अभियान चलाया।

– प्रेस सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने एक ही स्थान पर सभी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विशेष वेब पेज (http://pibarchive.nic.in/yogaday2018/) बनाया और मुख्य कार्यक्रम की विस्तृत कवरेज के लिए लगभग 50 मीडियाकर्मियों को देहरादून ले जाया गया।

– मुख्य कार्यक्रम के दौरान, उससे पहले और बाद की गतिविधियों को कवर करने के लिए पीआईबी ने व्यापक सोशल मीडिया कवरेज की।

- पीआईबी ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर स्वास्थ्य संपादकों का सम्मेलन आयोजित किया।
- प्रकाशन विभाग (डीपीडी) ने 18 जून को LoPN eu] LoLFk ru vkj LoPN i;koj.k नामक परिचर्चा का आयोजन किया।
- प्रकाशन विभाग (डीपीडी) द्वारा प्रकाशित रोज़गार समाचार का 16 से 22 जून का अंक ;kx fo'k"kkd था।

• सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 25 जनवरी, 2019 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के माननीय राष्ट्रपति के भाषण और 26 जनवरी, 2019 को गणतंत्र दिवस समारोह परेड का आंखों देखा हाल दिव्यांगों को सुलभ कराने के लिए और उन्हें इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस के साथ सार्थक रूप से जोड़ने के लिए उनके लिए सांकेतिक भाषा में व्याख्या के साथ टेलीकास्ट की व्यवस्था की।

- सभी टीवी चैनलों को डीडी न्यूज़/डीडी भारती की फीड निःशुल्क उपलब्ध कराई गई थी।
- दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति (गणतंत्र दिवस परेड, 2019 के मुख्य अतिथि, 25 जनवरी–26 जनवरी, 2019) की राजकीय यात्रा को व्यापक कवरेज दी गई।
- 69वें गणतंत्र दिवस समारोह 2018 के समापन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के 10 प्रमुखों की यात्रा का व्यापक प्रचार और कवरेज सभी मीडिया प्लेटफार्मों पर किया गया।

• 72वें स्वतंत्रता दिवस 2018 का व्यापक प्रचार किया गया।

- बीओसी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में ^n'k dk c<rk tkrk fo'okl] lkQ uh;r lgh fodkl^ विषय पर 14 राज्यों में 16 प्रदर्शनियां आयोजित कीं।
- प्रकाशन विभाग (डीपीडी) ने vuVkYM LVkjh v,Q c,MdkLV l M;fjx fDoV bfM;k eoeV और oeu bu lR;kxg नामक पुस्तकों का विमोचन किया और ej liuk dk Hkkjr विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।
- प्रेस सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने अपनी वेबसाइट पर एक वेब पेज लिंक 'स्वतंत्रता दिवस 2018' बनाया।

➢ प्रकाशन विभाग (डीपीडी) द्वारा प्रकाशित माननीय उप राष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू के चयनित भाषणों के प्रथम संस्करण का 15 फरवरी, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विमोचन किया गया। समारोह में माननीय उप राष्ट्रपति और माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, माननीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल व युवा मामले के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और राज्यसभा के माननीय उप सभापति श्री हरिवंश सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पुस्तक में 92 भाषण हैं, जिन्हें छह खंडों में वर्गीकृत किया गया है। पुस्तक का एक डिजिटल संस्करण भी जारी किया गया।

नई दिल्ली में 15 फरवरी, 2019 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू के भाषणों की पुस्तक 'सेलेक्टेड स्पीचेज़–वाल्यूम–I' का लोकार्पण किया। साथ में हैं, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, श्री थावर चंद गहलोत, माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ एवं अन्य गणमान्य अतिथि

➢ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संकलन, lcdk lkFk lcdk fodkl] का मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में 8 मार्च, 2019 को आयोजित समारोह में माननीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा विमोचन किया गया। इस अवसर पर माननीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले तथा खेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और भारत सरकार के कई सचिव उपस्थित थे। ये पुस्तकें देश के सभी नागरिकों को एकजुट देखने और सभी को समावेशी विकास के रास्ते पर ले जाने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना को दर्शाती हैं। डीपीडी द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित पांच खंडों की ये पुस्तकें एक साथ जारी की गईं।

➢ माननीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने 2 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित एक समारोह में eu dh ckr & jfM;k ij ,d lkekftd Økfr नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ''मन की बात'' कार्यक्रम की 50 कड़ियों पर आधारित है, जो आकाशवाणी (एआईआर) पर प्रसारित भारत के नागरिकों के साथ दिल से दिल की बात थी।

तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली सबका साथ सबका विकास (माननीय प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषण) पुस्तक का विमोचन करते हुए इस अवसर पर माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी उपस्थित थे

➢ लंदन पुस्तक मेले में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन 13 मार्च, 2019 को किया गया। इसमें भारत की संस्कृति, इतिहास और लोककथाओं पर विभिन्न पुस्तकों के साथ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए ^dyDVM oDl vkQ egkRek xk/kh^ के डिजिटल संस्करण को प्रदर्शित किया गया। मंडप में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत की अन्य प्रमुख उपलब्धियों और महात्मा गांधी के जीवन तथा समय पर एक इंटरैक्टिव डिजिटल मीडिया अनुभव भी उपलब्ध थाA कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी – प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक संस्करण तैयार करने पर एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया था। यह मेला लंदन ओलंपिया में 12 से 14 मार्च, 2019 तक आयोजित किया गया।

➢ jk"Vªh; çsl fnol 16 नवंबर, 2018 को भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा मनाया गया। तीन देशों बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की प्रेस परिषद के प्रतिनिधियों ने 'डिजिटल युग में पत्रकारिता संबंधी आचार नीति और चुनौतियां' विषय पर पैनल चर्चा में भाग लिया। राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय वित्त और कॉपोरेट मामलों के मंत्री, श्री अरुण जेटली ने किया। इस अवसर पर, विभिन्न खंडों में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए और पत्रकारिता मानकों का एक अद्यतन संस्करण जारी किया गया। भारतीय प्रेस परिषद ने श्रीलंका प्रेस परिषद के साथ एक द्विपक्षीय समझौते (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए और नेपाल की प्रेस परिषद के साथ इस समझौते का नवीनीकरण किया।

➢ माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने 13 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाली मीडिया इकाइयों के पहले वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है और भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के अधिकारियों को संचार प्रतिमानों में निरंतर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। यह भी बताया गया कि सरकारी संचार में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग महत्वपूर्ण है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के बीच तालमेल बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

नई दिल्ली में 13 फरवरी, 2019 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन को माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने संबोधित किया

➢ पीआईबी ने दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) के स्वंय–सहायता समूहों के सदस्यों, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थानों के लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री के lh/k lokn को व्यापक कवरेज प्रदान किया।

- लोकप्रिय वार्षिक संदर्भ ग्रंथ Hkkjr 2019 और bfM;k 2019 को 7 मार्च, 2019 को जारी किया गया। इन्हें न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) द्वारा संकलित किया गया है और मंत्रालय के अधीन प्रकाशन विभाग (डीपीडी) द्वारा संपादित और प्रकाशित किया गया। यह इस प्रतिष्ठित प्रकाशन का 63वां संस्करण है। ये पुस्तकें सरकार की नीतियों तथा उपलब्धियों को उजागर करने का महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

नई दिल्ली में 07 मार्च, 2019 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे ने प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक संदर्भ पुस्तक 'भारत–2019' का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक (एमएंडसी) श्री सीतांशु आर. कार प्रधान महानिदेशक (आरएनआई) श्री गणेशन एवं प्रकाशन विभाग की महानिदेशक डॉ. साधना राउत भी मौजूद थीं

- भारतीय प्रकाशक परिसंघ (एफआईपी) द्वारा शुरू किए गए वार्षिक पुरस्कारों में प्रकाशन विभाग (डीपीडी) को हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न श्रेणियों में पुस्तक प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए 7 पुरस्कार और एक मेरिट प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया।
- 'नया भारत–हम करके रहेंगे', 'साथ है विश्वास है, हो रहा विकास है', 'देश का बढ़ता जाता विश्वास', 'साफ नीयत सही विकास', तनाव प्रबंधन' और 'स्वच्छ भारत मिशन' विषय पर प्रदर्शनियों का आयोजन देशभर में विभिन्न स्थानों पर किया गया। बीओसी ने टीवी एवं रेडियो पर तथा ओपी के माध्यम से 'साफ नीयत सही विकास' विषय पर विशेष मल्टीमीडिया अभियान चलाया।
- आईआईएमसी और फेसबुक ने आईआईएमसी में एक फेसबुक न्यूज़ लैब की स्थापना की तथा संभावना का पता लगाया और फेक न्यूज़ के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए समूचे भारत में संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किए।
- प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका ;kstuk का दिसंबर 2018 का अंक माननीय प्रधानमंत्री के ^fMftVy bfM;k^ कार्यक्रम को समर्पित था। माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और विधि तथा न्याय मंत्री, श्री रविशंकर प्रसाद ने 30 नवंबर, 2018 को दिल्ली में इसका विमोचन किया। इसमें 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के तकनीकी से लेकर सामाजिक–आर्थिक पहलुओं को दर्शाने वाले लेख थे।

izlkj.k foHkkx

- सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर, मंत्रालय की मीडिया इकाइयों द्वारा की गईं पहल :

– विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए एक विशेष प्रचार अभियान ^pkj lky ekuh ljdkj^ के तहत दूरदर्शन (डीडी) समाचार ने कई केंद्रीय मंत्रियों के इंटरव्यू ^loky vkids tokc ea=kky; dk^ के रूप में लिए। यह कार्यक्रम 31 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों से पुनः प्रसारित किया गया और प्रचार के लिए सोशल मीडिया तथा व्हाट्सएप ग्रुपों पर प्रोमो

पर्याप्त रूप से चलाए गए। प्रमुख विशेषज्ञों के साथ cnyrk Hkkjr ij ppkZ शीर्षक के तहत परिचर्चा श्रृंखला भी प्रसारित की गई।

– टॉकथॉन और विशेष कार्यक्रम çxfr dk 4 lky का आयोजन और प्रसारण दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया गया।

– आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए अपने करंट अफेयर कार्यक्रम के तहत pkj lky ekSnh ljdkj पर केंद्रीय मंत्रियों और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ साक्षात्कार और परिचर्चा कार्यक्रमों का प्रसारण किया।

– आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने समाचार बुलेटिनों और परिक्रमा कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर ग्राउंड रिपोर्ट/सफलता की कहानियों के रूप में विशेष ऑडियो कैप्सूल का प्रसारण किया।

➢ मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों ने egkRek xka/kh dh 150oha t;arh dk lekjksg पर कई पहल कीं।

नई दिल्ली में 02 अक्तूबर, 2018 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

– 2 अक्तूबर, 2018 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित egkRek xka/kh varjjk"Vªh; LoPNrk lEesyu और गांधी स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का लाइव प्रसारण/टेलीकास्ट किया गया। फिक्स्ड स्लॉट तथा विशेष कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

डीडी न्यूज़, विदेश मंत्रालय द्वारा निर्मित और विदेशी कलाकारों द्वारा गाए गए ^o".ko tu rks* के अंतरराष्ट्रीय गायन का प्रसारण प्रतिदिन कर रहा है।

– डीडी न्यूज़ गांधी और स्वच्छता पर ^egkRek dk ea=^ शीर्षक से विशेष कार्यक्रम और ^[kknh oL= ugha ,d fopkj/kkjk^ पर विशेष श्रृंखला दिखा रहा है और नियमित रूप से सभी समाचार घटनाओं को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपलोड कर रहा है।

– दूरदर्शन ने गांधीजी के पसंदीदा भजन o".ko tu rks का एक वीडियो तैयार किया, जो 1 अक्तूबर, 2018 से चल रहा है।

➢ मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों ने 31 अक्तूबर, 2018 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाये जाने पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को व्यापक कवरेज दिया और प्रचार के लिए कई गतिविधियां कीं।

– 31 अक्तूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा का डीडी न्यूज़ ने लाइव टेलीकास्ट किया।

– दूरदर्शन ने माननीय गृहमंत्री द्वारा पुष्पांजलि और ^ju Q,j ;qfuVh^ कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया।

– पहली बार, दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों ने हिंदी फ़िल्म "सरदार" को अंग्रेजी, गुजराती, बांग्ला, मराठी, तमिल और तेलुगू में उप–शीर्षकों के साथ दिखाया।

– आकाशवाणी ने वार्षिक सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान, 2018 का आयोजन 25 अक्तूबर, 2018 को 'ड्रीम इंडिया 2030–अवॉएडिंग द पिटफाल्स' विषय पर किया, जिसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, श्री अजीत डोभाल वक्ता के रूप में शामिल हुए।

– दूरदर्शन और आकाशवाणी ने समाचारों के त्वरित और व्यापक प्रचार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से फोटो, वीडियो, ट्वीट, साउंड–बाइट और लाइव स्ट्रीमिंग पोस्ट करके सोशल मीडिया का उपयोग किया।

– मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों ने 23 सितंबर, 2018 को रांची, झारखंड में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना 'आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)' के शुभारंभ के लिए व्यापक कवरेज और प्रचार किया। चाईबासा और कोडरमा में मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास और 10 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के उद्घाटन के साथ, इस योजना पर एक प्रदर्शनी के लिए माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा की व्यापक कवरेज की।

– दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रम की लाइव कवरेज के अलावा, 'न्यू इंडिया संकल्प' के तहत विशेषज्ञों द्वारा लाइव पैनल चर्चाएं, स्पॉट और इंफोग्राफिक्स, पैनल चर्चाएं और पीएमजेएवाई के विभिन्न विषयों पर साक्षात्कार के साथ दिखाई गईं।

– डीडी न्यूज़ ने सरकारी और निजी क्षेत्र से विशेषज्ञों के पैनल के साथ ^VkVy gYFk çkxke^ सहित विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पीएमजेएवाई और लक्षित समूह को पहुंचे फायदों पर प्रकाश डालते हुए देशभर में क्षेत्रीय समाचार इकाइयों द्वारा समाचार बुलेटिनों में समाचार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा सीईओ, एनएचए के बाइट दिखाए गए।

– आकाशवाणी समाचार और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने सभी प्रमुख बुलेटिनों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों को विभिन्न स्वरूपों जैसे समाचार आधारित कार्यक्रमों, वार्ताओं और करेंट अफेयर, ग्राउंड रिपोर्ट आदि में प्रसारित किया।

– सोशल मीडिया विंग ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक पहुंच और कवरेज भी प्रदान की।

➢ प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले कुंभ मेला 2019 की मंत्रालय की मीडिया इकाइयों ने पर्याप्त कवरेज की। डीडी न्यूज़ ने अपने ppk e 'कार्यक्रम श्रृंखला के तहत dqHk 'kkgh Luku vkj dqHk fo'k"k शीर्षक से कुंभ मेले पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग और इसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने कुंभ पर विशेष रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट प्रसारित कीं। इनमें लखनऊ से रोज़ाना आधे घंटे का एक कार्यक्रम भी शामिल है।

➢ डीडी न्यूज़ ने 14 फरवरी, 2019 को ^^i|yokek vkr|dh geyk^^ पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने i|yokek d 'kghnk dk ueu पर विशेष कार्यक्रम का भी प्रसारण किया। डीडी न्यूज़ ने बड़े पैमाने पर भारत सरकार द्वारा किए गए एहतियाती उपायों से संबंधित समाचारों को कवर किया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने 26–02–2019 को अपने विशेष द्विभाषी स्पॉटलाइट/न्यूज़ एनालिसिस कार्यक्रम में "आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रभावी हमला" शीर्षक से एक विशेष परिचर्चा और 27–02–2019 को "आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर कूटनीतिक कार्रवाई" पर एक परिचर्चा का प्रसारण किया।

➢ आम बजट 2018–19 का व्यापक कवरेज और प्रचार किया गया।

– केंद्रीय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली का एक विशेष साक्षात्कार टेलीकास्ट किया गया।

– पहली बार डीडी न्यूज़ स्टूडियो में आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ विशेष पैनल चर्चा और साक्षात्कार आयोजित किए गए।

– हैशटैग #AskYourFM के साथ वित्तमंत्री की एक टॉकथॉन भी आयोजित की गई जिसमें जनता के सवालों के जवाब दिए गए।

– इन कार्यक्रमों के अलावा, बजट के प्रमुख मुद्दों का क्षेत्रीय विश्लेषण, वित्त मंत्रालय के सचिवों, विशेषज्ञों, आदि के साथ बातचीत के माध्यम से किया गया था।

➢ 21 जून, 2018 को चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया और देशभर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का व्यापक कवरेज और प्रचार किया गया। योग और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2018 के बारे में जागरुकता पैदा करने के अभियान के बारे में सभी टीवी चैनलों, सभी एफएम रेडियो चैनलों और सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए एक सलाह जारी की गई।

– दूरदर्शन समाचार ने विशेष कार्यक्रम चलाए जिनमें विशेष कहानियों ^;kx io^ विशेष वृत्तचित्र ^;kx xkFkk^, दैनिक विशेष कार्यक्रम ^;kx l|okn^ और योग विशेषज्ञों पर कहानियां तथा साक्षात्कार और योग पर केंद्रित साप्ताहिक कार्यक्रम ^x|M U;t bfM;k^ थे।

– आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने विशेष समाचार दर्शन कार्यक्रम चलाया।

नई दिल्ली में 21 जून, 2018 को राजपथ पर चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कॉमन योग प्रोटोकॉल के दौरान एकत्र सहभागी

– न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) द्वारा व्यापक सोशल मीडिया कवरेज दिया गया।

➢ 72वें स्वतंत्रता दिवस 2018 का व्यापक प्रचार किया गया।

– माननीय राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संदेश और लालकिले से माननीय प्रधानमंत्री के भाषण की लाइव कवरेज और लाइव स्ट्रीमिंग की गई।

– दूरदर्शन समाचार ने माननीय प्रधानमंत्री के भाषणों पर आधारित कई विशेष कार्यक्रम जैसे ;x bfM;k @ 71, oknk fuHkk;k] Hkkjr dh cnyrh rLohj, j{kd Hkkjr d आदि दिखाए।

➢ दूरदर्शन समाचार और इसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने अपने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेटवर्क पर xkmM fjikVZ@ tehuh gdhdr के बारे में एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण किया जिसमें 5000 से अधिक सफलता की कहानियों/ग्राउंड रिपोर्टें शामिल हैं, जो सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के लाभार्थियों पर केंद्रित हैं। ये रिपोर्टें दूरदर्शन समाचार के पत्रकारों और स्ट्रिंगरों की टीम द्वारा तैयार की गई थीं। इनमें से ज्यादातर रिपोर्टें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब, ट्विटर आदि पर और अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया टैब के तहत वेबसाइट पर डाली गईं।

– प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 50वां संस्करण 25 नवंबर, 2018 को प्रसारित किया गया था। विशेष कार्यक्रम के तहत, दूरदर्शन समाचार ने 14 राज्यों और संघशासित प्रदेशों के 29 लोगों की भागीदारी के साथ विशेष श्रोता आधारित कार्यक्रम 'मन की बात सबके साथ' का आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने इनका जिक्र अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में किया था।

➢ माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6.2.2019 को आकाशवाणी (एआईआर) और दूरदर्शन की योजनाओं जिसमें डीडी अरुणप्रभा चैनल भी शामिल है, को 3 साल के लिए 2017–18 से 2019–20 तक जारी रखने के बारे में 1054.55 करोड़ रुपये की लागत वाली प्रसार भारती की प्रसारण बुनियादी ढांचा और नेटवर्क विकास योजना के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

➢ दूरदर्शन समाचार ने महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों/मुख्यमंत्रियों के साथ आधे घंटे के lh/kk lokn dk;Øe के तहत साक्षात्कार सहित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए।

➢ डीडी न्यूज़ ने माननीय प्रधानमंत्री से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्री–घरेलू, अंतरराष्ट्रीय और स्वतंत्रता दिवस पर विधिवत रूप से प्रधानमंत्री को सबसे व्यापक कवरेज दिया। डीडी न्यूज़ ने नियमित कार्यक्रमों के अलावा विशेष कार्यक्रम Hkkjr dh cnyrh rLohj (सरकार की योजनाओं की सफलता की कहानियों पर आधारित), oknk fuHkk;k (माननीय प्रधानमंत्री के वादों और उनकी पूर्ति पर आधारित), वादे और डिलीवरी, रक्षक भारत के और विशेष दर्शकों पर आधारित यंग इंडिया @71 कार्यक्रम काकोरी, बैरकपुर, वेल्लोर, साबरमती आश्रम जैसी जगहों से किए। डीडी न्यूज़ ने पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल विहारी वाजपेयी के निधन पर भी विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए।

– दूरदर्शन की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसके बेड़े में वृद्धि के कार्यक्रम के तहत, 9 डिजिटल उपग्रह समाचार संकलन (डीएसएनजी) वैन को 10 सितंबर, 2018 को माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एचडी सिग्नल अपलिंक सक्षम वैन से पूर्वोत्तर से दूरदर्शन की लाइव टेलीकास्ट क्षमता में वृद्धि होगी क्योंकि इनमें से 4 वैन गंगटोक, कोहिमा, इंफाल और अगरतला के लिए हैं और अन्य को इलाहाबाद, विशाखापत्तनम, चंडीगढ़, जगदलपुर और पुणे में तैनात किया जा रहा है।

नई दिल्ली में 10 सितंबर, 2018 को माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने दूरदर्शन की 9 डीएसएनजी वैन्स को झंडी दिखाई। साथ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे, प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ. ए. सूर्य प्रकाश एवं मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे

➢ सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) – देश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना में संभावित आवेदकों को प्रोत्साहित करने के लिए सामुदायिक

रेडियो (सीआर) स्टेशनों की स्थापना के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है।

- डीडी न्यूज़ ने केरल बाढ़ के दौरान बचाव और राहत कार्यों को व्यापक कवरेज दी। केरल के लोगों को सहायता प्रदान करने में सरकार के प्रयासों को पूर्ण कवरेज देने के लिए सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, एनडीआरएफ आदि के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। डीडी न्यूज़ ने केरल की बाढ़ के बाद की समस्याओं और महामारी जैसी स्थिति को कम करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की कवरेज जारी रखी।
- आकाशवाणी ने विभिन्न केंद्रीय कैबिनेट/राज्य मंत्रियों के साथ साक्षात्कार की ^^tu lok lokn^^ शीर्षक से साप्ताहिक शृंखला का राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण किया।
- मंत्रालय ने केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 18 दिसंबर, 2018 को एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में देशभर के प्रमुख मल्टीपल सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) की व्यापक भागीदारी देखी गई। लाइसेंसिंग, राइट ऑफ वे, टेक्नोलॉजी और समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के संबंध में उठाए गए मुद्दों को स्वीकार किया गया और एमएसओ को आश्वासन दिया गया कि सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे।
- वित्त वर्ष 2018–19 में 49 नए एफएम रेडियो चैनलों को चालू किया गया है।

fQYe fox

- 65oa jk"Vh; fQYe iqjLdkj 2017 की घोषणा 13 अप्रैल, 2018 को की गई थी और भारत के माननीय राष्ट्रपति ने तत्कालीन माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री के साथ 3 मई, 2018 को पुरस्कार प्रदान किए।

नई दिल्ली में 03 मई, 2019 को माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 65वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए

- जाने–माने हिंदी फ़िल्म अभिनेता श्री विनोद खन्ना को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत दादासाहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- अन्य प्रमुख विजेताओं में असमिया फ़िल्म ^foyst j,dLVkl^ सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म श्रेणी में और संपूर्ण मनोरंजन के लिए सबसे लोकप्रिय फ़िल्म श्रेणी में ^ckgqcyh&n dUDyw tu^ फ़िल्में शामिल थीं।
- रिद्धि सेन और श्रीदेवी को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (फ़िल्म– नगरकीर्तन) और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (फ़िल्म– मॉम) का पुरस्कार दिया गया।
- 'निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली प्रदर्शित फ़िल्म' का पुरस्कार पंपल्ली द्वारा निर्देशित जसारी भाषा की फ़िल्म ^flatj^ को इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया।
- फ़ीचर फ़िल्म श्रेणी में 'सर्वश्रेष्ठ निर्देशक' का पुरस्कार जयराज को फ़िल्म ^Hk;kude^ के लिए और गैर फ़ीचर फ़िल्म, श्रेणी में नागराज मंजुले को दिया गया।
- मध्य प्रदेश को ekLV fQYe ÝsMyh vokMZ से और उत्तराखंड को ^fQYe ÝsMyh ,Uok;jUesV^ के लिए विशेष उल्लेख प्रमाण–पत्र, से सम्मानित किया गया।
- ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) (विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, डीएवीपी) ने 'राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार (पृष्ठभूमि और पहचान सूचक)' पर दो प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया, जिनका उद्घाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति ने विज्ञान भवन में और माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री ने इसी दिन नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में किया।
- माननीय प्रधानमंत्री ने 19 जनवरी, 2019 को फ़िल्म प्रभाग परिसर, मुंबई में Hkkjrh; jk"Vh; fluek lxgky; (एनएमआईसी) का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने फ़िल्म बिरादरी की एक सभा को संबोधित किया और एनएमआईसी के उद्घाटन के लिए सभी को बधाई दी। एनएमआईसी ने भारतीय सिनेमा के संपूर्ण इतिहास को एक जगह दिखाया।
- मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समारोहों के सिलसिले में कई पहल की।

- भारतीय बाल फ़िल्म सोसायटी, ने वैष्णव जन गीत पर बच्चों के लिए एनीमेशन फ़िल्म के 125 शो प्रदर्शित किए।
- फ़िल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से 1 से 31 अक्तूबर, 2018 तक पोर्ट ब्लेयर में फ़िल्म समारोह आयोजित किया। डीएफएफ ने 29 और 30 सितंबर को नागांव, असम में दो दिवसीय फ़िल्म समारोह का भी आयोजन किया।
- राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी) ने MyGov प्लेटफॉर्म पर लघु फ़िल्म प्रतियोगिता में प्राप्त फ़िल्मों की समीक्षा की।
- भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) ने यरवदा जेल (पुणे), राजभवन (मुंबई) और द्वितीय गुवाहाटी अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में प्रदर्शनियों का आयोजन किया।
- साबरमती आश्रम, अहमदाबाद की एक प्रतिकृति पुणे में भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई थी।
- मंत्रालय ने देशभर में कई अवसरों पर और कार्यक्रमों में फ़िल्म समारोह आयोजित करके फ़िल्म समारोहों को संचार के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उपयोग किया।
- फ़िल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) ने गोवा सरकार के सहयोग से 20 से 28 नवंबर, 2018 तक गोवा में 49वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (आईएफएफआई) 2018 का आयोजन किया।
- आईएफएफआई 2018 ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के महोत्सव कैलाइडोस्कोप और विश्व पैनोरमा वर्गों के तहत 67 से अधिक देशों की 220 से अधिक फ़िल्मों का प्रदर्शन किया।
- फोकस देश इजरायल था और पहली बार, आईएफएफआई 2018 में एक राज्य फोकस वर्ग रखा गया, जिसमें इस वर्ष का फोकस राज्य झारखंड था।
- माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री ने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) द्वारा आयोजित 'सेल्युलॉइड पर महात्मा' मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रकाशन विभाग (डीपीडी) और एनएफएआई ने 'विमेन इन इंडियन सिनेमा' शीर्षक से पुस्तकों और पत्र सूचना कार्यालय की vkbl,Q,Qvkbl 2018 ¶yi'k chfQx fLdYl को अमेजन एलेक्सा स्मार्ट स्पीकर्स पर लॉन्च किया।
- उद्घाटन और समापन समारोह में राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म उद्योग के कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति जैसे कि अक्षय कुमार, करण जौहर, रणधीर कपूर, अनिल कपूर, जुलियन लैंडियास, डायना पेंटी, चित्रांगदा सिंह, अरबाज खान, राकेश ओमप्रकाश मेहरा, कबीर बेदी आदि उपस्थित थे। इसमें श्रव्य दृश्य प्रदर्शन भी किए गए।
- समारोह में उद्घाटन और समापन फ़िल्में वर्ल्ड प्रीमियर्स थीं और इन्हें फ़िल्मों के शौकीनों से असाधारण प्रतिक्रिया मिली।
- वयोवृद्ध इजराइली फ़िल्म निर्माता डैन वोलमैन को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईएफएफआई विशेष पुरस्कार सलीम खान को सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया गया।
- यूक्रेन की फ़िल्म Mkuckl ने आईएफएफआई 2018 में 'सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म' के लिए पुरस्कार जीता, जिसमें स्वर्ण मयूर ट्रॉफी, प्रमाण–पत्र और 40,00,000 रु की नकद राशि दी जाती है। 'सर्वश्रेष्ठ निर्देशक' का पुरस्कार लिजो जोस पेलिसरी को दिया गया और 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' का पुरस्कार चेम्बन विनोद को फ़िल्म bl- ek- ;,- के लिए दिया गया। 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' का पुरस्कार 'अनस्तासिया पुस्टोविट को यूक्रेनी फ़िल्म 0gu n Vht Q,y के लिए दिया गया।
- 'विशेष जूरी' पुरस्कार, मिल्को लजारोव को उनकी यकूत फ़िल्म vkxk के लिए प्रदान किया गया। इसमें पुरस्कार स्वरूप रजत मयूर और 15,00,000 रु. नकद दिए जाते हैं।
- अल्बर्टो मोंटेरस II को 'बेस्ट डेब्यू' फ़ीचर फ़िल्म ऑफ ए डायरेक्टर का शताब्दी पुरस्कार उनकी फिलिपिनो फ़िल्म 'रेसपेटो' के लिए मिला। इस श्रेणी में 'टू लैट' और 'वोलकानो' फ़िल्मों का विशेष उल्लेख किया गया।
- लद्दाखी फ़िल्म 'वॉकिंग विद द विंड' को आईसीएफटी–यूनेस्को गांधी मेडल से सम्मानित किया गया।
- एनएफएआई ने स्पोर्ट्स फ़िल्म फेस्टिवल का आयोजन (पुणे में खेलो इंडिया 2019 की पूर्व संध्या पर इसका उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले तथा खेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने किया) किया। इसमें 3 दुर्लभ फ़िल्में/फुटेज दिखाई गईं –
- 1948–49 में कोल्हापुर में खेले गए औपचारिक क्रिकेट

मैच में छत्रपति शिवाजी महाराज (द्वितीय) की क्रिकेट खेलते हुए क्लिप।

- बर्लिन ओलंपिक 1936।
- डलहौजी क्लब और मोहन बागान के बीच कोलकाता में 8 जनवरी, 2019 को एनएफएआई मुख्य थियेटर में खेले गए 1950 के फुटबॉल मैच की फुटेज।
- 22 से 27 जुलाई, 2018 तक अंतरराष्ट्रीय डरबन फ़िल्म समारोह (डीआईएफएफ) के साथ, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित rhlj fcDl fQYe lekjkg में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।
- चार भारतीय फ़िल्में दिखाई गईं और अंतिम दिन को 'भारत देश दिवस' के रूप में मनाया गया।
- भारतीय फ़िल्मों की अभिनेत्री भनीता दास को foyt j,dLVkl के लिए 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' का, अमित मसूरकर की U;wVu को 'सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म' का और रीमा दास की 'foyt j,dLVkl' को 'विशेष जूरी पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।
- 18 जून, 2018 को नई दिल्ली में ;jkih; l?k fQYe lekjkg का उद्घाटन किया गया। इस साल का फ़िल्म समारोह, फ़िल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) और यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा आयोजित किया गया, जिसके लिए यूरोपीय संघ के 23 सदस्य देशों की 24 नवीनतम यूरोपीय फ़िल्मों का चयन किया गया था। यह समारोह 18 जून से 31 अगस्त, 2018 तक नई दिल्ली, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, पुद्दुचेरी, कोलकाता, जयपुर, विशाखापत्तनम, त्रिशूर, हैदराबाद और गोवा सहित भारत के 11 शहरों से गुजरा।

नई दिल्ली में 18 जून, 2018 को यूरोपीय संघ फ़िल्म समारोह 2018 के उद्घाटन के अवसर पर माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। साथ में हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे एवं अन्य गणमान्य अतिथि

- dkl fQYe QsfLVoy 2018 में भारतीय मंडप का उद्घाटन फ्रांस के कांस में किया गया। विख्यात अभिनेता श्री शरद केलकर द्वारा आयोजित उद्घाटन सत्र में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में फ्रांस में भारत के राजदूत, एच.ई. विनय मोहन क्वात्रा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि, फ़िल्म अभिनेता, निर्माता और अन्य हितधारक सदस्य शामिल थे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच सह–निर्माण के अवसरों का पता लगाने के लिए बैठकों का भी आयोजन किया और ब्राजील, फिलीपींस, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, स्वीडन, ताइवान, कनाडा और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों के साथ सहयोग का पता लगाने के लिए एक गोलमेज चर्चा भी आयोजित की गई।
- फ़िल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) द्वारा 25 से 30 मई, 2018 तक आयोजित vkfl;ku Hkkjr fQYe lekjkg का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और खेल व युवा मामले के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 25 मई, 2018 को किया। महोत्सव की टैगलाइन 'फ़िल्मों के माध्यम से दोस्ती' थी। फ़िल्म समारोह में विभिन्न आसियान देशों की फ़िल्मों का प्रदर्शन करके सिनेमा की उत्कृष्टता का जश्न मनाया गया और सदस्य देशों के फ़िल्म उद्योग से जुड़े लोगों को सिनेमा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान किया।
- फ़िल्म समारोह निदेशालय ने विदेश मंत्रालय और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन के दूतावास के सहयोग से तीन दिवसीय Hkkjr&phu fQYe lekjkg का आयोजन 22 से 24 दिसंबर, 2018 तक सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में किया। समारोह का आयोजन सांस्कृतिक और वैयक्तिक आदान–प्रदान पर भारत–चीन उच्च स्तरीय तंत्र के साथ किया गया। समारोह का एक प्रतीकात्मक उद्घाटन 21 दिसंबर, 2018 को प्रवासी भारतीय केंद्र में सांस्कृतिक पर्व के दौरान किया गया था। इस अवसर पर माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन स्टेट काउंसिलर और विदेश मंत्री तथा एच.ई. श्री वांग यी उपस्थित थे। इसमें चीन की चार और भारत की तीन फ़िल्मों सहित कुल सात फ़िल्में दिखाई गईं।
- Hkkjrh; ihukjek fQYe lekjkg] 4 से 13 जनवरी, 2019 तक फ़िल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन 4 जनवरी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने प्रारंभिक फ़ीचर फ़िल्म 'ओलू' के निदेशक श्री शाजी एन. करुण

की उपस्थिति में सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में किया। समारोह के दौरान कुल 26 Qhpj fQYe vkSj 21 गैर–फीचर फ़िल्में प्रदर्शित की गईं, जिनमें 49वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में भारतीय पैनोरमा खंड के तहत चुनी गई सभी फ़िल्में शामिल थीं।

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से बर्लिन इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल 2019 में 7 से 17 फरवरी, 2019 तक बर्लिन, जर्मनी में भाग लिया।
- बर्लिनले 2019 में भारतीय पवेलियन और भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (आईएफएफआई) 2019 के पोस्टर का उद्घाटन किया गया।
- रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, जोया अख्तर और रितेश सिधवानी सहित फ़िल्म 'गली बॉय' की टीम ने भी भारतीय पवेलियन का दौरा किया और आईएफएफआई 2019 का ब्रोशर जारी किया।
- भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सहयोग के नए अवसर तलाशे और समारोह में इंडिया नेटवर्किंग गाला की मेजबानी की। आईएफएफआई गोल्डन जुबली

बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (बर्लिनेल) 2019 में भारतीय पवेलियन के उद्घाटन के अवसर पर फ़िल्म समारोह निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक श्री चैतन्य प्रसाद एवं अन्य गणमान्य अतिथि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ

समारोह के लिए, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों में आईएफएफआई की स्थिति पर भी चर्चा की गई।

- 8 मार्च, 2018 को ''अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस'' के सिलसिले में भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) ने ^vk'k; vkSj vk;ke^ के सहयोग से 9 से 11 मार्च, 2018 तक महिला फ़िल्म समारोह का आयोजन किया।
- भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) ने सिंबॉयोसिस (ईएलटीआईएस) के सहयोग से 24–25 फरवरी, 2018 को एनएफएआई मुख्य रंगमंच पर 'फ्रैगरैंसेज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट' समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सात भाषाओं की फ़िल्में दिखाई गईं और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा आहार उत्सव आयोजित किए गए।
- भारतीय बाल फ़िल्म समिति (सीएफएसआई) फ़िल्म बोनान्ज़ा का आयोजन मुंबई में 7 से 9 फरवरी, 2018 तक किया गया। इसमें कमजोर वर्ग के 3,101 बाल दर्शकों के लिए 18 शो किए गए।
- फ़िल्म 'शोले' के 43 साल पूरे होने के अवसर पर, डीएफएफ ने l{ke U;kl, lfi;V के सहयोग से, 29 सितंबर, 2018 को सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में श्रव्य–विवरण, हिंदी उपशीर्षक और संकेत भाषा में व्याख्या के साथ इसके प्रदर्शन का आयोजन, राजधानी क्षेत्र दिल्ली स्कूलों, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य संस्थानों के लगभग 800 दृष्टि और श्रवण बाधित बच्चों के लिए किया।
- फ़िल्म प्रभाग ने 72वें स्वतंत्रता दिवस 2018 के अवसर पर, उल्लेखनीय वृत्तचित्रों की स्क्रीनिंग के लिए ^^ÝhMe LVªxy ,.M ÝhMe QkbVlZ^^ विषय पर एक फ़िल्म समारोह आयोजित किया।
- भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार ने 25 से 27 जुलाई, 2018 तक पुणे के मैक्समुलर भवन के सहयोग से 'जेननेक्स्ट फ़िल्म फेस्टिवल 10.0' शीर्षक से जर्मन फ़िल्म समारोह की करते हुए स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन चार फ़िल्मों के दो शो आयोजित किए।
- मंत्रालय ने 1 से 3 फरवरी, 2019 तक रांची, झारखंड में द्वितीय झारखंड अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (जेआईएफएफ) के आयोजन में सहयोग किया। इसे एक गैर–सरकारी संगठन uoHkkjr fuek.k l?k ने आयोजित किया।
- भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार ने पुणे इंटरनेशनल सेंटर (पीआईसी) के सहयोग से 10 से 13 अगस्त, 2018 तक श्रीलंकाई फ़िल्म समारोह का आयोजन किया और दर्शकों के लिए 11 फ़िल्मों का प्रदर्शन किया।

➢ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम

(एनएफडीसी) को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा मिनी रत्न श्रेणी (श्रेणी द्वितीय) के तहत विजेता चुना। इसका चयन अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के अनुकरणीय कार्य को मान्यता देकर प्रोत्साहित करने के लिए किया गया।

- भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) की फ़िल्म एजुकेशन आउटरीच इनीशिएटिव ,ldvkbl,QVh (फ़िल्म और टेलीविजन में भारत को कुशल बनाना) के तहत, पिछले 14 महीनों में 3800 से अधिक प्रतिभागियों के लिए देशभर के 23 स्थानों में 84 लघु पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

- भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) ने भारतीय फ़िल्म अध्ययन में 1 o"khl; LukrdksÙkj fMIykek पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (एसपीपीयू) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। फ़िल्म प्रस्तुति का एक घटक, पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा और इस पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

- एफटीआईआई ने 6 राज्यों के 59 प्रतिभागियों के लिए फ़िल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) के सहयोग से नई दिल्ली में Hkkjrh; fluek ei xhr fp=kdu dk eY;kdu पर एक सप्ताह का पाठ्यक्रम आयोजित किया।

- भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) ने बच्चों के लिए सात दिवसीय fQYe fuekl.k cfu;knh Kku dk;l'kkyk का आयोजन 23 से 29 अप्रैल, 2018 तक किया, जिसमें प्रतिभागियों ने 5 लघु फ़िल्में बनाईं। बच्चों को फ़िल्म निर्माण में बुनियादी जानकारी देने के लिए 15 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 23 अप्रैल से 7 मई, 2018 तक किया गया जिसमें 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

- एफटीआईआई ने चार दिन के सप्ताहांत भारतीय फ़िल्म संगीत मूल्यांकन पाठ्यक्रम का आयोजन 7, 8, 14 और 15 अप्रैल, 2018 को एफटीआईआई कैंपस में भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार (एफटीआईआई) के सहयोग से किया।

19 जनवरी, 2019 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय के उद्घाटन अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे फिल्म जगत के गणमान्य अतिथियों के साथ

संवादात्मक डिजिटल प्रदर्शनी ''एक भारत, स्वच्छ और सक्षम भारत'' वाराणसी का मुख चित्र

,d >yd

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, रेडियो, टेलिविजन, फ़िल्मों, प्रेस और प्रकाशनों, विज्ञापन तथा संचार के परंपरागत माध्यमों जैसे नृत्य एवं नाटकों के जरिए जनता को सूचना की शुल्क रहित प्राप्ति में असरकारी भूमिका निभाता है। मंत्रालय विभिन्न आयु वर्ग की मनोरंजन की जरूरतों का भी ध्यान रखता है और साथ ही, राष्ट्रीय अखंडता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, निरक्षरता का अंत और महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों एवं समाज के अन्य पिछड़ा वर्ग के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। मंत्रालय को तीन कार्यकारी विभागों में बांटा गया है, जो हैं, सूचना विभाग, प्रसारण विभाग और फिल्म्स विभाग। मंत्रालय 19 मीडिया इकाइयों/संबंधित एवं अधीन कार्यालयों, स्वायत्त अंगों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के जरिए काम करता है। मंत्रालय का मुख्य सचिवालय एक सचिव के अंतर्गत काम करता है जिसके अधीन एक अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएसएंडएफए), एक अतिरिक्त सचिव, एक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार, चार संयुक्त सचिव एवं एक अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार होते हैं। मुख्य सचिवालय के विभिन्न प्रखंडों में 21 पद निदेशक/उप–निदेशक/वरिष्ठ पीपीएस, 38 पद अंडर सेक्रेटरी/पीपीएस स्तर अधिकारियों के, 67 पद विभाग अधिकारियों/पीएस स्तर के अधिकारियों के एवं 184 अराजपत्रित पद हैं।

मंत्रालय का सूचना प्रभाग प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के संबंध में भारत सरकार की नीतियों एवं गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण एवं व्याख्या का कार्य करता है, साथ ही, यह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑनलाइन मंचों पर नियत सरकारी दरों से जुड़े नीतिगत दिशानिर्देशों की भी स्थापना करता है और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, 1867, पत्र सूचना अधिनियम, 1978, भारतीय सूचना सेवा का कैडर मैनेजमेंट (आईआईएस) एवं मंत्रालय से जुड़ी आम सूचना का कार्य भी देखता है।

प्रसारण प्रभाग प्रसार भारती अधिनियम, 1900 के प्रशासनिक कार्यों के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के कार्य देखता है। यह केबल टेलिविजन नेटवर्क्स (नियमन) अधिनियम 1995 और नीतिगत दिशानिर्देशों के माध्यम से समय–समय पर निजी सेटेलाइट चैनलों और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों के नेटवर्क तथा स्थानीय केबल ऑपरेटरों के कार्यक्रमों पर नियंत्रण रखता है। प्रभाग द्वारा ही ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों के निजी एफएम रेडियो चैनलों और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की नीलामी का कार्य संपन्न किया जाता है।

12 अगस्त, 2018 को जयपुर में रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा आयोजित चित्र प्रदर्शनी ''साफ नीयत सही विकास'' का अवलोकन करते हुए युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण (सवतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

फ़िल्म प्रभाग सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 के अंतर्गत फ़िल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन से जुड़ा प्रमाणीकरण, फ़िल्म उद्योग से जुड़े मामले जिनमें विकास एवं प्रोत्साहन गतिविधियां, फ़िल्मों का संरक्षण, वृत्तचित्रों का निर्माण एवं प्रसारण, अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सवों का व्यवस्थापन, पुरस्कारों के जरिए स्वस्थ सिनेमा को प्रोत्साहन आदि जैसे कार्यों को देखता है।

मंत्रालय के वित्त, बजट और लेखा से संबंधित मामले एकीकृत वित्त प्रभाग देखता है।

मंत्रालय का आर्थिक प्रभाग योजना, बजट, योजना समन्वयन, ओएंडएम गतिविधियां और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कैबिनेट सचिव को विभिन्न मामलों की नियतकालीन सूचना देने का कार्य देखता है। आर्थिक सलाहकार द्वारा सीपीजीआरएएम पोर्टल, यातायात एवं संचार के क्षेत्रीय समूह सचिवों (एसजीओएस) से जुड़े कार्य, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए नोडल अफसरों के अंतर्मंत्रालयी और न्यू इंडिया कोड पोर्टल का संचालन, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की सालाना बैठक के संयोजन से जुड़े मामले और साइबर सुरक्षा कानून के अलावा सूचना एवं प्रसारण सचिव को आर्थिक मामलों में सहयोग देने के कार्य देखे जाते हैं।

Lkpuk ,o i lkj.k e=ky; dk dk;{k=

मंत्रालय को उसके कार्यों में 11 संबद्ध और अधीन कार्यालय, 6 स्वायत्त संगठन और 2 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां सहयोग देते हैं।

Lkc)@v/khu dk;ky;

1. पत्र सूचना कार्यालय
2. ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन
3. भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक का कार्यालय
4. प्रकाशन विभाग
5. न्यू मीडिया विंग
6. फोटो प्रभाग
7. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर
8. फ़िल्म प्रभाग
9. केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड

गोवा के पणजी में 21 नवंबर, 2018 को भारत के 49वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (आईएफएफआई–2018) के अवसर पर आयोजित एक मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी, 'सेल्युलॉयड पर महात्मा' का अवलोकन करते हुए युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। साथ में हैं, फ़िल्मकार श्री सुभाष घई और अभिनेत्री श्रीमती पूनम ढिल्लों

10. राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय
11. फ़िल्म महोत्सव निदेशालय

Lok;Ÿk lxBu

1. भारतीय प्रेस परिषद
2. भारतीय जन–संचार संस्थान
3. प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया)
4. राष्ट्रीय फ़िल्म एवं टेलिविजन इंस्टीट्यूट, पुणे
5. सत्यजित रे फ़िल्म एवं टेलिविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता
6. बाल चित्र समिति, भारत

lkoZtfud {k= bdkbZ;k

1. ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
2. राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम

lpuk ,oa izlkj.k e=ky; dk vf/kdkj {k=

- देशवासियों तथा प्रवासी भारतीयों के लिए ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) तथा दूरदर्शन (डीडी) पर समाचार सेवाएं;
- प्रसारण एवं टेलिविजन का विकास;
- फ़िल्म उद्योग का विकास एवं प्रोत्साहन;
- फ़िल्म महोत्सवों एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान का आयोजन;
- भारत सरकार की ओर से विज्ञापन एवं चित्र प्रचार तथा प्रकाशन से जुड़ा फीडबैक प्राप्त करना;
- समाचार पत्रों के संबंध में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, 1867 का संचालन;
- फ़िल्म प्रमाणन के संबंध में सिनेमेटोग्राफ एक्ट, 1952 का संचालन;
- प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) एक्ट, 1990 (1990 का 25) का प्रसार नियंत्रण एवं संचालन;
- केबल टेलिविजन नेटवर्क्स (विनियमन) एक्ट, 1995, (1995 का 7);
- प्रेस काउंसिल अधिनियम, 1978 का संचालन (1978 का 37);
- भारतीय सूचना सेवा का कैडर प्रबंधन (ग्रुप ए और बी);
- राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भारत और देश से बाहर सूचना का प्रकाशनों के माध्यम से विस्तार;
- मंत्रालय की मीडिया इकाइयों को शोध, संदर्भ एवं प्रशिक्षण में सहयोग;
- मंत्रालय के संस्थानों को बड़ी मात्रा में सहयोग देने वाले प्रतिष्ठित कलाकारों, संगीतकारों, वादकों, नर्तकों, नाट्यकारों को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना;
- प्रसारण एवं समाचार सेवाओं के मामले में अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करना।

■ ■ ■

नई दिल्ली में 13 फरवरी, 2019 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों की पहली अखिल भारतीय बैठक के दौरान एक समूह चित्र में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के साथ युवा मामले और खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। साथ में हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे

2 e=ky; dh Hkfedk vkj dk;l

सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की भूमिका और कार्य निम्न हैं :

I. i lkj.k uhfr vkj i'kklu

1. भारतीय संघ में रेडियो और टेलिविजन से जुड़े सभी मामले जिनमें राजनीतिक दलों द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा चुनावों के समय ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के इस्तेमाल और किसी शीर्ष नेता के निधन के अवसर पर राष्ट्रीय शोक के समय सभी आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा कार्यविधि का पालन किया जाता है।
2. भारत में रेडियो और टेलिविजन से जुड़े कानूनों को स्पष्ट करना और अमल में लाना।
3. प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) का प्रसारण नियंत्रण एवं प्रबंधन।
4. प्रसार भारती के सुपुर्द किए जाने तक भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा और भारतीय प्रसारण (अभियांत्रिकी) सेवा से जुड़े सभी मामले देखना।

II. dcy Vfyfotu uhfr

1. केबल टेलिविजन नेटवर्क्स ¼विनियमन½ अधिनियम, 1995 ¼1995 का 7½।

III. jfM;k

1. ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी कार्य जिनमें घरेलू कार्यक्रमों में समाचार सेवाओं का उपयोग, विदेशों और प्रवासी भारतीयों के लिए कार्यक्रम, रेडियो जर्नल्स, प्रसारण अभियांत्रिकी के क्षेत्र में शोध, विदेशी प्रसारणों की जांच, कार्यक्रम आदान–प्रदान एवं प्रतिलेखन सेवाएं, सामुदायिक श्रवण योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को सामुदायिक सेट्स देना आदि।
2. भारतीय संघ में रेडियो प्रसारण का विकास, रेडियो स्टेशनों की स्थापना और रखरखाव एवं टांसमीटरों तथा प्रसारण सेवाओं का संचालन।

IV. njn'ku

1. टीवी कार्यक्रमों के सांस्कृतिक एवं अन्य आदान–प्रदान।
2. देशभर में कार्यक्रम निर्माण केंद्रों एवं टांसमीटरों तथा टेलिविजन सेवाओं की स्थापना, रखरखाव और संचालन सहित उनकी सेवाएं चलाना।

मुंबई में 12 मार्च, 2019 को 'एफआईसीसीआई फ्रेम्स 2019' के 20वें संस्करण के दौरान तीन दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर दीप प्रज्ज्वलित करते सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे। सम्मेलन का थीम 'फ्रेम्स@20:ग्लोबल गोज़ इंडिया' था

3. दूरदर्शन से बाहर के टेलिविजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन।

V. fQYe

1. संघीय सूची की प्रविष्टि 60 के अंतर्गत, 'प्रदर्शन के लिए सिनेमेटोग्राफ फ़िल्मों को मंजूरी'।
2. सिनेमेटोग्राफ एक्ट, 1952 ¼1952 का 37½ का प्रबंधन।
3. थियेटर और गैर–थियेटर प्रदर्शन के लिए फ़ीचर एवं लघु फ़िल्मों का आयात।
4. विकास एवं प्रोत्साहन सहित फ़िल्म उद्योग से जुड़े सभी मामले।
5. राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों की स्थापना के जरिए भारत में निर्मित सार्थक सिनेमा को प्रोत्साहन। इसमें राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम लिमिटेड का सहयोग रहता है।
6. आंतरिक और बाहरी प्रचार के लिए फ़िल्म अंश, वृत्तचित्रों एवं न्यूज़ रीलों का निर्माण तथा वितरण।
7. फ़िल्मों और फ़िल्म संबंधी सामग्री का संरक्षण।
8. भारत में अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों का आयोजन और भारत को विदेशी अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों में सहभागिता में सहयोग
9. सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत फ़िल्म समारोहों का आयोजन।
10. फ़िल्म सोसाइटी अभियान को सहयोग।

VI. foKkiu ,oa n'; izpkj

1. भारत सरकार की ओर से मीडिया योजनाएं, निर्माण एवं विज्ञापन वितरण तथा सरकारी विज्ञापनों से संबंधित विज्ञापन नीति के निर्माण में सहयोग करना।

VII. izsl

1. प्रेस के माध्यम से भारत सरकार की नीतियों एवं गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण और व्याख्या।
2. सरकार को प्रेस से जुड़ी सूचना समस्याओं से अवगत कराना, प्रेस में प्रकाशित प्रमुख जन रुझानों की जानकारी सरकार को देना और सरकार तथा प्रेस के बीच संपर्क का कार्य।
3. सशस्त्र सेवाओं के लिए प्रसार कार्य।
4. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ¼1974 का 2½ की धारा 95

नई दिल्ली में 02 मार्च, 2019 को वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली 'मन की बात– ए सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो' के लोकार्पण के अवसर पर। साथ में हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे, प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ. ए. सूर्य प्रकाश एवं अन्य गणमान्य अतिथि

और 96 के संचालन से इतर प्रेस के प्रति सरकार के आचार–व्यवहार की देखरेख।

5. समाचार–पत्रों के संबंध में प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 ¼1867 का 25½ का संचालन।

6. प्रेस काउंसिल अधिनियम, 1978 ¼1978 का 37½ का संचालन।

7. न्यूज़प्रिंट आयात के लिए प्रकाशकों के स्व–प्रमाण पत्रों का प्रमाणीकरण।

8. सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों तथा फोटोग्राफिक दस्तावेजों का दृश्य प्रचार।

VIII. izdk'ku

1. भारत के बारे में देश एवं बाहर आमजन को सही सूचना प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर आंतरिक एवं बाहरी प्रचार के लिए लोकप्रिय प्रचार पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन, बिक्री और वितरण।

IX. 'kks/k ,oa lanHkZ

1. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों तथा सरकार से बाहर के संस्थानों की मीडिया इकाइयों को शोध सामग्री वाले प्रकाशित कार्यों आदि में संकलन, एकत्र एवं तैयार करने में सहयोग करना।

2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों एवं सरकार से इतर संगठनों की मीडिया इकाइयों को मौजूदा एवं अन्य मुद्दों पर दिशानिर्देश तथा पृष्ठभूमि नोट जारी करना और महत्वपूर्ण विषयों पर संक्षिप्त सूचना तैयार करना।

X. fofo/k

1. भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं नीतियों का प्रचार।

2. पत्रकार कल्याणकारी योजना का संचालन।

3. ऑल इंडिया रेडियो और मंत्रालय की अन्य इकाइयों की सफलता में असीम योगदान देने वाले प्रतिष्ठित संगीतकारों, गायक और वादकों, नर्तकों तथा नाटककारों या विषम परिस्थितियों में रहने वाले उनके उत्तराधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

4. एशिया–पेसेफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन और गुट–निरपेक्ष न्यूज़ एजेंसी पूल से जुड़े मामलों की देखरेख।

5. विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों (सीईपी)/अनुबंध/समझौता ज्ञापन/प्रोटोकॉल से जुड़े मामले; इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन (आईपीडीसी)/यूनेस्को, उदाहरण के तौर पर बजट मामले, नामांकन आदि से जुड़े सभी कार्य देखना।

6. भारतीय सूचना सेवा (ग्रुप ए और बी) के कैडर प्रबंधन से जुड़े कार्य।

कुम्भ–2019, प्रयागराज, में बी.ओ.सी. द्वारा आयोजित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी

3 e=ky; dh ubl igy

- मुंबई के पेड्डार रोड, कंबाला हिल फ़िल्म प्रभाग कैंपस में 19 जनवरी, 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय सिनेमा संग्रहालय (एनएमआईसी) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संग्रहालय का दौरा किया और वहां मौजूद फ़िल्म समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर सबको एनएमआईसी के उद्घाटन की बधाई दी और कहा कि यहां एक ही छत के नीचे भारतीय सिनेमा का समूचा इतिहास मिलता है। उन्होंने फ़िल्म समुदाय को बधाई दी जिसके मार्गदर्शन में भारतीय सिनेमा नित नए आयाम स्थापित कर रहा है।

- अरुणाचल प्रदेश में 9 फरवरी, 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डीडी अरुणप्रभा का शुभारंभ किया तथा साथ ही फ़िल्म एवं टेलिविजन इंस्टीट्यूट (एफटीआई) और राज्य में कई अन्य परियोजनाओं की नींव रखी। डीडी अरुणप्रभा दूरदर्शन का 24वां चैनल है और यह पूर्वोत्तर को देश के साथ जोड़ने में मददगार होगा। यह पूर्वोत्तर की भव्यता को दर्शाते हुए वहां की स्थानीय जनता की जरूरतों एवं आकांक्षाओं के अनुसार संवेदनशील कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा।

मुंबई में 19 जनवरी, 2019 को भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय के उद्घाटन समारोह के दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

- माननीय प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर भारतीय और विदेशी फ़िल्मों के फ़िल्मांकन में लाई जाने वाली आसानी की घोषणा की। भारत में विदेशी फ़िल्मकारों को मंजूरी देने के लिए वेब पोर्टल https://ffo.gov.in पहले से ही कार्य कर रहा है। फ़िल्म सुविधाकरण कार्यालय (एफएफओ) के पोर्टल और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों एवं अन्य सरकारी विभागों के उचित समन्वयन के बाद यह सुविधा भारतीय फ़िल्मकारों को भी मिलनी शुरू हो जाएगी।

- 6 फरवरी, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रालय द्वारा ^flusesVksxzkQ ,DV] 1952 esa la'kks/ku & flusesVksxzkQ ¼la'kksf/kr½ fo/ks;d] 2019* की सिफारिश को मंजूरी दी गई। विधेयक में फ़िल्मों की अनाधिकृत कैम्कॉर्डिंग और उनकी प्रतिछवि तैयार करने पर तीन वर्ष की जेल या 10 लाख रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान होगा। यह विधेयक 12 फरवरी, 2019 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया।

- एक ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत निजी एफएम रेडियो प्रसारकों को अंग्रेजी/हिंदी में ऑल इंडिया रेडियो के समाचार बुलेटिनों को, विशेष नियम तथा शर्तों के अनुसार, उनके नियत समय पर प्रसारण करने की अनुमति दी गई है। 31 मई, 2019 तक इसे शुल्करहित आधार पर किया जाएगा। यह शुरुआत लोगों को शिक्षित, सूचना देने और सशक्त करने के लिए सभी रेडियो स्टेशनों को एक साथ लाने का संयुक्त प्रयास है।

नई दिल्ली में 08 जनवरी, 2019 को 'शेयरिंग ऑफ एआईआर न्यूज़ विद प्राइवेट एफएम ब्रॉडकास्टर्स' के शुभारंभ पर दीप प्रज्ज्वलित करते हुए माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे एवं अन्य गणमान्य अतिथि भी साथ में मौजूद हैं

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित 8वीं दर संरचना समिति की सिफारिशों पर ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी, पूर्व में डीएवीपी) द्वारा प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापनों की दरों में 08.01.2019 से संशोधन कर मौजूदा विज्ञापनों से बढ़ाकर 25 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई। इस निर्णय से बड़ी संख्या में क्षेत्रीय एवं देशी भाषाओं के छोटे और मझोले समाचार–पत्रों को बेहद लाभ पहुंचेगा।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन की सिफारिश के आधार पर 25 जनवरी, 2019 को निजी टीवी चैनलों के लिए विज्ञापन दरों को संशोधित किया है। इस संशोधन से 2017 की दरों की अपेक्षा अधिकांश टीवी चैनलों की दरों में 11 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि कुछ अन्य के लिए, यह उनकी पहुंच और टीवी रेटिंग्स के अनुसार अधिक रहेगा। समाचार और गैर–समाचार टीवी चैनलों की अंतर्संबंधी दरों को भी स्पष्ट किया जा रहा है, यह देशभर में उनकी पहुंच पर आधारित होगा। इस निर्णय के बाद टीवी चैनलों को बीओसी के साथ जोड़ने में आसानी रहेगी ताकि वह उच्च दरों का लाभ उठा सकें।

- सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित एवं प्रसारित तथा सोशल मीडिया मंचों पर अपलोड की जाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट श्रृंखला की सफलता के बाद, जिसमें 5,000 ग्राउंड रिपोर्ट हैं और विभिन्न लाभार्थियों और सफल गाथाओं का ब्यौरा है, डीडी न्यूज़ सरकार की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना vk;q"eku Hkkjr पर भी इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट श्रृंखला तैयार करने का कार्य कर रही है। डीडी न्यूज़ आयुष्मान भारत और पीएमजेएवाई की कहानियां अपने राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित कर रहा है जिन्हें इन योजनाओं के लाभार्थियों को मिले स्वास्थ्य लाभ अनुभवों के आधार पर एकत्रित किया गया है। यह सब कहानियां हिंदी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित की जा रही हैं और इन्हें यूट्यूब चैनल तथा वेबसाइट www.ddnews.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

- गोवा सरकार के साथ पणजी, गोवा में फ़िल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) ने 20 से 28 नवंबर, 2018 तक भारत के 49वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह का आयोजन किया। आईएफएफआई 2018 द्वारा इस अवसर पर कई नई पहल की गईं जिसमें खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत छह भारतीय खेल जीवनीपरक फ़िल्मों की स्क्रीनिंग भी थी। साथ ही, मास्टरक्लासेज और फ़िल्म उद्योग की

गोवा के पणजी में 20 नवंबर, 2018 को 49वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (आईएफएफआई–2018) के उद्घाटन के अवसर पर माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, अभिनेता श्री अक्षय कुमार और निर्देशक श्री करण जौहर

कई जानी–मानी हस्तियों की अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत भी इस सत्र में आयोजित की गई। आईएफएफआई में इस वर्ष ए स्केच ऑन स्क्रीन (एनिमेशन फ़िल्मों का पैकेज) की भी शुरुआत की गई। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए एक विशेष पैकेज के अंतर्गत शोले और हिचकी फ़िल्मों का भी प्रदर्शन किया गया। मरणोपरांत दादासाहेब फाल्के पुरस्कार विजेता विनोद खन्ना की पांच फ़िल्मों का पुनरावलोकन भी इस दौरान किया गया। फ़िल्म समारोह की एक अन्य विशेषता इंगमार बर्गमैन की जन्मशती के अवसर पर उनकी फ़िल्मों का पुनरावलोकन भी था। साथ ही, पहली बार राज्य विशेष पर फोकस भी प्रदर्शित हुआ। आईएफएफआई का पहला फोकस राज्य झारखंड था।

- प्रसार भारती ने डीडी फ्री डिश के माध्यम से उपग्रह से प्रसारित होने वाले 11 और राज्यों के डीडी चैनलों को खरीदा है जिनमें पूर्वोत्तर के पांच चैनल शामिल हैं। यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और उत्तराखंड को अपने डीडी चैनल सेटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से डीडी फ्री डिश से प्राप्त हुए हैं। प्रादेशिक प्रसारण तक अधिकाधिक पहुंच के माध्यम से क्षेत्रीय संस्कृति और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

- प्रकाशन विभाग ने ;kt uk पत्रिका के विशेषांक 'रोज़गार एवं स्वरोज़गार' का प्रकाशन किया और 24 अगस्त, 2018 को इसका विमोचन किया गया। इस विशेषांक के विषय का चयन अर्थशास्त्रियों के अध्ययनों और हालिया रिपोर्ट्स के आधार पर किया गया जिसके कारण कहा जाता है कि देश में रोज़गार संबंधित डाटा सही रोज़गार से जुड़ी सही तस्वीर पेश नहीं करता। इस विशेषांक में विश्वसनीय रोज़गार डाटा से पेरोल रिपोर्टिंग के लाभ, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों से एमएसएमई के रूप में रोज़गार के नए साधनों; रोज़गार निर्माण में उद्यमिता की भूमिका से लेकर भारतीय श्रम बाज़ार के विभिन्न पक्षों जैसे विविध विषयों का विस्तार से आकलन किया गया है।

- आमजन को स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) द्वारा 2–7 अक्तूबर, 2018 को एक 6 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसका विषय था– 'बापू री–लिव्डः इन वर्ड, डीड एंड एक्शन'। इस दौरान, पहली बार किसी प्रदर्शनी में नई तकनीकी का इस्तेमाल हुआ, जिसमें महात्मा के दर्शन पर प्रश्नावली, महात्मा का क्रमिक विकास, महात्मा के जीवन पर पुस्तिका, प्रक्षेपित स्वच्छता चश्मा, स्वच्छता पर प्रश्नोत्तरी, सेल्फी कॉर्नर, ऑनलाइन प्रतिज्ञा मंच और लाइव परफॉरमेंस हॉल प्रमुख थे। प्रदर्शनी का आरंभ दूरदर्शन एवं फ़िल्म प्रभाग द्वारा गीत 'वैष्णव जन तो तेने कहिये...' के गायन से किया गया। इस अभियान में लोगों को मुख्यतौर पर कार्यांजली के जरिए स्वच्छ भारत मिशन में अंशदान करने के लिए और अक्तूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित किया गया।

- प्रयागराज में 2019 के अर्द्धकुंभ मेला के अवसर पर वहां एकत्र अपार जनसमूह को देखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपनी व्यापक पहुंच की गतिविधियों के अंतर्गत मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी एकीकृत कार्यक्रम 'एक भारत, स्वच्छ और सक्षम भारत–बापू और सरदार के सपनों का भारत' का आरंभ किया। सरकार की आउटरीच गतिविधियों में कला एवं संस्कृति और सीधे एकीकृत संचार अभियान शामिल हैं। साथ ही, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विजन से प्रभावित नये भारत की यात्रा का भी आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में अनेक दर्शक पहुंचे और इसमें सरकार की उपलब्धियों और नई पहलों को प्रदर्शित किया गया।

- डीडी न्यूज़ ने विभिन्न समूहों के लिए अनेक विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ किया है। नए भारत और युवाओं की प्रासंगिकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम 'बदलते भारत पर चर्चा' की शुरुआत की गई। 'नेशनवाइड' नामक एक नए कार्यक्रम में स्थानीय विषय उठाए जाते हैं जिन्हें प्रादेशिक नेटवर्क प्रसारित करते हैं। रविवार को देश में नवीन शुरुआत करने वालों और निजी सफलताओं की रचना करने वालों के बारे में बताने वाले कार्यक्रम 'गुड न्यूज़ इंडिया' का प्रसारण किया जाता है। सरकार की प्रमुख योजनाओं के अमल में लाए जाने और उनकी सफलता के बारे में विमर्श करने वाले कार्यक्रम 'पॉजीटिव इंडिया' का प्रसारण गुवाहाटी, चेन्नई, भोपाल, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली से किया जाता है।

- दूरदर्शन (डीडी) किसान चैनल ने 14 दिसंबर, 2018 को अपनी किस्म के पहले रियलिटी शो 'महिला किसान अवाड्र्स' का शुभारंभ किया। इस शो के प्रत्याशियों का चुनाव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और देशभर से शो में हिस्सा लेने आई महिला कृषकों ने किया। 'महिला किसान अवाड्र्स' ऐसा रियलिटी शो है जो न केवल लोगों को शिक्षित करेगा बल्कि भारतीय कृषि से जुड़े अज्ञात नायकों की अनोखी कहानियां भी दर्शकों को बताने का कार्य करेगा।

- दूरदर्शन पर हाल में एक यात्रावृत्त कार्यक्रम 'रग रग में गंगा' और क्विज शो 'मेरी गंगा' का शुभारंभ किया गया। यह यात्रा चित्र और क्विज शो दूरदर्शन के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) के सहयोग से तैयार किया गया है। गोमुख से गंगासागर तक की गंगा नदी की यात्रा को 'रग रग में गंगा' धारावाहिक की 21 कड़ियों में समेटा गया है जिसका प्रसारण 2 फरवरी, 2019 से आरंभ हुआ। धारावाहिक में अनोखे और रोचक प्रारूप में गंगा नदी को फिर से नया करने और सरकार द्वारा गंगा को स्वच्छ किए जाने के प्रयासों के बारे में बताया गया है। क्विज शो 'मेरी गंगा' में देश के सभी क्षेत्रों के स्कूली बच्चों को एकत्रित कर उनमें गंगा की सफाई से जुड़े कार्य के बारे में कौतुहल जगाने की कोशिश की गई है ताकि वह इससे जुड़ाव महसूस कर सकें।

- डीडी न्यूज़ प्रतिदिन प्रातः 10:55 बधिर श्रोताओं के लिए 5 मिनट के न्यूज़ बुलेटिन का प्रसारण करता है। डीडी न्यूज़ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम 'मन की बात' का भी सांकेतिक भाषा में डीडी भारती के लिए निर्माण करता है।

- बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जीवनवृत पर एक फ़िल्म और 1971 के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संघर्ष पर एक फ़िल्म तथा वृत्तचित्र के लिए एक रोडमैप तैयार करने हेतु भारत–बांग्लादेश संयुक्त समिति की पहली बैठक 12 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक के बाद अनेक दृश्य–श्रव्य मुद्दों पर आपसी सहमति बनी जिनमें भारतीय फ़िल्मों का बांग्लादेश में प्रदर्शन, दूरदर्शन और बांग्लादेश टीवी के बीच सहयोग, सामुदायिक रेडियो क्षेत्र में सहयोग, ऑल इंडिया रेडियो और बांग्लादेश बेतार के बीच सहयोग प्रमुख थे।

- ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) की स्ट्रीमिंग सेवाओं का अमेजन एलेक्सा स्मार्ट स्पीकर्स पर शुभारंभ माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने 28 सितंबर, 2018 को किया। अब एआईआर की विविध भारती एवं 14 अन्य प्रादेशिक भाषाओं की स्ट्रीमिंग अमेजन एलेक्सा पर हो रही है।

- दृश्य–श्रव्य क्षेत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फ़िल्म प्रभाग की गतिविधियों के अंतर्गत, फ़िल्म सुविधाकरण कार्यालय (एफएफओ) एक वेब पोर्टल स्थापित करने का कार्य कर रहा है जिसमें भारत में फ़िल्मों के निर्माण/पोस्ट प्रोडक्शन से जुड़ी लोकेशन और अन्य सुविधाओं की सूचना दी जाएगी। पोर्टल के माध्यम से भारत में फ़िल्मांकन करने वाली कंपनियों को मदद, प्रस्तावित लाभ (वास्तविक/अवास्तविक) का पता लगाने और देश की विभिन्न लोकेशनों का विवरण पता करने में मदद मिलेगी जिससे प्रस्तावित फ़िल्म की कथावस्तु में भी सुधार किया जा सकेगा।

- देश में पहली बार भारतीय सेना ने पुणे के फ़िल्म एवं टेलिविजन इंस्टीट्यूट (एफटीआईआई) के साथ मिलकर कश्मीर के बारामूला में पहला 20 दिवसीय 'फाउंडेशन कोर्स इन स्क्रीन एक्टिंग' का आयोजन किया, जिसमें 33 युवाओं ने भाग लिया जिनमें 4 महिलाएं थीं। एफटीआईआई

नई दिल्ली में 28 सितंबर, 2018 को अमेजन एलेक्सा स्मार्ट स्पीकर्स पर ऑल इंडिया रेडियो की स्ट्रीमिंग सेवाओं का उद्घाटन करते हुए माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। साथ में हैं, प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ. ए. सूर्य प्रकाश, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शशि शेखर वेम्पती और ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक श्री एफ. शहरयार

ने 9 से 13 मई, 2018 को जम्मू और कश्मीर में पहले 'फ़िल्म एप्रिसिएशन कोर्स' का भी आयोजन किया जिसमें 36 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

- सप्ताह के पांच दिन डीडी न्यूज़ पर स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित पांच मिनट का बुलेटिन प्रसारित किया जाता है, जिसका शीर्षक है स्वच्छता समाचार। बुलेटिन में उन लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य दिखाए जाते हैं जो देश को स्वच्छ रखने के लिए इस अभियान से जुड़े हैं। बुलेटिन का प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 7.50 और सायं 6.50 पर होता है। इसमें एक स्वच्छता युक्ति के साथ स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी ख़बरें, लोगों की पहल और फ़ीचर ख़बरें होती हैं।

■ ■ ■

नई दिल्ली में 19 फरवरी, 2019 को 7वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह के अवसर पर विवरणिका का लोकार्पण करते युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। साथ में हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे, पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक श्री सीतांशु आर. कार

4 lpuk {k= dh xfrfof/k;k

i= lpuk dk;kZy; ¼ihvkbZch½

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों तथा उपलब्धियों से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। यह विभाग सरकार और मीडिया के बीच सेतु का काम करता है और मीडिया में दिख रही लोगों की प्रतिक्रियाओं पर सरकार को फीडबैक देता है।

1- ihvkbZch dk fotu

भारत की जनता को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में सूचना का प्रचार–प्रसार करना।

2- ihvkbZch dk dk;Z

पीआईबी सरकार और मीडिया के बीच सेतु का काम करता है। सरकार को मीडिया की आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से उपयुक्त संचार कार्यनीतियों के बारे में सरकार को परामर्श देता है। पत्र सूचना कार्यालय का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में मीडिया में दिख रही लोगों की धारणाओं के बारे में सरकार को सूचित करना है।

पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट्स, फ़ीचर लेख, पृष्ठभूमि, प्रेस ब्रीफिंग्स, साक्षात्कारों, संवाददाता सम्मेलनों और प्रेस दौरों आदि जैसे विविध साधनों के माध्यम से सूचना का प्रसार करता है। पीआईबी सूचना का प्रसार करने के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भी करता है। सूचना अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के साथ–साथ 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जारी की जाती है, जो देशभर के अखबारों और मीडिया संगठनों तक पहुंचती है।

पीआईबी में न्यूज़ रूम/न्यूज़ मॉनिटरिंग सेल है, जो सूचना के प्रसार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सालभर क्रियाशील रहता है।

पीआईबी मीडियाकर्मियों को प्रत्यायन की सुविधा भी उपलब्ध कराता है, ताकि वे सरकारी स्रोतों से सूचना प्राप्त करने के लिए उन तक पहुंच बना सकें।

3- lxBukRed <kpk

पीआईबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं कम्युनिकेशन) होते हैं। इसके अतिरिक्त ब्यूरो में महानिदेशक, अपर महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा मीडिया और कम्युनिकेशन अधिकारी तथा सूचना सहायक होते हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों में अधिकारियों के रैंक, मंत्रालय के आकार, महत्व और संवेदनशीलता को देखते हुए संबद्ध किए जाते हैं।

क्षेत्रीय मीडिया की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीआईबी के पांच ज़ोन हैं, जिनमें अपर महानिदेशक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व वाले 19 क्षेत्रीय कार्यालय और एक सूचना केंद्र सहित 17 शाखा कार्यालय शामिल हैं।

पूर्व केंद्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्री, श्रीमती स्मृति ईरानी 10 मई, 2018 को 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ

4- ihvkbZch dh ipkj l lcf/kr xfrfof/k;k

d- e=ky;k@foHkkxk dk ipkj %

पीआईबी के अधिकारी मंत्रालय/विभाग से संबद्ध होते हैं और वे उसके अधिकृत प्रवक्ता होते हैं। अधिकारी मंत्रालय/विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी मीडिया को देते हैं, सूचना का प्रसार करते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण देते हैं या गलतफहमियां दूर करते हैं। अधिकारी अख़बारों के संपादकीय, लेखों तथा टिप्पणियों में व्यक्त जन प्रतिक्रिया का विश्लेषण करते हैं, ताकि मंत्रालय/विभाग को लोगों की प्रतिक्रियाओं से अवगत कराया जा सके। पीआईबी के अधिकारी मंत्रालय/विभाग को मीडिया तथा आईईसी कार्यनीति के बारे में सलाह देते हैं।

पीआईबी के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय के अधिकारी मुख्यालय द्वारा जारी सूचना का प्रसार करने के अलावा अपने–अपने क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्रालयों या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण आयोजनों का प्रचार करते हैं। ये कार्यालय किसी क्षेत्र विशेष के लिए महत्वपूर्ण केंद्र सरकार के लक्षित प्रचार निर्णयों को भी सतत सूचना प्रसार के आधार पर लागू करते हैं। पीआईबी के स्थानीय/शाखा कार्यालय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों तथा सचिवों के क्षेत्र/राज्य के दौरों के अवसर पर भी मीडिया कवरेज सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सूचना का प्रसार करने के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए पीआईबी द्वारा निम्नलिखित संचार कार्यनीतियों का उपयोग किया जाता हैं :

1. संचार के परंपरागत स्वरूप, यानी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर संवाददाता सम्मेलन (वीडियो माध्यम सहित),
2. महत्वपूर्ण घोषणाओं और आयोजनों से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियां और फोटोज़ जारी करना। इनके बारे में मीडियाकर्मियों को एसएमएस अलर्ट, ट्वीट्स तथा फोन कॉल भी किए जाते हैं।
3. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर साक्षात्कार, विशेष चर्चाओं आदि का प्रबंध।
4. वेबसाइट्स पर नियमित रूप से जानकारी प्रदान करने के अलावा ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाइन जैसे नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग करना।
5. पीआईबी के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के अतिरिक्त प्रमुख भाषाओं– मलयालम, ओडिया, कन्नड़, तेलुगू, तमिल, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमी तथा बांग्ला में अखिल भारतीय कवरेज सुनिश्चित करना।
6. स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, आम बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (आईएफएफआई), राष्ट्रीय एकता दिवस, योग दिवस, स्वच्छ भारत सप्ताह आदि महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए प्रचार के विशेष प्रबंध किए जाते हैं।

असम के शहरी विकास मंत्री श्री पीजूष हजारिका क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो, गुवाहाटी द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में गुवाहाटी में 14 अगस्त, 2018 को आयोजित ''स्वच्छ भारत अभियान'' और ''साफ नीयत, सही विकास'' विषयों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए। महानिदेशक (मीडिया एवं संचार), पीआईबी, गुवाहाटी, श्री के. एस. धतवालिया भी इस अवसर पर मौजूद थे

7. अंग्रेजी और हिंदी में दैनिक मीडिया रिपोर्ट के रूप में मीडिया से मिले फीडबैक को प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजना, प्रत्येक मंत्रालय के अधिकारी द्वारा दैनिक मीडिया फीडबैक अपने मंत्रालय को भेजना संबंधित विशेष अवसरों पर विशेष फीडबैक सहित।
8. पीआईबी जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों सहित दुरस्थ क्षेत्रों में लोक सूचना अभियान (पीआईसी) के माध्यम से अंतिम छोर तक पहुंच बनाता है।

मीडिया उत्पाद/सेवा/माध्यम	संख्या (1 अप्रैल, 2018 से 25 फरवरी, 2019 के दौरान)
प्रेस विज्ञप्तियां	20901
फोटोग्राफ/इंफोग्राफिक्स	13479/92
मीडिया निमंत्रण	1015
औपचारिक संवाददाता सम्मेलन	93
वार्तालाप	59
राष्ट्रव्यापी मीडिया फीडबैक	दैनिक
विशिष्ट विषयों पर विश्लेषणात्मक मीडिया रिपोर्ट्स	दैनिक/साप्ताहिक

ट्वीट्स	80–100 प्रतिदिन
एसएमएस	मीडिया को बल्क एसएमएस
प्रेस प्रत्यायन कार्ड जारी करना	2553 (1 अप्रैल, 2018 से 25 फरवरी, 2019 के दौरान)

[k- ç/kkuea=h bdkbZ

प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए प्रचार और मीडिया समर्थन देने के लिए पीआईबी की यह एक समर्पित इकाई है। यह इकाई वर्ष पर्यन्त कार्य करती है और माननीय राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिवालय, नीति आयोग और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के भी प्रचार का दायित्व संभालती है।

यूनिट में निम्नलिखित प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं :

¼d½ QhMcSd

- दैनिक इंग्लिश मीडिया रिपोर्ट और हिंदी मीडिया रिपोर्ट सुबह तैयार की जाती है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रेस, दोनों को शामिल किया जाता है।
- दैनिक फ़ीडबैक रिपोर्ट सुबह 7.30 बजे तक प्रधानमंत्री आवास पहुंचा दी जाती है।
- संपादकीयों और ओप–एड्स (विशेष आलेख) के बारे में पीएमओ को दैनिक रिपोर्ट भेजी जाती है।
- दैनिक और साप्ताहिक उर्दू फीडबैक रिपोर्ट पीएमओ को भेजी जाती है।
- नीति आयोग को दैनिक फ़ीडबैक रिपोर्ट भेजी जाती है।
- पीएमओ और प्रधान महानिदेशक, पीआईबी को साप्ताहिक मैगज़ीन रिपोर्ट भेजी जाती है।
- प्रधानमंत्री के प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया फ़ीडबैक रिपोर्ट।
- प्रमुख कार्यक्रम या प्रधानमंत्री के प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बाद मीडिया फ़ीडबैक रिपोर्ट।
- प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की प्रेस कवरेज के विश्लेषण की रिपोर्ट।
- विभिन्न मामलों/कार्यक्रमों के बारे में पीएमओ/प्रधान महानिदेशक की आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय फ़ीडबैक रिपोर्ट्स।

¼[k½ vkfèkdkfjd dE;fudsku

- प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के दौरान प्रेस विज्ञप्तियां, यह इकाई विभिन्न टाइम ज़ोन्स से पृथक वास्तविक समय में सामग्री का प्रसार करती है।
- प्रधानमंत्री के आधिकारिक भाषण (पीएमओ के परामर्श से प्रतिलेखित, पुनरीक्षित और जारी)।
- पीआईबी के ट्विटर हैंडल पर पीएम की आधिकारिक फोटोग्राफ्स का प्रकाशन।
- 'मन की बात' का मूल पाठ हिंदी और अंग्रेजी, दोनों में जारी करना।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 जून, 2018 को चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, उत्तराखण्ड में देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में सामूहिक योग प्रदर्शन में भाग लिया

- राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी भाषणों सहित विज्ञप्तियां।
- कैबिनेट की प्रेस विज्ञप्तियों और कैबिनेट ब्रीफिंग के लिए मीडिया के साथ तालमेल।
- नीति आयोग के कार्यक्रमों की प्रेस विज्ञप्तियां और तस्वीरें जारी करना।

¼x½ vuqokn

- प्रधानमंत्री के भाषणों, प्रेस विज्ञप्तियों और फोटो अनुशीर्षकों का अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद।
- प्रधानमंत्री के भाषणों और संदेशों को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराने के लिए मानव संसाधन सहायता का प्रावधान है।
- पीआईबी के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के साथ समन्वय कर प्रधानमंत्री के ट्वीट, रचनाओं इत्यादि का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद

¼?k½ ehfM;k lqfoèkk

- प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के लिए अग्रिम सुरक्षा संपर्क (एएसएल) बैठकों में भाग लेना और मीडिया उपस्थिति के बारे में फैसला करना।
- प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए मीडिया प्रवेश पास हेतु दिल्ली पुलिस, पीएम सुरक्षा के साथ संपर्क।
- राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रमों के लिए मीडियाकर्मियों को पास बांटना।
- नीति आयोग के कार्यक्रमों के लिए मीडिया सुविधा।

¼M½ osclkbV vkSj vU; xfrfofèk;k

- प्रधानमंत्री इकाई नियमित रूप से विभिन्न अवसरों (उदाहरण के लिए एनडीए सरकार की प्रमुख पहलें, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2018, स्वाधीनता दिवस 2018 और राष्ट्रीय एकता दिवस) के लिए विशेष वेब पेज का डिजाइन एवं विषय–वस्तु का प्रबंधन करती है।

x- lks'ky ehfM;k izdks"B

सरकार से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते पीआईबी भारतीय और वैश्विक स्तर पर निरंतर बढ़ रहे ऑनलाइन नागरिक वर्ग के साथ संपर्क और संबंध बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है।

सोशल मीडिया पर पीआईबी की उपस्थिति ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर है। इनके अलावा पीआईबी एक ब्लॉग भी चलाता है। सरकार के सभी आधिकारिक फोटो, वीडियो और प्रेस विज्ञप्ति कई सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर साझा किए जाते हैं, जो प्रतिमाह 18 मिलियन से अधिक इंप्रेशन बनाते हैं। इनके अलावा, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया ब्रीफिंग को फेसबुक, ट्विटर और पीआईबी के यूट्यूब चैनल पर लाइव–ट्वीट और लाइव–स्ट्रीम किया जाता है, जिससे सरकार से संबंधित नए समाचार वास्तविक समय में ही प्रदान कर दिए जाते हैं। समाचार साझा करने के अलावा, पीआईबी सुशासन के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए सरकार की नीतियों और कार्यों के बारे में जागरुकता फैलाने और नागरिक सहभागिता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया अभियान चलाता है।

fVoVj % पीआईबी के मुख्य ट्विटर हैंडल @PIB_India को फॉलो करने वालों की संख्या 1.47 मिलियन है और इसमें हर महीने औसतन 12 हजार 500 (12.5 के) फॉलोअर्स की वृद्धि हो रही है।

पीआईबी तेजी के साथ नई विषय–वस्तु तथा प्रस्तुतिकरण के नए रूपों को अपना रहा है। नागरिकों तक पहुंचने और उन्हें साथ जोड़ने के लिए पीआईबी ट्विटर वीडियो, जी.आई.फ., सर्वेक्षणों तथा ट्विटर मूवमेंट जैसे उपायों को अपना रहा है।

@PIB_Hindi हैंडल को फॉलो करने वालों की संख्या 64 हजार 500 (64.5 के) है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया में क्षेत्रीय भाषाओं की संभावनाओं को देखते हुए पीआईबी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार से जुड़ी ख़बरों को क्षेत्रीय भाषाओं में साझा करना शुरू कर दिया है।

Qslcqd % वर्तमान वर्ष में पीआईबी के फेसबुक पेज के प्रशंसकों के आधार में फरवरी 2019 में 23 हजार, 600 (236 के) की वृद्धि हुई है। ऐसा कम्युनिकेशन और संपर्क के सृजनात्मक तरीकों को अपनाने से संभव हो सका है।

;wVîwc % पीआईबी के यूट्यूब चैनल पर 4,320 वीडियो, 27 मिलियन व्यूज़ तथा 31 हजार 700 (317 के) सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं। पीआईबी, नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलनों और अन्य आयोजनों के अतिरिक्त दिल्ली से बाहर होने वाले आयोजनों, जैसे– पीएम लाइव, विशेष सरकारी कार्यक्रमों आदि को भी अब चैनल पर लाइव दिखाया जाता है।

bULVkxzke % आकर्षक चित्र और लघु वीडियो पीआईबी के इंस्टाग्राम पर प्रकाशित किए गए हैं। फरवरी 2019 के आखिर तक पीआईबी के इंस्टाग्राम के लगभग 22,300 से ज्यादा फ़ॉलोअर्स हो चुके थे।

ihvkÃch Cy‚x % इस का इस्तेमाल सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में फीचर्स और सॉफ़्ट स्टोरीज़ साझा करने के लिए किया जाता है। अब तक 726 लेख प्रकाशित किए जा चुके हैं जिन्हें 56,700 ज्यादा पेज व्यू मिले हैं।

lk'ky ehfM;k fun'ku vkj leFku % पीआईबी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अपनी पहुंच होने के बावजूद उन्हें सोशल मीडिया अपनी उपस्थिति को बेहतर ढंग से स्थापित और व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान कर रहा है।

u, dne %

fefuLVj LihDl % मंत्रियों की ओर से पीआईबी को दिए गए विशेष बाइट्स।

bu gkml ikMD'ku % विविध मंत्रालयों के विविध कार्यक्रमों के विशेष वीडियो, जी.आई.फ. और चित्र।

ykbo ohfM;k ckbV l % पीआईबी भारत सरकार का अकेला ऐसा विभाग है, जो कार्यक्रमों के बाइट्स को लाइव प्रकाशित करता है।

u, vfHk;ku

#,f'k;kehfM;klfeV] #bVju'kuyMvkQ ;kxk] #c tV2019] #LoPNHkkjr] #jk"Vh;,drkfnol] #xk/kh150] #lcdh;ktuklcdkfodkl] #vkbvkb,l,Q 2018

?k- ehfM;k vkmVjhp dk;Øe vkj fo'k"k dk;Øeka dk fy, ipkj

मीडिया आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और जिला स्तरों पर मीडिया संपर्क सत्रों के आयोजन के द्वारा सरकार की प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में सूचना का प्रसार करना है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता दर्शाने के लिए प्रेस दौरों का भी आयोजन किया जाता है।

M- pukoka d nkjku lpuk dk çlkj

पीआईबी भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) तथा मीडिया के बीच सेतु का काम करता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद पीआईबी पिछले लोकसभा आम चुनावों तथा विधानसभा चुनावों की सूचना उपलब्ध कराने के लिए 'आम चुनावों के लिए संदर्भ पुस्तिका' तथा विधानसभा चुनावों पर पुस्तिकाएं जारी करता है। इसके अतिरिक्त चुनावों से पहले नियमित रूप से संदर्भों और तथ्यों के माध्यम से मीडिया को सूचना उपलब्ध कराई जाती है। लोकसभा के आम चुनावों तथा विभिन्न राज्य विधानसभाओं के चुनावों दौरान, मतदान और मतगणना प्रक्रिया की कवरेज में सहायता के लिए नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मीडिया के प्रतिनिधियों को पीआईबी भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकृत पत्र जारी करता है। तथा मतदान के गिनती वाले दिन अपनी विशेष वेबसाइट द्वारा रूझानों/परिमाणों की वस्तुस्थिति का भी प्रसार एन.आई.सी एवं भारत निवार्चन आयोग द्वारा प्राप्त काउंटिंग डाटा के अनुसार करता है।

5- QhMcd idk"B

पत्र सूचना कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में मीडिया में प्रदर्शित लोगों की धारणाओं से सरकार को अवगत कराना है। इस बारे में देश की राजधानी में प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी एवं हिंदी के समाचारों से, पीआईबी के स्थानीय/शाखा कार्यालयों से स्थानीय भाषा के समाचार–पत्रों से प्राप्त होने वाले व टीवी समाचार चैनलों, वेब मीडिया एवं पत्रिकाओं से इनपुट प्राप्त किए जाते हैं। पीआईबी अधिकारी इस फीडबैक को अपने संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों को भेजते हैं।

विशेष सेवाओं के भाग के रूप में पीआईबी का फीडबैक प्रकोष्ठ मंत्रालयों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय समाचार–पत्रों और पत्रिकाओं के आधार पर दैनिक सार–संक्षेप और विशेष सार–संक्षेप तैयार करता है। 1 अप्रैल से 27 फरवरी, 2019 तक लगभग 222 सार–संक्षेप और 55 स्पेशल सार–संक्षेप भेजे गए तथा प्रधानमंत्री कार्यालय व विभिन्न मंत्रालयों के विभागीय प्रचार अधिकारियों को लगभग 5,600 एसएमएस अलर्ट/मेल भेजे गए।

6- çsl lqfo/kk,a

1½ v,uykbu çR;k;u ç.kkyh

प्रेस और मीडियाकर्मियों को ऑनलाइन प्रत्यायन प्रदान करने की प्रणाली 2010 से शुरू की गई। ऑनलाइन प्रणाली को गतिशील और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली में निरंतर परिवर्तन शामिल किए गए। वर्ष के दौरान ब्यूरो ने ऑनलाइन प्रत्यायन की प्रक्रिया का उपयोग सफलतापूर्वक किया और प्रोसेसिंग तथा पत्रकारों को प्रेस प्रत्यायन काड्र्स जारी करने के लिए इस प्रणाली का अनुरक्षण एवं सेवा प्रदान करने का कार्य नेशनल इंफोमैटिक्स सिस्टम (एनआईसी) द्वारा किया गया।

2½ vkbZ,Q,QvkbZ] xksok esa ehfM;k dæ

पीआईबी ने गोवा में आईएफएफआई (भारत के अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह), 2018 में अंतरराष्ट्रीय समारोह के दौरान मीडियाकर्मियों को प्रत्यायन प्रदान करने और आईएफएफआई से संबंधित सूचनाओं का प्रसार करने के लिए मीडिया सुविधा केंद्र की स्थापना की। पीआईबी के मीडिया सेंटर ने इस आयोजन को कवर करने वाले पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को प्रेस किट्स, मीडिया प्रत्यायन पास और अन्य सेवाएं प्रदान कीं। इस आयोजन को कवर करने के लिए भारतीय और विदेशी मीडिया को पीआईबी प्रत्यायन प्रदान किए गए। पीआईबी की सोशल मीडिया टीम ने इस आयोजन को पूरी सहायता प्रदान की।

3½ i=dkj dY;k.k ;kstuk

पीआईबी 'पत्रकार कल्याण कोष' योजना का कार्यान्वयन करता आया है। संशोधित योजना में कठिनाइयों का सामना करने वाले पत्रकारों तथा उनके परिवारों को अविलंब अनुग्रह राहत उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत पत्रकार के लिए पांच लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत की जा सकती है। पत्रकार की मृत्यु के कारण परिवार को होने वाली परेशानी और पत्रकार की स्थायी अपंगता को देखते हुए उसके परिवार को राहत दी जा सकती है। कैंसर, गुर्दा रोग, हृदय रोग तथा ब्रेन हेमरेज आदि गंभीर बीमारियों में होने वाले खर्च में सहायता दी जाती है। दुर्घटना से गंभीर चोट तथा अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में भी वित्तीय सहायता दी जाती है। मामलों की प्रोसेसिंग पीआईबी द्वारा की जाती है और सिफारिशों को मंजूरी के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की उच्चस्तरीय समिति के पास भेजा जाता है। आलोच्य अवधि, यानी 01 अप्रैल, 2018 से अब तक मंत्रालय द्वारा पत्रकार कल्याण योजना के तहत 16 पत्रकारों को भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

7- vkikr fLFkfr;k esa fu;a=.k d{k

किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पीआईबी में एक न्यूज़ रूम/नियंत्रण कक्ष 365 दिन कार्य करता है। अल्प अवधि में संवाददाता सम्मेलन आयोजित करना और साथ–साथ पूरे देश में पीआईबी केंद्रों के माध्यम से वेबकास्ट की पूरी तैयारी रखी जाती है, ताकि रात्रि 9.00 बजे के बाद अप्रत्याशित स्थिति से निपटा जा सके। आपात और संकट के समय नियंत्रण कक्ष 24X7 आधार पर काम करता है। महत्वपूर्ण समाचार चैनलों की मॉनिटरिंग की जाती है और वरिष्ठ अधिकारियों को ताज़ा घटनाओं की जानकारी देने तथा तथ्य संबंधी गलतियों के बारे में सूचित किया जाता है, ताकि मीडिया में सही समय पर हस्तक्षेप किया जा सके।

8- 2018&19 dk nkjku mBk, x, dne

इस अवधि के दौरान पीआईबी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए:

क) सरकार की विभिन्न पहलों और उपलब्धियों पर इंफोग्राफिक्स विकसित किये गए हैं, जो संक्षिप्त और आकर्षक तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करते हैं। इन इंफोग्राफिक्स के लिए प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है, जो सामान्य व्याख्यान वाली विषयवस्तु के साथ जनता के औसत जुड़ाव की तुलना में इस विषयवस्तु के प्रति जनता की उच्च संबद्धता की दर से स्पष्ट हो जाता है।

ख) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संचार प्रभारी पीआईबी अधिकारियों ने आधिकारिक पीआईबी– अधिकृत ट्विटर हैंडल्स का उपयोग करते हुए आधिकारिक नवीनतम जानकारी साझा करना शुरू कर दिया है।

ग) पीआईबी मुख्यालय में आयोजित सभी प्रेस सम्मेलनों का अब फेसबुक, ट्विटर और पीआईबी के यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है।

पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) श्री सीतांशु आर. कार 31 अक्तूबर, 2018 को श्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में पीआईबी के अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ दिलाते हुए

घ) इंस्टाग्राम जैसे विभिन्न सोशल मीडिया एजेंसियों से संपर्क किया गया, ताकि हमारे अधिकारियों को प्रचार से संबंधित उद्देश्यों के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया का लाभ उठाने के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा सके।

9- dk;ky; dk Lopyu ;k vkWVkse'ku

पीआईबी ने कार्यालय के स्वचलन या ऑटोमेशन के लिए अनेक उपाय किए हैं, जैसे :

1. पीआईबी की बहुभाषी वेबसाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है और उसके एप को पत्रकारों के लिए एन्ड्रॉयड और आईओएस पर लॉन्च किया गया है।
2. पीआईबी के आईटी प्रचालनों के लिए मानव संसाधन (एचआर) सहायता की व्यवस्था की गई।
3. बेसिल के माध्यम से ग्राफिक्स और विश्लेषण, दोनों के लिए सोशल मीडिया आउटसोर्सिंग।
4. 1947 से 2003 तक की पुरानी प्रेस विज्ञप्तियों की डिजिटल आर्काइविंग।
5. पीआईबी के समस्त प्रचार अधिकारियों के लिए स्मार्ट डिवाइस की खरीद।
6. जीईएम पोर्टल के माध्यम से मदों की प्राप्ति।
7. पीआईबी मुख्यालय में ई–ऑफिस का कार्यान्वयन।
8. मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में उपकरणों को अद्यतन किया गया।

10- ihvkbZch dh 2018&19 dh çeq[k xfrfof/k;k

,½ vke ctV 2019&20

केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी, 2019 को संसद में वर्ष 2019–20 का अंतरिम बजट पेश किया। पीआईबी ने इसके लिए अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया था, जिन्होंने नॉर्थ ब्लॉक में विशेष रूप से बनाए गए अलग क्षेत्र में मौजूद रह कर प्रेस विज्ञप्तियां, इंफोग्राफिक्स और अन्य सोशल मीडिया उत्पाद तैयार किए। संसद में बजट भाषण समाप्त होते ही, पीआईबी टीम द्वारा तैयार की गई सभी प्रेस विज्ञप्तियां और इंफोग्राफिक्स तुरंत पीआईबी वेबसाइट पर अपलोड किए गए। वित्त मंत्री का बजट भाषण और संबंधित दस्तावेजों को भी पीआईबी वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

ch½ i;kxjkt e v)dqEHk 2019

अर्धकुंभ 2019 का पीआईबी की ओर से बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया। आवश्यक प्रचार संबंधी कार्य करने के लिए मुख्यालय से अधिकारियों की टीम को प्रयाग भेजा गया था। 25 फरवरी, 2019 तक 20 से अधिक प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं। कुंभ की गतिविधियों और विशेष कार्यक्रमों की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर जारी और अपलोड की गईं। प्रख्यात व्यक्तियों के ऑडियो और वीडियो बाइट्स अपलोड किए गए और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किए गए।

lh½ çoklh Hkkjrh; fnol

प्रवासी भारतीय दिवस 21 से 23 जनवरी, 2019 तक वाराणसी में मनाया गया। प्रेस विज्ञप्तियों, फोटो और विशेष इंफोग्राफिक्स के माध्यम से इस आयोजन को व्यापक कवरेज प्रदान की गई। प्रधानमंत्री द्वारा इस आयोजन के उद्घाटन और राष्ट्रपति द्वारा समापन सत्र के लिए व्यापक प्रचार की व्यवस्था की गई। युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन भी विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक रूप से कवर किया गया।

Mh½ jk"Vh; ,drk fnol& fo'o dh lcls Åph çfrek dk ykdki.k

जयंती स्मरणोत्सव और राष्ट्रीय एकता दिवस से संबंधित आयोजन को सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से व्यापक रूप से कवर और प्रचारित किया गया। मुख्य कार्यक्रम सरदार सरोवर नर्मदा बांध परियोजना में हुआ, जिसकी शोभा माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी उपस्थिति से बढ़ाई। 31 अक्तूबर, 2018 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा देशभर में किए गए आयोजनों का पीआईबी ने इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया। पीआईबी द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस पर एक विशेष वेब पेज तैयार किया गया। पीआईबी ने प्रचार के प्रभाव को बढ़ाने के लिए डीएवीपी, आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य मीडिया इकाइयों के साथ भी समन्वय किया।

उत्तराखंड में देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में 21 जून, 2018 को चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 2018 का एक दृश्य

b½ pkFkk vrjjk"Vh; ;kx fnol

देहरादून में 21 जून, 2018 को आयोजित चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईवाईडी) का राष्ट्रव्यापी प्रचार किया गया। इस आयोजन से पहले ही योग के बारे में बैकग्राउंडर ब्रीफिंग्स, टीज़र वीडियो, पुस्तिकाओं आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। आईवाईडी–2018 के बारे में मीडिया को जागरूक बनाने के लिए आयुष मंत्रालय और पीआईबी द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में स्वास्थ्य संपादकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन आयुष राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने किया। मीडिया को इस आयोजन को कवर करने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रेस विज्ञप्तियां और तस्वीरें भी पीआईबी वेबसाइट पर जारी किए गए।

,Q½ LoPNrk gh lok vfHk;ku

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 15 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2018 तक 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान का आयोजन किया। इस दौरान पूरे देश को स्वच्छता अपनाने और शौचालयों का निर्माण करने के लिए संघटित किया गया। पीआईबी ने इस पखवाड़े के दौरान 'स्वच्छता ही सेवा' से संबंधित गतिविधियों का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक प्रचार किया। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक ने भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी वरिष्ठ संपादकों/संवाददाताओं से इस अभियान पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया।

th½ i;Vu io

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पर्यटन मंत्रालय के 'पर्यटन पर्व' का उद्घाटन किया। पत्र सूचना कार्यालय ने 16 सितंबर–27 सितंबर, 2018 तक देशभर में 12 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम 'पर्यटन पर्व' (देखो अपना देश) के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक प्रचार किया। इस आयोजन के दौरान पांच प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं और क्षेत्रीय कार्यालयों के तालमेल से व्यापक मीडिया कवरेज सुनिश्चित की गई। इन गतिविधियों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया।

,p½ ijkØe io

देशभर में 28 सितंबर से 30 सितंबर, 2018 के दौरान आयोजित किए गए 'पराक्रम पर्व' को पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक रूप से प्रचारित किया गया। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक ने 25 सितंबर, 2018 को पीआईबी के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संबोधित किया, जिसमें सेना के पीआरओ कर्नल अमन आनंद ने भी भाग लिया। पीआईबी के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों से अपने क्षेत्र के रक्षा पीआरओ के साथ समन्वय करने और आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को उपयुक्त रूप से प्रचारित करने कहा गया।

लगभग 23 विज्ञप्तियां तथा फोटो प्रभाग और पीआईबी की इकाइयों द्वारा लिए गए फोटोग्राफ मुख्यालय और क्षेत्रों, दोनों स्थानों से जारी किए गए। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रेस क्लिपिंग्स और फोटोग्राफ्स के रूप में फीडबैक मंगवाया गया। ट्विटर पर लगभग 48 ट्वीट्स किए गए, जिन्हें क्षेत्रीय पीआईबी के हैंडल्स और पराक्रमपर्व द्वारा रिट्वीट किया गया, उन्होंने काफी ध्यान आकृष्ट किया।

vkb½ Hkkjr vrjjk"Vh; fQYe lekjkg dk 49ok lLdj.k vkb,Q,Qvkb 2018

भारत अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के 49वें संस्करण आईएफएफआई 2018 का आयोजन गोवा के पणजी में 20–28 नवंबर, 2018 को किया गया। पत्र सूचना कार्यालय मीडिया से तालमेल और प्रबंधन से संबद्ध रहा। आयोजन को कवर करने के लिए आने वाले मीडिया की सहायता के लिए समारोह स्थल पर पीआईबी द्वारा मीडिया सेंटर बनाया गया। मीडिया की सहायता के अंतर्गत समारोह के उद्घाटन और समापन कार्यक्रम तथा फ़िल्मों के पास का प्रावधान करना शामिल था। कुल 508 मीडियाकर्मियों को प्रत्यायन दिया गया। आईएफएफआई मीडिया सेंटर में पीआईबी द्वारा 30 संवाददाता सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें निदेशकों, निर्माताओं, अभिनेताओं, आईएफएफआई जूरी और अन्य फ़िल्मी हस्तियों ने मीडिया को संबोधित किया।

आईएफएफआई के अन्य कार्यक्रमों, जैसे– मास्टर क्लासेज, इन–कन्वर्सेशन सेशंस, रेड कार्पेट आयोजनों और प्रस्तुतियों की मीडिया कवरेज की गई। इस आयोजन के दौरान 82 प्रेस विज्ञप्तियां और 666 तस्वीरें जारी किए गए। पीआईबी द्वारा ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर व्यापक सोशल मीडिया कवरेज की गई, जिसमें संवाददाता सम्मेलनों, उद्घाटन और समापन समारोहों का सीधा प्रसारण, क्विज, वीडियो प्रोडक्शंस और बाइट्स, प्रोमोज़, ट्रेलर्स, इंफोग्राफिक्स और तस्वीरें शामिल थे।

t½ o"kkr lehkk

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विभागीय प्रचार अधिकारियों ने वर्ष 2018 के दौरान अपने–अपने मंत्रालयों/विभागों की पहलों और उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए 58 प्रेस विज्ञप्तियां जारी कीं और उन्हें पीआईबी के मुख्यालय और क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया।

d½ jktx ljdkj ds pkj o"kk iwj gku ds volj ij xfrfof/k;k

सरकार की पिछले चार वर्षों की उपलब्धियों, पहलों और

नीतियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए पीआईबी द्वारा बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी आउटरीच कार्यक्रम चलाया गया। क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों ने देशभर में लगभग 40 कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें शामिल हैं: –

1) क्षेत्र के वरिष्ठ संपादकों के साथ संवाद
2) रेडियो जॉकी के साथ संवाद
3) क्षेत्रीय मीडिया के साथ संवाददाता सम्मेलन

भारत के कई स्थानों पर केंद्रीय मंत्रियों द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित किए गए। इन आयोजनों की प्रेस विज्ञप्तियां और तस्वीरें पीआईबी द्वारा जारी किए गए।

vU; xfrfof/k;k

पीआईबी ने 19–25 नवंबर, 2018 को आयोजित 'कौमी एकता सप्ताह' और देशभर में 22 नवंबर, 2018 को आयोजित 'झंडा दिवस' और 'मन की बात' को भी सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर प्रचारित किया। पीआईबी ने भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में विभिन्न मंत्रालयों के मंडपों के उद्घाटन को भी व्यापक रूप से प्रचारित किया।

11- ;kstuk fu"iknu 2018&19

वर्ष 2018–19 के दौरान, पीआईबी केंद्रीय क्षेत्र की दो योजनाओं यथा (क) संचार एवं सूचना प्रचार–प्रसार का विकास (डीसीआईडी) और (ख) मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी) के साथ संबद्ध रहा।

2. केंद्रीय क्षेत्र की योजना यथा– मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी) के अंतर्गत पीआईबी निम्नलिखित उपयोजनाओं का अनुसरण कर रहा है :

   (1) पीआईबी का आधुनिकीकरण

   (2) स्वच्छता कार्ययोजना (एसएपी)

   (3) सोशल मीडिया हब की स्थापना

3. वर्ष 2018–19 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 10.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। पीआईबी की निम्नलिखित उपयोजनाओं के लिए 10.00 करोड़ रुपये की राशि का वितरण इस प्रकार रहा :

   (1) पीआईबी का आधुनिकीकरण : 3.80 करोड़ रुपये
   (2) स्वच्छता कार्ययोजना (एसएपी) : 1.20 करोड़ रुपये
   (3) सोशल मीडिया हब की स्थापना : 5.00 करोड़ रुपये

   dqy% 10-00 djksM+ #i;s

4. इस योजना का उद्देश्य पीआईबी में संचार और सूचना प्रसार–प्रचार प्रणालियों को आधुनिक और अद्यतन बनाना है, ताकि आधुनिक प्रौद्योगिकी का पूर्णतया उपयोग किया जा सके और पीआईबी की दक्षता मुख्यालयों और उसके क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों, दोनों स्थानों पर निम्नलिखित गतिविधियों के लिए बढ़ाई जा सके :–

   क) सभी अधिकारियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बुनियादी ढांचा और संचार के आधुनिक साधन
      - उपभोग्य सामग्रियों की खरीद
      - एएमसी शुल्क
      - रंगीन बहु–उद्देश्यीय डिजिटल कार्यालय मशीनों की खरीद
      - हार्डवेयर और अन्य उपकरणों की खरीद
      - इंटरनेट डोंगल कनेक्शंस के लिए भुगतान
      - लैन नेटवर्किंग आदि
      - फीडबैक और प्रभाव विश्लेषण; दैनिक रिपोर्ट्स

   ख) सभी कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करना

   ग) पीआईबी के शाखा कार्यालयों में लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा प्रदान करना

   घ) पीआईबी कार्यालयों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की स्थापना और मानव संसाधन उपलब्ध कराना

5. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 25 सितंबर, .2018 के अपने पत्र के जरिए आईटी पेशेवरों की अधिक संख्या को काम पर रखने और एएमसी के लिए दोबारा निविदा और नवीकरण करने जैसी अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट अनुमान 2018–19 में 'सोशल मीडिया हब की स्थापना' उप–योजना के लिए आवंटित निधियों को 'पीआईबी का आधुनिकीकरण करने' संबंधी उपयोजना के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए 50 लाख रुपये की निधियों के पुनः वितरण को मंजूरी देने की जानकारी दी।

6. जनवरी 2019 तक उप–योजना 'पीआईबी का आधुनिकीकरण करने' संबंधी उप–योजना के अंतर्गत 3.15 करोड़ रुपये की राशि प्रयोग की जा चुकी थी। उप–योजना ''स्वच्छता कार्ययोजना'' के तहत 31 जनवरी, 2019 तक 74.10 लाख रुपये की धनराशि उपयोग में लाई जा चुकी थी। 'सोशल मीडिया हब की स्थापना' उप–योजना के संबंध में यहां इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि चूंकि केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में सूचना के प्रवाह को सुगम बनाने हेतु ऑनलाइन डेटा की निगरानी करने के लिए सोशल मीडिया हब की स्थापना करने का प्रस्ताव वापस लिया जा चुका है, इसलिए 2018–19 के आरई प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय पीआईबी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को

4.50 करोड़ रुपये की धनराशि लौटा दी है। तदनुसार, 2018–19 के संशोधित अनुमानों में योजना के तहत पीआईबी प्रस्तावित जरूरत 5.50 करोड़ थी। (4.30 करोड़ रुपये की राशि 'पीआईबी के आधुनिकीकरण' के लिए और 1.20 करोड़ रुपये की राशि 'स्वच्छता कार्ययोजना' के लिए)। हालांकि, 2018–19 के संशोधित अनुमानों में निधियां आवंटित करते हुए, पीआईबी को 5.00 करोड़ रुपये की निधियां आवंटित की गई हैं (4.00 करोड़ रुपये की राशि 'पीआईबी के आधुनिकीकरण' के लिए और 1.00 करोड़ रुपये की राशि 'स्वच्छता कार्ययोजना' के लिए)।

7. केंद्रीय क्षेत्र की योजना यथा संचार एवं सूचना प्रचार–प्रसार का विकास (डीसीआईडी) के तहत पीआईबी के निम्नलिखित दो संघटक हैं:–

क) मीडिया आउटरीच कार्यक्रम

ख) आईएफएफआई एवं पीबीडी

¼1½ ehfM;k vkmVjhp dk;Øe

मीडिया आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और जिला स्तरों पर मीडिया संपर्क सत्रों के आयोजन द्वारा सरकार की प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में सूचना का प्रचार–प्रसार करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम की सफलता दर्शाने के लिए प्रेस दौरों का भी आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान कुल 4.99 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया, 4.60 करोड़ रुपये की राशि इस संघटक के लिए आवंटित की गई।

foÙk o"k 2018&19 d fy, ^ehfM;k vkmVjhp dk;Øe* d lc/k e okLrfod y{;k dh rqyuk e miyfC/k;k ¼31-01-2019 rd½

Øe la[;k	{k= dk uke	okrkyki		jk"Vh;@{k=h; lEesyu		ikl nkjs	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	सी. आर. भोपाल	14	9	–	–	1	–
2	एन. आर. चंडीगढ	10	6	–	–	–	–
3	एस. आर. चेन्नई	6	5	–	–	–	–
4	एन. ई. आर. गुवाहाटी	12	9	1	–	2	2
5	एस. सी. आर. हैदराबाद	7	5	–	–	1	–
6	ई. आर. कोलकाता	8	6	1	–	–	–
7	ई. सी. आर. लखनऊ	8	3	–	–	1	–
8	डब्ल्यू. आर. मुंबई	7	6	–	–	1	–
9	मुख्यालय	–	–	1	–	–	2
	कुल	72	49	3	–	6	4

(*) वार्तालाप का वास्तविक लक्ष्य, जैसा कि मंत्रालय को सूचित किया गया, केवल 60 है।

[k½ vkbZ,Q,QvkbZ ,oa ihchMh

इस योजना के अंतर्गत आईएफएफआई 2018 के आयोजन के लिए इस संघटक के तहत 39.00 लाख रुपये आवंटित किए गए थे। गोवा में नवंबर 2018 में इसका सफल आयोजन किया गया।

चालू वित्त वर्ष के दौरान बजट आवंटन, 31 जनवरी, .2019 तक हुआ खर्च और केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत 2018–19 का संशोधित अनुमान निम्नलिखित है :–

बीई 2018–19	499.00 लाख रुपये
आरई 2018–19	501.70 लाख रुपये
खर्च हुआ	349.89 लाख रुपये

ifjf'k"V&1

ctV d vkdM+s&2018&19

1 1. बी.ई. 2018–2019 (गैर–योजना) – 6935.00 लाख रु.

2. आर.ई. 2018–2019 (गैर–योजना) – 7543.21 लाख रु.

2. 1. बी.ई. 2018–2019 (योजना) – 1499.00 लाख रु.

2. आर.ई. 2018–2019(योजना) – 1001.70 लाख रु.

okLrfod [kpZ

3. 1. गैर–योजना – 6453.59 लाख रु. (जनवरी 2019 तक)

2. योजना – 739.34 लाख रु. (जनवरी 2019 तक)

ihvkbZch e[;ky; e jktHkk"kk fgnh dk çxkeh mi;kx

राजभाषा अधिनियम 1963 (1967 में यथा संशोधित) और राजभाषा नियम, 1976 (1987 में यथा संशोधित) के तहत वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों सहित राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों और निर्देशों का पालन करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय के मुख्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रगामी उपयोग की दिशा में हरसंभव प्रयास किए जाते हैं।

पीआईबी मुख्यालय में पीजीडी (एमएंडसी) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) का गठन किया गया है, जो तिमाही बैठकों के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति पर नजर रखती है। समिति की सभी बैठकें नियमित रूप से होती हैं और उनमें सामान्य और प्रधानमंत्री की विज्ञप्तियों, पीआईबी की वेबसाइट से संबंधित मामलों, ट्विटर, फेसबुक आदि जैसे सोशल मीडिया पर हिंदी का इस्तेमाल, हिंदी भाषा, टंकण एवं आशुलेखन का प्रशिक्षण, हिंदी के प्रगामी उपयोग के बारे में पीआईबी के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण जैसे मामलों पर चर्चा की जाती है। इन बैठकों में तिमाही रिपोर्ट्स की तुलनात्मक समीक्षा भी की जाती है। पीआईबी मुख्यालय के राजभाषा अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों का समय–समय पर दौरा किया जाता है और उन्हें राजभाषा नीति एवं नियमों की जानकारी दी जाती है और इन कार्यालयों में उनके कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाती है। पीआईबी की वेबसाइट द्विभाषिक (हिंदी एवं अंग्रेजी) रूप से उपलब्ध है।

इस ब्यूरो में 01–15 सितंबर, 2018 को हिंदी पखवाड़ा–2018 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान हिंदी निबंध लेखन, अनुवाद, टिप्पण और आलेखन, सामान्य हिंदी ज्ञान, हिंदी टंकण, हिंदी आशु लेखन और हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता जैसी विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में अधिकारियों/मुख्यालय के अधिकारियों ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया और विभिन्न पुरस्कार जीते। ब्यूरो में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान, डीजी (एमएंडसी) ने हिंदी पखवाड़ा प्रतियोगिताओं और साथ ही पीआईबी के कर्मचारियों को मूल रूप से हिंदी में अपना काम करने और अपने सभी आधिकारिक काम हिंदी में करना जारी के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कार्यान्वित की गई प्रोत्साहन योजना 2017–18 के विजेताओं को प्रमाण–पत्र प्रदान किए।

1- dsnh; iz'kklfud vf/kdj.k ¼dSV½ ds Qlyk@vkns'kk dk dk;kZUo;u

Øe la[;k	ehfM;k bdkb;k@ vuHkkx	o"kZ 2017&18 ds fy, dSV ls ikIr vkns'kks dh la[;k	o"kZ 2017&18 ds nkjku dk;kZfUor Qlyk@vkns'kks dh la[;k
1	2	3	4
1	पीआईबी (सतर्कता अनुभाग)	शून्य	शून्य

2- f'kdk;r fuokj.k ra=

श्री एस.एन. चौधरी, निदेशक (एमएंडसी), पीआईबी को कर्मचारी/सार्वजनिक शिकायत निवारण अधिकारी नामित किया गया है और इसके लिए प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का निपटान तय समय के भीतर किया गया है।

3- efgykvks ds dY;k.k ls lacaf/kr xfrfof/k;k

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों और नियमों, जिन्हें नियम–3सी के तहत सीसीएस (आचरण) नियम 1964 में शामिल किया जा चुका है, के अनुसार पीआईबी (मुख्यालयों) क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में महिला कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया गया है। हाल ही में पीआईबी (मुख्यालय) में आईसीसी का पुनर्गठन किया गया है। इस समिति की संरचना निम्नलिखित है :–

Øe la[;k	uke	in	nwjHkk"k
1	सुश्री श्रुति पाटिल, निदेशक	अध्यक्ष	दूरभाष : 23388517/23488364
2	सुश्री पुनीथा एस., उप निदेशक	सदस्य सचिव	दूरभाष : 23386977/23488050
3	रिक्त	पुरुष सदस्य	
4	सुश्री मधु बाला, अनुभाग अधिकारी	सदस्य	दूरभाष : 23385388

5	सुश्री सोनाली दत्ता, अनुभाग अधिकारी	सदस्य	दूरभाष : 23381137
6	सुश्री सुहासिनी धर्माहा, मनोचिकित्सक	बाहरी सदस्य	मोबाइल नंबर : 91–8826177144

lrdrk idk"B

¼1½ lxBu ds fy, e[;ky;k vkj 'kk[kk dk;ky;k LFkkfir lrdrk vuHkkxk dk fooj.k %

पीआईबी का सतर्कता ढांचा प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) की समग्र निगरानी में कार्य कर रहा है, जिन्हें सतर्कता अधिकारी (एडीजी/निदेशक के स्तर पर), उपनिदेशक (सतर्कता), और अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता प्राप्त है। सतर्कता मामलों के संबंध में प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख को भी सौंपे गए हैं। ब्यूरो के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के संबंध में सतर्कता के मामलों से निपटने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में एक प्रशासनिक अधिकारी का पद है, जो ऐसे मामलों से निपटने में क्षेत्रीय प्रमुखों को सहायता देता है। क्षेत्रीय कार्यालयों को समय–समय पर मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान किए जाते हैं।

¼2½ bl le;kof/k e dh xbl fuokjd lrdrk xfrfof/k;k

i) इस अवधि के दौरान किए गए सामान्य निरीक्षणों एवं औचक निरीक्षणों की संख्या– शून्य

¼3½ bl vof/k e dh xbl fuxjkuh ,o irk yxku lc/kh xfrfof/k;k%

1) fuxjkuh ds fy, fy, pu x, {k=k dk fooj.k %

ब्यूरो के ऐसे अनुभाग अर्थात सामान्य, प्रेस संपर्क अनुभाग, एनएमसी प्रकोष्ठ और स्वचलन अनुभाग सर्तकता के लिए निर्धारित हैं। इन अनुभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को संवेदनशील समझा जाता है। इन अनुभागों में कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों की समय–समय पर अदला–बदली की जाती है।

2) निगरानी में रखने के लिए चिन्हित किए गए व्यक्तियों की संख्या– शून्य

¼4½ nMkRed xfrfof/k;k [4¼1½ ls ¼x½ ds foijhr l[;k bfxr dh tk,xh] tgk fu;kDrk ikf/kdkjh jk"Vifr ds vykok dkbl vU; g] %

i) इस अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें/संदर्भ–06

ii) कितने मामलों में शुरुआती जांच की गई– शून्य

iii) कितने मामलों में शुरुआती जांच की रिपोर्ट प्राप्त हुई – शून्य

iv) कितने मामलों में बड़े जुर्माने के लिए आरोप पत्र जारी किए गए– शून्य

v) कितने मामलों में छोटे जुर्माने के लिए आरोप पत्र जारी किए गए– शून्य

vi) कितने लोगों पर बड़ा जुर्माना लगाया गया– शून्य

vii) कितने लोगों पर छोटा जुर्माना लगाया गया– शून्य

viii) कितने लोगों को निलंबित किया गया– शून्य

ix) कितने लोगों के खिलाफ़ प्रशासनिक कार्रवाई, मसलन – चेतावनी आदि जारी की गई– शून्य

x) नियम के उपयुक्त प्रावधानों के तहत कितने लोगों को समय से पहले सेवानिवृत्त किया गया– शून्य

इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि पहले प्राप्त की गई चार शिकायतों के संबंध में की जा रही विभागीय जांच अभी जारी है।

lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 ls lcf/kr ekey

पीआईबी का प्रशा.–1 अनुभाग पीआईबी (मुख्यालय) में आरटीआई से संबंधित मामलों के लिए नोडल अनुभाग नामित किया गया है। डीओपी एंड टी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, सीपीआईओ और अपीली प्राधिकरण को नागरिकों द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए नामित किया गया है।

पीआईबी (मुख्यालय) सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध जानकारी को स्व–प्रेरणा से उद्घाटित करने और उसे अपनी वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में अपलोड करने से संबंधित धारा–4 (बी)(1)और 4(2) के तहत अपने दायित्व पहले ही पूरे कर चुका है। प्राप्त किए गए, खारिज और हस्तांतरित किए गए आवेदनों/अपीलों के आंकड़े दर्शाने वाली तिमाही रिपोर्ट को सीआईसी की वेबसाइट पर नियमित रूप से आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर अपलोड किया जाता है।

fgnh rFkk mnl ;fuV dh xfrfof/k;k

हिंदी तथा उर्दू इकाइयों की मुख्य गतिविधियों में हिंदी/उर्दू दैनिकों के मुख्य समाचारों और संपादकीयों का अंग्रेजी

अनुवाद करने सहित दैनिक प्रेस राउंडअप तैयार करना, प्रेस विज्ञप्तियों, फ़ीचरों, संदर्भों, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री के भाषणों का हिंदी तथा उर्दू में अनुवाद करना, नियमावलियों और पुस्तिकाओं का अनुवाद एवं पुनरीक्षण करना शामिल है। हिंदी और उर्दू यूनिट द्वारा 1 अप्रैल, 2018 से 25 फरवरी, 2019 तक 11,552 प्रेस विज्ञप्तियां और संदर्भ हिंदी और उर्दू में जारी किए गए।

C;wjks vkWQ vkmVjhp ,.M dE;wfuds'ku ¼chvkslh½

ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) की स्थापना 8 दिसंबर, 2017 को पूर्ववर्ती विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) और गीत एवं ड्रामा प्रभाग (एस एंड डीडी) को राष्ट्रीय, मंडलीय, क्षेत्रीय और फील्ड स्तरों पर एकीकृत करके की गई थी और सरकार के आउटरीच संचार को सुचारु बनाने के लिए उन्हें बीओसी के अंतर्गत तीन अलग–अलग प्रभागों में रूपांतरित किया गया था, ताकि मीडिया में कवर नहीं होने वाले क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करके और प्रिंट मीडिया विज्ञापन, ऑडियो विजुअल विज्ञापन, आउटडोर प्रचार, प्रदर्शनियां, न्यू मीडिया आदि जैसे विविध संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए जनता के साथ उसको समझ में आने वाले स्वरूप और भाषा में संवाद करके जा सके।

बीओसी का विज्ञापन एवं दृश्य संचार प्रभाग (पूर्व डीएवीपी) बीओसी का नोडल प्रभाग है, जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) तथा स्वायत्त निकायों की ओर से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में संचार के विविध माध्यमों, जैसे–प्रिंट मीडिया विज्ञापन, ऑडियो–विजुअल विज्ञापन, मुद्रित प्रचार, प्रदर्शनियों, आउटडोर प्रचार, न्यू मीडिया तथा मासमेलिंग का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण तथा शहरी, दोनों आबादी को सूचित और शिक्षित करता है तथा उन्हें विकास गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है।

बीओसी का लोक संचार प्रभाग 'सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों का प्रचार–प्रसार करने के लिए नाटक, नृत्य–नाटक, मिश्रित कार्यक्रमों, कठपुतली, बैले, ओपरा, लोक और पारंपरिक गायन, पौराणिक गायन और अन्य स्थानीय लोक तथा पारंपरिक विधाओं जैसी विभिन्न प्रदर्शन कलाओं का इस्तेमाल करते हुए लाइव मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ अंतर्संवाद स्थापित करने में संलग्न है। प्रभाग का प्रमुख कार्य मनोरंजन के माध्यम से जन–सामान्य के बीच सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति जागरुकता और भावनात्मक संवेदनशीलता उत्पन्न करना है, जो राष्ट्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है।

बीओसी का क्षेत्रीय प्रचार प्रभाग जनता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से संबंधित भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए स्थानीय स्तर पर असर रखने वाले नेताओं और लक्षित लाभार्थियों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित करने, समूह चर्चा करने, घर–घर जाने, गांवों और अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से उनसे सीधे संवाद करने और अंतर्वैयक्तिक संचार कार्यक्रम संचालित करने के लिए अधिदेशित है। विभिन्न हितधारकों, यथा– राज्य सरकार और स्थानीय कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन आदि के समर्थन से विशेष आउटरीच कार्यक्रम (एसओपी) आयोजित किए जाते हैं। स्थानीय भाषा में और नजदीकी स्थानों पर आयोजित होने के कारण इन संचार कार्यक्रमों का प्रभाव सरकार की योजनाओं की बेहतर समझ को संभव बनाता है और व्यवहार में परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। इन प्रयासों को पारंपरिक और लोक मीडिया और अन्य पारंपरिक और गैर–पारंपरिक तरीकों के उपयोग से मदद मिलती है। एफसीडी के क्षेत्रीय अधिकारी कार्यान्वयन एजेंसियों के लाभ के लिए सरकार के कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में फीडबैक जुटाते हैं।

lxBukRed <kapk

ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसमें 23 क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो (आरओबी) और 148 फील्ड आउटरीच ब्यूरो (एफओबी) शामिल हैं।

बीओसी का नेतृत्व मुख्यालय में प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है, और 23 आरओबी की कमान अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी के हाथ होती है। 23 आरओबी को 5 जोन्स में विभाजित किया गया है, प्रत्येक मंडल का नेतृत्व महानिदेशक (मंडल) द्वारा किया जाता है।

2018&19 ds nkSjku çeq[k uhfrxr fu.kZ;@igy

सरकार ने प्रिंट मीडिया/समाचार–पत्रों में बीओसी के माध्यम से जारी होने वाले सरकारी विज्ञापनों की दरों में 25 प्रतिशत तक वृद्धि कर दी है। ये दरें 09 जनवरी, 2019 से कार्यान्वित हो चुकी हैं।

सरकार ने प्राइवेट सी एंड एस टीवी चैनलों में बीओसी के माध्यम से जारी होने वाले सरकारी विज्ञापनों की दरों में संशोधन किया है। ये दरें 25 जनवरी, 2019 से लागू हो चुकी हैं।

o"k d: ie[k vkd"k.k 2018

Øe l-	fo"k;	eghuk
1	गांधीजी की 150वीं जंयती का समारोह	अक्तूबर 2018
2	प्रदर्शनी ''बापू री–लिब्ङः, इन वर्ड डीड एंड एक्शन'' का राजीव चौक, नई दिल्ली में आयोजन	अक्तूबर 2018
3	प्रधानमंत्री को ''चैंपियन ऑफ अर्थ अवॉर्ड'' की सूचना	अक्तूबर 2018
4	पराक्रम पर्व	सितंबर 2018
5	रन फॉर यूनिटी	अक्तूबर 2018
6	भारत के संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर को श्रद्धांजलि	अप्रैल और दिसंबर 2018
7	भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि	दिसंबर 2018
8	आईएफएफआई, 2018	नवंबर 2018
9	साफ नीयत सही विकास	मई 2018

egRoi.k xfrfof/k;k¡

➢ xkekh th dh 150oE t;rh dk lekjkg

महात्मा गांधीजी की 150वीं जयंती मनाने के लिए सालभर के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई, जिनकी शुरुआत राजीव चौक नई दिल्ली में ''बापू री–लिब्ङः, इन वर्ड डीड एंड एक्शन'' विषय पर महात्मा गांधी के जीवन, कार्यों और मूल्यों पर केंद्रित छह दिवसीय मल्टी मीडिया प्रदर्शनी के आयोजन के साथ हुई। इन प्रदर्शनियों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के जरिए देश के युवाओं को महात्मा गांधी के साथ जोड़ने के लिए उनमें रुचि उत्पन्न करना है।

गोवा में आईएफएफआई के आयोजन के दौरान पणजी स्थित कला अकादमी 21–28 नवंबर, 2018 को ''महात्मा ऑन सेल्यूलॉयड'' विषय पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसमें सेल्यूलॉयड के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन और आदर्शों की कवरेज पर प्रकाश डाला गया। इस प्रदर्शनी ने प्रतिभागियों को फ़िल्मकारों की पीढ़ी और सेल्यूलॉयड उद्योग को प्रभावित करने वाली महात्मा गांधी की विरासत को समझने और सराहने का अभिनव अवसर प्रदान किया।

ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन आयोजित सभी प्रमुख कार्यक्रमों को **https://gandhi.gov.in** पर अपलोड किया गया है।

➢ i/kkue=h dk ^pfi;u vkQ vFk vokM^ dh lpuk

विश्व के पर्यावरण को बचाने में भारत के योगदान को स्वीकार करते हुए भारत के प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'चैंपियन ऑफ़ अर्थ अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया, पूरे देश में पर्यावरण बचाने की पहल के महत्व पर जोर देने के लिए दूर–दूर तक जिसका प्रचार–प्रसार किया गया। इस सम्मान को हाईलाइट करने के लिए देश के प्रमुख प्रकाशनों के पहले पन्ने पर इस बारे में पूरे पेज का विज्ञापन जारी किया गया।

➢ पराक्रम पर्व

भारतीय रक्षा बलों द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ का जश्न मनाने और भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी से लड़ने की भावना का सम्मान करने के लिए 28–30 सितंबर, 2018 को इंडिया गेट पर रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर "पराक्रम पर्व" का आयोजन किया गया। इस दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया –

1) इंडिया गेट लॉन पर कार्यक्रम : "जवानों" के प्रति देश की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, 29 और 30 सितंबर, 2018 को इंडिया गेट पर पराक्रम पर्व के अवसर पर निम्नलिखित कार्यक्रम किए गए :

   क) विज्ञापन का निर्माण और श्री प्रसून जोशी द्वारा रचित विशेष गान, जिसे श्री कैलाश खेर ने अपने सुरों से सजाया।

   ख) प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा संगीतमय प्रस्तुतियोंः क्रमशः 29 और 30 सितंबर, 2018 को श्री सुखविंदर सिंह और श्री कैलाश खेर ने प्रस्तुति दी।

महात्मा गांधी की 150वीं जन्मशती पर स्मरणोत्सव

पराक्रम पर्व के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रम

ग) पराक्रम पर्व का संदेश देश के कोने–कोने तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन के साथ समन्वय कर संगीत समारोह का सीधा प्रसारण किया गया।

घ) पराक्रम पर्व के संदेश वाली ब्रांडेड टी–शर्ट और टोपियां एनएसएस स्वयंसेवकों के बीच वितरित की गईं।

2) देशभर में कार्यक्रम : रक्षा बलों के साथ मिलकर देशभर के चिन्हित स्थानों पर तीन दिन के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

3) कार्यक्रम के लिए प्रचार : इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए देश के प्रमुख दैनिक समाचार–पत्रों में आधे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें देशवासियों से हमारे बहादुर सैनिकों की निडरता का अभिनंदन करने का अनुरोध किया गया था। 28 से 30 सितंबर, 2018 को इंडिया गेट लॉन में आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों का विवरण प्रदान करते हुए दिल्ली में एक विशेष आउटडोर कैंपेन भी चलाया गया।

➢ ju Qkj ;fuVh

राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के सम्मान में, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 31 अक्तूबर को नर्मदा नदी के तट पर दुनिया में उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित किए जाने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, देशभर के प्रमुख दैनिक समाचार–पत्रों में ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन द्वारा एक पूरे पेज का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया। प्रिंट मीडिया में किए गए प्रचार के अलावा टेलीविजन पर प्रचार तथा पूरे देश में होर्डिंग्स, बिल बोर्ड, पैनल आदि के माध्यम से 15 दिनों का बाह्य प्रचार आयोजित किया गया। इस उद्देश्य के लिए डिजिटल सिनेमा एजेंसियों (मूवी हॉल) के माध्यम से लोक सेवा विज्ञापन अभियान भी चलाया गया।

देश को एकजुट वाले लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्तूबर, 2018 को पूरे देश में "रन फॉर यूनिटी" का आयोजन किया गया। इस संबंध में 30 अक्तूबर, 2018 को प्रमुख दैनिक समाचार–पत्रों में एक चौथाई पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया, ताकि लोगों को अपने–अपने कस्बों और गांवों में आयोजित की जा रही रन फॉर यूनिटी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सरदार पटेल के जीवन पर प्रकाश डालने वाली पुस्तिका और एकता दिवस संकल्प की 30,000 प्रतियां वितरित की गईं।

➢ Hkkjr dk lafoèkku fuekZrk M,- ch- vkj- vacsMdj dks J)katfy

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 अप्रैल, 2018 को डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया। 13 अप्रैल, 2018 को अखिल भारतीय स्तर पर प्रिंट कैंपेन जारी कर जनता को इस स्मारक की विशेषताओं, इसके भीतर बने अत्याधुनिक संग्रहालय से अवगत कराया गया। इस संग्रहालय में आधुनिक तकनीक के माध्यम से डॉ. बी. आर. अंबेडकर के जीवन और कार्यों को दर्शाया गया है।

14 अप्रैल, 2018 और 6 दिसंबर, 2018 को डॉ. बी. आर. अंबेडकर की जयंती और पुण्यतिथि पर अखिल भारतीय प्रिंट कैंपेन भी जारी किए गए, जिसमें मजबूत, समृद्ध भारत के प्रति बाबासाहेब के विजन पर प्रकाश डाला गया।

➢ iwoZ iz/kkuea=h Hkkjr jRu Jh vVy fcgkjh oktis;h dks J)katfy

भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन और साथ ही साथ उनके 94वें जन्म दिवस पर समाचार–पत्रों में प्रचार के जरिए राष्ट्र ने उनके योगदान को याद किया।

भारत को एक आधुनिक राष्ट्र में परिवर्तित करने की दिशा में उनके द्वारा दिए गए व्यापक योगदान के सम्मान में बीओसी ने एक प्रिंट कैंपेन और एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और उपलब्धियों पर 25–27 दिसंबर, 2018 तक तीन दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया।

➢ vkbZ,Q,QvkbZ 2018

बीओसी ने भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (आईएफएफआई) 2018 की पूर्व सूचना के तौर पर विशाल आयोजन किया। इसके उद्घाटन से पहले देशभर में प्रमुख फ़िल्म प्रकाशनों में आधे पेज का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया। समाज में फ़िल्मों की भूमिका के बारे में जागरुकता का स्तर बढ़ाने के लिए विभिन्न शहरों में आउटडोर कैंपेन भी आयोजित किए गए।

➢ lkQ uh;r lgh fodkl

जनसाधारण में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए साफ नीयत सही विकास विषय पर प्रिंट, टीवी, रेडियो, ओपी में विशेष मल्टीमीडिया कैंपेन की संकल्पना की गई, इसकी योजना बनाई गई और इसे कार्यान्वित किया गया।

क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो की मदद से 11 विषयों पर मुद्रित सामग्री वितरित की गई, जिनमें विकास को सबसे गरीब तक

पहुंचाना, किसानों को सबसे पहले रखना, युवा शक्ति को उपयोग में लाना, सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, 125 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तेजी से विकास करना, भ्रष्टाचार मिटाना, विकास को बढ़ावा देना, ईमानदारी को स्थापित करना, पारदर्शिता बढ़ाना, स्वस्थ भारत का निर्माण करना, अनपेक्षित गति और पैमाने पर राष्ट्र की कायापलट करना, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के जरिए भारत की पूर्ण क्षमता को अनुभव करना और नए भारत के लिए नई अवसंरचना शामिल है।

➢ fo"k;&oLr| dk l'tu

बीओसी (पूर्ववर्ती डीएवीपी), अपने पैनल में शामिल श्रव्य–दृश्य निर्माताओं के माध्यम से बीओसी द्वारा स्वीकृत दरों पर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की ओर से विभिन्न भाषाओं में वृत्त चित्र फ़िल्मों, श्रव्य–दृश्य विज्ञापनों, विज्ञापन गीतों, प्रायोजित रेडियो कार्यक्रमों (एसआरपी) आदि जैसे श्रव्य–दृश्य निर्माण के कार्यों का निष्पादन करता है।

foŸk o"k 2018&19 d i e[k J0;&n'; fuek.k dk;

- पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संगठन (पीसीआरए) के लिए 'ऊर्जा एक आस' शीर्षक के एक ik;kf t r jfM;k dk;Øe ¼,lvkjih½ dh 9 dfM;k dk निर्माण किया गया है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए 'आधी आबादी पूरा सच' शीर्षक के एक ,lvkjih का भी निर्माण किया गया।
- oŸkfp= fQYe& वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान वस्त्र मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस–2018 के अवसर पर 'बुनकर मुद्रा योजना', 'बीमा योजना' और 'विविध योजनाओं के कार्यान्वयन की उपलब्धियों' पर फ़िल्में, एम्स के लिए 'जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन' पर फ़िल्म और पेंशन एवं पेंशनभागी कल्याण विभाग की ओर से 'जीवन प्रमाण' और 'संकल्प' पर फ़िल्मों का निर्माण कराया गया।
- J0;& n'; foKkiu@foKkiu xhr& गृह मंत्रालय के लिए 'साइबर अपराध' से संबंधित विषयों पर विज्ञापन गीत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के चलचित्र समारोह निदेशालय के लिए 'आसियान भारत फ़िल्म समारोह' पर रेडियो विज्ञापन और 'आईएफएफआई–2018' पर वीडियो विज्ञापन, एम्स के लिए 'स्वच्छता' पर वीडियो विज्ञापन, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (कारा) के लिए रेडियो विज्ञापन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 'फर्स्ट ऐड फॉर आई केयर ऑन एसिड बर्न्स' पर वीडियो विज्ञापन, आणविक ऊर्जा विभाग के लिए 'भोजन एवं कृषि' विषय पर वीडियो विज्ञापनों का निर्माण किया गया।

vkmVjhp l pkj

vity&fl rcj] 2018 dh vof/k d nkjku chvkslh u 229 in'kuh fnolk dk doj djr g], d y 44 in'kfu;k yxkbA bu in'kfu;k dk fooj.k fuEufyf[kr g %

in'kuh dk fo"k;	fnukd	LFkku
विधानसभा पुरस्कार	अप्रैल, 2018	गंगटोक, सिक्किम
''नया भारत–हम करके रहेंगे''	अप्रैल, 2018	शिलांग, मेघालय
''नया भारत–हम करके रहेंगे''	अप्रैल, 2018	चंडीगढ़ (संघ शासित प्रदेश)
राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार (बैकड्रॉप एंड सिनएज)	मई, 2018	विज्ञान भवन, नई दिल्ली
स्वच्छ भारत	जून, 2018	दादरी (उप्र), बादलपुर (उ.प्र.), छाचेड़ा (हरियाणा)
देश का बढ़ता जाता विश्वास, साफ नीयत सही विकास एवं तनाव प्रबंधन	जुलाई, 2018	सोनीपत (हरियाणा), नई दिल्ली
राज्य सभा, आजादी 70– याद करो कुर्बानी और देश का बढ़ता जाता विश्वास, साफ नीयत सही विकास	अगस्त, 2018	नई दिल्ली
देश का बढ़ता जाता विश्वास, साफ नीयत सही विकास	अगस्त, 2018	विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन (आंध्र प्रदेश), हैदराबाद (तेलंगाना), त्रिशूर और अंगमाली (केरल), रायपुर (छत्तीसगढ़), नागपुर (महाराष्ट्र), पटना (बिहार), ढेंकनाल (ओडिशा), यमुनानगर (हरियाणा), हमीरपुर (हिमाचल

		प्रदेश), गुवाहाटी (असम), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), रांची (झारखंड), जयपुर (राजस्थान), भोपाल (मध्य प्रदेश), अहमदाबाद (गुजरात)
देश का बढ़ता जाता विश्वास, साफ नीयत सही विकास	सितंबर, 2018	इंडिया गेट लॉन, राजपथ, नई दिल्ली
साफ नीयत सही विकास (पर्यटन पर्व 2018 में सहभागिता)	सितंबर, 2018	इंडिया गेट लॉन, राजपथ, नई दिल्ली
सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ –पराक्रम पर्व	सितंबर, 2018	इंडिया गेट लॉन, राजपथ, नई दिल्ली

QhYM lapkj ,oa vkmVjhp

बीओसी के फील्ड संचार प्रभाग ने इस अवधि के दौरान 668 विशेष आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन विशेष आउटरीच कार्यक्रमों (एसओपी) के विषय सरकार के चार साल– साफ नीयत सही विकास, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, स्वच्छता ही सेवा थे। इन कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित है :

➢ vkokl ,oa 'kgjh ekeyksa ds ea=ky; dh vksj ls LoPN Hkkjr fe'ku ¼'kgjh½ ds ckjs esa tkx#drk vfHk;ku

बीओसी के फील्ड संचार प्रभाग ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए 225 चिन्हित शहरों/नगर निगमों में सितंबर 2018 से 31 दिसंबर, 2018 तक आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से विशेष जागरुकता अभियान चलाया।

इस अभियान के दौरान देशभर में 1,000 विशेष आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नवंबर 2018 तक राज्यों और नगर निगमों में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) अधिकारियों के सहयोग से एसबीएम के बारे में 200 से ज्यादा एसओपी आयोजित किए गए।

➢ lhekorhZ {ks=h; çpkj xfrfof/k;k

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू–कश्मीर, मेघालय–मिजोरम–त्रिपुरा (एमएमटी), नगालैंड तथा मणिपुर, उत्तर–पश्चिम (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश), राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल (उत्तर) तथा सिक्किम और पश्चिम बंगाल (दक्षिण) के क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो के तहत फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा सीमावर्ती इलाकों में प्रचार अभियान चलाए गए। इन इकाइयों ने सीमावर्ती गांवों को भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही योजनाओं के बारे में बताया। राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया।

➢ okeiaFkh mxzokn çHkkfor {ks=ksa esa çpkj

फील्ड आउटरीच ब्यूरो के तहत vka/kz çns'k] fcgkj] NÙkhlx<+] >kj[kaM] egkjk"Vª e/; çns'k] vksfM'kk] mÙkj çns'k] if'pe caxky (दक्षिण) के फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भारत सरकार के सभी प्रमुख कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए प्रचार अभियान चलाया गया।

➢ नवंबर 2018 तक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बीओसी के फील्ड आउटरीच ब्यूरो (एफओबी) द्वारा एसओपी के अलावा 284 नियमित जागरुकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिनमें 421 फ़िल्म शो, 1011 मौखिक संचार कार्यक्रम, 600 फोटो प्रदर्शनियां शामिल थीं और लक्षित दर्शकों से 102 फीडबैक एकत्र किए गए।

miyfC/k;ka % vçSy ls uoacj 2018

1	आयोजित किए गए फ़िल्म शो की संख्या	5,273
2	आयोजित की गई समूह चर्चाओं की संख्या	9,554
3	आयोजित की गई फोटो प्रदर्शनियों की संख्या	6,164
	dqy xfrfof/k;ka	20]991
4	एकत्र की गई फीडबैक कहानियों की संख्या	2,793
5	कवर किए गए गांवों की संख्या	7,583
6	कुल दर्शकों तक पहुंच बनाई गई	29,20,506

ykd lapkj

बीओसी के लोक संचार प्रभाग ने इस अवधि के दौरान देशभर में 4,670 कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रमों की प्रस्तुति के दौरान व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए सरकार की निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों पर विशेष तौर पर रोशनी डाली गई : ^^LoPN Hkkjr fe'ku &¼,d dne LoPNrk dh vksj½^^] ^^,d Hkkjr&Js"B Hkkjr^^] ^^iz/kkuea=h tu /ku ;kstuk^^] ^^u;k Hkkjr ge djsaxs^^] ^^ladYi ioZ^^] ^^LoPNrk i[kokM+k^^] ^^vVy

i'ku ;kstuk^] ^fe'ku bUn/kuq"k^] ^iz/kkuea=h lqj{kk chek ;kstuk^] ^iz/kkuea=h thou T;ksfr chek ;kstuk^] ^lcdk lkFk lcdk fodkl^] ^csVh cpkvks&csVh i<kvks^] ^iz/kkuea=h Qly chek ;kstuk^] ^i;ZVu dks ikSRlkgu^ vkfnA

bl vof/k ds nkSjku okeiFkh mxzokn çHkkfor ftyksa esa ykbZo lapkj iHkkx ds ek/;e ls izLrqr fd, x, fo'ks"k dk;ZØe gSa %

Øe la-	jkT;	vizSy&uoEcj] 2018 ds nkSjku dk;kZfUor fd, x, dk;ZØeksa dh la[;k	doj fd, x, fo"k;
1	छत्तीसगढ़	226	कार्यक्रमों की प्रस्तुति के दौरान व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए सरकार की निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों पर विशेष तौर पर रोशनी डाली गई : ^LoPN Hkkjr fe'ku &¼,d dne LoPNrk dh vksj½^] ^,d Hkkjr&Js"B Hkkjr^] ^LoPNrk i[kokMk^] ^vVy isa'ku ;kstuk^] ^fe'ku bUn/kuq"k^] ^iz/kkuea=h lqj{kk chek ;kstuk^] ^lcdk lkFk lcdk fodkl^] ^csVh cpkvks&csVh i<kvks^ vkfnA संदर्भाधीन अवधि के दौरान उपरोक्त के अलावा, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, भाषाई सद्भाव; कुपोषण के खिलाफ प्रचार कार्यक्रमों पर भी विशेष ध्यान दिया गया।
2	मध्य प्रदेश	12	
3	महाराष्ट्र	38	
4	ओडिशा	217	
5	केरल	07	
6	उत्तर प्रदेश	94	
7	पश्चिम बंगाल	05	
8	झारखंड	508	
9	बिहार	165	
10	आंध्र प्रदेश	25	
11	तेलंगाना	56	
	कुल	1,353	

- देशभर में सरकार की स्वच्छ भारत मिशन – (एक कदम स्वच्छता की ओर) की अवधारणाओं पर रोशनी डालते हुए 709 कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्वच्छता पखवाड़ा (01.07.2018 से 15.07.2018) के आयोजन के दौरान लगभग 150 कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 9 (नौ) विशेष कार्यक्रम दिल्ली में कार्यान्वित किए गए।

- विभाग के कलाकारों की सेवाओं का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में 02.08.2018, 08.08.2018 और 09.08.2018 को भारत के स्वाधीनता संग्राम, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्र गान, भाषायी सद्भाव आदि पर रोशनी डालने वाले विशेष संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और माननीय सांसदगण एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रजत जयंती समारोह के दौरान 6 (छह) संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इनमें से 3 (तीन) कार्यक्रम 01.10.2018 को, 1 (एक) 04.10.2018 और 1 (एक) 09.10.2018 को प्रस्तुत किया गया तथा 12.10.2018 को 1 (एक) विशेष संगीत कार्यक्रम देशभक्ति के गीत, राष्ट्रीय एकता और हिंदी भाषा के राजभाषा के रूप में कार्यान्वयन के संबंध में बीओसी (एस एंड डीडी) के कलाकारों द्वारा संसद भवन, नई दिल्ली में प्रस्तुत किया गया। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और माननीय सांसदगण एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

vU; ea=ky;ksa dh vksj ls lapkj dk izpkj izlkj

➢ चालू वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान अब तक विभिन्न मंत्रालयों की ओर से कुछ बड़े प्रचार अभियान आयोजित किए गए हैं :

e=kly;	fiV	,ih	vkih	ih,elh	,u,e
वित्त	आईटीआर दाखिल करना, टीडीएस विवरण दाखिल करना, अग्रिम कर, जानिए नकद लेन–देन को कब न कहना है, जीएसटी के एक साल का जश्न, मुनाफाखोरी विरोधी, कारोबार करने की सुगमता, क्या आप जानते हैं–जीएसटी के लाभ, ई–वे बिल्स, जीएसटी रिटर्न के बारे में सूचना संबंधी जागरुकता, अटल पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना	आयकर रिटर्न, पीएफआरडीए	वस्तु एवं सेवा कर–जीएसटी के तहत ई–वे बिल सिस्टम और विशिष्टता, कस्टम्स के लाभ		आयकर आईटी रिटर्न, अग्रिम कर नियत तिथि
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	राष्ट्रीय वयोश्री योजना, सामाजिक अधिकारिता शिविर, बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि				
विद्युत	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना –न्यू इंडिया रोशन इंडिया, सौभाग्य–प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना	प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)	प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), ऊर्जा दक्षता आयोग (बी.ई.ई)		बी.ई.ई., बी.ई.ई. पोंटिग प्रतियोगिता और बी.ई.ई.– 24 डिग्री
पर्यटन	राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार, पर्यटन पर्व	भारत पर्व		सामाजिक संदेश	सामाजिक संदेश, भारत पर्व और डिजिटल कैलेंडर
विधि एवं न्याय	ई–कोर्ट्स, न्याय मित्र				
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	सक्षम राष्ट्रीय प्रतियोगिता–2018, नौवीं सीजीडी बोली उद्घाटन समारोह				पीसीआरए
महिला एवं बाल विकास	पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण मिशन	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान और पोषण मिशन	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और राष्ट्रीय पोषण मिशन	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कारा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, परिवार नियोजन, डेंगू और मलेरिया से बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष	प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, स्तनपान, खसरा–रुबेला टीकाकरण, राष्ट्रीय पोषण मिशन, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम,	प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए), मिशन इंद्रधनुष, तपेदिक जागरुकता, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, (आयुष्मान भारत) राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण, निःशुल्क औषधि एवं निदान, राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम	आयुष्मान भारत, एएनईएमआईए, मिशन इंद्रधनुष, नाको, तपेदिक जागरुकता नाको कुष्ठ रोग, जनसंख्या स्थिरता कोष
आयुष	अंतरराष्ट्रीय योग दिवस–2018	अंतरराष्ट्रीय योग दिवस	अंतरराष्ट्रीय योग दिवस		अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
कृषि एवं किसान कल्याण	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम–एएएसएचए), न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), कृषि कल्याण अभियान	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	प्रमुख योजनाएं और डीएमआई योजना		कृषि कल्याण अभियान
संचार			डिजिटल तरीके से भुगतान, जीवन बीमा, डिजिटल इंडिया, बीडी एवं एमडी तथा डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन		डिजिटल तरीके से भुगतान को प्रोत्साहन और डाक जीवन बीमा
उपभोक्ता मामले			सामाजिक संदेश	सामाजिक संदेश	भारतीय मानक ब्यूरो
श्रम एवं रोज़गार			बाल श्रम उन्मूलन		
पर्यावरण एवं वन			विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून)		विश्व पर्यावरण दिवस, ग्रीन गुड्स डीड्स
पेयजल एवं स्वच्छता		स्वच्छ भारत मिशन	दरवाजा बंद (स्वच्छ भारत)		
लघु एवं सूक्ष्म उद्योग			राष्ट्रीय एससी एसटी केंद्र (एनएसआईसी)		

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी		यूआईडीएआई – आधार, भीम एप्प, उमंग एप्प	यूआईडीएआई		
अल्पसंख्यक कार्य			हुनर हाट		
शिपिंग एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग			सड़क सुरक्षा		
खेल एवं युवा मामले		खेलो इंडिया, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल	खेलो इंडिया		
कौशल विकास एवं उद्यमिता			कौशल विकास (एनएसडीसी)		
रक्षा		इंडियन नेवी इमेज प्रोजेक्शन			भारतीय नौ सेना
गृह		साइबर अपराध, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)			आरजीआई
पंचायती राज		ग्राम स्वराज अभियान एवं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस			
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी					राष्ट्रीय नवाचार प्रतिष्ठान
शहरी विकास					शहरी विकास
नीति आयोग					यूआईडीएआई

efnzr lkfgR; dk tfj, lapkj

मुद्रित प्रचार (पीपी) प्रकोष्ठ बीओसी द्वारा लॉन्च किए गए अभियानों के व्यापक प्रचार के लिए मुद्रित सामग्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह प्रकोष्ठ बहुरंगी पोस्टरों, कैलेंडरों, डायरियों, ब्रोशर, फोल्डरों, टेबल कैलेंडरों तथा अन्य सामग्री, वॉल हैंगरों, स्टीकरों के मुद्रण कार्यों की आयोजना, निर्माण और निगरानी का कार्य करता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए प्रिंट कार्यों के योजना अनुमान जरूरत के मुताबिक और आवंटित बजट के आधार पर किए जाते हैं।

बीओसी सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, बंगाली, असमिया, उड़िया, पंजाबी, उर्दू और हिंदी में मुद्रित प्रचार सामग्री तैयार करता है। इस प्रकोष्ठ में मुद्रकों, टाइपसेटर्स तथा डायरी बनाने वालों का पैनल है, ताकि कम–से–कम संभव समय में कार्य पूरा किया जा सके और अधिक लागत पर नियंत्रण रखा जा सके।

मुद्रित प्रचार प्रकोष्ठ ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा विभिन्न ग्राहक मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए के हर प्रकार के प्रचार के 60 आइटम्स के 1,29,77,750 करोड़ कॉपियों वाले 19 कार्यों को पूरा किया।

मास मेलिंग

मास मेलिंग विंग प्रधानमंत्री के भाषणों सहित विभिन्न ग्राहक मंत्रालयों/विभागों तथा संगठनों की ओर से बुकलेट्स, फोल्डर्स, पोस्टर्स, पुस्तिकाएं, ब्रोशर आदि मुद्रित प्रचार सामग्रियों को प्राप्त करता है। इस मुद्रित सामग्री का वितरण ग्राहक विभागों के निर्देशों के आधार पर या प्रचार निर्देशों/आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष कैलेंडर, डायरियों का प्रकाशन कराया जाता है, ताकि उनका सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तथा सभी मंत्रालयों और उनके संबद्ध कार्यालयों के वीआईपी जैसी श्रेणियों में निःशुल्क वितरण कराया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के लिए यह वितरण भुगतान के आधार पर किया जाता है।

वर्तमान में इस मास मेलिंग विंग में 5,57,108 पतों का संग्रह है। ये पते 501 से अधिक श्रेणियों में फैले हैं। चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के कायापलट (बुकलेट, समग्र–सही नीयत सही विकास, किट फोल्डर–सही नीयत सही विकास), यूजीसी–रैगिंग विरोधी पोस्टर, हिंदी हैंगर–अपील, महिलाओं का अधिकार, भारतीय नौसेना के लिए सीएससी फ्लेक्स बैनर, पराक्रम पर्व, जन कनेक्ट बुकलेट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह–2018 जैसे विभिन्न विषयों पर मुद्रित सामग्री की 1,09,03,925 प्रतियां वितरित/प्रेषित की गई हैं।

लेखा

बीओसी का लेखा प्रकोष्ठ प्रत्येक वर्ष लगभग 950 से 1000 करोड़ रुपये के भुगतान का निष्पादन करता है। अपने बजट के अतिरिक्त बीओसी अपने सभी ग्राहकों, स्वायत्त संस्थानों, विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से निधियां प्राप्त करता है और उचित जांच के बाद कार्य आदेश के अनुसार और मीडिया संगठनों यथा समाचार–पत्रों, आउटडोर प्रचार एजेंसियों, रेडियो चैनलों, टीवी चैनलों, प्रोडक्शन घरानों और तथा बीओसी के पैनल में शामिल एजेंसियों तक डिलीवरी का प्रमाण मिलने के बाद इन निधियों को व्यय करता है। बीओसी द्वारा उनको जारी किए गए रिलीज ऑर्डर में निर्धारित पूर्व शर्तो के अनुसार विज्ञापन के प्रकाशन या प्रसारण के प्रमाणन के बाद भुगतान होता है। लेखा स्कंध की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

1. संगठन तथा ग्राहक मंत्रालयों प्राधिकार पत्रों से संबंधित सभी बिलों की पीएफएमएस के माध्यम से सफल प्रोसेसिंग की जाती है तथा भुगतानों को तीव्र और सुचारु बनाया गया है।
2. प्रोसेसिंग तथा बिलों के भुगतान दोनों की जानकारी वेबसाइट से ली जा सकती है और इस बारे में विवरण एजेंसियों के लॉगिन क्षेत्र में विवरण प्रदान किया गया है। इससे एजेंसियों के बिलों की स्थिति के बारे में पारदर्शिता आती है, विशेषकर इससे पता चल सकता है कि क्या वे किसी कारण से अस्वीकार या पास कर दिए गए हैं या वे किस स्तर पर हैं।
3. चाहे किसी भी तरह का कार्य/प्रचार हो, सभी एजेंसियों का 100 प्रतिशत भुगतान इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी/आरटीजीएस) के माध्यम से फौरन किया जाता है और इस तरह भुगतान में विलंब होने और डाक द्वारा भेजे जाने पर चेक गुम होने की आशंका खत्म हो जाती है।
4. बिल की प्रॉसेसिंग का सफल कार्यान्वयन हितधारकों को पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान के दोषमुक्त साधन के लिए नई शुरू की गई 'वेब सेवाओं' के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में यह मॉड्यूल योजना और गैर–योजना, दोनों के लिए काम कर रहा है। एलओए के लिए वेब सेवाएं विकसित करने का कार्य जारी है।
5. वर्ष 2018–19 में 3 इकाइयों यथा डीएवीपी, एस एंडडीडी और डीएफपी को बीओसी में एकीकृत किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय 23 क्षेत्रों में क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो (आरओबी) के रूप में प्रारंभ हो गए हैं। सभी आरओबी में पृथक पीएफएमएस लेखे हैं और बीओसी (मुख्यालय) द्वारा खर्च 23 क्षेत्रों में सम्मिलित रूप से बरकरार रखा जाता है।
6. भुगतान और बिल की स्थिति के विवरण बेहतर पारदर्शिता के लिए एजेंसी के लॉग इन में उपलब्ध कराए गए हैं। भुगतान एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से किए जाते हैं।

सतर्कता

(1) संगठन का मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता की व्यवस्था का विवरण

बीओसी के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में संपूर्ण सतर्कता अनुभाग है। मुख्यालयों और क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो (आरओबी) के सतर्कता से संबंधित समस्त मामलों को सतर्कता अनुभाग द्वारा वरीयता क्रम, जैसे– एसओ, उप निदेशक, निदेशक (सतर्कता) और एडीजी (सतर्कता) द्वारा प्रोसेस किया जाता है और/या उनकी निगरानी की जाती है। सतर्कता अनुभाग डीजी, बीओसी के समग्र निरीक्षण के तहत कार्य करता है।

(2) इस समयावधि में की गई निवारक सतर्कता गतिविधियां

i) इस अवधि के दौरान किए गए सामान्य निरीक्षणों की संख्या– शून्य

ii) इस अवधि के दौरान किए गए औचक निरीक्षणों की संख्या–शून्य

¼3½ bl vof/k e dh xb fuxjkuh ,o irk yxku dh xfrfof/k;k

i) निगरानी के लिए लिए चुने गए क्षेत्रों का विवरण – शून्य

ii) निगरानी में रखने के लिए चिन्हित किए गए व्यक्तियों की संख्या– शून्य

¼4½ nMkRed xfrfof/k;k [4¼1½ l ¼x½ d foijhr l[;k bfxr dh tk,xh] tgk fu;kDrk ikf/kdkjh jk"Vifr d vykok dkbl vU; g]

i) इस अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें/संदर्भ– 01

ii) कितने मामलों में शुरुआती जांच की गई– शून्य

iii) कितने मामलों में शुरुआती जांच की रिपोर्ट प्राप्त हुई– शून्य

iv) कितने मामलों में बड़े जुर्माने के लिए आरोप पत्र जारी किए गए– शून्य

v) कितने मामलों में छोटे जुर्माने के लिए आरोप पत्र जारी किए गए– शून्य

vi) कितने लोगों पर बड़ा जुर्माना लगाया गया– शून्य

vii) कितने लोगों पर छोटा जुर्माना लगाया गया– शून्य

viii) कितने लोगों को निलंबित किया गया–शून्य

ix) कितने लोगों के ख़िलाफ़ प्रशासनिक कार्रवाई, मसलन– चेतावनी आदि जारी की गई– शून्य

x) नियम के उपयुक्त प्रावधानों के तहत कितने लोगों को समय से पहले सेवानिवृत्त किया गया– शून्य

i'kklu

बीओसी के सामान्य प्रशासन प्रकोष्ठ ने आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण और ई–कॉमर्स के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. इस ब्यूरो के कार्य पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत हैं। पूर्ववर्ती डीएवीपी की एक आईटी और आधुनिकीकरण परियोजना पर विचार चल रहा है और इसे अंतिम रूप देते ही पूर्ववर्ती डीएवीपी के समस्त आईटी और सॉफ्टवेयर कार्य अलग–अलग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के माध्यम से अद्यतन हो जाएंगे।

2. सरकार के ई–कॉमर्स पोर्टल अर्थात गवर्मेंट ई–मार्केट प्लेस (जीईएम) को पूरी तरह से बीओसी में लागू किया गया है और बीओसी पोर्टल पर उपलब्ध ज्यादातर उत्पाद केवल बीओसी पोर्टल के माध्यम से खरीदे जाते हैं।

3. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त बिंदुओं पर बीओसी द्वारा की गई कार्रवाई के अलावा, इस ब्यूरो में 15 सितंबर से 2 अक्तूबर 2018 तक स्वच्छता पखवाड़ा भी बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। सूचना भवन परिसर के आसपास और उसके नजदीकी क्षेत्रों, जैसे – केंद्रीय विद्यालय, प्रगति विहार और मेहर चंद बाज़ार में साफ–सफाई की विभिन्न गतिविधियां की गईं, ताकि आम जनता, बच्चों, दुकानदारों आदि में स्वच्छता के प्रति जागरुकता फैलाई जा सके।

Hkkjr dk lekpkj&i= iath;d dk;ky; ¼vkj,uvkb½

भारत के समाचार–पत्र पंजीयक कार्यालय (आरएनआई) की स्थापना 1 जुलाई, 1956 को प्रथम प्रेस आयोग की 1953 की सिफारिश के आधार पर और प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के संशोधन के द्वारा की गई थी। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है। आरएनआई वैधानिक और गैर वैधानिक कार्यों का निर्वहन करता है।

lxBukRed <kpk

आरएनआई का मुख्यालय अब 9वीं मंजिल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में है।

इसके प्रमुख प्रेस पंजीयक होते हैं, जिनकी सहायता एक अपर प्रेस पंजीयक, दो उप प्रेस पंजीयक और तीन सहायक प्रेस पंजीयक करते हैं। कार्यालय में शीर्षक के सत्यापन, प्रसार और प्रशासन संबंधी कार्यों के लिए पृथक अनुभाग हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा पुनर्गठन किए जाने के बाद आरएनआई के मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल और गुवाहाटी कार्यालय बंद कर दिए गए और पत्र सूचना कार्यालय तथा पूर्ववर्ती क्षेत्र प्रचार निदेशालय (अब ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन) के सहायक निदेशक स्तर के अधिकारियों को पंजीकरण सुपरवाइजर और उपनिदेशक/निदेशक/अपर महानिदेशक स्तर के अधिकारियों को क्रमशः सहायक/उप/अपर प्रेस पंजीयक निर्दिष्ट किया गया, जो प्रेस पंजीयक के अधीक्षण और निर्देशन में अपनी शक्तियों का निर्वहन कर रहे हैं।

vkj,uvkb d dk;

आरएनआई के कार्यों में देशभर में प्रकाशित होने वाले समाचार–पत्रों और प्रकाशनों का रजिस्टर रखना, समाचार–पत्रों

और प्रकाशनों के पंजीकरण का प्रमाण–पत्र जारी करना, समाचार–पत्रों के नए नाम शीर्षक की स्वीकृति के बारे में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को जानकारी देना तथा समाचार–पत्रों और प्रकाशनों के प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वक्तव्यों की जांच और विश्लेषण करना शामिल है। आरएनआई प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक देश में प्रिंट मीडिया की स्थिति को दर्शाने वाली ''भारत में प्रेस'' रिपोर्ट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। अपने ग़ैर वैधानिक कार्यों के अंतर्गत यह कार्यालय आरएनआई से पंजीकृत वास्तविक उपयोगकर्ताओं को अख़बारी काग़ज़ आयात पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी करता है और साथ–साथ मुद्रण मशीनरी के आयात के लिए आवश्यक प्रमाण–पत्र भी जारी करता है। आरएनआई प्रकाशकों से प्राप्त अनुरोध या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के आधार पर पंजीकृत प्रकाशनों के प्रसार का सत्यापन करता है।

'kh"kd dk lR;kiu

आरएनआई को शीर्षकों के सत्यापन के लिए इच्छुक प्रकाशकों के आवेदन जिलाधिकारी द्वारा विधिवत अग्रेषित किए जाते हैं और कार्यालय पीआरबी अधिनियम की धारा 6 के तहत सत्यापन प्रक्रियाओं पर कार्य करता है। आवेदकों की सुविधा के लिए आरएनआई ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है। आवेदक को भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर संबद्ध डीएम के पास जमा कराना होता है, ताकि वह उसका सत्यापन करके उसे आरएनआई को अग्रेषित कर सके। आरएनआई द्वारा आवेदन प्राप्ति और सत्यापन की स्थिति के बारे में आवेदकों को एसएमएस और ई–मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है। आवेदनों की स्थिति के बारे में आरएनआई की वेबसाइट (www.rni.nic.in) से जाना जा सकता है। शीर्षक स्थिति पत्र भी आरएनआई वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अप्रैल, 2018 से नवंबर 2018 तक आरएनआई ने शीर्षकों के सत्यापन वाले 10,454 आवेदनों की जांच की, जिनमें से 2,122 शीर्षकों का सत्यापन किया जा चुका है।

'kh"kdk l jkd gVkuk

शीर्षक के सत्यापन के बाद यदि 2 वर्ष तक आरएनआई को पंजीकरण के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते, तो शीर्षक से रोक हटा ली जाती है और वह शीर्षक के सत्यापन के आरएनआई के दिशानिर्देशों और पीआरबी अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार अन्य इच्छुक आवेदकों के लिए उपलब्ध हो जाता है। अप्रैल, 2018 से नवंबर 2018 के बीच आरएनआई द्वारा करीब 2,135 शीर्षकों से रोक हटाई गई।

i thdj.k

शीर्षक का सत्यापन हो जाने के बाद प्रकाशक को प्रकाशन का पंजीकरण कराना होता है। प्रकाशन का पंजीकरण कराने के लिए प्रकाशक को संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया घोषणापत्र, आरएनआई द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कराना होता है। पीआरबी अधिनियम के प्रावधानों के तहत, प्रकाशन को रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रकाशक को पंजीकरण का प्रमाण–पत्र (सीआर) जारी किया जाता है। इस संबंध में आरएनआई के रजिस्टर में प्रविष्टि भी की जाती है। 1 अप्रैल, 2018 से नवंबर 2018 के बीच लगभग 1,375 प्रकाशनों का पंजीकरण किया गया। अप्रैल, 2018 से नवंबर 2018 के दौरान कुल 2,704 पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किए गए, जिनमें 1,375 नए मामले और 1,309 संशोधित प्रमाण–पत्र तथा 20 प्रतिलिपि या डुप्लीकेट प्रमाण–पत्र शामिल हैं।

okf"kd fooj.k

पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 19डी के अनुसार, समाचार–पत्र के प्रकाशक से अपेक्षा की जाती है कि वह हर वर्ष मई के अंतिम दिन से पहले तक फॉर्म–2 में वार्षिक विवरण, जोकि समाचार–पत्र पंजीकरण (सेंट्रल) नियम, 1956 में निर्दिष्ट है, प्रेस रजिस्ट्रार को सौंपे। यह हर प्रकाशक के लिए बाध्यकारी है कि वह अपने प्रकाशन पहले अंक में (हर साल फरवरी माह के अंतिम दिन के बाद) फॉर्म–4 के स्वामित्व और अन्य संबंधित विवरणों को इंगित करने वाला वक्तव्य प्रकाशित करे। प्रकाशकों द्वारा जमा कराए गए वार्षिक विवरण के आधार पर आरएनआई प्रिंट मीडिया के संबंध में हुई वृद्धि संकलन और विश्लेषण करते हुए हर साल 'भारत में प्रेस' रिपोर्ट लाता है।

ऑनलाइन वार्षिक विवरण जमा कराने की शुरुआत 2013–14 से हुई थी, जिसे सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 के लिए लगभग 31,717 प्रकाशकों ने वार्षिक विवरण भरे हैं।

dI;Vjhdj.k

वर्तमान में शीर्षक के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा कराए जा सकते हैं। शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण की कंप्यूटरीकृत प्रोसेसिंग के बाद सभी सत्यापित शीर्षकों को आरएनआई की वेबसाइट पर डाला जाता है और इसे आवेदक डाउनलोड कर सकते हैं। इस सुविधा के लागू होने से कोई भी व्यक्ति/संभावित प्रकाशक वर्तमान शीर्षक डाटा बेस तक पहुंच सकता है। यह डाटा राज्यवार/भाषा के अनुसार उपलब्ध होता है। आरएनआई ने नई उपयोग–सुलभ वेबसाइट विकसित की है। डिजिटलीकरण के दूसरे चरण में, शीर्षक के आवेदन और पंजीकरण से संबंधित कार्यालय की विभिन्न प्रक्रियाएं पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएंगी। प्रक्रियाओं के ऑनलाइन

होते ही, सभी संबद्ध जिला अधिकारीयों को आवेदनों को विधिवत सत्यापित करने के बाद आरएनआई को अग्रेषित करने के लिए व्यक्तिगत लॉगइन उपलब्ध कराया जाएगा।

^Hkkjr e i l^ dk idk'ku

पीआरबी अधिनियम,1867 की धारा 19 (जी) के अनुसार, प्रेस पंजीयक केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है, जिसमें भारत में समाचार–पत्रों के बारे में पिछले वर्ष प्राप्त की गई सूचनाओं का सारांश शामिल होता है। 'भारत में प्रेस' शीर्षक वाली यह रिपोर्ट हर साल दिसंबर में सौंपी जाती है। वर्ष 2013–14 से, 'भारत में प्रेस' सीडी जैसे डिजिटल प्रारूप में भी लाई जा रही है।

ilkj lR;kiu

प्रकाशन की नियमित प्रसार जांच/सत्यापन का उद्देश्य वार्षिक रिटर्न/रिपोर्ट में प्रकाशनों द्वारा दिए गए प्रसार आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि करना है, क्योंकि प्रसार के इन आंकड़ों का उपयोग पूर्ववर्ती विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय–डीएवीपी (अब ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन) सहित विभिन्न सरकारी विभाग सरकारी विज्ञापन आवंटित करने के बारे में निर्णय लेने के लिए करते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 7 जून, 2016 को जारी की गई नई प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति के अंतर्गत 45 हजार से ऊपर के प्रसार दावों का आरएनआई/एबीसी द्वारा सत्यापन अनिवार्य बना दिया गया। इस नीति का अनुसरण करते हुए प्रसार जांच से संबंधित आरएनआई के दिशानिर्देशों में 2017 में संशोधन किया गया और इससे प्रसार सत्यापन की ज्यादा प्रभावी व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ, ताकि समाचार–पत्रों द्वारा फर्जी प्रसार दावों की समाप्ति सुनिश्चित की जा सके। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रसार जांच का कार्य आरएनआई/पीआईबी अधिकारियों द्वारा प्रेस पंजीयक के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण में लेखाकारों (यानी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म्स) के प्रमाणित पैनल के साथ किया जाता है, जो एबीसी, कैग या आरबीआई के पैनल में शामिल लेखाकार होते हैं। साथ ही बीओसी की ओर से प्रेस विशेषज्ञों की आवश्यकता के स्थान पर स्व–घोषणा पत्र फॉर्म को शामिल किया गया है, जिसमें प्रकाशकों द्वारा प्रसार सत्यापन के लिए मुद्रण से संबंधित विवरण उपलब्ध कराया जाता है।

v[kckjh dkxt

किसी समाचार–पत्र द्वारा आयात की जा सकने वाली अख़बारी कागज की अधिकतम मात्रा को निर्दिष्ट करने से संबंधित पात्रता प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया आरएनआई द्वारा 2017 में समाप्त कर दी गई। वर्तमान में, पंजीकृत प्रकाशकों को अख़बारी कागज आयात करने से पहले एक स्व–घोषणा प्रमाण–पत्र जमा कराना होता है, जिसमें वर्ष के दौरान आयात किए गए अख़बारी कागज की मात्रा और उपरोक्त मात्रा में से आज की तिथि तक वास्तव में कितनी खपत की गई, इसकी जानकारी दी जाती है। आरएनआई और पीआईबी के क्षेत्रीय शाखा कार्यालय यह सुनिश्चित करने के बाद स्व–घोषणा प्रमाण–पत्र को प्रमाणित करते हैं कि प्रकाशक न्यूज़प्रिंट का 'वास्तविक उपयोगकर्ता' है, अर्थात प्रकाशन आरएनआई के साथ पंजीकृत है। आरएनआई अब आयात होने वाले अख़बारी कागज की मात्रा तय नहीं करता।

jkt Hkk"kk

आरएनआई कार्यालय ने 1 से 14 सितंबर, 2018 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया, जिसमें सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस कार्यालय में अनुवाद में सहायता प्रदान करने और भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक सहायक निदेशक (ओएल) नियुक्त हैं।

tu f'kdk;r rFkk vkjVhvkbl

कार्यालय में एक जन शिकायत प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। शीर्षक आवेदक तथा प्रकाशक ईमेल pqrcrni@nic.in के माध्यम से सीधे या आरएनआई की वेबसाइट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। एक उप प्रेस पंजीयक को इस कार्यालय की आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था का प्रमुख बनाया गया है। अप्रैल 2018 से नवंबर 2018 के दौरान आरटीआई कानून के अंतर्गत लगभग 440 आवेदन प्राप्त हुए और उनके उत्तर दिए गए।

ukxfjd pkVZj

नागरिक चार्टर तैयार किया गया है। इसे कार्यालय की वेबसाइट (http://www.rni.nic.in) पर डाल दिया गया है।

pkngo foÿk vk;kx dh 'k"k vof/k d fy, Iyku ;kstuk

vkj,uvkbl e[;ky; dk ln<hdj.k

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरएनआई ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की व्यापक योजना 'मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत 'आरएनआई मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण' के अंतर्गत योजना पर 1.65 करोड़ रुपये की राशि खर्च की। योजना अवधि के दौरान प्रस्तावित विविध लक्ष्यों में से एक उप–संघटक 'वार्षिक विवरणों की ई–फाइलिंग' को पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया। अब चौदहवें वित्त आयोग की शेष अवधि, यानी 2017–20 तक के लिए योजना निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ जारी है :–

– रिकॉर्ड्स/दस्तावेजों का डिजिटलीकरण

- शीर्षक आवेदन दाखिल करना और डीएम द्वारा ऑनलाइन अग्रेषित करना
- घोषणापत्र फॉर्म ऑनलाइन जमा कराना
- पंजीकरण प्रमाणपत्र ऑनलाइन उत्पन्न करना
- दस्तावेज जमा कराने सहित पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन
- पब्लिक इंटरफेस सिस्टम की स्थापना और पब्लिक रिस्पांस क्वेरी सिस्टम को मजबूत बनाना

i;l ,o iLrd ithdj.k ¼ihvkjch½ vf/kfu;e] 1867 % i;l ,o idk'ku ithdj.k ¼ihvkjih½ fo/k;d] 2018

वर्तमान में लागू प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम 1867 का उद्देश्य भारत में प्रकाशित पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की प्रतियों का संरक्षण और ऐसी पुस्तकों और पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए प्रिंटिंग प्रेसों तथा समाचार–पत्रों का नियमन करना है।

देश में समकालीन प्रिंट मीडिया परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए पीआरबी अधिनियम 1867 में संशोधन करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए प्रेस एवं पुस्तकों और प्रकाशनों के पंजीकरण (पीआरबीपी) नामक विधेयक तैयार किया गया और नवंबर 2011 में मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद लोकसभा में पेश किया गया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने विधेयक की जांच की और कुछ सिफारिशें कीं। हालांकि, 15वीं लोकसभा की अवधि समाप्त हो जाने के कारण यह विधेयक कालातीत हो गया। 16वीं लोक–सभा प्रारंभ होने के बाद नया विधेयक तैयार करने का फैसला किया गया। हालांकि, मौजूदा पीआरबी अधिनियम, 1867 की जगह लेने के लिए 'प्रेस और प्रकाशन का पंजीकरण विधेयक, 2018 नामक नए विधेयक का मसौदा तैयार हो चुका है। वर्तमान में इस विधेयक का मसौदा पर मंत्रालय में विचाराधीन है।

idk'ku foHkkx

e[; fcn vkj miyfC/k;k

- प्रकाशन विभाग ने आदेश के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के चुने हुए भाषणों के दो खण्ड प्रकाशित किए। इनमें एक खण्ड अंग्रेजी और एक हिंदी में है। इसमें उनके कार्यकाल के प्रथम वर्ष के भाषणों को भी शामिल किया गया है। 'द रिपब्लिकन एथिक' और 'लोकतन्त्र के स्वर' शीर्षक वाले ये खण्ड राष्ट्र निर्माण के बारे में विशेषकर राष्ट्र के प्रति प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों के विविध पहलुओं पर माननीय राष्ट्रपति के विज़न और विचारों को प्रस्तुत करते हैं। ये संस्करण राष्ट्रपति के कार्यालय के सहयोग

नई दिल्ली में 8 दिसंबर, 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित भारत के राष्ट्रपति के चुनिन्दा भाषणों के ई–बुक्स संग्रह ''दी रिपब्लिकन एथिक'' और ''लोकतंत्र के स्वर'' का विमोचन करते हुए माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू। इस अवसर पर केन्द्रीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, श्री अमित खरे, चेयरमैन, प्रसार भारती डॉ. ए. सूर्य प्रकाश और प्रधान महानिदेशक, प्रकाशन विभाग डॉ. साधना राउत भी उपस्थित रहे

से प्रकाशित किए गए हैं और 8 दिसंबर, 2018 को इनका विमोचन माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौड़ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव, श्री अमित खरे की मौजूदगी में किया गया।

- प्रकाशन विभाग ने माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा उनके कार्यकाल के प्रथम वर्ष दिए गए चुनिंदा भाषणों का संस्करण प्रकाशित किया। इस संस्करण का विमोचन 15 फरवरी, 2019 को माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्री श्री थावर चंद गहलौत, माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौड़, राज्यसभा के उप सभापति श्री हरिवंश और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे की मौजूदगी में किया गया।

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के वर्षवार संस्करण प्रकाशित करने का प्रतिष्ठित एवं विशाल कार्य भी प्रकाशन विभाग द्वारा सम्पन्न किया गया। पांच खण्डों में विभाजित ये भाषण ''सबका साथ, सबका विकास'' के अंतर्निहित विषयवस्तु के साथ हमारे राष्ट्रीय जीवन के विविध पहलुओं को समाहित करते हैं। इन पांच संस्करणों में से–तीन संस्करण हिंदी में हैं जो वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 को समेटते हैं तथा दो संस्करण अंग्रेजी में हैं जो वर्ष 2014–15 और 2015–16 को समाहित करते हैं। इस कार्य वित्त वर्ष

नई दिल्ली में 08 मार्च, 2019 को माननीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने (माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का संकलन) पुस्तक 'सबका साथ सबका विकास' का लोकार्पण किया। साथ में हैं, माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे एवं अन्य गणमान्य अतिथि।

2018–19 में सम्पन्न किया गया। इन संस्करणों का विमोचन वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौड़, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव, श्री अमित खरे की मौजूदगी में किया गया।

- प्रतिष्ठित bfM;k@Hkkjr 2019 का विमोचन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे द्वारा 7 मार्च, 2019 को किया गया। इस प्रमुख प्रकाशन के ई–संस्करण भी साथ ही जारी किए गए। इस वार्षिक संदर्भ ग्रंथ में देश और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, शिक्षा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उसकी प्रगति का समग्र विवरण के साथ सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामलों पर खण्ड हैं।

- ^xqokgkVh gkbZ dksVZ % fgLVh ,aM gfjVst^ गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए प्रकाशित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत में वैविध्यपूर्ण एवं परंपरागत न्याय प्रणालियों के ऐतिहासिक उद्गम और विकास पर प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तक का विमोचन भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने गुवाहाटी में 25 अगस्त, 2018 को किया था। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल भी उपस्थित थे।

- प्रकाशन विभाग ने अपनी विषयवस्तु का आधार और पहुंच बढ़ाने के लिए अप्रैल 2018 में भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) के साथ सह–प्रकाशन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके परिणामस्वरूप ^foeu bu bfM;u fluek^ जैसी प्रतिष्ठित पुस्तक की रचना संभव हो सकी। इस पुस्तक में भारतीय सिनेमा

'विमन इन इंडियन सिनेमा' शीर्षक पुस्तक का विमोचन माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने 20 नवम्बर, 2018 को आईएफएफआई–2018 के उद्घाटन के अवसर पर किया

की प्रिज्म के जरिए भारतीय महिला की तेजी से बदलती यात्रा को प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौड़ ने आईएफएफआई–2018 के उद्घाटन के अवसर पर 20 नवंबर, 2018 को किया।

- भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गुप्त राष्ट्रवादी प्रसारणों की गाथा का एक महत्वपूर्ण प्रकाशन vuVkYM LVkjh vkQ c,MdkLV M;fjx fDoV bfM;k eoeV इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के सहयोग से प्रकाशित किया गया और अगस्त 2018 में माननीय संस्कृति मंत्री श्री महेश शर्मा द्वारा उसका विमोचन किया गया।

विख्यात गांधीवादी श्री ए. अन्नामलाई और सुश्री वर्षा दास 16 नवंबर, 2018 को पुस्तक दीर्घा, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन में राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह (14–20 नवंबर, 2018) के दौरान ''हिंद स्वराज–जीवन परिवर्तन में पुस्तकों का महत्व'' विषय पर एक पुस्तक चर्चा कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए

- प्रकाशन विभाग ने xkèkh th dh 150oÈ t;rh के समारोह से संबंधित पुस्तकों के प्रकाशन और आउटरीच गतिविधियों की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। प्रकाशित होने वाली पुस्तकों में उल्लेखनीय हैं – 1930 ds n'kd esa विख्यात विद्वान–कवि डॉ. क्षमा राव द्वारा संस्कृत में रचित गीतों का धरोहर प्रकाशन *सत्याग्रह गीता* का संस्कृत मूलपाठ और हिंदी एवं अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशन, विख्यात विदुषी डॉ. अपर्णा बसु की foeu bu lR;kxzg, *एमके गांधीः एन इंडियन पेट्रियट इन साउथ अफ्रीका* xka/kh th ds nf{k.k vÝhdh fe= tks lQ Mksd }kjk nf{k.k vÝhdk esa xka/kh th ds ikjafHkd o"kksa ij fy[kh xbZ mudh iFke thouh] तथा युवाओं और सामान्य पाठकों को प्रेरित करने वाली अनेक अन्य पुस्तकें शामिल हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान गांधीजी के विचारों और आदर्शों के विविध पहलुओं पर आधारित 17 पुस्तकें प्रकाशित की गईं। गांधीजी के विचारों और आदर्शों के विविध पहलुओं पर आधारित अनेक ई–पुस्तकों का भी प्रकाशन किया गया।

- fMftVy xkaèkh% गांधीजी के बारे में श्रव्य, श्रव्य–दृश्य और मूलपाठ सहित पहले के स्मरणीय कार्यों, अभिलेखीय और ऑडियो–बुक सामग्री के साथ राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के सहयोग से तैयार किया गया व्यापक ई–संकलन है और यह लगभग पूरा हो चुका है। *महात्मा गांधी– अ लाइफ इन लेन्सेज़ (गांधी एलबम)* अंग्रेजी और हिंदी में व्यापक राइटअप्स सहित लगभग 450 दुर्लभ ऐतिहासिक फोटोग्राफ बेहतर गुणवत्ता के साथ तैयार किया गया है और इसका प्रकाशन जल्द होने वाला है।

- pEikj.k lR;kxzg 'krkCnh lekjksg के अवसर पर, प्रकाशन विभाग ने गांधी अध्ययन केंद्र, चेन्नई के सहयोग से, 10 अप्रैल, 2018 को चेन्नई में डीजी तेंदुलकर के xka/kh bu pEikj.k के तमिल संस्करण का विमोचन किया।

- प्रकाशन विभाग ने सम्पूर्ण गांधी वांग्मय (एसजीवी) (97वां संस्करण), सीडब्ल्यूएमजी के हिंदी संस्करण (100 संस्करण) की डिजिटल मास्टर प्रति तैयार करने के लिए गुजरात विद्यापीठ के साथ जुलाई 2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना इस धरोहर दस्तावेज के संरक्षण और भविष्य में एसजीवी के संपूर्ण एवं आधिकारिक मुद्रित खण्डों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

- तत्कालीन माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्रीमती स्मृति ईरानी ने प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित तीन पुस्तकों का अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च, 2018) के अवसर पर विमोचन किया। इनमें *रानी लक्ष्मी बाई* और *रजिया सुल्तान* शामिल थीं। इस अवसर पर Þ,d Hkkjr J"B Hkkjrß परियोजना के तहत प्रत्येक पुस्तक के 13 भाषाओं में संस्करण जारी किए गए। सस्ता साहित्य मंडल के साथ सह–प्रकाशन कार्यक्रम के तहत प्रकाशित एक अन्य पुस्तक ''प्राचीन भारत के नारी रत्न'' का विमोचन भी सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा किया गया। "एक भारत श्रेष्ठ भारत" परियोजना के तहत, 15 चयनित किताबों के 13 भारतीय भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन के काम में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, अब तक लगभग 150 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं।

- सस्ता साहित्य मंडल (एसएसएम) के साथ सहयोग से कई नई पुस्तकों के प्रकाशन के रूप में प्रगति हुई। इनमें से तीन पुस्तकों– *भक्तिः उत्तर और दक्षिण भारत के समन्वय सूत्र, श्रुति और स्मृति तथा भारतीय संस्कृति के आंतरिक स्रोत* का अगस्त 2018 को दिल्ली पुस्तक मेले के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे द्वारा विमोचन किया गया।

- प्रकाशन प्रभाग ने हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं की विभिन्न श्रेणियों में पुस्तक प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए 7 iqjLdkj vkSj ,d ;kX;rk çek.k&i= प्राप्त किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे ने फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स द्वारा स्थापित वार्षिक पुरस्कार वितरित किए। प्रकाशन विभाग की पुस्तकों *सरदार पटेलः सचित्र जीवनी* (हिंदी), *लाइफ*

दिल्ली पुस्तक मेला 2018 के समापन समारोह में आईटीपीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ भाषा प्रदर्शन श्रेणी में प्रकाशन विभाग को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया

एट राष्ट्रपति भवन (अंग्रेजी), और *पुस्तक सूची* (हिंदी) को प्रथम पुरस्कार मिला। भारत – 2018 (हिंदी), योजना– अप्रैल 2017 (अंग्रेजी), बाल भारती– सितंबर 2017 (हिंदी) और *अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट* ने द्वितीय पुरस्कार और *बुद्धिज्म–द पाथ ऑफ कम्पैशन* ने योग्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया।

- ;kstuk और d#{k= सहित प्रकाशन विभाग की पत्रिकाएं सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचनाओं को प्रसारित करने के प्रयास जारी रखे हुए हैं। ;kstuk की ओर से *"रोज़गार और स्व रोज़गार" ''स्वच्छता विचार से वास्तविकता'' और ''अवसंचरना''* तीन विशेषांक निकाले गए हैं। ***कुरुक्षेत्र*** ने अपने अंक ग्रामीण अवसंरचना, ग्रामीण स्वास्थ्य, एमएसएमई, पंचायती राज आदि को समर्पित किए हैं, जिनमें सम्बद्ध मंत्रालयों के सचिव/मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लेख शामिल रहे। jkstxkj lekpkj ने 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक 4,539 से अधिक विज्ञापन प्रकाशित किए हैं।

- इस दौरान प्रकाशित अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों में आती हैं : *द एशियाटिक लॉयन–रिवाविंग द प्राइड ऑफ गीर, बुद्धिज्मः द पाथ ऑफ कम्पैशन, पोर्ट्रेट्स ऑफ स्ट्रेन्थ–रविन्द्रनाथ की कला सृष्टि, पराक्रम गाथा* और *संकल्प से सिद्धि–* स्वच्छता के बारे में माननीय प्रधानमंत्री के उद्धरण।

- कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें जो प्रकाशन के क्रम में हैं उनमें *सत्याग्रह गीता* की अगली कड़ी *उत्तर सत्याग्रह गीता*, कस्तूरबा गांधी की जीवनी और नारायण देसाई की पुस्तक *माई स्टोरी इन हिंदी* शामिल हैं।

- योजना की ehfM;k voljpuk fodkl कार्यक्रम उप–योजना के तहत 'प्रकाशन प्रभाग ने fMftVkbTM iLrdk dh l[;k 2]300 ls vf/kd करते हुए अपनी पुस्तकों के डिजिटल भंडार को और समृद्ध करने की दिशा में काम किया। इनमें से 370 से अधिक ई–पुस्तकों को अमेजन और गूगल प्ले जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से बिक्री के लिए प्रस्तुत किया गया। ई पुस्तकों की लगभग 11,000 प्रतियों की बिक्री हुई।

- प्रकाशन विभाग ने अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2019 तक 36 से ज्यादा घरेलू पुस्तक मेलों में भाग लिया। प्रकाशन विभाग ने 25 अगस्त से 2 सितंबर, 2018 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित वार्षिक fnYyh iLrd esys में भाग लिया। इसमें विभिन्न विषयों पर आधारित पुस्तकों का समृद्ध प्रदर्शन किया गया। प्रकाशन विभाग के स्टाल का मुख्य आकर्षण भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तकें थीं। पुस्तक मेले के दौरान कुल 19 पुस्तकों का विमोचन किया गया। प्रकाशन विभाग ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2019 में भी बड़े पैमाने पर भाग लिया।

- प्रकाशन विभाग ने चार अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेलों यानी मॉरीशस में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन, 2018 (18–20 अगस्त 2018), बीजिंग इंटरनेशनल बुक फेयर (22–26 अगस्त, 2018) और फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल बुक फेयर (10–14 अक्तूबर 2018) और लंदन पुस्तक मेला (12–14 मार्च, 2019)में भाग लिया। कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों से प्रकाशन अधिकारों/विपणन अधिकारों/ ई–पुस्तकों प्रकाशन विभाग की पुस्तकों के विपणन के लिए पेशकश प्राप्त हुईं। प्रकाशन विभाग ने पहली बार फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में अपनी पुस्तकों की बिक्री शुरू की।

प्रकाशन विभाग की महानिदेशक डॉ साधना राउत और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री विक्रम सहाय ने लंदन पुस्तक मेले में भारत के मण्डप का उद्घाटन किया

- प्रकाशन विभाग द्वारा व्यापक दर्शकों तक पहुंच बनाने के प्रयासों के तहत 2018 के दौरान हर महीने समसामयिक महत्व के विषयों जैसे गांधीजी की 150वीं जयंती, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि पर पुस्तक चर्चा कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री राम बहादुर राय, श्री सच्चिदानंद जोशी, श्री ए अन्नामलाई, श्रीमती मृदुला गर्ग, सुश्री नासिरा शर्मा, सुश्री मंजरी चतुर्वेदी जैसे प्रमुख लेखकों/हस्तियों को "भारतीय स्त्री – परंपरा और अपेक्षाएं", "पुस्तक संस्कृति और पठनीयता", "भारतीय सिनेमा के नये आयाम, "स्वच्छ मन, स्वच्छ तन और स्वच्छ पर्यावरण'', "आज़ादी मेरी नज़र में'' आदि जैसे विषयों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया।

- प्रकाशन विभाग को 16–31 जनवरी, 2019 तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के दौरान उसके प्रदर्शन के लिए मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार–2019 से सम्मानित किया गया।

ifjp;

राष्ट्रीय महत्व और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं के भंडार प्रकाशन विभाग की स्थापना 1941 में की गई थी। यह भारत सरकार के ऐसे प्रमुख प्रकाशन गृह के रूप में उभर कर सामने आया है जो ज्ञान के राष्ट्रीय भंडार को समृद्ध करने में निम्नलिखित तरीके से अपना योगदान कर रहा हैः 1) भारत भूमि और यहां के लोगों, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास, कला और संस्कृति, जीव–जंतुओं और वनस्पतियों, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनियों, संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, साहित्य आदि के क्षेत्र की महान हस्तियों के बारे में श्रेष्ठ पुस्तकें प्रकाशित करके भारत की धरोहर का संरक्षण और प्रदर्शन, (2) राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री के भाषणों के प्रकाशन से समसामयिक घटनाक्रम को लिपिबद्ध करना; समसामयिक विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इतिहास और अन्य् विषयों पर भारतीय समाज और पाठकों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए पुस्तकें छापना और (3) कथात्मक और गैर–कथात्मक बाल साहित्य का प्रकाशन।

विभाग ने गांधीवादी दर्शन पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया है जिनमें 100 खण्डों में अंग्रेजी में कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (सीडब्ल्यूएमजी) शामिल है, जिसे गांधीजी के लेखन का सबसे व्यापक और प्रामाणिक संग्रह माना जाता है। प्रकाशन विभाग ने गुजरात विद्यापीठ के साथ मिलकर प्रमुख गांधीवादी विद्वानों की निगरानी में कलेक्टिड वर्क ऑफ महात्मा गांधी का ई–संस्करण (ई–सीडब्ल्यूएमजी) भी तैयार किया है। मास्टर कॉपी सुरुचिपूर्ण ढंग से डिजाइन की गई डीवीडी के सेट के रूप में उपलब्ध है, इसमें किसी भी विषय को आसानी से खोजा जा सकता है, जो गांधी हैरिटेज पोर्टल पर भी उपलब्ध है। प्रकाशन विभाग और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय कई प्रामाणिक और सुरुचिपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित करने में सहयोग कर रहे हैं।

प्रकाशन विभाग चार मासिक पत्रिकाओं *योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल* तथा साप्ताहिक *रोज़गार समाचार* का भी प्रकाशन करता है। ये पत्रिकाएं आर्थिक विकास, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सामुदायिक विकास, बाल साहित्य और रोज़गार एवं करियर के विकल्पों पर सूचना जैसे समकालीन विषयों को कवर करती हैं।

lxBukRed <kpk

प्रकाशन विभाग निदेशालय के प्रधान महानिदेशक (डीजी) होते हैं। उनकी सहायता के लिए एक अपर महानिदेशक और निदेशक स्तर के अधिकारी होते हैं जो संपादकीय, व्यावसायिक, उत्पादन और प्रशासन प्रभागों एवं रोज़गार समाचार को देखते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली स्थित सूचना भवन में है और इसके बिक्री केंद्र– नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हैदराबाद तथा तिरुअनंतपुरम में हैं। *योजना* पत्रिका के कार्यालय नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम तथा बंगलुरु में हैं।

iqe[k xfrfof/k;k

iLrdk dk iidk'ku

वर्ष 2018–19 में प्रकाशन विभाग ने मार्च 2018 तक लगभग 168 पुस्तकों का प्रकाशन किया। इनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं : माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में दिए गए चुनिंदा भाषण 'n fjifCydu ,fFkd' (अंग्रेजी)और *ykdrU= d Loj* (हिंदी) हैं, माननीय उप राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रथम वर्ष के चुनिंदा भाषणों का एक संस्करण, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के पांच संस्करण और संदर्भ ग्रंथ bfM;k 2019 और Hkkjr 2019 शामिल हैं।

गांधीजी के 150वें जयंती वर्ष के दौरान श्रद्धांजलि स्वरूप गांधीवादी पुस्तकों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। इस खण्ड की उल्लेखनीय पुस्तकें हैं :

डॉ. अपर्णा बसु की *विमन इन सत्याग्रह*, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नई दिल्ली के सहयोग से कस्तूरबा गांधी की जीवनी, अंग्रेजी और हिंदी में व्यापक लेख सहित लगभग 500 दुर्लभ चित्रों वाली गांधी एलबम, डी.जी. तेंदुलकर की प्रमुख पुस्तक *गांधी इन चम्पारण* के तमिल और कन्नड़ संस्करण, गांधीजी के दक्षिण अफ्रीकी मित्र जोसेफ डोक द्वारा दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी के प्रारंभिक वर्षों पर लिखी गई उनकी प्रथम जीवनी, बच्चों और युवाओं को प्रेरित करने वाली कई अन्य गांधीवादी पुस्तकों सहित बच्चों के लिए अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, गुजराती और असमिया में महात्मा के जीवन के आरंभिक चरण को कवर करने वाली गांधीजी की सचित्र जीवनी शामिल हैं।

माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने नई दिल्ली में 2 अक्तूबर, 2018 को बीओसी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी के अवसर पर 11 महत्वपूर्ण गांधीवादी पुस्तकों का विमोचन किया, जिनमें मौलिक, अनूदित और पुनःस्थापित पुस्तकें शामिल थीं।

शीर्ष संस्थाओं के बारे में पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए जारी प्रयासों के तहत प्रकाशन विभाग ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए ^xokgkVh gkbZ dkVZ % fgLVh ,M gfjVt^ का प्रकाशन किया है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत में वैविध्यपूर्ण एवं परंपरागत न्याय प्रणालियों के ऐतिहासिक उद्‌गम और विकास पर प्रकाश डाला गया है।

प्रकाशन विभाग ने अपनी आउटरीच बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) के साथ मिलकर 'oeu bu bfM;u flusek^^ पुस्तक प्रकाशित कर बीते वर्षों में भारतीय सिनेमा में भारतीय महिला के चित्रण में आए बदलाव पर रोशनी डाली। इस पुस्तक का विमोचन माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने गोवा में आईएफएफआई के दौरान 20 नवम्बर, 2018 को किया। इससे पहले प्रकाशन विभाग का आईजीएनसीए के साथ सहयोग भी फलदायी रहा और *"अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्ट ड्युरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट"* शीर्षक से एक महत्वपूर्ण पुस्तक का प्रकाशन किया गया। इस पुस्तक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय देशभक्तों द्वारा चलाए जाने वाले गुप्त राष्ट्रवादी प्रसारणों की गाथा है। सस्ता साहित्य मंडल के साथ सहयोग की बदौलत भारतीय संस्कृति और लोकाचार पर आधारित कई पुस्तकों जैसे ––– *श्रुति और स्मृति, भक्तिः उत्तर और दक्षिण का समन्वय सूत्र, तथा भारतीय संस्कृति की आंतरिक लय के स्रोत* का प्रकाशन किया गया।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों में : *बुद्धिज्म–द पाथ ऑफ कम्पैशन, पोर्ट्रेट ऑफ स्ट्रेन्थ, लोक में जल, रवींद्रनाथ की कला सृष्टि, चम्पारण पुराण, विवेकानंद की कहानी, डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार* (कन्नड़), *पंडित दीन दयाल उपाध्याय* (कन्नड़), *तेलुगू में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार* और तमिल में *शहीदों के खत।* बाल साहित्य की कुछ पुस्तकें : *थोड़ा सा तो हो न बचपन, बादल की सैर और वनवासी बच्चे। सरल पंचतंत्र, चिल्ड्रेन्स महाभारत, रानी लक्ष्मीबाई* जैसी प्रेरक पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में अनूदित और प्रकाशित की गईं।

xka/kh th dh 150oha t;arh मनाने के प्रकाशन विभाग के प्रयासों के तहत राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय (एनजीएम) के सहयोग से तैयार डिजिटल गांधी–गांधीजी से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेखीय सामग्री को कवर करने वाले ऑडियो, विजुअल और मूलपाठ, पूर्व स्मरणीय संस्करणों के मूलपाठ, गांधीजी के जीवन और संदेशों से युक्त बापू के बारे में समकालीनों की टिप्पणियों सहित एक ऑडियो पुस्तक का ई–संकलन है। सुविधाजनक पेन–ड्राइव में उपलब्ध इस संकलन को गांधीवादी विद्वानों द्वारा पूरी तरह से अन्वेषित और प्रमाणित किया गया है और इसे शहीद दिवस (30 जनवरी, 2019) के अवसर पर जारी किया गया। गांधीजी के विचारों और आदर्शों के विविध पहलुओं पर आधारित 37 ई–पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। प्रकाशन विभाग की ई–पुस्तकों के भंडार को समृद्ध करते हुए, प्रसिद्ध विद्वान डॉ. क्षमा राव द्वारा 1930 के आसपास संस्कृत छंद में रचित पुस्तक सत्याग्रह गीता को हिंदी और अंग्रेजी अनुवादों के साथ पुनः प्रकाशित किया गया और उसको डिजिटल प्रारूप में लाया गया।

çdk'ku dk fMftVhdj.k

योजना के अंतर्गत 'मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम' की उप योजना के तहत 2000 से अधिक पुस्तकों का डिजटलीकरण किया गया। वर्तमान में डिजिटल आर्काइव्स में 2300 से ज्यादा पुस्तकें हैं। इसके अलावा प्रकाशन विभाग ने 370 से ज्यादा विविध ई–कॉमर्स वेबसाइट्स पर तलाशे जा सकने और विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों पर डाउनलोड किए जा सकने वाले प्रारूपों में पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करते हुए डिजिटल प्रकाशन के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है।

if=dkvksa dk çdk'ku

प्रकाशन विभाग कुल 18 पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है। इनमें अंग्रेजी, हिंदी तथा अन्य 11 क्षेत्रीय भाषाओं में *योजना, कुरुक्षेत्र* (अंग्रेजी और हिंदी), *आजकल* (हिंदी और उर्दू), *बाल भारती* (हिंदी) और *इंप्लायमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार* (अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू) शामिल हैं। साल भर में अपनी–अपनी विधा के अनुरूप प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, इन सभी पत्रिकाओं ने सजगता और निरंतरता के साथ गांधीजी के जीवन, आदर्शों और विचारों पर लेखों का प्रकाशन किया।

d½ ;kstuk ¼vaxzsth] fgUnh vkSj 11 {ks=h; Hkk"kkvksa esa ivdkf'kr½

योजना का प्रकाशन 1957 से किया जा रहा है और आर्थिक विकास के विषय को समर्पित पत्रिका है, जो 13 भाषाओं के संस्करणों– अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बांग्ला, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में प्रकाशित की जाती है। पिछले एक वर्ष के दौरान पत्रिका ने रोज़गार, विमुद्रीकरण, जीएसटी, सामाजिक सुरक्षा, युवा सशक्तीकरण, एमएसएमई, उपभोक्ता जागरुकता आदि जैसे समसामयिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। योजना के तीन विशेषांक *रोज़गार और स्व–रोज़गार,* 'स्वच्छता विचार से वास्तविकता तक' तथा 'बुनियादी ढाचा' भी निकाले गए।

[k½ dq#{ks= ¼vaxzsth vkSj fgUnh½

कुरुक्षेत्र 1952 से प्रकाशित की जा रही ग्रामीण विकास और बुनियादी स्तर के विषयों को समर्पित पत्रिका है, जो

शिक्षाविदों, योजनाकारों, गैर–सरकारी संगठनों और विचारकों को एक मंच प्रदान करती है।

2017–18 के दौरान, *कुरुक्षेत्र* ने स्वच्छता, किसानों की आय को बढ़ावा देने, ग्रामीण स्वास्थ्य, सिंचाई और जल संरक्षण, डिजिटल ग्रामीण भारत, ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने, ग्रामीणों और निर्धन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की पहलों, ग्रामीण विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, ग्रामीण रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहन देने, गांवों को खुले में शौच से मुक्त तथा स्वच्छ बनाने के लिए पहल आदि जैसी सरकार की पहलों पर प्रकाश डाला।

x½ vkt dy ¼fgUnh vkSj mnZw½

साहित्य एवं संस्कृति को समर्पित *आजकल* (हिंदी) पत्रिका का प्रकाशन 1945 से किया जा रहा है। पिछले एक साल के दौरान इस पत्रिका ने राहुल सांकृत्यायन, केदारनाथ सिंह, आचार्य शिवपूजन सहाय, कुंवर नारायण आदि जैसे विख्यात साहित्यकारों पर विशेषांक निकाले। पत्रिका ने महिलाओं के मसलों पर अनेक लेखों और कला एवं संस्कृति से जुड़ी सूचना का प्रकाशन किया। आजकल ने संगीत आजकल और पत्रिका आजकल, पुस्तक परिचय जैसे नियमित स्तम्भों का प्रकाशन आरंभ किया है।

साहित्यिक पत्रिका *आजकल* (उर्दू) ने जुलाई 2017 में निरंतर प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे किए। वर्ष 2018–19 के दौरान *आजकल* (उर्दू) ने ग़ालिब और महिलावादी लेखकों पर विशेषांक निकाले।

?k½ cky Hkkjrh ¼fgUnh½

1948 से लगातार प्रकाशित की जा रही *बाल भारती,* बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के अलावा, सूचनात्मक लेखों, लघु कथाओं, कविताओं और सचित्र कहानियों के माध्यम से उनमें सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने में मदद करती है। *बाल भारती* ने स्कूल जाने वाले बच्चों तक माननीय प्रधानमंत्री के संदेशों को प्रसारित करने के लिए लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की। इसके अलावा, बाल भारती, डॉ. जाकिर हुसैन, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत आदि जैसे प्रख्यात विद्वानों और लेखकों द्वारा रचित कविताओं और कहानियों को नियमित रूप से पुनः प्रकाशित करती है।

bEIyk;esaV U;wt@jkstxkj lekpkj ¼vaxzsth] fgUnh] mnZw½

1976 में शुरू किया गया, *रोज़गार समाचार* सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रमुख साप्ताहिक है, जो अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होता है। यह विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं में रोज़गार की सूचना प्रदान करने वाली एकल खिड़की के रूप में कार्य करता है। यह व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रवेश नोटिस, परीक्षा सूचनाओं तथा यूपीएससी, एसएससी तथा अन्य सामान्य भर्ती निकायों के परिणामों को भी प्रकाशन करता है। इसके अतिरिक्त *इंप्लायमेंट न्यूज़* में संपादकीय अनुभाग भी होता है जो युवाओं के व्यावसायिक तथा सूक्ष्म कौशल को उन्नत बनाने के अतिरिक्त बाजार में उपलब्ध विभिन्न रोज़गारों के लिए तैयारी में सहायता देता है। इसका देशव्यापी प्रसार प्रति सप्ताह लगभग 1.3 लाख है। इसके ई–संस्करण तथा मुद्रित संस्करण को उपभोक्ता वेबसाइट www.employmentnews.gov.in से सब्सक्राइब किया जा सकता है। इसकी ट्विटर तथा फेसबुक जैसे विविध सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी उपस्थिति है।

रोज़गार समाचार ने 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के दौरान 4539 से अधिक विज्ञापनों का प्रकाशन किया।

0;kikj ,oa forj.k uSVodZ

(क) प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और पत्रिकाओं की ब्रिक्री एवं विपणन का कार्य दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, तिरुवअनंतपुरम स्थित बिक्री केंद्रों के नेटवर्क तथा अहमदाबाद और बंगलुरु स्थित ;kstuk के बिक्री कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, यह देशभर में अपने एजेंटों/वितरकों के नेटवर्क के माध्यम से अपनी पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री करता है। बिक्री और प्रचार का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र पुस्तक प्रदर्शनियों/पुस्तक मेलों (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों) और कुछ आउटरीच गतिविधियों में भागीदारी हैं।

प्रकाशन विभाग ने दो साल पहले अपनी किताबों और पत्रिकाओं की ऑनलाइन बिक्री शुरू की और अब इसकी मुद्रित पुस्तकों के साथ–साथ ई–बुक्स और मुद्रित पत्रिकाएं साथ ही साथ ई–जर्नल्स भारत कोष पोर्टल, गूगल प्ले और अमेजन जैसे ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए बेची जाती हैं। 400 से अधिक पुस्तकें अब ई–बुक्स के तौर पर उपलब्ध हैं, जिनमें गांधी साहित्य श्रेणी, आधुनिक भारत के निर्माता श्रृंखला, राष्ट्रपति भवन श्रृंखला, कला और संस्कृति, इतिहास, आदि प्रकाशन विभाग की प्रमुख पुस्तकें शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय बिक्री और विपणन को सुगम बनाने के लिए व्यापार नीति में परिर्वतन किए गए हैं, जो अब अंतरराष्ट्रीय बिक्री और विपणन से संबंधित प्रावधान करने के साथ ही साथ

इन पुस्तकों का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में मूल्य निर्धारण भी करती है। प्रकाशन विभाग अमेजन (अमेरिका) अैर अमेजन (यूके) मंचों जैसे अंतरराष्ट्रीय ई–कॉमर्स मंचों के जरिए बिक्री का प्रबंधन करने में समर्थ हो सका। वर्ष 2018–19 के दौरान अमेजन के जरिए ई–पुस्तकों की लगभग 11,000 प्रतियों की बिक्री हुई जबकि ई–पुस्तकों की 11,000 प्रतियां भारतकोश के माध्यम से बेची गईं।

प्रकाशन विभाग की लगभग 300 पुस्तकों का डेटाबेस पहली बार अंतरराष्ट्रीय खरीददारों तक पहुंच बनाने के मार्ग एसी नीलसन्स डेटाबेस में शामिल किया गया।

(ख) प्रकाशन विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरीज़ को अपनी पुस्तकों की बिक्री करने के उद्देश्य से ई–रिसोर्स एग्रीगेटर मैसर्स जीआईएसटी के साथ समझौता करने के जरिए ''डिजिटल वर्जन'' विपणन में कदम रखा है। जीआईएसटी ने पिछले साल कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों को लगभग 3500 पुस्तकों की बिक्री की।

(ग) एक मोबाइल एप विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से खरीद की सुविधा और सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराई गई है।

vkmVjhp xfrfof/k;k

¼1½ iLrd eyk vkj çn'kfu;k

प्रकाशन विभाग ने पाठकों के बीच अपनी पुस्तकों की पहुंच बढ़ाने के लिए घरेलू साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भी भाग लिया। इसने अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 तक लखनऊ, चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, पटना, सिलवासा, हैदराबाद, बंगलुरु, तिरुअनंतपुरम, कोच्चि, लखनऊ, वर्धा आदि में 36 से अधिक घरेलू पुस्तक मेलों में भाग लिया। प्रकाशन विभाग ने 25 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक दिल्ली पुस्तक मेले में भाग लिया। इसने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2019 में भी बढ़–चढ़ कर भाग लिया।

अगस्त 2018 में आयोजित दिल्ली पुस्तक मेला 2018 में प्रकाशन विभाग का मंडप भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया गया था और उनके चुनिंदा भाषणों पर प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के जरिए उनकी विरासत का जश्न मनाया गया

¼2½ varjjk"Vªh; iLrd eyk vkj çn'kfu;k

प्रकाशन विभाग ने चार अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेलों/ प्रदर्शनियों अर्थात मॉरीशस में 18 अगस्त से 20 अगस्त, 2018 तक विश्व हिंदी सम्मेलन, बीजिंग में 22 अगस्त से 26 अगस्त, 2018 तक बीजिंग इंटरनेशनल बुक फेयर, 2018, तथा 10 अक्तूबर से 14 अक्तूबर, 2018 तक फ्रैंकफर्ट बुक फेयर और 12 मार्च से 14 मार्च, 2019 तक लंदन बुक फेयर में भाग लिया। प्रकाशन विभाग पुस्तकों के प्रकाशन अधिकार/ विपणन अधिकार/ ई–बुक्स मार्केटिंग के लिए कुछ प्रमुख वैश्विक प्रकाशकों से प्रस्ताव प्राप्त हुए।

¼3½ eyk LFkkiu ij çn'kfu;k

स्वाधीनता दिवस, गांधी जयंती, हिंदी पखवाड़ा, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय पुस्तक दिवस आदि जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजनों के लिए प्रकाशन विभाग ने देशभर में अपने बिक्री केंद्रों के परिसरों के भीतर लगभग 60 पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

¼4½ xkaèkh @ **150**

प्रकाशन प्रभाग, ने अनेक गांधीवादी और एनजीएम, गांधी स्मारक निधि, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) जैसी अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य किया और अपने गांधीवादी साहित्य का प्रदर्शन किया। इसी तरह मुख्यालयों और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में मूल स्थान पर प्रदर्शन/प्रदर्शनियां/गतिविधियां आयोजित की गईं। दिल्ली में, 2 अक्तूबर, 2018 को बीओसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने प्रकाशन विभाग की 11 गांधीवादी पुस्तकों का विमोचन किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री कुमारस्वामी द्वारा बंगलुरु में, प्रकाशन विभाग के *"गांधी एट चम्पारण"* के कन्नड़ संस्करण का विमोचन किया गया। चेन्नई में प्रकाशन विभाग ने एक कार्यक्रम में भाग लिया जिसमें तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल मुख्य अतिथि थे। प्रकाशन विभाग ने अपनी *गांधी पर्व* गतिविधियों के तहत 5 अक्तूबर, 2018 को, आईजीएनसीए के साथ मिलकर गांधीजी के संदेश की चुनौतियों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।

माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह में 2 अक्तूबर, 2018 को नई दिल्ली में मल्टीमीडिया प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान प्रकाशन विभाग के प्रकाशनों का विमोचन करते हुए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव, श्री अमित खरे और अन्य गणमान्य अतिथि भी इस अवसर पर मौजूद थे

¼5½ vU; vkmVjhp dk;Øe

भारत के स्वाधीनता संग्राम के बारे में जानकारी और जागरुकता का प्रसार करने के लिए प्रकाशन विभाग ने अपनी आउटरीच गतिविधियों के तहत, 24 जुलाई, 2018 को दिल्ली के बाहरी इलाके में एक गांव मांडी के जवाहर बाल भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया। बाल भवन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा समर्थित, इस कार्यशाला में गांव के बच्चों को आजादी मेरी नज़र में 'विषय पर कविताएं, स्लोगन, छोटे लेख लिखने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यशाला के बाद, इन बच्चों को 26 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली के सूचना भवन स्थित प्रकाशन विभाग की बुक गैलरी में आमंत्रित किया गया।

प्रकाशन विभाग ने कॉलेज के छात्रों और अकादमिक

माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ 2 अक्तूबर, 2018 को नई दिल्ली में मनाई जा रही महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में प्रकाशन विभाग के स्टॉल में

बिरादरी तक पहुंच बनाने के लिए दयाल सिंह कॉलेज (सायं), दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 8 अगस्त, 2018 को 'मेरे सपनों का भारत' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।

lwph izca/ku dk dEI;wVjhdj.k vkSj 0;kikj lca/kh vU; izfØ;kvksa dk dk;kZUo;u ¼lhvkbZ,e ifj;kstuk½ esa egRoiw.kZ lQyrk izkIr dh xbZA यह परियोजना नए दौर के पाठकों तक पहुंच बनाने और उन्हें उनकी पसंद के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सूचित और शिक्षित करने और बदलते प्रौद्योगिकीय और व्यवसायिक वातावरण के साथ तालमेल रखने के प्रकाशन विभाग के प्रयासों का केंद्र है। प्रकाशन विभाग ने वर्तमान में जारी इस परियोजना के अधिकांश महत्वपूर्ण पड़ाव पूरे कर लिए हैं। प्रकाशन विभाग के बिक्री केंद्रों में कम्प्यूटरीकृत बिलिंग के परीक्षण सहित इस ईआरपी परियोजना के सभी मॉड्यूल्स की शुरुआत की गई थी। प्रकाशन विभाग ने देशभर में अपनी पुस्तकों के पूरे स्टॉक की बार–कोडिंग भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रकाशन विभाग ने अपनी नई Mk;ukfed osclkbV और उसके डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सक्षम एप– fMftVy izdk'ku foHkkx को प्रारंभ किया है। इस नए वेब पोर्टल के माध्यम से, प्रिंट और ई–बुक दोनों को सीधे तौर पर ग्राहकों को बेचना संभव होगा। इसी तरह, डिजिटल प्रकाशन विभाग एप के माध्यम से, मोबाइल उपकरणों को ई–बुक्स के डिजिटल राइट्स बेचना और उनका प्रबंधन करना संभव होगा।

ckj&dksfMax vkSj lwph dk dk;Z iw.kZ djuk– प्रकाशन विभाग ने अपनी सीआईएम परियोजना के तहत पूरे देश में लगभग 15 लाख पुस्तकों के पूरे स्टॉक की बार–कोडिंग पूरी कर ली है। परियोजना के तहत दो अलग–अलग उप–परियोजनाएं शुरू की गईं – (1) सम्पूर्ण सूची का निर्माण करने के लिए मौजूदा स्टॉक की गिनती और (2) प्रत्येक शीर्षक के लिए विशिष्ट बार–कोड बनाना और उसको प्रत्येक प्रति पर चिपकाना। यह गहन परियोजना हर प्रकाशन विभाग के प्रत्येक कार्यालय में सफलतापूर्वक किया गया, ताकि प्रकाशन विभाग को एक विस्तृत सूची बनाने और ऑनलाइन बिलिंग शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके। यह परियोजना पूरी हो चुकी है और प्राप्त किए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान में प्रकाशन विभाग में 15 भाषाओं में 2364 लाइव टाइटल्स हैं। संपूर्ण स्टॉक की सफल बार–कोडिंग और कम्प्यूटरीकृत सूची से बड़े पैमाने पर डिजिटल मार्केटिंग में जाने का मार्ग प्रशस्त होगा और प्रकाशन विभाग वास्तविक आंकड़ों के आधार पर कारोबारी निर्णय लेने में समर्थ होगा।

dEI;wVjh—r fcfyax – कम्प्यूटरीकृत बिलिंग और इस तरह की बिलिंग का कम्प्यूटरीकृत सूची के साथ एकीकरण सीआईएम परियोजना की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। सभी प्रकाशन विभाग बिक्री केंद्रों में ऑनलाइन बिलिंग का प्रायोगिक परीक्षण पूरा हो चुका है। कम्प्यूटरीकृत मांगपत्र आदि के जरिए सूची के ऑनलाइन प्रबंधन जैसे सभी संबंधित कार्य भी पूरे हो चुके हैं।

परियोजना के अन्य मॉड्यूल जैसे पत्रिका प्रबंधन, लेखक प्रबंधन, शिकायत प्रबंधन और समग्र वित्तीय मॉड्यूल जैसे भी तैयार हैं और लाइव परीक्षण के लिए शुरू कर दिए गए हैं।

LoPNrk vfHk;ku

प्रकाशन विभाग में 16–18 जनवरी, 2019 को स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। शानदार प्रदर्शन के लिए प्रकाशन विभाग को मंत्रालय की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। प्रकाशन विभाग ने 15 सितम्बर – 2 अक्तूबर, 2018 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता संबंधी अनेक गतिविधियों का आयोजन किया। एक विशेष सफाई अभियान चला कर फीडर स्टोर, फरीदाबाद और करंट स्टोर, प्रकाशन विभाग मुख्यालय में पुरानी, गंदी और बिकने की हालत में न होने वाली किताबों का निपटान किया गया। पुस्तकों को फीडर स्टोर से करंट स्टोर दिल्ली लाया गया, ताकि उनका उचित भंडारण, प्रदर्शन और उनकी पुनर्प्राप्ति और पुस्तकों की ऑनलाइन बिक्री को सुगम बनाया जा सके। 15 सितंबर, 2018 को प्रकाशन विभाग के मुख्यालय में कर्मचारियों द्वारा श्रमदान का भी आयोजन किया गया। जिसके परिणामस्वरूप फीडर स्टोर में लगभग 6000 वर्ग फुट के 3 हॉल और सूचन भवन के नौ कमरे पूरी तरह से साफ किए गए। प्रकाशन विभाग में जनवरी, 2019 में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

lks'ky ehfM;k

प्रकाशन विभाग ने अपने फॉलोअर्स और संभावित पाठकों तक पहुंच बनाने के लिए सोशल मीडिया का कारगर ढंग से उपयोग किया है। राष्ट्रीय रुझानों का अनुसरण करते हुए प्रकाशन विभाग तथा रोज़गार समाचार के लिए फेसबुक तथा ट्विटर अकाउंट बनाए गए, दोनों ही कारगर रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रकाशन विभाग की सोशल मीडिया से उपस्थिति का परिणाम उत्साहजनक रहा और ट्विटर हैंडल प्रतिमाह 1,60,000 इंप्रेशन को पार कर गया तथा फेसबुक पर प्रतिमाह इंप्रेशन 3,60,000 हो गया।

QkVk iHkkx

1- ifjp;

भारत सरकार की विभिन्न गतिविधियों को फोटो कवरेज के जरिए विजुअल सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित फोटो प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक मीडिया इकाई है। अक्तूबर 1959 में स्थापित, फोटो प्रभाग शायद देश का एकमात्र संगठन है, जिसके पास स्वतंत्रता–पूर्व युग से लेकर वर्तमान समय तक का डिजिटल प्रारूप में 10 लाख से अधिक नेगेटिव्स/ट्रांसपेरेंसीज का संकलन है। इस प्रकार फोटो डिवीजन स्टिल फोटोग्राफ के प्रोडक्शन और भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो बेहद ऐतिहासिक महत्व के हैं।

फोटो प्रभाग सालभर में लगभग 4500–5000 समाचार और फ़ीचर कार्य कवर करता है। फोटोग्राफ स्वीकृत दरों पर आम जनता के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

प्रभाग ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे करने के अवसर पर साल 2010 में राष्ट्रीय फोटो पुरस्कारों की शुरुआत की। बीते वर्षों में इन वार्षिक पुरस्कारों ने फोटोग्राफी की कला को प्रोत्साहन देने और देश के विभिन्न पहलुओं, जैसे– कला, संस्कृति, विरासत, जनजीवन, समाज और इसकी परंपराओं आदि को देश के एमेच्योर और पेशेवर फोटोग्राफर्स की नज़रों विजुअल रूप से दर्ज करते हुए उन्हें संरक्षित करने के अपने दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया है।

युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ 19 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में 7वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में श्री अशोक द्विवेदी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित करते हुए

2- QkVk iHkkx dk dk;l

फोटो प्रभाग का प्रमुख कार्य देश के सामाजिक–आर्थिक विकास और राजनीतिक उपलब्धियों का चित्रों में दस्तावेजीकरण करना है और इनका प्रचार–प्रसार और अभिलेख करना है। इसके विशिष्ट कार्यों में शामिल हैं –

1. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों को विजुअल (चित्र) प्रदान करता है, ताकि उन्हें आगे मीडिया को प्रसारित किया जा सके।

क) पत्र सूचना कार्यालय का प्रेस फोटो प्रचार पूरी तरह फोटो प्रभाग द्वारा समर्थित है।

ख) ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन (बीओसी) प्रदर्शनी प्रकोष्ठ को लाइफ साइज प्रिंट्स और फोटो से जुड़ी अन्य

आवश्यकताओं की तैयारी में फोटो प्रभाग से सहायता मिलती है।

2. यह प्रभाग भारत के माननीय प्रधानमंत्री को विशेष कवरेज (365 दिन और चौबीसों घंटे) प्रदान करता है। प्रधानमंत्री के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के संबंध में व्यापक फोटो शूट किए जाते हैं। इसके बाद, पीएम के दौरे की तस्वीरों वाली विशेष एलबम तैयार की जाती हैं।

युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ 8 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में ''आकाशवाणी समाचार निजी एफएम प्रसारकों के साथ साझा करना'' के शुभारंभ को संबोधित करते हुए

3. माननीय राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, माननीय लोक सभाध्यक्ष, कैबिनेट मंत्रियों के कार्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक आयोजनों के लिए फोटो कवरेज प्रदान करना और उनका दस्तावेजीकरण करना।

4. वीवीआईपी, राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के दौरों को व्यापक कवरेज उपलब्ध कराने के संदर्भ में विदेश मंत्रालय के एक्सपी प्रभाग को सहायता प्रदान करना। प्रभाग की ओर से आने वाले गणमान्य व्यक्तियों की तस्वीरों वाला एक विशेष एलबम उन्हें प्रस्तुत किया जाता है।

5. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष अभियान चलाते हुए वहां की विकास संबंधी गतिविधियों का फोटोग्राफ के माध्यम से दस्तावेजीकरण करना।

6. गैर–प्रचार संगठनों, निजी प्रकाशकों और आम जनता को मूल्य निर्धारण योजना के अनुसार भुगतान के आधार पर तस्वीरें प्रदान करना।

3- lkxBfud <kpk

फोटो प्रभाग सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में स्थित है। इस विभाग के प्रमुख निदेशक (फोटो प्रभाग) हैं और उनके सहयोग के लिए उपनिदेशक, वरिष्ठ फोटोग्राफिक अधिकारी, फोटोग्राफिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य तकनीकी तथा अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं।

इसके अलावा, वरिष्ठ फोटोग्राफिक अधिकारी/फोटोग्राफिक अधिकारी और वरिष्ठ तकनीकी कर्मचारी उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को व्यापक फोटो कवरेज और फोटो प्रचार सामग्री प्रदान करने के लिए देश और विदेश की यात्राओं में उनके साथ आते हैं। फ़ोटोग्राफ़िक अधिकारी इन छवियों का उचित प्रलेखन भी करते हैं, इस प्रकार प्रभाग के फोटो अभिलेखागार को समृद्ध करते हैं।

4- QkVk iHkkx dk vk/kfudhdj.k

योजना स्कीम के दौरान प्रदर्शनी के लिए लाइफ साइज प्रिंट का प्रावधान करने हेतु बड़े फॉर्मेट इंकजेट फोटो प्रिंटर, वीवीआईपी एलबम की तैयारी के लिए बैक–टू–बैक प्रिंट बनाने के लिए विशेष डिजिटल फोटो प्रिंटर जैसे उपकरणों को अद्यतन करके फोटो प्रभाग की सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा, अभिलेखन, इंडेक्सिंग, कैटलॉगिंग और 8–10 लाख डिजिटल छवियों की पुनर्प्राप्ति के लिए एक उच्च क्षमता वाला सर्वर स्थापित किया गया है।

5- jk"Vªh; QkVkxkQh ijLdkj

प्रभाग ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे करने के अवसर पर साल 2010 में देश के एमेच्योर और पेशेवर फोटोग्राफर्स को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय फोटो पुरस्कारों की शुरुआत की। इससे देश की समृद्ध धरोहर, कला और संस्कृति के दस्तावेजीकरण को भी बढ़ावा मिला। प्रभाग अब तक 11 विख्यात फोटोग्राफर्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित कर चुका है।

6- vU; ehfM;k bdkbZ;ksa ls rkyesy

संबद्ध मीडिया इकाइयों की डिजिटल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए फोटो प्रभाग बदलते समय के साथ विकसित होता गया है। पत्र सूचना कार्यालय और संबंधित हितधारकों को फोटो भेजने में देरी से बचने के लिए प्रभाग का न्यूज़ फोटो नेटवर्क पूर्ण डिजिटल मोड पर काम कर रहा है। उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दौरे पर आए वीवीआईपी से संबंधित आयोजनों की कवरेज के लिए आयोजन स्थल से ही फोटो को डिजिटली ट्रांसमिट करने के लिए लैपटॉप और वी–डेटा कार्ड के साथ डिजिटल कैमरा उपकरण का उपयोग किया गया है। प्रदर्शनियों में इस्तेमाल के लिए लाइफ साइज डिजिटल इंकजेट इमेजेस प्रभाग बीओसी की जरूरत को पूरा करता है।

7 okf"kd ;kstuk 2018&19

12वीं योजना के दौरान, ''मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम' (एमआईडीपी) की योजना के तहत फोटो प्रभाग ने "नेशनल सेंटर ऑफ़ फ़ोटोग्राफ़ी (एनसीपी) और स्पेशल ड्राइव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन" उप योजना को कार्यान्वित किया है। इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक इंडेक्सिंग के लिए पुस्तकालय विज्ञान के पेशवरों की सेवाओं को आउटसोर्स करके डिजिटल फोटो लाइब्रेरी को सरल बनाना और आईटी पेशेवरों की सेवाओं से डिजिटल इमेजिस को उच्च क्षमता वाले सर्वर पर अपलोड करने और प्राप्त करने के उद्देश्यों की पूर्ति करना है। इससे प्रभाग आर्काइव्स में छवियों को बनाए रखने और पुनः प्राप्त करने में सक्षम होता है।

एनसीपी का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग वार्षिक रूप से राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार आयोजित करना है। देश के प्रतिष्ठित फोटोग्राफरों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड के साथ पुरस्कृत करने के अलावा प्रतिवर्ष छह पुरस्कार एमेच्योर और व्यावसायिक श्रेणी में दिए जाते हैं। प्रभाग अब तक देश के ग्यारह विख्यात फोटोग्राफर्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित कर चुका है।

युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ 19 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में 7वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए

प्रभाग ने 19 फरवरी, 2019 को देशभर के पेशेवर और एमेच्योर फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करने के लिए 7वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह का आयोजन किया है।

8- bl o"k dh xbl egRoi.k QkVk dojt

प्रभाग की गतिविधियों के अलावा, निम्नलिखित आयोजनों के फोटो दस्तावेजीकरण का कार्य किया गया :

mi jk"Vifr dk nkjs	
Hkkjr	fon's'k
अप्रैल 2018 के दौरान हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, बंगलुरु, आंध्र प्रदेश, गुवाहाटी, शिलांग, जोरहाट, कुरुक्षेत्र, हैदराबाद और देहरादून।	मई 2018 के दौरान ग्वाटेमाला, पनामा और पेरू

मई 2018 के दौरान चेन्नई, कोच्चि, केरल, रायपुर, भोपाल, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), दीमापुर (नगालैंड), अगरतला (त्रिपुरा), लेंगपुई, आइजोल (मिजोरम), हैदराबाद और जम्मू–कश्मीर।	सितंबर 2018 के दौरान अमेरिका
जून 2018 के दौरान बागडोगरा, असम, मुंबई, पुणे, बंगलुरु और कोलकाता	अक्तूबर, 2018 के दौरान बेल्जियम
जुलाई 2018 के दौरान हैदराबाद (तेलंगाना), पोर्ट ब्लेयर, पांडिचेरी, चेन्नई (तमिलनाडु), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), हैदराबाद (तेलंगाना) और उत्तराखंड।	नवंबर 2018 के दौरान अफ्रीका और फ्रांस
अगस्त 2018 के दौरान हैदराबाद, गुजरात, विजयवाड़ा, विजाग (आंध्र प्रदेश), भुवनेश्वर (ओडिशा), मैसूर, केरल, कर्नाटक।	
सितंबर 2018 के दौरान हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, जयपुर, झारखंड, गोवा, मुंबई, इलाहाबाद, ग्वालियर, आंध्र प्रदेश और जयपुर।	
अक्तूबर 2018 के दौरान महाराष्ट्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, बंगलुरु, तमिलनाडु, यूपी, जालंधर (ट्रांजिट हाल्ट), फगवाड़ा (पंजाब), गोवा और मुंबई।	
नवंबर 2018 के दौरान बंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और गुजरात।	
दिसंबर 2018 के दौरान बंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई।	
जनवरी 2019 के दौरान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, मुंबई, इलाहाबाद, नेल्लोर और चेन्नई।	

i/kkue=h ds nkSjs	
Hkkjr	fon'k
चौथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून, 2018	जून 2018 के दौरान चीन
नवंबर 2018 के दौरान राजस्थान	
राष्ट्राध्यक्षों / शासनाध्यक्षों के दौरे	
1. नेपाल के प्रधानमंत्री।	
2. सेशेल्स के राष्ट्रपति।	
3. कोरिया के राष्ट्रपति।	
4. मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति।	
5. भूटान के प्रधानमंत्री।	
6. दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति	

प्रत्येक यात्रा के पूरा होने पर, फोटो प्रभाग ने देश की यात्रा पर आने वाले वीवीआईपी को भारत से विदा होते समय सरकार की ओर से एक रंगीन एलबम भेंट किया।

9 ikMD'ku lca/kh vkadM+s

कवर किए गए कार्यक्रम, प्राप्त की गई छवियां, अपलोड किए गए प्रिंट्स, तैयार किये गए एल्बम्स इस प्रकार हैं :

1	कवर किए गए न्यूज़ और फ़ीचर असाइनमेंट्स	2193
2	पीआईबी की वेबसाइट पर भेजी गई / अपलोड की गई छवियां	6011
3	फोटो प्रभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई छवियां	6190
4	आंतरिक स्तर पर प्राप्त की गई डिजिटल छवियां	338690
5	बनाए गए / आपूर्ति किए गए डिजिटल प्रिंट	18947
6	तैयार की गईं वीवीआईपी एल्बम्स	27

10- jktHkk"kk dk dk;kZUo;u

फोटो प्रभाग मुख्यालय में अपने छोटे से कार्यालय में राजभाषा के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल है। लेखा और प्रशासन अनुभाग में बड़ी संख्या में फाइलों में सिर्फ हिंदी में काम होता है। प्रभाग ने हिंदी में कई गतिविधियां की हैं। सितंबर 2018 में हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

11- Lohd`r ctV

(हजारों में)

			O;;	
o"kZ	LFkkiuk O;;	dEI;wVj {k= dh ;kstuk	LFkkiuk O;; **(January 2019)**	dEI;wVj {k= dh ;kstuk
2018–2019	46100	13300	38690 रुपये	6521

12- o"kZ 2018 ds fy, lrdZrk dk;Z dh okf"kZd fjiksVZ

1	संगठन में मुख्यालय और फील्ड कार्यालयों में सतर्कता ढांचे का विवरण	सतर्कता से संबंधित कार्य के लिए अलग से कोई कर्मचारी अनुमोदित नहीं किए गए हैं। हालांकि, वरिष्ठ अधिकारी आम तौर पर ऐसे मामलों का निपटारा अपने अधीनस्थों की सहायता से करते हैं।
2	इस समयावधि में की गई निवारक सतर्कता गतिविधियां :	
	i) इस अवधि के दौरान किए गए सामान्य निरीक्षणों की संख्या :	4
	ii) इस अवधि के दौरान किए गए औचक निरीक्षणों की संख्या :	2
3	इस अवधि में की गईं निगरानी एवं पता लगाने की गतिविधियां :	
	i) निगरानी के लिए लिए चुने गए क्षेत्रों का विवरण	सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण जहां। प्रोडक्शन कार्य किया गया।
	ii) निगरानी में रखने के लिए चिन्हित किए गए व्यक्तियों की संख्या	शून्य
4	दंडात्मक गतिविधियां [4(1) से (x) के विपरीत संख्या इंगित की जाएगी, जहां नियोक्ता प्राधिकारी राष्ट्रपति के अलावा कोई अन्य है] :	
	i) इस अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें/संदर्भ	शून्य
	ii) कितने मामलों में शुरुआती जांच की गई	शून्य
	iii) कितने मामलों में शुरुआती जांच की रिपोर्ट प्राप्त हुई	शून्य
	iv) कितने मामलों में बड़े जुर्माने के लिए आरोप पत्र जारी किए गए	शून्य
	v) कितने मामलों में छोटे जुर्माने के लिए आरोप पत्र जारी किए गए	शून्य
	vi) कितने लोगों पर बड़ा जुर्माना लगाया गया	शून्य
	vii) कितने लोगों पर छोटा जुर्माना लगाया गया	
	viii) कितने लोगों को निलंबित किया गया	शून्य
	ix) कितने लोगों के ख़िलाफ़ प्रशासनिक कार्रवाई, मसलन–चेतावनी आदि जारी की गई	
	x) नियम के उपयुक्त प्रावधानों के तहत कितने लोगों को समय से पहले सेवानिवृत्त किया गया	

Hkkjrh; tu&lapkj lLFkku

1-1 ifjp;

भारतीय जन–संचार संस्थान (आईआईएमसी) 17 अगस्त, 1965 को अस्तित्व में आया। यह संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत संस्था है। इस संस्थान की स्थापना जन–संचार के क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण और उपक्रम अनुसंधान के मूल उद्देश्य के साथ की गई थी।

शुरुआत के समय इस संस्थान में निदेशक के अलावा चार प्रोफेसर और यूनेस्को का एक परामर्शदाता थे। 52 वर्षों में इस संस्थान ने आधुनिक दौर में तेजी से विकसित और परिवर्तित होते मीडिया की विविधतापूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक विशेष पाठ्यक्रमों की शुरुआत की है।

1-2 'k{kf.kd ,oa if'k{k.k xfrfof/k;k

भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के अलावा आईआईएमसी प्रिंट पत्रकारिता, रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता और विज्ञापन एवं जनसंपर्क में निम्नलिखित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है :

1. हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दिल्ली
2. अंग्रेजी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दिल्ली, ढेंकनाल, आइजोल, अमरावती, जम्मू और कोट्टायम
3. विज्ञापन और जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दिल्ली
4. रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दिल्ली
5. उर्दू पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दिल्ली
6. ओड़िया पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, ढेंकनाल, ओडिशा
7. मलयालम पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, कोट्टायम, केरल,
8. मराठी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम अमरावती, महाराष्ट्र,
9. संस्कृत पत्रकारिता में उच्च प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, दिल्ली।

2018–19 के दौरान डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए कुल छात्रों की संख्या 430 है, जिन्हें 6,000 से अधिक उम्मीदवारों द्वारा दी गई राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चुना गया है।

आईआईएमसी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से एशियाई, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और पूर्वी यूरोपीय देशों के मध्यम स्तर के श्रमजीवी पत्रकारों के लिए विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। यह

17 सितंबर, 2018 को राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा के ट्रेनी अफ़सरों के साथ भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द

पाठ्यक्रम चार महीने की अवधि का होता है, जो साल में दो बार– जनवरी से अप्रैल तथा अगस्त से नवंबर में संचालित किया जाता है और प्रत्येक बैच में 25 प्रतिभागी होते हैं।

एक सप्ताह से चार सप्ताह तक की अवधि वाले, विशेष रूप से रक्षा अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के लिए और विभिन्न मीडिया, प्रचार और परिचालन संगठनों तथा केंद्र और राज्य सरकारों, साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले संचार पेशेवरों की बढ़ती प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विशेष अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी चलाए किए जाते हैं। जुलाई 2018 में भारतीय सेना के जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के लिए वीडियोग्राफी में एक लघु पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था।

2017 के बाद से, आईआईएमसी ने स्क्रीन राइटिंग, एक्टिंग, डिजिटल सिनेमैटोग्राफी आदि में लघु पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए फ़िल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, (एफटीआईआई), पुणे के साथ हाथ मिलाया है। आईआईएमसी के दिल्ली परिसर में अप्रैल–अक्तूबर 2018 के बीच डिजिटल सिनेमैटोग्राफी में दो पाठ्यक्रम, एक–एक पाठ्यक्रम अभिनय, टीवी के लिए कथा लेखन और स्क्रीन लेखन के लिए संचालित किए गए।

Hkkjrh; lwpuk lsok

आईआईएमसी ने भारतीय सूचना सेवा के ग्रुप ए और ग्रुप बी के 500 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। वर्ष के दौरान, भारतीय सूचना सेवा 2017 बैच के 19 ग्रुप ए अधिकारी आईआईएमसी में प्रवेश के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आईआईएस प्रशिक्षण को बदलते मीडिया परिवेश के अनुरूप संशोधित और व्यवस्थित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय सूचना सेवा के 6 ग्रुप बी अधिकारियों ने वर्ष के दौरान अपने 6 महीने का ओरिएंटेशन प्रशिक्षण पूरा किया।

वर्ष के दौरान, आईआईएमसी ने 6 से 15 अगस्त, 2018 तक भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ और मध्य–स्तर के अधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए गोल्डमैन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले, अमेरिका के साथ समन्वय किया। अक्तूबर–नवंबर 2018 के दौरान थॉमसन फाउंडेशन, लंदन, यूके के सहयोग से पहली बार 2016 बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए फॉरेन कंपोनेंट ट्रेनिंग शामिल की गई।

vkbZvkbZ,elh dk ;ksxnku

आईआईएमसी देश में प्रशिक्षित संचार पेशेवरों को तैयार करने में अग्रणी रहा है। आज तक 8,000 से अधिक छात्र आईआईएमसी के स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं और आईआईएमसी के अनेक पूर्व छात्रों ने मीडिया और सार्वजनिक संचार क्षेत्र में नेतृत्व के पदों पर आसीन होकर खुद के लिए विशेष स्थान बनाया है, ने 128 देशों के 1600 से अधिक विदेशी नागरिकों को भी प्रशिक्षित किया है।

ledkyhu pukfr;ksa dk çHkkoh <x ls lkeuk djus ds fy, vkbZvkbZ,elh f'k{kkfonksa vkSj m|ksx ds fo'ks"kKksa dh enn ls viuus ikBîØe ds ikB;fo’k;ksa dks yxkrkj lq'kksfèkr dj jgk gSA ;g laLFkku lapkfyr fd, tk jgs ikB;Øeksa dk ckt+kj vkSj lekt dh t:jrksa ds vuq:Ik çHkkoh 'kSyh cukus esa l{ke cukrk gSA vkÃvkÃ,elh dh le) ikBî lkexzh vkSj m|ksx mUeq[k –f"Vdks.k us mls çeq[k lekpkj&i=ksa vkSj if=dkvksa }kjk çdkf'kr fofHkUu lo{k.kksa esa ns'k esa ehfM;k vkSj lapkj laLFkku ds uacj 1 jSad ij yxkrkj cus jgus esa enn dh gSA

1-3 lapkj vuqlèkku

आईआईएमसी एशिया का पहला संस्थान है, जिसके पास विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए अनुसंधान/विश्लेषण और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने वाला एक समर्पित संचार अनुसंधान विभाग है। अनुसंधान मुख्य रूप से सरकारी अभियानों, प्रभाव विश्लेषण, प्रतिक्रिया आदि पर ध्यान केंद्रित करता है, सरकारी अभियानों और संचार कार्यक्रमों की कार्यनीति तैयार करने के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करता है, ताकि लोगों तक उनकी प्रभावी और व्यापक पहुंच संभव हो सके।

वर्ष 1965 से मंत्रालयों और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों आदि के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के मसलों, ग्रामीण विकास, उपभोक्ता संरक्षण आदि जैसे विभिन्न विषयों और थीम्स के बारे में 200 अधिक शोध और मूल्यांकन अध्ययन संपन्न किए

माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू आईआईएमसी नई दिल्ली में 20 मार्च, 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक भाषण को संबोधित करते हुए

जा चुके हैं। वर्तमान में, आईआईएमसी 'मीडिया में महिलाओं की भूमिका' विषय पर 9 देशों के यूनेस्को प्रोजेक्ट के प्रमुख सहयोगी के रूप में काम कर रहा है।

1-4 lkeqnkf;d jsfM;ks dk fodkl

आईआईएमसी के पास एक समर्पित सामुदायिक रेडियो सशक्तीकरण एवं संसाधन केंद्र' है, जिसकी स्थापना दो साल पहले कार्यरत और महत्वाकांक्षी सामुदायिक रेडियो पेशेवरों को विषय वस्तु, प्रौद्योगिकी और संसाधनों के सृजन का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गई थी।

आईआईएमसी के परिसर में सामुदायिक रेडियो–'अपना रेडियो' भी है, जो इसको और साथ–साथ स्थानीय समुदाय को व्यावहारिक संपर्क प्रदान करने के जरिए संचार के इस अत्यधिक प्रभावी माध्यम के विकास और प्रसार को बढ़ावा देता है। आईआईएमसी इसको एक आदर्श सामुदायिक रेडियो स्टेशन के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया में है।

1-5 lapdk; fodkl

मीडिया शिक्षा, अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करने के आईआईएमसी के विज़न के अनुरूप, यहां राष्ट्रीय मीडिया संकाय विकास केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र का उद्घाटन तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने 27 अप्रैल, 2018 को किया था।

1-6 çdk'ku

आईआईएमसी की प्रतिष्ठित समकक्ष समीक्षित पत्रिकाओं यथा– अंग्रेजी में 'कम्युनिकेटर' और हिंदी में 'संचार माध्यम' को दुनियाभर से पांडुलिपियां आमंत्रित करके त्रैमासिक रूप से निकाला जा रहा है। आईआईएमसी, संस्थान के सभी परिसरों की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए त्रैमासिक न्यूज़लेटर 'आईआईएमसीअन' भी निकाला जा रहा है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी 29–30 अक्तूबर, 2018 को ''भारतीय भाषायी पत्रकारिता की स्थिति और प्रशिक्षण' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर 'संचार माध्यम' का ताजा संस्करण प्रस्तुत करते हुए

1-7 ehfM;k ykbczjh

संस्थान के पास देश में मीडिया और जनसंचार प्रकाशनों का सबसे विशाल और विशिष्ट पुस्तकालय है। इसके पास जनसंचार और प्रिंट मीडिया, प्रसारण, विज्ञापन, संचार, संचार अनुसंधान, जनसंपर्क, रेडियो और टेलीविजन, फ़िल्म सूचना प्रौद्योगिकी और पारंपरिक मीडिया जैसे संबद्ध विषयों के विभिन्न पहलुओं पर पुस्तकों और जिल्दबंद पत्रिकाओं के 40,000 से अधिक संस्करणों का संग्रह है।

1-8 vkÃvkÃ,e lh & {k=h; foLrkj

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियों की बढ़ती लोकप्रियता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से, 1993 में आईआईएमसी ने ढेंकनाल, ओडिशा में एक क्षेत्रीय केंद्र खोला। वर्तमान में, ढेंकनाल क्षेत्रीय केंद्र दो पाठ्यक्रमों का संचालन करता हैः अंग्रेजी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और ओडिया पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

संस्थान के विस्तार का अगला चरण 2011–12 और 2012–13 में हुआ। 2011 में, आईआईएमसी के दो नए क्षेत्रीय परिसर आइजोल (मिजोरम) और अमरावती (महाराष्ट्र) में खोले गए। 2012 में, आईआईएमसी के दो और क्षेत्रीय परिसर जम्मू (जम्मू–कश्मीर) और कोट्टायम (केरल) में खोले गए। इन चारों नए क्षेत्रीय परिसरों ने शुरुआत अंग्रेजी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के साथ की और 2017 में क्षेत्रीय परिसर अमरावती ने मराठी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और क्षेत्रीय परिसर कोट्टायम ने मलयालम पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया।

1-9 vkbvkbZ,e lh dk MhEM fo'ofo|ky; dk n tk

संचार प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर देने सहित देश में एक "संचार विश्वविद्यालय" स्थापित करने की दृष्टि से आईआईएमसी ने 'डी–नोवो श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' के लिए आवेदन किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने मई 2018 में आईआईएमसी की बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण किया और आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी। यूजीसी की सिफारिश के आधार पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अगले तीन वर्षों के भीतर आवश्यक शर्तों को पूरा करने की शर्त पर डी–नोवो श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का आशय पत्र आईआईएमसी को जारी किया है।

1-10 o"kZ d nkjku çe[k xfrfofèk;k

आईआईएमसी ने 7–8 अप्रैल, 2018 को डेटा विश्लेषण विषय पर बॉलिंग ग्रीन यूनिवर्सिटी, ओहायो, अमेरिका के प्रो. श्रीनिवास मेलकोटे द्वारा संचालित दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

अप्रैल 2018 में यूनिसेफ और थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन, यूके के सहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी संवाददाताओं के लिए महत्वपूर्ण मूल्यांकन कौशलों पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया।

यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डिफ़, वेल्स, ब्रिटेन के प्रो. मैथ्यू स्वाइन ने 11 अप्रैल, 2018 को मल्टी मीडिया और डिजिटल स्टोरी टेलिंग के लिए कार्यनीतियां विषय पर एक मास्टर क्लास का आयोजन किया।

साउथ एशिया वूमंस नेटवर्क और यूनेस्को के सहयोग से क्षेत्रीय प्रशिक्षण और परामर्श "वूमन फॉर चेंज : बिल्डिंग अ जेंडर्ड मीडिया इन साउथ एशिया" पर संयुक्त रूप से क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया।

आईआईएमसी ने 10–12 मई, 2018 को 15 वें एशियाई मीडिया शिखर सम्मेलन की सह–मेजबानी की।

सुश्री लिंडा रोथ, वाइस प्रेसिडेंट, विल्सन सेंटर, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका ने अगस्त 2018 के दौरान आईआईएमसी दिल्ली परिसर में दो सप्ताह का शिक्षण कार्य किया।

मॉरीशस में 18–20, अगस्त, 2018 को आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में श्री के जी सुरेश, महानिदेशक, आईआईएमसी ने संस्थान का प्रतिनिधित्व किया। वह सम्मेलन की स्मारिका के संपादकीय बोर्ड के सदस्य भी थे।

सुश्री कैम्बेल ब्राउन, ग्लोबल हेड, न्यूज़ पार्टनरशिप्स, फेसबुक ने संस्थान में फेसबुक न्यूज़ लैब स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आईआईएमसी प्रबंधन के साथ बातचीत की।

संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ भागीदारी कर 'मानव अधिकारों के बारे में जागरुकता फैलाने में मीडिया की भूमिका' विषय पर एक संगोष्ठी और पैनल चर्चा आयोजित की।

आईआईएमसी के तत्वावधान में 29–30 अक्तूबर, 2018 को भारतीय भाषायी पत्रकारिता और प्रशिक्षण पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। भारतीय सामाजिक विज्ञान और अनुसंधान परिषद, आईसीएसएसआर द्वारा समर्थित यह संगोष्ठी, समस्त माध्यमों में भारतीय भाषायी पत्रकारिता से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित थी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इसमें मुख्य अतिथि थे।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सहयोग से 31 अक्तूबर–1 नवंबर, 2018 को जैव विविधता पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

1-11 'kkl h lajpuk

संस्थान एक सोसाइटी द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसका गठन द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। सोसाइटी में 50 सदस्य हैं। सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक सेवा संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक जीवन के प्रख्यात व्यक्तियों आदि में से मनोनीत किया जाता है। मनोनीत सदस्यों के अलावा, इस सोसाइटी में सूचना एवं

प्रसारण मंत्रालय, उसकी मीडिया इकाइयों और राज्य सरकारों के सूचना विभागों आदि के पदेन सदस्य होते हैं।

आईआईएमसी के महानिदेशक श्री के. जी. सुरेश मुख्य अतिथि, भारत के निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और सम्मानित अतिथि, उज्बेकिस्तान के राजदूत श्री फर्होद अरज़ीव का स्वागत करते हुए

सोसाइटी के कार्य व्यवहार के संचालन का दायित्व कार्यकारी परिषद को सौंपा गया है, जिसमें 15 सदस्य शामिल हैं। कार्यकारी परिषद के सदस्यों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के अलावा, शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधि, सार्वजनिक जीवन और आईआईएमसी के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं।

आईआईएमसी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सहायता अनुदान के रूप में धनराशि प्राप्त होती है, जो जन–संचार में प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुसंधान, भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण, केंद्र और राज्य स्तरीय योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई वास्तविक और वित्तीय प्रगति के तहत उसके प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए वार्षिक कार्ययोजना से संबंधित समझौता ज्ञापन पर आधारित है।

आईआईएमसी के पास वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान अन्य केंद्रीय व्यय के लिए 25.74 करोड़ रुपये (5.35 करोड़ रुपये का आंतरिक राजस्व जुटाने सहित) का बजट परिव्यय है और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 16.15 करोड़ रुपये (15 लाख रुपये आंतरिक राजस्व उत्पादन सहित)।

1-12 vkbZvkbZ,elh esa dsaæh; {ks= dh ;kstuk,a dh fLFkfr%

आईआईएमसी में केंद्रीय क्षेत्र की दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं: –

1. आईआईएमसी को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत बनाना
2. आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्रों का उद्घाटन

केंद्रीय क्षेत्र की योजना ^vkbZvkbZ,elh dk varjjk"Vh; ekudksa ds vuq:i mUur cukuk^ में नई दिल्ली और ढेंकनाल में नई इमारतों के निर्माण के साथ–साथ नई दिल्ली में मौजूदा मुख्य भवन और लेक्चर ब्लॉक में अतिरिक्त मंजिल का निर्माण शामिल है। ढेंकनाल में नई इमारतों का निर्माण और नई दिल्ली में मौजूदा भवन में अतिरिक्त मंजिल का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। दिल्ली में नई इमारतों के निर्माण को विनियामक मंजूरी मिलना बाकी है।

केंद्रीय क्षेत्र की योजना ^vkÃvkÃ,elh ds u, {ks=h; dsæksa dk mn~?kkVu^ को 12वीं योजना में 'आइजोल (मिजोरम), अमरावती (महाराष्ट्र), जम्मू (जम्मू–कश्मीर) और कोट्टायम (केरल) में स्थायी परिसरों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी।

आइजोल और कोट्टायम में स्थायी परिसरों के निर्माण का कार्य 80–90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। जम्मू परिसर में चारदीवारी का निर्माण कार्य 280 हो चुका है, जबकि अमरावती में आवश्यक निवेश से पूर्व गतिविधियां की गई हैं।

Hkkjrh; çsl ifj"kn

ifjp;

भारतीय प्रेस परिषद संवैधानिक अर्ध–न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है, जिसे संसद के एक कानून प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने तथा भारत में समाचार–पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बरकरार रखने व उसे सुधारने के दोहरे कार्यों की पूर्ति करने के लिए 1979 में पुनःस्थापित किया गया।

यह परिषद शाश्वत उत्तराधिकार वाली संस्था है। परिषद में एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। परिपाटी के अनुसार, इसके अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के वर्तमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें एक समिति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिसके सदस्यों में राज्य सभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और परिषद के सदस्यों के बीच से चुना गया एक व्यक्ति शामिल होता है। इसके 28 सदस्यों में से 20 विशेषतौर पर प्रेस के निर्धारित खंड का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा इसके 8 अन्य सदस्य– संसद के दोनों सदनों तथा देश के प्रमुख साहित्यिक एवं विधिक निकायों यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधि परिषद तथा साहित्य अकादमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होती है।

अधिनियम की धारा 13 में सम्मिलित किए गए प्रेस परिषद के उत्तरदायित्वों में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और

समाचार–पत्रों व समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखना तथा उसमें सुधार लाना शामिल है। यह अधिनियम परिषद सलाहकार की भूमिका भी प्रदान करता है, जिसके तहत यह या तो स्वयं संज्ञान लेकर या कानून की धारा 13(2) के तहत सरकार द्वारा संदर्भित किए जाने पर वह प्रेस से संबंधित किसी भी विधेयक, विधान, कानून या अन्य मामलों का अध्ययन करती है और उनके बारे में सरकार को या अन्य संबद्ध व्यक्ति को अपनी राय से अवगत कराती है। सार्वजनिक महत्व के मामलों में भी, परिषद अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों तहत स्वतः संज्ञान ले सकती है और मौके पर जांच करने के लिए विशेष समिति का गठन कर सकती है।

शिकायतों के मामलों में परिषद –चाहे वे प्रेस के खिलाफ पत्रकारिता के आदर्शों के उल्लंघन की शिकायत हो या प्रेस द्वारा अपनी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप की शिकायत हो, अधिनिर्णय के माध्यम से प्रमुख रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करती है। जांच के बाद यदि परिषद इस बात पर आश्वस्त हो जाती है कि किसी समाचार–पत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकारिता के आदर्शों के मानकों या लोक रुचि का उल्लंघन किया है अथवा किसी संपादक या श्रमजीवी पत्रकार ने कोई पेशेवर कदाचार किया है, तो परिषद उन्हें चेतावनी दे सकती है, डांट सकती है या उनकी भर्त्सना कर सकती है या उनके आचरण की निंदा कर सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में परिषद के पास यह अधिकार है कि वह प्रेस की स्वतंत्रता में बाधक सरकार सहित किसी भी संस्था के आचरण पर अपनी टिप्पणी कर सकती है। धारा (4) के तहत परिषद के निर्णय अंतिम होते हैं और न्यायालय में इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती।

संसद के एक अधिनियम के तहत गठित होने के कारण परिषद को अपने कोष का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार से अनुदान सहायता के रूप में संसद द्वारा उचित विनियोजन के बाद प्राप्त होता है, क्योंकि समाचार–पत्रों से ग्रेडेड या श्रेणीबद्ध संरचना के तहत एकत्र की जाने वाली फीस और अन्य प्राप्तियों के माध्यम से इसके पास अपना धन भी होता है।

ifj"kn d le{k f'kdk;r

समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल, 2018 से 30 नवंबर, 2018 तक के दौरान, परिषद में कुल 558 शिकायतें पहुंचीं। इनमें से, 136 शिकायतें प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए सरकार के अधिकारियों के खिलाफ प्रेस द्वारा की गई थीं और 422 शिकायतें पत्रकारिता के आदर्शों के उल्लंघन के लिए को प्रेस के खिलाफ की गई थीं। पिछले वर्ष से लंबित 779 मामलों सहित परिषद को कुल 1337 मामलों का निपटान करना था। इनमें से, 815 मामलों को या तो अधिनिर्णय के माध्यम से या अध्यक्ष की मध्यस्थता से हुए समझौते पर अध्यक्ष द्वारा संक्षिप्त निपटान के माध्यम से या पूछताछ के लिए पर्याप्त आधार न होने या गैर–अनुपालन के कारण; मामला वापस लेने या विचाराधीन होने के कारण वर्ष के दौरान निपटाया गया। इनमें से 522 मामलों में से दो मामलों को अधिनिर्णय के लिए सीधे परिषद के समक्ष रखा गया था। वर्ष के अंत में कुल मिलाकर 520 मामलों पर कार्रवाई की जा रही थी।

ijke'knk;h dk;l

परामर्शदाता की हैसियत से परिषद ने सरकार और अन्य अधिकारियों को विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय प्रदान की है।

परिषद ने निम्नलिखित मामलों में मीडियाकर्मियों के खिलाफ हिंसा और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरे की घटनाओं का संज्ञान लिया :

1. ईटानगर पुलिस द्वारा डॉनलिट पोस्ट के संपादक और प्रकाशक को तलब किया जाना
2. पश्चिम बंगाल में पत्रकारों पर हमला
3. छत्तीसगढ़ में भूंकाल समाचार के संपादक/पत्रकार, श्री कमल शुक्ला, के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना।
4. वरिष्ठ पत्रकार श्री मोहम्मद सुभान तेलंगाना पुलिस द्वारा गिरफ्तारी।
5. वरिष्ठ पत्रकार और राइजिंग कश्मीर के प्रधान संपादक श्री शुजात बुखारी की हत्या।
6 कश्मीर ऑब्जर्वर, के रिपोर्टर श्री आबिक जावेद, की 6 जुलाई, 2018 को एनआईए द्वारा गिरफ्तारी
7. पंजाब पुलिस मुख्यालय में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध।
8. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास प्राधिकरण द्वारा एक पत्रकार के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करना।
9. झारखंड में आज के पत्रकार चंदन तिवारी की मृत्यु।
10. झारखंड में 15.11.2018 को पत्रकारों पर हमला
11. द हिंदू के पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार।

çl vkj ithdj.k vihyh; cksM

प्रेस और पंजीकरण कानून, 1867 की धारा 8सी भारतीय प्रेस परिषद को धारा 6 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए घोषणा पत्र के अप्रमाणन के आदेश अथवा उक्त कानून की धारा 8बी के तहत उसको रद्द करने के आदेश पर अपील की सुनवाई का अधिकार प्रदान करती है। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है और एक अन्य सदस्य होता है, जिसको भारतीय प्रेस

परिषद अपने सदस्यों में से नामित करती है।

दो बेंच बोर्ड में माननीय अध्यक्ष श्री यू सी शर्मा/वैकल्पिक सदस्य के तौर पर प्रो. सुषमा यादव के साथ शामिल थे, ने 1 अप्रैल, 2018 से 30 नवंबर, 2018 के बीच 3 बैठकें कीं और 7 अपीलों पर सुनवाई की गई, 3 का निपटान किया गया और 4 को खारिज कर दिया।

jk"Vh; çsl fnol 2018

राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल आयोजित किया जाता है। इस साल देशभर में चर्चा विषय 'डिजिटल दौर में पत्रकारिता के आदर्श और चुनौतियां' रखा गया था। तीन देशों अर्थात बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की प्रेस परिषदों ने उपरोक्त विषय पर हुई पैनल चर्चाओं में भाग लिया।

मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि, वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री, श्री अरुण जेटली ने किया। इस अवसर पर इस विषय पर अपने विचार साझा करते हुए श्री जेटली ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, "यदि आपातकाल को फिर से लागू किया गया, तो यह बहुत साधारण कारण से विफल रहेगी, क्योंकि आपातकाल की एक ताकत प्रेस सेंसरशिप थी और प्रौद्योगिकी आज प्रेस सेंसरशिप की अनुमति नहीं देती"।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारतीय प्रेस परिषद मीडिया पर नियंत्रण को बढ़ावा नहीं देती और अपेक्षा करती है कि मीडिया स्वतंत्र हो, लेकिन जिम्मेदारी के साथ कार्य करे। उन्होंने कहा कि "पहले अच्छी ख़बरें या बुरी ख़बरें होती थीं, लेकिन अब हमारे पास फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ हैं।" उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि "डिजिटल युग के विकास के साथ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करना और अधिक गोपनीय हो गया है।" वास्तविक समाचारों और फर्जी समाचारों (रियल न्यूज़ और फेक न्यूज़) के बीच का अंतर धुंधला गया है।"

इस अवसर पर पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2018 के निर्णायक मंडल के संयोजक और भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य श्री अमर देवुल्लापल्ली ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि पत्रकारिता के पेशे को दो ज्वलंत मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है और वे हैंः (1) स्वतंत्र और आदर्शवादी पत्रकारिता के लिए खतरा, (2) पत्रकारों की सुरक्षा। उन्होंने यह भी कहा कि एक रिपोर्ट से पता चला है कि काम के दबाव संबंधी बीमारियों के कारण 2014 के बाद से 218 पत्रकारों की मृत्यु हो गई। उन्होंने केंद्र सरकार से मुद्दों पर कठोर कदम उठाने का अनुरोध किया।

इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। देशभर से प्राप्त प्रविष्टियों में से 'राजा राम मोहन रॉय' पुरस्कार, श्री राम को दिया गया, 'ग्रामीण पत्रकारिता' सुश्री रूबी सरकार और श्री राजेश परशुराम जोस्टे ने साझा किया। 'विकासात्मक रिपोर्टिंग' के लिए श्री वीएस राजेश, 'फोटो पत्रकारिता–सिंगल न्यूज़ पिक्चर' के लिए श्री सुभाष पॉल, 'फोटो फ़ीचर' के लिए श्री मिहिर सिंह', बेस्ट न्यूज़पेपर आर्टः कवरिंग कार्टून्स, कैरिकेचर और इलस्ट्रेशन' के लिए श्री पी. नरसिंहा को दिया गया। इस अवसर पर देशभर के श्रेष्ठ नामित नेताओं के सद्भावना संदेशों साथ–ही–साथ विवेचना के विषय पर मीडिया विशेषज्ञों पेशेवरों और शिक्षाविदों की राय वाली एक स्मारिका भी जारी की गई।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2018 के समारोह को यादगार बनाने के लिए 'नॉर्म्स ऑफ़ जर्नलिस्टिक कंडक्ट' का एक अद्यतन संस्करण भी जारी किया गया।

vrjjk"Vh; lid@le>kSrk Kkiu

इसके इतर भारतीय प्रेस परिषद ने श्रीलंका की प्रेस परिषद के साथ द्विपक्षीय समझौते (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए और नेपाल की प्रेस परिषद के साथ इस समझौते का नवीकरण किया गया। यह समझौता देशों के बीच पांच साल की अवधि के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने पर केंद्रित था।

देशभर में विभिन्न प्लेटफार्म्स पर विचार–विमर्श किए गए और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया द्वारा उनको व्यापक रूप से कवर किया गया था।

नई दिल्ली में 29 जून, 2019 को क्षेत्रीय मीडिया इकाइयों (आरएनयू) की एक वर्कशॉप को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे। प्रसार भारती के चेयरमैन डॉ. ए. सूर्य प्रकाश तथा अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे

5 çlkj.k {k= dh xfrfof/k;k

प्रसारण क्षेत्र को मोटे तौर पर दो श्रेणियों 'सामग्री या कॉन्टेंट' और 'कैरिज सेवाओं' में बांटा जा सकता है। प्रसारण कैरिज सेवाओं में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)/लोकल केबल ऑपरेटर्स (एलसीओ), डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) ऑपरेटर्स, हैडएंड इन द स्काई (हिट्स) ऑपरेटर्स और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा प्रदाता शामिल हैं।

Mk;jDV V gke ¼MhVh,p½

डीटीएच एक एक्सेसेबल प्रणाली है और यह पूरे देश को कवर करती है। डीटीएच सेवा में, बड़ी संख्या में टेलीविजन चैनलों को डिजिटल रूप से संपीड़ित या कम्प्रेस्ड, इनक्रिप्ट किया जाता है और केयू बैंड में बेहद हाई पावर सेटेलाइट्स या उच्चशक्ति उपग्रहों से प्रसारित किया जाता है। डीटीएच के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रम इमारतों में सुविधाजनक स्थानों पर छोटे डिश एंटेना स्थापित करके सीधे घरों में प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रथम डीटीएच सेवा प्रदाता ने अपनी सेवाओं का संचालन 2003 को शुरू किया था और वर्ष 2007 तक निजी डीटीएच सेवा प्रदाताओं की संख्या छह तक पहुंच गई। तब से छह निजी डीटीएच सेवा प्रदाताओं में से दो का विलय हो गया, वर्तमान में निजी डीटीएच सेवा प्रदाताओं की संख्या घटकर पांच रह गई है। इसके अलावा दूरदर्शन भी फ्री–टू–एयर आधार पर डीटीएच सेवाएं प्रदान करता है।

इस मंत्रालय ने मैसर्स भारती टेलीमेडिया लिमिटेड के संबंध में, लगभग 2,150 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एडडीआई) को मंजूरी प्रदान की है, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी निवेशक मैसर्स लायन मीडो इंवेस्टमेंट लिमिटेड द्वारा उसके 20 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया गया है।

eYVh flLVe v,ijVj

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) का आशय ऐसे केबल ऑपरेटर से है, जो प्रसारणकर्ता से प्राप्त की गई प्रोग्रामिंग सेवा का पुनःप्रसारण अथवा अपनी प्रोग्रामिंग सेवाओं का प्रसारण समकालिक रिसेप्शन या प्राप्ति के लिए सीधे तौर पर या लोकल केबल ऑपरेटर्स (एलएसओ) के माध्यम से विविध ग्राहकों को करता है। एमएसओ सामग्री के लिए प्रसारणकर्ताओं पर और कनेक्टीविटी व सबस्क्रीप्शन राजस्व संग्रहण के लिए एलसीओ पर मध्यवर्ती रूप से निर्भर करता है। एमएसओ उपग्रह से प्रसारक के सिग्नलों को डाउनलिंक करने, और इंक्रिप्टेड चैनलों को डिक्रिप्ट करने और एलसीओ को विविध चैनलों के फीड का पुलिंदा उपलब्ध कराने में भूमिका निभाता है। एमएसओ, एलसीओ के रूप में कार्य कर सकता है और ग्राहकों को सीधे तौर पर सिग्नल उपलब्ध करा सकता है। भारतीय बाज़ार में इस समय लगभग 6,000 एमएसओ मौजूद हैं, इनमें से 1,471 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत हैं।

gM,M bu n Ldkb ¼fgV1½

हेडएंड इन द स्काई (हिट्स) सेवा उपग्रह और केबल टीवी का मिश्रण है। हिट्स ऑपरेटर टीवी प्रसारण को उपग्रह के साथ अपलिंक करता है, जिसे एमएसओ/एलसीओ द्वारा डाउनलिंक किया जाता है और केबल नेटवर्क के जरिए व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के परिसरों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार हिट्स ऑपरेटर्स केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों तक सिगनल पहुंचाते हैं। हिट्स ऑपरेटर और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि एक उपग्रह के जरिए चैनलों का पुलिंदा केबल ऑपरेटरों तक पहुंचाता है, जबकि दूसरा यही कार्य केबल के जरिए करता है। हिट्स के माध्यम से उपभोक्ता मुनासिब दामों पर कई डिजिटल चैनल, अच्छी तस्वीर और बेहतर सेवाओं का लुत्फ़ उठा सकता है। मंत्रालय की ओर से केवल दो हिट्स ऑपरेटर्स को लाइसेंस जारी किया गया है।

bVjuV çkVkdky Vyhfotu

इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा, केबल ऑपरेटरों के अलावा, अपने नेटवर्क पर पात्र दूरसंचार या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग के जरिए स्वीकृत उपग्रह टीवी चैनलों के वितरण का एक अन्य साधन है। आईपीटीवी प्रदाताओं को परिभाषित दूरसंचार और केबल ऑपरेटरों के लिए आईपीटीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन स्व घोषणा की आवश्यकता होती है।

[ky i1lkj.k flXuy ¼i1lkj Hkkjrh d lkFk vfuok;l lk>nkjh½ vf/kfu;e] 2007

खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझेदारी) अधिनियम, 2007 भारत के भीतर और विदेश में होने वाली राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं तक बड़ी तादाद में श्रोताओं और दर्शकों को फ्री टू एयर आधार पर पहुंच प्रधान करने के लिए पारित किया गया। अधिनियम की धारा 2 (1) (एस) केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों को कवरेज के लिए अधिसूचित करने का अधिकार देती है।

यह मंत्रालय कुछ खेल आयोजन/आयोजनों को राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजन के रूप में अधिसूचित करने के लिए समय–समय पर अधिसूचना जारी करता है, ताकि श्रोताओं और दर्शकों की सबसे बड़ी तादाद को राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों तक फ्री टू एयर आधार पर पहुंच उपलब्ध हो सके। हाल ही में, इस मंत्रालय ने '2018 हॉकी पुरुष विश्व कप' और 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स –2019' के सभी मैचों को राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों के रूप में अधिसूचित करने के लिए राजपत्रित अधिसूचनाएं जारी की हैं।

Hkkjr esa mixg Vhoh pSuyksa dh fLFkfr

1- uhfr

वर्ष 2000 में पहले निजी उपग्रह टीवी चैनल को भारत की धरती से अपलिंक करने की अनुमति प्रदान की गई थी। इससे पहले, निजी टीवी चैनलों को केवल विदेश से ही अपलिंकिंग करने की अनुमति थी। भारत में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के कई गुणा विकास और देश से ही टीवी चैनलों के अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग करने की मांग कई गुणा बढ़ गई जिसके कारण 2002 में अपलिंकिंग और 2005 में डाउनलिंकिंग के लिए नीति और दिशानिर्देश तय किया जाना अनिवार्य हो गया। इन दिशानिर्देशों को दिसंबर 2011 में संशोधित किया गया। ये दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.mib.nic.in पर उपलब्ध हैं।

lSVsykbV fn'kkfunsZ'kksa dh izeq[k fo'ks"krk,a

1. सभी टीवी चैनलों को अनुमति की तिथि से एक साल की अवधि के भीतर अपने चैनलों को चालू करना होगा। जिसके लिए गैर–समाचार एवं सम–सामयिक चैनलों को एक करोड़ रुपये की निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) पर हस्ताक्षर करने होंगे वहीं समाचार एवं सम–सामयिक चैनलों को दो करोड़ रुपये की निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) देनी होगी। यदि चैनल एक वर्ष के भीतर चालू नहीं हुए, तो प्रदर्शन बैंक गारंटी को जब्त कर लिया जाएगा और अनुमति रद्द कर दी जाएगी।

2. चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग की अनुमति समान रूप से 10 वर्ष के लिए होगी।

3 विलय, विघटन और एकीकरण के प्रस्ताव को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रक्रिया के अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद अनुमति दी जाएगी।

4 टीवी चैनल की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग की अनुमति 10 वर्ष की अवधि के लिए होगी। टीवी चैनलों की अनुमतियों के नवीनीकरण की अवधि 10 वर्ष की होगी लेकिन साथ ही यह शर्त होगी कि वह चैनल किसी कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का पांच या उससे अधिक बार उल्लंघन करने का दोषी नहीं पाया गया हो। उल्लंघन का फैसला स्थापित स्व–नियमन मानदंडों के अनुसार विचार–विमर्श के बाद तय किया जाएगा।

5. विदेशों और वहां के दर्शकों के लिए भारत से संचालित तथा अपलिंक होने वाले चैनलों द्वारा उस लक्षित देश के नियम और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करना होगा, जिसके लिए सामग्री का निर्माण और अपलिंक किया जा रहा है।

2- u, mixg Vhoh pSuyksa ds fy, vuqefr çnku djus dh çfØ;k

नए टीवी चैनलों के आवेदनों पर अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग नीति निर्देशों में दिए गए पात्रता मापदंड के आलोक में विचार किया जाएगा। ये दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.mib.nic.in पर उपलब्ध हैं। कंपनी तथा उसके निदेशक मंडल के लिए सुरक्षा अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदनों को गृह मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। साथ ही साथ आवेदनों को आवश्यक स्वीकृति के लिए अंतरिक्ष विभाग/राजस्व विभाग को भेजा जाएगा। कम्पनी की पात्रता निर्धारित करने के लिए अन्य पात्रता मानदंडों के साथ–साथ कंपनी की नेटवर्थ की भी जांच की जाएगी। अंतर–मंत्रालयी अनुमति मिलने तथा लागू पंजीकरण और अनुमति शुल्क लेने के बाद आवेदकों को अनुमति पत्र जारी किए जाते हैं।

,- Vhoh pSuyksa dk fodkl

1. वर्ष 2000 में पहले निजी उपग्रह टीवी चैनल 'आज तक' को अनुमति दी गई। उसके बाद से देश में बड़ी संख्या में निजी उपग्रह टीवी चैनलों का तेज गति से विस्तार हो रहा है। 31 अक्तूबर, 2018 तक मंत्रालय 866 चैनलों को अनुमति दे चुका है। अपलिंकिंग (यू/एल) तथा डाउनलिंकिंग (डी/एल) दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त टीवी चैनलों की संख्या में वृद्धि का वर्षवार ब्योरा आगे दिया गया है :

e=ky; }kjk vuefr çkIr Vhoh puyk dh la[;k

2001 ls vuefr ikIr puy

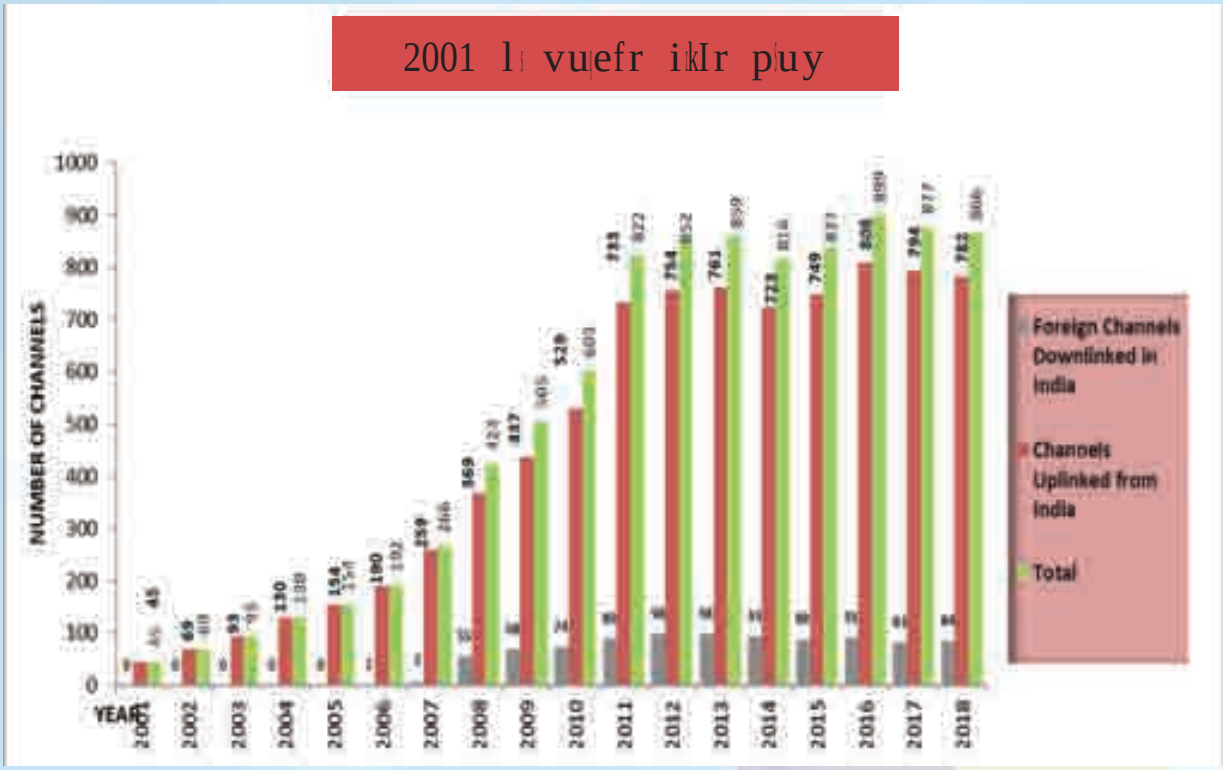

2. मंत्रालय द्वारा सिर्फ दो प्रकार के टीवी चैनलों को प्रसारण करने की अनुमति दी गई है अर्थात– 'समाचार एवं सम–सामयिक चैनल' और 'गैर–समाचार एवं सम–सामयिक चैनल। कुल अनुमति प्राप्त चैनलों में से समाचार और गैर–समाचार चैनलों के हिस्से का ब्योरा निम्नलिखित है: (383 समाचार और 483 गैर–समाचार चैनल)

J.khokj vuefr ikIr puy

vuefr ikIr Vhoh puy

¼ lekpkj cuke xj&lekpkj ½

e=kky; }kjk vuqefr ikIr VsyhikVZl dh l[;k

2001 ls vuqefr ikIr VsyhikVZl

3- ubZ igy

,- izlkj.k Ldh/k dk Lopkyu

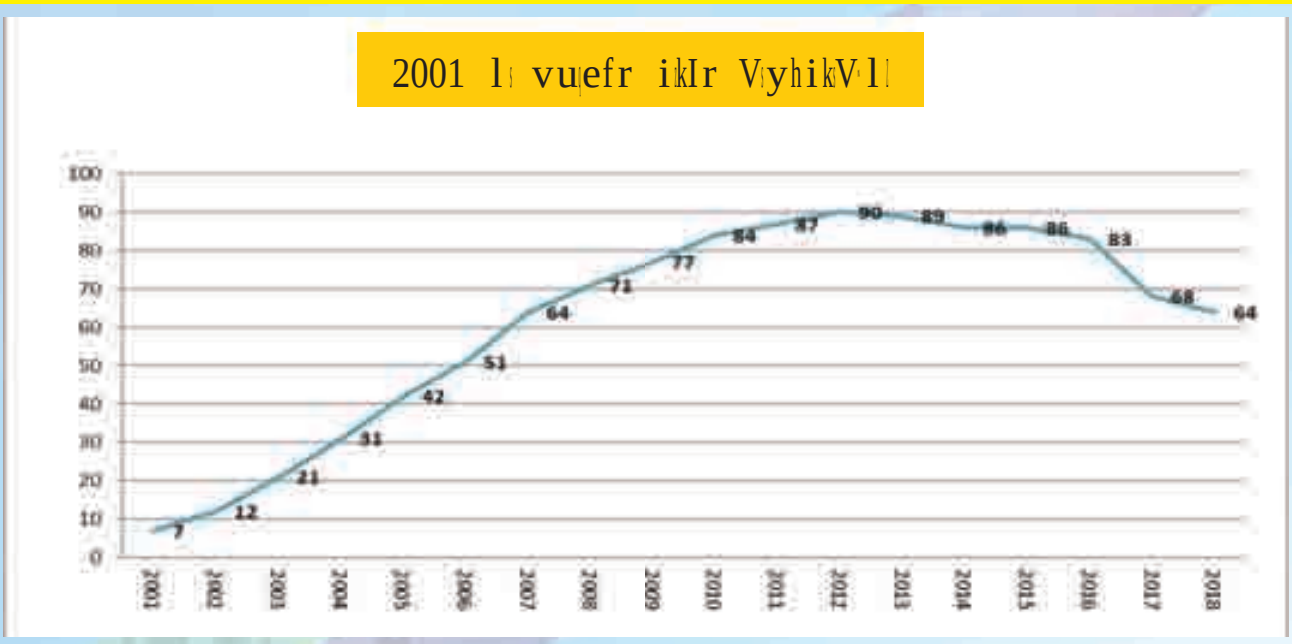

कंपनियों के लंबित मुद्दों के बारे में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 21 जनवरी, 2010 को परिचालित किए गए सॉफ्टवेयर सैटेलाइट टीवी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (एसटीएटीएस) को बेसिल के माध्यम से शुरू की जा रही स्वचालन परियोजना के अंग के रूप में मौजूदा अनुमति धारकों/आवेदकों के आंकड़ों के पूर्ण डिजिटलीकरण के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इसके तहत मंत्रालय ने प्रसारण क्षेत्र के विकास और प्रबंधन के हेतु कुशल और पारदर्शी व्यवस्था प्रदान करने के लिए सभी प्रसारण सेवाओं के लिए एक पोर्टल –c,MkLV lsok विकसित किया है। c,MkLV lsok, अपने निम्नलिखित मॉड्यूलों के माध्यम से आवेदकों को सेवाओं का व्यापक संग्रह प्रदान करती है :

1. मौजूदा प्रसारकों द्वारा वार्षिक अनुमति शुल्क का भुगतान।
2. अस्थाई अपलिंकिंग की अनुमतियों के लिए आवेदन।
3. टेलीपोर्ट स्थापित करने की अनुमति।
4. विदेशी मुद्रा विप्रेषण (फोरेक्स) के लिए आवेदन।
5. चैनल में विभिन्न परिवर्तनों के लिए आवेदन अर्थात् नाम और लोगो का परिवर्तन, उपग्रह का परिवर्तन, टेलीपोर्ट और टेलीपोर्ट के स्थान का परिवर्तन, चैनल की श्रेणी/भाषा का परिवर्तन, प्रसारण का माध्यम।

ch- u,@vfrfjDr Vhoh pSuyksa@VsyhikVZl ds fy, vkosnu ij ,e,lh, dh fVIif.k;ka ikIr djus dh izfØ;kxr vko';drk lekIr dj nh xbZ gSA

4- ikjnf'krk vkSj tokcnsgh ykuk

1- vksiu gkml cSBdsa

प्रसारकों के साथ हर महीने की गईं ओपन हाउस बैठकें काफी लाभदायक साबित हुईं। इन बैठकों में भाग लेने वाले प्रसारकों की संख्या पिछले एक साल में बढ़ी है। इन बैठकों से मिलने वाली प्रतिक्रिया से मंत्रालय को मंजूरी देने के कार्य में तेजी लाने और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए नए कदम उठाने में मदद मिली है। इन बैठकों में प्रसारणकर्ताओं के साथ नए और अनुमतिप्राप्त टीवी चैनलों, टेलीपोर्ट्स, एसएनजी/डीएसएनजी वैन, अस्थायी अपलिंकिंग के मामले, उपग्रह का परिवर्तन, नाम और लोगो में परिवर्तन, शेयर होल्डिंग की पद्धति में परिवर्तन, नये निदेशकों को शामिल करने, एफआईपीबी मंजूरी इत्यादि जैसे मुद्दों पर मुक्त और निष्पक्ष ढंग से चर्चा की गई है। इन बैठकों के जरिए न सिर्फ आवेदकों को मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत का अवसर मिला है, बल्कि इससे आवेदकों को सीधे सूचना प्राप्त करने में भी मदद मिली है। इससे किसी मध्यस्थ की जरूरत खत्म हुई है। सीधी बातचीत से प्रणाली में विश्वास का निर्माण हुआ है और अनावश्यक पत्राचार और फोन कॉल पर निर्भरता कम हो गई है।

2- vkuykbu vkonuk@iLrkok dh ykbo Vfdx

आवेदक कंपनियां (प्रसारक/टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स) ऑनलाइन दर्ज किए गए आवेदनों की लाइव ट्रैकिंग/स्थिति अब वेब पोर्टल www.broadcastseva.gov.in पर देख सकते हैं। इस संबंध में प्रसारकों द्वारा अपने आवेदनों को लाइव ट्रैक करने के लिए अपनाई जाने वाली नियत प्रक्रिया के बारे में भी उन्हें सूचित कर दिया गया है।

5- çlkj.k {k= e çR;{k fon'kh fuo'k ¼,QMhvkbZ½ uhfr dh leh{kk

एफडीआई नीति की समीक्षा की गई है और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की समेकित एफडीआई नीति 2017 के अनुसार, अनुच्छेद 5.2.7.1 और अनुच्छेद 5.2.7.2 प्रसारण क्षेत्र के लिए है और वह इस तरह है :

{k=@xfrfof/k	fon'kh fuo'k dh lhek	ço'k ekx
5-2-7-1-1 (1) टेलीपोर्ट्स (अपलिंकिंग हब/टेलीपोर्ट्स की स्थापना) (2) डायरेक्ट टू होम (डीटीएच); (3) केबल नेटवर्क्स (राष्ट्रीय या राज्य या जिला स्तर पर संचालित मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) ज्यादा पर तथा डिजिटलीकरण सरकारी जरिए से और अड्रेसेबिलिटी की दिशा में नेटवर्क्स के उन्नयन का दायित्व लेना); (4) मोबाइल टीवी; (5) हेडएंड–इन–द स्काई ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (हिट्स)	100 प्रतिशत	स्वतः
5-2-7-1-2 केबल नेटवर्क्स (डिजिटलीकरण और अड्रेसेबिलिटी की दिशा में नेटवर्क्स के उन्नयन का दायित्व नहीं लेने वाले अन्य एमएसओ और स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ)	100 प्रतिशत	स्वतः
5-2-7-2-1 स्थलीय प्रसारण एफएम (एफएम रेडियो) एफएम सरकारी रेडियो स्टेशन की स्थापना हेतु मंजूरी देने के लिए सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले नियमों व शर्तों के अधीन।	49 प्रतिशत	सरकारी
5-2-7-2-2 'समाचार एवं सामयिक विषय' टीवी चैनलों की अपलिंकिंग	49 प्रतिशत	सरकारी
5-2-7-2-3 'गैर समाचार एवं सामयिक विषय' टीवी चैनलों की अपलिंकिंग, टीवी चैनलों की डाउन लिंकिंग	100 प्रतिशत	स्वतः

6- ekud Qke vkj vkonu&i=

कंपनी से जानकारी मांगने और कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए लगने वाले समय की अवधि कम हो गई है और प्रक्रिया में अब तेजी लाई गई है।

Vhoh puyk dh lkexh dk fu;eu

1. टेलीविजन पर प्रसारित सामग्री के विनियमन ने उन चिंताओं को उभार दिया है, जिनका उदय भारतीय लोकाचारों एवं सांस्कृतिक मूल्यों पर इसके नकारात्मक प्रभाव के कारण, जहां एक ओर महिलाओं और बच्चों के इससे प्रभावित होने के सर्वाधिक जोखिम के कारण उनके हितों की देखभाल तथा दूसरी ओर अपने विचार प्रकट करने और रचनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण हो रहा है। मंत्रालय ने पहले ही 869 निजी उपग्रह टीवी चैनलों को अनुमति दे दी है जिनमें से 483 गैर समाचार तथा सम–सामयिक चैनल तथा 386 समाचार एवं सम–सामयिकी चैनल हैं। पिछले कुछ वर्षों से क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी के चैनलों के बीच प्रतियोगिता और भी कड़ी हो गयी है और बाज़ार इनसे परिपूर्ण होता जा रहा है। डीटीएच सेवाओं का तेजी से विकास होने के बावजूद आज भी चैनलों का वितरण केबल ऑपरेटरों द्वारा किया जा रहा है जो 1 अप्रैल, 2017 से देशभर में डिजिटल केबल टीवी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

2. प्रत्येक प्रसारणकर्ता को विविध नीतिगत दिशा निर्देशों के जरिए केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम 1995 तथा इसके अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया गया है। ये संहिताएं विविध प्रसारण माध्यमों के जरिए समस्त वीडियो सामग्री पर लागू की गई हैं।

3. सामग्री से संबंधित मामलों की प्रकृति मुख्यतः अश्लीलता, महिलाओं की छवि को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना, बच्चों पर बुरे प्रभाव, गलत ख़बर और मानहानि वाली ख़बरें दिखाना, गुमराह करने वाले विज्ञापन आदि जैसे विषयों से संबंधित है। इन सभी मामलों में, मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की गई और जहां आवश्यक था, वहां परामर्श, चेतावनी या क्षमा–प्रार्थना प्रसारित करने के आदेश जारी किए गए।

4. वर्ष 2017–2018 के दौरान (नवंबर, 2018 तक) मंत्रालय

ने चैनलों को परामर्श, चेतावनी और आदेश जारी किए, जिनका विवरण निम्नलिखित है :

1) 8 सामान्य परामर्श– टीवी चैनलों को विज्ञापन संहिता के नियम 7(10) का अनुपालन करते हुए गणतंत्र दिवस परेड और स्वतंत्रता दिवस समारोह को सांकेतिक भाषा टिप्पणी के साथ प्रसारित करने, विज्ञापनों का प्रसारण करते समय औषधि एवं चमत्कारिक उपचार अधिनियम 1954 के प्रावधानों का पालन करने, रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच कंडोम के विज्ञापनों का प्रसारण करने तथा माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए अनुसूचित जाति से संबंधित सदस्यों का उल्लेख करते हुए "दलित" शब्द का उपयोग करने से बचने तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जारी किए गए राष्ट्रपति आदेशों में अधिसूचित अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी में संवैधानिक शब्द 'शैड्यूल्ड कास्ट' और अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में उसके समुचित अनुवाद का उपयोग सभी आधिकारिक लेन देन, मामलों, व्यवहारों, प्रमाण–पत्रों आदि के लिए करने की सलाह दी जाती है।

2) 1 विशेष परामर्श–टीवी चैनल को कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का पालन करने का परामर्श दिया गया।

3) 03 आदेश– विभिन्न चैनलों को अलग–अलग दिनों के लिए प्रसारण रोकने के निर्देश जारी किए गए।

vrj&ea=ky;h lfefr

5- उपग्रह चैनलों की सामग्री के विनियमन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया। इस समिति में गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विदेश मंत्रालय, रक्षा, उपभोक्ता मामले का मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है, जो इस बात की सिफारिश करती है कि उल्लंघन किया गया है या नहीं। आईएमसी सिफारिश करने की क्षमता में कार्य करती है। समिति की सिफारिशों के आधार पर दंड और उसकी मात्रा के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाता है।

bysDVª,fud ehfM;k e,fuVfjax lsaVj

6. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) की स्थापना सरकार द्वारा एक अत्याधुनिक सुविधा के रूप में केबल टेलीविजन नेटवर्क्स एवं विनियमन अधिनियम 1995 और उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत उपग्रह टीवी चैनलों के कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का उल्लंघन करने वाली सामग्री की रिकार्डिंग और उसकी निगरानी के लिए की गयी है।

jkT; Lrjh; ,oa ftyk Lrjh; fuxjkuh lfefr;ka

7. राज्य/जिला स्तर पर केबल अधिनियम और नियमों को लागू करने के लिए मंत्रालय ने 6 सितंबर, 2005 को राज्य, जिला/स्थानीय स्तर पर केबल टेलीविजन चैनलों पर कार्यक्रम और विज्ञापनों के प्रसारण पर निगरानी के लिए 'निगरानी समिति' की व्यवस्था लागू की है। बाद में, मंत्रालय ने 19 फरवरी, 2008 को जिला स्तरीय निगरानी समिति और राज्य स्तरीय निगरानी समिति के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। हालांकि, बाद में, राज्य/जिला स्तरीय निगरानी समितियों के गठन के बारे में पिछले समस्त आदेशों, उपर्युक्त उल्लिखित आदेशों को शामिल करते हुए विस्तृत दिशानिर्देश दिनांक 26 अप्रैल, 2017 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों, राज्य सूचना सचिवों और सभी जिला मजिस्ट्रेटों को जारी किए गए। समितियों को निजी एफएम रेडियो चैनल और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की निगरानी के लिए भी अधिकृत किया गया है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in.पर उपलब्ध हैं।

lekpkj pSuyksa ds ekeys esa Lofu;eu

8. lekpkj çlkjd la?k ¼,uch,½] ने अपने स्वनियमन तंत्र के अंग के रूप में समाचार प्रसारण को स्व–विनियमित करने के लिए सिद्धांतों के विस्तृत दायरे को कवर करते हुए एक uSfrdrk vkSj çlkj.k ekud lafgrk तैयार की है। उन्होंने सामग्री से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए दो स्तरीय ढांचे का गठन किया है। स्तर–1 में आने वाली शिकायतों को व्यक्तिगत प्रसारकों द्वारा अपने स्तर पर अलग–अलग प्रसारकों द्वारा निपटाया जाता है, जबकि स्तर–2 से आने वाली शिकायतों का निपटारा एनबीए द्वारा 2008 esa LFkkfir lekpkj çlkj.k ekud çkf/kdj.k ¼,uch,l,½] द्वारा किया जाता है।

9. समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण का उद्देश्य मनोरंजन करना और समाचार प्रसारकों से संबंधित किसी भी तरह की शिकायतों पर निर्णय करना है, जहां तक कि उनका संबंध किसी सामग्री से हो। यह किसी प्रसारण की सामग्री से संबंधित होता है। प्राधिकरण का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है और

इसके आठ अन्य सदस्य होते हैं जिनमें से चार प्रतिष्ठित संपादक होते हैं, जो प्रसारकों के साथ कार्यरत हैं और चार सदस्य कानून, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, साहित्य, लोक प्रशासन, उपभोक्ता मामले, पर्यावरण, मानव मनोविज्ञान और/या संस्कृति क्षेत्र में विशेषज्ञता होते हैं। ,uch,l, ds orZeku v/;{k mPpre U;k;ky; ds lsokfuoÙk U;k;k/kh'k vkj- oh- johaæu gSA विवरण एनबीए की वेबसाइट http://www.nbanewdelhi.com पर उपलब्ध है।

xSj&lekpkj ¼lkekU; euksjatu½ pSuyksa esa Lo&fu;eu

10. bfM;u czkMdkfLVax QkmaMs'ku ¼vkbZch,Q½ ने मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद गैर–समाचार चैनलों के मामले में स्व–नियमन के लिए एक तंत्र की स्थापना की है। आईबीएफ ने टेलीविजन पर प्रसारण के लिए सामग्री से संबंधित सिद्धांतों और मापदंड को शामिल करते हुए lkexzh lfgrk vkSj çek.ku fu;e 2011 तय किये हैं। इस तंत्र के हिस्से के रूप में शिकायतों के निवारण की द्वि–स्तरीय प्रणाली भी बनाई गई है। इसके स्तर–1 में प्रत्येक प्रसारक को अपने चैनलों पर प्रसारित विषय–वस्तु से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए विषय–वस्तु परीक्षक सहित मानक और कार्यप्रणाली (एस एंड पी) विभाग स्थापित करना होता है।

11 तंत्र के स्तर–2 पर 1 जुलाई, 2011 को प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद (ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल –बीसीसीसी) की स्थापना एवं संचालन किया गया। वर्तमान में बीसीसीसी 12 सदस्यीय संस्था है, जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं समाज के चार विशिष्ट व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। विभिन्न विषयों के 13 सदस्य होते हैं। परिषद में राष्ट्रीय आयोगों का भी प्रतिनिधित्व होता है, जिसमें चार प्रसारक सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त परिषद में एक विशेष आमंत्रित मेहमान होते हैं, जो भाषा शिकायतों का निपटारा करने में इसकी सहायता करते हैं। वर्तमान में बीसीसीसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) विक्रमाजीत सेन हैं। विवरण आईबीएफ की वेबसाइट http://www.ibfindia.com पर उपलब्ध हैं :

Vhoh pSuyksa ij foKkiu dk Lo&fofu;eu

12. टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों के नियमन के संबंध में ,MojVkbft ax LVSaMMZ~l dkmafly vkQ bafM;k ¼,,llhvkbZ½ की संहिता को स्व–नियमन निकाय के रूप में ग्रहण किया गया है, जिन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्कस (विनियमन) नियम, 1994 में सम्मिलित किया गया है। एएससीआई ने विज्ञापनों से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए miHkksDrk f'kdk;r ifj"kn ¼lhlhlh½ की स्थापना की है। सीसीसी के वर्तमान में 28 lnL; gSA इनमें से 12 उद्योग से हैं और 16 सदस्यों को सिविल सोसाइटी से लिया गया है, जिनमें प्रसिद्ध डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षाविद, उपभोक्ता कार्यकर्ता शामिल हैं। विवरण एएससीआई की वेबसाइट https://www.ascionline.org पर उपलब्ध है।

lkekU; fgr ls lacaf/kr U;k;ky; ds fu.kZ;

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2000 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या.387 – सामान्य हित बनाम भारत संघ एवं अन्य– के मामले में 12 जनवरी, 2017 को पारित अपने आदेश में, उपर्युक्त मौजूदा तंत्र को स्वीकार किया।

dscy Vhoh fMftVyhdj.k dh oLrqfLFkfr

1- ns'k esa dscy Vhoh ç.kkyh

केबल टीवी प्रणाली देश में प्रसारण वितरण उद्योग का आधार है। पिछले 20 वर्षों के दौरान केबल उद्योग ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। डीटीएच सेवाओं के तेजी से होते विकास के बावजूद, टीवी चैनलों के वितरण में आज भी केबल सेवाओं का वर्चस्व है। ट्रांसमिशन की एनालॉग प्रकृति के कारण इस प्लेटफॉर्म की कई सीमाएं हैं।

2- çlkj.k m|ksx dh :ijs[kk

केबल टीवी सेवा मूल्य श्रृंखला में चार मुख्य आपूर्तिकर्ता इकाइयां शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं : प्रसारक, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ), स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ) और अंतिम उपभोक्ता। प्रसारक टीवी पर प्रसारित होने वाली सामग्री का निर्माण करता है जिसे दर्शक देखते हैं। प्रसारक उपग्रह के लिए सामग्री के सिग्नल प्रेषित या ''अपलिंक'' करता है। एमएसओ प्रसारकों के सिग्नल को उपग्रह से डाउनलिंक करता है, किसी भी इन्क्रिप्टेड चैनल को डिक्रिप्ट करता है और कई चैनलों के फीड का समूह एलसीओ को प्रदान करता है। ट्राई के अनुसार, भारत में लगभग 6000 एमएसओ काम कर रहे हैं। एमएसओ का व्यापार, सामग्री (कंटेट) के लिए प्रसारक तथा अंतिम कनेक्टिविटी और सदस्यता राजस्व संग्रह के लिए एलसीओ पर निर्भर रहता है। एमएसओ को टीवी सिग्नल प्राप्त करने के लिए हेडएंडस की आवश्यकता होती है। एलसीओ एमएसओ से कई सिग्नल प्राप्त करता है और केबल के माध्यम से इसे अपने ग्राहकों तक पहुंचाता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 60,000 केबल ऑपरेटर हैं।

3- Vyhfotu forj.k IyVQkEl dk Lo:i

भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टीवी बाज़ार है। फिक्की–ईवाई रिपोर्ट मार्च 2018 के अनुसार, निम्न प्लेफार्म वितरण के हिसाब से भारत में 183 मिलियन घरों में टीवी हैं :

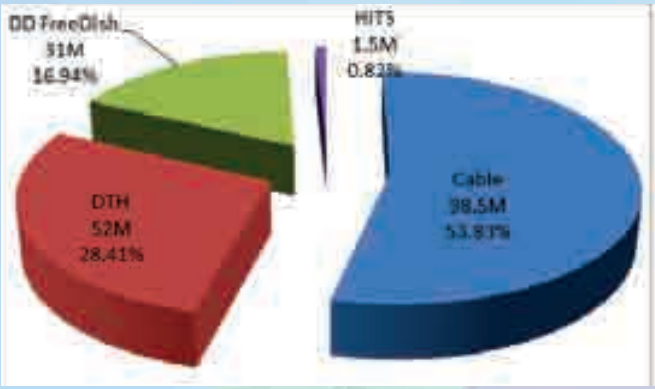

4- ,uky,x dcy Vhoh dh dfe;k

एनालॉग केबल टेलीविजन में निम्नलिखित अंतर्निहित कमियां हैं :–

- चूंकि स्वीकृत सेटेलाइट टीवी चैनलों की संख्या 700 के पार चली गई है, एनालॉग प्रणाली के पास केवल 70–80 चैनलों को वहन करने की क्षमता है। यह ग्राहक की पसंद को गंभीर रूप से सीमित करता है और ग्राहक को प्रसारण क्षेत्र में बड़ी संख्या में उपलब्ध टीवी चैनलों तक पहुंच बनाने से वंचित रखता है।
- सीमित संख्या में चैनल वहन करने की क्षमता से एनालॉग प्रणाली टीवी प्रसारकों के व्यापार को विकृत करती है, क्योंकि प्रसारणकर्ता को फीस का भुगतान करके अपने चैनलों का वहन करने के लिए एमएसओ को प्रोत्साहित करने पर मजबूर होना पड़ता है।
- एनालॉग केबल के पास में ए–ला–कार्टे (व्यक्तिगत) चैनलों के चयन की सुविधा वाली तकनीकी विशेषता नहीं है। इस वजह से ग्राहक को मजबूरी में अपनी इच्छा के विपरीत जाकर केबल ऑपरेटर द्वारा तैयार चैनलों के समूह का चयन करना पड़ता है। इस प्रकार, एनालॉग प्रणाली ग्राहकों के अनुकूल नहीं है।
- एनालॉग सेवाओं की एक अन्य गंभीर तकनीकी सीमा पारदर्शिता की कमी है जिसमें ग्राहक आधार सटीक तरीके से बरकरार और रिपोर्ट नहीं किया जाता। इस तरह ग्राहक से प्राप्त राजस्व कम दर्शाया जाता है और इसके परिणामस्वरूप कर राजस्व को छिपाया जाता है।
- सीमित वहनीय क्षमता और पारदर्शिता की कमी प्रसारकों के लिए व्यापार मॉडल को विकृत करती है और इससे विज्ञापन राजस्व पर उनकी निर्भरता बढ़ जाती है और इससे सदस्यता राजस्व की संभावना सीमित रह जाती है (65:35)। तदनुसार, उच्च टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) के लिए चैनल अक्सर टीवी पर सनसनीखेज़ सामग्री का इस्तेमाल करते हैं।
- एनालॉग केबल में पिक्चर की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि एक चैनल प्राइम बैंड या ग़ैर–प्राइम बैंड में कितना देखा जा रहा है।
- केबल ऑपरेटरों को डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) और आईपीटीवी सेवाओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता की सामग्री और मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान कर पाने की स्थिति में हैं और ऐसे में जब तक केबल ऑपरेटर अपनी सेवाओं को उन्नत नहीं कर लेते वे नए प्लेटफॉर्म्स के सामने व्यापार से बाहर हो जाएंगे।

5- Vkbl dh flQkfj'k

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 5 अगस्त, 2010 की ''भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल प्रणाली (डीएएस)' को लागू करने'' संबंधी अपनी अनुशंसाओं में अन्य बातों के साथ–साथ यह सिफारिश की थी कि केबल टीवी सेवाओं में एड्रेसेबिलिटी के साथ डिजिटीकरण प्राथमिकता के साथ लागू किया जाए और, तदनुसार, केबल टीवी क्षेत्र में एनालॉग प्रणाली को डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली (डीएएस) में परिवर्तित करने की चार चरणों की समय–सीमा की सिफारिश की।

6- fMthVyhdj.k dk ykHk

एड्रेसबिलिटी का अर्थ है केबल ऑपरेटर के सिग्नल एन्क्रिप्टेड (कूट रूप में) होंगे। सेवा प्रदाता से विधिवत अनुमति लेने के उपरांत सिग्नल केवल सेट टॉप बॉक्स के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार, यह प्रत्येक ग्राहक की पहचान और डेटा बेस के रखरखाव, पारदर्शिता लाने और चोरी को रोकने के लिए सक्षम है। डीएएस के कार्यान्वयन से सभी हितधारकों को लाभ होगा। विभिन्न हितधारकों के लिए डिजिटलीकरण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं :

¼i½ Xkkgd

- ग्राहकों को यह अधिकार दिया गया है कि वह मैन्यू में से अपनी रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार अपनी मनमर्जी के चैनल का चयन करें और अपने बजट के अनुसार केवल उन्हीं चैनलों के लिए भुगतान करना होगा, जिन्हें वे देखना चाहते हैं।
- उपभोक्ताओं को पेशकश किए जाने वाले चैनलों की संख्या मौजूदा 70–80 से बढ़कर सैंकड़ों तक पहुंच चुकी

है। इसने उपभोक्ताओं को एक बेहतर तकनीक देखने का अनुभव प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में उच्च गुणवत्ता/हाई डेफिनेशन डिजिटल टेलीविजन चैनलों को देखने में सक्षम बनाया है।

❖ डीटीएच और आईपीटीवी ग्राहकों की तरह, केबल टीवी ग्राहकों को भी बेहतर गुणवत्ता की सामग्री मिल रही है और उनकी पहुंच भी इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम गाइड, मूवी–ऑन डिमांड, वीडियो–ऑन–डिमांड, व्यक्तिगत वीडियो, गेमिंग आदि जैसे विभिन्न इंटरएक्टिव सेवाओं तक है।

¼iii½ dcy vkijVlZ

- डिजीटलीकरण ने केबल ऑपरेटर्स को ट्रिपल प्ले (तीन सेवाएं एक साथ) की सुविधा मुहैया कराने में सक्षम बनाया है जिसमें वीडियो और डाटा यानी टीवी, टेलीफोनी, इंटरनेट और आईटी सक्षम सेवाएं मौजूद हैं। डिजिटल चैनलों के साथ बंडलिंग ब्रॉडबैंड एक आशाजनक प्रस्ताव था और डीटीएच से यह महत्वपूर्ण रूप से अलग था। इसने उन्हें डीटीएच सेवाओं के साथ प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया, उनका प्रति उपयोगकर्ता (एआरपीयू) औसत राजस्व बढ़ाया और प्रसारण एवं दूरसंचार सेवाओं के अभिसरण को सक्षम किया। केबल टीवी सेवाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से भारत में ब्रॉडबैंड पैठ भी बढ़ेगी।

¼iiii½ çlkj.kdrkZ

❖ यह सवंर्धित क्षमता प्रसारणकर्ताओं को आला चैनल और एचडीटीवी (हाई डेफिनिशन टेलीविजन) चैनलों की पेशकश करने में सक्षम बनाएगी। बढ़ा हुआ सदस्यता राजस्व प्रसारकों को टीआरपी केंद्रित सामग्री से दूर रखने में मदद करेगा और प्रसारणकर्ता अंकेक्षण योग्य उपभोक्ता आधार पर अपना कारोबार चला पाने में समर्थ होंगे।

(iv) ljdkj

❖ सरकार के कर संग्रह से वास्तविक बाज़ार का आकार मेल खाएगा।

❖ ग्राहक आधार में पारदर्शिता होने से हानि में ज़बरदस्त कमी आई है जिस कारण सरकार के राजस्व चोरी में भी कमी आई है।

❖ ब्रॉडबैंड और अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं का उपयोग बढ़ने के माध्यम से सेवा कर राजस्व और मनोरंजन कर ज्यादा सृजित होगा।

❖ डिजिटल केबल टीवी नेटवर्क ब्रॉडबैंड की पैठ के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों की ई–गवर्नमेंट सेवाओं तक पहुंच बनाई जा सकती है।

7- Mh,,l dk ykxw djus dh fy, dcy vf/kfu;e esa l'kks/ku

ट्राई की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की 13 अक्तूबर, 2010 की बैठक में, केबल टीवी सेवाओं में डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) को अनिवार्य रूप से लागू करने वाले मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें अन्य बातों के साथ, केबल टीवी सेवाओं में अखिल भारतीय स्तर पर एड्रेसेबिलिटी सहित डिजिटलीकरण के साथ कार्यान्वयन की समय सीमा और रोड मैप को शामिल किया गया। जिससे 31 दिसंबर, 2014 तक पूर्ण रूप से एनालॉग टीवी सेवाओं को बदलने का मार्ग प्रशस्त हो। मंत्रिमंडल ने अध्यादेश यथा– केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2011 की घोषणा के माध्यम से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में कुछ संशोधनों को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश को 25 अक्तूबर, 2011 को लागू किया गया था। इसके बाद 31 दिसंबर, 2011 से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2011 लागू किया गया।

8- Mh,,l dk pj.kc) dk;kZUo;u dh fy, vf/klwpuk

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 11 नवंबर, 2011 को जारी अपनी अधिसूचना में भारत में चार चरणों के भीतर केबल टीवी नेटवर्क के डिजिटलीकरण का चरणवार कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। अधिसूचित तिथियां निम्नलिखित हैं :

चरण 1	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के महानगर	मूल रूप से 30 जून, 2012 को शुरू किया जाना था। इसे संशोधित कर 31 अक्तूबर, 2012 किया गया।
चरण 2	38 शहर (1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले)	31 मार्च, 2013
चरण 3	अन्य शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिकाएं)	मूल रूप से 30 सितंबर, 2014 को शुरू होना था। इसे संशोधित कर 31 दिसंबर, 2015 किया गया (न्यायालय के मुकदमों का निपटान होने पर, मंत्रालय द्वारा 31.01.2017 तक तीसरे चरण के क्षेत्रों में डीएएस के पूर्ण कार्यान्वयन की अनुमति दी गई।)

चरण 4	शेष भारत	मूल रूप से 31 दिसंबर, 2014 को शुरू होना था। इसे संशोधित कर 31 दिसंबर, 2016 किया गया। (न्यायालय के मुकदमों के निपटान के बाद इसे फिर से संशोधित कर 31 मार्च, 2017 किया गया)

9- ea=ky; }kjk dk;kZUo;u@igy

इस बात पर विचार करते हुए कि केबल टीवी नेटवर्क का डिजिटलीकरण एक बड़ा कदम है, इसलिए इसमें तमाम हितधारकों यथा– प्रसारणकर्ताओं, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) और लोकल केबल ऑपरेटर्स (एलसीओ) आदि का शामिल होना जरूरी था। एनालॉग व्यवस्था से डिजिटलीकरण का काम सहजता के साथ संपन्न करने के लिए आवश्यक ढांचागत व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास डिजिटलीकरण की व्यवस्था लागू करने का अधिकार है इसीलिए मंत्रालय ने यह कार्य समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के लिए निम्नलिखित अहम कदम उठाए :

(i) dk;Zcy % सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया। इस कार्यबल में निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व रहा :

- प्रसारणकर्ता
- एमएसओ
- एलसीओ
- डीटीएच ऑपरेटर
- सीईएएमए– उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपकरण निर्माता एसोसिएशन
- उपभोक्ता फोरम
- दूरसंचार विभाग
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–ट्राई
- राज्य सरकारें
- प्रसार भारती

कार्यबल की बैठक हर महीने हुई जिसमें उसने काम काज की प्रगति की समीक्षा की।

पहले चरण के लिए कार्यबल की 20 बैठकें हुईं, दूसरे चरण के लिए 6 और तीसरे और चौथे चरण के लिए 21 बैठकें की गईं।

(ii) jk"Vªh; Lrj ds ,e,lvks mi lewgksa vkSj Lora= ,e,lvks rFkk ,ylhvks ds lkFk cSBdsa % कामकाज की प्रगति की समीक्षा और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए इन उप समूहों के साथ अलग से बैठकें की गईं।

(iii) 12 {ks=h; bdkb;ka % केबल डिजिटलीकरण के कार्यान्वयन के लिए मिशन डिजिटलीकरण परियोजना के रूप में 12 क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया गया।

(iv) çf'k{k.k % इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि डिजिटलीकरण के काम में उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और साथ ही लोकल केबल ऑपरेटरों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का कार्य भी चलता रहे, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) से छोटे–छोटे समूहों में लोकल केबल ऑपरेटरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने को कहा गया। हालांकि इस बारे में केबल ऑपरेटरों की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं रही। अब केबल टीवी उद्योग के तकनीशियन को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बेसिल के सहयोग से इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, सर्विलान्स एंड कम्युनिकेशन सेक्टर स्किल काउंसिल (आईएएससी–एसएससी) द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

(v) tu tkx#drk vfHk;ku % इस बदलाव के बारे में जनसाधारण को जागरुक बनाने और उनकी चिंताएं मिटाने और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में बड़े पैमाने पर सूचना और जागरुकता अभियान चलाया गया। हितधारकों की ओर से केबल टीवी सेवाओं के अनाधिकृत और अवैध ट्रांसमिशन के बारे में प्रश्न एकत्र करने के लिए व्हॉट्सएप नंबर +91729198976 शुरू किया गया।

(vi) Vksy Ýh gSYiykbu % जनता की ओर से पूछे जाने वाले विविध प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक बहुभाषीय टोल फ्री नंबर 1800&180&4343 चालू किया गया। यह टोल फ्री नंबर फिर से शुरू कर दिया गया है और अब यह चालू है।

(vii) osclkbV % पूर्णतः इस काम को समर्पित एक वेबसाइट www.digitalindiamib.com बनाई गई है।

(viii) jkT; ljdkjksa ds lkFk vuqjfØ;k,a इस बात पर विचार करते हुए हुए कि स्थानीय स्तर पर इस काम को आगे बढ़ाने में राज्य सरकारों की महती भूमिका होगी इसलिए उनके साथ भी कई बैठकें की गईं ताकि उन्हें उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं से अवगत कराया जा सके।

केबल टीवी डिजीटलीकरण की वेबसाइट www.digitalindiamib.com

चरण–2 के लिए प्रमुख सचिवों से आग्रह किया गया कि वे चरण–2 के 38 शहरों में से प्रत्येक के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें ताकि डीएएस में परिवर्तन के लिए समयबद्ध तैयारी की जा सके। चरण–3 और 4 के लिए भी जिलावार नोडल अधिकारी नामित किए गए और उनके साथ बैठकों का आयोजन किया गया। नोडल अधिकारियों के साथ कार्यशालाएं/बैठकें की गईं।

(ix) tux.kuk dk vkdMk % डिजीटलीकरण के लिए शहर और चरणों के मुताबिक सेट टॉप बॉक्स–एसटीबी की आवश्यकता की जानकारी वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर हासिल की गई। घरों में एक से ज्यादा टीवी और कार्यालयों/दुकानों के टीवी सेटों के लिए 20 प्रतिशत का प्रावधान जोड़ा गया। इन आंकड़ों की जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई।

(x) lsV Vki ckDl ¼,lVhch½ lhfMax MsVk dk laxg vkSj fo'ys"k.k % चरण–1 और चरण–2 की प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय ने व्यापक आधार पर एक डाटा बेस तैयार किया। इसमें एमएसओ से एसटीबी की उपलब्धता और उनकी सीडिंग के बारे में व्यवस्थित जानकारी जुटाई गई। डीटीएच ऑपरेटरों से भी आंकड़े एकत्र किए गए।

शुरुआत में साप्ताहिक आधार पर आंकड़े जमा किया जाता रहा लेकिन जैसे ही पहले और दूसरे चरण में एक महीने का समय रह गया तो दैनिक आधार पर आंकड़े जमा करने का काम किया जाने लगा।

एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) तैयार की गई, जिसमें सभी पंजीकृत ऑपरेटर्स (एमएसओ, डीटीएच और हिट्स ऑपरेटर्स) से कहा गया कि वे इलाके के अनुसार एसटीबी सीडिंग की स्थिति का विवरण दें। इन आंकड़ों को देखने का अधिकार नोडल अधिकारियों को भी दिया गया ताकि वे अपने राज्य/जिले में हुई प्रगति की समीक्षा कर सकें।

(xi) QhYM Vhe % मिशन डिजिटिकरण परियोजना की क्षेत्रीय इकाई और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से बड़े पैमाने पर इलाकों का दौरा किया गया।

इन दौरों में मंत्रालय की टीमें एमएसओ, एलसीओ तथा एसटीबी निर्माताओं के प्रतिष्ठानों में भी गईं।

इन दौरों में खासतौर पर दूर–दराज के इलाकों और झुग्गी बस्तियों में बसने वाले उपभोक्ताओं से बातचीत की गई ताकि उनकी जरूरतों का पता चल सके और साथ ही उनकी प्रतिक्रिया भी हासिल हो पाए।

चरण–2 की बड़ी जरूरतों को देखते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से कहा गया कि समस्त 38 शहरों में से प्रत्येक के लिए तकनीकी टीमों का गठन करें। ये टीमें एमएसओ प्रतिष्ठानों की लगातार यात्राएं करती रहीं और तमाम जानकारी और आंकड़े लगातार मंत्रालय को उपलब्ध कराती रहीं।

चरण–3 को लागू कराने के दौरान भी इसी तरह की व्यवस्थाएं की गईं और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के अधिकारियों से कहा गया कि वे पंजीकृत एमएसओ के हैडएंड्स का लगातार निरीक्षण करते रहें।

(xii) ukMy vf/kdkfj;ksa ds lkFk cBdsa % राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों के साथ नियमित बैठकों का दौर चलता रहा। केबल टीवी डिजिटिकरण के कार्यान्वयन की

दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए एमडीपी क्षेत्रीय इकाई के कर्मचारी नियमित रूप से जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों के पास जाते रहे।

(xiii) ,e,lvk dk ithdj.k% डिजिटल रूप में केबल टीवी सेवाएं उपलब्ध कराने के इच्छुक सभी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पंजीकरण कराना था। डिजिटल रूप में केबल टीवी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय की ओर से 1471 एमएसओ पंजीकरण जारी किए गए। गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी नहीं देने के कारण 10 एमएसओ का पंजीकरण रद्द कर दिया गया और 6 एमएसओ का पंजीकरण करने से इंकार कर दिया गया।

(xiv) ,e,lvk ithdj.k d fy, vkuykbu i.kkyh % एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है और उसे 1.5.2017 से लागू कर दिया गया है, जिसमें आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वे अपने आवेदनों की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकते हैं।

(xv) Hkkjr dk"k d tfj, vkuykbu Hkxrku % मंत्रालय ने भारत कोष के माध्यम से केवल ऑनलाइन एमएसओ पंजीकरण के लिए प्रॉसेसिंग फीस प्राप्त करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में, वेबसाइट पर एक परिपत्र अपलोड किया गया है, जिसके अनुसार एमएसओ पंजीकरण के लिए प्रॉसेसिंग फीस भारत कोष के माध्यम से प्रॉसेस्ड किया जाना आवश्यक है।

10- fMftVyhdj.k dh fLFkfr

10-1 pj.k&1

डिजिटलीकरण के चरण–1 का कार्य 31 अक्तूबर, 2012 को पूरा हो गया। चार मेट्रो शहरों में से 3 शहरों, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में डिजिटलीकरण का कार्य पूरे होने को था, बाद में चेन्नई में भी अनेक अदालती मुकदमों के बाद भी डिजिटल परिवर्तन किया गया।

पहले चरण के दौरान तक लगभग 1.42 करोड़ केबल सेट टॉप बॉक्स लगाए गए। दिल्ली में सबसे ज्यादा 50 लाख सेट टॉप बॉक्स, उसके बाद मुंबई में 29 लाख और कोलकाता में 38 लाख तथा चेन्नई में 24 लाख सेट टॉप बॉक्स लगाए जा चुके हैं।

10-2 pj.k&2

14 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैले 38 शहरों में 31 मार्च, 2013 तक चरण–2 संचालित किया गया।

10-3 pj.k&3

केबल टीवी नेटवर्क के डिजिटलीकरण के चरण–3 के लिए कट–ऑफ तिथि 31 दिसंबर, 2015 निर्धारित की गई थी, लेकिन कुछ न्यायालयों द्वारा विस्तार/रोक लगाए जाने के कारण मुकदमों का निपटान होने पर मंत्रालय द्वारा चरण–3 के क्षेत्रों में डिजिटलीकरण के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए 31 जनवरी, 2017 तक की अनुमति दी गई थी। एमआईएस पोर्टल के अनुसार, चरण–3 के क्षेत्रों में लगभग 6.74 करोड़ एसटीबी स्थापित किए गए।

10-4 pj.k&4

भारत के शेष हिस्सों को कवर करने वाले चरण–4 को 31 दिसंबर, 2016 तक पूरा किया जाना था। लेकिन अदालती मुकदमों के कारण बाज़ार में अनिश्चितता की वजह से कट–ऑफ तिथि संशोधित कर 31.03.2017 कर दी गई थी। अदालत के मामलों के निपटान के बाद, चरण–4 में एसटीबी की प्रगति की वर्तमान स्थिति 4.98 करोड़ है, जो लक्ष्य का 67 प्रतिशत है।

11-orleku fLFkfr vkj ekey

1. दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से पूरे देश में केबल टीवी डिजिटलीकरण अधिदेशित कर दिया गया है। मंत्रालय ने दिनांक 30 मार्च, 2017 के अपने परिपत्र के जरिए सभी प्रसारणकर्ताओं, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स और लोकल केबल ऑपरेटर्स को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 31 मार्च, 2017 के बाद केबल नेटवर्क पर किसी भी एनालॉग सिग्नल का ट्रांसमिशन न हो। ऐसा करने में विफल रहने पर दोषियों के खिलाफ केबल टीवी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

2. देश के कुछ हिस्सों से 31 मार्च, 2017 के बाद भी एनालॉग सिग्नल के ट्रांसमिशन की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। तदनुसार, मंत्रालय ने 21 अप्रैल, 2017 को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सभी प्राधिकृत अधिकारियों, सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों को परामर्श जारी कर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि किसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा किसी भी एनालॉग सिग्नल का ट्रांसमिशन न हो। किसी भी एमएसओ/केबल ऑपरेटर्स द्वारा इन निर्देशों/आदेशों, का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में इस मंत्रालय की ओर से दी गई चेतावनी के तहत केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम की 11 धारा के अधीन उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

3. मंत्रालय ने प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा एमएसओ के निरीक्षण के लिए एक चेक–लिस्ट तैयार की थी। इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी प्राधिकृत अधिकारियों को 25 अप्रैल, 2017 को भेज दिया गया था।

4. मंत्रालय ने 12 जून, 2017 को राज्यों के मुख्य सचिवों से भी अनुरोध किया कि वे सभी डीएम को निर्देश दें कि वे धारा–11 के तहत अपनी शक्तियों के अनुसार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई

करें और इस मामले की निगरानी डीसी, आईजी पुलिस के राजस्व सचिव, जैसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाए।

5. एमआईएस के अनुसार, अब तक 110 प्रतिशत से अधिक एसटीबी लगाए जा चुके हैं।

fMftVyhdj.k d dk;kUo;u d ckj e ifrfØ;k% विभिन्न हितधारकों एकत्र किए गए आंकड़ों से संकेत मिलता है कि डिजिटलीकरण से कुछ अहम लाभ होने शुरू हो गए हैं, जो निम्नलिखित हैं :–

,pMh pSuyk lesr cgqla[; pSuyk e ls pSuko dk fodYi % एनालॉग व्यवस्था के समय में केबल प्रणाली में 75 से 80 चैनल दिखाने ही क्षमता थी। ये सभी चैनल स्टैंडर्ड डिफिनेशन (एसडी) गुणवत्ता के थे लेकिन डिजिटल स्वरूप में वही केबल केवल 600 से 700 चैनलों को वहन करने की क्षमता ही नहीं रखता है बल्कि उसमें एचडी (हाई डिफिनेशन) चैनल भी वहन किए जा सकते हैं। एमएसओ से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में प्रत्येक एमएसओ 300 एसडी और 20 एचडी चैनलों को वहन कर रहा है। इसीलिए उपभोक्ताओं के पास बहुसंख्यक चैनलों में से अपनी पसंद और गुणवत्ता का चैनल चुनने का अवसर मौजूद है।

,M&Ýh ¼foKkiu jfgr½ vkj mPp xq.koÙkk okys pSuy % डिजिटल व्यवस्था में चैनल एनक्रिप्टेड (कूट रूप में) होते हैं और उपभोक्ता केवल वही चैनल देख सकते हैं जिनके वे ग्राहक होते हैं। चूंकि डिजिटल व्यवस्था में सैंकड़ों चैनलों को वहन करने की क्षमता होती है, इसलिए प्रसारणकर्ता नए उच्च गुणवत्ता और यहां तक की एड फ्री चैनल शुरू कर रहे हैं। केबल उपभोक्ताओं ने अतिरिक्त पैसा चुकाकर इन चैनलों का ग्राहक बनना भी शुरू कर दिया है। यह सब एनालॉग व्यवस्था में संभव नहीं था।

fiDpj vkj vkokt dh xq.koÙkk % एनालॉग व्यवस्था में पिक्चर और आवाज़ की गुणवत्ता न केवल खराब थी बल्कि वह इस बात पर निर्भर करती थी कि चैनल आखिर किस बैंड (वीएचएफ–1, वीएचएफ–2 या यूएचएफ) पर है। डिजिटल व्यवस्था में डिजिटल होने की वजह से गुणवत्ता शानदार है और साथ ही यह उस फ्रीक्वेंसी के बैंड से भी मुक्त है, जिस पर एमएसओ द्वारा चैनल को वहन किया जाता है।

çkxke xkbM % डिजिटल व्यवस्था में केबल उपभोक्ताओं के पास कार्यक्रमों की जानकारी हासिल करने के पूरे अधिकार हैं। वे यह बात आसानी से जान सकते हैं कि इस समय कहां कौन–सा कार्यक्रम चल रहा है और अलग–अलग समय पर कौन–सा कार्यक्रम आने वाला है।

f'kdk;r fuokj.k r= % ट्राई के नियमों के मुताबिक हरेक एमएसओ और उसके केबल ऑपरेटर के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण का तंत्र हो जिसका टोल फ्री नंबर हो, वेब आधारित व्यवस्था हो ताकि शिकायतों की स्थिति और ट्रैकिंग और नोडल अधिकारियों की अधिसूचनाओं के लिए लॉगिंग की जा सके। ज़ाहिर है एनालॉग के दौर में यह व्यवस्था नहीं थी। अब डिजिटल व्यवस्था में तमाम शिकायतों का प्रभावी रूप से निवारण किया जाता है। ट्राई ने यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण निर्धारित समय के भीतर किया जाए।

ikjnf'kZrk d dkj.k bVh vkj ,lVh laxg e c<ksÙkjh % केबल टीवी डिजिटलीकरण के कारण पारदर्शिता आई है। अब किसी एमएसओ या केबल ऑपरेटर के लिए अपने ग्राहकों की संख्या को कम करके दिखाना संभव नहीं है। नीचे दी गई सारिणी से पता चलता है कि 11 राज्यों से प्राप्त मनोरंजन कर संग्रह के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इन राज्यों में ईटी संग्रह वर्ष 2012–13 में 188 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 448 करोड़ रुपये हो गया।

dfjt 'kYd e dVkSrh % जब से डिजिटल प्रणाली की क्षमता में वृद्धि हुई है तब से एमएसओ अपने सिस्टम पर वहन करने के लिए प्रसारकों से चैनलों की मांग कर रहे हैं और इस प्रकार एमएसओ द्वारा प्रसारकों पर लगाए जाने वाले कैरिज शुल्क की राशि में कमी आई है।

xkgdh 'kYd d jktLo e of) % डिजिटल प्रणाली में ग्राहक आधार में पारदर्शिता के कारण, प्रसारकों को एमएसओ/एलसीओ से प्राप्त होने वाले ग्राहकी शुल्क के राजस्व में वृद्धि देखने को मिली है।

dscy uVodZ ij eY;of/kr vkj fVªiy Iys lfoZlst d fy, vuqdwy fLFkfr % केबल टीवी नेटवर्क के डिजिटलीकरण के कारण, अब इस नेटवर्क का उपयोग एमएसओ/एलसीओ द्वारा उपभोक्ताओं को मूल्यवर्धित और ट्रिपल प्ले सर्विसेज़ प्रदान करने और अपने कारोबार को व्यापक बनाने के लिए अनुकूल स्थिति तैयार हो चुकी है। हालांकि फिलहाल केबल टीवी डिजिटलीकरण के किसी भी औपचारिक प्रभाव आकलन करना जल्दबाजी होगा, लेकिन प्रारंभिक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि डिजिटलीकरण से उपरोक्त प्रमुख लाभ होने शुरू हो चुके हैं।

Lkkeqnkf;d jsfM;ks

fogaxkoyksdu

सामुदायिक रेडियो, सार्वजनिक सेवा और वाणिज्यिक मीडिया से अलग, प्रसारण का महत्वपूर्ण तीसरा स्तर है। यह स्थानीय लोगों को, उनके जीवन से संबंधित मुद्दों को स्वर देने के लिए एक मंच मुहैया कराता है। पिछले कुछ वर्षों के

दौरान भारत में यह क्षेत्र धीरे–धीरे, लेकिन प्रभावी ढंग से वृद्धि कर रहा है। सामुदायिक रेडियो, वास्तव में, कम क्षमता के रेडियो स्टेशन हैं, जो स्थानीय समुदायों द्वारा स्थापित और संचालित किए जाते हैं। भारत में सीआरएस स्थापित करने की अनुमति केवल शैक्षणिक संस्थानों, कृषि संस्थानों और सामाजिक संगठनों जैसे गैर–लाभकारी संगठनों को प्रदान की गई हैं। सीआरएस स्थानीय समुदायों में स्थित हैं और इनका स्वामित्व और प्रबंधन स्वयं समुदायों द्वारा किया जाता है। यह उन्हें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि आदि स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की विशेष सुविधा देता है। इसके अलावा, सीआर क्षेत्र समाज के हाशिये पर मौजूद वर्गों को अपना पक्ष रखने का सशक्त माध्यम उपलब्ध कराता है।

यही नहीं, चूंकि प्रसारण स्थानीय भाषाओं और बोलियों में होता है, लोग फौरन इससे जुड़ने में समर्थ होते हैं। सामुदायिक रेडियो अपने समग्र दृष्टिकोण की वजह से विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को मजबूत करने की भी क्षमता रखता है। भारत जैसे देश में, जहां प्रत्येक राज्य की अपनी अलग भाषा और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, वहां सीआरएस स्थानीय लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत का संग्रह भी हैं। अनेक सीआरएस, भावी पीढ़ी के लिए स्थानीय गीतों को रिकॉर्ड और संरक्षित भी करते हैं और स्थानीय कलाकारों को समुदाय के समक्ष उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए मंच मुहैया कराते हैं। सकारात्मक सामाजिक बदलाव के साधन के रूप में सीआरएस की अनूठी स्थिति, इसे समुदाय के सशक्तीकरण का एक आदर्श उपकरण बना देती है। सामुदायिक रेडियो के लिए नीतिगत दिशानिर्देश और वर्तमान में संचालित सीआरएस की सूची https://mib.gov.in/all_broadcasting_documents पर देखी जा सकती है।

भारत सरकार ने 2002 में सुस्थापित शिक्षण संस्थानों को सीआरएस की स्थापना करने की अनुमति प्रदान करने की नीति मंजूर की थी। 2006 में, गैर–लाभकारी संस्थाओं को भी सीआरएस की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया, ताकि विकास और सामाजिक परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर सामाजिक संगठनों की व्यापक भागीदारी हो सके। वर्तमान में, 247 संचालित सीआरएस, 323 अनुमति प्रदान करने संबंधी समझौता (जीओपीए) धारक और 583 आशय–पत्र (एलओआई) धारक हैं।

सीआर प्रसारण ने आवेदन कार्यप्रणाली के सरलीकरण, आवेदनों की प्रोसेसिंग की पारदर्शिता में सुधार, मंजूरी की गति में तेजी, बेहतर समन्वय, जागरुकता बढ़ाने, हितधारकों के मध्य बेहतर तालमेल और सीआर के प्रसारण में अन्य मंत्रालयों की भागीदारी बढ़ाने जैसे कदम उठाकर भारत में सीआर के सार्थक विकास की ठोस नींव रखी है।

जुलाई 2018 में, 2019–2020 की अवधि के लिए 25 करोड़ रुपये के कुल आवंटन के साथ "भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता'' योजना जारी रखने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय को मंजूरी दी गई।

Hkkjr esa lhvkj,l dh fLFkfr

अब तक, 583 आवेदकों को आशयपत्र (एलओआई) जारी किए जा चुके हैं। इन 583 एलओआई धारकों में से 323 धारकों ने अनुमति प्रदान करने संबंधी समझौते (जीओपीए) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सीआरएस स्थापित करने की अनुमति देने के लिए करीब 275 नए आवेदन इस समय विचाराधीन हैं। अब तक, देश में 247 सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 110 सामाजिक संगठनों द्वारा, 122 शैक्षणिक

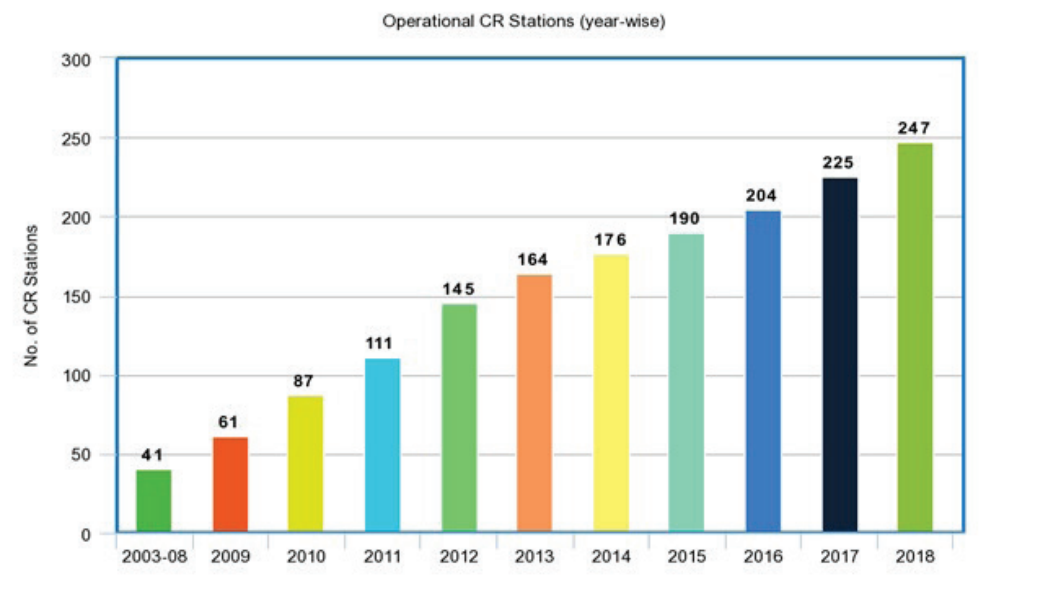

संस्थानों और 15 एसएयू/केवीके द्वारा संचालित हैं। संचालित सीआरएस की ग्राफिकल प्रस्तुति पिछले पृष्ठ पर है।

e=ky; dh vkj ls mBk, x, dne

midj.k ds fy, vuqnku % सामुदायिक रेडियो योजना को बढ़ावा देने तथा अधिक से अधिक संगठनों को सीआर स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास के तहत मंत्रालय ने उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान बढ़ाने का फैसला किया है। इसे अब 7.50 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ कुल अनुमानित खर्च के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अधिकतम अनुदान 7.5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ कुल अनुमानित खर्च

आइजोल, मिज़ोरम में सामुदायिक रेडियो जागरुकता कार्यशाला (6–8 फरवरी, 2019)

का 90 प्रतिशत होगा। अब तक वित्त वर्ष 2018–19 में 6 सीआर स्टेशनों को अनुदान जारी किया जा चुका है।

Hkkjr esa lhvkj,l ds izHkko ds ckjs esa v/;;u % सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के श्रोताओं, पहुंच और प्रभाव के बारे में अध्ययन किया गया। यह अध्ययन सामुदायिक रेडियो के प्रभाव और आस–पास के समुदाय तक इसकी पहुंच का आंकलन करने के लिए किया गया था। रिपोर्ट से पता चलता है कि सीआरएस जमीनी स्तर पर संचार का बहुत प्रभावी साधन रहा है। रिपोर्ट में सीआरएस की सफलता की कई कहानियों पर भी प्रकाश डाला गया है।

lkeqnkf;d jsfM;ks ij tkx#drk dk;Z'kkyk,a % भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन की सफलता के लिए जागरुकता उत्पन्न करना महत्वपूर्ण है, इसलिए मंत्रालय विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर जागरुकता कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से इस योजना का प्रचार करता है। ये कार्यशालाएं दिशानिर्देशों, अनुप्रयोग प्रक्रियाओं, सीआरएस के लिए सामग्री एवं निरंतरता संबंधी मामलों आदि से जुड़े मुद्दों का समाधान करने में सफल रही हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, विभिन्न स्थानों पर 5 कार्यशालाएं आयोजित की गईं। पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), आइजोल (मिजोरम), हैदराबाद (तेलंगाना), पणजी (गोवा) और धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)। एक अन्य कार्यशाला शिलांग (मेघालय) में आयोजित होने वाली है। कार्यशाला का उद्देश्य संभावित संगठनों के बीच सीआर नीति दिशानिर्देशों और योजनाओं के बारे में जागरुकता उत्पन्न करना और इन संगठनों को देश के दूरदराज के हिस्सों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करने में सहायता करना है।

इन कार्यशालाओं में विभिन्न क्षेत्रों के शैक्षणिक संस्थानों, गैर–सरकारी संगठनों और कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़े लगभग 200 संगठनों ने भाग लिया। कार्यशाला में स्थानीय मीडिया, पीआईबी, आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था। आयोजन सफल रहे हैं। इन कार्यशालाओं को विभिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कवरेज दिया गया था। प्रतिभागियों ने सामुदायिक रेडियो की अवधारणा और महत्व को समझा, और सीआर लाइसेंस के लिए आवेदन करने का वादा किया।

ykblsaflax çfØ;k dks vklku cukus vkSj lapkfyr lhvkj,l dh la[;k c<kus ds fy, uhfr fn'kkfunsZ'kksa esa la'kks/ku % अगस्त 2018 में नीति दिशानिर्देशों में संशोधन

धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक रेडियो जागरुकता कार्यशाला (24–26 अक्तूबर, 2018)

किया गया। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय (केंद्र और राज्य), सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल और कृषि विज्ञान केंद्रों (सरकार द्वारा संचालित) को एक ही स्थान पर मंजूरी (यानी सिंगल विंडो क्लीयरेंस) मिलेगी। कोई अलग मंजूरी पाना आवश्यक नहीं होगा। स्वायत्त निकायों और कृषि विश्वविद्यालयों सहित केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय, जिनमें एक से अधिक परिसर हों, उनको एक से अधिक स्थानों पर सीआरएस संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), शैक्षिक संस्थानों, और शाखा परिसर, यदि कोई हो तो, को जिस समुदाय में सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक हैं, वहां के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर ट्रांसमीटर और एंटीना लगाने की अनुमति दी जाएगी।

,Q,e iHkkx

1. एफएम रेडियो देशभर के युवाओं और वयस्कों के बीच मनोरंजन के पसंदीदा साधनों में से एक है। स्थानीय भाषाओं में विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली विविध प्रकार के कार्यक्रमों का जनता ने स्वागत किया है, जो हाल के वर्षों में चैनलों की संख्या में वृद्धि और जारी ई–नीलामी में निजी एफएम प्रसारकों द्वारा नए रेडियो चैनलों के अधिग्रहण के लिए दिखाए गए उत्साह से जाहिर है। यह स्थानीय कारोबारियों के लिए रेडियो विज्ञापनों के जरिए अपनी पहुंच बढ़ाने के एक संभावित माध्यम के रूप में भी उभर कर सामने आया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय निजी एफएम रेडियो का उपयोग सरकार के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में भी कर रहा है, महिला भेदभाव के खिलाफ जनता को जागरूक करने, और स्वच्छ भारत अभियान जैसे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों की पहुंच व्यापक बनाने के जिंगल शामिल हैं।

2. मंत्रालय का एफएम प्रकोष्ठ निजी एजेंसियों के चरण–3 के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार के बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 7 जुलाई, 2011 को अनुमोदित नीति दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में निजी एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित सभी मामलों की देखरेख करता है। ये दिशानिर्देश नवीनतम जानकारी के साथ मंत्रालय की वेबसाइट https://mib.gov.in/all_broadcasting_documents पर उपलब्ध हैं।

3. सरकार ने 12 शहरों, मुख्य रूप से राज्यों की राजधानियों में 21 एफएम रेडियो चैनलों के साथ जुलाई, 1999 में एफएम रेडियो क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोला था। 2005 में एफएम का चरण–2 शुरू किया गया था जिसमें 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों में निजी एफएम रेडियो के विस्तार का प्रावधान किया गया था। चरण–2 के तहत 26 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के 86 शहरों में 245 निजी एफएम चैनल शुरू हुए जिनमें से 21 चैनल प्रथम चरण से थे।

4 एफएम रेडियो की पहुंच को और बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने 25 जुलाई, 2011 को एफएम चरण–3 नीतिगत दिशानिर्देशों की घोषणा की, जिनका उद्देश्य एक लाख और उससे अधिक आबादी वाले सभी शहरों के अलावा

futh एफ.एम केन्द्रों के चरण 1, 2 और 3 की प्रस्तावित प्रचालिता

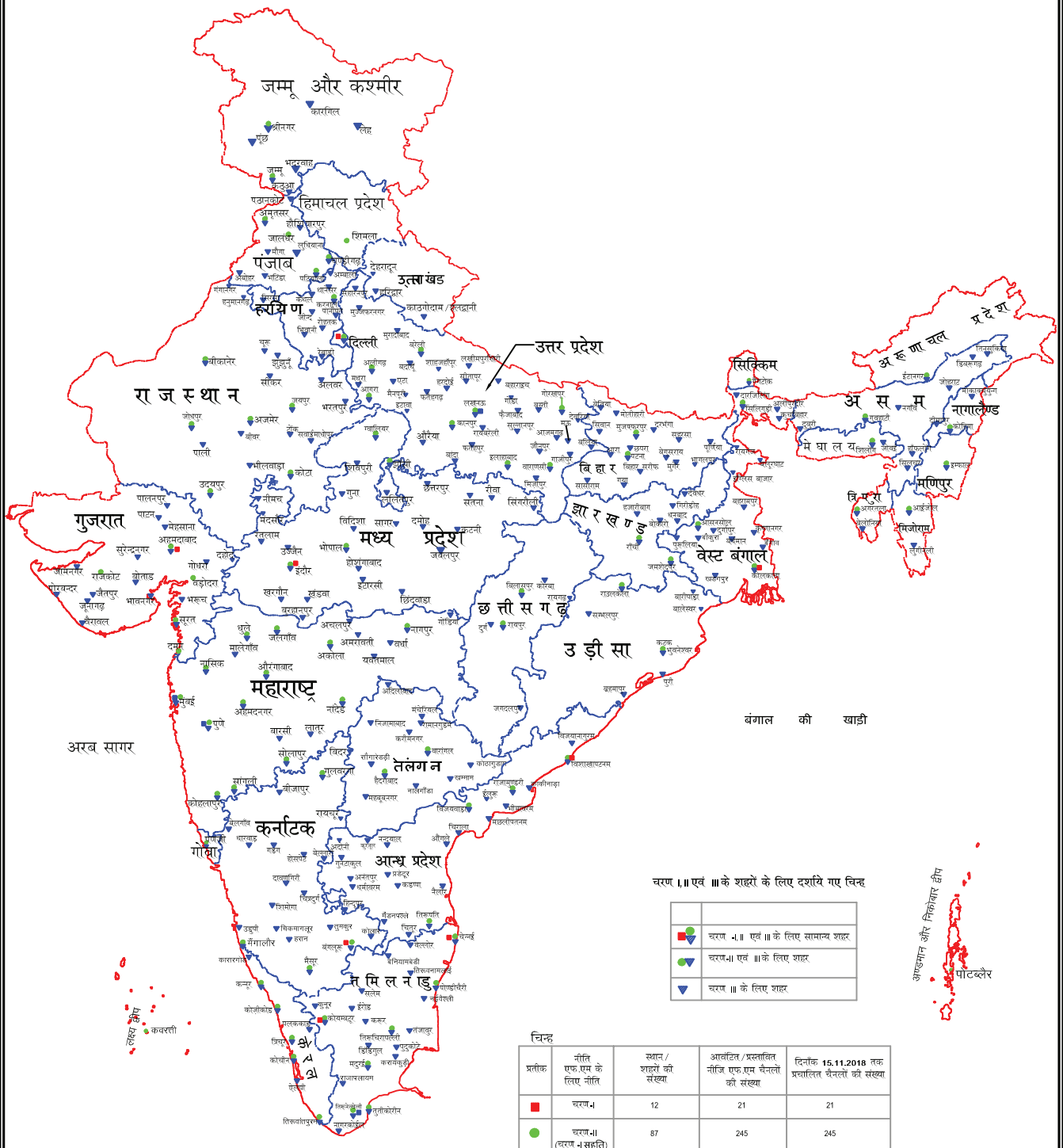

चिन्ह

प्रतीक	नीति एफ.एम के लिए नीति	स्थान / शहरों की संख्या	आवंटित / प्रस्तावित नीजि एफ.एम चैनलों की संख्या	दिनाँक 15.11.2018 तक प्रचालित चैनलों की संख्या
■	चरण-I	12	21	21
●	चरण-II (चरण -I सहित)	87	245	245
▼	चरण -III (चरण -II सहित)	101 (कुल परिसंपत्ति 313)	395 (कुल परिसंपत्ति 839)	369

THIS DRAWING IS COPYRIGHT AND THE PROPERTY OF "B E C I L" AND IS NOT TO BE REPRODUCED, COPIED HANDED OVER TO A THIRD PARTY OR USEDFOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT FOR WHICH IT HAS BEEN ISSUED.

Map No. BECIL/FM/E&P/STATION/001/A

BECIL
BROADCAST ENGINEERING CONSULTANTS INDIA LIMITED
HEAD OFFICE:- 14-B, RING ROAD, I. P. ESTATE, NEW DELHI-110 002 (INDIA),
Tele:- 2337 8823, Fax No. 2337 9885

जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के एक लाख से कम आबादी वाले 11 सीमावर्ती शहरों में एफएम रेडियो का विस्तार करना था। एफएम रेडियो चरण–3 के तहत ई–नीलामी के 2 बैच पूरे होने के बाद, मंत्रालय ने देशभर में 162 और चैनल जोड़े हैं। देहरादून से 11–07–2018 को एक निजी एफएम चैनल का संचालन शुरू होने के साथ ही उत्तराखंड ने निजी एफएम रेडियो मानचित्र पर पहली बार अपनी जगह बनाई। सरकार एफएम चरण–3 के बाद के बैचों में 263 शहरों में 683 और चैनलों के लिए ई–नीलामी आयोजित करने की प्रक्रिया में है।

5. संलग्न किए गए मानचित्र में उन शहरों को दर्शाया गया है, जहां निजी एफएम चैनल संचालित किए जा रहे हैं। इसमें एफएम चरण–3 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित शहरों को भी दर्शाया गया है। 31 मार्च, 2019 तक, देश के 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 103 शहरों में 374 एफएम रेडियो चैनल चालू हैं।

पारदर्शिता के उपाय और निगरानी

6. एफएम रेडियो चैनल कंपनियों को बढ़ते ई–नीलामी के आधार पर आवंटित किए गए हैं। निजी प्रसारकों से तिमाही लाइसेंस शुल्क के रूप में वसूला जाने वाला राजस्व भारतकोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जाता है। मंत्रालय ने राजस्व संग्रह व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) टीम के साथ मिलकर प्रसारकों के लिए एक व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया।

7. पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, प्रसारण सेवाओं का डिजिटलीकरण भी एक ऑनलाइन पोर्टल "ब्रॉडकास्ट सेवा" के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

8. निजी प्रसारकों द्वारा हस्ताक्षरित एफएम चरण–3 के नीतिगत दिशानिर्देशों और अनुमति प्रदान करने संबंधी समझौता (जीओपीए) में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के एफएम प्रकोष्ठ अधिकारी रेडियो स्टेशनों और कॉमन ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीटीआई) सुविधाओं का निरीक्षण करते हैं।

सरकार को मिलने वाले राजस्व में वृद्धि

9. सरकार निजी प्रसारणकर्ताओं से अप्रतिदेय एकमुश्त प्रवेश शुल्क, प्रवासन शुल्क और वार्षिक लाइसेंस शुल्क के माध्यम से राजस्व प्राप्त करती है।

10. वित्त वर्ष 2018–19 की पहली तीन तिमाही के दौरान, सरकार ने 15 नवंबर, 2018 तक 129.27 करोड़ रुपये (लगभग) राजस्व की प्राप्ति की।

11. सरकार ने देश में वर्ष 2000 से निजी एफएम रेडियो प्रसारण के माध्यम से अप्रतिदेय एकमुष्त प्रवेष शुल्क, प्रवासन शुल्क और वार्षिक लाइसेंस शुल्क के जरिए लगभग 5743 करोड़ रुपये (लगभग) का कुल राजस्व प्राप्त किया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

सालाना लाइसेंस शुल्क	एकमुश्त प्रवेश शुल्क	प्रवासन शुल्क	कुल
1497.55 करोड़	1993.63 करोड़	2252.74 करोड़	5744 करोड़

प्रसार भारती

प्रसार भारती, देश में लोक सेवा प्रसारक है। उसके दो संघटक–आकाशवाणी और दूरदर्शन हैं। प्रसार भारती 23 नवंबर, 1997 को अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य जनता को सूचना देने, शिक्षित करने और उसका मनोरंजन करने वाली लोक प्रसारण सेवाओं का आयोजन और संचालन करना तथा देश में प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।

उद्देश्य

- देश की एकता, अखंडता और देश के संविधान द्वारा संस्थापित मूल्यों को बनाए रखना।
- राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।
- लोक हित के सभी मामलों की सूचना पाने के नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना और निष्पक्ष और संतुलित सूचना प्रदान करना।
- शिक्षा और साक्षरता के प्रसार, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना,
- महिलाओं से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरुकता फैलाना और बच्चों, वृद्धों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना।
- विभिन्न संस्कृतियों, खेलों और युवा मामले को समुचित कवरेज प्रदान करना।
- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और कामगारों व अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और
- शोध को बढ़ावा देना और प्रसारण सुविधाओं का विस्तार और प्रसारण तकनीक का विकास करना।

çlkj Hkkjrh ckM

प्रसार भारती निगम, प्रसार भारती बोर्ड द्वारा चलाया जाता है जिसमें एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य (जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है), सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक), छह अंशकालिक सदस्य, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक पदेन सदस्यों के रूप में और निगम के कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रसार भारती अध्यक्ष अंशकालिक सदस्य होता है, जिसका कार्यकाल तीन साल और सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष होती है। कार्यकारी सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होता है जिसका कार्यकाल पांच वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) भी पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल छह वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है।

2018–19 के दौरान और वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड की संरचना निम्नलिखित है :

1) डॉ. ए सूर्य प्रकाश	अध्यक्ष
2) श्री शशि शेखर वेम्पति	कार्यकारिणी सदस्य
3) रिक्त	सदस्य (कार्मिक)
4) श्री राजीव सिंह	सदस्य (वित्त)
5) श्री अली आर. रिजवी ए.एस. एवं वित्तीय सलाहकार	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि
6) श्री सुनील अलघ	अंशकालिक सदस्य
7) श्री अशोक कुमार टंडन	अंशकालिक सदस्य
8) श्रीमती काजोल	अंशकालिक सदस्य
9) रिक्त	अंशकालिक सदस्य
10) रिक्त	अंशकालिक सदस्य
11) रिक्त	अंशकालिक सदस्य
12) श्री एफ. शहरयार, महानिदेशक	आकाशवाणी पदेन सदस्य
13) श्रीमती सुप्रिया साहू, महानिदेशक	दूरदर्शन पदेन सदस्य

lxBukRed <kpk

निगम के मामलों का सामान्य संचालन, निर्देशन और प्रबंधन प्रसार भारती बोर्ड करता है। बोर्ड समय–समय पर बैठकें करता है और महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार–विमर्श करता है, महत्वपूर्ण नीतियां तय करता है और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश देता है। कार्यकारी सदस्य निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्य करते हैं और बोर्ड का नियंत्रण और निरीक्षण करते हैं और बोर्ड के ऐसे अधिकारों का उपयोग तथा ऐसे कार्यों का संपादन करते हैं जो बोर्ड उन्हें सौंपता है।

दो महानिदेशक आकाशवाणी महानिदेशालय और दूरदर्शन महानिदेशालय के प्रमुख होते हैं। वे बोर्ड के नीतिनिर्देशों और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की रोज़मर्रा के मामलों के प्रबंधन के लिए सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक) और सीईओ के सहयोग से कार्य करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में, विभिन्न गतिविधियों, जैसे कार्यक्रम, इंजीनियरिंग, प्रशासन और वित्त के लिए मोटे तौर पर चार अलग–अलग स्कंध हैं।

çlkj Hkkjrh d vrjjk"Vh; lc/k

प्रसार भारती का अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रभाग अन्य देशों/संगठनों आदि के साथ समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर, सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों (सीईपी) से संबंधित मामलों का कार्यान्वयन, आतिथ्य, अन्य देशों के गणमान्य व्यक्तियों की यात्राओं का समन्वय, देश में कार्यशालाओं/सम्मेलनों/कार्यक्रमों का आयोजन; अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों सम्मेलनों, प्रशिक्षण–कार्यशालाओं आदि में भाग लेने जैसी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों को संभालता करता है।

o"k d nkjku gLrk{kfjr le>krk Kkiu ¼,evk;½

वर्ष 2018–19 के दौरान, बांग्लादेश बेतार, बांग्लादेश, मंगोलियन नेशनल ब्रॉडकास्टर (एमएनबी), मंगोलिया, मिज़िमा मीडिया को. लिमिटेड, म्यांमार, जॉर्डन रेडियो और टेलीविजन, कोरियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, ज़िम्बाब्वे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (जेडबीसी), ज़िम्बाब्वे नेशनल टीवी एंड रेडियो कम्पनी उज़्बेकिस्तान के साथ प्रसारण और आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग और सहकार्यता के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के परामर्श से देशों के बीच एमओयू/सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों (सीईपी) के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए।

dk;Øek dk lg&fuek.k ¼ प्रसार भारती और ईबीएस, कोरिया के बीच "डिजिटल वेव" नामक एक संयुक्त सह–निर्माण कार्यक्रम का निर्माण किया गया, जिसके लिए ईबीएस ने प्रसार भारती को 7000 डॉलर और जीएसटी के वित्तपोषण की पेशकश की।

dkEed@çf'k{k.k dk vknku&çnku ¼ भारत में उज़्बेकिस्तान के राजदूत के अनुरोध पर मीडिया कंपनी रेडियो

एंड टीवी के कर्मचारियों को टेलीप्रॉम्प्टर का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु प्रसार भारती के दो अधिकारियों को उज़्बेक कर्मियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए नामित किया गया। प्रसार भारती/आकाशवाणी ने एनएचके रेडियो जापान की हिंदी सेवा के लिए अगले "हिंदी भाषा प्रसारण विशेषज्ञ" के चयन के लिए समन्वय किया। नया अधिकारी अगले साल एक साल की प्रतिनियुक्ति पर एनएचके वर्ल्ड से संबद्ध हो जाएगा।

dk;Øe@lkexh dk vknku&çnku % भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए 5 भारतीय टीवी कार्यक्रमों– मालगुडी डेज़, तहरीर, महात्मा–द ग्रेट सोल, मुल्ला नसरुद्दीन और चेखोव की दुनिया वाली एक हार्ड डिस्क मिस्र के सरकारी टीवी को उसके नेटवर्क्स पर प्रसारित करने के लिए भेजी गयी। लता मंगेशकर, मो. रफी, मुकेश, पंकज उधास आदि भारतीय गायकों पर 13 गीत कार्यक्रमों वाली एक हार्ड डिस्क फिजी ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (एफबीसी), फिजी को भेजी गई। दो कार्यक्रमों "डेस्टिनेशन हिमालयाज़" और "वर्ल्ड हेरिटेज (मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया)" वाली एक एक हार्ड डिस्क ताजिक पक्ष के साथ साझा करने के लिए ताजिकिस्तान दूतावास को भेजी गई।

,f'k;k&iflfQd czkMdkfLVax ;wfu;u ¼,ch;w½ rFkk ,f'k;k&iSlfQd bULVhV~;wV QkWj czkMdkfLVax Moyiesa V ¼,vkbZchMh½ xfrfof/k;k¡

प्रसार भारती (आकाशवाणी) एबीयू के संस्थापक सदस्यों में से एक है और उसने एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रसारण के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी विभिन्न तकनीकी गतिविधियों में बहुत योगदान दिया है। आकाशवाणी ने एबीयू रेडियो अवाड्र्स 2018 में भाग लिया और एबीयू प्राइज 2018 की ऑन–एयर पर्सनैलिटी केटेगरी में "राइडिंग ऑन एआईआर" शीर्षक वाले उसके एक फ़ीचर कार्यक्रम को 'विशेष प्रशंसा' मिली, जिसका निर्माण आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग, नई दिल्ली की प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव सुश्री मोनिका गुलाटी ने किया था।

प्रसार भारती एआईबीडी की गतिविधियों में भी बहुत सक्रिय है। एआईबीडी की ओर से नेशनल अकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीमीडिया (एनएबीएम) द्वारा एशिया–प्रशांत क्षेत्र के प्रतिभागियों के लिए कई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए गए हैं। आकाशवाणी की "फ्रॉम स्लम टू ग्लोरी" प्रविष्टि ने एआईबीडी रेडियो अवाड्र्स 2018 की 'डाइवर्सिटी थ्रू स्पोर्ट्स' श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता। इसका निर्माण आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल की प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव सुश्री शर्मिला गोस्वामी ने किया था। इस पुरस्कार में 500 डॉलर का नकद पुरस्कार, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण–पत्र शामिल था। आकाशवाणी ने 30वें यूआरटीआई इंटरनेशनल रेडियो ग्रां प्री 2018 अवार्ड में भी भाग लिया।

श्रीलंका के कोलंबो में 2 से 4 अगस्त, 2018 को आयोजित 17वें वार्षिक आम सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले महानिदेशक श्री एफ. शहरयार को एशिया–पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) का अध्यक्ष चुना गया।

तुर्कमेनिस्तान के अश्गाबात में 30 सितंबर से 5 अक्तूबर, 2018 तक आयोजित एशिया–पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (एबीयू) की 55वीं महासभा और संबद्ध बैठकों में आकाशवाणी को एबीयू की तकनीकी समिति के लिए भी चुना गया।

आकाशवाणी को मई 2018 में दिल्ली में एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन 2018 के आयोजन की जिम्मेदारी भी दी गई। इसके लिए तारीखों का चयन, स्थल का चयन, लागत का अनुमान, आदि प्रारंभिक कार्य प्रसार भारती द्वारा किए गए। हालाँकि, शिखर सम्मेलन का आयोजन बाद में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के सहयोग से 10 से 12 मई, 2018 को नई दिल्ली के होटल ताज डिप्लोमैटिक एन्क्लेव में किया। प्रसार भारती ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए मानव संसाधन तैनात करने सहित मंत्रालय को सभी प्रकार की सहायता प्रदान की।

,ch;w bVju'kuy Mkal QfLVoy 2019 % प्रसार भारती/दूरदर्शन को नई दिल्ली में 7–9 मार्च, 2019 को द्वितीय एबीयू अंतरराष्ट्रीय नृत्य महोत्सव की मेजबानी का सम्मान प्राप्त हुआ है। यह डीडी/पीबी के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन और दुनियाभर की सांस्कृतिक विविधताओं को पारदर्शी, रचनात्मक तरीके से लाइमलाइट में लाने का प्रयास है। आयोजन की तैयारी चल रही है।

o"kZ 2018&19 ds nkSjku vUrjjk"Vªh; vk;kstuksa dh lwph ftuesa izlkj Hkkjrh us Hkkx fy;k

Øe la-	vk;kstu dk uke	vof/k	LFkku@ns'k
1	एबीयू मध्य वर्ष की प्रशासनिक परिषद की बैठक	4–5 मई, 2018	ताशकंद, उज्बेकिस्तान
2	अंतरराष्ट्रीय सह–निर्माण सम्मेलन–2018	28 जून, 2018	सियोल, दक्षिण कोरिया

3	एबीयू रेडियो एशिया सम्मेलन, रेडियो गीत समारोह, मीडिया 2020 सम्मेलन	10–12 जुलाई, 2018	अस्ताना, कज़ाकिस्तान
4	ग्लोबल न्यूज़ फोरम (जीएनएफ) –2018	24–25 जुलाई, 2018	वियतनाम
5	44वीं वार्षिक सभा/17वीं एआईबीडी आम सम्मेलन और संबद्ध बैठकें	02–04 अगस्त, 2018	कोलंबो, श्रीलंका
6	एआईबीडी पुरस्कार–2018	02 अगस्त, 2018	कोलंबो, श्रीलंका
7	11वां विश्व हिंदी सम्मेलन	18–20 अगस्त, 2018	मॉरीशस
8	आईसीटी विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम	19 अगस्त से 8 सितंबर, 2018	सियोल, दक्षिण कोरिया
9	ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग कोर्स	20 अगस्त से 6 सितंबर, 2018	सियोल, दक्षिण कोरिया
10	अंतरराष्ट्रीय प्रसारण सम्मेलन (आईबीसी)–2018	14–18 सितंबर, 2018	एम्स्टर्डम, नीदरलैंड
11	एबीयू महासभा और संबद्ध बैठकें–2018	30 सितंबर–5 अक्तूबर, 2018	अश्गाबात, तुर्कमेनिस्तान
12	एबीयू टीवी सॉन्ग फेस्टिवल	02 अक्तूबर, 2018	अश्गाबात, तुर्कमेनिस्तान
13	एनएबी शो –2018	17–18 अक्तूबर, 2018	न्यूयॉर्क, अमेरिका
14	2018 इंडियन नेक्स्ट–जेनरेशन लीडर्स	21–27 अक्तूबर, 2018	दक्षिण कोरिया
15	प्रसारण के माध्यम से जेंडर के मामलों पर नए दृष्टिकोण पर एआईबीडी/होसो बुका फाउंडेशन (एचबीएफ) क्षेत्रीय कार्यशाला	11–4 दिसंबर, 2018	कुआलालम्पुर, मलेशिया

vkdk'kok.kh

dk;Øe xfrfof/k;k

,- egRoi.kZ lh/kk izlkj.k

- 20 अप्रैल, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली से माननीय उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू की उपस्थिति में सिविल सेवा दिवस के उद्घाटन सत्र का सीधा प्रसारण।
- 21 अप्रैल, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली से सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2018 का सीधा प्रसारण।
- 23 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से रक्षा निवेश समारोह–2 का सीधा प्रसारण।
- 3 मई, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली से माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की उपस्थिति में आयोजित 65वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्रस्तुतिकरण समारोह का सीधा प्रसारण।
- 15 मई, 2018 को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव और चुनाव परिणाम के संबंध में लाइव रेडियो ब्रिज द्विभाषी चर्चा (एनएसडी कार्यक्रम)।
- 20 जून 2018 को कृषि विकास केंद्रों के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की बातचीत का सीधा प्रसारण।
- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 2018 के अवसर पर 21 जून, 2018 को वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन समारोह का सीधा प्रसारण।
- 12 जुलाई, 2018 को तिलक मार्ग, नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए भवन के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।

नई दिल्ली में 28 सितंबर, 2018 को अमेजन अलेक्सा स्मार्ट स्पीकर्स पर ऑल इंडिया रेडियो की स्ट्रीमिंग सेवा आरंभ होने के अवसर पर संबोधन करते हुए युवा मामले एवं खेल मामले तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। साथ में हैं, प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ. ए. सूर्य प्रकाश, प्रसार भारती के सीईओ डॉ. शशि शेखर वेम्पती और एआईआर के महानिदेशक श्री एफ. शहरयार

- 15 जुलाई, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली से कॉस्ट एंड वर्क एकाउंटेंट्स (आईसीडब्ल्यूए) के प्लेटिनम जुबली वर्ष समारोह का सीधा प्रसारण, माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की उपस्थिति ने इस समारोह की शोभा में चार चांद लगाए।
- स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद का राष्ट्र के नाम संबोधन।
- 5 सितंबर, 2018 को माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू की उपस्थिति में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह–2017 का सीधा प्रसारण।
- 7 सितंबर, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा "ग्लोबल मोबिलिटी समिट–2018" के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।
- 07 सितंबर, 2018 को प्रवासी भारतीय केंद्र, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सम्मानित करने के लिए आयोजित किए जा रहे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण (यूएनईपी) चैंपियंस ऑफ़ अर्थ अवार्ड प्रस्तुतिकरण समारोह का सीधा प्रसारण।
- 3 अक्तूबर, 2018 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से मुख्य न्यायाधीष न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण।
- 10 अक्तूबर, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली से सीआईएसएफ के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के समापन समारोह का सीधा प्रसारण।

ch- vU; egRoi.k dojt@ilkj.k

- 6 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रमंडल खेल 2018 पर विशेष रिपोर्ट।
- 10 अप्रैल, 2018 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के गांधी मैदान में स्वच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण की रिकॉर्डिंग।
- 12 अप्रैल, 2018 को महाबलीपुरम, तमिलनाडु में डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन पर माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण की रिकॉर्डिंग।
- 21 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सिविल सेवा दिवस पर एक समेकित रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण।
- 16 जून, 2018 को "जन सेवा संवाद" के तहत रेल मंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ साक्षात्कार का प्रसारण।
- 7 जुलाई, 2018 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ साक्षात्कार का प्रसारण।
- दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 27 जुलाई, 2018 को आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन की रिकॉर्डिंग।
- 11 अगस्त, 2018 को आईआईटी मुंबई के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन की रिकॉर्डिंग।

lh- jfM;k fjikVZ

- 9 से 12 अप्रैल, 2018 को इंदौर में आयोजित 8वें रीजनल 3 आर फोरम इन एशिया एंड पेसेफिक 2018 पर समेकित रेडियो रिपोर्ट।
- 20 अप्रैल, 2018 को सिविल सेवा दिवस 2018 के अवसर पर प्रथम दिवस की कार्यवाही की रिपोर्ट।
- 30 जुलाई, 2018 को चेन्नई में आयोजित डब्ल्यूएसएफ वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप–2018 पर रेडियो रिपोर्ट।
- भारत के 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला, नई दिल्ली की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन सहित ध्वजारोहण समारोह पर रेडियो रिपोर्ट।

10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर नवीन सुविधाओं से युक्त, ऑल इंडिया रेडियो, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश के लोकल रेडियो स्टेशन का उद्घाटन करते माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू

Mh- Likdu oM

वर्ष 2018–19 के दौरान आकाशवाणी 471 स्टेशनों के अपने नेटवर्क पर सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को समर्थन देता है। स्पोकन वर्ड डिवीजन भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के महत्वपूर्ण विषय/योजनाओं/नीतियों के प्रचार से संबंधित है। आकाशवाणी के देशभर के सभी स्टेशनों द्वारा अप्रैल, 2018 से अक्तूबर, 2018 की अवधि के लिए कार्यक्रम के विभिन्न प्रारूपों के माध्यम से निम्नलिखित सरकारी योजनाओं का नियमित प्रचार किया गया :

1 एक भारत श्रेष्ठ भारत और स्वच्छ भारत अभियान दो प्रमुख अभियान हैं, जिनकी शुरुआत के बाद से ही सभी आकाशवाणी केंद्र इन योजनाओं लगातार का व्यापक रूप से प्रचार कर रहे हैं। मंत्रालय को नियमित रूप से कृत कार्रवाई रिपोर्ट्स उपलब्ध कराई जा रही हैं।

2. सरकार की प्रमुख योजनाओं में निम्नलिखित 27 योजनाएं शामिल हैं जिनका प्रचार किया गया और जो अब तक जारी है।

3. सरकार की उपलब्धि को हाईलाइट करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए।

4. देश में भीड़ द्वारा हत्याओं पर रोक लगाने के लिए निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले का व्यापक प्रचार किया गया।

5. विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के निम्न अभियानों का प्रचार किया गया : –

i. कपड़ा मंत्रालय–आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत वस्त्र आदेश 2001।

ii. पर्यटन मंत्रालय–16.09.2018 से 27.09.2018 तक 'पर्यटन पर्व'।

iii. रक्षा मंत्रालय–सशस्त्र बल झंडा दिवस।

iv. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–मानव अधिकार पर लघु फ़िल्मों की वार्षिक प्रतियोगिता–स्लोगन/टैगलाइन/लोगो प्रतियोगिता।

v. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय– डिजिटल इंडिया और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरुकता।

vi. जल संसाधन मंत्रालय– स्वच्छता ही सेवा।

6.. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न दिनों/सप्ताहों पर आयोजित कार्यक्रमों/आयोजनों/गतिविधियों जैसे साक्षरता दिवस, योग दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, सिविल सेवा दिवस, सतर्कता जागरुकता सप्ताह, महिला दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस आदि के लिए प्रचार।

7. विभिन्न विषयों/विधेयकों पर लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों से प्राप्त अधिसूचना/घोषणाओं का प्रचार किया गया।

8. विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा और अमरनाथ यात्रा 2018 का व्यापक प्रचार किया गया।

9. 25 अक्तूबर, 2018 को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र के सभागार में ''ड्रीम इंडिया 2030–अवायडिंग द पिटफाल्स'' विषय पर सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल द्वारा दिया गया। इसका प्रसारण 31 अक्तूबर, 2018 को राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया गया।

10. सरदार पटेल, डॉ. बी. आर. अंबेडकर और अन्य नेताओं के शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों/समारोहों का प्रचार किया गया। सरदार पटेल की शताब्दी को "राष्ट्रीय एकता दिवस" के रूप में मनाया गया। गुजरात में सरदार सरोवर बांध, केवडिया में सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण जैसे कार्यक्रमों को समुचित प्रचार और कवरेज प्रदान की गई।

11. मेगा प्रोजेक्ट (संस्कार गीत) – आकाशवाणी ने एक व्यक्ति के जीवनकाल में विभिन्न चरणों से जुड़े अनुष्ठानों के आधार पर गाने रिकॉर्ड करने की एक परियोजना शुरू की है। यह योजना अभी जारी है।

12. प्रसार भारती को मासिक कैबिनेट सारांश हर महीने भेजा गया, ताकि वह समय–सीमा के भीतर इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेज सके।

13. सूचना और प्रसारण मंत्रालय/प्रसार भारती को समय–समय पर प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम सहित विभिन्न विषयों पर रिपोर्ट भेजी जाती है।

b½ ljnkj iVsy Lekjd 0;k[;ku

यह व्याख्यानमाला स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में 1956 से आयोजित की जा रही है। इस व्याख्यानमाला में जाने–माने विद्वानों, प्रशासकों, न्यायविदों, इतिहासकारों, सामाजिक चिंतकों, अर्थशास्त्रियों आदि विशिष्ट व्यक्तियों को उनके द्वारा चुने हुए विषय पर आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष अंग्रेजी में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रथम व्याख्यान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल डॉ. सी. राजगोपालाचारी ने दिया था। उसके बाद से व्याख्यान देने वालों में भारत के प्रधान न्यायाधीश श्री पी. एन. भगवती, जाने–माने इतिहासकार प्रोफेसर बिपिन चंद्र एवं प्रोफेसर रोमिला थापर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन सहित अनेक विशिष्टजन शामिल रहे हैं।

वर्ष 2018 के लिए सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान 25 अक्तूबर, 2018 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल द्वारा ^^Mhe bfM;k 2030&vok;fMx n fiVQkYl^^ विषय पर दिया गया। इस व्याख्यान की रिकार्डिंग 31 अक्तूबर, 2018 को रात 9.30 बजे आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित की गई।

,Q½ vkdk'kok.kh ykd laink laj{k.k egkifj;kstuk ¼laLdkj xhr½

,d fo'kky ifj;kstuk vkdk'kok.kh ykd laink laj{k.k नवंबर 2014 को शुरू की गई थी। आकाशवाणी ने हमारी लोक विरासत और 6000 जातियों, उपजातियों और भारत के जनजातीय समुदाय की विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक विशेष परियोजना शुरू की है। भारत अपनी जातीय–भाषाई विविधता के लिए विलक्षण है। इसके सभी प्रकार के रंग–रूप को उसकी सांस्कृतिक मोजेक के साथ समाहित करना कठिन कार्य है। यह कई क्षेत्रों, समुदायों और संस्कृतियों की प्रचुर और समृद्ध लोककथाओं में सबसे अच्छी तरह से परिलक्षित होता है। शानदार गीत और धुनों की एक अलग महक है, लेकिन इनके विलुप्त होने का खतरा है। देश के लोक सेवा प्रसारक के रूप में आकाशवाणी ने इस दिशा में कदम उठाने और लोकगीतों एवं रस्मी गीतों को उनकी प्राचीन शुद्धता में रिकॉर्ड करने का निर्णय लिया है।

आकाशवाणी की इस परियोजना के अंतर्गत (1) विभिन्न अनुष्ठानों (संस्कारों) – किसी व्यक्ति के जीवन में विभिन्न चरणों/ऐतिहासिक अवसरों से संबद्ध गीतों (2) ऋतु गीत, पर्व गीत, शर्म गीत, नदी गीत, वृक्ष गीत, स्थल गीत, पर्वत गीत और आंदोलन गीत जैसे विभिन्न प्रकार के लोक गीतों और (3) लोक गाथाओं (आख्यानों) की रिकार्डिंग शामिल है। आने वाली संततियों के लिए भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में आकाशवाणी की कई प्रमुख उपलब्धियों में एक यह भी शामिल है।

आकाशवाणी के लगभग 130 स्टेशनों द्वारा गानों की रिकॉर्डिंग की गई है और इन्हें 150 जिलों और 155 भाषाओं और बोलियों में तैयार किया गया है। यहूदी धर्म के अतिरिक्त सभी जातियों, उप–जातियों और जनजातियों के सभी अनुष्ठानों से संबंधित गीत रिकॉर्ड किए गए हैं।

इस प्रक्रिया के अंतर्गत 87 भाषाओं/बोलियों में लगभग 25,000 संस्कार गीत और परंपरागत लोकगीत रिकार्ड किए गए हैं और आकाशवाणी ध्वनि अभिलेखागार में संरक्षित किए गए हैं। इन गीतों का अभिलेखीय महत्व देखते हुए, संस्कृति मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली और साहित्य अकादमी ने आकाशवाणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तीनों संगठनों ने इन गीतों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। इसी तर्ज़ पर साहित्य अकादमी ने 10 भाषाओं/बोलियों में पुस्तकों के प्रकाशन का काम शुरू कर दिया है, जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने पूर्वोत्तर की विभिन्न भाषाओं/बोलियों में रस्मी/पारंपरिक गीतों को प्रकाशित करने की पेशकश की है।

th½ vkdk'kok.kh okf"kZd iqjLdkj

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार– 2017, गांधी दर्शन और लोक सेवा प्रसारण पुरस्कार– 2018 के लिए जूरी सत्र पूरा हो गया और पुरस्कार प्रस्तुतिकरण समारोह का आयोजन जनवरी– 2019 में प्रस्तावित है।

,p½—f"k vkSj x`g çlkj.k

आकाशवाणी पांच दशक से अधिक समय से अपने ग्रामीण श्रोताओं के प्रति समर्पित है। आकाशवाणी के सभी केंद्रों द्वारा कृषि और गृह कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इनके अंतर्गत कृषक समुदाय की रोज़मर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए कार्यक्रम डिजाइन किए जाते हैं, जिनमें उत्कृष्ट कृषि पैदावार के लिए अद्यतन जानकारी और प्रौद्योगिकी शामिल की जाती है।

आकाशवाणी ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के सहयोग से फरवरी, 2004 में 'किसानवाणी' शीर्षक से —f"k foLrkj esa tulapkj ek/;e lgk;rk की एक विशिष्ट परियोजना शुरू करते हुए अपने कृषि प्रसारणों का विस्तार किया। इसका उद्देश्य स्थानीय किसानों को रोज़मर्रा के बाज़ार भावों से अवगत कराना, मौसम संबंधी ख़बरें और उनके क्षेत्रों से संबद्ध रोज़मर्रा की जानकारी सूक्ष्म स्तर तक पहुंचाना है। वर्तमान में 'किसानवाणी' कार्यक्रम देशभर में चुने हुए 96 आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया जा रहा है। नैरो कास्टिंग मोड पर प्रसारित यह कार्यक्रम अधिकतर वार्तालाप आधारित होता है, जिसमें किसानों के खेतों पर आधारित रिकार्डिंग और स्टूडियो में विशेषज्ञों और कृषक समुदाय के बीच फोन के जरिए वार्तालाप शामिल किए जाते हैं, जो लक्षित श्रोताओं में अत्यंत लोकप्रिय हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से सितंबर, 2018 से, किसानवाणी की तर्ज़ पर एक नया कृषि कार्यक्रम 'किसान की बात', शुरू किया गया है और इसे आकाशवाणी, दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से प्रसारित किया जा रहा है।

,- dhVuk'kdksa ds lqjf{kr vkSj ;qfDrlaxr bLrseky ds ckjs esa vfHk;ku

क आम लोगों और विशेष रूप से कृषक समुदाय में जागरुकता पैदा करने के लिए कीटनाशकों के सुरक्षित और युक्तिसंगत इस्तेमाल तथा फलों और सब्जियों के इस्तेमाल से पहले कीटनाशकों के अवशेष न्यूनतम करने के तौर–तरीकों के बारे में कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं।

ख. इस बारे में आकाशवाणी केंद्रों को व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें कीटनाशकों की खरीद, भंडारण, परिचालन और छिड़काव करते समय किसानों के लिए विधि–निषेधों का व्यापक ब्योरा शामिल है। खाद्य वस्तुओं, फलों और सब्जियों में कीटनाशकों के अवशेष कम से कम करने के बारे में उपभोक्ताओं और नागरिकों के लिए भी विधि–निषेध आकाशवाणी केंद्रों द्वारा अपने कार्यक्रमों में शामिल किए गए।

ch- fdlkuksa ds fy, lexz ekSle iwokZuqeku

क. आकाशवाणी के सभी केंद्रों 'किसानवाणी' कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले सभी 96 केंद्रों के दैनिक कृषि एवं गृह कार्यक्रमों में किसानों को 5 मिनट के बुलेटिन के रूप में मौसम के समग्र पूर्वानुमान की जानकारी दी जाती है। दैनिक मौसम पूर्वानुमान कवरेज के अंतर्गत वर्षा, तापमान, मृदा और वायु में नमी, रेडिएशन, गर्म, शुष्क, शीत और आर्द्र चक्रों और

सूखा, बाढ़, ओला वृष्टि, तूफान, आंधी, पाला आदि अतिवादी स्थितियों की जानकारी शामिल होती है ताकि किसानों को सचेत किया जा सके और फसल के नुकसान को कम करने में मदद की जा सके।

lh- i;kоj.k

क. आकाशवाणी के सभी केंद्रों में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। सामाजिक वानिकी, भू–कटाव और मरुस्थलीकरण रोकने, ओजोन ह्रास, फसल कटाई के बाद पराली का प्रबंधन जैसी पारिस्थितिकी के अनुकूल कृषि पद्धतियां, जलवायु परिवर्तन, जल संचयन, स्वच्छता (स्वच्छ भारत अभियान) और ध्वनि प्रदूषण जैसे मुद्दों को विशेषज्ञों का साक्षात्कार लेकर और प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित करने के जरिए उपयुक्त ढंग से उठाया जाता है।

ख. आकाशवाणी के सभी केंद्र पर्यावरण और वानिकी से संबंधित कानूनी कारकों का व्यापक प्रचार अपने कार्यक्रमों में शामिल कर रहे हैं। आकाशवाणी केंद्रों द्वारा भेजे जाने वाले मासिक विवरणों के जरिए निदेशालय इन कार्यक्रमों की नियमित रूप से निगरानी करता है।

ग. केंद्र ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सफाई के महत्व पर ध्यान केंद्रित करके सभी के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए 'स्वच्छ भारत अभियान' के अंतर्गत स्वच्छता के महत्व का निरंतर प्रचार कर रहे हैं।

घ.' स्वच्छ भारत अभियान' के तहत मीडिया अभियान के अंग के रूप में खेती और गृह तथा 'किसानवाणी' कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले आकाशवाणी केंद्रों को सलाह दी गई कि वे विभिन्न प्रारूपों में उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित करें ताकि कृषक समुदाय में कार्बनिक ठोस कचरे को कृषि कार्यों में खाद के रूप में इस्तेमाल करने के प्रति जागरुकता पैदा की जा सके। आकाशवाणी के इन केंद्रों को निर्देश दिए गए कि वे कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों पर ऑडियो विज्ञापन प्रसारित करें।

Mh- fdlkuk dk Qly fo'k"k lcf/kr lykg dk çpkj

क. आलू उगाने वाले क्षेत्रों में स्थित केंद्रों को केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, मेरठ द्वारा व्यक्त किए गए मौसमी आलू की फसलों में फफूंद जनित रोगों के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों के लिए ऐहतियाती उपाय करने के संबंध में जागरुकता कार्यक्रम प्रसारित करने की सलाह दी गई है।

ख. हरियाणा और पंजाब राज्यों में स्थित केंद्रों को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परामर्श के अनुसार खरीफ कपास फसलों में व्हाइट फ्लाई के संक्रमण की घटनाओं के मद्देनज़र किसानों के लिए जागरुकता अभियान चलाने की सलाह दी गई थी।

b- fdlkuok.kh iHkko vkdyu vkj {kerk fuek.k dk;'kkyk,

क. कृषि और गृह इकाई, डीजी : आकाशवाणी ने वित्त वर्ष 2016–17/2017–18 के दौरान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से, सभी चिन्हित 96 किसानवाणी प्रसारण आकाशवाणी केंद्रों के किसानवाणी कार्यक्रम निर्माताओं के लिए देशभर में पांच 'प्रभाव आकलन और क्षमता निर्माण' कार्यशालाओं का आयोजन किया है। इन कार्यशालाओं में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और महानिदेशालय, आकाशवाणी के अधिकारियों के प्रतिनिधित्व के अलावा, क्षेत्रीय विषय वस्तु/कृषि उद्योग के विशेषज्ञों, कृषि वैज्ञानिकों, आईएमडी के कृषि मौसम विज्ञानियों, राज्य कृषि विभाग/जिला प्रशासन अधिकारियों, एनआईसी वैज्ञानिकों, आईटी विशेषज्ञों, प्रगतिशील किसानों आदि ने भाग लिया। इस तरह की पांच कार्यशालाएं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में 29 से 30 मार्च, 2017; शेर–ए–कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू, जम्मू–कश्मीर में 29 से 30 जून, 2017 तक; मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोच्चि, केरल में 18 से 19 जनवरी, 2018 तक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, अहमदनगर, महाराष्ट्र में 22 से 23 मार्च, 2018 तक और आईसीएआर, उमियाम, शिलॉन्ग में 30 मई से 01 जून, 2018 तक तक सफलतापूर्वक आयोजित की गईं।

,Q- jfM;k fdlku fnol

क. आकाशवाणी पर किसानवाणी कार्यक्रम के माध्यम से प्रसारित जानकारी से लाभान्वित होने वाले प्रगतिशील किसान, अपने साथी किसानों के साथ अपनी क्षेत्रीय भाषा/बोली में अपने अनुभव साझा करते हैं। आकाशवाणी अपने सभी किसानवाणी प्रसारण केंद्रों पर 15 फरवरी को रेडियो किसान दिवस के रूप में

मनाता है। किसानवाणी कार्यक्रम प्रसारित करने वाले केंद्र वरिष्ठ जिला प्रशासन अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ, 15 फरवरी, 2019 को विशेष रूप से दर्शकों के कार्यक्रमों को पिछले वर्षों की तरह आयोजित करेंगे।

th- vkdk'kok.kh uVod ij çe[k@fo'k"k dk;Øek dk çlkj.k

आकाशवाणी के सभी केंद्रों को सलाह दी गई है कि वे सरकार की विभिन्न योजनाओं और कृषक समुदाय में जागरुकता पैदा करने के बारे में विभिन्न प्रारूपों में कार्यक्रम प्रसारित करें। इस बारे में प्रसारित किए गए कुछ कार्यक्रमो का ब्योरा नीचे दिया गया है :

1½ fdlku dY;k.k dk;l'kkyk

आकाशवाणी के सभी केंद्रों को 14 अप्रैल से 5 मई, 2018 तक आयोजित किए जाने वाले ग्राम स्वराज अभियान के तहत 2 मई, 2018 को आयोजित की जाने वाली 'किसान कल्याण कार्यशालाओं' को समुचित रूप से कवर करने की सलाह दी गई थी, जिसका उद्देश्य '2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने' के लिए अपनाई जाने वाली कार्यनीतियां तैयार करने के लिए किसानों के बीच जागरुकता उत्पन्न करना है।

2½ jk"Vh; ipk;rh jkt fnol

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की पूर्व संध्या पर, 24 अप्रैल, 2018 को मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रामनगर, से, माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन का मल्टी–चैनल स्टेशनों सहित सभी राजधानी और स्थानीय रेडियो स्टेशनों द्वारा सीधा प्रसारण किया गया था।

3½ df"k dY;k.k vfHk;ku

किसानों को खेती की तकनीक में सुधार लाने और उनकी आय बढ़ाने में सहायता करने और परामर्श देने के लिए देश के 111 महत्वाकांक्षी जिलों के 25 चुनिंदा गांवों में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि कल्याण अभियान शुरू किया गया। केंद्रों को सरकार के अभियान के बारे में उपयुक्त प्रचार करने का निर्देश दिया गया।

4½ U;ure leFku eY;

न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति किसानों को बाज़ार मूल्य में उतार–चढ़ाव से बचाने और किसानों की आय में स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आकाशवाणी केंद्रों को वार्ता, साक्षात्कार, चर्चा, डायल–इन/डायल–आउट, आदि जैसे प्रोग्रामिंग प्रारूपों के अलावा खरीफ फसलों के लिए बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्यों को जिंगल्स आदि के जरिए हाइलाइट करने की सलाह दी गई। 2018–19 सीजन की रबी फसलों के लिए सवंर्धित न्यूनतम समर्थन मूल्यों के बारे में भी जागरुकता फैलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिनका विपणन 2019–20 सीजन में किया जाएगा।

,p- ijkyh tykus dk ekeyk

फसल की कटाई के बाद की पराली जलाने जैसी अकुशल फसल प्रबंधन पद्धतियां विशेष रूप से खरीफ़ की फसल की कटाई के मौसम के दौरान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे कई राज्यों में गंभीर पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण हैं। देशभर में फैले आकाशवाणी के केंद्रों को विभिन्न अत्याधुनिक तकनीकों, वैकल्पिक फसल अवशेष प्रबंधन प्रद्धतियों, प्रोत्साहन योजनाओं तथा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए विभिन्न दंडात्मक उपायों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए इस मुद्दे के बारे में जागरुकता फैलाने की सलाह दी गई है।

vkb- LokLF; vkj ifjokj dY;k.k dk;Øe

d- efgyk dk;Øe

i. आकाशवाणी बालिका शिशु के कल्याण के लिए विभिन्न प्रारूपों में अनेक कार्यक्रम प्रसारित करता है। केंद्रों के परिवार कल्याण अनुभाग के कार्यक्रमों का सामान्य तौर पर लक्ष्य कानून की जानकारी के प्रसार के जरिए कन्या भ्रूण हत्या और लड़के–लड़की में भेदभाव जैसे मुद्दों और महिलाओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रति सामाजिक जागरुकता पैदा करना है। ग्रामीण श्रोताओं के साथ संवाद कायम करने के लिए विभिन्न परंपरागत लोक रूपों का भी इस्तेमाल किया गया। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद आकाशवाणी महानिदेशक ने सभी केंद्रों को निर्देश जारी किए कि वे अपने कार्यक्रमों की योजना बनाते समय 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान को लोकप्रिय बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करें। यही प्रचार अभियान 2018 में भी जारी रहा।

ii. आकाशवाणी ने अपने नेटवर्क के सभी केंद्रों को निर्देश दिए हैं कि वे महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित कानूनों, नियमों, विनियमन और दिशानिर्देशों का व्यापक प्रचार करें और आपराधिक अपील संख्या

786/2010 में दिल्ली के उच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कानूनी प्रावधानों तथा इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर होने वाली सजा के लिए बड़े पैमाने पर जागरुकता फैलाने के लिए विविध प्रारूपों में कार्यक्रमों का प्रसारण करें।

iii. 'राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन' के बारे में जागरुकता फैलाने और इसे प्रचारित के निर्देश जारी किए गए थे, जिनमें महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित विविध मुद्दों को शामिल किया गया था।

आकाशवाणी के महानिदेशक श्री एफ. शहरयार 11 मई, 2018 को नई दिल्ली में 15वें एशिया मीडिया समिट में 'सशक्त कहानियां सुनानाः चुनौतियां और अवसर, रेडियो और सामुदायिक रेडियो' पर पूर्ण अधिवेशन–3 को संबोधित करते हुए

[k- LokLF; dk;Øe

i. स्वास्थ्य संबंधी सभी मुद्दे जैसे बीमारियों के बारे में जागरुकता, उनके कारण और रोकथाम, उपलब्ध उपचार के बारे में जानकारी, टीकाकरण के बारे में जागरुकता, विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए सरकारी सुविधाओं की जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी सरकारी योजनाएं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों की विषयवस्तु रहे हैं।

ii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3.40 करोड़ बच्चों को कवर करने के लिए मीज़ल्स–रूबेला टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है, आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर आम जनता में जागरुकता फैलाने के लिए विभिन्न स्वरूपों में कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

iii. देश के कुछ भागों में डेंगू और चिकनगुनिया फैलने के समय आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर डेंगू की रोकथाम के बारे में विशेष जागरुकता कार्यक्रम प्रसारित किए गए। आकाशवाणी कार्यशालाओं और जागरुकता कार्यक्रमों के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सहयोग भी कर रहा है।

iv. प्रतिकूल बाल लिंग अनुपात के बारे में जागरुकता फैलाने और कन्या भ्रूण का गर्भपात कराने के लिए जिम्मेदार नकारात्मक मानसिकता को बदलने के लिए देशभर में आकाशवाणी के केंद्रों से विभिन्न प्रारूपों में कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं।

v. टीकाकरण कवरेज में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में शुरू किए गए कार्यक्रम 'मिशन इंद्रधनुष' को पूरे वर्ष में आकाशवाणी नेटवर्क के जरिए व्यापक कवरेज प्रदान की गई। वर्ष 2018 के दौरान इस अभियान के माध्यम से टीकाकरण के अगले चरण को कवर किया गया है और आकाशवाणी इसकी व्यापक कवरेज और प्रचार कर रहा है। पूर्ण टीकाकरण कवरेज में सुधार के लिए मिशन इन्द्रधनुष का विशेष चरण 22 अक्तूबर, 2018 को शुरू किया गया, नियमित टीकाकरण के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने और मिशन इन्द्रधनुष को व्यापक कवरेज देने के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

vi. आकाशवाणी प्रसारण के अनेक कार्यक्रमों में महिलाओं और बच्चों के पोषण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

vii. ग्रामीण/महिला/युवा और स्वास्थ्य जैसे विशेष श्रोता कार्यक्रमों में आकाशवाणी ने कुछ श्रोता समूहों का पंजीकरण किया है। ये समूह स्वास्थ्य संबंधी विषयों के बारे में सामान्य जागरुकता के प्रसार में योगदान करते हैं।

viii. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तपेदिक को समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने तथा रोकथाम और देखभाल के उपायों के साथ समस्त प्रभावित लोगों तक पहुंच बनाने के लिए 26 सितंबर, 2018 को तपेदिक पर पहली उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। आकाशवाणी के सभी केंद्रों को टीबी पर यूएनजीए की बैठक की सामग्री और विषय से अवगत करा दिया गया और उन्हें भारत से टीबी को खत्म करने के अपने प्रयासों में तेजी लाने की सलाह दी गई।

ix. जब देश के कुछ हिस्सों में ज़ीका वायरस फैलने की सूचना मिली थी, तो निदेशालय द्वारा ज़ीका वायरस के लक्षणों, रोकथाम और उपचार पर

कार्यक्रमों को प्रसारित करने की राष्ट्रव्यापी सलाह जारी की गई थी।

x. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, भारत सरकार ने लौह यात्रा : देश में सुरक्षित और पौष्टिक आहार के संदेश को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय रिले साइकिल अभियान शुरू किया गया। नमक सत्याग्रह, लौह यात्रा के लिए प्रेरणा स्रोत होने के नाते यह देश में एनीमिया के बढ़ते मामलों को दूर करने के लिए डबल फोर्टिफाइड नमक (लोहे और आयोडीन के साथ फोर्टिफाइड किया गया नमक) पर ध्यान केंद्रित करता है। अभियान को प्रचारित करने, स्वस्थ और पौष्टिक आहार के स्वास्थ्य लाभों के बारे में आम लोगों में जागरुकता पैदा करने और डबल फोर्टिफाइड नमक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निर्देश जारी किए गए।

xi. भारत सरकार ने 23 सितंबर, 2018 को स्वस्थ भारत का निर्माण करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम vk;q"eku Hkkjr कार्यक्रम शुरू किया है। आकाशवाणी रांची ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत– प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुभारंभ को लाइव कवरेज प्रदान किया। देशभर में आकाशवाणी के सभी केंद्रों को इस प्रमुख योजना यानी vk;q"eku Hkkjr&ih,e t;,okbZको व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए विभिन्न प्रारूपों में उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित करने की सलाह दी गई।

xii. महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आकाशवाणी के समस्त केंद्रों द्वारा सितंबर महीने के दौरान पोषण संबंधी विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित किए गए और पोषण माह के बाद भी यह सिलसिला लगातार जारी रहा। "राष्ट्रीय पोषण माह" के समर्थन के लिए आकाशवाणी को संस्थानों की श्रेणी में प्रशंसा प्रमाण–पत्र दिया गया।

xiii. ई–सिगरेट, हीट–नॉट–बर्न डिवाइस, वेप, ई–शीशा, ई– निकोटीन फ्लेवर हुक्का और इसी तरह के उत्पादों सहित इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परामर्श को भी व्यापक प्रचार प्रदान किया गया।

xiv. अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस 26 जून, 2018 को मादक पदार्थों से मुक्त अंतरराष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में मनाया गया। ऑल इंडिया रेडियो ने अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी के विरोध पर केंद्रित विभिन्न प्रारूपों में कार्यक्रमों के प्रसारण के जरिए व्यापक प्रचार प्रदान किया।

t- cPpksa dk dk;Øe

आकाशवाणी के सभी केंद्र नियमित आधार पर बच्चों के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। आकाशवाणी सभी केंद्रों से 3 श्रेणियों के बच्चों, अर्थात् 5 से 7 वर्ष की आयु और 8 से 14 वर्ष की आयु तथा ग्रामीण बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित करता है।

कुछ कार्यक्रम साप्ताहिक आधार पर प्रसारित किये जाते हैं। नाटक, लघु कथाएं, फ़ीचर, समूह वृंदगान, साक्षात्कार, महाकाव्यों से कहानियां आदि इस प्रसारण का हिस्सा होती हैं।

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुरोध पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्वीकृत 'बच्चों के बारे में मीडिया रिपोर्टिंग संबंधी दिशानिर्देशों' को व्यापक रूप में प्रचारित किया गया। आकाशवाणी ने देशभर में सूचना का प्रसार करते हुए यूनिसेफ के कार्यक्रमों में योगदान किया।

'बाल यौन शोषण' संबंधी यूनिसेफ की कार्यशाला में आकाशवाणी के अधिकारियों ने हिस्सा लिया, ताकि बच्चों से संबंधित मुद्दों में उनकी समझ और जानकारी के प्रसार में सुधार हो सके।

"सेफ नेबरहुड फॉर चाइल्ड सेफ्टी" नामक अखिल भारतीय अभियान को प्री–लॉन्च प्रचार प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए गए।

d- laxhr

आकाशवाणी अपनी स्थापना के समय से ही लोकसेवा प्रसारक की सच्ची प्रतिबद्धता के नाते भारतीय संगीत के प्रसार और प्रश्रय में बड़े संरक्षक की भूमिका अदा कर रहा है।

आलोच्य वर्ष (अप्रैल 2018 से मार्च 2019) की शुरुआत संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में त्रिमूर्ति और अन्य वाद्यकार संगीत सम्मेलनों के प्रसारण के साथ हुई। चेन्नई की विदुषी सीता नारायणन (R;kxjkt dh jpuk,), बंगलुरु

के डॉ. मुरलीधर (’;ke 'kkL=h dh jpuk,¡) त्रिशूर के श्री एम. एस. परमेस्वरन (eÙkLokeh nhf{krkj dh jpuk,¡½ और हैदराबाद की सुश्री धवलेश्वरपु वर्धिनी ¼p,;j pÙxojk; 'kkL=h dh jpuk,¡½ जैसे प्रख्यात कलाकारों ने प्रस्तुति दी। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर एक विशेष कार्यक्रम ^Hktj eulk Jh—".ke* प्रसारित किया गया जिसमें भगवान कृष्ण के बारे में विविध रचनाओं को प्रसारित किया गया। कार्यक्रम का संचालन कर्नाटक संगीत की प्रतिनिधि चेन्नई की विदुषी आर. वेदवल्ली द्वारा किया गया।

d {k=h; lxe ,o ykd lxhr

होली के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया गया, जिसमें प्रख्यात पार्श्व गायिका विदुषी वाणी जयराम और पं. बिरजू महाराज ने प्रस्तुति दी। (आकाशवाणी, चेन्नई का योगदान)। अन्य कार्यक्रमों में सुगम संगीत (तेलुगू) आकाशवाणी विजयवाड़ा के मोदुमोडी सुधाकर (स्टाफ कम्पोजर), निसार हुसैन द्वारा राजस्थानी लोकसंगीत, बृज किशोर त्रिपाठी द्वारा भोजपुरी लोकसंगीत, सलमान अल्लाहवाले द्वारा ग़ज़ल, डॉ. विजय कपूर द्वारा गीत–भजन, तुलिका दास द्वारा बांग्ला लोकसंगीत, रंजना बरुआ द्वारा आधुनिक भजन, सानिया पाटनाकर (मराठी), होली के रंग गीतों के संग– होली पर गीत (श्री हेमंत सपकाले द्वारा प्रस्तुति)।

[k- vkdk'kok.kh lxhr lEeyu] 2018

i. यह एक वार्षिक संगीत सम्मेलन है जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। कलाकारों और संगीत प्रेमियों दोनों को ही इसका इंतजार रहता है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन पिछले 6 दशकों से संगीत प्रेमियों के दिलो–दिमाग में आकाशवाणी के ब्रैंड नेम के रूप में विकसित हुआ है। इसका आयोजन देशभर में किया जाता है, जिसमें हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के वरिष्ठ और उदीयमान, दोनों तरह के कलाकारों को शामिल किया जाता है। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में नाम शामिल किए जाने के बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कोई भी कलाकार इस अवसर को छोड़ता नहीं है।

आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, 2018

ii. इस वर्ष के आकाशवाणी संगीत सम्मेलन की मुख्य विशेषता यह रही कि इसमें परंपरागत रूप में हिस्सा लेने वाले शास्त्रीय कलाकारों के समूह के अलावा लोक, सुगम और पश्चिमी संगीत के कलाकारों को भी शामिल किया गया, जिससे यह एक पूर्ण संगीत उत्सव बन गया।

iii. इस वर्ष आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अंतर्गत 6 अक्तूबर, 2018 (शनिवार) को 24 स्थानों पर संगीत कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें देशभर से अनेक वरिष्ठ और उदीयमान कलाकारों ने हिस्सा लिया। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के सांध्य सम्मेलन 19 स्थानों– दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरु, लखनऊ, जयपुर, पटियाला, धारवाड़, शिमला, इंदौर, पटना, नागपुर, तिरुअनंतपुरम, त्रिचूर, मदुरई, विशाखापट्टनम और

मैसूर में आयोजित किए गए। प्रातःकालीन सम्मेलनों में हिंदुस्तानी संगीत के कार्यक्रम दो स्थानों – रायपुर और अगरतला में आयोजित किए गए। सुगम और लोक संगीत के कार्यक्रम शाम के समय तीन स्थानों – वडोदरा, श्रीनगर और कडप्पा में आयोजित किए गए।

iv. ये संगीत सम्मेलन 10 नवंबर, 2018 से 21 दिसंबर, 2018 तक आकाशवाणी के सभी राजधानी और क्षेत्रीय स्टेशनों के नेशनल हुकअप पर, इसके अलावा डीटीएच पर 'रागम' चैनल, वेब–स्ट्रीमिंग और मोबाइल एप एआईआर लाइव पर प्रसारित किए गए।

x- R;kxjkt vkjk/kuk lxhr mRlo dk lh/kk ilkj.k

संगीतकार त्यागराज के 172वें आराधना संगीत उत्सव के अवसर पर 23 जनवरी, 2018 को संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में त्यागराज आराधना संगीत उत्सव का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही 25 जनवरी, 2018 को आराधना दिवस यानी पुष्य बहुला पंचमी को प्रातः तिरुवय्यारू से पंचरत्न गोष्ठी गणम् (पंच रत्न रचनाओं की सामूहिक प्रस्तुति) का भी सीधा प्रसारण किया जाएगा।

?k- vkdk'kok.kh lxhr çfr;kfxrk,] 2018

आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता आकाशवाणी का वार्षिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य युवा प्रतिभाओं की तलाश करना और उन्हें संगीत के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना है। यह प्रतियोगिता देशभर में पश्चिमी संगीत सहित विभिन्न शैलियों में आयोजित की जाती है। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को फरवरी, 2019 में एक पुरस्कार वितरण समारोह में प्रमाण–पत्र और स्मृति–चिन्ह के साथ नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

,y- [ky

अप्रैल, 2018 से 31 अक्तूबर, 2018 तक आकाशवाणी ने अपने राष्ट्रीय नेटवर्क और क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल गतिविधियों की समुचित कवरेज प्रदान की। राष्ट्रीय स्तर पर कवरेज में शामिल कुछ प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार थीं :

cg&fo"k;h [ky

1- 21oka jk"VeMy [ky 2018] xkYM dkLV] v,LVfy;k

आकाशवाणी ने 4 से 15 अप्रैल, 2018 के दौरान गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2018, के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों का प्रसारण किया।

d- dVu jtj

3 अप्रैल, 2018 को कर्टन रेज़र कार्यक्रम, आकाशवाणी के सभी राजधानी केंद्रों, एफएम गोल्ड नेटवर्क और अन्य इच्छुक केंद्रों पर प्रसारित किया गया। कर्टन रेज़र के क्षेत्रीय संस्करणों को भी गैर–हिंदी आकाशवाणी राजधानी केंद्रों पर उसी दिन सुबह के प्रसारण में प्रसारित किया गया और उसी को संबंधित भाषा क्षेत्रों में अन्य आकाशवाणी केंद्रों द्वारा रिले किया गया।

[k- nfud gkbykbV dIly

दिनभर की घटनाओं के मुख्य आकर्षण को कवर करने वाले 30 मिनट की अवधि के दैनिक कैप्सूल 6 अप्रैल, 2018 से 15 अप्रैल, 2018 तक 22:30 बजे से 23:00 बजे तक राष्ट्रीय हुकअप और आकाशवाणी के सभी राजधानी केंद्रों व एफएम गोल्ड नेटवर्क द्वारा प्रसारित किए गए। इनके क्षेत्रीय भाषायी संस्करणों को गैर–हिंदी आकाशवाणी राजधानी केंद्रों और आकाशवाणी के अन्य केंद्रों द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में प्रसारित किया गया।

x- viMV@cÇdx U;t

6 से 14 अप्रैल, 2018 तक एफएम रेनबो पर लाइव अपडेट्स प्रसारण प्रसारित किए गए साथ ही ब्रेकिंग न्यूज़ का प्रसारण एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड चैनल्स पर किया गया।

?k- deVjh

- विशेष रूप से हॉकी इंडिया के पुरुष और महिला सेमीफाइनल और फाइनल मैचों की ऑफ–ट्यूब कमेंटरी
- पुरुष और महिला बैडमिंटन एकल, युगल, मिश्रित– विशेष रूप से भारत से संबंधित सेमीफाइनल और फाइनल मैचों की ऑफ–ट्यूब कमेंटरी

2- bMkuf'k;k d tdkrk vkj ikyeckx e vk;kftr 18o ,f'k;kÃ [ky&2018

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पालेमबांग में 18 अगस्त से 2 सितंबर, 2018 तक आयोजित 18वें एशियाई खेल–2018 एक अन्य बहु–विषयक खेल आयोजन था जिसने देशभर के खेल प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट किया था। इन्हें बड़े पैमाने पर कवर किया। आकाशवाणी की कवरेज टीम ने जकार्ता का दौरा किया और व्यापक कवरेज प्रदान की, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

d- dVu j t j

17 अगस्त, 2018 को 2230 बजे से 2300 बजे तक 30 मिनट की अवधि का कर्टन रेज़र राष्ट्रीय हुकअप पर प्रसारित किया गया और आकाशवाणी के सभी राजधानी केंद्रों और एफएम गोल्ड नेटवर्क और अन्य इच्छुक केंद्रों द्वारा प्रसारित किया गया। कर्टन रेज़र के क्षेत्रीय संस्करणों को भी गैर–हिंदी आकाशवाणी राजधानी केंद्रों के सुबह के प्रसारणों के दौरान उनकी सुविधा के समय पर प्रसारित किया गया जिन्हें आकाशवाणी केंद्रों द्वारा संबंधित भाषा क्षेत्रों में रिले किया गया।

[k- nfud gkbykbV

दिन की घटनाओं के मुख्य आकर्षण को कवर करते हुए 30 मिनट की अवधि के दैनिक हाइलाइट्स 18 अगस्त, 2018 से 2 सितंबर, 2018 तक नेशनल हुकअप पर राष्ट्रीय हुकअप और आकाशवाणी के सभी राजधानी केंद्रों व एफएम गोल्ड नेटवर्क और अन्य इच्छुक केंद्रों द्वारा प्रसारित किए गए। इनके क्षेत्रीय भाषायी गैर–हिंदी आकाशवाणी राजधानी केंद्रों के सुबह के प्रसारणों के दौरान उनकी सुविधा के समय पर प्रसारित किया गया जिन्हें आकाशवाणी केंद्रों द्वारा संबंधित भाषा क्षेत्रों में रिले किया गया।

x- viMV

19 अगस्त, 2018 से 1 सितंबर, 2018 तक एफएम रेनबो पर लाइव अपडेट्स प्रसारण प्रसारित किए गए साथ ही ब्रेकिंग न्यूज़ का प्रसारण एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड चैनल्स पर किया गया।

?k- deVjh

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अलावा, विशेष रूप से भारत के पुरुष और महिला मैचों, हॉकी के सेमीफाइनल और फ़ाइनल मैचों और विशेष रूप से भारत के पुरुष और महिला बैडमिंटन के मैचों, सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल मैचों की ऑफ–ट्यूब कमेंटरीज का दिल्ली से प्रसारण किया गया।

M- cCdx U;t

भारतीयों के पदक जीतने पर एफएम गोल्ड और एफएम इंद्रधनुष चैनलों पर तत्काल ब्रेकिंग न्यूज़ आइटम का प्रसारण किया।

3- fØdV

i) आयरलैंड में 27 और 29 जून, 2018 को खेले गए भारत–आयरलैंड टी 20 क्रिकेट–2018 मैच की कमेंटरी प्रसारित की गई।

ii) इंग्लैंड में 3 से 17 जुलाई, 2018 तक खेली गई भारत–इंग्लैंड एकदिवसीय/टी–20 क्रिकेट शृंखला की बॉल–बाय–बॉल कमेंटरी प्रसारित की गई।

iii). दुबई और अबूधाबी में 15 से 28 सितंबर, 2018 तक खेले गए एशिया कप क्रिकेट, 2018 का सीधा प्रसारण साथ ही साथ बॉल–बाय–बॉल कमेंटरी का प्रसारण आकाशवाणी द्वारा किया गया।

iv). ‘LVEIM^–सीरीज़ 4 आकाशवाणी–बीबीसी–एबीसी सह–निर्माण का 1 अप्रैल, 2018 से 31 अक्तूबर, 2018 तक (हर शनिवार एफएम रेनबो नेटवर्क पर) प्रसारण किया गया।

4- g,dh

ब्रेडा, नीदरलैंड्स में आयोजित हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, 2018 की ऑफ–ट्यूब कमेंटरी 23 जून, से 1 जुलाई, 2018 तक प्रसारित की गई।

5- QVc,y

भुवनेश्वर में 20 अप्रैल, 2018 को खेले गए इनॉग्रल सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच का सीधा प्रसारण किया गया।

6- Vfu l

विंबलडन टेनिस चैम्पियनशिप, 2018 पर दैनिक रिपोर्ट एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड नेटवर्क पर 4 से 17 जुलाई, 2018 तक प्रसारित की गई।

7- LDo'k

चेन्नई में 19 से 29 जुलाई, 2018 तक खेली गई डब्ल्यूएसएफ वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, 2018 की सम्मिलित रेडियो रिपोर्ट 30 जुलाई, 2018 को प्रसारित की गई थी।

2018&2019 e doj fd, tku oky çLrkfor vk;ktu

आकाशवाणी वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों का अपने राष्ट्रीय हुकअप पर जहाँ भी आवश्यकता हो, प्रसारण अनुमति/अधिकार प्राप्त करने की स्थिति लाइव कवरेज प्रदान करने की पेशकश करता है। ऐसे कुछ आयोजनों का विवरण इस प्रकार है :

d½ fØdV

ऑस्ट्रेलिया में नवंबर 2018 में भारत–ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शृंखला और जनवरी और फरवरी, 2019 में भारत–न्यूज़ीलैंड क्रिकेट शृंखला।

[k½ cMÇeVu

सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप–2018 और बीडब्ल्यूएफ इंडिया ओपन बैडमिंटन–2019 (मार्च, 2019)।

x½ g,dh

भुवनेश्वर में नवंबर–दिसंबर–2018 के दौरान आयोजित हॉकी पुरुष विश्व कप, 2018।

?k½ QVc,y

सुब्रतो कप, 2018, संतोष ट्रॉफी, 2019।

Ã½ ^LVEIM^

आकाशवाणी–बीबीसी–एबीसी सह–निर्माण 1 नवंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 (हर शनिवार एफएम रेनबो नेटवर्क पर)।

,e- lekpkj lsok çHkkx

आकाशवाणी (एआईआर) को दुनिया के प्रमुख प्रसारण संगठनों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी) भारत और विदेशों में श्रोताओं तक समाचार और समाचार आधारित कार्यक्रमों का प्रसार करता है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडीःएआईआर) भारत और विदेशों में श्रोताओं के लिए समाचार और समाचार–आधारित कार्यक्रम प्रसारित करता है। यह सरल भाषा में महत्वपूर्ण घटनाओं, नए घटनाक्रमों और समकालीन मुद्दों के बारे में प्रामाणिक जानकारी का प्रसार करता है।

lxBukRed <kpk

7.1 समाचार सेवा प्रभाग का नेतृत्व महानिदेशक (समाचार) करते हैं, जो भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक होते हैं। महानिदेशक (समाचार) को अपर महानिदेशकों (समाचार), निदेशकों (समाचार), उप निदेशकों (समाचार), सहायक निदेशकों (समाचार), समाचार संपादकों और संवाददाताओं की एक टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

7.2 एनएसडी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में विभिन्न परिचालन स्कंधों में शामिल हैं : सामान्य समाचार कक्ष, हिंदी समाचार कक्ष, रिपोर्टिंग यूनिट, वार्ता और सम सामयिक मामले यूनिट, न्यूज़रील यूनिट, भारतीय भाषा इकाइयाँ, संदर्भ और पीपी एंड डी यूनिट, आईटी और वेबसाइट यूनिट और प्रशासनिक स्कंध।

7.3 विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय समाचार इकाइयों (आरएनयू) का नेतृत्व निदेशक या उप/सहायक निदेशक के पद के अधिकारी करते हैं और समाचार संपादक, संवाददाताओं और समाचार वाचक–सह–अनुवादकों उनकी सहायता करते हैं।

lekpkj lxg dju dk uVod

8.1 एनएसडी समाचार और संबंधित सेवाओं का निर्माण सुनिश्चित करता है जो समयबद्धता और गुणवत्ता के मामले में कुछ मानकों का पालन करते हैं। यह समाचार संग्रह करने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करता है। एनएसडी मुख्यालय में विभिन्न बीट्स को कवर करने वाली ऊर्जावान रिपोर्टर्स/संवाददाताओं की एक टीम उपलब्ध है। विदेश संवाददाता बीजिंग, कोलंबो, ढाका, दुबई और काठमांडू जैसे महत्वपूर्ण शहरों में तैनात हैं। संवाददाताओं को आरएनयू में भी तैनात किया जाता है। देश के 500 से अधिक जिलों में अंशकालिक संवाददाता (पीटीसी) भी अपने संबंधित आरएनयू को समाचार एकत्र करने में सहायता करते हैं।

8.2 पीटीआई, यूएनआई, आईएएनएस, हिंदुस्तान समाचार सहित समाचार एजेंसियां और अन्य भी उपयुक्त इनपुट के साथ न्यूज़रूम की सहायता करती हैं। सोशल मीडिया यथा–सत्यापित ट्विटर हैंडल, प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों–राजनीतिक और अन्य के फेसबुक अकाउंट भी नियमित रूप से ट्रैक किए जाते हैं, और समाचार निर्माण के लिए जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत साबित होते हैं।

8.3 मुख्यालय और आरएनयू की रिपोर्टिंग इकाई में रिपोर्टर्स, संवाददाता और पीटीसी घटनाक्रमों, घटनाओं, सरकार की योजनाओं के लॉन्च, महत्वपूर्ण संवाददाता सम्मेलनों, रैलियों, कार्यशालाओं, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे सिरी फोर्ट नई दिल्ली में विदेश प्रसारण दिवस कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए

केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा संबोधित किए जाने पर सेमिनारों को व्यापक रूप से कवर करते हैं।

8.4 आयुष्मान भारत, पोषण अभियान जैसी योजनाओं, महिलाओं की सुरक्षा के उपाय और मैं नहीं हम पोर्टल के लॉन्च, निर्वाचन आयोग द्वारा मोबाइल एप सी–विजिल के लॉन्च, विजिटर, एयर क्वालिटी इमरजेंसी अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन–2019, स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी, ग्लोबल मोबिलिटी समिट को समाचार संवाददाताओं द्वारा नियमित कवरेज के अलावा प्राथमिकता के आधार पर कवर किया गया।

8.5 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते महत्व के साथ विभिन्न शासनाध्यक्षों की भारत यात्राओं में भी बढ़ोत्तरी हुई है। उनकी इन भारत यात्राओं को व्यापक रूप से कवर किया गया। राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठकों और अन्य कार्यक्रमों को व्यापक रूप से कवर किया गया।

8.6 रिपोर्टिंग यूनिट विभिन्न मंत्रालयों और अन्य सरकारी संगठनों, भारत निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग जैसे संवैधानिक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निरंतर संपर्क में रहने के कारण स्पॉट न्यूज़ कवरेज के लिए समाचार और संबंधित जानकारी जुटाती है। उनकी बैठकें, कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर की जाती हैं।

8.7 यह हिंदी में प्रसारित होने वाले प्रादेशिक बुलेटिनों के लिए भी समाचार उपलब्ध कराती है। दिल्ली और एनसीआर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम इन बुलेटिनों के लिए विशेष रूप से कवर किए जाते हैं।

8.8 यूनिट ने हर महीने मन की बात पर कार्यक्रम किया। मन की बात के 50वें संस्करण के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए, जिनमें सरकारी अधिकारियों, निजी क्षेत्र और आम जनता सहित महत्वपूर्ण हितधारकों से विशेष साक्षात्कार/साउंड बाइट्स लिए गए।

आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली में 'लोक सेवा प्रसारण दिवस' का आयोजन

okrk ,o le&lkef;d ekeyk dk dk;Øe

9.1 वार्ता एवं सम–सामयिक मामलों संबंधित यूनिट को विभिन्न विषयों पर विश्लेषणात्मक समाचार आधारित कार्यक्रम प्रसारित करने का दायित्व सौंपा गया है।

इसका लक्ष्य श्रोताओं को प्रमुख समाचार गतिविधियों को समझने में मदद करना, चीजों को सही संदर्भ में प्रस्तुत करना और किसी विषय की विस्तृत जानकारी देना है। तदनुरूप वार्ता यूनिट ने अपने दैनिक और साप्ताहिक कार्यक्रमों यथा– सामायिकी, स्पॉटलाइट/न्यूज़ एनालिसिस, पब्लिक स्पीक, मनी टॉक, वाद–संवाद, चर्चा का विषय है, कंट्रीवाइड, सुर्खियों में, और करंट अफेयर्स कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

अंग्रेजी में पंद्रह मिनट के स्पॉटलाइट और न्यूज़ एनालिसिस कार्यक्रम दैनिक रूप से प्रसारित होते हैं। इसमें विषय विशेष का विशेषज्ञ और एक पत्रकार समकालीन महत्व के विषय पर चर्चा करते हैं। सामायिकी और गल्फ चर्चा हिंदी कार्यक्रम हैं।

'पब्लिक स्पीक' बहुत लोकप्रिय लाइव फोन–इन प्रोग्राम है। यह आधे घंटे का द्विभाषी कार्यक्रम है। इसमें सप्ताह के विषय पर श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए मंत्रियों, मंत्रालय के अधिकारियों सहित दो विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है।

मनी टॉक में, सप्ताह के महत्वपूर्ण वित्तीय समाचारों पर चर्चा आयोजित की जाती है। दूसरी ओर, वाद संवाद में दो विशेषज्ञ महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं।

इसी तरह, 'चर्चा का विषय है', एक लंबा कार्यक्रम है जो उस सप्ताह के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विषय के दो विशेषज्ञों को एक साथ लाता है।

कंट्रीवाइड, महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों जैसे मंत्रियों को जनता के सामने अपने विचार रखने का एक आदर्श माध्यम है, क्योंकि समाचार सेवा प्रभाग द्वारा उनका साक्षात्कार किया जाता है।

'सुर्खियों में' और 'करंट अफेयर्स' भी ऐसे कार्यक्रम हैं जो समाचार में महत्वपूर्ण समकालीन विषयों पर विचार विमर्श प्रस्तुत करते हैं।

9.2 वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में एनडीए सरकार के 4 साल पूरे होने पर चर्चा कार्यक्रमों की एक श्रृंखला, जम्मू–कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की पहल और उपलब्धियां, पोषण अभियान, आयुष्मान भारत, किसान कल्याण, केंद्रीय मंत्रियों के साथ साक्षात्कार, स्वच्छता ही सेवा, पराक्रम पर्व, सशस्त्र बल सप्ताह, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, स्वच्छ भारत अभियान, महिला सुरक्षा पर कार्यक्रम, मिशन इन्द्रधनुष शामिल हैं।

9.3 यूनिट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं की सुरक्षा पर आधारित कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया है।

9.4 भारत को एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान और प्रधानमंत्री की चीन और रूस की अनौपचारिक यात्राओं पर विस्तृत चर्चा कार्यक्रमों का भी सीधा प्रसारण किया गया।

9.5 जिन विशेष कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया गया, उनमें राज्य विधानसभा चुनाव और कर्नाटक में मतगणना, पीएमजेएवाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि और महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ शामिल हैं। पराक्रम पर्व और रक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम का भी प्रसारण किया गया। जीएसटी के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए कई चर्चा कार्यक्रमों, साक्षात्कारों का प्रसारण किया गया।

9.6 चर्चा कार्यक्रमों के माध्यम से महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं को उचित कवरेज प्रदान किया गया। इस तरह, वार्ता और समसामयिक मामलों के कार्यक्रमों का उद्देश्य आम जनता और सरकारी तंत्र दोनों की सेवा करना है।

9.7 राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री के मासिक प्रसारण मन की बात पर भी चर्चा प्रसारित की गई। संसद के मानसून सत्र के प्रारंभ से पहले विशेष कार्यक्रम अंग्रेजी में इश्यू बिफोर पार्लियामेंट और हिंदी में संसद के समक्ष मुद्दे प्रसारित किए गए। संसद में अविश्वास प्रस्ताव एक विशेष लाइव प्रोग्राम भी तैयार किया गया।

9.8 वार्ता यूनिट द्वारा नवंबर, 2018 से मार्च, 2019 तक जिन कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है उनमें : चुनावों पर कार्यक्रम और पांच राज्यों के चुनाव परिणामों पर एक लाइव चर्चा, संसद का शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले इश्यू बिफोर पार्लियामेंट और संसद के समक्ष मुद्दे, वर्षान्त कार्यक्रम और अर्द्ध कुंभ मेला, प्रवासी भारतीय दिवस, स्वच्छ भारत यात्रा, सांप्रदायिक सद्भाव, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, केंद्रीय बजट और आम चुनाव से संबंधित कार्यक्रम शामिल हैं।

9.9 न्यूज़रील यूनिट प्रतिदिन न्यूज़रील और समाचार दर्शन कार्यक्रमों को प्रसारित करती है, जिनमें दैनिक समाचारों के अलावा, किसी कार्यक्रम या विभिन्न गतिविधियां और स्वच्छ भारत अभियान, योग दिवस जैसे और अन्य कार्यक्रमों की रिपोर्टें भी शामिल हैं। 15 अगस्त को 30 मिनट का विशेष न्यूज़रील कार्यक्रम प्रसारित किया गया,

जिसमें देशभर में स्वतंत्रता समारोह की रिपोर्टें शामिल थीं। प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को, एक विशेष राउंड–अप कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है जिसमें पूरे वर्ष होने वाली घटनाओं की रिपोर्ट होती है। साथ ही, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर 30 मिनट का विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।

{k=h; lekpkj bdkb;k

आकाशवाणी की 46 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां (आरएनयू) जनता की सूचना आवश्यकताएं पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

10.1 आकाशवाणी की 46 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां (आरएनयू) क्षेत्रीय कलेवर के साथ जनता की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इस तरह मूल स्तर पर अपनी पहुंच को व्यापक बनाती हैं।

10.2 क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों की शुरुआत पचास के दशक के आरंभ में हुई थी। पहले ऐसे समाचार बुलेटिनों का प्रसारण अप्रैल 1953 में लखनऊ और नागपुर केंद्रों से किया गया था। 1954–55 में, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में आरएनयू की स्थापना की गई। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और वर्तमान में, देश के विभिन्न हिस्सों में 46 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां कार्यरत हैं।

10.3 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां 77 क्षेत्रीय भाषाओं/बोलियों में बुलेटिन और कार्यक्रम प्रसारित करती हैं ताकि ख़बरों को क्षेत्र विषयक और श्रोताओं के अनुरूप बनाया जा सके। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक क्षेत्रीय समाचार इकाई है और बड़े राज्यों में चार क्षेत्रीय समाचार इकाइयां कार्यरत हैं, ताकि समूचे राज्य में गतिविधियों की प्रभावी कवरेज की जा सके। क्षेत्रीय समाचार इकाइयां हर रोज 478 बुलेटिन प्रसारित करती हैं, जिनकी कुल प्रसारण अवधि करीब 39 घंटे है जिसमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, विदेश प्रसारण, डीटीएच सेवाएं और एफएम हेडलाइंस शामिल हैं।

10.4 ये इकाइयां हर महीने 1060 समाचार आधारित कार्यक्रम भी प्रसारित करती हैं, जिनकी कुल अवधि लगभग 140 घंटे होती है। इसके अलावा ये इकाइयां गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या राष्ट्रीय महत्व के किसी अन्य अवसर पर विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित करती हैं। राज्य विधानसभाओं के अधिवेशन के दौरान भी ये विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करती हैं।

10.5 एफएम हेडलाइंस शहरों और कस्बों में रोज़मर्रा की व्यस्त जिंदगी के दौरान श्रोताओं की सूचना संबंधी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करती हैं। वर्तमान में क्षेत्रीय समाचार इकाइयों द्वारा 17 भाषाओं में 255 हेडलाइन बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं।

10.6 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में देशभर में करीब 76 पूर्णकालिक संवाददाता/संपादक (गैर–आरएनयू संवाददाताओं सहित) कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर 526 अंशकालिक संवाददाताओं (पीटीसी) की सेवाएं ली जा रही हैं ताकि दूर–दराज के क्षेत्रों से ख़बरें प्राप्त की जा सकें। क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में नियमित संवाददाताओं और संपादकों द्वारा अंशकालिक संवाददाताओं को मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक सहायता दी जाती है। पीटीसीज का व्यावसायिक कौशल बढ़ाने के लिए एनएसडी समय समय पर उनके लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करता है ताकि बेहतर मात्रात्मक और गुणात्मक आउटपुट प्राप्त किया जा सके।

10.7 आरएनयू ने सोशल मीडिया में भी अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। अब 45 आरएनयू के ट्विटर हैंडल, 41 आरएनयू के अपने फेसबुक अकाउंट हैं और 6 आरएनयू ने अपने यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं।

10.8 एनएसडी ने जिन राज्यों– राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम में चुनाव होने वाले हैं, वहां पीटीसी कार्यशालाओं का आयोजन किया ताकि उन्हें चुनाव कवरेज और आदर्श आचार संहिता के बारे में जागरूक किया जा सके।

10.9 2018–19 में आरएनयू के लिए संशोधित एसबीजी 21.045 करोड़ रुपये है।

fo'k"k dk;Øe

l lnh; dk;okgh dh doj t

11.1.1 अधिवेशनों के दौरान संसद में कार्यवाही की अंग्रेजी और हिंदी में दैनिक और साप्ताहिक समीक्षा 14 फरवरी, 1961 से शुरू की गई। दैनिक समीक्षा को अंग्रेजी में 'टुडे इन पार्लियामेंट' और हिंदी में 'संसद समीक्षा' कहा जाता है और इसके दो भाग हैं, एक भाग लोकसभा की कार्यवाही और दूसरा राज्यसभा की कार्यवाही पर होता है। अंग्रेजी में 'दिस वीक इन पार्लियामेंट' और हिंदी में– 'इस सप्ताह संसद में' के अंतर्गत पूर्ववर्ती सप्ताह के दौरान दोनों सदनों में कार्यवाही की महत्वपूर्ण हाइलाइट्स का सार प्रस्तुत किया जाता है।

11.1.2 राज्य विधानमण्डलों के अधिवेशनों की कार्यवाही की दैनिक और साप्ताहिक समीक्षाओं का प्रसारण 1971–72 में संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू किया गया। 'दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही' की समीक्षा 14 दिसंबर, 1993 से शुरू की गई थी।

x.kr= fnol

11.2 समाचार सेवा प्रभाग ने गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति के भाषण और 69वें गणतंत्र दिवस समारोह से संबंधित अन्य कार्यक्रमों को क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार बुलेटिनों, समाचार–आधारित कार्यक्रमों, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सहित अपने समाचार बुलेटिनों में व्यापक रूप से शामिल किया और उन्हें अपने प्रमुख समाचार बुलेटिनों का मुख्य समाचार बनाया।

Lor=rk fnol

11.3 समाचार सेवा प्रभाग ने अपने समाचार बुलेटिनों में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति के भाषण के मुख्य अंशों, साथ ही 15 अगस्त, 2018 को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री के भाषण भारत के 72वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह से संबंधित अन्य कार्यक्रमों को क्षेत्रीय भाषा के समाचार बुलेटिनों, समाचार–आधारित कार्यक्रमों साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स सहित प्रमुख समाचार बुलेटिनों में मुख्य समाचारों के साथ शामिल किया। 15 अगस्त को 27 मिनट का एक विशेष समाचार दर्शन कार्यक्रम भी प्रसारित किया गया। 14 और 15 अगस्त को क्रमशः राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषणों की लाइव ट्वीटिंग की गई।

egkRek xka/kh dh 150oha t;arh dk lekjksg

11.4.1 समाचार सेवा प्रभाग ने नई दिल्ली में चार दिवसीय महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के अंत में माननीय उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबोधनों को अंग्रेजी और हिंदी में अपने दोनों बुलेटिनों में दोनों में साथ ही साथ सभी भाषाओं के बुलेटिनों में शामिल किया। प्रधानमंत्री द्वारा साझा की गई दुनियाभर के विभिन्न गायकों की वैष्णव जन तो तेने कहिये की प्रस्तुति को महीने के दौरान सभी प्रमुख बुलेटिनों में कवरेज प्रदान की गई। वार्ता और समसामयिक कार्यक्रमों में विशेष चर्चाएं भी प्रसारित की गईं।

11.4.2 समाचार सेवा प्रभाग के सोशल मीडिया स्कंध ने ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफार्मों पर फोटो, वीडियो और ट्वीट भी पोस्ट किए। ट्वीट और फेसबुक पोस्ट के अलावा, यूट्यूब पर महात्मा गांधी के 150 साल के वीडियो को भी अपलोड किया गया।

11.4.3. महात्मा के भाषणों के मल्टीमीडिया आर्काइव्स को 2 अक्तूबर, 2018 से व्यापक कवरेज के लिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर साझा किया जा रहा है। # नोदमहात्मा– गांधीवादी विचारकों के साथ साक्षात्कार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महात्मा गांधी पर एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की जा रही है। लौह यात्रा की थीम पर विशेष कार्यक्रम यथा पोषण एवं स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान के तहत पोषण और स्वास्थ्य का भी प्रसारण किया गया।

jk"Vªh; ,drk fnol

11.5.1 समाचार सेवा प्रभाग के मुख्यालय और सभी 46 आरएनयू ने 31 अक्तूबर, 2018 को गुजरात के नर्मदा जिले के केवडिया में सरदार वल्लभाई पटेल के सम्मान में निर्मित, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, राष्ट्र को समर्पित करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम को व्यापक रूप से कवर किया गया। समाचार सेवा प्रभाग ने भारत के लौह पुरुष की 143वीं जयंती पर दुनिया में उनकी सबसे ऊची 182 मीटर की प्रतिमा का अनावरण किए जाने से संबंधित कार्यक्रम को कवर किया। नई दिल्ली के संसद मार्ग स्थित पटेल चौक पर आयोजित समारोह को समाचार सेवा प्रभाग द्वारा अपने बुलेटिनों में व्यापक कवरेज भी दी गई, जिसमें सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। रन फॉर यूनिटी को भी कवरेज प्रदान की गई थी जिसे दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से रवाना किया गया। राष्ट्रीय एकता के विषय, सरदार पटेल के योगदान पर प्रकाश डालने वाले चर्चा के कार्यक्रम एनएसडी के वार्ता और करंट अफेयर्स कार्यक्रमों में भी प्रसारित किए गए।

11.5.2 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने संबंधित घटनाओं को भी कवर किया।

ijkØe io

11.6.1. सशस्त्र बलों के साहस, वीरता और बलिदान को प्रदर्शित करने के लिए 28–30 सितंबर, 2018 को पराक्रम पर्व मनाया गया। समाचार सेवा प्रभाग ने तीन दिवसीय पराक्रम पर्व से संबंधित कार्यक्रमों को क्षेत्रीय समाचार समाचार बुलेटिनों, समाचार पत्रिका कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित अपने समाचार बुलेटिनों में व्यापक रूप से शामिल किया। इस कवरेज में 28 सितंबर, 2018 को इंडिया गेट लॉन में आयोजित मुख्य समारोह के उद्घाटन साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राजस्थान में जोधपुर

सैन्य स्टेशन में तीन दिवसीय प्रदर्शनी ijkØeio का उद्घाटन भी शामिल है।

11.6.2 फेसबुक पर लगभग 33 लाख फालोअर्स और ट्विटर पर 20 लाख फॉलोअर्स की व्यापक पहुंच के साथ समाचार सेवा प्रभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने पराक्रम पर्व का ब्योरा देते हुए कर्टन रेजर का प्रचार–प्रसार किया। सशस्त्र बलों की बहादुरी को हाइलाइट करने वाला एक वीडियो मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा किया गया, जिसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। एनएसडी ने अपने कार्यक्रमों में भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता पर प्रकाश डाला है। युद्ध और शांति में भारतीय सशस्त्र बलों की भूमिका वार्ता और समसामयिक मामलों के खण्ड में विशेष टॉक शो में कवर की गई। क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने भी रक्षा पीआरओ के साथ समन्वय कर संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में विशेष चर्चा कार्यक्रम प्रसारित किए।

सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ 29 सितंबर, 2018 को इंडिया गेट लॉन राजपथ, नई दिल्ली में आयोजित 'पराक्रम पर्व' समारोह में शामिल हुए। साथ में हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे

djfxy fot; fnol

11.7 आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा 26 जुलाई, 2018 को कारगिल विजय दिवस का जश्न भाषायी बुलेटिनों सहित अपने समाचार बुलेटिनों में व्यापक रूप से शामिल किया गया। स्पॉट न्यूज़ कवरेज में द्रास वार मेमोरियल और देशभर में अन्य स्थानों पर आयोजित समारोह शामिल किए गए। क्षेत्रीय समाचार इकाई, करगिल से प्राप्त वीडियो और तस्वीरें एनएसडी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट की गईं।

iol çekkue=h vVy fcgkjh okti;h ls lcfekr doj t

11.8 आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन वाले दिन अपने समाचार बुलेटिन में विस्तृत श्रद्धांजलि प्रसारित की। देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित की गईं श्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्राओं को भी कवर किया गया। समाचार सेवा प्रभाग ने विशेष प्रार्थना सभाओं और देशभर की नदियों में अटलजी की अस्थियों के विसर्जन को भी कवर किया। कई वार्ता कार्यक्रम भी

प्रसारित किए गए। समसामयिक मामलों के स्लॉट के तहत कई अन्य संबंधित कार्यक्रमों को प्रसारित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के आकस्मिक निधन का समाचार सभी क्षेत्रीय भाषाओं में विशेष ब्रेकिंग न्यूज़ द्वारा प्रसारित किया गया।

eu dh ckr

11.9.1 प्रत्येक माह राष्ट्र को प्रधानमंत्री के संबोधन 'मन की बात' क्षेत्रीय भाषाओं के बुलेटिनों सहित सभी प्रमुख समाचार बुलेटिनों में शामिल की जाती है। एनएसडी की वेबसाइट पर लाइव वेबकास्टिंग भी की गई।

11.9.2 राष्ट्र को प्रधानमंत्री के संबोधन 'मन की बात' पर विशेष कार्यक्रम वार्ता और समसामयिक मामलों के स्लॉट में भी प्रसारित किए गए।

11.9.3 आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की आरएनयू ने 77 भाषाओं और बोलियों में 223 बुलेटिनों में और 255 एफएफ हेडलाइन्स में 'मन की बात' को कवर किया। इसके अलावा, आरएनयू ने अपने संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर क्षेत्रीय भाषाओं में ट्वीट करके इसका व्यापक प्रचार किया।

मन की बात के 50वें एपिसोड समाचार बुलेटिनों में 140 बार प्रसारित हुआ, 126 बार एफएम शीर्षकों और 3 बार आरएनयू धारवाड़ के विशेष कार्यक्रमों का हिस्सा बनी।

vkjHk fd, x, izeq[k vfHk;ku % 2018

vk;q"eku Hkkjr dk;Øe

12.1 आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने, 50 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लक्षित करने वाले सरकार द्वारा वित्त पोषित, दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम vk;q"eku Hkkjr] प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर, 2018 में किए गए शुभारम्भ को व्यापक कवरेज प्रदान की गई। वार्ता और समसामयिक मामलों के खण्ड में एक विशेष कार्यक्रम और टॉक शो भी प्रसारित किए गए। क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने अपने समसामयिक मामलों के खण्ड में vk;q"eku Hkkjr पर लाभार्थियों की बाइट्स सहित ग्राउंड रिपोर्ट्स प्रसारित कीं। आयुष्मान भारत पर ग्राउंड रिपोर्ट भी एनएसडी द्वारा प्रसारित की गई थी।

LoPN Hkkjr fe'ku

12.2 आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को कवर किया, जिनमें वर्ष के दौरान विभिन्न मंत्रालयों का स्वच्छ पखवाड़ा शामिल है। स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों पर चर्चा कार्यक्रम और ग्राउंड रिपोर्ट/सफलता की कहानियां भी समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की गईं। एनएसडी ने 15 सितंबर, 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए पखवाड़ा–भर चलने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान से संबंधित आयोजनों को व्यापक रूप से कवर किया। एनएसडी ने अपने दैनिक आज सवेरे कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा पर 10 मिनट के विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से ग्राउंड रिपोर्ट को भी शामिल किया गया। व्यवहार परिवर्तन और स्वच्छता के बारे में जागरुकता फैलाने के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक पद्म भूषण डॉ. बिंदेश्वर पाठक को भी आमंत्रित किया गया।

iks"k.k vfHk;ku

12.3 पोषण अभियान के तहत, सितंबर माह को देशभर में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया। समग्र पोषण के महत्व के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए एनएसडी ने विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए। सोशल मीडिया पर चलाए गए अभियान का उद्देश्य जनता को पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करना तथा सरकार की ओर से बच्चों और गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए प्रदान की जाने वाली पूरक पोषाहार सेवाओं तक उनकी पहुंच कायम करना था। 11 सितंबर, 2018 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत को एक विशेष कवरेज प्रदान की गई। पोषण मिशन पर एक फोन–इन कार्यक्रम प्रसारित किया गया। इसके अलावा पोषण अभियान पर चर्चा का प्रसारण किया गया, जिसमें नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. पॉल ने भाग लिया।

u, dne % 2018

1. केंद्रीय युवा मामले एवं खेल और सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री राज्यवर्धन राठौड़ ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए, 08 जनवरी 2019 को आकाशवाणी के समाचारों को निजी एफएम प्रसारकों के साथ साझा करने की शुरुआत की। आकाशवाणी समाचार शुरुआत में परीक्षण के आधार पर 31 मई, 2019 तक निःशुल्क साझा किए जाएंगे। समाचार बुलेटिन प्रसारित करने का इरादा रखने वाले निजी एफएम प्रसारक को सबसे पहले समाचार सेवा प्रभाग : ऑल इंडिया रेडियो के साथ उसकी वेबसाइट

http://newsonair.com पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकृत एफएम चैनलों की सूची एनएसडी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 14 tuojh] 2019 rd 200 l vfèkd ,Q,e puyk u vkdk'kok.kh lekpkj dk vifjofrr :Ik e xg.k dju d fy, ithdj.k djk;k gA

2. आकाशवाणी दिल्ली के अधिकारियों, विदेशी संवाददाताओं और क्षेत्रीय समाचार इकाई के लिए eksckby i=dkfjrk कार्यशाला आयोजित की गई, ताकि वे मोबाइल का उपयोग करके समाचारों को रिपोर्ट करने और न्यूज़ स्टोरीज़ का निर्माण करने में सक्षम हो सकें।

3. एनएसडी का ;Vîc puy शुरू किया गया और 5 जुलाई, 2018 से प्रमुख बुलेटिन और विशेष कार्यक्रम उस पर नियमित रूप से अपलोड किए जा रहे हैं। 6 दिसंबर, 2018 तक उसके ग्राहकों की संख्या 29,000 का आंकड़ा पार कर चुकी थी।

4. 14 अगस्त, 2018 से, हिंदी दर्शकों को समाचार अलर्ट प्रदान करने के लिए ट्विटर हैंडल **@AIRNewsHindi** का उपयोग किया जा रहा है। 6 दिसंबर, 2018 तक इसके फालोअर्स की संख्या 3,200 का आंकड़ा पार कर चुकी थी।

5. एनआईसी के क्लाउड–आधारित प्लेटफ़ॉर्म पर शिफ्ट करने के बाद वेबसाइट www.newsonair.nic.in का डिज़ाइन और लुक बदल गया है। नई वेबसाइट के डिज़ाइन और पहुंच को अनेक लोगों ने सराहा है।

6. likndk vkj ihVhlh d fy, dk;l'kkyk,a % समाचार वाचकों, संपादकों, रिपोर्टर्स और संवाददाताओं के लिए एक मोबाइल पत्रकारिता कार्यशाला सहित प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। अक्तूबर, 2018 में एनएसडी, नई दिल्ली में संपादकों और समाचार वाचकों के लिए रिफ्रेशर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कर्नाटक में चुनावों के कवरेज के बारे में पीटीसी को जानकारी प्रदान करने के लिए अप्रैल में आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाताओं (पीटीसी) के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। पीटीसी को संबंधित राज्यों के चुनावों से पहले आदर्श आचार संहिता और चुनाव रिपोर्टिंग के प्रति अवगत कराने के लिए नवंबर में आइजोल, रायपुर, हैदराबाद, भोपाल और जयपुर में पीटीसी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

7. समाचार वाचकों के लिए नेतिया सॉफ्टवेयर पर एक द्विभाषी ऑडियो उच्चारण डेटाबेस तैयार किया गया।

8. वर्ष 2018–19 में निम्नलिखित क्षेत्रीय समाचार इकाइयों (आरएनयू) ने uÃ igy@cqyfVu शुरू किए :

- vkj,u;w jkph % 26 अक्तूबर, 2018 से हिंदी में 10 मिनट की अवधि के एक अतिरिक्त मिड–डे बुलेटिन की शुरुआत की। आरएनयू दिए गए बजट में से ही अतिरिक्त बुलेटिन का प्रबंधन कर रही है।
- vkj,u;w bEQky % 1 अक्तूबर, 2018 से अपने मिड–डे बुलेटिन की अवधि में पांच मिनट की वृद्धि की (12:00 बजे से 12:10 बजे) तथा 09:30 बजे और 10:30 बजे दो अतिरिक्त एफएम हेडलाइंस शामिल कीं।
- vkj,u;w t;iqj % सितंबर 2018 से प्रत्येक बुलेटिन की अवधि 5 मिनट बढ़ा दी गई है।
- vkj,u;w ngjknwu % अप्रैल, 2018 से देहरादून से ही अपने शाम के बुलेटिन का प्रसारण शुरू की। . पहले यह बुलेटिन आरएनयू लखनऊ से प्रसारित होता था।
- vkj,u;w dkfgek % अक्तूबर, 2018 से 15:00 बजे पर नई एफएम हेडलाइंस शुरू की गईं।
- vkj,u;w ikVZ Cys;j % 2 दिसंबर, 2018 से पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रीय बुलेटिन का प्रसारण एक एफएम चैनल के रूप में शुरू हुआ।

9. vkj,u;w i.kk ने 04 जनवरी, 2019 को विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर ब्रेल लिपि में एक दृष्टिबाधित समाचार वाचक द्वारा समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया।

,u- okf.kfT;d Lda/k

15 सीबीएस केंद्रों और सीएसयू मुंबई सहित आकाशवाणी के पूरे वाणिज्यिक ढांचे के काम की निगरानी का दायित्व आधार आकाशवाणी के वाणिज्यिक स्कंध पर है। इसके अधिदेश में संगठन के राजस्व को सीधे प्रभावित करने वाली विभिन्न गतिविधियों की देखभाल करना शामिल है। इनमें से कुछ गतिविधियां है : आकाशवाणी की विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों के संबंध में नियमित, और समय पर बिलिंग का सतत ट्रैक रखना, बिलिंग पर आधारित राजस्व आंकड़े, बैंकों में वास्तविक राजस्व प्राप्तियां, बकाया देय राशि की स्थिति, मध्यस्थता मामलों और न्यायालय के मामलों की आदि स्थिति, देशभर के विभिन्न सीबीएस केंद्रों में विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों आदि को मान्यता के लिए स्वीकृति प्रदान करना आदि।

जब से जीएसटी लागू हुआ है, तब से कमर्शियल विंग की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है। हालांकि, जीएसटी देयता को हटाते हुए विकेंद्रीकृत किया गया है, फिर भी यह केंद्रीय

बिंदु है जो पूरे सेट अप के जीएसटी से संबंधित कार्य की निगरानी करता है।

राजस्व को सीधे प्रभावित करने वाली विभिन्न जिम्मेदारियों के अलावा यह यूनिट ने हाल ही में विभिन्न सीबीएस केंद्रों के राजस्व सृजन प्रयासों की निगरानी के लिए केंद्र बिंदु थी। बढ़ते प्रतिस्पर्धी परिदृश्य के मद्देनजर केवल राजस्व में वृद्धि की दिशा में ही नहीं ठोस, बल्कि प्राप्त किए गए कारोबार से राजस्व की प्राप्ति की दिशा में भी प्रबल और केंद्रित प्रयास करने की जरूरत महसूस की गई। इसके लिए, वाणिज्यिक ढांचे को दो स्वतंत्र वर्टिकल में बांटने यानी वाणिज्यिक और विपणन में स्थापित वाणिज्यिक को धीरे–धीरे अलग करने की पहल की गई है। प्रसार भारती द्वारा अलग से वाणिज्यिक और विपणन गतिविधियों के लिए जोनल डीडीजी को पोस्ट करना इस दिशा में पहला कदम है। यह देशभर में वाणिज्यिक मुद्दों के सभी पहलुओं के त्वरित निपटान में मदद करेगा। पाइप लाइन में परिभाषित परिवर्तनों के साथ, इस विंग का ध्यान धीरे–धीरे बिलिंग की निगरानी, राजस्व वसूली और बकाया आदि की ओर अधिक सख्ती से बढ़ रहा है। राजस्व प्राप्ति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कॉरपोरेट और सरकारी ग्राहकों के लिए विस्तृत राजस्व विवरण तैयार करना शुरू किया गया है। इन प्रयासों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से खरीदे गए व्यापार के खिलाफ वास्तविक राजस्व प्राप्तियों की निगरानी में सुधार करेंगे।

बकाया राशि की वसूली के लिए समर्पित प्रयास करने के लिए, 9 सीबीएस केंद्रों पर रिकवरी परस्यूट सेल भी स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के परिणाम सामने आने लगे हैं।

आकाशवाणी का वाणिज्यिक स्कंध भी समय–समय पर आकाशवाणी की वाणिज्यिक नीति को अद्यतन करने के साथ–साथ विभिन्न सीबीएस केंद्रों को विभिन्न वाणिज्यिक संबंधित मुद्दों के बारे में प्रत्येक चरण में मार्गदर्शन देने में समान रूप से शामिल रहा है।

नई पहलों के साथ, हमें उम्मीद है कि लगातार बढ़ते चुनौतीपूर्ण वातावरण के बावजूद सफलतापूर्वक अपना धरातल आगे बढ़ाएंगे। पिछले पांच वर्षों से आकाशवाणी के राजस्व दर्शाने वाली तालिका नीचे दी गई है :

vkdk'kok.kh ds jktLo dh fiNys ikp o"kksZ dh rkfydk

o"kZ	jktLo
2013–14	510.95 करोड़ रुपये (सकल)
2014–15	473.05 करोड़ रुपये (सकल)
2015–16	524.13 करोड़ रुपये (सकल)
2016–17	531.01 करोड़ रुपये (सकल)
2017–18	547.91 करोड़ रुपये (शुद्ध) *

2018–2019 (अक्तूबर 2018 तक) में वाणिज्यिक सहित सभी स्रोतों से अर्जित शुद्ध राजस्व 298.56 करोड़ रुपये है।

*foÙkh; o"kZ 2017&18 ls jktLo ds vkdMs+ dk 'kq) eY;kadu cuk, j[kk tk jgk gSA 'kq) jktLo & foÙkh; o"kZ 2018&19 ¼1 vçSy ls vDrwcj] 2018 rd½ 2018&19 ds fy, y{; 375 djksM+ ¼'kq)½

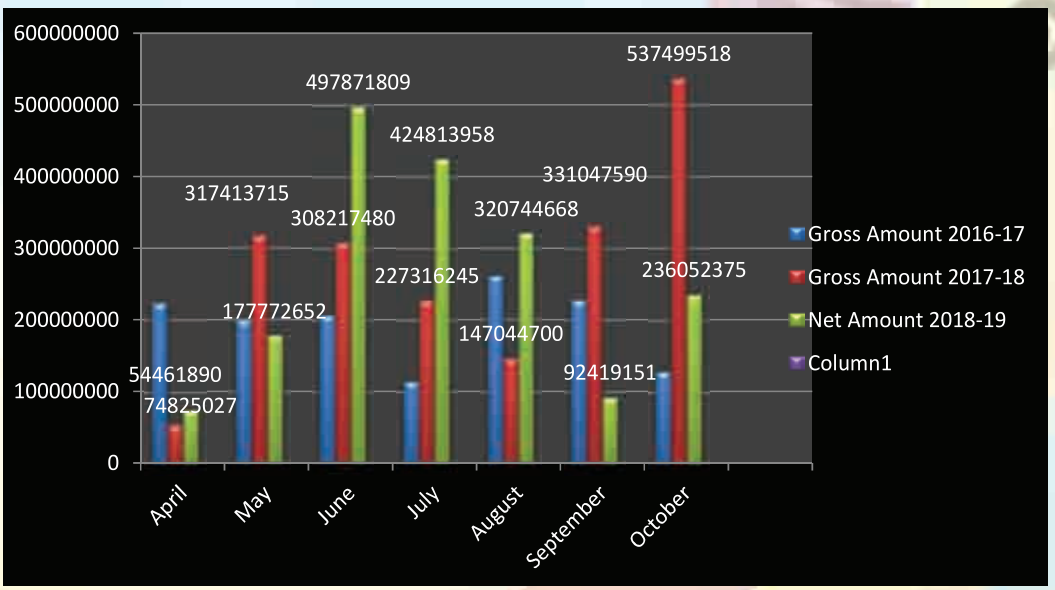

ih- fons'k lsok çHkkx

d- lf{kIr ifjp;

आकाशवाणी ने भी 1 अक्तूबर, 1939 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विशुद्ध रूप से मित्र देशों के प्रचार के माध्यम के रूप में विदेश प्रसारण पश्तो भाषा में शुरू किया। इसका लक्ष्य क्षेत्र में जर्मनी रेडियो ब्लिट्जक्रेग के प्रचार का सामना करना और विश्व के इस भाग में बीबीसी के प्रयासों को बल प्रदान करना था। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारत और शेष विश्व के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है, विशेषकर उन देशों में, जहां भारतीय लोगों के रहने की वजह से भारत के हित उनके साथ गुंथ गए हैं।

150 से अधिक देशों में 28 भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करने वाले vkdk'kok.kh dk fons'k lsok çHkkx का दर्जा पहुंच और रेंज दोनों ही दृष्टियों से विश्व के विदेश रेडियो नेटवर्क्स के बीच बहुत ऊंचा है। अपने विदेश प्रसारण के जरिए आकाशवाणी का लक्ष्य विदेश स्थित श्रोताओं को भारत के लोकाचार से जोड़ना है। आकाशवाणी जिन भाषाओं में अपने विदेशी श्रोताओं तक पहुंचता है, उनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्वाहिली, अरबी, फारसी, तिब्बती, चीनी, थाई, बर्मी और इंडोनेशियाई भाषा शामिल है। हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगू, मलयालम, ओड़िया, कन्नड़ और गुजराती में भी प्रसारण सेवाएं विदेश स्थित भारतीयों को ध्यान में रख कर की जाती हैं। भारतीय प्रायद्वीप और भारत के निकटवर्ती पड़ोसी देशों में रह रहे श्रोताओं के लिए उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सरायकी, सिंहला, बांग्ला और नेपाली में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। विदेश प्रसारण प्रभाग एक मिश्रित पैटर्न का अनुसरण करता है, जिसमें आमतौर पर समाचार बुलेटिन, समीक्षाएं, सम–सामयिक घटनाओं पर टीका और भारतीय प्रेस समीक्षा शामिल की जाती है। इसमें औपचारिक वार्ता, साक्षात्कार, फ़ीचर, सभी शैलियों का भारतीय संगीत, रेडियो नाटक आदि भी शामिल हैं।

न्यूज़रील के अलावा खेलों और साहित्य के बारे में पत्रिका कार्यक्रम, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विषयों पर वार्ताएं और परिचर्चाएं, विकासात्मक गतिविधियों, महत्वपूर्ण घटनाओं और संस्थानों पर फ़ीचर, भारत के विविध क्षेत्रों के शास्त्रीय, लोक और आधुनिक संगीत समग्र कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं।

विदेश प्रसारण सेवा में सभी कार्यक्रमों का मुख्य ध्येय एक सुदृढ़ धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत की वास्तविक छवि प्रस्तुत करना है। श्रोताओं को यह एहसास कराना है कि भारत एक सशक्त, प्रगतिशील राष्ट्र है, जो आर्थिक, औद्योगिक और प्रौद्योगिकी संबंधी तीव्र प्रगति में संलग्न है। भारत की विस्तृत तकनीकी कार्मिक क्षमता और उसकी उपलब्धियों तथा पारिस्थितिकी संतुलन संबंधी तथ्यों को सरल और सामान्य कार्यक्रमों के जरिए प्रस्तुत किया जाता है।

इसी प्रकार अहिंसा में भारत के विश्वास, सार्वभौमिक मानवाधिकारों एवं अंतरराष्ट्रीय शांति के प्रति उसकी वचनबद्धता और नई वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण में उसका योगदान प्रभाग के कार्यक्रमों के जरिए बार–बार व्यक्त किया जाता है।

[k- ubZ igy vkSj vk/kqfudhdj.k ds ç;kl

- आकाशवाणी की वैश्विक पहुंच में सुधार की दिशा में पहले कदम के रूप में, पिछले दो वर्षों से प्रसार भारती और एमआईबी के माध्यम से विदेश मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ फिर से जुड़ने के लिए कदम उठाए गए हैं। एमईए से हमारी विदेश नीति और विदेशी संबंधों के महत्व के दृष्टिकोण से उन देशों और क्षेत्रों को इंगित करने को कहा गया है, जिन्हें वे आकाशवाणी द्वारा कवर करना चाहते हैं।

- अपनी स्थापना के बाद से लेकर 2016 तक, विदेश प्रसारण मुख्यतः टेरिस्टलीय रूप से मीडियम वेव (निकट पड़ोसी देशों के लिए) और शॉर्टवेव (दूरस्थ देशों के लिए) के माध्यम से किया जा रहा है। तकनीकी प्रगति के साथ, उपरोक्त माध्यमों के पूरक के तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। तदनुसार, पिछले दो वर्षों में आकाशवाणी की विदेश सेवा ने अपनी मौजूदा सभी 28 भाषा सेवाओं (15 विदेशी और 13 भारतीय) के लिए एक मल्टीमीडिया वेबसाइट airworldservice.org विकसित की है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। मल्टीमीडिया वेबसाइट में कार्यक्रमों, पॉडकास्ट, टेक्स्ट, वीडियो और तस्वीरों की लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा एक मोबाइल एप एयरवर्ल्डसर्विसावा जैसी विशेषताएं हैं, जो आकाशवाणी के विदेश प्रसारण को सही मायने में वैश्विक बना रही हैं। इसे अतिरिक्त रेडियो गार्डन, ट्यून इन, अमेजन एलेक्सा आदि जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग इसे पूर्णता प्रदान कर रहा है।

- ईएसडी के सभी वेब पोर्टलों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आदि जैसे विविध सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ जोड़ा गया है ताकि उन्हें अधिक इंटरैक्टिव और सहभागी बनाया जा सके जिसमें दुनिया के किसी भी कोने से श्रोता अपने अनुरोध और प्रतिक्रिया में भेज सकें।

- चालू वर्ष में एक अंतरराष्ट्रीय संघ के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों/देशों में एफएम, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव ट्रांसमीटरों को साथ जोड़ने का प्रस्ताव है जो ईएसडी कार्यक्रमों की प्राप्ति और पहुंच में और वृद्धि करेंगे।

- इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान ईएसडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक स्मार्ट टीवी एप को एकीकृत करने की पहल की गई है, जो दृश्य सामग्री को उसी तरह प्रसारित करने में मदद करेगा, जैसे बीबीसी, सीआरआई, वीओए आदि जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय रेडियो प्रसारकों द्वारा किया जा रहा है।

- बहुत से अफ्रीकी–एशियाई देशों में इंटरनेट के प्रवेष की सीमाओं के मद्देनजर, अंतरराष्ट्रीय प्रसारण के लिए शॉर्टवेव पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता। तदनुसार, आकाशवाणी ने वर्तमान में विदेश प्रसारण के लिए उपयोग में लाए जा रहे 7 शॉर्टवेव ट्रांसमीटरों को बदलने हेतु धन उपलब्ध कराने के लिए प्रसार भारती/सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है, जो अपना जीवनकाल समाप्त होने के बाद भी चल रहे हैं और आकाशवाणी की वैश्विक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए उन्हें तत्काल बदले जाने की आवश्यकता है।

- आकाशवाणी ने बांग्लादेश और बंगाली प्रवासियों की दुनिया को लक्षित करते हुए 2016 में 1000 मेगा वाट डीआरएम ट्रांसमीटर के माध्यम से और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा 16 घंटे का दैनिक विशेष आकाशवाणी मैत्री चैनल भी शुरू किया।

- 2018 में, आकाशवाणी ने दुनिया भर के अनिवासी ओडिया लोगों तक पहुंच बनाने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग के साथ ओडिया भाषा की एक वेबसाइट लॉन्च की।

- आकाशवाणी ने भूटान के लिए ज़ोंग्खा भाषा में एक विशेष सेवा शुरू करने के लिए भी कदम उठाए हैं जिसे विदेश मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। सरकार की पड़ोसी देशों को अहमियत देने वाली नीति को देखते हुए यह सेवा प्रस्तावित की गई।

- देश के लिए सीआईएस देशों, जापान, पूर्वी एशिया और दक्षिण अफ्रीका के महत्व को देखते हुए आकाशवाणी ने एमईए से इस बारे में भी इंगित करने का अनुरोध किया है कि इन देशों के लिए किसी भी सेवा की आवश्यकता है या नहीं।

- आकाशवाणी द्वारा विदेश प्रसारण की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विदेशी राजनयिकों, भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों और विदेशी संवाददाताओं को साथ जोड़ते हुए उन्हें विदेश प्रसारण के बारे में जानकारी देने के लिए 1 अक्तूबर, 2018 को एक भव्य समारोह में विदेश प्रसारण दिवस (ईबीडी) मनाया गया।

- उपरोक्त के अलावा, आकाशवाणी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रसारण संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से भी अपनी वैश्विक उपस्थिति में सुधार लाने के लिए लगातार साझेदारी कर रहा है।

D;- jk"Vªh; puy

1. हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित किए जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री के "मन की बात" को प्रसारित करने के लिए एक विशेष दोपहर प्रसारण सेवा शुरू की गई, क्योंकि राष्ट्रीय चैनल का नियमित प्रसारण रोजाना शाम 6:50 बजे शुरू होता है। इस कार्यक्रम को हमारे नियमित प्रसारण में उसी दिन रात 8:00 बजे प्रसारण के लिए शेड्यूल किया जा रहा है।

2. राष्ट्रीय चैनल में सरकार की नई कल्याणकारी योजनाओं जैसे "प्रधानमंत्री आवास योजना", "प्रधानमंत्री मातृत्व योजना", "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ", "स्वच्छ भारत अभियान", "महिला सशक्तीकरण योजना", "उज्ज्वला योजना", "प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना", "फसल बीमा योजना", "अल्पसंख्यकों के लिए उस्ताद योजना'', "सुकन्या समृद्धि योजना", और "दिव्यांगों के कल्याण के लिए योजनाएं" पर प्रकाश डालने वाले कई कार्यक्रमों की पेशकश की गई और उसी अवधि में उनका प्रसारण किया गया।

3. समाज के विभिन्न वर्गों के लिए समय–समय पर शुरू की गई कई अन्य योजनाओं पर कार्यक्रम प्रसारित किए गए। इनमें सरकार की गरीबी एवं बेरोज़गारी उन्मूलन योजनाएं, 'प्रधानमंत्री जन धन योजना', 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना', 'आयुष्मान भारत : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना', 'मेक इन इंडिया' आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

4. कार्यक्रमों में पर्यावरण के उन मुद्दों को शामिल किया गया, जिनमें विभिन्न प्रतिबद्ध एनजीओ के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया और उनकी बहुमूल्य सूचनाएं प्रसारित की गईं। इन कार्यक्रमों में ओज़ोन परत की सुरक्षा, जैव विविधता, वन और जलवायु परिवर्तन और जैविक खेती से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया।

5. संस्मरण आधारित कार्यक्रमों में से एक "जीवन के रंग" में एक वर्ष के भीतर उत्तर से दक्षिण ध्रुव के बीच स्कींग करने वाले पद्मश्री से सम्मानित अजीत बजाज जैसे विख्यात व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित एक अन्य हस्ती प्रसिद्ध भाषाविद गणेष नारायणदास डेवी, से भी विविधा कार्यक्रम में साक्षात्कार प्रसारित किया गया।

6. मई–जून, 2018 में "रमज़ान" की अवधि के दौरान "सहरगही" कार्यक्रम का "राष्ट्रीय प्रसारण सेवा (राष्ट्रीय

चैनल)" से प्रसारण किया गया जिसमें हमद, नात, कव्वाली और कुरान पाठ शामिल थे।

7. 'संतवाणी' शीर्षक के तहत कुछ विशेष साहित्यिक और आध्यात्मिक प्रकार के कार्यक्रम निर्मित और प्रसारित किए गए। इस कार्यक्रम में गौतम बुद्ध, नामदेव, भगवान कृष्ण भक्त रसखान और तुकाराम आदि प्रमुख भारतीय संतों के जीवन और दर्शन पर प्रकाश डाला गया।

8. नया कार्यक्रम 'मैसेज मेल' (श्रोताओं के संदेशों और बीच–बीच में फ़िल्म संगीत) श्रोताओं की खुशी और आनंद के लिए प्रसारित किया जा रहा है।

9. स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2018) पर एक विशेष मुशायरा 'जश्न–ए–जम्हूरियत' प्रसारित किया गया जिसमें अलीगढ़ और आगरा के प्रतिष्ठित शायरों को आमंत्रित किया गयाा।

10. मीडिया में महिलाओं के सकारात्मक चित्रण के माध्यम से जनता में जागरुकता फैलाने और उसे संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से वार्ता/साक्षात्कार/चर्चा प्रारूप में उपयुक्त कार्यक्रम बनाए गए। कुछ कार्यक्रम "यौन उत्पीड़न से महिला संरक्षण" (बातचीत), "विज्ञापन में नारी छवि का चित्रण एवं सामाजिक दृष्टिकोण (वार्ता)", "मीडिया में महिलाओं का चित्रण" (चर्चा), "महिला मानवाधिकर और अस्मिता "(वार्ता) शीर्षक से प्रसारित किए गए थे।

11. अप्रैल 2018 से अक्तूबर 2018 की संपूर्ण अवधि के दौरान हिंदी कविता पाठ, कथा वाचन, कवि सम्मेलन, हिंदी साहित्यिक वार्ता और चर्चा सहित कई साहित्यिक कार्यक्रम पाक्षिक कार्यक्रम 'साहित्य दर्पण' में प्रसारित किए गए।

12. अगस्त में राष्ट्रीय चैनल को अंग्रेजी फ़ीचर ''फ्रॉम स्लम टू ग्लोरी'' के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एआईबीडी रेडियो पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस फ़ीचर का निर्माण राष्ट्रीय चैनल, आकाशवाणी की प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव सुश्री शर्मिला गोस्वामी द्वारा किया गया था।

13. महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर अक्तूबर महीने में "गांधीयन थॉट्स" (चिंतन) का प्रसारण किया गया। इसके अलावा, "गांधी चर्चा" (गांधीजी की आत्मकथा के अंश) भी प्रातः प्रसारण में हर शुक्रवार को प्रसारित किया गया। इसके अलावा "साफ–सफाई" और "स्वच्छ्ता" से संबंधित कार्यक्रमों को वार्ता और साक्षात्कार प्रारूपों में प्रसारित किया गया। कुछ कार्यक्रमों के शीर्षक "स्वच्छता हेतु कृषि अवशेषों का प्रबंधन", "कचरा प्रबंधन", "ई–कचरा प्रबंधन एवं चुनौती" और "प्लास्टिक को करें बाय–बाय" आदि थे।

vkj- vUrjjk"Vªh; lEcU/k bdkbZ

ऑल इंडिया रेडियो की अंतरराष्ट्रीय संबंध इकाई के उसके कार्यक्रम स्कंध से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों से संबंधित है। इसके कार्यों में अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण–कार्यशालाओं आदि में आकाशवाणी के अधिकारियों की भागीदारी के लिए प्रक्रिया और समन्वयन करना, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आकाशवाणी के कार्यक्रमों की भागीदारी, देश के भीतर कार्यशालाओं/सम्मेलनों/कार्यक्रमों का आयोजन; आतिथ्य और अन्य देशों के गणमान्य व्यक्तियों के दौरों, आकाशवाणी से संबंधित गतिविधियों और औपचारिकताओं का समन्वय; अंतरराष्ट्रीय मीडिया निकायों के साथ आकाशवाणी की सदस्यता; सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों (सीईपी), अन्य देशों/संगठनों के साथ समझौतों और समझौता ज्ञापनों आदि से संबंधित मामलों का कार्यान्वयन करना शामिल है।

xfrfofèk;k¡ vkSj miyfC/k;k¡

इकाई ने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे– एबीयू अवार्ड्स 2018 और 30वें यूआरटीआई इंटरनेशनल रेडियो ग्रां प्री 2018 में आकाशवाणी की भागीदारी को सफलतापूर्वक समन्वित किया।

njn'kZu

vUrjjk"Vªh; lEesyu@,ch;w dk;Z'kkyk,¡

दूरदर्शन के अधिकारियों ने 2018–19 (अक्तूबर, 2018 तक) के दौरान विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/एबीयू कार्यशालाओं में भाग लिया :

1. अश्गाबात, तुर्कमेनिस्तान में 30 सितंबर से 05 अक्तूबर, 2018 एबीयू महासभा 2018,

2 अश्गाबात, तुर्कमेनिस्तान में 30 सितंबर से 05 अक्तूबर, 2018 एबीयू तकनीकी समिति की बैठक।

3.. बीजिंग, चीन में एआईबीडी/बीआईआरटीवी मीडिया कोऑपरेशन एक्सचेंज प्रोजेक्ट 21 से 26 अगस्त, 2018 तक।

egRoiw.kZ ?kVukvksa dk dojst

वर्ष 2018–19 (31.10.2018 तक) के दौरान दूरदर्शन

द्वारा ओबी/ईएफपी वैन का उपयोग करके 195 से अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया गया है। इसके अलावा, 31.03.2019 तक लगभग 23 प्रमुख आयोजनों को कवर किया जाना प्रस्तावित है। दूरदर्शन द्वारा लाइव कवर किए जाने और प्रस्तावित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम अनुलग्नक–6 में दिए गए हैं।

MhMh u'kuy& çe[k puy

राष्ट्र के लोक सेवा प्रसारक के मुख्य और प्रमुख चैनल के रूप में, डीडी नेशनल मनोरंजन, सूचना और शिक्षा का स्वस्थ मिश्रण प्रदान करता है। यह स्थलीय मोड में प्रातः 05. 30 बजे से मध्य रात्रि तक और उपग्रह मोड में चौबीसों घंटे उपलब्ध है।

प्रमुख घटनाओं का सीधा प्रसारण डीडी नेशनल के प्रमुख घटकों में से एक है। वर्ष 2018 में, डीडी नेशनल ने सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को हाइलाइट करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण भी किया। इसके अलावा, गणतंत्र दिवस और प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण जैसे राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों का सीधा प्रसारण किया।

महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की जयंती/पुण्यतिथि (जैसे स्वामी विवेकानंद, बाबा साहिब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल, पं. दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख) को कवर किया गया और डीडी नेशनल समुचित महत्व प्रदान करते हुए प्रसारित किया गया। सतर्कता जागरुकता और राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम भी डीडी नेशनल पर प्रसारित किए गए।

स्वास्थ्य पर सामाजिक रूप से प्रासंगिक कार्यक्रम और विशेष रूप से संचारी रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संबंधी अन्य मुद्दों के बारे में जागरुकता फैलाने वाले विज्ञापन डीडी नेशनल के कार्यक्रम में नियमित रूप से शामिल हैं।

डीडी के पास एक समर्पित खेल चैनल होने के बावजूद सभी महत्वपूर्ण खेल आयोजनों को डीडी नेशनल के प्रसारणों में शामिल किया गया है।

माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन मन की बात का प्रसारण डीडी नेशनल पर किया जाता है और इसके क्षेत्रीय भाषायी संस्करणों को क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा दोहराया जाता है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण के अलावा, देशभर के विभिन्न केंद्रों से लाइव इनपुट के साथ दिन भर का विशेष मेगा टॉकथॉन कार्यक्रम स्टूडियो में पैनलिस्टों के साथ प्रसारित किया गया। "सेवा दिवस" और "काला धन विरोधी दिवस" के अवसरों पर लाइव टॉकथॉन शो का प्रसारण बातचीत कर रहे पैनलिस्टों सहित देश के विभिन्न हिस्सों से लाइव रिपोर्ट के साथ किया गया।

युवा मामले एवं खेल और सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 31 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में दूरदर्शन के यात्रा कार्यक्रम "रग–रग में गंगा" और क्विज़ शो "मेरी गंगा" के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित करते हुए

दूरदर्शन ने दिनांक 12.04.2018 को पीएसएलवी–सी41/आईआरएनएसएस–11, 16.04.2018 को पीएसएलवी–सी42/नोवा एसएआर +एसआई–4, 14.11.2018 को जीएसएलवी एमके–111 डी2, जीसेट–29 को, 29.11.2018 को पीएसएलवी–सी43 और 05.12.2018 को जीएएसटी–11 लॉन्च करने की विस्तृत व्यवस्था की।

वर्ष के दौरान, डीडी नेशनल ने गोवा में आयोजित आईएफएफआई–2018 को भी व्यापक कवरेज प्रदान की।

बीबीसी के सहयोग से यूनिसेफ द्वारा किशोरों के लिए निर्मित "आधा फुल", चिल्ड्रन फ़िल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित बच्चों के लिए एक जासूसी धारावाहिक, "वी –3", डॉयचे वेले (जर्मन टीवी) के सहयोग से "मंथन" और "गली–गली सिम–सिम", सीसेम वर्कशॉप ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित बच्चों का कार्यक्रम, डीडी नेशनल पर वर्ष के दौरान चलने वाले कुछ अन्य लोकप्रिय शो हैं।

हमेशा की तरह 31 दिसंबर को डीडीके मुंबई द्वारा निर्मित नववर्ष की पूर्व संध्या के विशेष प्रसारण के साथ वर्ष का समापन हुआ। क्षेत्रीय केंद्रों ने भी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में नए साल की पूर्व संध्या कार्यक्रमों का प्रसारण किया।

वर्ष 2019 के लिए योजनाएं (01.01.2019 से 31.03.2019 तक पहली तिमाही)

- दर्शकों को वापस खींचने के लिए डीडी नेशनल पर ब्लॉक बस्टर फ़िल्म और सामाजिक रूप से प्रासंगिक सामग्री वाली उच्च मनोरंजन मूल्यों के साथ निर्मित फ़िल्म प्रदर्शित करना।
- डीडी नेशनल भी लुक और फील बढ़ाने, ग्राफिक्स, सेट डिजाइन, प्रोमो और लोगो टेम्प्लेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है।
- समर्पित प्रचार अभियान और एक सुविचारित बिक्री रणनीति का प्रस्ताव किया गया है ताकि सामग्री का उचित मुद्रीकरण सुनिश्चित किया जा सके और दर्शकों को आकृष्ट किया जा सके।
- गणतंत्र दिवस समारोह, बीटिंग द रिट्रीट समारोह आदि जैसी प्रमुख घटनाओं को भी पिछले वर्षों की तरह कवर किया जाएगा।

fQYe%

2018–19 के दौरान डीडी के फ़िल्म अनुभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियां

दूरदर्शन प्राइम टाइम बैंड में प्रतिदिन हिंदी फ़ीचर फ़िल्म दिखा रहा है। or%eku e% vkB ¼08½ çgnh Qhpj fQYe% lkIrkfgd :i l% çlkfjr dh tk jgh gS] जिसके कारण दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या और उच्च जीवीएल रेटिंग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और पूर्ववर्ती कार्यक्रमों की तुलना में दूरदर्शन राष्ट्रीय नेटवर्क के प्राइम टाइम के लिए टाइम स्पेंट हासिल किया गया है।

फ़िल्म अनुभाग ने विभिन्न अवसरों के मौके पर fo'k"k fQYeksa का प्रसारण किया है जो इस प्रकार हैं

Ø-l-	fQYe dk uke	i%lkj.k dh frfFk	अवसर
1	डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर	14.04.2018	डॉ. बी. आर. अंबेडकर की जयंती
2	अ जर्नी ऑफ संयक बुद्धा	30.04.2018	बुद्ध पूर्णिमा
3	टॉयलेट–एक प्रेम कथा	26.05.2018	वर्तमान सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता मिशन के चार (04) वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए
4	इंदुसरकार	03.07.2018	इमरजेंसी से संबंधित (1975)।
5	दंगल	15.08.2018	स्वतंत्रता दिवस की 72वीं वर्षगांठ।
6	परमाणु	15.08.2018	स्वतंत्रता दिवस की 72वीं वर्षगांठ। यह फ़िल्म पोखरण –2 (1998) से प्रेरित है
7	प्रहार	28.09.2018	पराक्रम पर्व
8	बेबी	29.09.2018	पराक्रम पर्व
9	हीरोज़	30.09.2018	पराक्रम पर्व
10	गांधी	02.10.2018	महात्मा गांधी की 150वीं जयंती।
11	सरदार	31.10.2018	राष्ट्रीय एकता दिवस (सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती)

- फ़िल्म अनुभाग ने अक्तूबर में डीडी नेशनल पर ऑस्कर नामित और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फ़िल्म þU;Vuþ का प्रीमियर किया।

- फ़िल्म अनुभाग ने प्रस्तावकों/निर्माताओं/ग्राहकों की सुविधा और शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मई 2018 और जुलाई 2018 के महीने में दो (02) ओपन हाउस सत्रों का आयोजन किया।

- ऑनलाइन पोर्टल प्रणाली की सहायता से फ़िल्म खरीद की प्रणाली को डिजिटल बनाने/सरल बनाने के लिए कदम उठाए गए।

- फ़िल्म अनुभाग ने प्रत्येक शुक्रवार को शाम 3 बजे से 5 बजे तक प्रस्तावकों/निर्माताओं/ग्राहकों की सुविधा और शिकायतों के निवारण के लिए एक "ओपन विंडो" शुरू की है।

- प्रख्यात प्रस्तावकों/निर्माताओं/बैनर्स को आकर्षित करने के प्रयास किए गए हैं। अधिकांश प्रस्तावकों/निर्माताओं ने दूरदर्शन को सर्वश्रेष्ठ फ़िल्मों की पेशकश की। वर्तमान में दूरदर्शन के पास लगभग 179 प्रस्तावक हैं।

- फ़िल्म अनुभाग ने डीडी नेशनल पर फ़िल्मों के प्रसारण के लिए विषयगत स्लॉट जैसे– रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, फ्राइडे हाउसफुल, शनिवार जुबली, संडे ब्लॉकबस्टर और रेट्रो बनाए हैं, साथ ही मशहूर हस्तियों जैसे सलमान खान स्पेशल, शाहरुख खान स्पेशल, अक्षय कुमार स्पेशल और फेस्टिवल स्पेशल जैसे– दिवाली धमाका जैसे विशेष फ़िल्में दिखाई हैं।

- फ़िल्म अनुभाग ने डीडी भारती, डीडी कशीर, डीडी उर्दू और डीडी किसान जैसे अन्य चैनलों को हिंदी फ़ीचर फ़िल्में प्रदान की हैं, जिससे उन्हें उच्च टीआरपी मिलीं।

- फ़िल्म अनुभाग ने अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 तक भुगतान की गई रॉयल्टी की तुलना में फ़िल्मों से अधिक राजस्व सफलतापूर्वक अर्जित किया।

Ø- l-	eghuk	jk;YVh dk Hkqxrku ¼djksM+ #i;k esa½	vftZr jktLo ¼djksM+ #i;k esa½
1	अप्रैल'18	2.1	9.9
2	मई'18	1.8	5.3
3	जून'18	1.7	9.7
4	जुलाई'18	2.1	9.5
5	अगस्त'18	2.0	11.6
6	सितंबर'18	1.6	12.1
	dqy	11-4	58-1

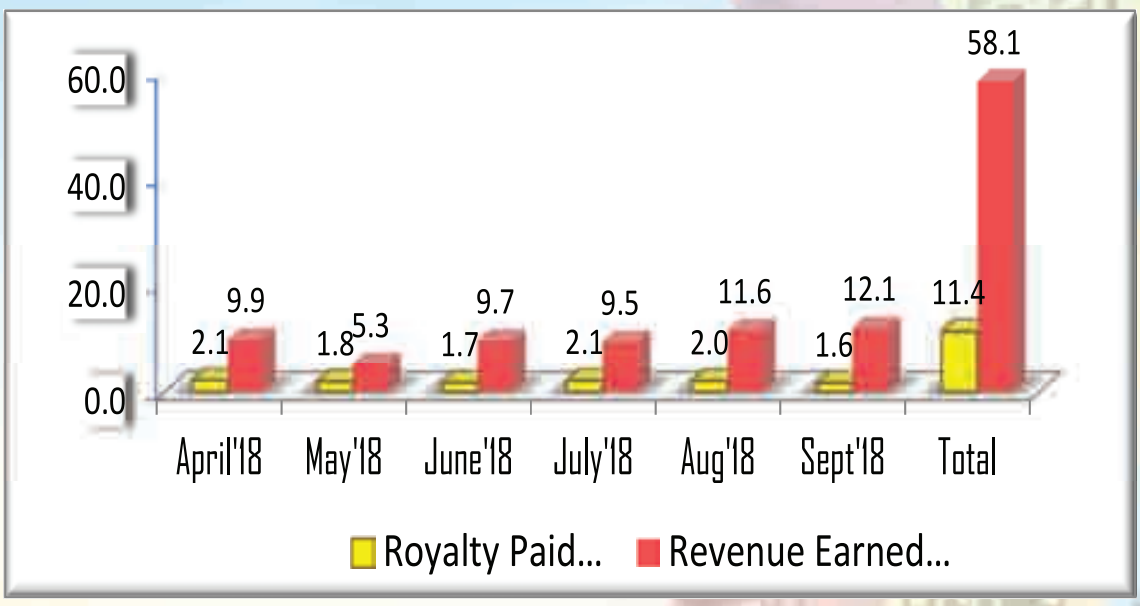

तालिका में रॉयल्टी का भुगतान (करोड़ों में) और अर्जित राजस्व (करोड़ों में) दर्शाया गया है

यह अनुभाग दर्शकों के मनोरंजन के लिए आगामी अवसरों/त्योहारों/दिवसों जैसे नए साल के जश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस, गणतंत्र दिवस, होली आदि पर और भी बेहतर सामग्री के साथ हर संभव प्रयास कर रहा है। अप्रैल 2018 से नवंबर 2018 तक डीडी नेशनल पर फ़िल्म अनुभाग द्वारा प्रसारित की गई फ़िल्मों की टीआरपी आगे दी गई तालिका में दर्शाई गई है :

vçy^18	vkl r Vhoh, y
मई'18	6.9
जून'18	6.1
जुलाई'18	5.8
अगस्त'18	6.2
सितंबर'18	9.0
अप्रैल'18	7.8
अक्तूबर'18	8.3
नवंबर'18	9.5

(स्रोत :बीएआरसी)

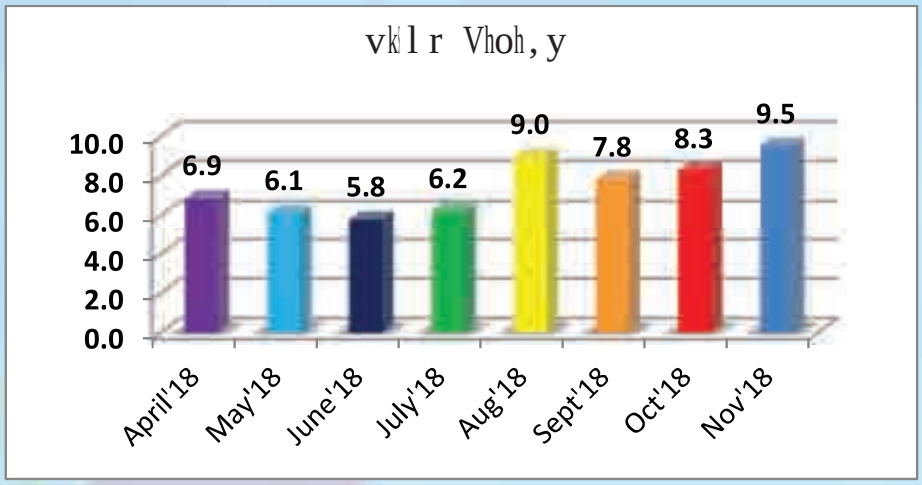

MhMh U;wt

डीडी न्यूज़ देश का एकमात्र स्थलीय–सह–उपग्रह और बहुभाषी समाचार चैनल है। डीडी न्यूज़ गैर–केबल, गैर–उपग्रह घरों में स्थलीय संचरण मोड के माध्यम से भी उपलब्ध है।

डीडी न्यूज़ 3 नवंबर, 2003 डीडी मेट्रो चैनल को 24 घंटे के समाचार चैनल में में परिवर्तित करके शुरू किया गया था। दिल्ली स्थित मुख्यालय से यह वर्तमान में मूक बधिर लोगों के लिए दो विशेष बुलेटिनों के अलावा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत भाषाओं में समाचार प्रसारित कर रहा है। इसमें प्रतिदिन कुल 18.5 घंटे लाइव प्रसारण द्वारा इन भाषाओं में 40 से अधिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण होता है।

चैनल पर प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों में स्वास्थ्य, युवा मामले, सिनेमा, कला और संस्कृति, फ्लैगशिप योजना, प्रमुख योजनाएं, अंतरराष्ट्रीय आयोजन, बाज़ार के घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर कार्यक्रम शामिल हैं।

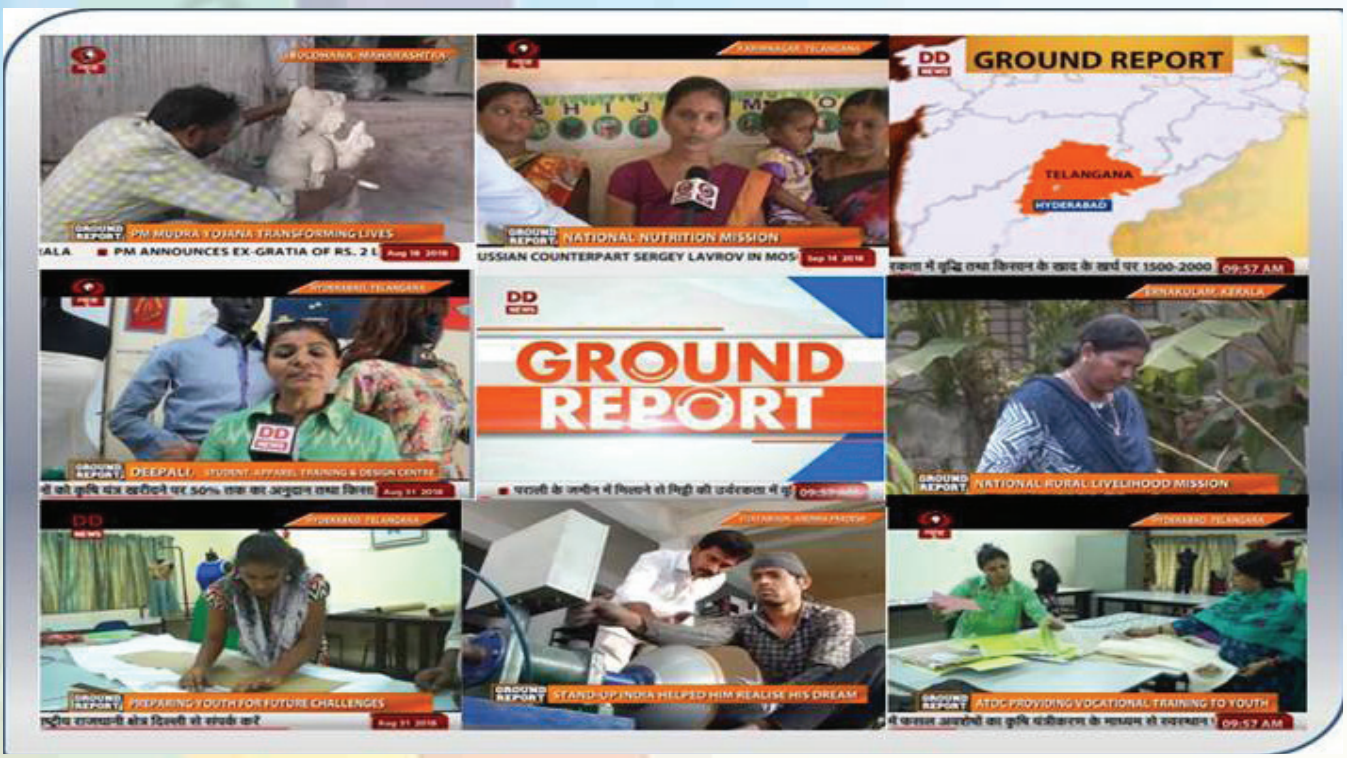

"ग्राउंड रिपोर्ट": डीडी न्यूज़ नेटवर्क द्वारा सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के लाभार्थियों की 5000 से अधिक सफलता की कहानियों का प्रसारण किया गया था

lekpkj lxg.k

डीडी न्यूज़ में नवीनतम उपग्रह आधारित प्रौद्योगिकियों के जरिए, डीएसएनजी/ओबी वैन के साथ और फाइल इंटरनेट/सेलुलर मोबाइल आधारित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से दूर–दराज इलाकों सहित देशभर से समाचारों का संग्रहण किया जाता है। डीडी न्यूज़ अपने अधिकांश समाचार निम्नलिखित स्रोतों से एकत्रित करता है :

– मुख्यालय और क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में कार्यरत अपने संवाददाताओं से

– स्ट्रिंगर और अंशकालिक संवाददाताओं से

– एजेंसियों (पीटीआई, यूएनआई, रायटर्स, एएनआई) से

– अंतरराष्ट्रीय साझेदारों (उदाहरण के लिए अन्य राष्ट्रीय प्रसारकों, एशियाविजन) से

miyfC/k;k

चैनल के प्रारूप और सामग्री का पुनर्गठन डीडी न्यूज़ की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। हाल ही में कई नए कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

इनमें से कुछ हैं: –

ग्राउंड रिपोर्ट्स/ज़मीनी हक़ीकत; स्वच्छता समाचार; ख़बर जल्दी–जल्दी; 5 मिनट फ्लैश 15; वार्ता, संस्कृत समाचार, बदलते भारत पर चर्चा और मूक बधिरों के लिए एक अतिरिक्त बुलेटिन

इन्हें रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चाओं, जेन–नेक्स्ट, रंग तरंग, जानने का हक टोटल हेल्थ– समसामयिक मामलों का कार्यक्रम, सिनेमा इस हफ्ते, तेजस्विनी, सोशल कनेक्शन, वार्तावली, नया सवेरा, ब्रेकफास्ट शो, मार्केट दिस वीक, मनी मंत्रा, गुड न्यूज़ इंडिया, स्पेशल स्टोरीज फ्रॉम कश्मीर और ओपन फ्रेम पीएसबीटी के जरिए पूर्णता प्रदान की गई है।

डीडी न्यूज़ ने प्रधानमंत्री के "मन की बात" संबोधन को रेडियो प्रसारण के साथ–साथ टीवी प्रसारण के लिए अपनाया है, जिसे कई निजी चैनलों पर भी प्रसारित किया गया। इसे पैकेज्ड स्टोरीज, चर्चाओं और लोगों की प्रतिक्रियाओं के जरिए पूर्ण कवरेज प्रदान की गई।

9 फरवरी, 2019 को अरुणाचल प्रदेश में डीडी अरुणप्रभा चैनल के लोकार्पण के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं अन्य गणमान्य सदस्य

rduhdh volajpuk

इस 24x7 न्यूज़ चैनल का दिल्ली में अपना राष्ट्रीय न्यूज़ रूम और दो स्टूडियो हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से उपग्रह आधारित समाचार एकत्र करने के लिए, विभिन्न राज्यों में 16 डीएसएनजी वैन मौजूद हैं। सबसे बढ़कर, जहां डीएसएनजी वैन उपलब्ध नहीं हो पाती हैं या तैनात नहीं की जा सकती हैं, तो वहां मोबाइल कनेक्टिविटी आधारित बैकपैक उपकरण तैनात किए जाते हैं।

डीडी न्यूज़ अपने सहयोगी चैनलों के लिए समाचार तैयार करता है। डीडी न्यूज़, डीडी उर्दू के लिए भी 10 लाइव

बुलेटिन और समाचार स्क्रोल्स बनाता है। किसान चैनल की शुरुआत के साथ ही डीडी न्यूज़ किसानों की दिलचस्पी के दो नए बुलेटिन बनाकर दे रहा है।

डीडी न्यूज़ ने अपने निर्माण में वीडियो वॉल्स जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं की शुरुआत की है। अधिकांश समाचार बुलेटिन, कार्यक्रम और लाइव शो वीडियो वॉल्स की सहायता से प्रस्तुत किए जाते हैं।

bVjusV vkj lk'ky ehfM;k ij MhMh U;wt

न्यूज़ चैनल ने अपनी वेबसाइट के अलावा भी सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है जिसमें फेसबुक पेज, अंग्रेजी और हिंदी में ट्विटर हैंडल और एक यूट्यूब चैनल शामिल है। डीडी न्यूज़ की वेबसाइट तक www.ddinews.gov.in या www.ddinews.com. पर देखी जा सकती हैं। सितंबर, 2013 में वीडियो देखने की सुविधा के साथ वेबसाइट को एक नए अंदाज में लांच किया गया था और इसे और संवारा गया है और उपयोग सुलभ बनाया गया है।

डीडी न्यूज़ के इंग्लिश ट्विटर हैंडल @DDNewslive की शुरुआत जनवरी 2013 में की गई थी और अब इसे 23 लाख से अधिक (23,79,476) लोगों द्वारा फॉलो किया जाता है और दिन–प्रतिदिन इसके फॉलोअर्स की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। हिंदी में इसके नए ट्विटर हैंडल @DDNewsHindi की शुरुआत जनवरी 2014 में की गई थी और इसके भी 18 लाख से ज्यादा (18,15,119) फॉलोअर्स हैं।

एक समर्पित यूट्यूब चैनल http://www.youtube.com/ddnews की शुरुआत फरवरी 2013 में की गई थी। डीडी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल के 8 लाख से अधिक (8,73,153) सब्सक्राइबर हैं।

डीडी न्यूज़ मोबाइल एप लोगों को समाचार और समसामयिक मामलों की जानकारी तक सुगमता से पहुंच बनाने में सक्षम बना रहा है। इस एप का नया संस्करण जल्द ही शुरू किया जाएगा। डीडी न्यूज़ तक निम्नलिखित साधनों के माध्यम से भी पहुंच बनाई जा सकती है :

- वेबसाइट
- मोबाइल एप
- यूट्यूब चैनल
- एनआईसी का लाइव कास्ट चैनल : http://webcast.gov.in

{k=h; lekpkj bdkb;k

डीडी न्यूज़ ने बीते वर्षों में देशभर में 31 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों/ब्यूरो स्थापित किए हैं। ये आरएनयू एक दिन में 23 भाषाओं/बोलियों में 235 से अधिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण करते हैं और प्रतिदिन कुल मिलाकर 61 घंटे से अधिक समय तक प्रसारण करते हैं।

o"kZ 2018&19 d nkjku MhMh U;wt dh miyfC/k;k¡ ¼vçSy l vDrwcj] 2018 rd½

डीडी न्यूज़ ने अपने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेटवर्क पर ईजीएसए और विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं (कुल 27 योजनाओं) पर 5,000 से अधिक ग्राउंड रिपोर्ट्स का निर्माण और प्रसारण किया है। 4,800 से अधिक ऐसी कहानियां अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई हैं। इसने 4,200 से अधिक कहानियों को भी अपलोड किया है जो डीडी न्यूज़ वेबसाइट .www.ddnews.gov.in पर अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं।

डीडी न्यूज़ अपने राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ–साथ अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर आयुष्मान भारत और पीएमजेएवाई की सफलता की कहानियों का प्रसारण कर रहा है। एक महीने की अल्पावधि के भीतर ही आयुष्मान भारत योजना के तहत वास्तव में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने वाले असली लाभार्थियों से 100 से अधिक कहानियों को एकत्र किया गया है।

1. अक्तूबर, 2018 से कार्यक्रमों के लिए "लुक एंड फील" के नए सेट के साथ अंग्रेजी और हिंदी मिड डे प्राइम में एक घंटे के शो लॉन्च किए गए।

2. "बदलते भारत पर चर्चा" नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका प्रसारण वीक डे यानी सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10:30 से 11:00 बजे तक किया जाता है। दिन भर के विषय पर एक अन्य विशेष कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 7:30 से 8:00 बजे तक प्रसारित किया जाता है।

3. वीक डे यानी सोमवार से शुक्रवार तक शाम 6.30 से 7.30 बजे तक एक नया शो नेशनवाइड शुरू किया गया है, जिसमें अपने क्षेत्रीय नेटवर्क द्वारा साझा की जाने वाली क्षेत्रीय सामग्री पर विशेष ध्यान दिया गया है।

4. डीडी न्यूज़ ने विशेष कार्यक्रमों– भारत की बदलती तस्वीर (सरकारी योजनाओं की सफलता की कहानियों पर आधारित), वादा निभाया (माननीय प्रधानमंत्री के वादों और उन्हें निभाए जाने पर आधारित), प्रॉमिसेज एंड डिलिवरीज़, रक्षक भारत के और अपने नियमित कार्यक्रमों के अलावा विशेष दर्शकों पर आधारित कार्यक्रम यंग इंडिया@71 काकोरी, बैरकपुर, वेल्लोर, साबरमती आश्रम जैसी जगहों से प्रसारित किया है।

5. खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ द्वारा एशियाई खेलों के पदक विजेताओं के अभिनंदन का डीडी न्यूज़ द्वारा सीधा प्रसारण।

6. केरल में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्यों की व्यापक कवरेज का प्रसारण।

7. डीडी न्यूज़ ने सितंबर 2018 में राष्ट्रीय पोषण माह पर विशेष चर्चा कार्यक्रम "पोषण माह" प्रसारित किया।

8. वैंकूवर में विश्व संस्कृत सम्मेलन और मॉरीशस में विश्व हिंदी सम्मेलन की विशेष और विशिष्ट कवरेज।

9. डीडी न्यूज़ ने 15 सितंबर, 2018 से 2 अक्तूबर, 2018 तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया।

10. जनादेश : – मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना राज्यों में विधानसभा चुनाव डीडी न्यूज़ द्वारा व्यापक रूप से कवर किए गए थे।

11. डीडी न्यूज़ ने 21 जून, 2018 को देहरादून में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 2018 का व्यापक कवरेज किया और योग से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया।

12. डीडी न्यूज़ ने 31 अक्तूबर, 2018 को केवडिया, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अनावरण कार्यक्रम की व्यापक और विशेष कवरेज की और इसे सरदार पटेल को समर्पित किया।

MhMh Hkkjrh

डीडी भारती चैनल कला और संस्कृति को समर्पित है। जनवरी 2002 में आरंभ होने के बाद से ही यह चैनल भारत की सांस्कृतिक विरासत का ऑन–एयर भंडार बन गया है। यह चैनल भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत और नृत्य के स्वरूपों, कला–शिल्प, रंगमंच, भारतीय वास्तुकला, विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों की जीवनियों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं के समृद्ध संग्रहों के जरिए इतिहास, विरासत और आधुनिक संस्कृति को बढ़ावा और संरक्षण दे रहा है।

डीडी भारती अनेक सराहनीय और विख्यात नृत्य (प्रसिद्ध कलाकार, विभिन्न जनजातीय नृत्यों और कला रूपों, नृत्यांजली नृत्य महोत्सव माटी के रंग), संगीत और साहित्य महोत्सवों का सीधा प्रसारण करता आ रहा है। उपर्युक्त अवधि के दौरान इसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के लगभग 250 से अधिक सीधे प्रसारण किए हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल शामिल है। इसमें सार्वजनिक महत्व के ऐसे कार्यक्रम भी शामिल हैं, जिनमें माननीय राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भाग लेते हैं। दीपावली, होली, रक्षाबंधन ईद, बकरीद, विजयदशमी आदि जैसे सभी त्योहारों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

अपनी पहुंच और दर्शकों का आधार बढ़ाने के लिए पूरे भारत में होने वाली घटनाओं का ईएनजी कवरेज को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

डीडी भारती पर इस अवधि के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम :–1 *मौसिकी एक खोज* : उस्ताद सुजात खान द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय संगीत आधारित कार्यक्रम; *उत्तर कथा*: प्रख्यात लेखक श्री नरेश मेहता के उपन्यास पर आधारित धारावाहिक; *गोरा : गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर* के इसी नाम के क्रांतिकारी उपन्यास पर आधारित धारावाहिक; *बूंद और समुद्र* : पद्मभूषण श्री अमृत लाल नागर के उपन्यास पर आधारित और एन. चंद्रा द्वारा निर्देशित धारावाहिक; *संन्यासी* : पं. इला चंद जोशी के उपन्यास पर आधारित धारावाहिक; *टैगोर की कविता* (त्रयोदशी): गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं पर बुद्धदेव गुप्ता द्वारा निर्देशित विशेष फिक्शन कार्यक्रम; *योग विज्ञान* : बाबा रामदेव पर आधारित तथा योग और हमारी पारंपरिक जड़ी–बूटियों के महत्व को दर्शाता है; प्रसिद्ध निर्देशक बिनॉय के. बहल द्वारा *पेंटिंग्स ऑफ इंडिया*; बिनॉय के बहल द्वारा *स्कल्पचर ऑफ इंडिया*; कृष्ण कली शिवानी द्वारा लिखित और अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित; *ये है इंडिया मेरी जान*: सईद मिर्ज़ा द्वारा निर्देशित ट्रैवल शो; *उत्तर रामचरितम*: जी.वी. अय्यर द्वारा निर्देशित संस्कृत धारावाहिक महाकवि *भवभूति*; जी.एस. चन्नी और ज्ञान देव सिंह द्वारा निर्देशित *फ़ोर्ट्स ऑफ इंडिया*; *एक प्रेम कथा*: बासु चटर्जी की लघु प्रेम कहानियों पर शृंखला; *तहरीर*: मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यासों गोदान और निर्मला पर आधारित; *नाच्यो बहुत गोपाल*: पद्मभूषण अमृत लाल नागर के उपन्यास पर धारावाहिक; *मेरा स्टूडियो मेरा मेहमान* : प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट स्वर्गीय सुधीर तैलंग द्वारा *अंतिम शृंखला*; और, *नाद भेद*: भारतीय शास्त्रीय संगीत पर पहला रियलिटी शो; और क्विज प्रोग्राम, *कल्चर–वल्चर*।

इस अवधि के दौरान निर्मित इन हाउस कार्यक्रमों में शामिल हैं: *राग रंग* सुप्रसिद्ध संगीत विशेषज्ञ विजय किचलू द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सराहना कार्यक्रम; अजय टोकस द्वारा 10 कड़ियों वाला *म्यूजिकल एंड प्रोटोकॉल, योगा एंड अष्टांग योगा* नामक एक विशेष कार्यक्रम; *चारों दिशाएं मंजिल को जाएं*, वर्तमान सरकार के चार साल पूरा करने पर कार्यक्रम (ईएनजी रिकॉर्डिंग और स्टूडियो–बेस्ड कार्यक्रम पर आधारित)।

चैनल ने 2 मार्च, 2018 से सप्ताहांत पर भारती क्लासिक्स बैनर के तहत हिंदी फ़ीचर फ़िल्म (एक ब्रेक वाली फ़िल्म) दिखाना शुरू किया है, जिसके परिणामस्वरूप अच्छी टीआरपी मिली है।

माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सांकेतिक भाषा (दिव्यांग दर्शकों के लिए) के साथ प्रसारित किया जाता है। संस्कृत प्रतिलेखन के साथ यह कार्यक्रम का शाम को भी दोबारा प्रसारित किया जाता है।

शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य के प्रचार और प्रसार के लिए डीडी भारती पर टेलीकास्ट के लिए दैनिक स्लॉट्स मौजूद हैं। डीडीके केंद्रों की ओर से भी इस समर्पित स्लॉट के लिए कार्यक्रमों का योगदान किया जाता है।

कोशिश से कामयाबी तक – प्रख्यात बॉलीवुड सितारों, संगीतकारों, गायकों आदि के एक साक्षात्कार पर आधारित एक विशेष शृंखला।

Hkfo"; d fy, dk;uhfr

डीडी भारती देशभर के सांस्कृतिक/सामाजिक/साहित्य आयोजनों को कवर और प्रदर्शित करने की योजना बना रहा है। यह सांस्कृतिक संस्थानों के पास उपलब्ध सॉफ़्टवेयर की क्षमता का पता लगाने और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों सहित हमारे अपार अभिलेखीय संसाधनों से लाभ उठाने और चयन करने की भी कोशिश कर रहा है।

चैनल पूरे भारत में ईएनजी/लाइव कवरेज बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसके अलावा यह सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी उपस्थिति बढ़ाने की योजना बना रहा है। डीडी भारती उत्कृष्ट कार्यक्रम निःशुल्क प्राप्त करने और देश के नए कलाकारों और नई प्रतिभाओं को तैयार करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ साझेदारियां करने की योजना बना रहा है।

MhMh mnw

डीडी उर्दू 15 अगस्त, 2006 को दूरदर्शन के उर्दू चैनल के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें प्रतिदिन आठ घंटे का प्रसारण होता था। बाद में, 14 नवंबर 2007 से चैनल के चौबीसों घंटे के प्रसारण की शुरुआत हो गई। इस समृद्ध भाषा की महान सांस्कृतिक विरासत और साहित्यिक पहलू के संरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए एक विरासत चैनल के रूप में परिकल्पित डीडी उर्दू देश के उर्दू चैनलों में से सबसे अधिक देखा जाने वाला चैनल है। यह चैनल प्रतिदिन 10 समाचार बुलेटिनों का प्रसारण करता है।

डीडी उर्दू अनेक इन–हाउस कार्यक्रमों का निर्माण कर रहा है, उदाहरण के लिए स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम–सेहत की बात, फिटनेस प्रोग्राम फिटनेस प्लस, फ़िल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम, यादों के दरीचे से और मुशायरे के अलावा टीवी रिपोर्ट्स और त्योहारों व वर्षगाँठ पर विशेष कार्यक्रम। डीडी उर्दू ने गणतंत्र दिवस, माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, मन की बात और अन्य कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण करता

नई दिल्ली में 10 सितंबर, 2018 को दूरदर्शन की 9 डीएसएनजी वैन्स के फ्लैग–ऑफ आयोजन के अवसर पर युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। साथ में हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे, प्रसार भारती के चेयरमैन डॉ. ए. सूर्य प्रकाश एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी गण

है। डीडी उर्दू हर बुधवार और शुक्रवार को फ़ीचर फ़िल्मों का प्रसारण करता है।

हाल के प्रमुख आयोजनों में स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण शामिल हैं जैसे कि *दम मस्त कलंदर,* रूहानी बहनों और अन्य प्रमुख गायकों के सूफ़ी *संगीत सम्मेलन* की श्रृंखला; सेवा दिवस पर विशेष कार्यक्रम *रोशन मुस्तक़बिल,* मोहर्रम, ईद–उल–फितर, ईद–उल–अज़हा, दशहरा, दिवाली आदि पर कार्यक्रम, एकता दिवस पर *कौमी यक्जहती और सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद* आदि के कार्यक्रम प्रसारित किए गए। डीडी उर्दू सभी प्रमुख त्योहारों और उर्दू हस्तियों पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण भी करता है। एक फिटनेस शो फिटनेस प्लस भी दिसंबर 2018 में टेलीकास्ट के लिए तैयार है।

डीडी उर्दू ने सभी सरकारी योजनाओं और गतिविधियों जैसे 'स्वच्छता पखवाड़ा', 'पराक्रम पर्व', 'गंगा मिशन', ' कौमी एकता सप्ताह' तक का अवलोकन और प्रचार किया।

डीडी उर्दू नये इन–हाउस कार्यक्रम जैसे– महिलाओं पर साप्ताहिक कार्यक्रम, कुकरी शो, संगीत और महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के साक्षात्कार पर आधारित कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है

MhMh % bfM;k

दूरदर्शन ने 14 मार्च, 1995 को अपना अंतरराष्ट्रीय चैनल प्रारंभ करके दुनिया के लिए अपनी खिड़की खोल दीं। पहले इस चैनल का नाम 'डीडी वर्ल्ड' रखा गया, जिसे बाद में 2002 में बदल कर 'डीडी इंडिया' कर दिया गया। आरंभ होने के बाद से डीडी इंडिया संगीत, नृत्य, कला और शिल्प, इतिहास, विरासत, विज्ञान, ऊर्जा, पर्यावरण, परंपरा, त्योहारों तथा अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए भारत के व्यक्तित्वों के लिए पूर्व निर्धारित स्लॉट्स सहित अपने समृद्ध संग्रह से हिंदी/अंग्रेजी आधारित अभिलेखीय और नए कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। अब यह चैनल पूरी तरह से इंग्लिश न्यूज़ और करंट अफेयर्स चैनल बनने की राह पर है और वर्तमान में डीडी न्यूज़ और आरएसटीवी आदि की सहायता से डीडी इंडिया 13 घंटे के अंग्रेजी न्यूज़ बुलेटिन और अंग्रेजी भाषा में बनाए गए 11 घंटे के सूचना–आधारित वृत्तचित्रों का प्रसारण करता है। इसके अलावा, डीडी इंडिया सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और माननीय प्रधानमंत्री के राष्ट्र के साथ–साथ दुनिया के नाम संबोधनों का सीधा प्रसारण कर रहा है। इस चैनल ने इस वर्ष में 175 से अधिक लाइव टेलिकास्ट किए हैं। यह चैनल संगीत वीडियो और लघु वीडियो आदि के माध्यम से सरकार की सभी सार्वजनिक कल्याण योजनाओं को भी प्रचारित कर रहा है।

भविष्य में, डीडी इंडिया नेशन फर्स्ट, हेल्थ फॉर यू, स्पेशल ब्रेकफास्ट शो, न्यूज़ ऑफ द आवर, बिजनेस मॉर्निंग, न्यू इंडिया, माय इनवेस्टमेंट्स, वाइड स्पेक्ट्रम, प्राइम टाइम इंडिया और स्पोर्ट्स बज़ आदि जैसे अनेक नए समाचारों और करंट अफेयर्स कार्यक्रमों/लाइव शो का निर्माण करेगा।

वर्तमान में डीडी इंडिया के पास निश्चित निर्माण स्टूडियो और उचित मानव संसाधन नहीं है। लेकिन सीमित मानवशक्ति के साथ इस चैनल को अच्छी टीआरपी रिपोर्ट्स मिल रही हैं (जैसा कि बीएआरसी से प्राप्त किया गया है) और एक बार अपनी सुविधाएं प्राप्त करते ही यह चैनल शीर्ष सूचना और सामग्री–आधारित चैनलों में से एक बनने का वादा करता है।

MhMh LikV'kl

2018–2019 डीडी स्पोर्ट्स के लिए बुनियादी परिवर्तन का साल था। इस वर्ष चैनल को उद्योग मानकों के अनुरूप लाने के लिए कई उपाय किए गए। ज्यादा बल राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों से जुड़ी विशेष गतिविधियों के बेहतर प्रदर्शन, देशभर में निचले स्तर पर होने वाले खेल आयोजनों के समग्र कवरेज और नए दौर के सोशल और डिजिटल मीडिया के साथ चैनल के एकीकरण पर दिया गया। चैनल की अब खेलों की विधा में विलक्षण और विशिष्ट पहचान है, जहां एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसे विविध खेल आयोजनों से लेकर भारतीय भागीदारी वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच तक खेल गतिविधियां कवर की जाती हैं। पूर्वोत्तर में खेल गतिविधियों पर आधारित बुलेटिन डीडी न्यूज़ में नियमित खेल बुलेटिनों के साथ सहयोगी खेल के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। डीडी स्पोर्ट्स अब खेल विधा में परिभाषित उद्देश्य के साथ प्रमुख चैनल के रूप में उभर रहा है।

2 uokUes"kh igy

1. U;w ,t ehfM;k ds lkFk fMftVy ,dhdj.k% चैनल ने नए दौर के मीडिया के परिदृश्य में अपना विस्तार करने के निरंतर प्रयास किए हैं। इनमें यू–ट्यूब और फेस बुक पर स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी की लाइव स्ट्रीमिंग और फेसबुक और ट्विटर पर नियमित स्पोर्ट्स अपडेट शामिल हैं।

2. . n'kHkj d [ky ?kVukØe % पिछले कुछ वर्षों से डीडी स्पोर्ट्स, जमीनी स्तर पर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के मामले में वर्षों से सबसे अग्रणी रहा है। इस पृष्ठभूमि के बीच, चैनल ने पूर्वोत्तर से एक साप्ताहिक बुलेटिन शुरू किया है जिसमें इस क्षेत्र की खेल गतिविधियों का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। इनके अलावा, चैनल डीडी न्यूज़ के साथ समन्वय में अंग्रेजी और हिंदी में खेल बुलेटिनों को प्रसारित करता है।

3- iLrfr dh vR;k/kfud 'kyh % राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों के पूर्व–शो, मध्यान्ह–शो और आयोजन के बाद के शो की अत्याधुनिक प्रस्तुति शैली को इस साल पहले से बेहतर और जीवंत बनाया गया है। इन स्टूडियो से होने वाली शो की प्रस्तुति को नवीनतम ग्राफिक्स के साथ पूर्णता प्रदान की जाती है जो किसी भी खेल चैनल के लिए महत्वपूर्ण हैं।

4- m|kx d loJ"B ,dj@fo'k"kK@lEekfur vfrfFk % इन कार्यक्रमों के एंकर/विशेषज्ञ/ टिप्पणीकार और खेल हस्तियों का प्रोफाइल इस साल काफी बेहतर किया गया है। अपनी इस विशेषता में, डीडी स्पोर्ट्स अब उद्योग के सर्वश्रेष्ठ चैनलों को प्रतिस्पर्धा दे रहा है। डीडी स्पोर्ट्स के कार्यक्रमों इस वर्ष में शामिल होने वाली कुछ प्रमुख खेल हस्तियों में– क्रिकेट जगत के श्री के. श्रीकांत, श्री मोहिंदर अमरनाथ, श्री दिलीप वेंगसरकर, श्री मनोज प्रभाकर, श्री किरण मोरे, श्री वेंकटेश प्रसाद और श्री गैरी कर्स्टन, फुटबॉल में श्री बाइचुंग भूटिया और श्री रेंडी सिंह, बैडमिंटन में श्री पुलेला गोपीचंद, सुश्री पीवी सिंधु और सुश्री अश्विनी पोनप्पा, कुश्ती में श्री बजरंग पुनिया, सुश्री दिव्या काकरान, हिना सिद्धू आदि, जिमनास्टिक्स में दीपा करमाकर और शतरंज में विश्वनाथन आनंद का नाम शामिल हैं। इसी तरह, खेल जगत के सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स एंकर और व्यक्तियों ने डीडी स्पोर्ट्स के कार्यक्रमों में भाग लिया है। ये हस्तियां न केवल खेल की घटनाओं पर अपनी अमूल्य राय देती हैं, बल्कि अपने उन अनुभवों को भी साझा करते हैं, जिनकी बदौलत उन्होंने कामयाबी हासिल करने में मदद मिली है जो उन्हें शिखर पैमाने पर लाने में मदद करते हैं। इससे डीडी स्पोर्ट्स की सामग्री की गुणवत्ता बढ़ती है।

5. MhMh LikVl d fo'k"k dk;Øe %– डीडी स्पोर्ट्स ने इस वर्ष विशेष अवसरों के लिए विशेष कार्यक्रमों की परिकल्पना और आयोजन किया है। इनमें एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं के कार्यक्रम शामिल हैं। चैनल ने क्रिकेट टेल्स नामक विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किया, जो– क्रिकेट कोचिंग और क्रिकेट का एक अनोखा संगम था। इसी तरह, 'हौसलों की उड़ान' कार्यक्रम में– सुश्री मैरी कॉम आदि सहित खेल जगत की हस्तियों ने चैंपियन बनने के लिए अपने विचारों को साझा किया।।

6- MhMh LikVl ij vkbih,y %–विश्व क्रिकेट की सफलतम क्रिकेट लीगों में से एक–इंडियन प्रीमियर लीग भी पहली बार डीडी स्पोर्ट्स पर प्रसारित की गई। कुल 12 मैचों को विलंबित या डिफर्ड लाइव दिखाया गया, जबकि बाकी मैचों को एक घंटे के हाईलाइट के रूप में दिखाया गया।

7- MhMh LikVl ij [kyk bfM;k – चैनल ने प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैचों का अविराम सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर प्रसारित किया गया।

3- MhMh LikVl fo'k"k dk;Øe

1- gkl yk dh mMku

Øe-l-	fnukd	le;	dfM;k
1	11.05.2018	रात 09:00 बजे	साक्षी मलिक
2	18.05.2018	रात 09:00 बजे	दीपा कर्माकर
3	25.05.2018	शाम 06:00 बजे	एम सी मैरीकॉम
4	01.06.2015	रात 09:00 बजे	भाईचुंग भूटिया
5	08.06.2018	रात 09:00 बजे	देवेंद्र झाझरिया
6	15.06.2018	रात 09:00 बजे	अजीत पाल सिंह
7	22.06.2018	रात 09:00 बजे	गीत सेठी

2- ge fQV rk bfM;k fQV & युवाओं में फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों के आधार पर।

3- fo'k"k lk{kkRdkjk ij vk/kkfjr 'kk

Øe-l-	fnukd	le;	dfM;k
1	23.04.2018	रात 09:00 बजे	किंग ऑफ 64 स्क्वेयर्स (विश्वनाथन आनंद)
2	04.05.2018	रात 09:00 बजे	दंगल क्वीन (दिव्या काकरान)
3	19.05.2018	रात 09:00 बजे	पिस्टल क्वीन (हिना सिद्धू)
4	26.06.2018	रात 09:00 बजे	गुरु गैरी (गैरी कर्स्टन)
5	07.07.2018	रात 09:00 बजे	बजरंगी पहलवान (बजरंग पुनिया)
6	27.07.2018	रात 09:00 बजे	एवरेस्ट गर्ल (शिवांगी पाठक)

4- fØdV VYl – विशेष रूप से क्रिकेट पर शो जिसमें कोचिंग टिप्स को क्रिकेट जगत की विख्यात हस्तियों के किस्सों के साथ जोड़ा गया।

5- çh vkÃih,y 'kk – जिसमें खेलों से जुड़े विभिन्न हितधारक इसे देश के खेल प्रेमियों के लिए और अधिक आकर्षक और प्रासंगिक बनाने में संलग्न रहे।

6- djV vQ;l 'kk & iokÿkj

MhMh U;t LikV'l cyfVu	lk;a 05:30–06:00	हिंदी	26.4.2018
	lk;a 07:00–07:30	अंग्रेजी	26.4.2018
vkj,lVhoh QVcky 'kk	lk;a 07:00–07:30	अंग्रेजी	21.06.2018

7- jk"Vh; egRo d vk;kstuk dh dojt

Øe-l-	vk;ktu	fnukd	le;
1	भारत का दक्षिण अफ्रीका दौरा	01/2, 04/2, 07/2, 10/2, 13/2, 16/2, 18/2	सायं 04:00 बजे से
2	निधास ट्रॉफी	06/3, 08/3, 12/3, 14/3, 18/3	सायं 06:00 बजे से
3	भारत का आयरलैंड दौरा	27/6 एवं 29/6	सायं 07:30 बजे से
4	भारत का इंग्लैंड दौरा	3/7, 6/7,8/7 एवं 12/7, 14/7, 17/7	रात्रि 09:00 बजे से और सांय 04:00 बजे से
5	वेस्टइंडीज का भारत दौरा	21/10, 24/10, 27/10, 29/10, 01/11, 04/11, 6/11	सायं 06:00 बजे से
6	भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा	21/11, 23/11, 25/11	दोपहर 01:20 बजे से
7	ओडिशा हॉकी विश्व कप	28 नवंबर–16 दिसंबर	सायं 05:00 बजे से
8	राष्ट्रमंडल खेल	04/04/2018–15/04/2018	प्रातः 04:00 बजे से – सायं 06:00 बजे तक
9	चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी	23/06/2018	सायं 05:00 बजे से
		24/06/2018	अपराह्न 03:00 बजे से
		27/06/2018	सायं 06:00 बजे से
		28/06/2018	रात्रि 08:00 बजे से
		30/06/2018	सायं 07:00 बजे से
		01/07/2018	सायं 07:00 बजे से

Øe-l-	vk;kt u	fnukd	l e;
10	फीफा विश्व कप 2018	14 / 06 / 2018	रात्रि 08:25 बजे से
		10 / 07 / 2018	रात्रि 11:25 बजे से
		11 / 07 / 2018	रात्रि 11:25 बजे से
		15 / 07 / 2018	रात्रि 08:25 बजे से
11	महिला हॉकी विश्व कप	21 / 7 / 2018	सायं 06:30 बजे से
		26 / 07 / 2018	सायं 06:30 बजे से
		29 / 07 / 2018	रात्रि 09:30 बजे से
		31 / 07 / 2018	रात्रि 10:30 से
12	यूएस ओपन	08 / 09 / 2018	देर रात 01:30 बजे से
		09 / 09 / 2018	देर रात 01:.30 बजे से
13	ऑस्ट्रेलिया ओपन	27 / 01 / 2018	दोपहर 01:30 बजे से
		28 / 01 / 2018	दोपहर 01:30 बजे से
14	विंबलंडन	14 / 7 / 2018	सायं 06:30 बजे से
		15 / 7 / 2018	सायं 06:30 बजे से
15	फ्रेंच ओपन	09 / 06 / 2018	सायं 06:.30 बजे से
		10 / 06 / 2018	सायं 06:30 बजे से

8- ?kjyw [ky vk;kt uk dh dojt

Øe-l-	fnukd	l e;	vk;kt u
1	18 / 03 / 2018–27 / 03 / 2018	02:30 रात्रि 10:30 तक	छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग
2	23 / 7 / 2018 एवं 29 / 07 / 2018	सायं 05:00 बजे से. 07:.00 तक	विश्व जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप
3	15 / 07 / 2018	प्रातः 08:00–10:00बजे तक	एशियाई खेल टॉर्च रिले
4	26 / 11 / 2018–02 / 12 / 2018		बैडमिंटन टाटा ओपन

MhMh % fdlku

दूरदर्शन के स्वामित्व में 26 मई, 2015 को लॉन्च किया गया किसान टीवी किसानों और विशाल कृषि क्षेत्र के लिए विशेष रूप से समर्पित 24 घंटे का चैनल शुरू करने की दिशा में लोक प्रसारणकर्ता की प्रथम पहल है। किसानों को नई तकनीक, फसल सुरक्षा, उर्वरक, बीज, सिंचाई और जल संरक्षण, फसल चयन, खेत मशीनीकरण, कृषि व्यवसाय तथा अन्य मामलों के अलावा विशाल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन मुर्गी पालन, डेयरी और पशुपालन, बागवानी और जैविक खेती की जानकारी सहित विभिन्न कृषि और कृषि संबंधी मुद्दों पर वास्तविक समय पर जानकारी देता है। इसे खेती के लिए महत्वपूर्ण सभी चीजों – जल संरक्षण और जैविक खेती से लेकर सरकारी कृषि कार्यक्रमों के माध्यम से ऋण कैसे प्राप्त करें तक को दर्शाने के लिए तैयार किया गया है।

यह चैनल किसानों को कृषि तकनीकों के नए नवाचारों से अवगत कराने के लिए वृत्तचित्रों का भी प्रसारण करता है, इसके अलावा किसानों की दिलचस्पी वाले रियलिटी और कुकरी शो की भी मेज़बानी करता है तथा मौसम की जानकारियां भी नियमित रूप से देता है।

चैनल का आईएमडी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ गठजोड़ है। अधिकांश कार्यक्रम इन–हाउस में निर्मित किए जाते हैं।

किसान चैनल द्वारा दैनिक आधार पर औसत सात घंटे की नवीनतम सामग्री का निर्माण किया जाता है। चैनल ने

सभी डीडीके और पीजीएफ को डीडी किसान के कार्यक्रमों निर्माण करने से जोड़कर दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क को जोश से भर दिया है। चैनल का प्रचार और जागरुकता फैलाना। निम्नलिखित कदमों के माध्यम से गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने का निरंतर और सतत प्रयास किया जा रहा है:

- सभी कार्यक्रमों की समीक्षा की जा रही है और कार्यक्रम के विशिष्ट प्रारूप लागू किए गए हैं।
- कार्यक्रम को विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के साथ इसे और अधिक रोचक बनाने के लिए कार्यक्रम को खंडों में विभाजित किया गया है।
- कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न और पृथक ग्राफिक्स पेश किए गए हैं।
- अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य के लिए प्रत्येक कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से इनपुट

14 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में डीडी किसान पर रियलिटी शो 'महिला किसान अवार्ड्स 'के शुभारंभ अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे, अध्यक्ष प्रसार भारती, डॉ. ए. सूर्य प्रकाश, अपर सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सुश्री जयश्री मुखर्जी, सीईओ, प्रसार भारती, श्री शशि एस. वेम्पती महानिदेशक, दूरदर्शन, सुश्री सुप्रिया साहू, महानिदेशक, एनएसडी–आकाशवाणी, सुश्री ईरा जोशी एवं अन्य गणमान्य अतिथि

निम्नलिखित के माध्यम से जागरुकता पैदा करने के लिए कई पहल की गई हैं:

- दूरदर्शन नेटवर्क का क्रॉस चैनल प्रचार।
- सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय उपस्थिति।
- इंटरएक्टिव और क्षेत्र आधारित कार्यक्रम
  इस अवधि के दौरान की गई नई पहल :
- मौसम ख़बर – लाइव अपडेटेड बुलेटिन सुबह, दोपहर और शाम के टाइम बैंड में शुरू किया गया है।
- कृषि और संबद्ध गतिविधियों में सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करने के लिए यात्रा वृत्तांत प्रारूप में 'ये है मेरा इंडिया' कार्यक्रम की एक श्रृंखला।
- एक मेगा रियलिटी शो, डीडी महिला किसान पुरस्कार का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल करते हुए 114 महिला किसानों को आईसीएआर द्वारा नामित किया गया है। यह 56 एपिसोड की श्रृंखला होगी। बाद में ग्रैंड फिनाले होगा।
- निर्मित और टेलीकास्ट किए गए कुछ विशेष कार्यक्रमों में किसानों पर फोकस करता केंद्रीय बजट, सरकार के चार साल, विजय दिवस का उत्सव आदि शामिल हैं।

{k=h; Hkk"kkvk d mixg puy

MhMh % lg;kæh

डीडी सह्याद्री 24 x 7 क्षेत्रीय मराठी चैनल है जिसमें सुबह 6 बजे से 9 बजे (रविवार को छोड़कर) और अपराह्न 3 बजे से सायं 7 बजे (सभी दिन) तक स्थलीय समर्थन प्राप्त है। यह चैनल 2 अक्तूबर, 1972 को चालू किया गया था और मराठी में क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवा 15 अगस्त, 1994 से शुरू

हुई थी। 5 अप्रैल, 2000 को इसने चौबीसों घंटे की सेवा शुरू की। आज, डीडी सह्याद्री पांच स्टूडियो और एचडी ट्रांसमिशन से लैस है।

डीडी सह्याद्री महाराष्ट्र में उपलब्ध सभी मराठी टीवी चैनलों के बीच एकमात्र लोक सेवा प्रसारक है। यह 17 मराठी चैनलों में 9वें स्थान पर है और इसके मराठी समाचार बातंया (बीएआरसी की रेटिंग्स के अनुसार) मराठी न्यूज़ चैनलों की रैंकिंग में शीर्ष पर है। 18.10.2018 से पूवाह्न 11-00 ct dk 30 feuV dh vofèk dk lekpkj cqysfVu का शुरू किया गया था।

vofèk dk nkSjku egRoiw.kZ dk;ZØe dk çlkj.k

डीडीके मुंबई द्वारा 24 अप्रैल, 2018 को डीडीके मुंबई द्वारा एक लाइव रोड शो आयोजित किया गया था, ताकि "डीडी फ्री डिश" सेवा और डिजिटल स्थलीय के प्रसारण को लोकप्रिय बनाया जा सके।

- सह्याद्री कृषि सम्मान सोहला, 2018 का 11वां सीजन। पुरस्कार समारोह 8 जून, 2018 को आयोजित किया गया।
- डीडी सह्याद्री पर एक नया इनहाउस कार्यक्रम ÞueLdkj eMyhÞ 18.10.2018 से शुरू किया गया।
- विशेष कार्यक्रम onu x.k'k 13 सितंबर, 2018 से 23 सितंबर, 2018 तक प्रसारित किया गया।
- x.kifr rk l[kdrk rk n[kgrk पर विशेष टीवी रिपोर्ट 13 सितंबर, 2018 और 23 सितंबर, 2018 को प्रसारित की गई थी।
- Þ62ok èkEepØ çorZu fnuÞ 18 अक्तूबर, 2018 को नागपुर से प्रसारित किया गया था।
- njn'kZu lákæh के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 2 अक्तूबर, 2018 को एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया गया।

MhMh % fxjukj

गुजराती में उपग्रह क्षेत्रीय भाषा चैनल डीडी–11, दिल्ली से अपलिंकिंग के माध्यम से 1 अक्तूबर, 1993 को प्रारंभ हुआ और इसी सेवा ने 15 अगस्त, 1994 को स्थानीय स्तर से अपलिंकिंग प्रारंभ कर दी। क्षेत्रीय उपग्रह भाषा सेवा पर 01.05.2000 से चौबीस घंटे का प्रसारण आरंभ हो गया और डीडी गिरनार 02.10.2007 से जाना–पहचाना ब्रांड बन गया।

अप्रैल, 2018 से वर्तमान तक की अवधि के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

- गुजरात स्थापना दिवस के अवसर पर लाइव कार्यक्रम – रंग छे गुजरात 1 मई, 2018 को प्रसारित।
- केंद्र सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम 16 मई, 19 मई, 21 मई, 23 मई, 25 मई और 31 मई, 2018 को प्रसारित किया गया।
- योग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण – 21 जून, 2018 को विश्व योग दिवस के अवसर पर अहमदाबाद में कॉम्बिनेशन ऑफ योग, भरतनाट्यम एंड कलरीपेटी।
- 14 जुलाई, 2018 को अहमदाबाद से भगवान जगन्नाथ यात्रा का सीधा प्रसारण।
- 19 अगस्त, 2018 से 22 अगस्त, 2018 तक संस्मरणों भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी पर कार्यक्रम।
- 3 सितंबर, 2018 को द्वारका से जन्माष्टमी महोत्सव 'वाहलो मारो अवाशे आथम नी अधाराते' का सीधा प्रसारण।
- 28 सितंबर, 2018 को पराक्रम पर्व(वृत्तचित्र) पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण।
- 2 अक्तूबर, 2018 को गांधी जयंती के अवसर पर साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से सर्व धर्म प्रार्थना का सीधा प्रसारण।
- नवरात्रि उत्सव 2018 पर कार्यक्रमों– 'गरबो रामातो जय' का प्रसारण 10 अक्तूबर, 2018 से 19 अक्तूबर, 2018 तक।
- 23 अक्तूबर, 2018 को सरदार पटेल की जयंती पर–एकता व शिल्पी सरदार का सीधा प्रसारण।
- 31 अक्तूबर, 2018 को केवडिया, नर्मदा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा फूलों की घाटी टेंट सिटी का उद्घाटन, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण।

दिसंबर 2018 से मार्च 2019 के दौरान प्रस्तावित टेलीकास्ट

- 12 जनवरी, 2019 को पतंग महोत्सव और वाइब्रेंट गुजरात का सीधा प्रसारण।
- 26 जनवरी, 2019 को राज्य के विभिन्न जिलों में गणतंत्र दिवस समारोह पर टीवी रिपोर्ट।

दूरदर्शन द्वारा योग दिवस की कवरेज

- 4 फरवरी, 2019 को सोमनाथ, जूनागढ़ और वडनगर से शिवरात्रि महोत्सव का सीधा प्रसारण।
- 21 मार्च, 2019 को होली महोत्सव के अवसर पर संगीत समारोह का प्रसारण।

MhMh % ikf/kxbZ

क्षेत्रीय भाषा का 'तमिल उपग्रह चैनल–पोधिगई 15 जनवरी, 2001 से 24 घंटे के प्रसारण के साथ प्रारंभ हुआ।

इस अवधि के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

- चेन्नई में डिफेंस एक्स्पो 2018 का उद्घाटन – 12 अप्रैल, 2018।
- 14 अप्रैल, 2018 को डॉ. बी. आर. अंबेडकर की जयंती और तमिल नव वर्ष के संबंध में विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया।
- 21 जून, 2018 को इंटरनेशनल योगा डे एंड योगा पब्लिक डेमोंस्ट्रेशन का एफआरआई, देहरादून से सीधा प्रसारण।
- तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि का अंतिम संस्कार– 8 अगस्त, 2018।
- केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम– 7 अगस्त, 2018, 14 अगस्त, 2018, 21 अगस्त, 2018 और 28 अगस्त, 2018।
- विनायक चतुर्थी के संबंध में 13 सितंबर, 2018 को विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया गया।
- देशभक्ति की फ़ीचर फ़िल्म– आई लव इंडिया का 29 सितंबर, 2018 को प्रसारण।

MhMh % ;nkfxjh

संयुक्त आंध्र प्रदेश के दो राज्यों में विभाजित होने के बाद डीडी सप्तगिरि चैनल को हैदराबाद में डीडी–यदागिरी चैनल का नाम दिया गया और उसने 27 सितंबर, 2014 से कार्य करना शुरू कर दिया।

इस अवधि के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

- 7 अप्रैल, 2018 और 5 मई, 2018 को "अमरनाथ यात्रा" पर विशेष वृत्तचित्र का प्रसारण।
- 13 अप्रैल, 2018 को डॉ. अंबेडकर पर विशेष तेलुगू फ़ीचर फ़िल्म का प्रसारण।
- 26 अप्रैल, 2018 को एचएमडीए ग्राउंड से आईपीएल –2018 पर रोड शो का सीधा प्रसारण।
- केंद्र सरकार की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर मई, 2018 में विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण।
- 11 जून, 2018 को योग पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण।
- 16 अगस्त, 2018 को स्वतंत्रता दिवस पर विशेष युवा मंच का प्रसारण – मी वेदिका का प्रसारण।
- 10 से 18 अक्तूबर, 2018 तक तिरुमला से श्रीवारी नवरात्रि ब्रह्मोत्सवालु का सीधा प्रसारण।
- 10 से 12 अक्तूबर, 2018 तक बाथुकम्मा विशेष मन माता मन पाता का प्रसारण।
- 19 अक्तूबर, 2018 को मैसूर दशहरा जुलूस (जंबो सवारी) का सीधा प्रसारण।
- 28 अक्तूबर, 2018 को दूरदर्शन केंद्र, हैदराबाद की 41वीं वर्षगांठ "नवरसा झारी– 2018"।
- 31 अक्तूबर, 2018 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर फ़ीचर फ़िल्म का प्रसारण।

MhMh % lIrfxfj

डीडी सप्तगिरि 27 सितंबर, 2014 को आंध्र प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया।

इस अवधि के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

- कुरनूल में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन – 2018, 3 अप्रैल, 2018 को प्रसारण।
- बुद्ध पूर्णिमा पर बैले–गौतम बुद्धा का 30 अप्रैल, 2018 को प्रसारण।
- 2 मई, 2018 को द्वारका तिरुमला में तिरुकल्याणोत्सवम का प्रसारण।
- केंद्र सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 26 मई, 2018 को टॉकथॉन प्रगति पदम लो नालुगु येलु का प्रसारण।
- 21 जून, 2018 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस "दत्त क्रिया योग" पर विशेष कार्यक्रम।
- 15 अगस्त, 2018 को जन्माष्टमी का सीधा प्रसारण।
- 29 सितंबर, 2018 को कार्यक्रम ना देसम भारता देसम और वी द सोल्जर्स का प्रसारण।
- इंद्रा कीलाद्री, विजयवाड़ा में 10 अक्तूबर से 20 अक्तूबर, 2018 तक आयोजित दशहरा उत्सवलु का प्रसारण।
- 31 अक्तूबर, 2018 को सरदार पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस पर विशेष कार्यक्रम उक्कू मानुषी की इक्याठा निवाली का प्रसारण।
- 7 नवंबर, 2018 को विशेष कार्यक्रम मन दीपावली का प्रसारण।

MhMh % ckXyk

20 अगस्त, 1992 को शुरू किया गया डीडी बांग्ला 1 जनवरी, 2000 से 24 घंटे का चैनल बन गया। डीडी बांग्ला बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डीडीके, कोलकाता का अप्रैल, 2018 से अक्तूबर, 2018 की अवधि का शुद्ध राजस्व 1,35,46,168 रुपये रहा।

इस अवधि के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

- 15 अप्रैल, 2018 को बंगाली नववर्ष के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम स्वगाता – 1425 का प्रसारण किया गया।
- 2 मई, 2018 को अपराजितो सत्यजीत नामक वृत्तचित्र का प्रसारण।
- 9 मई, 2018 को रवीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कवि प्रणामोन का सीधा प्रसारण किया गया।
- वर्तमान केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर 15 मई, 2018 को कार्यक्रम का प्रसारण।
- 25 मई, 2018 को शांति निकेतन में विश्व भारती दीक्षांत समारोह और बांग्लादेश भवन के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण किया गया।

दूरदर्शन में स्टूडियो के पैनल की एक झलक

- 21 जून, 2018 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम "योगासने महाध्याने" का प्रसारण।
- 20 जुलाई, 2018 को खड़गपुर से आईआईटी खड़गपुर के 64वें दीक्षांत समारोह का सीधा प्रसारण।
- 3 अक्तूबर, 2018 से 12 अक्तूबर, 2018 तक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला पुजो आसछे का प्रसारण।
- रामकृष्ण मठ, बेलूर और दुर्गा पूजा परिक्रमा से 15 अक्तूबर, 2018 से 19 अक्तूबर, 2018 तक अलग–अलग टाइम स्लॉट में दुर्गा पूजा समारोह का सीधा प्रसारण।
- 17 अक्तूबर, 2018 से 21 अक्तूबर, 2018 तक विभिन्न केंद्रों के योगदान ईबार पूजोय भारत दर्शन।
- 6 नवंबर, 2018 को दक्षिणेश्वर मंदिर से श्यामा पूजा का सीधा प्रसारण।
- बोलपुर, शांतिनिकेतन से 23 दिसंबर, 2018 को "पौष उत्सव" का सीधा प्रसारण।
- 31 दिसंबर, 2018 को नए साल की पूर्व संध्या पर विशेष कार्यक्रम।

जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 के दौरान प्रसारित होने वाले कार्यक्रम :

- जनवरी 2019 में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण।
- जनवरी, 2019 में कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला –2017 के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण।
- जनवरी, 2019 में "गंगासागर मेला" पर कार्यक्रम का प्रसारण।
- मार्च, 2019 में बसंत उत्सव पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण।

MhMh % i¡tkch

डीडी पंजाबी एक 24 घंटे का पंजाबी चैनल है, जिसे उपग्रह जीसैट–17 के माध्यम से भारत और अन्य देशों में व्यापक रूप से देखा जाता है। डीडी पंजाबी चैनल उपग्रह जीसैट–15 पर डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है और इसे पूरी दुनिया में इंटरनेट के माध्यम से देखा जा सकता है।

इस अवधि के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

- 14 अप्रैल, 2018 को वैसाखी पर विशेष कार्यक्रम "मेला वैसाखी दा" प्रसारित किया गया।
- 27 अप्रैल, 2018 को "सुर सम्राट– ग्रैंड फिनाले" का सीधा प्रसारण।
- 14 जून, 2018 को केंद्रीय मंत्री श्रीमती "हरसिमरत कौर बादल, के साथ लाइव "रूबरू" का प्रसारण।
- फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून से 21 जून, 2018 को चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण।
- डीडी पंजाबी की वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम जश्न–ए–शाम का 5 अगस्त, 2018 को सीधा प्रसारण।
- 26 अगस्त, 2018 को विशेष कार्यक्रम तेरी मेरी तू–तू मैं मैं (कॉमेडी) का प्रसारण किया गया।
- 22 सितंबर, 2018 को कुकरी रियलिटी शो मास्टर शेफ पंजाबी का प्रसारण किया गया।
- 23 सितंबर, 2018 को बानी गुरु गुरु है बानी का सीधा प्रसारण।

MhMh % d'khj

डीडी–कशीर चैनल 26 जनवरी, 2000 को लॉन्च किया गया था, जिसे बाद में 15 मार्च, 2003 से 24 घंटे के चैनल में परिवर्तित कर दिया गया। चैनल राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा बोली जा रही 12 अलग–अलग भाषाओं/बोलियों में कार्यक्रमों का निर्माण कर रहा है। चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का उपयोग डीडी–कशीर के सभी कार्यक्रमों और इंटरैक्टिव शो की लाइव स्ट्रीमिंग को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। यह चैनल डीडी–किसान में भी योगदान दे रहा है। डीडी कश्मीर क्षेत्रीय सेवा के लिए नया लोगो पेश किया गया है। 23 जुलाई, 2018 से दैनिक आधार पर फ़ीचर फ़िल्मों का प्रसारण शुरू किया गया है। चैनल की व्यावसायिक आमदनी (अक्तूबर, 2018 तक) 50,00,000रु. है। डीडी कशीर नियमित आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा चिंहित सीपीजी कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है।

2018–19 के दौरान प्रमुख पहल और उपलब्धियां

- "गली गली सिम सिम" कार्यक्रम का कश्मीरी संस्करण शुरू किया गया है।
- राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की जम्मू–कश्मीर यात्रा का प्रसारण।
- रमज़ान के पवित्र महीने में माह–ए–रहमत, माह–ए–मगफिरत और माह–ए–नजत के विशेष शो आयोजित किए गए।
- मुहर्रम, 2018 के पहले दस दिनों में आशूरा–ए–मुहर्रम के सिलसिले में विशेष श्रृंखला "याद–ए–कर्बला" का प्रसारण।
- ईद–ए–मिलाद–उन–नबी (एसएडब्ल्यू), पवित्र अमरनाथ यात्रा, नवरात्र, मेला खीर भवानी, गुरु पूरब और अन्य वर्षगांठ और त्योहारों के संबंध में विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण।
- केंद्र सरकार के चार साल पूरे होने के सिलसिले में ''पेशरफ्त'' नामक विशेष कार्यक्रमी श्रृंखला का प्रसारण।

प्रथम जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक की संभावित योजना :

- महाशिवरात्रि के संबंध में विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण।
- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के संबंध में विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण।
- विश्व रंगमंच दिवस के संबंध में विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण।

MhMh % vkfM;k

डीडी ओडिया ने 2 अक्तूबर, 1993 से डीडी–5 के रूप में कार्य करना शुरू किया। 1 अप्रैल, 2001 को इसे 24–घंटे का चैनल बनाया गया। इस अवधि (अक्तूबर 2018 तक) के दौरान केंद्र की व्यावसायिक कमाई की 22,96,315 रुपये है।

2018–19 की अवधि के दौरान डीडी–ओडिया की महत्वपूर्ण गतिविधियां :

- अप्रैल 2018 को उत्कल दिवस का उत्सव उत्कलिया अस्मिता संदाना का प्रसारण किया गया।
- 19 मई, 2018 को डीडी रोड शो का सीधा प्रसारण – फ्री टू एयर सर्विसिज डीटीटी ट्रांसमिशन और डीडी फ्री डिश।
- 26 मई, 2018 को "मोदी सरकार के 4 साल" का सीधा प्रसारण।

- 21 जून, 2018 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रसारण।
- पुरी से भगवान जगन्नाथ यात्रा का सीधा प्रसारण : 28 जून, 2018, 14 जुलाई, 2018, 22 जुलाई, 2018, 23 जुलाई, 2018, 24 जुलाई, 2018 और 25 जुलाई, 2018।
- 25.08.2018 को एम्स, भुवनेश्वर के पहले दीक्षांत समारोह का सीधा प्रसारण।
- 22 सितंबर, 2018 को संकल्परा नुआ भारत : पूर्वोदयारु हेबा नुआ भारतारा बीकाशा का सीधा प्रसारण।
- 9 अक्तूबर, 2018 को उत्कल मणि गोपबंधु दास पर कार्यक्रम का प्रसारण।
- ओडिशा में 18 अक्तूबर, 2018 तथा 19 और 20 अक्तूबर, 2018 को दशहरा उत्सव परबना बेला का सीधा प्रसारण।
- चक्रवात तितली पर कार्यक्रम का प्रसारण।

प्रस्तावित सीधा प्रसारण/अन्य महत्वपूर्ण प्रसारण।

- कोणार्क महोत्सव 1 से 5 दिसंबर, 2018 तक।
- मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव : 14 से 16 जनवरी, 2019।
- राजारानी संगीत समारोह : 18 से 20 जनवरी, 2019।
- धौली–कलिंग महोत्सव : 6 से 8 फरवरी, 2019।

MhMh % ey;kye

डीडी मलयालम ने 1985 में अपनी शुरुआत से ही पूरे देश में अपनी उपस्थिति महसूस कराई है। केंद्र में तिरुअनंतपुरम, त्रिचूर और कालीकट में निर्माण की सुविधाएं और राज्य भर में स्थलीय ट्रांसमीटरों का नेटवर्क है। अवधि के दौरान कुछ नए मनोरंजन शो जैसे; बीट द फ्लोर, नो योर मिनिस्टर, वी द सोल्जर्स, डेली मॉर्निंग शो का – 'सुदिनम' शुरू किए गए। केंद्र के आगामी कार्यक्रमों में : इंटरएक्टिव टीवी शो रंगोली–पुराने हिट्स, संगीत शो, कॉमेडी सीरियल, इवनिंग लाइव शो और इंटरएक्टिव कार्यक्रम शामिल हैं।

इस अवधि के दौरान प्रसारित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

- डीडी केरल पर यात्रा–वृत्तांत (यात्रा अनुभवम) का प्रसारण 14 अप्रैल, 2018 से शुरू किया।
- 14 अप्रैल, 2018 को विशु उत्सव पर संगीत कार्यक्रम नीलमझायिल संगीथा सिल्पम का प्रसारण।
- 25 अप्रैल, 2018 को त्रिचूर पूरम उत्सव का सीधा प्रसारण।
- 10 मई, 2018 को तिरुअनंतपुरम में डीटीटी और डीटीएच को बढ़ावा देने वाले रोड शो का सीधा प्रसारण।
- 29 और 30 मई, 2018 को 4 साल मोदी सरकार का प्रसारण।
- 15 जून, 2018 से 'फीफा विश्व कप' के दैनिक विश्लेषण का प्रसारण।
- 20 और 21 जून, 2018 को योग दिवस पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण।
- 6 अगस्त, 2018 को राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की केरल यात्रा का सीधा प्रसारण।
- 17 अगस्त, 2018 को भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 'श्रद्धांजलि' का सीधा प्रसारण।
- 18 अगस्त, 2018 को कार्यक्रम प्रलयकेदुथियिल केरलम (बाढ़ में केरल) का प्रसारण।
- ओणम के दिनों में ओणम पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया।
- 17 सितंबर, 2018 से विशेष कार्यक्रम केरलम अथीजीवानाथिलेक्कू का प्रसारण शुरू।
- 8 अक्तूबर, 2018 को विशेष कार्यक्रम "वेल्डन केरल" का प्रसारण।
- 10 नवंबर, 2018 को अलाप्पुझा में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 'का लाइव प्रसारण।
- 10 नवंबर, 2018 से 'चेम्बाई संगीत समारोह' का प्रसारण।

MhMh pnuk

15 अगस्त, 1994 को प्रारंभ किया गया डीडी चंदना कन्नड़ भाषा का उपग्रह चैनल है जिसे बंगलुरु एवं गुलबर्गा

के दूरदर्शन स्टूडियो का सहयोग मिलता है। वर्ष 2000 में यह चौबीस घंटे प्रसारण वाला चैनल हो गया तथा 24 मार्च, 2003 से इसकी कवरेज 30 से अधिक देशों में होने लगी। इस अवधि (31 अक्तूबर 2018) के दौरान इसकी वाणिज्यिक आमदनी 2,13,52,356 रुपये रही।

इस अवधि के दौरान प्रसारित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं :

- 24 मई, 2018, 27 मई, 2018 और 30 मई, 2018 को जाला होबली, बंगलुरु से फुटबॉल मैच "हीरो सेकेंड डिवीजन लीग 2017–2018" का प्रसारण।
- 5, 6 और 13 जून, 2018 को योग कार्यक्रम का प्रसारण।
- 14 जून, 2018 को केंद्र सरकार के चार साल पूरे होने पर कार्यक्रम का प्रसारण।
- 23 जून, 2018 को 200वां विशेष कार्यक्रम –मन्यांगलादल्ली मथुकाथे का प्रसारण।
- 1 सितंबर, 2018 को टाउन हॉल, बंगलुरु से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के लॉन्च का प्रसारण।
- 9 अक्तूबर, 2018 को बंगलुरु में दिवंगत दीनदयालु नायडू के जन्म शताब्दी के समापन समारोह का प्रसारण।
- 19 अक्तूबर, 2018 को मैसूर से दशहरा समारोह का प्रसारण।

MhMh % iokZUkj

डीडी पूर्वोत्तर 1 नवंबर, 1990 में कमीशंड किया गया और अंततः 15 अगस्त, 1994 को इसका शुभारंभ किया गया। 27 दिसंबर, 2000 से यह 24 घंटे प्रसारण वाला चैनल हो गया।

इस अवधि के दौरान प्रसारित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं:

- बसंतोत्सव – रोंगाली – अप्रैल, 2018
- अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस पर डॉक्यूमेंट्री श्रमबंधु अतुलसाइकिया – मई, 2018 को प्रसारण।
- कार्यक्रम वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट '2018– मई, 2018
- प्रो.जगदीश मुखी के साथ साक्षात्कार इतिहाशरेक काला अध्याय : 1975– जून, 2018
- योगशक्ति केंद्र, गुवाहाटी के सहयोग से योग पर कार्यक्रम– जून, 2018।
- वृत्तचित्र वन महोत्सव '2018 – जुलाई, 2018
- वृत्तचित्ररेसोमकास्वर्णयुग – अगस्त, 2018
- गांधीवादी दर्शन पर वृत्तचित्र–फ़ीचर –सत्याग्रह – सितंबर, 2018
- डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आमिएकेखान्नावोरेजात्री का प्रसारण – सितंबर, 2018

MhMh % jkt LFkku

डीडी राजस्थान, चौबीस घंटे प्रसारण वाले हिंदी क्षेत्रीय चैनल के रूप में 1 अगस्त, 2013 को अस्तित्व में आया और 15 अगस्त 2013 से इसने औपचारिक रूप से कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ किया। 24 घंटे प्रसारण वाला यह केंद्र विभिन्न शैलियों के कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।

केंद्र नियमित रूप से माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्रीमती स्मृति ईरानी और राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की राजस्थान यात्राओं पर अपने कार्यक्रम "सांसद आपके द्वार" में टीवी रिपोर्ट्स प्रसारित कर रहा है। इस अवधि (अक्तूबर 2018) के दौरान केंद्र की व्यावसायिक आमदनी 3,20,87,959 करोड़ रुपये रही।

अवधि के दौरान प्रमुख गतिविधियां, पहल और उपलब्धियां :

- 27.05.2018 को प्रश्नोत्तरी के 800वें एपिसोड के अवसर पर विशेष एपिसोड।
- 21 जून, 2018 को चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर – एफआरआई, देहरादून से डीडी राजस्थान पर सीधा प्रसारण
- प्रधानमंत्री की सरकारी योजनाओं के जयपुर से 12 लाभार्थियों द्वारा अनुभव साझा किए जाने का सीधा प्रसारण–7 जुलाई, 2018।
- श्री गंगानगर से करगिल दिवस समारोह का सीधा प्रसारण – 26 जुलाई, 2018।

- बीएसएफ पर विशेष कार्यक्रम – सीमा री गूंज का सीधा प्रसारण (3 एपिसोड)।
- डीडी राजस्थान की वर्षगांठ पर 6 जुलाई, 2018 को विशेष कार्यक्रम सार्थक (गजल इवनिंग) और 16 – 17 सितंबर, 2018 को विराट (संगीत समारोह) का प्रसारण।

MhMh % fcgkj

डीडी–बिहार, 24×7 क्षेत्रीय उपग्रह चैनल 01.05.2013 को लॉन्च किया गया। इसने उपग्रह चैनल के रूप में अपनी शुरुआत के बाद से देशभर में अपने क्षितिज का विस्तार जारी रखा।

अवधि के दौरान डीडीके, पटना की प्रमुख गतिविधियां

- 10 अप्रैल, 2018 को मोतिहारी और भागलपुर से शपथ समारोह सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह का सीधा प्रसारण।
- 12 अप्रैल, 2018 को बिहार दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रसारण।
- 26 मई, 2018 को बथनाहा (सीतामढ़ी) यज्ञ पर टीवी रिपोर्ट का प्रसारण।
- 27 मई, 2018 को जैन मंदिर (बासोकुंड, वैशाली) पर टीवी रिपोर्ट का प्रसारण।
- 8 जून, 2018 को महेश स्मृति पर वृत्तचित्र का प्रसारण।
- 21 जून, 2018 को देहरादून से चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का प्रसारण।
- 23 जुलाई, 2018 को चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण।
- 25 जुलाई, 2018 को टेली फ़िल्म, प्लास्टिक मैन का प्रसारण।
- 22 जुलाई, 2018 को मंथन– संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम का प्रसारण,।
- शहीद भगत सिंह की जयंती पर 28 सितंबर, 2018 को विशेष कार्यक्रम का प्रसारण।

MhMh % mÙkj çn'k

डीडी उत्तर प्रदेश, 24×7 हिंदी क्षेत्रीय उपग्रह चैनल 16 अगस्त, 2013 को अस्तित्व में आया। यह 24 घंटे का चैनल लोक संगीत, सुगम संगीत, नाटक, टॉक शो, क्विज़ और कुछ अभिलेखीय कार्यक्रमों जैसी शैलियों को कवर करता है। 2018–19 (अक्तूबर, 2018 तक) के दौरान इसका अर्जित राजस्व 1,27,76,000 रुपये रहा।

इस अवधि के दौरान प्रसारित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं :

- 14 अप्रैल, 2018 को अंबेडकर जयंती, मनाई गई।
- डीडी यूपी चैनल को बढ़ावा देने के लिए, 16 मई, 2018 को आईपीएल रोड शो का आयोजन किया गया।
- स्कूल जाने वाले बच्चे की देखभाल पर आधारित टेलीफ़िल्म cl FkkMk lk– 20 जून, 2018 को प्रसारित की गई।
- 15 अगस्त, 2018 को हापुड़ के ग्राम धनवाली में फसल संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
- 5 से 12 सितंबर, 2018 तक इलाहाबाद में रियलिटी शो "सिंगिंग स्टार ऑफ यूपी" का ऑडिशन।
- "राष्ट्रीय एकता दिवस" 31 अक्तूबर, 2018 को मनाया गया।

MhMh % e/; çn'k

डीडीके, भोपाल उपग्रह के माध्यम से पहले 24 घंटे की टेलीकास्ट सेवा के रूप में लॉन्च किया गया था, बाद में 25 जून, 2013 को इसका नाम बदलकर डीडी मध्य प्रदेश कर दिया गया। पीजीएफः ग्वालियर और पीजीएफः इंदौर डीडी मध्य प्रदेश पर प्रसारण के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं। हिंदी के अलावा, मालवी, बुंदेली, बघेली और निमरी जैसी स्थानीय बोलियों में भी कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं।

इस अवधि के दौरान प्रसारित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं :

- डिजिटल इंडिया मिशन पर कार्यक्रम।
- अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर कार्यक्रम।

- एक भारत श्रेष्ठ भारत।
- गुड मॉर्निंग एमपी पर कार्यक्रम।
- महात्मा गांधी पर विशेष कार्यक्रम।
- महिला किसान पुरस्कार, 2018 के लिए नामित श्रीमती विद्यारानी लोधी पर कार्यक्रम।
- मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर वृत्तचित्र।
- नवरात्रि पर विशेष कार्यक्रम।
- केंद्र सरकार के चार साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम टाकथॉन।

njn'ku 0;kolkf;d lok

कारोबार करने में सुगमता के साथ, एक नई पंजीकरण और प्रत्यायन नीति शुरू की गई है।

यह स्कंध प्रसारण समय या एयर टाइम की बिक्री के लिए विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों के साथ बातचीत करता है। निरंतर बदलते बाज़ार परिदृश्य को देखते हुए इस संबंध में नियम और नीतियां समय–समय निर्धारित किए जाते हैं और उनकी समीक्षा की जाती है। ग्राहकों के लिए मैनुअल बिलिंग के स्थान पर ऑनलाइन बिलिंग के लिए ब्रॉडकास्टिंग ऑटोमेटेड शेड्यूलर (बीएटीएस) शुरू किया गया। 2018–19 के दौरान (अक्तूबर, 2018) दूरदर्शन द्वारा अर्जित शुद्ध राजस्व (जीएसटी और कमीशन के अलावा) 452.24 करोड़ रुपये है।

fodkl lpkj iHkkx ¼Mh lhMh½

दूरदर्शन के विकास संचार प्रभाग (डीसीडी) की स्थापना मार्च, 2001 में की गई ताकि वह सिंगल विंडो विपणन प्रभाग और सरकार के विभिन्न विभागों, विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों की संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीन विकास संचार मॉडल सहित प्रॉडक्शन हाउस के रूप में कार्य कर सके। यह मीडिया प्लानिंग, कार्यक्रम निर्माण, शेड्यूलिंग और प्रभाव मूल्यांकन के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए टर्न–की समाधान प्रदान करता है। विकास संचार विभाग निम्नलिखित के लिए सिंगल विंडो सुविधा प्रदान करता है :

- दूरदर्शन एयरटाइम और निर्माण क्षमता का विपणन
- कंसल्टेंसी और कस्टमाइज़्ड मीडिया प्लानिंग
- देशव्यापी स्टेशन में क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रमों का निर्माण; और
- ग्राहकों के लिए प्रतिक्रिया और अनुसंधान सर्वेक्षण।

2018–19 के दौरान प्रसारित अभियान :

- वर्ष 2018–19 के दौरान पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सहयोग से विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान 'स्वच्छ भारत' प्रसारित किया गया।
- विभिन्न अभियान उदाहरण के लिए– स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तंबाकू विरोधी, चिकनगुनिया, डेंगू, टीकाकरण और स्तनपान संबंधी अभियान। पर्यटन मंत्रालय का अतुल्य भारत अभियान तथा वित्त मंत्रालय का आय घोषणा योजना और जीएसटी अप्रैल, 2018 से प्रसारित किए गए।
- उपभोक्ता कार्य मंत्रालय का 'जागो ग्राहक जागो' वर्ष 2018–19 से दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा रहा है।
- स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न मंत्रालयों के विज्ञापनों का दूरदर्शन पर प्रसारण किया गया।
- दूरदर्शन के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का 'डॉक्टर ऑन–लाइन' कार्यक्रम वर्तमान वर्ष में भी प्रसारित किया जा रहा है। इसके अलावा, 2018–19 के दौरान डेंगू, स्वाइन फ्लू, तपेदिक, परिवार नियोजन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर विज्ञापन/अभियान प्रसारित किए गए।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय की साझेदारी में शुरू किए गए विशेष अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चालू वित्तीय वर्ष में प्रसारण जारी रहा।
- पर्यटन मंत्रालय के लिए 15 लघु फ़िल्मों की शृंखला 'क्या आप जानते हैं ' का निर्माण किया जा रहा है और पर्यटन पर्व, 2018 के दौरान 12 का प्रसारण किया गया। पर्यटन पर्व 2017 के लिए आयोजित 'स्माइल इंडिया स्माइल' नामक फोटो प्रतियोगिता का जुलाई 2018 में प्रसारण किया गया।
- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और आयुर्वेद दिवस अभियान चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रसारित किए गए।

जनवरी से मार्च, 2019 तक की संभावित योजनाः

1. "क्या आप जानते हैं 'चरण–2' : पर्यटन मंत्रालय के लिए 15 नई लघु फ़िल्मों की शृंखला का निर्माण और प्रसारण किया जाएगा। इन फ़िल्मों के अलावा, फोटोग्राफी प्रतियोगिता 'मुसाफिर हूं यारों 'पूरी की जाएगी।
2. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के चार कार्यक्रम यथा– सफ़र मंज़िलों का (26 एपिसोड), चलो साफ़ करो (26 एपिसोड), कश्मीर टू कन्याकुमारी (26 एपिसोड)

और हमने ठानी सबने मानी (26 एपिसोड) पूरे किए जाएंगे।

3. एनएमसीजी के तीन कार्यक्रम यथा, रग–रग में गंगा (26 एपिडोड्स), बात गंगा की (26 एपिसोड), मेरी गंगा क्विज (16 एपिसोड) पूरे किए जाएंगे।

4. गृह मंत्रालय के लिए कट्टरपंथ विरोधी–मेरा घर इंडिया पर 10 लघु फ़िल्में पूरी की जाएंगी।

5. पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के दो कार्यक्रम यथा एसटीआईएनईआर टेक टॉक (13 एपिसोड) और क्लीनर इंडिया (26 एपिसोड) पूरे किए जाएंगे।

MhMh vkdkbZl

दूरदर्शन आर्काइव्स 2018 में अधिक गहन और घटनापूर्ण वर्ष का गवाह बना। इस दौरान डिजिटलीकरण ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। विरासत और इतिहास की कालातीत दृश्य–श्रव्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए गए। उपलब्ध बुनियादी ढांचे को अद्यतन को बनाने के लिए नई कार्यनीतियां तैयार की जा रही हैं। दूरदर्शन आर्काइव्स में उत्पादकता एक मुख्य चिंता रही है।

1 अप्रैल, 2018 से अब तक की गतिविधियां :

- कंटेंट का डिजिटलीकरण : डीडी आर्काइव्स ने मीडिया एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (एमएएम) के माध्यम से अब तक 12,508 घंटे की सामग्री का डिजिटलीकरण किया है। इनमें से 1,414 घंटे का डिजिटलीकरण इसी अवधि में किया गया।

- डबिंग : विरासत टेपों से 27,417 घंटे की सामग्री डिजिटल टेपों में डब की गई, इसमें से 1,415 घंटे 1 अप्रैल, 2018 से 31 अक्तूबर, 2018 की अवधि के दौरान डब किए गए हैं। टेपों के डिजिटलीकरण के अलावा, 4,750 तस्वीरों को हार्ड कॉपी से मीडिया प्रारूप में डिजिटाइज्ड किया गया है।

- मेटाडेटा : सूचियों या इन्वेंटॅरीज के अलावा 2,752 घंटे के मेटाडेटा की पहचान की गई है और इसमें से 588 घंटे इस अवधि के दौरान सृजित किए गए।

- राष्ट्रीय संसाधन विनिमय पूल (एनआरईपी) योजना के तहत, डीडी आर्काइव्स ने अन्य दूरदर्शन केंद्रों/कार्यालयों को 9,666 घंटे की सामग्री प्रदान की है, जिसमें से 451 घंटे की सामग्री इसी अवधि के दौरान प्रदान की गई।

- इन्वेंटरी : अब तक 1,46,759 प्लस इन्वेंटरी वेब आधारित लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में फीड की गई हैं और इस अवधि के दौरान इनमें से 1,409 को फीड किया गया है।

- पुराने कार्यक्रमों की रीपैकेजिंग : पुरानी सामग्री की रीपैकेजिंग के बाद प्रति सप्ताह छह कार्यक्रम डीडी नेशनल को प्रसारण के लिए भेजे जाते हैं। 'शहीदों की बातें', 'वो गुज़रा ज़माना' आदि जैसे कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है और उनका निर्माण किया गया है।

- सोशल मीडिया : ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक, के माध्यम से, डीडी आर्काइव्स ने आगामी कार्यक्रमों और डीडी आर्काइव्स में रीपैकेज्ड डीवीडी रिलीज के बारे में जनता को सचेत रखने के लिए अपना अकाउंट शुरू कर दिया है। इस अवधि के दौरान 1399 वीडियो के साथ 11,738 कार्यक्रम डीडी आर्काइव्स यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए हैं।

- अर्जित राजस्व : प्रसार भारती आर्काइव्स ने 1 अप्रैल, 2018 से 31 अक्तूबर, 2018 की अवधि के बीच 5,72,455 रुपये का राजस्व अर्जित किया है जिसमें से 3,55,983 रुपये की राशि डीवीडी की बिक्री के माध्यम से और 2,16,472 रुपये की राशि अभिलेखीय फुटेज की बिक्री के माध्यम से अर्जित की गई है।

- सबटाइटलिंगः डीडी, आर्काइव्स ने सी–डीएसी के जरिए मांग पर प्रासंगिक कार्यक्रमों की सबटाइटलिंग करना शुरू कर दिया है।

भविष्य की योजना के लिए चालू परियोजनाएं :

- आईपीआर और फुटेज बिक्री के बारे में एक नीति तैयार की गई है और प्रसार भारती में विचाराधीन है।

- अभिलेखीय कार्यक्रमों के आईपीआर सुनिश्चित करने के लिए, एक टीम को डीजी, दूरदर्शन पर तैनात किया गया है ताकि वे ऐसे कार्यक्रमों के अनुबंध, समझौतों और अन्य सभी प्रासंगिक कागजों को प्राप्त कर सकें।

- अभिलेखीय फुटेज की बिक्री के संबंध में रेट कार्ड का संशोधन निर्धारित किया गया है और वह प्रसार भारती में विचाराधीन है।

- सेंट्रल आर्काइव ने कुंभ–2019 के लिए आईजीएनसीए के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय को अपनी सेवाएं और सामग्री प्रदान की है।

- डीडी आर्काइव डिजिटलीकरण और डबिंग की प्रक्रिया में पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में है।

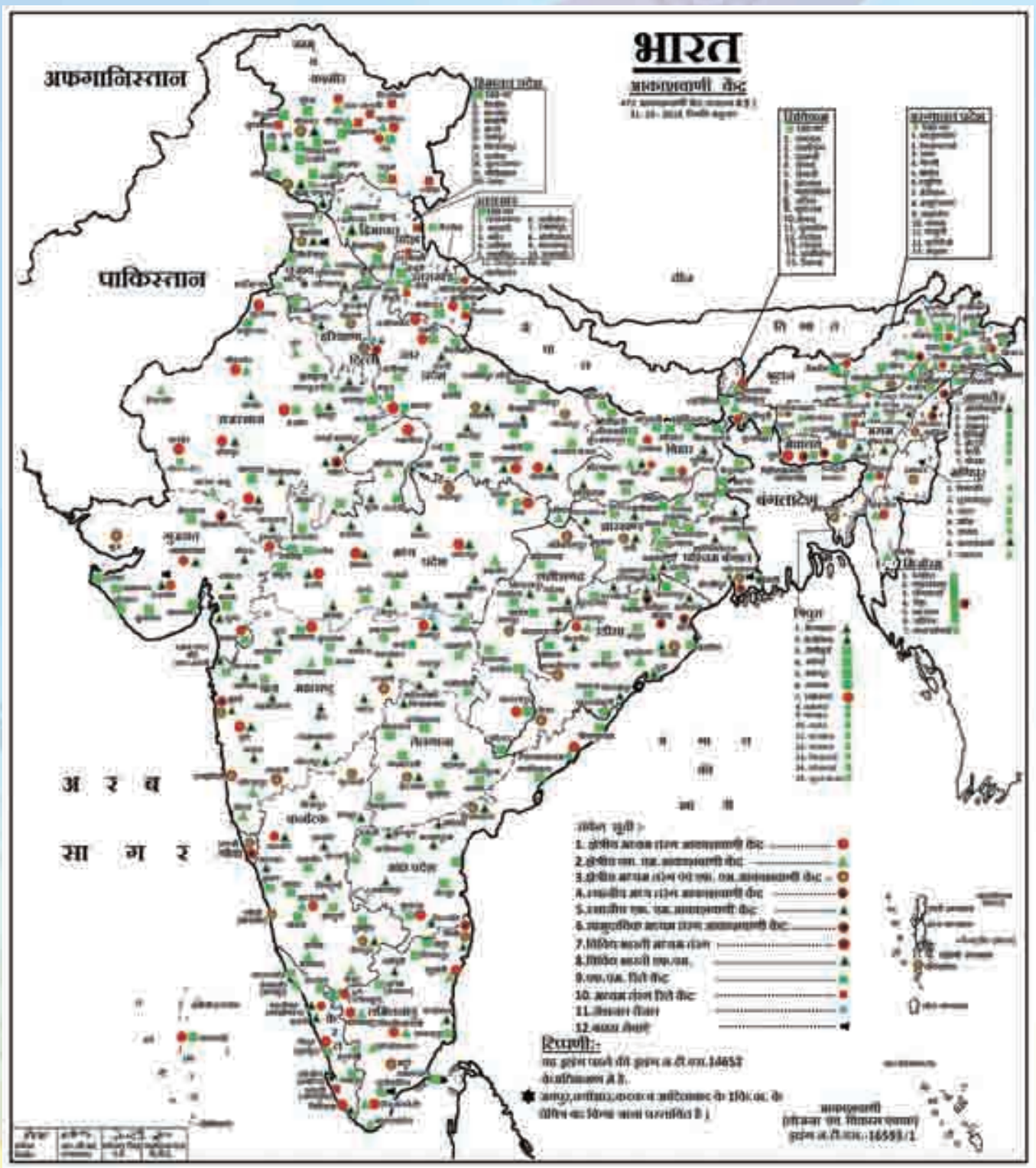
भारत
अफगानिस्तान
पाकिस्तान
अ र ब
सा ग र

vkdk'kok.kh

,d utj esa rF; ¼01-12-2018 rd½

1- iLkkj.k dsnz 472

- क) स्टूडियो के साथ पूर्ण विकसित स्टेशन 225
  - i) स्थानीय रेडियो स्टेशन (एलआरएस) 86
  - ii) एलआरएस के अलावा स्टूडियो के साथ स्टेशन 134
  - iii) सामुदायिक रेडियो स्टेशन 5
- ख) रिले केंद्र 247
  (100 डब्ल्यू एफएम रिले केंद्रों की 209 संख्या सहित)
- ग) एफएम ट्रासमीटर (ट्रांसमीटरों) वाले आकाशवाणी केंद्र 449
- घ) विविध भारती केंद्र 41
- च) विदेश सेवाओं के लिए 11
- छ) रिकॉर्डिंग स्टूडियो 1 (भुवनेश्वर)

2- VªkalehVjksa dh la[;k% 671

- क. मीडियम वेव 138
- ख. शॉर्ट वेव 48
- ग. एफएम 485

3- çlkj.k dojst

	{ks=Qy }kjk ¼%½	tula[;k }kjk ¼%½
प्राथमिक ग्रेड सिग्नल द्वारा (मी.वे + एफएम)	92.00%	99.20%
केवल एफएम सिग्नल द्वारा	39.00%	52.00%
केवल मी.वे सिग्नल द्वारा	90.65%	98.40%

4- dSfIVo vFkZ LVs'ku 37

5- LVwfM;ks 228

6- {ks=h; lekpkj bdkb;ka ¼vkj,u;w½ 47

7- vkdk'kok.kh dk MhVh,p pSuy 39

8- ykbo LVhfeax pSuy 17

bathfu;fjax

d- usVodZ vkSj dojst esa o`f)%

आकाशवाणी दुनिया में सबसे बड़े प्रसारण नेटवर्क में से एक है। आजादी के समय देश में छह रेडियो स्टेशन और 18 ट्रांसमीटर (6 मीडियम वेव और 12शॉर्ट वेव) थे जो देश की 11 प्रतिशत आबादी और 2.5 प्रतिशत क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करते थे।

31 अक्तूबर, 2018 तक, आकाशवाणी के नेटवर्क में विस्तार हुआ और 472 स्टेशन और 670 ट्रांसमीटर (138 मीडियम वेव, 48 शॉर्ट वेव और 485 एफएम) हो गए, जो देश के 92.00 प्रतिशत क्षेत्र में फैली 99.20 प्रतिशत आबादी को सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें लगभग 8–10 किमी के दायरे की स्थानीय कवरेज के लिए स्थापित 100 डब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर के 237 शामिल हैं।

[k- o"kZ dk nkSjku izeq[k xfrfof/k;ka%

1. 01.4.2018 से 31.10.2018 तक प्रभावी, स्टेशनों की संख्या 469 से बढ़कर 472 हो गई है और ट्रांसमीटरों की संख्या 662 से बढ़कर 670 हो गई है।

¼d½ o"kZ dk nkSjku pkyw fd, x, u, LVs'ku@VªkalehVj%

पटनीटॉप (जम्मू– कश्मीर)	10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर (रिले)
अमृतसर (पंजाब)	20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर (रिले)
चौटन हिल (राजस्थान)	20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर (रिले)

(ख) वर्ष के दौरान मौजूदा केंद्रों पर चालू किए गए ट्रांसमीटर

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)	10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर
जलगांव (महाराष्ट्र)	5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर
रीवा (मध्य प्रदेश)	5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर
अजमेर (राजस्थान)	5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर
आगरा (उत्तर प्रदेश)	5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर
मथुरा (उत्तर प्रदेश)	10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर

¼2½ fMftVyhdj.k ;kstuk

1. 98 स्टूडियो का डिजिटीकरण :
   - सभी 98 स्टेशनों पर डिजिटल कंसोल प्रदान किए गए हैं।
   - 48 स्टेशनों पर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, बैक–अप के साथ सर्वर प्रदान किए गए हैं।
   - शेष 50 स्टेशनों के लिए, कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
2. नए आरएनयू (क्षेत्रीय समाचार इकाइयां) का निर्माण (सं. 7) :
   - करगिल, संबलपुर और विशाखापत्तनम में आरएनयू पहले से ही चालू हैं। शेष 4 स्थानों जोधपुर, राजकोट, दरभंगा और पासीघाट में आर.एन.यू. कामकाज शुरू करने के लिए तैयार हैं।
   - डिजिटल स्टूडियो टीएक्स लिंक (सं. 127)।
   - डिजिटल स्टूडियो टीएक्स वर्ष के दौरान शेष स्थानों पर लिंक स्थापित और चालू किया गया।

3- tEew & d'ehj ds fy, fo'k"k iSdst ¼pj.k-III½ %

- जम्मू – कश्मीर में आकाशवाणी सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए विशेष पैकेज के तहत चार, 10 किलोवाट एफएम सेट–अप स्थापित किए जा रहे हैं। जबकि ऐसे ही दो नौशेरा और पटनीटॉप में चालू किए जा चुके हैं और शेष दो उरी और हिंबोटिंगला में पूरा होने के करीब हैं।

4- mÙkj&iwoZ fo'k"k iSdst ¼pj.k-II½ %

उत्तर पूर्व तथा द्वीप क्षेत्रों में आकाशवाणी सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए विशेष पैकेज के तहत, 1 किलोवाट एफएम स्टेशन निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किए जा रहे है जिनकी संख्या 19 होगी :

अरुणाचल प्रदेश	नामसाई, बोमडिला, अनिनी, चांगलांग, दापोरजियो, खोंसा
असम	करीमगंज, लुमडिंग, गोलपारा
मणिपुर	उखरूल, तामेंगलोंग
मेघालय	चेरापूंजी
मिजोरम	तुईपांग, चेम्फल, कोलासिब
नगालैंड	वोखा, जुनहेबोटो, फेक
त्रिपुरा	उदयपुर, नूतन बाज़ार

योजना की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है :

- 19 में से 18 स्थलों का अधिग्रहण परिपूर्ण किया जा चुका है।
- 8 स्थानों पर ट्रांसमीटरों को चालू किया गया है यथा गोलपारा, नूतन बाज़ार, चेरापूंजी, लुमडिंग, फेक, उखरुल, बोमडिला और वोखा। आठ स्थानों पर ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं और 1 स्थान पर काम प्रगति पर है।
- तमेंगलोंग (मणिपुर) में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थल ले लिया गया है।
- अनिनी (अरुणाचल प्रदेश) में एक उपयुक्त स्थल का अधिग्रहण किया जाना बाकी है। नामसाई (अरुणाचल प्रदेश) में एफएम स्टेशन विचाराधीन है।

5- 12oha ;kstuk ds rgr ubZ igy

d- lhfer mRiknu lqfo/kk ds lkFk u;k ,Q,e VkalehVj % 11 LFkku

i) 10 fdyksokV ,Q,e VkalehVj ¼8½ dkdhukMk ¼vka/kz innss'k½] eqt¶Qjiqj ¼fcgkj½ esa MhMh LFky ij] jryke ¼e-ç-½] —".kkuxj ¼if'pe caxky½ esa MhMh LFky] yqf/k;kuk ¼iatkc½] cknh ¼jktLFkku½ esa MhMh LFky] bVkok ¼m-ç-½] esjB ¼mç½

मेरठ (उ.प्र.) और रतलाम (म.प्र.) में नए स्टेशनों के लिए भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इटावा (उ.प्र.) में स्थल का अधिग्रहण कर लिया गया है। 10 किलोवाट एफएम के

चार ट्रांसमीटर खरीदे जा चुके हैं और शेष 4 स्थानों के लिए ऑर्डर दे दिया गया है।

ii) 5 fdyksokV ,Q,e VªkalehVj ¼3½ vyi>k ¼djy½] veBh ¼m-ç-½ vkSj jhok ¼e-ç-½ %

रीवा में 5 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर को चालू किया जा चुका है, जबकि अमेठी में अंतरिम सेटअप में काम कर रहे 5 किलोवाटएफएम ट्रांसमीटर को भवन निर्माण के बाद स्थाई सेट–अप में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

[k- ,Q,e VªkalehVj ds lkFk vfrfjä pSuy % 7 LFkku

i) 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर – 4 [दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई]

ii) 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर – 3 [कानपुर (उ.प्र.), विजयवाड़ा (आं. प्र.) पणजी (गोवा)]

- 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में चालू किए गए।
- 10 किलोवाट एफएम के 3 ट्रांसमीटरों की स्थापना भी प्रगति पर है।

x- ,yMCY;bZ ;kstuk ds rgr eh-o- VªkalehVj dk çfrLFkkiu %

जगदलपुर, विशाखापत्तनम, जेयपोर और संबलपुर में 100 किलोवाट मेगावाट के ट्रांसमीटरों की जगह नए 100 किलोवाट मी.वे डिजिटल रेडी ट्रांसमीटरों को लगाया गया। हैदराबाद और भवानीपटना में 200 किलोवाट मेगावाट के ट्रांसमीटरों की जगह नए 200 किलोवाट मी.वे डिजिटल रेडी ट्रांसमीटर लगाए गए।

?k- ekStwnk ,yihVh@,pihVh MhMh LFkyksa ¼100 LFkkuksa½ ij 100 MCY;w ,Q,e VªkalehVj dh LFkkiuk

100 डब्ल्यू एफएम के 100 ट्रांसमीटरों की खरीद का काम चल रहा है।

M- iqjkus ,Q,e VªkalehVjksa ¼77 LFkkuksa ij½ dk ,Q,e VªkalehVj }kjk çfrLFkkiu@mUu;u

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर चालू किए गए। 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर और 5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर क्रमशः 46 (63 स्थानों में से) और 11 स्थानों (11 स्थानों में से) पर चालू किए गए।

p- LFkkuksa ij iqjkus eh-o- VªkalehVjksa dk çfrLFkkiu ,Q,e VªkalehVjksa }kjk fd;k x;k

- किन्नौर (हि. प्र.) – 1 किलोवाट मी.वे ट्रांसमीटरों का प्रतिस्थापन 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटरों द्वारा करना।
- जोरंडा (ओडिशा) – 1 किलोवाट मी.वे ट्रांसमीटरों का प्रतिस्थापन 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटरों द्वारा करना।
- सोरो (ओडिशा) – 1 किलोवाट मी.वे ट्रांसमीटरों का प्रतिस्थापन 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटरों द्वारा करना।
- अल्मोड़ा (उत्तराखंड) – 1 किलोवाट मी.वे ट्रांसमीटरों का प्रतिस्थापन 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटरों द्वारा करना।
- ऊटाकामुंड (तमिलनाडु) – 1 किलोवाट मी.वे ट्रांसमीटरों का प्रतिस्थापन 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटरों द्वारा करना।
- मथुरा (उत्तर प्रदेश) – 1 किलोवाट मी.वे ट्रांसमीटरों का प्रतिस्थापन 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटरों द्वारा करना।

1 किलोवाट एफएम के 4 ट्रांसमीटर और 10 किलोवाट एफएम के 2 ट्रांसमीटर खरीदे गए हैं।

N- Hkkjr&usiky lhek ¼6 LFkku½ ds lkFk ,Q,e çlkj.k lsVvi

- इस योजना के तहत भारत–नेपाल सीमा के साथ, 6 स्थलों पर 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने हैं।
- 05 स्थलों जैसे गादानिया, नानपारा, नरकटियागंज, सीतामढ़ी और बथानाहा में भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई। महाराजगंज के लिए एमएचए की मंजूरी अभी भी प्रतीक्षित है।

t- LVwfM;ks

i. 29 स्टूडियो का डिजिटीकरण :

हाथ में पकड़े जाने वाले डिजिटल रिकॉर्डर, ओबी मिक्सर और फोन–इन–कंसोल जैसे उपकरण स्थलों पर प्राप्त हुए।

ii. आकाशवाणी के 6 स्टूडियो का नवीकरण :

6 स्थानों पर स्टूडियो का नवीनीकरण चल रहा है।

iii. गुवाहाटी में पुरातात्विक सुविधा का निर्माण :

गुवाहाटी में क्षेत्रीय पुरातत्व केंद्र की स्थापना से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

>- çf'k{k.k lqfo/kkvksa dk eatcwr cukuk

स्वीकृत योजना आवंटन के अनुसार दिल्ली और भुवनेश्वर में प्रशिक्षण सुविधा का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

r- vuqla/kku vkSj fodkl dk etcwr cukuk

आकाशवाणी के अनुसंधान एवं विकास विभाग ने स्वीकृत योजना आवंटन के अनुसार विकास और आधुनिकीकरण के लिए पहल की है।

Fk- ofdZyd LVªhfeax ij çlkj.k

50 चैनलों की ऑडियो स्ट्रीमिंग का कार्यान्वयन हो रहा है। आकाशवाणी के 17 चैनलों की लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत की गई है, जो इंटरनेट का उपयोग करने के साथ–साथ मोबाइल हैंडसेट, आईपैड, टैबलेट आदि पर उपयुक्त एप एंड्रॉइड, आईओएस डाउनलोड करके पूरी दुनिया में सुने जा सकते हैं।

6- vkdk'kok.kh lalk/kuksa dh xfrfof/k;k¡

आकाशवाणी संसाधन भूमि, भवन और टॉवर के रूप में अपने बुनियादी ढांचे को 99 स्थानों पर निजी एफएम ऑपरेटरों से, भारत भर में 346 निजी एफएम चैनल प्रसारण सेवाओं के साथ साझा कर रहे हैं।

इसके अलावा, आकाशवाणी संसाधन प्रसार भारती के बुनियादी ढांचे को 27 स्थानों पर बीएसएनएल, एमटीएनएल के साथ और 42 स्थानों पर निजी मोबाइल ऑपरेटरों के साथ साझा कर रहा है। आकाशवाणी संसाधन बीएसएनएल/एमटीएनएल से 16 स्थानों पर और निजी मोबाइल ऑपरेटरों के साथ 13 स्थानों के बारे में प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। आकाशवाणी संसाधन ने राजस्व साझा करने के आधार पर आकाशवाणी कार्यक्रमों पर एसएमएस आधारित सेवा के प्रबंधन संचालन और डेटा रखने, सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जनरल मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के साथ नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भारतभर में आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों पर विभिन्न मोबाइल ऑपरेटरों से एसएमएस की प्राप्ति और समझौते की शर्तों के अनुसार प्रसार भारती के लिए राजस्व हिस्सेदारी का पर्यवेक्षण कर रहे हैं।

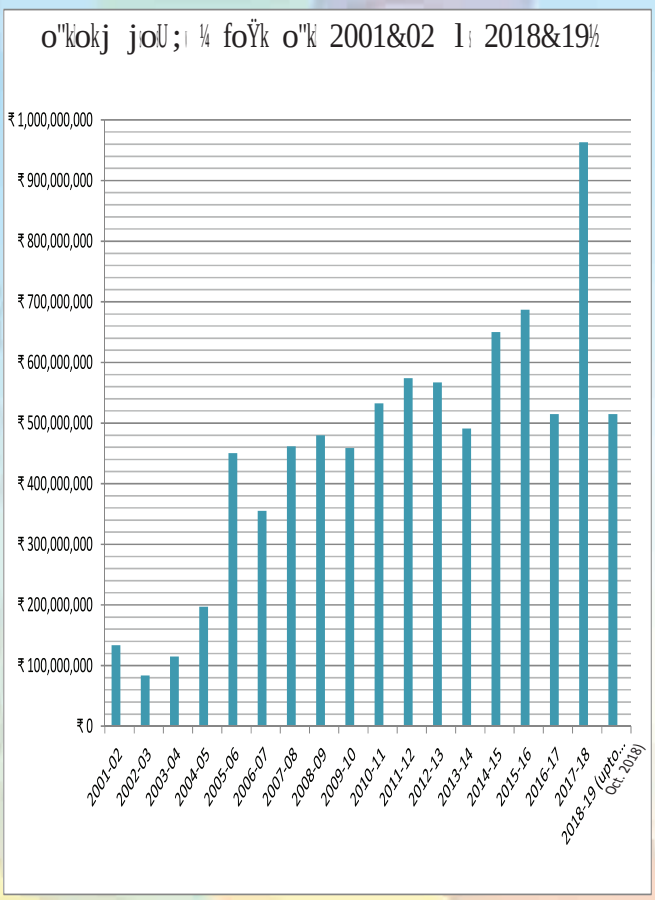

o"kZokj jktLo; ¼ foŸk o"kZ 2001&02 ls 2018&19½

आकाशवाणी संसाधन, भारत के 37 स्थानों पर ज्ञानवाणी एफएम ट्रांसमीटरों के संचालन और रखरखाव के लिए इग्नू के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते से भी आय अर्जित कर रहे हैं। इग्नू की ज्ञानवाणी सेवा शुरू हो चुकी है और आकाशवाणी नेटवर्क के माध्यम से चरणबद्ध रूप से ट्रांसमीटरों को फिर से शुरू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत जल्द ही सभी ज्ञानवाणी ट्रांसमीटरों से ये सेवाएं फिर से शुरू होने की संभावना है।

आकाशवाणी संसाधन अपनी स्थापना के वर्ष (2001–02) से राजस्व अर्जित कर रहा है। 2001–2002 से 2018–19 (01.04.2018–31.10.2018) तक अर्जित प्रगतिशील राजस्व 8,22,96,64,215 रु. है जिसे निम्न प्रकार से दर्शाया गया है :

चालू वित्त वर्ष के दौरान 31.10.2018 तक अर्जित राजस्व 51,49,75,704 रु.(जीएसटी सहित) है और वित्त वर्ष 2018–19 के लिए प्रसार भारती का निर्धारित लक्ष्य 100 करोड़ रुपये है। चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल, 2018 से (महीने के अनुसार) अर्जित राजस्व का चित्रमय प्रतिनिधित्व आगे दिया गया है :

¼7½ vuqla/kku foHkkx] vkdk'kok.kh vkSj nwjn'kZu

ifjp;%

आकाशवाणी का अनुसंधान विभाग मुख्य रूप से देश में प्रसारण सेवाओं के प्रसार अध्ययन और वैज्ञानिक नियोजन के लिए 1937 में स्थापित किया गया था। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, प्रसारण नेटवर्क के निरंतर विस्तार के साथ विभाग को /श्रव्य प्रसारण, इंटरनेट, वीडियो प्रसारण, ऑटोमेशन, उपग्रह, माइक्रोवेव और प्रचार आदि के क्षेत्र में विस्तृत अध्ययन और विकास कार्य करने के लिए लगातार संवर्धित किया गया है।

¼,½ varjjk"Vªh; fuxjkuh vkSj çkfIr dsaæ] VksMkiqj] ubZ fnYyh

नई दिल्ली के इंद्रपुरी के पास टोडापुर में स्थित अंतरराष्ट्रीय निगरानी और प्राप्ति केंद्र, विदेशी प्रसारकों से भारत की ओर मी.वे तथा शॉर्ट वे. सेवा और आकाशवाणी की आंतरिक तथा विदेश सेवाओं के संबंध में मी.वे तथा शॉर्ट वे., एफएम, डीआरएम और डीटीएच रेडियो सेवा सिग्नल की

REVENUE GENERATION FY 2018-19

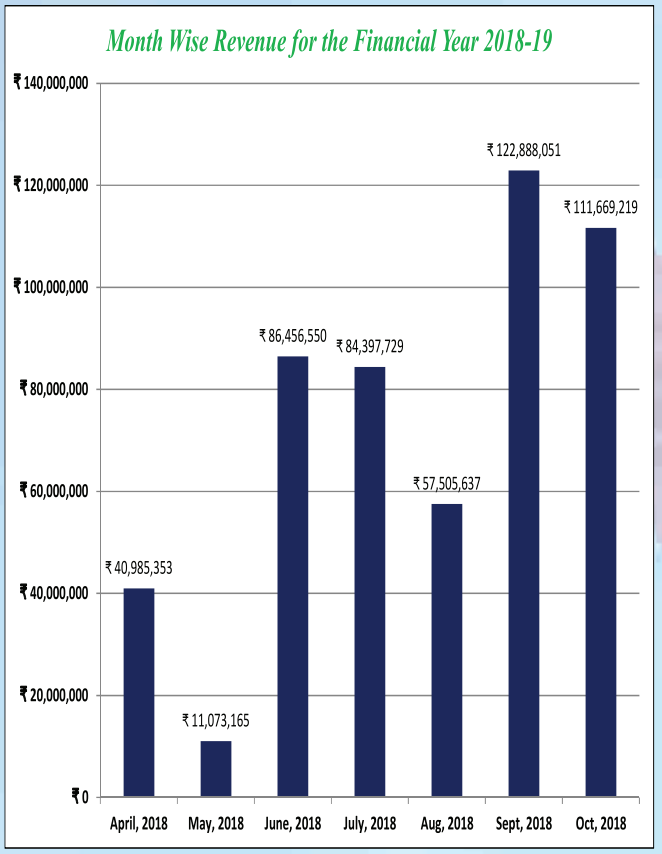

प्रसारण निगरानी का कार्य करता है। अंतरराष्ट्रीय निगरानी और प्राप्ति केंद्र, टोडापुर में 01/04/2018 से 31/10/2018 के दौरान की गई तकनीकी गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं :–

vkdk'kok.kh d ,e,Q vkj ,p,Q VklehVjk dh ÝhDosalh tkp

1. आकाशवाणी की आंतरिक, विदेश और विविध भारती सेवाएं प्रदान करने वाले सभी मी.वे तथा शॉर्ट वे. ट्रांसमीटरों यथा–किंग्सवे, खामपुर, अलीगढ़, बंगलुरु, चेन्नई, पणजी, मुंबई, चिनसुराह (एसपीटी), राजकोट (एसपीटी), जालंधर (एचपीटी), तूतीकोरिन (एचपीटी) की निगरानी निम्न उद्देश्यों से की :–
   - ट्रांसमीटरों का कार्य निष्पादन यानी ब्रेकडाउन, मॉड्यूलेशन, विरूपण, क्रॉस टॉक, अत्यधिक फ्रीक्वेंसी विचलन आदि।
   - कार्यक्रम के सही समय और उनकी तकनीकी गुणवत्ता की जांच करना।
2. भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, शिमला, गंगटोक, श्रीनगर, लेह, चेन्नई और मुंबई में स्थित क्षेत्रीय शॉर्ट वेव ट्रांसमीटरों की निगरानी।
3. आकाशवाणी डीआरएम ट्रांसमीटर (मी.वे) किंग्सवे–दिल्ली–सी (2 चैनल) और खामपुर–दिल्ली–ए (2 चैनल) से एनालॉग मोड और डिजिटल दोनों मोड ट्रांसमिशन की निगरानी।
4. सह चैनल और निकटवर्ती चैनल इंटरफेयरेंस (+) और (–) 5 हर्ट्ज के लिए आकाशवाणी के एचएफ शेड्यूल पर तीन दिनों की विशेष निगरानी। यह निगरानी एचएफ शेड्यूल की शुरुआत और मध्य में देखी गई थी।
5. रात के समय विदेशी प्रसारण केंद्रों से निकलने वाले इंटरफेयरेंस के बिंदु से आकाशवाणी के अधिकांश उत्तर भारतीय मीडियम वेव पर नजर रखी गई।
6. मीडियम वेव और शॉर्टवेव दोनों ट्रांसमीटर सहित 52 विभिन्न फ्रीक्वेंसी के बारे में फ्रीक्वेंसी विचलन उपाय किए गए। ईमेल द्वारा रिपोर्ट भेजी गई।

Dyh;j pSuy fuxjkuh vkj vkdk'kok.kh d 'kkVZoo pSuyk d bVjQ;jl dh igpku

आंतरिक, विदेश, विविध भारती और क्षेत्रीय शॉर्टवेव सेवाओं वाले आकाशवाणी चैनलों के इंटरफेयरिंग स्टेशनों की पहचान और क्लीयर चैनल निगरानी की गई। इस निगरानी से प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल सुधार कार्यों के लिए किया गया। गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय खेलों, राष्ट्रीय आयोजनों, अति महत्वपूर्ण प्रसारणों और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं पर कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए प्रत्येक मौसमी एरियल, फ्रीक्वेंसी अनुसूची को अंतिम रूप देने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए विभिन्न चैनलों पर विशेष निगरानी रखी गई। 01/03/2018 से 31/08/2018 के दौरान नीचे दी गई जानकारी के अनुसार विशेष निगरानी की गई :–

Ø- l-	fuxjkuh dk fooj.k	volj dh l[;k
1	विशेष निगरानी (102 विभिन्न फ्रीक्वेसियां)	29 दिन

vkj-,u- pSuyk dh fuxjkuh

प्रसारण भवन, नई दिल्ली से जीसैट –10 के सभी ''सी'' बैंड आरएन चैनलों की निगरानी। इन चैनलों पर प्रतिदिन हर घंटे निगरानी की जाती थी। इस दौरान कार्यक्रम की गुणवत्ता और सामग्री के संबंध में देखी गई असामान्यताएं प्रसारण भवन, नई दिल्ली को वास्तविक समय में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजी गईं और रिपोर्ट ईमेल की गईं।

,Q,e pSuy fnYyh

एफएम टेरेस्ट्रियल रेडियो के 4चैनलों की नियमित रूप से प्रतिदिन हर घंटे निगरानी की गई। इसमें पाई गईं असामान्यताएं आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित केंद्रों तथा टीवी टॉवर पीतमपुरा, दिल्ली को तुरंत भेजी गईं और रिपोर्टें ईमेल की गईं।

MhVh,p jsfM;ks fuxjkuh

40 डीटीएच रेडियो चैनलों की नियमित रूप से निगरानी रोजाना प्रति घंटा के आधार पर की गई। इसमें पाई गईं असामान्यताएं संबंधित केंद्रों और डीटीएच–डीडी को तुरंत सूचित की गईं ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके और रिपोर्ट ईमेल की जा सके।

fons'kh lsxBuksa ds izlkj.k dh fuxjkuh

भारत की ओर अग्रसर अन्य देशों के प्रसारण की तकनीकी निगरानी पारस्परिक आधार पर नियमित रूप से की गई। समय–समय पर रिपोर्टें तैयार की गईं और संबंधित प्रसारण संगठनों को ईमेल से भेजी गईं।

¼ch½ VsyhesVªh flLVe xzqi

d½ ,Mokal fjeksV e,fuVfjax ,.M daVªksy ¼eh-os@,Q,Ek VªkalehVj ds fy, oc vk/kkfjr VsyhesVªh flLVe½

आई.पी. आधारित टेलीमेट्री प्रणाली का वेब आधारित टेलीमेट्री प्रणाली में उन्नयन निम्न स्थानों पर किया गया है:

छतरपुर (मी.वे), अंबिकापुर (मी.वे), रोहतक (मी.वे), जलगाँव (मी.वे)।

वेब–आधारित टेलीमेट्री प्रणाली निम्न स्थानों पर भी स्थापित की गई है:

1. जलंधर (एफएम) 2. कसौली (एफएम) 3. कैलाशहर (एफएम) 4. आइजोल (मी.वे) 5. नागौर (एफएम), 6. सिल्चर (मी.वे), 7. तुरा (मी.वे), 8. रेवा (मी.वे), 9. रत्नागिरी (मी.वे), 10. ब्रह्मवर (मी.वे), 11. तिरुनेलवेली (मी.वे), 12. तिरुअनंतपुरम (मी.वे), 13.भुज (मी.वे), 14. लेह (मी.वे), 15. सतारा (मी.वे), 16. कटक (एफएम.),

इसके बाद, आकाशवाणी केंद्रों पर वेब आधारित टेलीमेट्री प्रणाली स्थापित की जा रही है : 1. दरभंगा (मी.वे), 2. हजारीबाग (एफएम)

आकाशवाणी विजयवाड़ा (एफएम) में वेब आधारित टेलीमेट्री सिस्टम की स्थापना तकनीकी रूप से संभव नहीं है, इसलिए, इसके वैकल्पिक स्थान के रूप में विजयवाड़ा के स्थान पर आकाशवाणी, पुणे के लिए प्रस्ताव किया गया है।

[k½ vkdk'kok.kh ds 23 dsanzksa ij lqfo/kkvksa es lq/kkj ds fy, vkdk'kok.kh dh 11oha ;kstuk ds rgr eh-os/,Q,e VªkalehVjksa ds fy, fjeksV e,fuVfjax ,.M daVªksy ¼VsyhesVªh½ ç.kkyh dk çko/kku ¼MhVhbZ l- 80@2010&11½ fd;k x;k gSA

- उपरोक्त वर्णित 23 में से 20 आकाशवाणी केंद्रों पर आई.पी. आधारित दूरस्थ निगरानी और नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई है।
- 15/11/18 से 2/12/18 तक आकाशवाणी, दरभंगा में एएम टेलीमेट्री प्रणाली और हजारीबाग में एफएम टेलीमेट्री सिस्टम की स्थापना और कमीशनिंग के लिए अनुसंधान और विकास दल ने आकाशवाणी njHkaxk vkSj gtkjhckx dk nkSjk fd;kA
- आकाशवाणी ट्रांसमीटरों के लिए वेब आधारित केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली भी विकसित की गई है।

x½ izlkj.k iz;ksx'kkyk

प्रसारण प्रयोगशाला ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन के टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों द्वारा प्रसारण सिग्नल (रेडियो और टेलीविजन) पर प्रसारण अध्ययन किया है और तकनीकी रिपोर्ट भी तैयार की है जो एसएमएस और नियोजन प्रभाग के लिए बहुत उपयोगी है।

परियोजना : डिजिटल रेडियो प्रसारण (डीटीई सं.: 05 /2009–10) के लिए प्रसारण उपाय और रिसेप्शन सर्वेक्षण प्रणाली का विकास।

अधिकांश डीटीई वस्तुओं जैसे हाथ में पकड़े जाने वाला स्पेक्ट्रम विश्लेषक, सॉफ्टवेयर के साथ लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, रंगीन प्रिंटर, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, पोर्टेबल जैनसेट, मोबाइल वैन, रिसीविंग एंटीना, यूपीएस बैक अप 60 मिनट, डीआरएम कमर्शियल रेडियो रिसीवर, हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर के साथ लैपटॉप आधारित डीआरएम रिसीवर, स्प्लिट एयर–कंडीशनर और टेक की खरीद कर ली गई है। फर्नीचर, इलक्ट्रोमैकेनिकल मास्ट और डीआरएम संदर्भ निगरानी विश्लेषक की भी खरीद कर ली गई है। मोबाइल / सर्वेक्षण वैन संबंधी कार्य पूरा हो चुका है और मोबाइल रेडियो वैन उपयोग के लिए तैयार है।

?k½ /ofud lsag % 11वीं योजना के तहत ध्वनिक प्रयोगशाला का उन्नयन और आधुनिकीकरण :

ध्वनिक प्रयोगशाला, आकाशवाणी और दूरदर्शन में मौजूदा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार ध्वनिक सामग्री

और नवनिर्मित स्टूडियो के विभिन्न ध्वनिक कार्य कर रही है। 1 अप्रैल, 2018 से 31 अक्तूबर, 2018 की अवधि के दौरान, निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:

विभिन्न निजी कंपनियों/ओईएम के संबंध में वाणिज्यिक आधार पर ध्वनिक सामग्री के एनआरसी और एसटीसी परीक्षण (14 नमूने) किए गए और राजस्व के रूप में 1,99,892 रु. अर्जित किए गए।

1. एनेचोइक चैंबर का नवीनीकरण/प्रतिस्थापन पूरा होने वाला है।

2. एनबीएच स्टूडियो का शोर मापन किया गया है।

vkbl,evkjlh] VkMkiij % 11oh ;ktuk d rgr vkbl,evkjlh] VkMkiij dk mUu;u vkj vk/kfudhdj.k%

1. आईएमआरसी, टोडापुर के लिए एक्टिव रिसीविंग एंटीना की खरीद की गई है।

2. दो सी–बैंड आरएन टर्मिनल को आईएमआरसी, टोडापुर में स्थापित और चालू किया गया है।

M½ Mhvkj,e i;kx'kkyk%

सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और डीआरएम रिसीवर का विकास प्रगति पर है।

p½ MhVh,p flXuy e,fuVfjx i;kx'kkyk%

दूरदर्शन निदेशालय के निर्देशों और केन्द्र सरकार की अधिसूचना एस.ओ. 2693 (ई) दिनांक 5 सितंबर, 2013 को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 8 की उप–धारा (1) के तहत, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अनुसंधान विभाग, ने जनवरी 2014 में विभिन्न निजी डीटीएच प्लेटफार्मों अर्थात टाटा स्काई, डिश टीवी, सन डायरेक्ट, एयरटेल, रिलायंस बिग टीवी, वीडियोकॉन डी 2 एच पर अनिवार्य रूप से दिखाए जाने वाले दूरदर्शन के 25 चैनलों की निगरानी के लिए एक पूर्ण सेटअप स्थापित किया था। अनुसंधान विभाग, उपरोक्त निजी डीटीएच सेवा प्रदाताओं की श्रव्य और दृश्य गुणवत्ता का अधिकरण संबंधी मूल्यांकन डीटीएच प्रयोगशाला में कर रहा है। छह प्राइवेट डीटीएच प्लेटफॉर्म पर 25 अनिवार्य चैनलों का मतलब है कुल (25ग6) 150 चैनलों की निगरानी और निशुल्क डिश डीडी चैनलों के साथ गुणवत्ता की तुलना करना। उपर्युक्त के संबंध में मासिक रिपोर्ट नियमित रूप से दूरदर्शन निदेशालय को, प्रसार भारती और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए भेजी जा रही है। यदि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 8 की उप–धारा (1) के तहत, अधिसूचना एस.ओ. 2693 (ई) दिनांक 5 सितंबर, 2013 के अनुरूप कोई अनिवार्य डीडी चैनल किसी भी डीटीएच निजी प्रदाता द्वारा नहीं दिखाया जा रहा है तो इस बारे में दूरदर्शन निदेशालय और सेवा प्रदाता को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया है। अनुसंधान विभाग दूरदर्शन निदेशालय के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करता है। निजी प्लेटफार्मों पर निशुल्क चैनल दिखाने के लिए डीटीएच के रीचार्ज के लिए लगभग 18000 रु. वार्षिक शुल्क का भुगतान अनुसंधान और विकास के ओ.ई. प्रमुख की ओर से किया जा रहा है।

njn'ku

दूरदर्शन – शाब्दिक रूप से दूर से एक झलक – 15 सितंबर, 1959 को लोक सेवा प्रसारण में एक मामूली प्रयोग की शुरुआत से लेकर, डिजिटल संचार के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी बनकर भारत के कायापलट का चेहरा बना है। यह प्रयोग 1965 में एक सेवा बन गया, जब दूरदर्शन ने देश की राजधानी, नई दिल्ली और उसके आस–पास के इलाकों तक पहुंचने के लिए सिग्नलों को दीप्तीमान करना शुरू किया। वर्ष 1972 तक, सेवाओं का विस्तार मुंबई तथा अमृतसर और 1975 तक सात और शहरों तक किया गया। उस समय यह आकाशवाणी का हिस्सा था। 1 अप्रैल, 1976 को इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक अलग विभाग बना और बाद में यह प्रसार भारती के अंतर्गत आ गया।

lxBukRed lajpuk

दूरदर्शन का प्रमुख महानिदेशक होता है जिसकी सहायता कार्यक्रम विंग और प्रशासन तथा वित्त विंग में अतिरिक्त महानिदेशक, इंजीनियरिंग विंग में इंजीनियर–इन–चीफ और समाचार विंग में महानिदेशक (समाचार) करते हैं।

नीति निर्माण, नियोजन तथा विकास, बुनियादी ढांचे तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन, बजटीय नियोजन तथा नियंत्रण, मानव संसाधन प्रबंधन, संचालन कार्यों की निगरानी और रखरखाव गतिविधियों आदि की देखरेख महानिदेशक, दूरदर्शन की जिम्मेदारी है।

इसके अलावा, छह प्रोग्रामिंग जोन–दिल्ली (उत्तर क्षेत्र), मुंबई (पश्चिम क्षेत्र), चेन्नई (दक्षिण क्षेत्र), लखनऊ (मध्य क्षेत्र), कोलकात्ता (पूर्व क्षेत्र) और गुवाहाटी (उत्तर पूर्व क्षेत्र) महानिदेशक को रिपोर्ट करते हैं। समानांतर में, चार इंजीनियरिंग क्षेत्रीय कार्यालय एक–एक अतिरिक्त महानिदेशक (अभियांत्रिकी) की

अध्यक्षता में परियोजना और रखरखाव गतिविधियों के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों में रखरखाव गतिविधियों के लिए गुवाहाटी में एक अन्य क्षेत्रीय कार्यालय है। दूरदर्शन के विभिन्न प्रतिष्ठान हैं– दूरदर्शन केंद्र (स्टूडियो सेंटर), हाई पावर ट्रांसमीटर (एचपीटी), रखरखाव केंद्र, कम शक्ति के ट्रांसमीटर (एलपीटी) और बहुत कम शक्ति के ट्रांसमीटर (वीएलपीटी)।

or|eku rduhdh l|jpuk

दूरदर्शन के पास 67 स्टूडियो केंद्रों का एक विशाल नेटवर्क है। देशभर में 67 स्टूडियो केंद्र इन–हाउस कार्यक्रम निर्माण की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इनमें राज्यों की राजधानियों में 17 प्रमुख स्टूडियो केंद्र, गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय निर्माण केंद्र और देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 49 अन्य स्टूडियो केंद्र शामिल हैं। 67 स्टूडियो केंद्रों में से 63 पहले ही पूरी तरह से डिजिटल हो चुके हैं। शेष 4 स्टूडियो केंद्र एनालॉग हैं।

पिछले कुछ वर्षों में डीडी नेटवर्क के विकास का चित्रण निम्न प्रकार किया गया है। यह गौर करने योग्य है कि दूरदर्शन के पास स्टूडियो बुनियादी ढांचे के अलावा, अलग–अलग शक्ति के 1108′ टैरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर भी हैं। दूरदर्शन फ्री–टू–एयर डीटीएच सेवा भी प्रदान करता है।

दूरदर्शन का टैरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर नेटवर्क मुख्य रूप से एनालॉग ट्रांसमीटरों से युक्त होता है। दूरदर्शन द्वारा इस्तेमाल की गईं नई तकनीकें डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन (डीटीटी) का उपयोग करके एकल ट्रांसमीटर के साथ कई टीवी चैनलों को प्रसारित करना संभव बनाती हैं। यह एनालॉग टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन को डीटीटी में परिवर्तित करने की वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है और इसके कई फायदे हैं, जैसे कि चित्र तथा ध्वनि की बेहतर गुणवत्ता, दर्शकों के लिए बड़ी संख्या में चैनल आदि। आधुनिक प्रसारण प्रवृत्तियों के मद्देनजर प्रसार भारती ने एनालॉग टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने और डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों की स्थापना को मंजूरी दी है। तदनुसार, दूरदर्शन ने अपने एनालॉग ट्रांसमीटरों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना शुरू कर दिया है। स्टूडियो केंद्रों की राज्यवार सूची अनुलग्नक– I में दी गई है।

टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीशन के लिए, देश के हर कोने में अलग–अलग शक्ति के 1108 ट्रांसमीटरों की स्थापना की गई है। ट्रांसमीटरों की राज्यवार सं अनुलग्नक–II में दी गई है।

टेरेस्ट्रियल एनालॉग टीवी ट्रांसमीटरों को जारी रखने की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने आधुनिक प्रसारण रुझानों के मद्देनजर 766 एनालॉग टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर (एटीटी) को बंद करने की सिफारिश

njn'ku dnk e of)

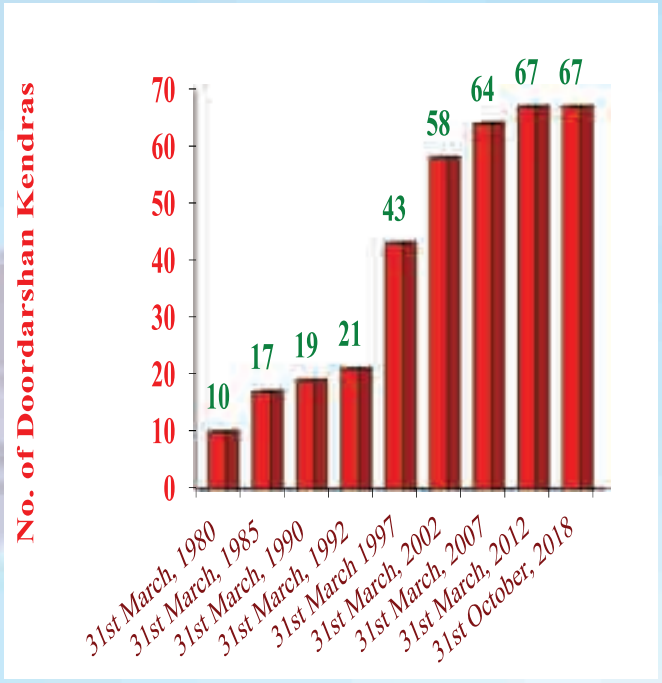

njn'ku Vk lehVj e of)

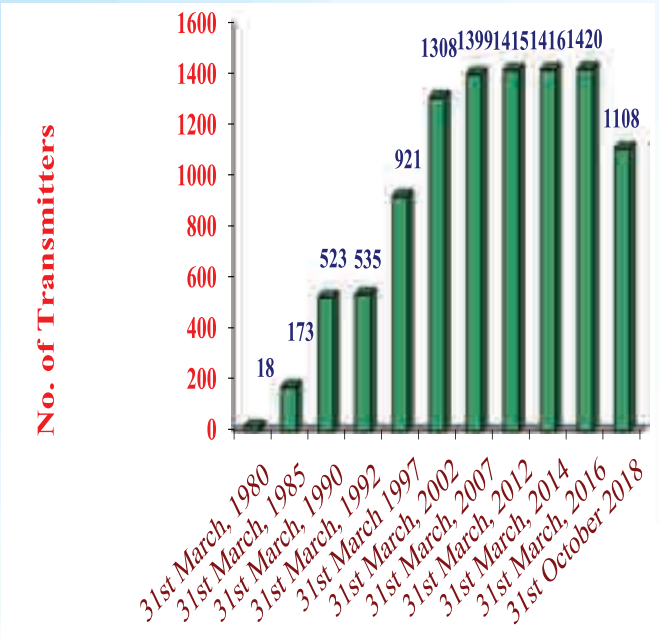

की। प्रसार भारती ने चरणबद्ध तरीके से 766 एटीटी को बंद करने को मंजूरी दी और तदनुसार, पहले चरण में 268 एटीटी को बंद कर दिया गया। एटीटी को बंद करने के दूसरे चरण के तहत, अपने उपयोगी समय के 15 साल पूरे करने वाले 236 एमएलपीटी, वीएलपीटी, ट्रांसपोजर्स और 214 ट्रांसमीटर (एलपीटी–169, वीएलपीटी–45) को बंद करने के आदेश क्रमश 16.10.2018 और 18.10.2018 को जारी किए गए हैं।

उपग्रह संचार के लिए, दूरदर्शन ने एमपीईजी–2 और एमपीईजी–4 कम्प्रेशन टेक्नालॉजी के साथ डीवीबी–एस और डीवीबी–एस2 मानकों को अपनाया है। दूरदर्शन वर्तमान में 34 उपग्रह चैनलों का संचालन कर रहा है। विवरण अनुलग्नक III में दिए गए हैं।

njn'ku uVodZ ekufp=

o"k d nkjku egRoi.k fodklkRed xfrfof/k;k %

i. तीन, नए, हाई पावर डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर (डीटीटी) को श्रीनगर (जम्मू–कश्मीर), हैदराबाद (तेलंगाना) और तिरुअनंतपुरम (केरल) में चालू किया गया है। डिजिटल एचपीटी ने मल्टीपल टीवी और रेडियो चैनलों को रिले के लिए सक्षम किया है।

ii. डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर (डीटीटी) का एक दूसरा चरण दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी शुरू किया गया है।

iii. एकीकृत समाचार उत्पादन सुविधा, समाचार मुख्यालय, नई दिल्ली में चालू की गई है।

iv. डिब्रुगढ़ (असम) में पुराने, उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (एचपीटी) के स्थान पर नए 10 किलोवाट एचपीटी लगाए गए हैं।

v. 56 हाई डेफिनिशन नॉन लीनियर एडिटिंग सिस्टम (एनएलई) की खरीद की गई है। इनसे लाभार्थी केंद्रों के दिन–प्रतिदिन के कार्यक्रम निर्माण में उत्पादन के बाद की सुविधाएं एचडी मोड में बढ़ सकेंगी।

vi. 09 स्थानों (गंगटोक, कोहिमा, इंफाल, अगरतला, इलाहाबाद, विशाखापत्तनम, चंडीगढ़, जगदलपुर और पुणे) पर नई डीएसएनजी वैन उपलब्ध कराई गईं। ये लाइव प्रसारण के उद्देश्य से इन केंद्रों की कार्यक्रम योगदान क्षमता को मजबूत करेंगी।

vii. स्पेक्ट्रम की तैनाती के बाद, जीसैट–16 सैटेलाइट पर 12 मेगाहर्ट्ज केयू–बैंड ट्रांसपोंडर क्षमता, दक्ष डीवीबी–एस2, सुन्मय केयू–बैंड डीएसएनजी को हटा दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप सालाना 2.98 करोड़ रुपये की बचत होगी।

viii. नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) अर्थ स्टेशन से ज्ञानदर्शन टीवी चैनल को अप–लिंक करने के लिए डब्ल्यूपीसी से वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है। इग्नू ने दूरदर्शन के साथ एक समझौता किया है।

ie[k ifj;kstuk,j ftUg dk;kfUor fd;k tk jgk g %

1) पटना, हैदराबाद, बंगलुरु, डीडीके दिल्ली और सीपीसी दिल्ली में अर्थ स्टेशनों का आधुनिकीकरण।

2) अरुणप्रभा और किसान चैनलों के लिए 16 हाई डेफिनिशन नॉन लाइनियर एडिटिंग सिस्टम (08 स्थान)।

3) जम्मू, श्रीनगर और लेह क्षेत्रों के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले 10 किलोवाट डिजिटल–तैयार यूएचएफ एनालॉग टीवी ट्रांसमीटर।

4) रायपुर, रांची, देहरादून, श्रीनगर और गोरखपुर में अर्थ स्टेशनों का उन्नयन।

gkbZ MsfQfu'ku Vhoh ¼,pMhVhoh½

दूरदर्शन का एचडीटीवी में स्थानांतरण 2007 में एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरू हुआ और दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक फील्ड प्रोडक्शन (ईएफपी) वैन तथा एचडीटीवी ईएनजी कैमकोर्डर और एडिट सूट उपलब्ध कराया गया। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान एचडी ईएफपी वैन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था।

मल्टी–कैमरा एचडी स्टूडियो निर्माण सुविधाएं स्थापित की गई हैं और 11वीं योजना के दौरान दिल्ली और मुंबई में 10 एचडी कैमरों से सुसज्जित आउटडोर निर्माण के लिए मल्टी–कैमरा मोबाइल सुविधा प्रदान की गई है। दिल्ली में प्लेआउट सुविधा स्थापित करने के अलावा चार महानगरों में ईएनजी आधारित निर्माण, निर्माण पश्चात और पूर्वावलोकन सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बाहरी निर्माण के लिए आठ एचडी कैमरों से लैस मल्टी–कैमरा मोबाइल सुविधाएं चेन्नई और कोलकाता में भी उपलब्ध कराई गई हैं।

12वीं योजना के भाग के रूप में, एचडीटीवी प्रारूप में एक मल्टी कैमरा स्टूडियो निर्माण सुविधा को सीपीसी, दिल्ली में स्थापित किया गया है। दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली में एचडीटीवी अपलिंकिंग की सुविधा उपलब्ध है।

ekuo lalk/ku fodkl

एनएबीएम अकादमी की स्थापना के बाद से इंजीनियरिंग कर्मचारियों के लिए रेडियो और टीवी निर्माण तथा प्रसारण के क्षेत्र में प्रशिक्षण का आयोजन कर रहा है। एनएबीएम, समय के साथ–साथ रेडियो और टेलीविजन निर्माण, पोस्ट–प्रोडक्शन और प्रसारण के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने वाला और एशिया–प्रशांत क्षेत्र में प्रसारकों के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में अग्रणी संगठन बन गया है।

भारत

वर्तमान दूरदर्शन नेटवर्क

(अक्टूबर ३१, २०१८ की स्थिति के अनुसार)

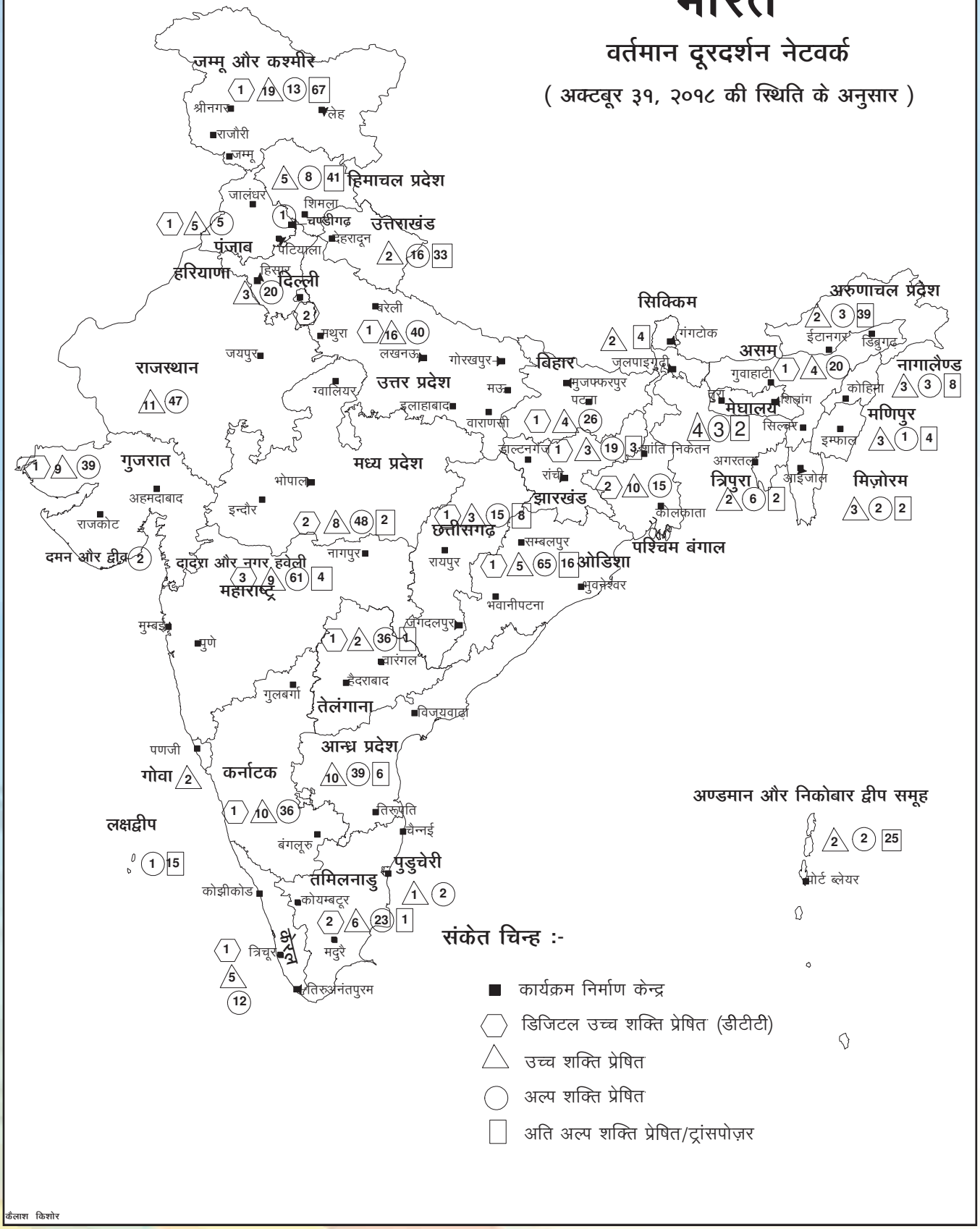

कैलाश किशोर

अकादमी में 7000 से अधिक तकनीकी पुस्तकों के संग्रह वाला एक पुस्तकालय है। अकादमी में 120 कमरों वाले छात्रावास में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। आरएबीएम मलाड में बहुत सीमित प्रशिक्षण सुविधाएं है।

अकादमी द्वारा हर साल हजार से अधिक इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया जाता है। दूरदर्शन कर्मचारियों के लिए नियमित पाठ्यक्रमों के अलावा निम्नलिखित विशेष पाठ्यक्रम / सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं।

i. एमडीआई गुरुग्राम में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए ''स्वयं के प्रबंधन और अन्य के नेतृत्व'' के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

ii. यूएए नैनीताल में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम।

iii. एलएंडटी वडोदरा में स्विचगियर असेंबली के इलेक्ट्रिकल डिजाइन पर कार्यशाला।

iv. दूरदर्शन केंद्र, श्रीनगर में डीटीटी कार्यशाला।

लगभग 336 दूरदर्शन इंजीनियरिंग अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके लिए 27 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अप्रैल 2018 और अक्तूबर 2018 के बीच आयोजित किए गए। इसके अलावा, ''इंजीनियरिंग छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण'' पर एक कोर्स आयोजित किय गया जिसमें तीन सौ चौबीस उम्मीदवारों ने भाग लिया था और महाराष्ट्र में पॉलिटेक्निक के संकाय के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में चौबीस सदस्यों ने भाग लिया।

इसके अलावा, उपकरण विनिर्माण द्वारा उनके केंद्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। नेटवर्क में शामिल किए जा रहे नए उपकरणों के लिए उपकरण निर्माताओं द्वारा विभिन्न ए/टी पर चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 188 इंजीनियरिंग अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

Ýh&V&,;j MhVh,p ^^MhMh Ýh fM'k^^

दूरदर्शन ने दिसंबर 2004 में 33 टीवी चैनलों के साथ अपनी फ्री–टू–एयर डीटीएच सेवा "डीडी फ्री डिश" (पहले डीडी डायरेक्ट प्लस़) शुरू की। बाद में डीटीएच प्लेटफार्म की क्षमता बढ़ाकर 59 टीवी चैनल कर दी गई। छोटे आकार की डिश रिसीवर इकाइयों की मदद से देश में कहीं भी (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर) डीटीएच सिग्नल प्राप्त किए जा सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सितंबर, 2009 से 10 चैनलों के साथ सी–बैंड में डीटीएच सेवा शुरू की गई थी। दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म ''डीडी फ्री डिश'' के 59 से 104 चैनलों का उन्नयन दिसंबर, 2014 में पूरा हो गया था और वर्तमान में, 80 टीवी चैनल डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

104 टीवी चैनलों के लिए डीडी फ्री डिश डीटीएच प्लेटफार्म का भी उन्नयन एमपीईजी–4 डीवीबी–एस 2 प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डीडी फ्री डिश डीटीएच प्लेटफॉर्म के लिए विकसित आईसीएएस की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का काम पूरा हो गया है। इसके अलावा, दूरदर्शन ने दर्शकों को दक्ष और मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए आईसीएएस सक्षम नई पीढ़ी सेट टॉप बॉक्स 'की भी शुरुआत की है। आईसीएएस सक्षम डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स की बिक्री, वितरण के लिए ग्यारह भारतीय सेट–टॉप–बॉक्स निर्माताओं की सूची बनाई गई है।

12वीं योजना के तहत डीडी के डीटीएच प्लेटफॉर्म के 250 टीवी चैनलों तक के और उन्नयन को मंजूरी दी गई है।

डीडी फ्री डिश चैनलों का 01.11.2018 तक का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक– IV में दिया गया है।

V|jfLV';y Vk lehVjk dk fMftVyhdj.k

डीटीटी कई उच्च गुणवत्ता वाले चैनलों के प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है जो विभिन्न उपकरणों जैसे कि फिक्स्ड टीवी, मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट आदि पर प्राप्त की जा सकती हैं।

11वीं और 12वीं योजना परियोजनाओं के तहत, 63 डीटीटी ट्रांसमीटरों को चरणबद्ध तरीके से देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। पहले चरण में, स्थापित किए जाने वाले 19 डीटीटी ट्रांसमीटरों में से एक–एक, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पटना, अहमदाबाद, रायपुर, लखनऊ, भोपाल, गुवाहाटी, इंदौर, बंगलुरु, जालंधर, रांची, कटक, औरंगाबाद, हैदराबाद तिरुअनंतपुरम और श्रीनगर में चालू किया गया है। ये डीटीटी ट्रांसमीटर, 5 डीडी चैनल जैसे कि डीडी नेशनल, डीडी न्यूज़, डीडी भारती, डीडी स्पोर्ट्स और डीडी किसान, क्षेत्रीय रिले कर रहे हैं। एक दूसरा डिजिटल टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर (डीटीटी) दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी शुरू किया गया है। 63 डीटीटी ट्रांसमीटरों के स्थान अनुलग्नक– V में दिए गए हैं।

njn'ku dæ ¼LVfM;k lVj½

jkT;@dUæ 'kkfl r çn'k	स्थान
vk/k çn'k	विजयवाड़ा
	तिरुपति
v#.kkpy çn'k	ईटानगर
vle	डिब्रूगढ़
	गुवाहाटी
	गुवाहाटी (पीपीसी)
	सिल्चर
fcgkj	पटना
	मुजफ्फरपुर
NÙkh l x<	जगदलपुर
	रायपुर
xkok	पणजी
x| t jkr	अहमदाबाद
	राजकोट
gfj ;k.kk	हिसार
fgekpy çn'k	शिमला
tEe vkj d'ehj	श्रीनगर
	जम्मू
	लेह
	राजौरी
>kj[kM	रांची
	डाल्टनगंज
dukVd	बंगलुरु
	गुलबर्गा
djy	कोझिकोड
	तिरुअनंतपुरम
	त्रिचुर
e/; çn'k	भोपाल
	इंदौर
	ग्वालियर
egkjk"V	मुंबई
	नागपुर
	पुणे
ef.kij	इंफाल
e?kky;	शिलांग
	तुरा
fe tkje	आईज़ोल
uxkyM	कोहिमा
vkfM'kk	भुवनेश्वर
	भवानीपाटन
	संबलपुर
i t kc	जालंधर
	पटियाला
jk t LFkku	जयपुर
f l fDde	गंगटोक
rfeyukM	चेन्नई
	कोयंबटूर
	मदुरै
r y xkuk	हैदराबाद
	वारंगल
f=ijk	अगरतला
mÙkj çn'k	इलाहाबाद
	बरेली
	लखनऊ
	गोरखपुर
	मऊ
	वाराणसी
	मथुरा
mÙkjk[kM	देहरादून
if'pe cxky	कोलकाता
	शांतिनिकेतन
	जलपाईगुड़ी
vMeku fudkckj }hi leg	पोर्टब्लेयर
pMhx<	चंडीगढ़
fnYyh	दिल्ली
	दिल्ली(सीपीसी)
iÌpjh	पुद्दुचेरी

Ø- l-	jkT;@dsUnz'kkflr izns'k	njn'ku (31.10.2018 dk)													
		Vkl ehVj dh l-													
		ikFkfed pSuy (MhMh1)					lekpkj pSuy (njn'ku lekpkj)				MhMh Vkl ehVj fjykbx {k=h; dk;Øe iLkj.k dh ijh vof/k dk nkjku				MhVh
		एचपी. टी	एलपीटी	वीएलपी. टी	टी. आर पी	कुल	एचपीटी	एलपी. टी	वीएलपी. टी	कुल	एचपी. टी	एलपी. टी	वीएल. पीटी	कुल	एचपीटी
1	आंध्र प्रदेश	7	33			40	3	6		9			6	6	
2	अरुणाचल प्रदेश	1	3	39		43	1			1				0	
3	असम	3	19			22	1	1		2				0	1
4	बिहार	3	25			28	1	1		2				0	1
5	छत्तीसगढ़	3	15	8		26				0				0	1
6	गोवा	1				1	1			1				0	
7	गुजरात	6	36			42	3	3		6				0	1
8	हरियाणा	2	13			15	1	7		8				0	
9	हिमाचल प्रदेश	3	7	39	2	51	2	1		3				0	
10	जम्मू और कश्मीर	10	7	60	1	78	5	3		8	4	3	6	13	1
11	झारखंड	2	17	2		21	1	2	1	4				0	1
12	कर्नाटक	7	35			42	3	1		4				0	1
13	केरल	3	10			13	2	2		4				0	1
14	मध्य प्रदेश	6	48	2		56	2			2				0	2
15	महाराष्ट्र	6	53			59	3	8		11			4	4	3
16	मणिपुर	2	1	4		7	1			1				0	
17	मेघालय	2	3	2		7	2			2				0	

18	मिजोरम	2	1	2		5	1	1		2				0	
19	नगालैंड	2	2	6	2	12	1	1		2				0	
20	ओडिशा	4	60		1	65	1	5	1	7			14	14	1
21	पंजाब	3	4			7	2	1		3				0	1
22	राजस्थान	7	43			50	4	4		8				0	
23	सिक्किम	1		4		5	1			1				0	
24	तमिलनाडु	5	17			22	1	6		7			1	1	2
25	तेलंगाना	2	36			38				0			1	1	1
26	त्रिपुरा	1	5	1	1	8	1	1		2				0	
27	उत्तर प्रदेश	10	35			45	6	5		11				0	1
28	उत्तराखंड	1	15	31	2	49	1	1		2				0	
29	पश्चिम बंगाल	7	13			20	3	2		5				0	2
30	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	1	1	19		21	1	1	6	8				0	
31	चंडीगढ़		1			1				0				0	
32	दादर और नगर हवेली					0				0				0	
33	दमन और दीव		2			2				0				0	
34	दिल्ली					0				0				0	2
35	लक्षद्वीप समूह		1	1		2			7	7			7	7	
36	पुद्दुचेरी	1	1			2		1		1				0	
	कुल	114	562	220	9	905	55	64	15	134	4	3	39	46	23
		ट्रांसमीटरों की कुल संख्या				1108									

दूरदर्शन उपग्रह चैनल

अखिल भारतीय चैनल (6)	डी.डी नेशलन	डी.डी न्यूज़	डी.डी स्पोर्ट्स
	डी.डी भारती	डी.डी उर्दू	डी.डी किसान
क्षेत्रीय चैनल (16)	डी.डी मलयालम	डी.डी चांदना	डी.डी यदागिरी
	डी.डी पोधिगई	डी.डी सहयाद्री	डी.डी गिरनार
	डी.डी उडिया	डी.डी कशीर	डी.डी पूर्वोत्तर
	डी.डी बांग्ला	डी.डी पंजाबी	डी.डी राजस्थान
	डी.डी बिहार	डी.डी उत्तरप्रदेश	डी.डी मध्यप्रदेश
	डी.डी सप्तगिरी		
राज्य नैटवर्क्स (11)	हिमाचल प्रदेश	झारखंड	चंडीगढ़
	हरियाणा	उत्तराखंड	त्रिपुरा
	मिज़ोरम	मेघालय	मणिपुर
	अरूणाचल प्रदेश	नगालैंड	

vuqyXud **-IV**

उपग्रह जीसैट 15, 93.5 ई

टीएस -1	टीएस -2	टीएस -3	टीएस -4	टीएस -5	टीएस -6 (टेस्ट)
फ्रीक्वेंसी (मेगाहर्टस) यू/एल -14140 डी/एल - 11090, एस.आर. - 29.5 एमएसपीएस, एफईसी - 3/4	फ्रीक्वेंसी (मेगाहर्टस) यू/एल -14220 डी/एल - 11170, एस.आर. - 29.5 एमएसपीएस, एफईसी - 3/4	फ्रीक्वेंसी (मेगाहर्टस) यू/एल -14270 डी/एल - 11470, एस.आर.- 29.5 एमएसपीएस, एफईसी - 3/4	फ्रीक्वेंसी (मेगाहर्टस) यू/एल -14310 डी/एल - 11510, एस.आर. -29.5 एमएसपीएस, एफईसी - 3/4	फ्रीक्वेंसी (मेगाहर्टस) यू/एल -14350 डी/एल - 11550, एस.आर. .- 29.5 Msps, एफईसी - 3/4	फ्रीक्वेंसी (मेगाहर्टस) यू/एल -14430 डी/एल - 11630, एस.आर. - 30 एमएसपीएस, एफईसी - 3/5

चैनल (As per एमपीईजी 4 सेट टॉप बॉक्स डीकोडिंग के अनुरूप)

1. डी.डी नेशलन	17. डी.डी राजस्थान	33. नापतोल ब्लू	49. बिग मैजिक	65. मनोरंजन मूवी	81. टेस्ट 601	
2. डी.डी न्यूज़	18. डी.डी उड़िया	34. डी.डी उर्दू	50. टेस्ट 402	66. मूवी हाउस	82. टेस्ट 602	
3. डी.डी स्पोर्ट्स	19. डी.डी पोधिगई	35. सिनेमा TV	51. 9X एम	67. हाउसफुल मूवीज	83. $ टेस्ट 603	
4. डी.डी किसान	20. डी.डी पंजाबी	36. डी.डी सप्तगिरि	52. महा मूवी	68. स्टार उत्सव मूवीज	84. $ टेस्ट 604	
5. डी.डी भारती	21. डी.डी सहयाद्री	37. इंडिया टीवी	53. ज़ी हिंदुस्तान	69. टेस्ट 505	85. $ टेस्ट 605	
6. डी.डी बांग्ला	22. डी.डी यदागिरि	38. वोव सिनेमा	54. स्टार उत्सव	70. ज़ी अनमोल सिनेमा	86. $ टेस्ट 606	
7. डी.डी चांदना	23. डी.डी मलयालम	39. मनोरंजन टीवी	55. ज़ी अनमोल	71. हाउसफुल एक्शन	87. $ टेस्ट 607	97. $ टेस्ट 617

8. डी.डी गिरनार	24. लोकसभा	40. न्यूज़ नेशन	56. मस्ती	72. टेस्ट 508	88. $ टेस्ट 608	98. टेस्ट 618
9. डी.डी कशीर	25. राज्यसभा	41. सोनी पाल	57. बी -4यू म्यूज़िक	73. चढ़दीकला टाइम टीवी	89. $ टेस्ट 609	99. टेस्ट 619
10. टेस्ट 110	26. टेस्ट 210	42. दबंग	58. टेस्ट 410	74. डी.डी इंडिया	90. टेस्ट 610	100. टेस्ट 620
11. टेस्ट 111	27. दंगल	43. रिश्ते	59. न्यूज़ राज्य उ.प्र./उत्तराखंड	75. 9X जलवा	91. $ टेस्ट 611	101. टेस्ट 621
12. बी -4यू मूवीज़	28. भोजपुरी सिनेमा	44. सोनी मिक्स	60. न्यूज़ 24	76. रिश्ते सिनेप्लैक्स	92. $ टेस्ट 612	102. टेस्ट 622
13. टेस्ट 113	29. डी.डी बिहार	45. होमशॉप 18	61. सोनी वाह	77. स्टार स्पोर्ट फर्स्ट	93. $ टेस्ट 613	103. टेस्ट 623
14. इंडिया न्यूज़	30. डी.डी पूर्वोत्तर	46. डी.डी एमपी	62. आजतक	78. एमटीवी बीट्स	94. $ टेस्ट 614	104. टेस्ट 624
15. न्यूज़ 18 इंडिया	31. डी.डी उ.प्र.	47. एन्टैर्र - 10	63. एबीपी न्यूज़	79. न्यूज़ 18 राजस्थान	95. $ टेस्ट 615	
16. बिग मैजिक गंगा	32. साधना नैशनल	48. स्टार भारत	64. ज़ी न्यूज़	80. न्यूज़ 18 उ.प्र./उत्तराखंड	96. $ टेस्ट 616	
J0; puy (,eihbith 4 lV Vki ckDl MhdkfMx d vulkj)						
MhMCY;Mh,l lok	MhMCY;Mh,l lok	MhMCY;Mh,l lok	MhMCY;Mh,l lok	----------	---------	
1. आकाशवाणी वि.वि.से.	9. आकाशवाणी गुजराती	17. आकाशवाणी कन्नड़	25. आकाशवाणी रागम	33. आकाशवाणी कोहिमा	च. 2901	
2. आकाशवाणी तेलुगू	10. रेनबो दिल्ली	18. आकाशवाणी बांग्ला	26. रेनबो बंगलूरू	34. आकाशवाणी आईजोल	च. 2902	
3. आकाशवाणी मराठी	11. आकाशवाणी पंजाबी	19. आकाशवाणी हिंदी	27. आकाशवाणी उर्दू	35. आकाशवाणी इटानगर	च. 2903	
4. आकाशवाणी तमिल	12. एफएम गोल्ड दिल्ली	20. आकाशवाणी पूर्वोत्तर	28. आकाशवाणी उड़िया	36. आकाशवाणी अगरतला	च. 2904	
5. आकाशवाणी नेशनल	13. रेडियो कश्मीर	21. रेनबो चेन्नई	29. आकाशवाणी मलयालम	37. आकाशवाणी रोहतक	च. 2905	
6. रेनबो कोलकाता	14. आकाशवाणी लखनऊ	22. एफएम गोल्ड मुंबई	30. आकाशवाणी असमी	38. आकाशवाणी शिमला	च. 2906	
7. आकाशवाणी विजयवाड़ा	15. आकाशवाणी पटना	23. आकाशवाणी जयपुर	31. एफएम गोल्ड चेन्नई	39. आकाशवाणी वाराणसी	च. 2907	
8. आकाशवाणी इंफाल	16. आकाशवाणी भोपाल	24. रेनबो मुंबई	32. एफएम गोल्ड कोलकाता	40. ज्ञानवाणी	च.2908	
					सबटाइटल स्ट्रीम	
					एमएसटीएआर ओटीए	
					एएलआई ओटीए	
					एसटी ओटीए	
16 Vhoh + **8** jfM;k	**16** Vhoh + **8** jfM;k	**16** Vhoh + **8** jfM;k	**16** Vhoh + **8** jfM;k	**16** Vhoh + **8** jfM;k		
कुल टीवी चैनल : 72 + 32 टेस्ट (एमपीईजी -2 में क्षमता 80 चैनल एमपीईजी 4 में + 24) कुल रेडियो चैनल : 40 (एमपीईजी -2 में क्षमता 40)						

01.11.2018 तक डी.डी फ्री डिश चैनलों का संक्षिप्त ब्योरा

mPp 'kfDr Vhoh Vkl ehVj ifj;kstuk,¡				
Ø-la-	jkT;@dsæ 'kkflr çns'k	11oha ;kstuk dh fgLls dh :Ik esa Lohd`r		12oha ;kstuk ds fgLls ds :Ik esa Lohd`r
		pj.k I – 19 la (pkyw fd, tkus ds ckn)	pj.k II – la- 21	la- 23
1	आंध्र प्रदेश		विजयवाड़ा	तिरुपति
2	अरुणाचल प्रदेश			ईटानगर
3	असम	गुवाहाटी		
4	बिहार	पटना		मुजफ्फरपुर
5	छत्तीसगढ़	रायपुर		जगदलपुर
6	गुजरात	अहमदाबाद	सूरत	
			वडोदरा	
			राजकोट	
7	हरियाणा			हिसार
8	हिमाचल प्रदेश		कसौली	शिमला
9	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर		जम्मू
10	झारखंड	रांची		जमशेदपुर
11	कर्नाटक	बंगलुरु	मैसूर	शिमोगा
				धरवाड़
12	केरल	तिरुअनंतपुरम	कोच्चि	कोझिकोड
13	मध्य प्रदेश	भोपाल	ग्वालियर	
		इंदौर		
14	महाराष्ट्र	मुंबई	नागपुर	अंबाजोगई
		औरंगाबाद	पुणे	
15	मणिपुर			चूड़ाचांदपुर
16	मेघालय			शिलांग
17	मिज़ोरम			लुंगलेई
18	नगालैंड			मोकोकचुंग
19	ओडिशा	कटक		बालासोर (बालेश्वर)
20	पंजाब	जालंधर	अमृतसर	
21	राजस्थान		जयपुर	बूंदी
				बाड़मेर
22	सिक्किम			गंगटोक
23	तमिलनाडु	चेन्नई	कोडईकनाल	रामेश्वरम
24	तेलंगाना	हैदराबाद		
25	त्रिपुरा			अगरतला

26	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	कानपुर	
			वाराणसी	
			इलाहाबाद	
			आगरा	
			बरेली	
27	उत्तराखंड		मसूरी	
28	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कुरसियांग	आसनसोल
			कृष्णानगर	
29	दिल्ली	दिल्ली		

U;w ehfM;k foax

^^U;w ehfM;k foax^^ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए सूचना सेवा इकाई के रूप में कार्य करता है। यह मंत्रालय, इसकी मीडिया इकाइयों और जनसंचार में लगे अन्य लोगों के उपयोग के लिए पृष्ठभूमि, संदर्भ और शोध सामग्री उपलब्ध कराता है। यह विंग सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया प्रचार, सार्वजनिक सूचना और जन–संचार संबंधी गतिविधियों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के न्यू मीडिया सेल को कार्यात्मक और परिचालन सहायता प्रदान करता है।

विंग संचार पहलुओं पर प्रशिक्षण भी आयोजित करता है और अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को सोशल मीडिया हैंडलिंग और सार्वजनिक पहुंच के संबंध में सहायता करता है।

lxBukRed lVvi

न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) का मुख्यालय सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003 में है। इसका प्रमुख महानिदेशक है जिसकी सहायता के लिए एक निदेशक, एक उप निदेशक, सहायक निदेशक और सहायक कर्मचारी होते हैं। अतिरिक्त महानिदेशक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, (ईएमएमसी) के पास न्यू मीडिया विंग का अतिरिक्त प्रभार है।

vçSy 2018 ls U;w ehfM;k foax dh xfrfof/k;k

1- lks'ky ehfM;k

1-1 ifjp;

हाल के दिनों में सोशल मीडिया बड़े पैमाने पर लोगों के बीच विविधतापूर्ण बातचीत का एक प्रभावी साधन बन गया है। इसकी संवादात्मक प्रकृति के कारण, जानकारी प्रदान करने और उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच कुशलता पूर्वक संबंध स्थापित किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का न्यू मीडिया विंग वर्चुअल दुनिया में बड़े पैमाने पर सरकार और जनता के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करके अंतःक्रियाओं को संभव बना रहा है।

मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल से संबंधित आंकड़े नीचे दी गई तालिका में संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं। ये आंकड़े नवंबर 2018 तक के हैं।

gSMy	IySVQkWe	lCLØkbcj@Qkyksvj
@एमआईबी इंडिया	ट्विटर, इंग्लिश हैंडल	962 हजार
@एमआईबी हिंदी	ट्विटर, हिंदी हैंडल	15.7 हजार
@सूचना और प्रसारण मंत्रालय	फेसबुक	1.3 मिलियन
@एमआईबी इंडिया	इंस्टाग्राम	53.8 हजार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	यू ट्यूब	90 हजार

मंत्रालय का ट्विटर हैंडल @एमआईबी इंडिया हर महीने औसतन 2 मिलियन इंप्रेशन तैयार करता है और यू ट्यूब चैनलों को प्रतिमाह 500 हजार व्यू मिलते हैं। मंत्रालय के फेसबुक पेज पर सामग्री हर महीने औसतन 389 हजार से अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचती है।

1-2 lks'ky ehfM;k lgHkkfxrk

दो अलग–अलग स्वरूपों में सोशल मीडिया सहभागिता टाकाथॉन और #फेसटूफेस, फेसबुक लाइव ने आम जनता के साथ मंत्रियों और निर्णय लेने वालों के बीच सीधे संवाद के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया है।

लाइव सोशल मीडिया संवाद, न्यू मीडिया विंग की एक अनूठी पहल रही है। इस तरह की बातचीत ने मंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों को वास्तविक समय के आधार पर जनता से जुड़ने का अवसर प्रदान किया है, जहां उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों–ट्विटर, फेसबुक आदि के माध्यम से प्राप्त

जनता के सवालों का जवाब दिया। नीति निर्माता, नागरिकों के साथ जुड़े और साथ ही नागरिक इस तरह के संवाद के माध्यम से पैनलिस्ट या अतिथि से अपने विचार, प्रश्न साझा कर पाए। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्मोत्सव 2018 के दौरान इस तरह के चार संवाद आयोजित किए गए थे।

1-3 dk;Øe vkj vk;ktuk dh dojt

न्यू मीडिया विंग भारत सरकार के कई आयोजनों और कार्यक्रमों के प्रचार और सूचना प्रसार के लिए मंत्रालय के सोशल मीडिया एकाउंट का लाभ उठाने में सक्षम रहा है।

न्यू मीडिया विंग ने सरकार के विभिन्न सोशल मीडिया अभियानों जैसे स्वच्छ भारत मिशन, पोशण अभियान का समर्थन किया है। इन्हें इन प्लेटफार्मों पर लोकप्रिय बनाने के लिए इन अभियानों के अवसरों पर सोशल मीडिया सामग्री तैयार की जाती है। इस तरह की सभी गतिविधियों को एक अन्य विभागों के साथ भी समन्वित किया गया ताकि इनका प्रभाव ज्यादा हो।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रचार के संबंध में, 65वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार और ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन की महात्मा गांधी बहु–मीडिया प्रदर्शनी जैसी गतिविधियों को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रचारित किया गया। न्यू मीडिया विंग ने 10–12 मई, 2018 के दौरान भारत में आयोजित एशिया मीट समिट के सोशल मीडिया पर प्रचार में प्रमुख भूमिका निभाई।

पणजी, गोवा में 49वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई–2018) के दौरान न्यू मीडिया विंग द्वारा फेस टू फेस नामक सोशल मीडिया संवादात्मक कार्यक्रम का आयोजन

न्यू मीडिया विंग ने सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव 2018 को व्यापक रूप से कवर किया। इन गतिविधियों का ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा जिसने इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को फ़िल्मोत्सव का हिस्सा बनने में मदद की। विंग ने जानी–मानी फ़िल्मी हस्तियों के साथ चार लाइव सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम रुफेसटूफेस आयोजित किए। मंत्रालय के हैंडल (@MIB_India vkSj @MIB_Hindi) से भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव 2018 के बारे में किए गए कई ट्वीट ने 1.2 मि. इम्प्रेशन जेनरेट किया जबकि फेसबुक पोस्ट को 1.25 मि. की पहुंच मिली है।

न्यू मीडिया विंग द्वारा सरकार की नीतियों तथा राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों तथा घटनाओं जैसे स्वतंत्रता दिवस और मन की बात को नियमित रूप से कवर किया गया और सोशल मीडिया पर प्रचार किया जाता है। विंग ने सोशल मीडिया पर कैबिनेट ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस विज्ञप्तियों को भी प्रचारित करता है।

25 मई, 2018 को नई दिल्ली में आसियान भारत फिल्म समारोह 2018 के उद्‌घाटन समारोह को संबोधित करते युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। इस अवसर पर विदेश प्रभार मंत्रालय, सचिव पूर्व ज़ोन श्रीमती प्रीती सरन एवं अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे

2- Hkkjr& okf"kd lnHk xFk

प्रकाशन विभाग, हर साल केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन और सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों द्वारा किए गए विकास और प्रगति पर संदर्भ पुस्तक, 'भारत– वार्षिक संदर्भ ग्रंथ का संकलन करता है। यह भारत के मंत्रालयों, विभागों और राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर देश के विभिन्न पहलुओं, इसकी राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी का मूल्यवान स्रोत है। यह हिंदी में Hkkjr और अंग्रेजी में bfM;k शीर्षक से एक साथ प्रकाशित होता है। Hkkjr 2019 और bfM;k 2019] वार्षिक संदर्भ ग्रंथ का 7 मार्च, 2019 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने अवलोकन किया। o"k 2019 d lnHk xFk d ldyu dk dke viu vfre pj.k e gA

3- çf'k{k.k

न्यू मीडिया विंग ने भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों के लिए दो दिवसीय सोशल मीडिया प्रशिक्षण मॉड्यूल का आयोजन किया। प्रशिक्षण का नेतृत्व फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ब्रांडवाच के विशेषज्ञों ने किया।

4- jktHkk"kk dk;kUo;u d rgr jktHkk"kk fgnh dk çxfr'khy mi;kx

न्यू मीडिया विंग में, सरकारी कार्यों में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है। विंग में हिंदी समिति की त्रैमासिक बैठकें अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में आयोजित की जाती हैं। 'हिंदी कर्मशाला' कर्मचारियों के लाभ के लिए और आधिकारिक कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर तिमाही आयोजित की जाती है। हिंदी 'पखवाड़ा' का आयोजन इस वर्ष 14 से 28 सितंबर तक किया गया था। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं।

5- lpuk dk vf/kdkj

एक सीपीआईओ और एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और आरटीआई अधिनियम के तहत तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार जानकारी प्राप्त करने

वाले व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण को नामित किया गया है।

6- fn0;kxk d fy, vkj{k.k

- ''दिव्यांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995'', दिव्यांगों के लिए समान अवसर और राष्ट्र निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास है।
- न्यू मीडिया विंग ने पीडब्ल्यूडी का आरक्षण लागू करने और समय–समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों तथा सभी संबद्ध नीतिगत निर्णयों का पालन के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं।

ckMdkLV bthfu;fjx dlYVV l bfM;k fyfeVM ¼cfly½

1- cfly dk lf{kIr bfrgkl

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 27001:2013, आईएसओ, आईईसी 20000:2012 प्रमाणित, सार्वजनिक क्षेत्र का मिनी रत्न उद्यम है जो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। इसकी स्थापना 24 मार्च, 1995 को ध्वनिकी और ऑडियो–वीडियो सिस्टम सहित टेरस्ट्रियल एंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, केबल और आईटी से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ क्षेत्रों में टर्नकी सोल्यूशन सहित प्रसारण और निर्माण प्रौद्योगिकियों में प्रसारण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों की परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी।

बेसिल भारत और विदेशों में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण इंजीनियरिंग, यथा–सामग्री निर्माण सुविधाओं, टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग, ट्रांसमिशन और सैटेलाइट एंड केबल ब्रॉडकास्टिंग के संपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए परियोजना परामर्शी सेवाएं और टर्नकी सोल्यूशन प्रदान करता है। यह प्रसारण से संबंधित डिजाइन और निर्माण, मानव संसाधन से संबंधित प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां, प्रशिक्षण, मानच संसाधन प्रदान करने जैसी सहायक सेवाएं भी प्रदान करता है। बेसिल रक्षा, पुलिस विभागों और विभिन्न अर्ध–सैन्य बलों को विशेष संचार, निगरानी, सुरक्षा और निगरानी प्रणाली की आपूर्ति भी करता है। बेसिल का मुख्यालय नई दिल्ली कॉरपोरेट कार्यालय नोएडा में और क्षेत्रीय कार्यालय बंगलुरु में है। बिजनेस पोर्टफोलियो में विविधता के कारण यह कई राज्यों में भौगोलिक विस्तार की संभावनाएं तलाश रहा है।

बेसिल ने पिछले वर्षों में, कोशिश करके अपने को तैयार किया है और इन–हाउस, बहुमुखी और समर्पित इंजीनियरों की एक टीम बनाई है और सार्वजनिक तथा निजी प्रसारण सहित प्रसारण उद्योग जिसमें प्रसारक, रक्षा और केबल उद्योग शामिल हैं, के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े पेशेवरों की बड़ी जमात को भी तैयार कर रहा है और उनकी प्रतिभा को निखार रहा है। साधन संपन्न तकनीकी पेशेवरों के इस नेटवर्क के माध्यम से, बेसिल ने उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी अखिल भारतीय उपस्थिति स्थापित की है।

बेसिल के पास बड़ी संख्या में विशेषज्ञ हैं और यह भारत के राष्ट्रीय प्रसारक आकाशवाणी (एआईआर) और दूरदर्शन (डी.डी) की विशेषज्ञता को एकीकृत करता है, और देश–विदेश में लाखों टीवी घरों तक पहुंचने वाली एनालॉग और डिजिटल उपग्रह प्रसारण सेवाओं द्वारा लगभग एक बिलियन लोगों और दुनिया के सबसे बड़े टेरेस्ट्रियल टेलीविजन नेटवर्क की जरूरतें पूरी करने वाले सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क का निर्माण करता है। यह ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कंसल्टेंसी एजेंसी, सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ–साथ टर्नकी सोल्यूशन प्रदाता के रूप में काम करता है।

बेसिल की ग्राहक सूची में सरकारी, अर्ध सरकारी, प्रवासी और निजी संगठन शामिल हैं। इसे कई कार्य सबसे पहले करने का श्रेय हासिल है जैसे भारत में पहला टेलीपोर्ट तथा बुंनियादी ढांचा स्थापित करना, बंगलुरु में 7 एफएम चैनलों के संयोजन से भारत में मल्टी–चैनल एफएम ट्रांसमिशन को सबसे पहले स्थापित करना और राष्ट्रपति सचिवालय तथा लोकसभा टीवी के लिए एचडीटीवी स्टूडियो सेट–अप को डिजाइन करना और स्थापित करना आदि।

2- ifjdYiuk

भारत और विदेश में कुल परियोजना समाधान के लिए संबंधित अवसंरचना विकास और ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ क्षेत्रों के लिए एक ब्रांड के रूप में मान्यता प्राप्त विश्व स्तरीय परामर्श संगठन बनना।

3- Yk{;

भारत और विदेशों में टेरेस्ट्रियल, केबल तथा उपग्रह प्रसारण के माध्यम से रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के आधुनिकीकरण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना और उत्कृष्टता प्राप्त करना।

4- mÌ';

- और अधिक संख्या में ग्राहकों को विशेषज्ञता और अनुकूलित समाधान प्रदान करके बाज़ार में वर्तमान हिस्सेदारी बढ़ाना।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नीति, विनियामक

और प्रसारण से संबंधित विभिन्न पत्रों के सूत्रीकरण में तकनीकी ज्ञान और परामर्श प्रदान करना।

- विदेशी बाज़ार में अवसरों का पता लगाना।
- उत्पाद विकास के लिए बाज़ार सर्वेक्षण करना।
- टीवी चैनलों और दूरस्थ शिक्षा केंद्रों के लिए सैटेलाइट अपलिंक और डाउनलिंक सिस्टम स्थापित करना।
- प्रसारण केंद्रों के संचालन को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए।
- प्रसारण पेशेवर प्रशिक्षित करना और उपलब्ध कराना।
- विशेषज्ञ प्रसारण उपकरणों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए।

5- ifj;kstukvksa dh çeq[k ckrsa&fu"ikfnr dh xbZ çeq[k ifj;kstuk,a

- एफएम चरण– III प्रसारण।
- आकाशवाणी (प्रसार भारती) के 18 स्थलों पर 16 पैनल एफएम एंटीना की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और परिचालन।
- दूरदर्शन (प्रसार भारती) के लिए 3 स्थलों पर सुपरटर्नस्टाइल एंटीना की आपूर्ति, परीक्षण और परिचालन।
- प्रसार भारती (दूरदर्शन) को 15 स्थानों पर डीटीटी एंटीना की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और परिचालन।
- मथुरा और मेरठ में आकाशवाणी टावर।
- टीपीडीएस परियोजना के शुरू से अंत कंप्यूटरीकरण के तहत उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) स्वचालन।
- डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम।
- एचएफ/वीएचएफ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम।
- निगरानी और अभिगम नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली (एसएसीएमएस)।
- श्रम और रोज़गार मंत्रालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के लिए अत्याधुनिक मीडिया संचार हब की स्थापना की दिशा में व्यावसायिक सेवाएं।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए प्रिंट (समाचार–पत्र/पत्रिकाएं), टेलीविजन और डिजिटल मीडिया (सोशल मीडिया सहित) के लिए एक निगरानी और विश्लेषण मंच की स्थापना।
- भारत के निर्वाचन आयोग के लिए सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब और रणनीति, शक्ति, दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली।
- सूचना और जनसंपर्क विभाग, लखनऊ के लिए सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब की स्थापना और कामकाज, संचालन तथा रखरखाव से संबंधित सेवाएं प्रदान करना।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण विंग के स्वचालन के लिए वेब–पोर्टल का डिजाइन, विकास और रखरखाव।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग निदेशालय के इन्वेंटरी प्रबंधन और अन्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण।
- नई दिल्ली में सूचना भवन की 10 वीं मंजिल पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमएस) में स्थापित विभिन्न मदों, उपकरणों, सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और परिचालन।
- ट्राई के विनियमों के अनुरूप ऑडिट।
- केबल टीवी डिजिटीकरण के चरण III और चरण IV के कार्यान्वयन के लिए मिशन डिजिटीकरण परियोजना।
- खुली नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से प्रसार भारती के लिए मानव संसाधन परीक्षण के लिए एक एजेंसी के चयन हेतु पेशेवर सेवाएं।
- दूरदर्शन समाचार चैनल (चैनलों) को रूचिकर बनाने तथा इनके प्रति दर्शकों का आकर्षण बढ़ाने और रचनात्मक सामग्री, तकनीकी बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन प्रदान करने के लिए पेशेवर ग्राफिक्स एजेंसी हेतु पेशेवर सेवाएं।
- छत्तीसगढ़ सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के लिए विज्ञापन/सामग्री के अभिज्ञान की सुविधा स्थापित करना।

- कू–बैंड (जीसैट–8) डीएसएनजी और मोबाइल वैन का शुरू से अंत तक पूर्ण समाधान, किराये के आधार पर प्रारंभिक तीन महीनों के लिए एसएपीएनईटी हेतु एसएपीएनईटी, आंध्र प्रदेश+ .एनएलई एंड डीटीपी वर्क्स को उपलब्ध कराना।
- ऑनलाइन भर्ती परीक्षा सेवा प्रदान करना।
- बीओसी के लिए जिला स्तरीय जमीनी सक्रियता और आउटरीच कार्यक्रम
- प्रसारण के क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल विकास

6- cfly & çc/ku vkj lxBu

बेसिल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एक पूर्णकालिक निदेशक (संचालन और विपणन), भारत सरकार द्वारा नामित दो निदेशक और एक अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक शामिल हैं। बोर्ड स्तर से नीचे महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, प्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक और कनिष्ठ प्रबंधक हैं। परियोजना का काम आगे चलकर कंपनी द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए कंसल्टेंट्स और प्रोजेक्ट मैनेजरों को सौंपा गया।

बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होते हैं :

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	श्री जॉर्ज कुरुविला
पूर्णकालिक निदेशक (ओ एंड एम)	श्री दीपक रंजन गोगोई
सरकार के नामित निदेशक	सुश्री अंजू निगम और श्री विनोद कुमार
अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक	सुश्री रंजना उपाध्याय

7- 0;kolkf;d xfrfof/k;k

- एफएम प्रसारण
- टीवी चैनलों की स्थापना
- टेलीपोर्ट की स्थापना
- डिजिटल न्यूज़ रूम सिस्टम का डिजाइन
- डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) सिस्टम
- भारतीय मानकों से वायर–लाइन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की अनुरूपता
- उपग्रह के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली
- ध्वनिकी, स्टेज प्रकाश, ध्वनि सुदृढ़ीकरण प्रणाली
- वायर–लाइन नेटवर्किंग में प्रशिक्षण/कौशल विकास
- ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करना

8- dk;{k=

- रेडियो और टीवी प्रसारण
- टी. वी. वितरण प्लेटफार्म– टेरेस्ट्रियल, सैटेलाइट, डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) प्रणाली, केबल हेड–एंड सिस्टम
- उपग्रह टीवी चैनलों की निगरानी, लॉगिंग और पुरालेखण
- सामुदायिक रेडियो स्टेशन
- इलेक्ट्रॉनिक्स निगरानी और निगरानी प्रणाली
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय को तकनीकी इनपुट
- एड्रेसेबल केबल सिस्टम का तकनीकी परीक्षण और प्रमाणन
- सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेटअप
- निगरानी और अभिगम नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली
- ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करना
- मानव संसाधन आउटसोर्सिंग

9- foÙkh; fof'k"Vrk,a

वित्त वर्ष 2016–17 के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ वित्त वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन इस प्रकार है :

	fooj.k	foÙk o"kZ	foÙk o"kZ
		2017-18	**2016-17**
क	संचालन का नतीजा		
	संचालन से आय	24200.88	22798.98
	o"kZ ds nkSjku dqy dkjksckj	**24200.88**	**22798.98**
	व्यय	24169.35	22153.68
	ऑपरेटिंग लाभ/(हानि)	31.53	645.30
	वित्त लागत	408.43	64.86
	घिसावट और ऋण परिशोधन	201.19	239.39
	संदिग्ध प्राप्तियों और अग्रिम के लिए अनुमति	-	-
	पूर्व अवधि समायोजन और असाधारण मदें	(8.60)	(4.95)
	ykHk@(gkfu) dj 0;; ls igys	**(586.69)**	**336.09**
	विलंबित कर	(158.91)	131.85
	ykHk@(gkfu) dj 0;; ls igys	**(427.78)**	**204.25**
	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए अंतरण	-	4.08
	vk;@(gkfu) ifr 'k;j (#-.)	**(313)**	**150.00**
ख	/ku d l kr		
	ईशू की गई, सब्सक्राइब की गई चुकता पूंजी संचय और अधिशेष	136.50	136.50
	संचय और अधिशेष	1104.31	1532.10
	गैर – चालू उत्तरदायित्व	699.97	643.81
	चालू उत्तरदायित्व	30330.34	21412.89
	dqy	**32271.12**	**23725.29**
	fuf/k;ksa dk bLrseky		
	अचल संपत्तियां	1297.99	1257.07
	चालू संपत्ति	30069.29	21785.95
	विलंबित कर संपत्तियां (शुद्ध)	866.93	667.18
	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	-	-
	अन्य गैर चालू संपत्तियां	36.91	15.09
	dqy	**32271.12**	**23725.29**
ग	vU; tkudkjh		
	vf/kd`r iwath	**250.00**	**250.00**
	लगाई गई पूंजी	1240.81	1668.59
	निवल संपत्ति	373.88	1001.42

'k;j iwath

बेसिल को 250 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ निगमित किया गया था। वर्ष 1995–96 में चुकता इक्विटी 25 लाख रुपये से बढ़कर 136.5 लाख रुपये हो गई। वर्तमान में भारत की केंद्र सरकार के पास 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी है। बेसिल को सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है।

fu"iknu

वर्ष के दौरान, कंपनी के कार्यों से राजस्व पिछले वर्ष के 223.43 करोड़ रु. से बढ़कर 240 करोड़ रु. हो गया जो कंपनी के निगमन के बाद सबसे अधिक है। हालांकि, बेसिल ने वित्त वर्ष 2017–18 में 4.27 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा उठाया है जिसमें ओवरड्राफ्ट राशि पर 3.72 करोड़ रु. ब्याज और 2 करोड़ रुपये का मूल्यह्रास शामिल है।

10- o"kZ ds nkSjku çca/kkRed igy vkSj O;kolkf;d xfrfof/k;k¡

वर्ष 2017–18 के दौरान, बेसिल ने निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं को अंजाम दिया है :–

,Q,e pj.k&III çlkj.k

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार ने एफएम रेडियो प्रसारण के तीसरे चरण को निजी भागीदारों के लिए खोलने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य रेडियो स्टेशनों के परिचालन से एफएम रेडियो कवरेज प्रदान करने के प्रयास बढ़ाने के लिए अधिक निजी एजेंसियों को आकर्षित करना है। ये रेडियो स्टेशन स्थानीय सामग्री और प्रासंगिकता वाले कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, स्थानीय प्रतिभा को प्रोत्साहित करते हैं और एफएम चरण–III रेडियो चैनल के बैच–1 और बैच–2 के लिए ई–नीलामी के माध्यम से रोज़गार पैदा करते हैं।

जिन शहरों में चरण–II का खाली चैनल है या एक अतिरिक्त चैनल प्रस्तावित है और बेसिल द्वारा सीटीआई बनाया गया है, सीटीआई के उन्नयन को बेसिल द्वारा चालू किया जाना है। इसके अलावा, स्थल पर एफएम चैनलों का सह–स्थान अनिवार्य है।

,Q,e pj.k&III ¼cSp&1½ में 56 मौजूदा शहरों (कोचीन में एक स्थल को छोड़कर) में 97 चैनल (जिनमें से मुजफ्फरपुर में 1 चैनल अध्यर्पित कर दिया गया है) शामिल है। बेसिल सभी सीटीआई स्थलों के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) है।

,Q,e pj.k&III ¼cSp&2½ में 48 शहरों में 66 चैनल शामिल हैं (जिनमें से 20 शहर एफएम चरण–II के तहत अस्तित्व में हैं)। बेसिल 21 शहरों में एस आई है।

सीटीआई पूर्णता स्थिति एफएम चरण–III (बैच–1 और 2) :

¼d½ foÙk o"kZ ¼2017&2018½ % 12 स्थल (बैच –1)+ 08 स्थल ((बैच –2)

¼[k½ foÙk o"kZ ¼2016&2017½ % 38 स्थल (बैच –1)

¼x½ foÙk o"kZ ¼2015&2016½ % 03 स्थल (बैच –1)

एफएम चरण–III (बैच–1 और 2) के तहत शेष स्थलों का निष्पादन प्रगति पर है।

एफएम चरण–III (बैच–1 और बैच–2) के तहत प्रसारणकर्ता निम्नानुसार हैं :

- हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लि.
- डिजिटल रेडियो (मुंबई) ब्रॉडकास्टिंग लि.
- एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लि.
- म्यूजिक ब्रॉडकास्ट प्रा. लिमिटेड
- रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लि.
- राजस्थान पत्रिका प्रा. लिमिटेड
- डीबी कार्पोरेशन लिमिटेड
- अभिजीत रीअल्टर्स एंड इंफ्रावेंचर्स प्रा. लिमिटेड
- रेंडर लाइव फ़िल्म एंड एंटरटेनमेंट प्रा. लिमिटेड
- सार्थक फ़िल्म्स प्रा.लिमिटेड
- अबीर बिल्डकॉन प्रा. लिमिटेड
- डिजिटल रेडियो (दिल्ली) ब्रॉडकास्टिंग लि.
- मातृभूमि प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड
- ओडिशा टेलीविजन लि.
- साउथ एशिया एफएम लि.
- पूर्वी ब्रॉडकास्ट (प्रा.) लि.
- मलयाला मनोरमा कंपनी लिमिटेड
- संभव मीडिया लि.
- कल रेडियो लिमिटेड
- मलार पब्लिकेशंस लिमिटेड
- जेसीएल इंफ्रा लि.
- रॉकस्टार एल प्रा. लिमिटेड

- उशोदया एंटरप्राइजेज (प्रा.) लिमिटेड

vkdk'kok.kh ¼çlkj Hkkjrh½ d 18 LFkyk ij 16 iuy ,Q,e ,Vhuk dh vkifr] LFkkiuk] ijh{k.k vkj ifjpkyu

प्रसार भारती (आकाशवाणी) ने 18 स्थलों पर संबद्ध उपकरणों के साथ 16 पैनल एफएम एंटीना की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशन के लिए आदेश जारी किया है। यह आर्डर वैश्विक निविदा प्रक्रिया में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करके प्राप्त किया गया था।

आपूर्तिकृत विस्तृत बैंड एंटीना, एफएम बैंड में काम करता है और प्रत्येक में 4 पैनल के 4 बेज़ का एपर्चर होता है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक में 16 पैनल एंटीना होते हैं। यह प्रणाली टॉवर के वर्गाकार हिस्से पर बढ़ते हुए व्यवस्थापन के साथ वृत्तीय तरंगित है। इस विधि में 3 "और 4" आकार के आरएफ केबल और संबंधित उपकरण जैसे एंटीना स्विच, कठोर लाइनें और डीहाईडरेटर शामिल हैं।

njn'ku ¼çlkj Hkkjrh½ d fy, 3 LFkyk ij lijVuLVkby ,Vhuk dh vkifr] ijh{k.k vkj ipkyu

बेसिल ने 3 स्थलों पर वीएचएफ और यूएचएफ सुपरटर्नस्टाइल एंटीना की आपूर्ति, परीक्षण और परिचालन के लिए आर्डर प्राप्त किया। यह आर्डर वैश्विक निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करके जीता गया था।

15 LFkkuk ij çlkj Hkkjrh ¼njn'ku½ dk MhVhVh ,Vhuk dh vkifr] LFkkiuk] ijh{k.k vkj ifjpkyu

प्रसार भारती (डी.डी) को डीटीटी एंटीना की आपूर्ति वर्ष 2012 में पूरी हो गई थी। स्थापना, परीक्षण और परिचालन 2017–18 में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

eFkjk vkj ejB e vkdk'kok.kh V,oj

आकाशवाणी ने मथुरा और मेरठ में टावर के निर्माण और स्थापन के लिए बेसिल को ऑर्डर जारी किया है जिसका मूल्य 4.68 करोड़ रु. है। यह कार्य मार्च 2019 तक पूरा होने वाला है और बेसिल को वित्त वर्ष 2018–19 में 100% बिलिंग करने की उम्मीद है।

VhihMh,l ifj;kstuk d 'kq: l vr rd dEI;Vhdj.k d rgr mfpr eY; dh nqdku ¼,Qih,l½ Lopkyu

पंजाब सरकार के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग ने पंजाब के 22 जिलों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) परियोजना के शुरू से अंत तक कंप्यूटरीकरण के तहत बेसिल से 1,417 ई–पीओएस मशीनों का ऑर्डर दिया है, जिसे पूरा कर दिया गया है और बेसिल को विभाग से इसके लिए मासिक किराया मिलेगा।

fMftVy flXuy çkslflx flLVe

ये, भारत में 2010–2012 के दौरान लागू की गई अपनी तरह की पहली परियोजनाएं हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को भारत सरकार द्वारा अपनी वाणिज्यिक शाखा मेसर्स एंट्रिक्स के माध्यम से इस परियोजना की जिम्मेदारी दी गई। इसरो ने जमीनी स्तर पर तैनात प्रौद्योगिकी उप–प्रणालियों के सभी पहलुओं की पहचान करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए बेसिल को अपना प्रौद्योगिकी भागीदार चुना। बेसिल एक प्रमुख और एकमात्र संगठन है जिसने इस तरह के इंटीग्रेटेड सेंसर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और परिचालन किया है। प्रणाली सोलह विभिन्न नेटवर्क पर काम कर सकती है और कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी अंतर्निहित निर्णय समर्थन प्रणाली के साथ लाखों सूचना आदानों के माध्यम निकाल सकती है।

,p,Q] oh,p,Q flXuy çkslflx flLVe

बेसिल स्थापित उच्च आवृत्ति विद्युत चुंबकीय सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए पूर्ण संचालन और रखरखाव सहायता प्रदान करता है।

fuxjkuh vfHkxe fu;=.k çcU/ku ç.kkyh ¼,l,lh,el½

यह परियोजना भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। यह परियोजना सभी मौजूदा सुविधाओं के इंटरफेस से जुड़े होने सहित संपूर्ण सेना भवन साउथ, ब्लॉक और इसके आस–पास के क्षेत्र की दूर से निगरानी, एकीकतृ नियंत्रण और केंद्रीय सुरक्षा प्रबंधन उपलब्ध कराने वाली संहिताओं और ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप पूरी तरह परिचालित निगरानी अभिगम नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली के लिए डिजाइन, प्राप्ति, स्थापन, समेकन, परीक्षण, संचालन और संबद्ध सेवाओं के बारे में है। एसएसीएमएस सख्त नियमों का पालन करेगा और अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकों, विश्वसनीयता के उच्चतम स्तर को अपनाएगा और इंट्रानेट, इंटरनेट, एलएएन, डब्ल्यूएएन जैसी नेटवर्किंग अवसंरचनाओं को एकीकृत करेगा। एसएसीएमएस के भीतर सभी इंटरफेस कॉरपोरेट इंट्रानेट, इंटरनेट/लैन, वैन पर टीसीपी, आईपी नेटवर्क प्रोटोकॉल कनेक्टिविटी पर आधारित होंगे। बेसिल इन परियोजनाओं को जीवनकाल सहायता प्रदान करता है और सतत संचालन और रखरखाव के लिए अंतिम उपयोगकर्ता की मदद करता है।

Je vkj jkt xkj e=ky;] deipkjh Hkfo"; fuf/k lxBu ¼bih,Qvk½ vkj deipkjh jkT; chek fuxe ¼b,lvkblh½ d fy, vR;k/kfud lk'ky ehfM;k dE;fud'ku gc dh LFkkiuk dh fn'kk e 0;kolkf;d lok,

बेसिल ने श्रम और रोज़गार मंत्रालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के लिए अत्याधुनिक सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब की स्थापना के लिए सेवाएं प्रदान की हैं, जिनमें सोशल मीडिया के बारे में प्रकाशन सामग्री, एसडी.डी, सुधार, डिजाइन और सामग्री का अनुरक्षण तथा कार्यान्वयन की अवधि के दौरान सोशल मीडिया साइट को संचालित करना, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, ईपीएफओ तथा ईएसआईसी के फेसबुक और ट्विटर पेज का रखरखाव शामिल है, टेम्प्लेट को बनाना, रखरखाव तथा नवीनीकरण, प्रक्रियाओं और प्रारूपों को मानकीकृत करना, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, ईपीएफओ तथा ईएसआईसी के एकाउंट का रखरखाव और संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट प्रदान करना और गतिविधि, मीडिया शेयर तथा अन्य पहचाने गए संकेतकों आदि के लिए संकेतक का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया के बारे में विस्तृत विश्लेषण प्रदान करना शामिल है।

lMd ifjogu vkj jktekx e=ky; d fy, fçV ¼lekpkj&i=] if=dk,½] Vyhfotu vkj fMftVy ehfM;k ¼lk'ky ehfM;k lfgr½ d fy, ,d fuxjkuh vkj fo'y"k.k ep dh LFkkiuk

बेसिल ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने और इसकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जी. पेज, यू ट्यूब चैनल का उपयोग किया है और एक ब्लॉग शुरू किया है।

Hkkjr d fuokpu vk;kx d fy, lk'ky ehfM;k dE;fud'ku gc ¼,l,elh,p½ vkj uhfr] 'kfä] –f"Vdk.k vkj dk;ç.kkyh miyC/k djkrk gA

इस परियोजना में आवश्यक आईटी बुनियादी ढांचे के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्थापन गतिविधियाँ शामिल हैं। बेसिल के पास ईसीआई की आवश्यकता या इसके संबंधित नोडल अधिकारियों के सुझावों के अनुरूप, फेसबुक आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की क्षमता है। बेसिल ने रचनात्मक डिजाइनिंग, सामग्री में नयापन तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री प्रकाशित करने, सुनने, वेब क्रॉलिंग, मॉनिटरिंग सिस्टम, कंटेंट को इंगेज, प्रकाशित करने के लिए एंटरप्राइज लेवल टूल एसआरएम (सोशल रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर) प्रदान किया है, अनुक्रिया का विभाजन तथा पृथकरण, संवेदी विश्लेषण के साथ विश्लेशणात्मक रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया ट्रैकिंग, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के साथ प्रतिक्रिया प्रबंधन, ब्रांडिंग और विज्ञापन सहायता, लोगो डिजाइनिंग तथा संग्रह आदि का काम किया है।

lk'ky ehfM;k dE;fud'ku gc ¼,l,elh,p½ dh LFkkiuk vkj lpuk rFkk tulid foHkkx] y[kuÅ d fy, ,l,elh,p dkedkt] lpkyu vkj j[kj[kko l lcf/kr lok, çnku djukA

बेसिल ने लखनऊ में उत्तरप्रदेश सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के लिए सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे काम करने वाली, संचालन और रखरखाव से संबंधित सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब सेवाओं के लिए निगरानी और प्रतिक्रिया सेवाएं उपलब्ध कराईं। इसके कार्यक्षेत्र में शामिल है– सोशल मीडिया पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों का विश्लेषण, समस्याग्रस्त गतिविधियों का पृथकरण, पेड और निजी मीडिया डेटा सहित पूरे सोशल मीडिया के लिए क्रालिंग क्षमता, ब्रोकर सब सिस्टम – प्रारंभिक चेतावनी, सोशल मीडिया सोशल मीडिया ट्रेंड्स और सेंटीमेंट्स की निगरानी, कार्रवाई योग्य डेटा की पहचान करना, विश्लेषणात्मक और रीच रिपोर्ट तैयार करना।

lpuk vkj çlkj.k e=ky; d çlkj.k fox d vkVke'ku d fy, oc&ikVy dk fMtkbu] fodkl vkj j[kj[kko

बेसिल ने प्रोजेक्ट विजन को प्राप्त करने और वांछित कंपनियों/आवेदकों को वेब–पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन के लिए एक आसान, कुशल और पारदर्शी तरीका अपनाने के वास्ते और अप्लाइड एप्लीकेशन का दर्जा प्राप्त करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रसारण शाखा की सहायता करने वाली प्रक्रियाओं और अनुप्रयोगों के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों को अंजाम दिया है।

lpuk vkj çlkj.k e=ky; d çdk'ku foHkkx d fun'kky; d bUoVjh çc/ku vkj vU; 0;kolkf;d çfØ;kvk dk dI;Vjhdj.kA

बेसिल ने प्रकाशन विभाग के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए विभिन्न मॉड्यूल तथा एसएमएस गेटवे, पेमेंट गेटवे के साथ वेबसाइट इंटरफेस के लिए विशेष रूप से एसएमएस गेटवे, के साथ–साथ मॉड्यूल के एकीकरण के लिए सेवाएं प्रदान कीं।

ubl fnYyh lpuk Hkou dh 10oh efty ij byDV,fud ehfM;k e,fuVfjx lVj ¼b,e,elh½ e]

yxkb xb i.kkyh d fy, fofHkUu enk] midj.kk dh vkifr] LFkkiuk] ijh{k.k vkj ifjpkyuAबेसिल ने ईएमएमसी को अतिरिक्त मशीनरी, उपकरण, अन्य तकनीकी सेटअप और कार्यालय स्थान के लिए प्रदान किए गए केंद्रीकृत निगरानी तंत्र की स्थापना के साथ 900 टीवी चैनलों की निगरानी के संवर्द्धन को अंजाम दिया है।

सेटअप के विस्तार में टीवी उपग्रह चैनलों की मौजूदा निगरानी क्षमता को 300 से बढ़ाकर 1500 करना, सिविल बदलाव करना, स्थायी कलात्मक गुणवत्ता की संरचना करना, कार्यात्मक आवश्यकता के अनुरूप कार्यात्मकता, बिजली की बाधारहित आपूर्ति सहित हाई वैल्यू इनटीरियर्स और ध्वनि संबंधी कार्य, विभिन्न आकारों के व्यावसायिक गुणवत्ता वाले डिश एंटीना की पर्याप्त संख्या, संबंधित इलेक्ट्रॉनिक लॉगर के लिए ऑडियो और वीडियो अनमार्गन का प्रावधान और 24X7 के आधार पर रिकॉर्डिंग का सेटअप जिसमें सेकेंडवार समय की स्टेंपिंग सटीकता स्वचालित सामग्री का पता लगाने के साथ मीडिया का अभिलेखण और फास्ट रिकॉर्डिंग तथा रीट्रीविंग शामिल है।

Vkbl fofu;eu d vu:Ik ijh{k.k

ट्राई विनियमन की अनुसूची I के अनुसार डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (सीएएस, एसएमएस, एसटीबी) की जांच की गई है। ट्राई विनियमन की अनुसूची I के अनुपालन के अनुसार जांच में डीएएस प्रणाली के लिए ग्राहक को सलाह देने के साथ–साथ परामर्श भी शामिल है। आवश्यकता के अनुसार सभी जांचें की गई हैं।

ekuuh; VhMhlV d funs'kk d vu|lkj v,fMV

बेसिल ने टीडीसैट के विशिष्ट निर्देशों के अनुसार ऑडिट किया है। ऑडिट कार्य का दायरा टीडीसैट के निर्देश के अनुसार मामले की स्थिति पर निर्भर करता है। यह वाणिज्यिक ऑडिट के साथ–साथ तकनीकी ऑडिट भी हो सकता है। टीडीसैट के सभी संदर्भों पर आवश्यकता के अनुसार काम किया गया।

dcy Vhoh fMftVyhdj.k d pj.k III vkj pj.k IV d dk;kUo;u d fy, fe'ku fMftVhdj.k ifj;kstuk

कार्य के दायरे में देशभर में 12 क्षेत्रीय इकाइयों की स्थापना, इन क्षेत्रीय इकाइयों में अनुबंध पर कर्मचारियों (पीडी, एपीडी, ओए और डीईओ) की भर्ती, बहुभाषी कॉल सेंटर की स्थापना, एसटीबी सीडिंग की निगरानी के लिए एमआईएस एप्लीकेशन का विकास, केबल टीवी डिजिटीकरण के सभी हितधारकों को अद्यतन और आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए वेबसाइट का विकास शामिल हैं। चरण III और चरण IV का कार्य प्रगति पर है। सभी गतिविधियों को अंजाम दिया गया है, हालांकि, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बाद में परियोजना की पूर्णता तिथि मार्च 2020 तक बढ़ा दी है और परियोजना जारी है।

çf'k{k.k vkj vU; xfrfof/k;k

1. बेसिल ने वायरलाइन ब्रॉडकास्टिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बेसिल के पास देशभर में प्रो दृश्य श्रव्य स्थापन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इंफोकॉम इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

   बेसिल ने इसके अलावा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत आईएएससी की सेक्टर स्किल काउंसिल की संचालन परिषद का सदस्य होने के नाते, विभिन्न एनओएस (राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों) और पाठ्यक्रम के विकास में शामिल है।

2. सीएटीव सेक्टर में कौशल प्रशिक्षण के लिए मैसर्स एमसीबीएस, गांधी नगर के साथ समझौता ज्ञापन।

[kyh ckyh çfØ;k d ek/;e l çlkj Hkkjrh d ekuo lklk/ku d vkfMV d fy, i'koj ,tlh dk p;u dju d fy, i'koj lok,

प्रसार भारती के अनुरोध पर, बेसिल प्रसार भारती के मानव संसाधन के ऑडिट के लिए एक पेशेवर एजेंसी के चयन के लिए अपनी पेशेवर सेवाएं प्रदान कर रहा है।

इस संबंध में, संभावित बोलीदाताओं से विस्तृत तकनीकी–व्यावसायिक प्रस्तावों की मांग के लिए एक खुली निविदा जारी की गई थी और एजेंसी के चयन का यह कार्य जारी है।

njn'ku lekpkj puy ¼puyk½ dk :fpdj cuku vkj bud ifr n'kdk dk vkd"k.k c<ku vkj jpukRed lkexh] rduhdh cfu;knh <kpk vkj ekuo lklk/ku çnku dju d fy, i'koj xkfQDl ,tlh d okLr i'koj lok, vkj njn'ku lekpkj dk nfud xkfQDl çnku djukA

दूरदर्शन समाचार के अनुरोध पर, चैनल (चैनलों) को रुचिकर बनाने और इनके प्रति दर्शकों का आकर्षण बढ़ाने और रचनात्मक सामग्री, तकनीकी बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन प्रदान करने के लिए पेशेवर एजेंसी को शामिल करने के वास्ते पेशेवर सेवाएं और दूरदर्शन समाचार को दैनिक ग्राफिक्स प्रदान करना।

इस संबंध में, एजेंसियों को सूची में से छांटने के लिए एक खुला टेंडर जारी किया गया था और चुने गए बोलीकर्ताओं से विस्तृत तकनीकी–व्यावसायिक प्रस्ताव मांगने के लिए आरएफपी जारी किया गया है।

lpuk vkj tulid foHkkx] NÙkhlx< ljdkj d fy, foKkiu@lkexh dh lfo/kk LFkkfir djuk

बेसिल ने छत्तीसगढ़ संवाद, छत्तीसगढ़ में एक वर्ष के लिए संचालन और रखरखाव के साथ टर्नकी आधार पर संबद्ध सुविधाओं के साथ एफएम और टीवी चैनल के भंडारण और अनुपालन लॉगिंग, निगरानी, सत्यापन और रिपोर्ट बनाने के लिए सुविधा की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग (डीपीआर), द्वारा एक एजेंसी के रूप में कार्य किया।

d;&cM ¼thlV&8½ Mh,l,uth vkj ekckby oSu dk 'k: l vr rd i.k lkY;w'ku fdjk; d vk/kkj ij çkjfHkd rhu eghuk d fy, ,l,ih,ubVh d okLr ,l,ih,ubVh] vk/k çn'k ,u,yb ,M MhVhih oDl dk miyC/k djkuk

सैपनैट माना टीवी दो शैक्षिक टेलीविजन चैनल, माना टीवी1 (प्ले बैक चैनल) और माना टीवी 2 (लाइव चैनल) चला रहा है। इस चैनल की स्थापना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के सहयोग से 17मेगाहर्टस–बैंड (एपी और टीएस) में उपग्रह संचार के माध्यम से शैक्षिक और मानव विकास सामग्री का प्रसारण करने के लिए की गई।

बेसिल को यह कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विस्तार, महिला विकास, ई–गवर्नेंस, ग्रामीण विकास, स्वयं–सहायता समूहों में जागरुकता पैदा करने, मानव संसाधन विकास, दूरस्थ प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, डिजिटल इंडिया के क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्र के लाइव कार्यक्रमों को कवर करने के लिए आवश्यक मानव संसाधन के साथ डीएसएनजी और ओबी वैन प्रदान करने के लिए निविदा के आधार पर मिला।

ekuo lalk/ku lyslesV lokvk d fy, ifj;kstuk

बेसिल ने पिछले कुछ वर्षों में आउटसोर्सिंग का एक नया कार्यक्षेत्र शुरू करके युवाओं के लिए रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेसिल निर्धारित भर्ती प्रक्रियाओं का पालन करके समूचे भारत में विभिन्न सरकारी संगठनों को तकनीकी और गैर–तकनीकी मानव संसाधन प्रदान कर रहा है।

बेसिल मानव संसाधन, वित्त, विपणन आदि के क्षेत्र में तकनीशियन, इंजीनियर, तकनीकी सहायक, प्रोग्रामर, सलाहकार, परामर्शदाता, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एमटीएस, चपरासी, संदेशवाहक, अकुशल, अर्ध–कुशल और कुशल मानव संसाधन आदि विभिन्न सरकारी कार्यालयों में उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करा रहा है और संभावित उम्मीदवारों का एक डेटाबेस रखता है। बेसिल निम्नलिखित सरकारी संगठनों को मानव संसाधन प्रदान कर रहा है :

1) प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ)
2) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)
3) भारत का निर्वाचन आयोग (ईसीआई)
4) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)
5) लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई)
6) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
7) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)
8) 2008 से दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू)
9) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी)
10) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
11) ग्रामीण विकास मंत्रालय
12) फरवरी 2015 से संस्कृति मंत्रालय, मीडिया सेल।
13) आकाशवाणी (एआईआर)
14) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली
15) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), झज्जर
16) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), एनडीटीसी, गाजियाबाद
17) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायपुर
18) पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) – अक्तूबर, 2014 के बाद से सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के तहत देशभर के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ दिल्ली में मुख्यालय।
19) फरवरी 2015 से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन भारत के समाचार पंजीयक (आरएनआई), आर.के. पुरम, दिल्ली और भोपाल कार्यालय।
20) 2010 से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)।
21) राज्यसभा टीवी चैनल।

22) दिसंबर 2013 से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू)।

23) मई 2011 से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)।

24) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए)

25) जून 2013 से राष्ट्रपति भवन

26) एसआरएसएसी, सैटकॉम, जयपुर

27) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

28) सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल (सीडीटीआई) जयपुर

29) आयकर महानिदेशालय (सतर्कता)

çlkj.k d {k= e çf'k{k.k vkj dk'ky fodkl

11- Hkfo"; dh 0;kolkf;d xfrfof/k

कंपनी का प्रबंधन वित्त वर्ष 2018–19 में परिचालन लाभ बढ़ाने का इरादा रखता है और इसके लिए निम्न गतिविधियां चलाता है :

- कंसल्टेंसी कारोबार बढ़ाना
- विदेशी निविदाओं में भागीदारी
- उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग
- वार्षिक रखरखाव अनुबंध में वृद्धि
- नए क्षेत्रों में दोबारा आर्डर प्राप्त करना

u, {k=k e fofo/krk

- मेक इन इंडिया के तहत सेट टॉप बॉक्स का विनिर्माण
- व्हाइट स्पेस कनेक्टिविटी
- स्किल इंडिया के तहत कार्यक्रम
- राजमार्ग की सलाह

12- lpuk vkj çlkj.k e=ky; d lkFk le>krk Kkiu

वित्त वर्ष 2018–19 के लिए बेसिल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr@vU; fiNMk ox@vYil[;d d fy, lcf/kr mEehnokjk dh fu;fä

कंपनी आरक्षण नीतियों पर सरकार के दिशानिर्देश/निर्देशों का पालन करती है। तदनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में आरक्षण के मामलों पर सरकार के दिशानिर्देशों/निर्देशों और कंपनी में भर्तियां और पदोन्नति करते समय अल्पसंख्यकों की नियुक्ति के लिए ध्यान रखा गया है।

13- lpuk dk vf/kdkj

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समय पर उचित कार्रवाई की जाती है। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और सूचनाओं को समयबद्ध रूप से देने के अनुपालन और प्रसार के लिए अत्यंत सावधानी बरती जा रही है।

14- fgnh dk çxfr'khy mi;kx

सरकारी कामकाज की भाषा पर रिपोर्ट के विभिन्न भागों में की गई सिफारिशों पर बेसिल द्वारा अनुपालन की आवश्यक कार्रवाई/अद्यतन स्थिति को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, बेसिल में 14 सितंबर, 2017 से 28 सितंबर, 2017 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी वाद विवाद, हिंदी कविता, हिंदी अनुवाद और हिंदी टाइपिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई। शब्दकोष और तकनीकी शब्दावली जैसी आवश्यक सहायता सामग्री सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में उनके आधिकारिक काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए उपलब्ध कराई गई थी।

15- lrdrk xfrfof/k;k

बेसिल में सतर्कता अनुभाग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सार्वजनिक उद्यम विभाग और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्देश के अनुसार बेसिल में अनुपालन के लिए निवारक सतर्कता के सभी पहलुओं को मजबूत करने के उपायों के बारे में नियमित रूप से नियम और दिशानिर्देश जारी कर रहा है।

समय–समय पर केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नियमित रूप से विवरणियां भेजी जाती हैं और समुचित तरीके से तुरंत जांच की जाती हैं, समय–समय पर औचक निरीक्षण किए जाते हैं और निरंतर सतर्कता बरती जाती है।

16- cfly dh 15oha ,f'k;k ehfM;k f'k[kj lEesyu vkj vU; dk;Øeksa esa Hkkxhnkjh

11 मई, 2018 को नई दिल्ली में 15 वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में एक समूह की तस्वीर में युवा मामले तथा खेल और सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

17- lkekU;

बेसिल का बजट खुले बाज़ार में प्रतिस्पर्धी निविदा प्रणाली के माध्यम से विभिन्न प्राप्तियों से संबंधित प्राप्तियों और व्यय की अपनी आंतरिक व्यवस्था है। कंपनी को सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है और अपने स्वयं के संसाधन उत्पन्न करता है।

कंपनी को, महिलाओं, उत्तर–पूर्व (सिक्किम सहित), रोज़गार सृजन, ग्रामीण घटक, आदिवासी उप योजना, विशेष घटक योजना, स्वयंसेवी क्षेत्र, सूचना और प्रचार, अल्पसंख्यक कल्याण आदि से संबंधित किसी भी केंद्रीय/केंद्र प्रायोजित योजना नहीं सौंपी गयी है।

byDVªkfud ehfM;k e,fuVfjax lsUVj

टेलीविजन चैनल विभिन्न आयु वर्ग के लोगों, संस्कृतियों तथा पृष्ठभूमि के लिए एक विशाल पहुंच के साथ संचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टेलीविजन चैनलों द्वारा उपभोक्ताओं को अवांछनीय सामग्री से बचाने के लिए, दुनिया में लगभग सभी प्रमुख लोकतंत्रों देशों में मानकों का पालन किया जाता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के किसी भी उल्लंघन के लिए भारत में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) को टीवी चैनलों के लिए प्रसारित सामग्री की निगरानी का काम सौंपा गया है। सबसे नई और भविष्य की मीडिया इकाइयों में से एक, ईएमएमसी को प्रसारण सामग्री की निगरानी, रिकॉर्ड और विश्लेषण करने के लिए उन्नत तकनीकों के साथ स्थापित किया गया है।

टेलीविजन में अश्लील रियलिटी शो, टॉल्क शो, अशिष्ट समाचार, वृत्तचित्र और सोप ओपेरा के खिलाफ शिकायतों के जवाब में सामग्री की निगरानी की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इसी तरह, टेलीविजन छोटे बच्चों के जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है, जो घर पर टेलीविजन के माध्यम से हिंसा और विसंगतिपूर्ण संस्कृति के संपर्क में आते हैं। वास्तविक जीवन की हिंसा के सीसीटीवी और मोबाइल से रिकॉर्ड किए गए वीडियो भी अक्सर प्रसारित होते हैं और समाचार चैनलों पर बार–बार प्रसारित होते हैं। केवल बच्चे ही नहीं, वयस्क दर्शकों को भी इस तरह की सामग्री परेशान करती है। कई बार, ऐसे मुद्दों की कवरेज के दौरान उत्पीड़न का शिकार होने वाली महिलाओं और बच्चों की पहचान का खुलासा कर दिया जाता है। इस तरह के विवरणों के व्यापक प्रसारण से जो स्थिति पैदा हो सकती है, वह चिंता का विषय है।

इसी तरह, भारतीय टेलीविजन उद्योग का एक प्रमुख हिस्सा विज्ञापन, किसी उत्पाद को खरीदने के निर्णयों को प्रभावित करता है। तंबाकू और शराब जैसे अस्वास्थ्यकर उत्पादों के विज्ञापन या भ्रामक विज्ञापनों के मद्देनजर, भारत सरकार ने हमेशा उचित विधानों, आदेशों और निर्देशों के माध्यम से ऐसे उत्पादों के विज्ञापनों पर अंकुश लगाने या प्रतिबंधित करने का प्रयास किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आगाह किया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत केबल टेलीविजन नेटवर्क के नियम, 1994 की विज्ञापन संहिता के नियम 7 (5) के अनुरूप, किसी उत्पाद के बारे में साबित नहीं हो सकने वाले चमत्कारी प्रतीत होने वाले गुणों पर विज्ञापन नहीं होना चाहिए।

ईएमएमसी में 900 चैनलों की सामग्री को रिकॉर्ड करने और निगरानी करने की तकनीकी सुविधा है, जो भारतीय क्षेत्र पर आधारित है, ताकि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत बनाई गई कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के किसी भी उल्लंघन की जाँच की जा सके। वर्तमान में सभी अनुमत चैनलों की निगरानी ईएमएमसी द्वारा की जाती है। केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 और इसके तहत बनाए गए नियम जो ऐसी कई संहिताओं के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं, जिनका सभी प्रसारण संस्थाओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, संशोधित अप–लिंकिंग दिशानिर्देश और भारत में प्रसारित चैनलों के लिए दिशानिर्देशों की डाउन लिंकिंग सामग्री की निगरानी भी संभावित उल्लंघन पर नजर रखने और सुधार उपायों के लिए आवश्यक है। ईएमएमसी कथित उल्लंघनों की रिपोर्ट, क्लिप के साथ जांच समिति को देता है, जो उल्लंघन की जांच करती है और अपने निष्कर्षों को अंतर–मंत्रालयी समिति तथा अन्य निकायों को भेजती है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

ईएमएमसी अपार सार्वजनिक महत्व के सामयिक मामलों की पहचान करता है और मूल्यांकन तथा उचित कार्रवाई के लिए उन्हें मंत्रालय को भेजता है। यह सरकार द्वारा वांछित विषयों पर विशेष रिपोर्ट तैयार करता है और मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। ईएमएमसी मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की भी निगरानी करता है।

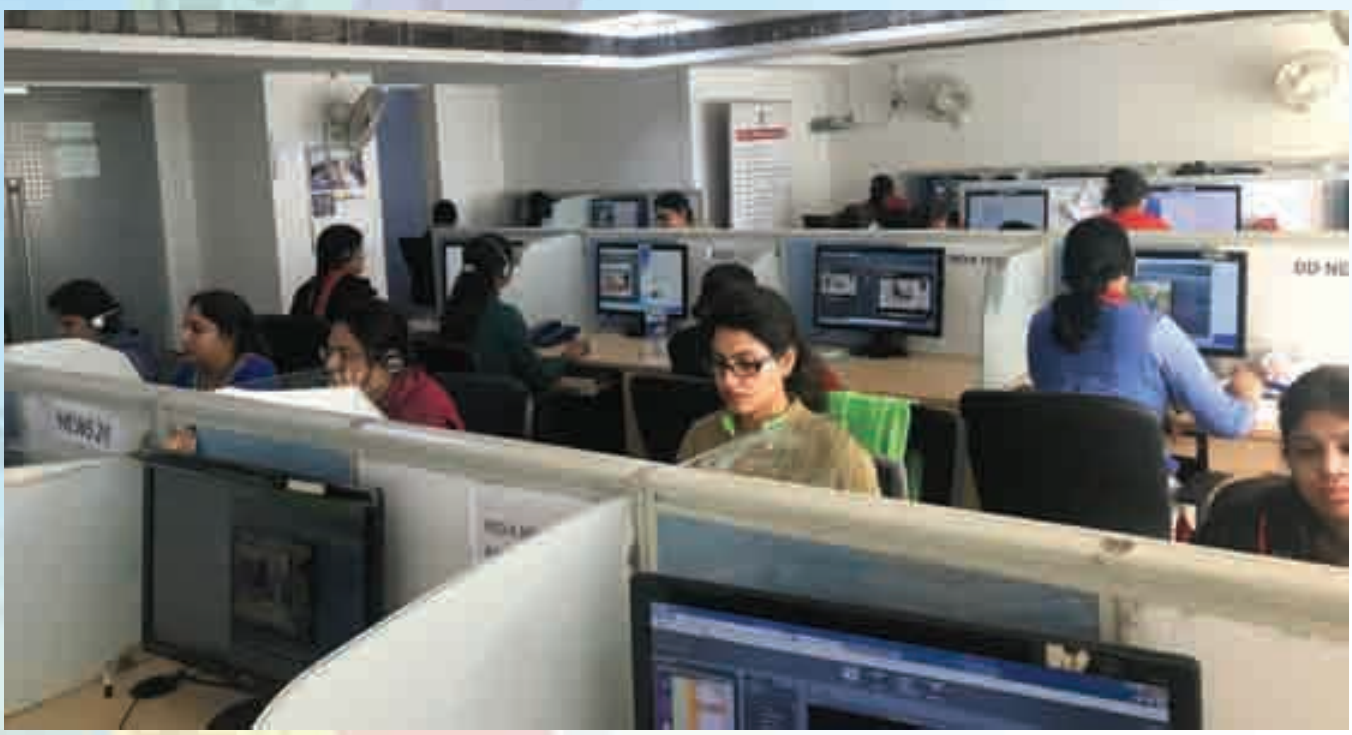

ईएमएमसी कार्यालय के अन्दर का दृश्य

b],e,elh dh dN çe[k miyfC/k;k¡

ईएमएमसी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए :

- विधानसभा चुनावों की निगरानी : ईएमएमसी ने कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में 2018 में विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव प्रबंधन से संबंधित समाचारों की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज की निगरानी की। मतदान के दिन और एक दिन पहले प्रमुख घटनाओं पर एसएमएस अलर्ट भारत के निर्वाचन आयोग को भेजे गए।

- ईएमएमसी ने आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम के विशेष प्रसारण जैसे विभिन्न कार्यक्रमों और घटनाओं को विभिन्न समाचार चैनलों द्वारा दी गई व्यापक कवरेज का तुलनात्मक विश्लेषण भी तैयार किया।
- केंद्र सरकार की संकट प्रबंधन योजना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन : ईएमएमसी के एसएमएस अलर्ट एक विशेष आरएएक्स लाइन के माध्यम से गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष से जुड़े होते हैं। सरकार के नियंत्रण और कार्रवाई प्रणाली की प्रभावकारिता के उन्नयन के लिए संकट प्रबंधन उपायों के वास्ते ईएमएमसी के विभागाध्यक्ष को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
- सामग्री विश्लेषण रिपोर्ट : ईएमएमसी ने विभिन्न समाचार चैनलों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और घटनाओं को दी गई कवरेज का तुलनात्मक विश्लेषण भी उपलब्ध कराया।

lkekftd&lkL—frd xfrfof/k;k % ईएमएमसी ने 2018–19 के दौरान कार्यालय में विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। घटनाओं की एक श्रृंखला यथा योग दिवस समारोह, हिंदी पखवाड़ा, संवैधानिक दिवस समारोह आदि का आयोजन किया गया। सितंबर 2018 में स्वछता ही सेवा अभियान के तहत भाषण और निबंध लेखन प्रतियोगिताओं और अक्तूबर 2018 में सतर्कता जागरुकता सप्ताह का आयोजन किया गया था। गैर–हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए भी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। नवंबर 2018 में सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह भी मनाया गया।

आईएफएफआई 2018 का उद्घाटन समारोह

6 fQYe {k= dh xfrfofèk;k

fQYe çHkkx

पिछले 100 वर्षों में भारतीय सिनेमा के फ़िल्म संग्रहालय के लिए उपयुक्त बहुत सी ऐतिहासिक सामग्री नष्ट, क्षतिग्रस्त या फिर उचित देखभाल न होने के कारण और संरक्षण सुविधाओं की कमी के कारण नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई हैं। इसलिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की गई जो फ़िल्मों के प्रदर्शन के लिए, फ़िल्म सूचना, उपकरण और यादगार वस्तुओं को संरक्षित, संग्रहित और संस्थापित करेगी और इस निर्णय के फलस्वरूप भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की गई।

एनएमआईसी का निर्माण फ़िल्म डिवीजन कॉम्प्लेक्स, मुंबई में किया गया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 19 जनवरी, 2019 को एनएमआईसी का उद्घाटन किया।

भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी) के उद्घाटन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

यह फ़िल्म संग्रहालय न केवल आम दर्शकों को सूचनाओं का ख़ज़ाना प्रदान करेगा, बल्कि फ़िल्म निर्माताओं, फ़िल्म छात्रों, उत्साही दर्शकों और आलोचकों को न केवल देश के सभी हिस्सों बल्कि पूरी दुनिया की कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सिनेमा के विकास को जानने में मदद करेगा। चूंकि अब तक एनएमआईसी के अलावा भारत में कोई फ़िल्म संग्रहालय नहीं है।

फ़िल्म प्रभाग गत 68 वर्षों से भारतीय नागरिकों को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। फ़िल्म प्रभाग के लक्ष्य और उद्देश्यों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जनता को शिक्षित और प्रेरित करना और भारतीय तथा विदेशी दर्शकों के समक्ष देश की छवि और धरोहर को प्रस्तुत करना शामिल है। फ़िल्म प्रभाग सिनेमा थियेटरों और गैर–थियेटर सर्किटों जैसे क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की इकाइयों, दूरदर्शन, शैक्षिक संस्थानों, फ़िल्म समितियों और स्वयंसेवी संगठनों की जरूरतें पूरी करने के लिए वृत्तचित्र, लघु और एनीमेशन फ़िल्मों का निर्माण करता है। प्रभाग परिसर में भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय

(एनएमआईसी) एक नए अनुभाग के रूप में शामिल किया गया है। इस संग्रहालय में प्रदर्शन दीर्घाओं का निर्माण और स्थापना का कार्य क्रमशः एनबीसीसी और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) द्वारा लगभग पूरा किया जा चुका है।

fQYEl foHkkx dk Ldaèk

भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी) परिसर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रभाग को चार स्कंधों में बांटा गया है:–

(1) निर्माण,

(2) वितरण,

(3) अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु और एनिमेशन फ़िल्म महोत्सव और

(4) प्रशासन

fuekZ.k Ldaèk

निर्माण स्कंध फ़िल्मों (वृत्तचित्र, विशेष रूप से ग्रामीण दर्शकों के लिए तैयार की गई लघु फ़ीचर फ़िल्में, एनीमेशन और वीडियो फ़िल्म्स में) के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और तीन अन्य निर्माण केंद्र बंगलुरु, कोलकाता और नई दिल्ली में हैं।

forj.k Ldaèk

वितरण विंग की बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, तिरुअनंतपुरम और विजयवाड़ा में सात शाखाएं हैं, जो सिनेमा थियेटरों को "स्वीकृत फ़िल्में" उपलब्ध कराती हैं, सार्वजनिक सूचना अभियानों, विदेश मंत्रालय के विदेशी प्रचार विभाग के माध्यम से विदेशी बाज़ारों में फ़िल्म डिवीजन की फ़िल्में की डीवीडी और चुनिंदा प्रिंट/वीडियो के वितरण में भाग लेता है।

vrjjk"Vªh; oÙkfp=] y?kq ,oa ,fues'ku fQYe egksRlo

1990 के बाद से फ़िल्म प्रभाग, "मुंबई इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल फॉर डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट एंड एनिमेशन फ़िल्म" (एमआईएफएफ) का द्विवार्षिक आयोजन करता है, जो फ़िल्म निर्माताओं, उत्पादकों, वितरकों और फ़िल्म समीक्षकों के विचारों और अवधारणाओं के आदान–प्रदान के लिए एक अनूठा अवसर है। 28 जनवरी से 3 फरवरी, 2020 के बीच एमआईएफ़–2020 का 16वां संस्करण अस्थायी रूप से आयोजित किया जाएगा।

çk'kklu Ldaèk

प्रशासन स्कंध में वित्त, कार्मिक, भंडार, लेखा, कारखाना प्रबंधन और सामान्य प्रशासन शामिल होते हैं। 31 जनवरी, 2019 को फ़िल्म प्रभाग की स्टॉफ संख्या/स्टॉफ की स्थिति इस प्रकार है :

la[;k	Js.kh	Lohd`r dkfeZd la[;k	inklhu deZpkjh	[kkyh inksa dh la[;k
d	[k	x	?k	M
1	समूह 'क'	31	16	15
2	समूह 'ख'	192	163	29
3	समूह 'ग'	386	327	59
	dqy %	609	506	103

o"kZ dh miyfCèk;ka

- भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 जनवरी, 2019 को मुम्बई के फ़िल्म प्रभाग में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया।
- 83 डॉक्यूमेंट्री फ़िल्मों का निर्माण जिनमे 49 फ़िल्में विभागीय और 34 फ़िल्में आउटसाइड प्रोड्यूसरों के माध्यम से निर्मित की गईं।
- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, फ़िल्म प्रभाग ने "वैष्णव जन तो..." शीर्षक से विशेष एनीमेशन फ़िल्म का निर्माण किया, जिसका राष्ट्रव्यापी रिलीज़ किया गया।
- फ़िल्म प्रभाग ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए इन–हाउस डायरेक्टर्स के माध्यम से 25 फ़िल्मों का भी निर्माण किया।

- प्रोडक्शन स्पेशल एक्शन प्लान के तहत, फ़िल्म डिवीजन ने स्वच्छता, जलियांवाला बाग, महात्मा गांधी के जीवन और संदेशों, सिस्टर निवेदिता, अंगकोर वाट पर केंद्रित फ़िल्मों का निर्माण किया है।
- विभिन्न संगठनों/संस्थानों/स्कूलों और कॉलेजों द्वारा आयोजित 42 विशेष स्क्रीनिंग में 239 फ़िल्मों की स्क्रीनिंग की गई।
- फ़िल्म डिवीजन ने वर्षभर में 10 फ़िल्म समारोह आयोजित किए।
- 2018–19 (आज तक) प्रविष्ट/चयनित/पुरस्कृत फ़िल्में।

फ़िल्म समारोहों में प्रविष्ट फ़िल्में	12 फ़िल्म समारोहों में 49 फ़िल्में
चयनित फ़िल्में	8 समारोहों में 23 फ़िल्में
पुरस्कार	8 पुरस्कार (4 राष्ट्रीय पुरस्कार सहित)

çe[k igy

oc lkbV

फ़िल्म प्रभाग के वेब पोर्टल को वर्तमान घटनाओं, स्क्रीनिंग, डीवीडी और फ़िल्म रिलीज के लिए उपलब्ध सूचनाओं को अपडेट करने के लिए अधिक इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है। अपलोड फ़िल्म प्रभाग कैटलॉग में फ़िल्म प्रभाग में निर्मित और प्रतिष्ठित सभी फ़िल्मों की जानकारियां शामिल हैं।

ohfM;k vujksèk

70 शीर्षकों के साथ वीडियो ऑन डिमांड सुविधा सक्रिय है। ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तहत ऑनलाइन डीवीडी खरीदी जा सकती है। फ़िल्म प्रभाग के डॉक्यूमेंट्री मीडिया सेक्शन के तहत वर्तमान में अवलोकन हेतु 476 वीडियोज़ एमआईबी वेबसाइट पर देखने हेतु उपलब्ध हैं।

vfHky[kh; vuqlèkku dæ

2013 से फ़िल्म निर्माताओं और छात्रों को वृत्तचित्र सामग्री का पूर्वावलोकन करने और शोध करने में मदद करने के लिए पंद्रह कार्यस्थानों वाला एक अभिलेखीय अनुसंधान केंद्र काम कर रहा है।

;V;c

फ़िल्म प्रभाग द्वारा चयनित फ़िल्मों को यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ अपलोड कर लोगों के लिए सुलभ बनाया जाता है। फ़िलहाल फ़िल्म डिवीज़न के यूट्यूब चैनल पर 598 वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। चैनल को 5.4 मिलियन दर्शक और कुल 46.5K सब्सक्राइबर मिले हैं।

Hkkjrh; fluek dk jk"Vªh; laxzgky;

पिछले 100 सालों में भारतीय सिनेमा के फ़िल्म संग्रहालय के लिए उपयुक्त बहुत–सी ऐतिहासिक सामग्री नष्ट, क्षतिग्रस्त या उचित देखभाल न करने और संरक्षण सुविधाओं की कमी के कारण ठीक से देखभाल नहीं की गई। इसलिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की गई जो फ़िल्मों के प्रदर्शन के लिए, फ़िल्म सूचना, उपकरण और यादगार वस्तुओं को समेट, संरक्षित, संग्रहित और संस्थापित करेगी और इस निर्णय के फलस्वरूप भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की गयी। एनएमआईसी का निर्माण फिल्म्स डिवीजन कॉम्प्लेक्स, मुंबई में किया गया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 जनवरी, 2019 को एनएमआईसी का उद्घाटन किया।

भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी) सामान्य जन को फ़िल्म संबंधी जानकारी का भंडार उपलब्ध कराएगा और फ़िल्म निर्माताओं, फ़िल्म विद्यार्थियों, जिज्ञासुओं और समीक्षकों को न केवल देश में बल्कि विश्व के सभी भागों के बारे में कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सिनेमा के विकास की जानकारी हासिल करने में मदद करेगा। भारत में कोई फ़िल्म संग्रहालय न होने को देखते हुए इस संग्रहालय का विशेष महत्व है।

lokvk e vtk] vtk] vfio dk çfrfufèkRo

समय–समय पर सरकार के निर्देशों के अनुसार सेवा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अन्य उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व के बारे में सरकार द्वारा आदेश/निर्देश दिए जाते हैं और इस उद्देश्य के लिए, फ़िल्म प्रभाग निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार नियम बनाए जाते हैं।

31 जनवरी, 2019 को अजा, अजजा, अपिव, महिला कर्मचारियों और शारीरिक विकलांग व्यक्तियों का सेवा में प्रतिनिधित्व इस प्रकार था :

ink dk oxÊdj.k	oreku e lokjr depkfj;k dh dy l[;k	vulfpr tkfr depkjh	vu- l- depkfj;k dk %	vulfpr tkfr depkjh	vu- l- tutkfr depkfj;k dk %	vU; fiNMk oxl depkjh	vkch lh depkfj;k dk %	efgyk depkjh	'kkjhfjd fodykx
समूह क	16	3	18.75	3	18.75	5	31.25	2	–
समूह ख	163	36	22.08	9	5.52	31	19.01	24	03
समूह ग	327	93	28.44	25	7.64	84	25.68	52	13
कुल	506	132	26.08	37	7.31	120	23.71	78	16

31.01.2019 को फ़िल्म प्रभाग में अजा, अजजा, अपिव के लिए पिछले न भरे पदों का ब्योरा इस प्रकार है :

Øe l	J.kh	Loh—r dk;Zed l[;k	inklhu LVkQ	fjä ink dh l[;k	vulfpr tutkfr e u Hkj x, in	vulfpr tkfr e u Hkj x, in	vU; fiNMk oxl e u Hkj x, in
1	समूह क	31	16	15	0	0	0
2	समूह ख	192	163	29	1	0	0
3	समूह ग	386	327	59	0	0	0
	dy %	609	506	103	1	0	0

fn0;kx tu

मंत्रालय ने फ़िल्म प्रभाग में निम्नलिखित क्षेणियों के पदों का चयन दिव्यांगजनों से भरने के लिए किया है।

leg [k	leg x
सहायक ले आउट कलाकार	सहायक रिकॉर्डिस्ट
कलाकार ग्रेड I	सहायक लेआउट कलाकार
कलाकार ग्रेड II (पोस्ट को समाप्त कर दिया गया)	अपर श्रेणी लिपिक
सहायक संपादक ग्रेड I	चपरासी (एमटीएस)
सहायक	पैकर (एमटीएस)

फ़िल्म प्रभाग में समूह 'क' की रिक्तियों में कोई पद ऐसा नहीं है, जिसकी पहचान दिव्यांगजनों से भरे जाने के लिए के लिए की गई हो। सीधे भर्ती के अंतर्गत दिव्यांगजनों से भरे जाने के लिए चुने गए पदों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

leg	depkfj;k dh l[;k				
	dy	pu g, ink e l	–f"V fodykx	Jo.k fodykx	vfLFk fodykx
1	2	3	4	5	6
समूह क	31	0	0	0	0
समूह ख	192	1	0	1	2
समूह ग	386	4	0	0	13
dy %	609	5	0	1	15

fodykx 0;fä ;k ds çfrfufèkRo dk okf"kd fooj.k ¼31-01-2019½

ea=ky;@foHkkx % सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

laxXu@vèkhuLFk dk;kZy; % फ़िल्म प्रभाग

leg			deZpkfj;ksa dh la[;k		
	¼dqy 30-10-2018 rkjh[k rd½	pqus gq, inksa esa ls	–f"V fodykx	Jo.k fodykx	vfLFk fodykx
1	2	3	4	5	6
समूह क	31	0	0	0	0
समूह ख	192	1	0	1	2
समूह ग एवं घ	386	4	0	0	13
dqy	609	5	0	1	15

दिव्यांगजनों से भरे जाने वाले पदों में कोई बैकलॉग रिक्तियां नहीं हैं।

ukxfjd pkVZj

फ़िल्म प्रभाग ने फ़िल्म प्रभाग की सूचना विवरणिका (इंफॉर्मेशन ब्रोशर ऑफ फ़िल्म्स डिवीजन) शीर्षक से नागरिक चार्टर तैयार किया है, जो वेबसाइट http://www.filmsdivision.org पर उपलब्ध है। प्रभाग ने नागरिक चार्टर समुचित कार्यान्वन के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया है और फ़िल्म प्रभाग के कार्यक्रमों से सीधे संबद्ध अधिकारियों के सम्मेलन/संगोष्ठी आयोजित किए जाते हैं।

tu f'kdk;r fuokj.k O;oLFkk

सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार जन–शिकायतों के निवारण के लिए व्यवस्था की गई है। फ़िल्म प्रभाग से संबंधित जन–शिकायतों के निवारण के लिए महानिदेशक को निर्दिष्ट किया गया है। जन–शिकायतों और कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान के बारे में अपेक्षित रिपोर्ट नियमित रूप से मंत्रालय को भेजी जाती है।

fganh vuqHkkx

हिंदी अनुभाग कार्यालय पत्राचार में हिंदी (राजभाषा) के इस्तेमाल की देख–रेख करता है। फ़िल्म प्रभाग में केंद्र सरकार की राजभाषा विभाग (ओएल), गृह मंत्रालय संशोधित मानदंडों के अनुसार प्रभाग में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद सृजित किए गए हैं।

lrdZrk xfrfofèk;ka

प्रभाग के कर्मचारियों के खिलाफ सतर्कता/अनुशासनात्मक मामलों की देखरेख के लिए सतर्कता/अनुशासनात्मक मामलों की देखरेख के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय संशोधित मामलों की देखरेख के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसमें एक अधीक्षक, दो सहायक और एक अपर श्रेणी लिपिक रखे गए हैं, जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी की देखरेख में काम करते हैं।

lwpuk vfèkdkj vfèkfu;e ¼vkjVhvkÃ½

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी तत्संबंधी अनुदेशों/दिशानिर्देशों के अनुपालन में फ़िल्म प्रभाग ने प्रशासन के निर्देशक को अपील प्राधिकारी और एक उप–महनिदेशक (प्रभारी) को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में नामित/नियुक्त किया है।

सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधित सभी मामले मुख्यालय में नोडल सेक्शन अर्थात स्थापना–1 अनुभाग में निपटाए जाते हैं।

,evkÃ,Q,Q dk lekjksg izn'kZu

2018–19 (अब तक) से विभिन्न स्थानों पर एमआईएफएफ पुरस्कार विजेता फ़िल्मों के समारोह

1.	एमआईएफएफ पुदुचेरी	31 मार्च से 2 अप्रैल, 2018
2.	एमआईएफएफ पुदुचेरी	09 मार्च से 11 मार्च, 2018
3.	एमआईएफएफ मदुरै	22 मार्च, 2018
4.	एमआईएफएफ सिल्वर	22 से 24 मार्च, 2018

5.	एमआईएफएफ मणिपुर	28 से 31 मार्च, 2018
6.	एमआईएफएफ नवी मुंबई	27 से 28 अप्रैल, 2018
7.	एमआईएफएफ गुवाहाटी	21 से 24 जून, 2018
8.	एमआईएफएफ कोचीन	23 से 24 जून, 2018
9.	एमआईएफएफ नंदन	22 से 24 अगस्त, 2018
10.	एमआईएफएफ कन्नूर	15 से 16 सितंबर, 2018
11.	एमआईएफएफ कोट्टयम	28 से 29 सितंबर, 2018
12.	एमआईएफएफ कोलकाता	5 अक्तूबर, 2018
13.	एमआईएफएफ कन्नूर	9 से 10 अक्तूबर, 2018
14.	एमआईएफएफ नई दिल्ली	13 से 18 अक्तूबर, 2018
15.	एमआईएफएफ चेन्नई	25 से 27 अक्तूबर, 2018
16.	एमआईएफएफ हल्द्वानी	24 से 25 दिसंबर, 2018
17.	एमआईएफएफ पुद्दुचेरी	01 से 3 फरवरी,2019
18.	एमआईएफएफ मुर्शिदाबाद	03 से 04 फरवरी, 2019
19.	एमआईएफएफ विजयवाड़ा	12 से 14 फरवरी, 2019
20.	एमआईएफएफ आइज़ोल	12 से 13 मार्च, 2019

Hkkjrh; cky fQYe lfefr

Hkfedk

भारतीय बाल फ़िल्म समिति (सीएफएसआई) की स्थापना मई, 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बच्चों के प्रति विशेष सरोकार रखते थे, की पहल और फ़िल्म जांच समिति (1949) की सिफारिश के आधार पर की गई थी। यह संस्था समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 अंतर्गत पंजीकृत है। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को फ़िल्मों के माध्यम से 'मूल्य आधारित' मनोरंजन उपलब्ध करना है।

समिति का मुख्य इसका अध्यक्ष होता है, जो सिनेमा क्षेत्र के किसी जानेमाने व्यक्ति को बनाया जाता है। वह कार्यकारी परिषद् और सामान्य निकाय का भी प्रमुख होता है। समिति सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के तहत काम करता है, जिसके अंतर्गत सभी विभागाध्यक्ष आते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोज़मर्रा के प्रशासन, निर्माण, विपणन और लेखा कार्यां का प्रबंधन देखता है।

सीएफएसआई का मुख्यालय मुम्बई में है और इसके शाखा कार्यालय नई दिल्ली और चेन्नई में है।

fuek.k xfrfofèk;k

➢ ijh dh xÃ fQYe

पाहुना (सिक्किम फ़ीचर फ़िल्म, इंग्लिश सबटाइटल के साथ) फ़िल्म पूरी की गई और सिक्किम में 7 दिसंबर, 2017 को रिलीज हुई।

➢ fQYek dh MÇcx

एनएफडीसी के माध्यम से सीएफएसआई की 10 फ़िल्मों की डबिंग पूर्वात्तर की 6 भाषाओँ और 3 फ़िल्में की डबिंग 13 क्षेत्रीय भाषाओं में की जा रही है। 94 फ़िल्मों में से 83 फ़िल्मों को प्रमाणित किया गया है।

➢ ÇçV r;kj djuk

परिसंचरण के लिए 17 डीसीपी, 6 ब्लू किरणें और सीएफ 85 के शीर्षक के 3,854 डीवीडी तैयार किए गए थे।

➢ cky funs'kdk }kjk cukÃ xÃ fQYe

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर बच्चों (लघु निर्देशक) द्वारा महात्मा गांधी पर लघु फ़िल्में बनाई गई, सीएफएसआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, देशभर के विभिन्न स्कूलों से 128 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। इन 128 प्रविष्टियों में

से, 56 को स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा पहले ही चयनित विषयों पर वर्गीकृत किया जा चुका है जो इस प्रकार हैं :

fofHkUu fo"k;ks ij cky&funs'kdks dh fQYeks dh fjiksVZ

Øekad	fo"k;	fQYe çfof"V l[;k	dqy
1	स्वच्छता	1,16,33,60,63,115,116,117,121	9
2	अहिंसा	1,7,13,16,19,22,33,74,91,105,115,120,123,125	14
3	स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा	1,3,6,7,13,23,24,31,33,41,58,61,63, 64, 66,70,74,88,90,91,93,95, 105,112,113,117,120	27
4	सांप्रदायिक एकता	4,26,33,89	4
5	अस्पृश्यता को दूर करना	108	1
6	स्त्री सशक्तीकरण	23	1
		dqy çfof"V 128	56

foi.ku@forj.k xfrfof/k;k

forj.k

- योजना स्कीम अर्थात "स्कूलों में सीएफएसआई फ़िल्म की प्रदर्शनी" के तहत उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु के 56,038 बच्चों को शामिल करते हुए चिल्ड्रन्स फ़िल्म बोनान्ज़ा के

राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित चिल्ड्रेन्स फ़िल्म बोनान्ज़ा

- चिल्ड्रेन्स फ़िल्म बोनान्ज़ा के माध्यम से योजना स्कीम के तहत त्रिपुरा में 5,000 बच्चों को शामिल करते हुए स्कूलों में सीएफएसआई फ़िल्म की प्रदर्शनी" नॉर्थ ईस्ट के तहत 10 शो आयोजित किये गए।
- मिज़ोरम, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में DoNER मंत्रालय के तहत चिल्ड्रेन्स फ़िल्म बोनान्ज़ा के माध्यम से 12,326 बच्चों को शामिल करते हुए 26 शो आयोजित किए गए।
- 159 व्यक्तिगत शो के माध्यम से 46,749 दर्शकों को कवर किया गया और गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से मिनी त्योहारों की व्यवस्था की गई।
- खासतौर पर स्वतंत्रता दिवस पर, आम जनता विशेषकर बच्चों की भागीदारी के लिए देशभर में उत्सव और देशभक्तिपूर्ण मूड बनाने के लिए।
- बाल दिवस समारोह के अवसर पर यानी 14 नवंबर, 2018 को महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली राज्यों में 149 शो के माध्यम से 18,239 बच्चों को शामिल किया गया।
- विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर यानी 3 दिसंबर, 2018 को, दृष्टिबाधित/श्रवण बच्चों के लिए दिल्ली राज्य में विशेष शो किया गया जिसमे 150 बच्चों को शामिल किया गया था।
- महाराष्ट्र, नई दिल्ली, हरियाणा, चेन्नई, तेलंगाना, और त्रिवेंद्रम राज्यों में 27,132 बाल दर्शकों को कवर करते हुए देशभक्ति की फ़िल्मों के 57 शो आयोजित किए गए।
- महात्मा गांधीजी की 150वीं जयंती के अवसर पर, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों में 3,29,055 बच्चों को कवर करते हुए 513 शो आयोजित किए गए।
- "वैष्णव जन" गीत की एनिमेशन फ़िल्म को 2.10.2018 को वात्सल्य फाउंडेशन, महालक्ष्मी, मुंबई लिम्बोनीबॉग बीएमसी स्कूल, गोवंडी, मुंबई में सीएफएसआई फ़िल्म "अभी कल ही की बात है" के साथ प्रदर्शित किया गया।
- दो सीफ़एसआई "बापू ने कहा था" और "अभी कल ही कि बात है" की स्क्रीनिंग 06.10.2018 को मुम्बई के म्यूनिसिपल स्कूलों में वर्चुअल स्टूडियो में की गई। इस स्क्रीनिंग के माध्यम से एक समय में 338 से अधिक स्कूलों

में कम से कम 6,760 बच्चों को लाभ मिल रहा है।

- राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्क्रीनिंग (समारोहों) में 20,988 बाल दर्शकों को कवर करने के लिए 59 शो आयोजित किए गए थे।
- लोकसभा टीवी दिल्ली पर 2 फ़िल्में प्रसारित की गईं, राज्यसभा टीवी, दिल्ली पर 2 फ़िल्में और राष्ट्रीय नेटवर्क, दूरदर्शन केंद्र, नई दिल्ली पर एक फ़िल्म प्रसारित की गई।

u,Fk ÃLV e xfrfofèk;k % पहली बार सीएफएसआई प्रत्यक्ष रूप से ने राज्य सरकार के साथ पूर्वोत्तर के राज्यों त्रिपुरा, मिजोरम, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में चिल्ड्रेन्स फ़िल्म बोनान्ज़ा का आयोजन, गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी के बिना किया।

uxkyiM e lh,Q,lvkÃ fQYe Þukuh rjh ekjuhß ¼uxkeh vkj vkf'kd :i ls çgnh½ fjyht % चिल्ड्रन्स फ़िल्म सोसाइटी, इंडिया (सीएफएसआई) ने गर्व के साथ पहली बार नागामीज़ फ़िल्म "नानी तेरी मोरनी" जिसका निर्देशन आकाशिमा लामा ने किया था का प्रदर्शन किया, जिसका प्रीमियर कोहिमा, आसीईएमपीए ऑडिटोरियम में 09.10.2018 को हुआ। जिसमें सबसे कम उम्र के म्होने बेनी इबंग की बहादुरी और साहस को सलाम करते हुए बहादुरी के लिए राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार दिया।

v#.kkpy çns'k e –f"Vckfèkr cPpk d –';vkj Jo.k d fy, fQYeks dh LØhfuax % दूसरे दिन 26 अक्तूबर, 2018 को विशेष स्क्रीनिंग के दौरान डोनी पोलो स्कूल में दृश्य और श्रवण बाधित बच्चों के लिए बाल फ़िल्म बोनान्ज़ा के अंतर्गत दो फ़िल्मों की स्क्रीनिंग की गई थी। ऑडियो वर्णित सीएफएसआई फ़िल्म 'हालो' दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रदर्शित की गई थी, जबकि अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ सीएफएसआई फ़िल्म 'गौरू' श्रवण बाधित बच्चों के लिए प्रदर्शित की गई। स्पेशल स्क्रीनिंग में 15 दृष्टिबाधित बच्चे और 90 श्रवण बाधित बच्चे शामिल हुए।

lh,Q,lvkÃ fQYeks dk foi.ku

- राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम पर 'चुलबुली फ़िल्मीं चटपटी गपशप' के अंतर्गत 5 फ़िल्मों का प्रसारण किया गया जिससे 3.82 लाख रुपयों का राजस्व प्राप्त हुआ।
- लोकसभा टीवी पर 19 फ़िल्में प्रसारित की गईं, जिससे 5.01 लाख रु का राजस्व प्राप्त हुआ।
- वर्ष 2018 के दौरान विभिन्न 2,593 सीएफएसआई फ़िल्मों की डीवीडी की बिक्री की गई, जिसके परिणामस्वरूप 2,95,435 रुपये का राजस्व वसूली की गई।
- अप्रैल से दिसंबर 2018 के दौरान कुल 27,51,562 लाख रुपयों का राजस्व प्राप्त किया गया।

lh,Q,lvkÃ us fuEufyf[kr le>kSrk e çol'k fd;k gS

सीएफएसआई ने पूरे भारत में और सभी विश्व इलेक्ट्रॉनिक अधिकारों के आधार पर फ़िल्म 'टेनिस फ्रेंड्स' (हिंदी) के मंचीय रिलीज के लिए मेसर्स कैंडेल मीडिया के साथ विशेष रूप से 50:50 के अनुपात के आधार पर और राजस्व हिस्सेदारी के साथ समझौता किया। फ़िल्म के रिलीज और वितरण का सारा खर्च मैसर्स कैंडल मीडिया द्वारा वहन किया गया।

सीएफएसआई ने मैसर्स थिंक टैंक के साथ 'नानी तेरी मोरनी' (नगामी एवं आंशिक रूप से हिंदी) के लिए पूरे भारत में और सभी विश्व इलेक्ट्रॉनिक अधिकारों के लिए विशेष रूप से राजस्व हिस्सेदारी 50:50 के अनुपात में जारी करने के लिए स्थायी आधार पर मैसर्स थिंक टैंक के साथ समझौता किया। फ़िल्म के रिलीज और वितरण का सारा खर्च मैसर्स थिंक टैंक द्वारा वहन किया गया।

सीएफएसआई ने मेसर्स पर्पल पेबल पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ सिक्किम राज्य में कोलकाता, बंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, गुड़गांव और पुणे के साथ फ़िल्म 'पाहुना–द लिटिल विजिटर्स'(सिक्किम) की नाटकीय रिलीज़ के लिए समझौता किया।

सीएफएसआई ने मेसर्स कारादी टेल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ पूरे भारत में फ़िल्म 'गोपी गवइया बाघा बैजय्या' (हिंदी) की नाटकीय रिलीज़ के लिए समझौता किया। फ़िल्म के रिलीज और वितरण का सारा खर्च मैसर्स कारादी टेल्स प्रा. लिमिटेड ने वहन किया।

vrjjk"Vªh; fQYe lekjksgksa e Hkkxhnkjh

सीएफएसआई की 38 फ़िल्मों ने 40 देशों में 82 अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों में भाग लिया।

fQYe ,M Vsyhfotu bLVhV;wV vkWQ bafM;k] iq.ks

1960 में स्थापित फ़िल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 1974 में टेलीविजन विंग को जोड़ा गया। इसका नाम बदलकर 'फ़िल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' रखा गया और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन, 1860 के तहत अक्तूबर, 1974 में इसे एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। एफटीआईआई सोसायटी जो अध्यक्ष द्वारा संचालित फ़िल्म, टेलीविज़न, संचार, संस्कृति के साथ जुड़, संस्थान के पूर्व छात्रों और पूर्व–सरकारी अधिकारियों,

प्रतिष्ठित व्यक्ति और एक गवर्निंग काउंसिल द्वारा शासित है।

संस्थान के दो स्कंध हैं– फ़िल्म और टेलीविजन स्कंध। जो फ़िल्म और टेलीविजन दोनों में पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सिनेमेटोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग और साउंड डिज़ाइन, के पाठक्रम शामिल है। संपादन और डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन डिज़ाइन का पुरस्कार दिया जाता है। संस्थान एक्टिंग में दो साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स, फ़ीचर फ़िल्म स्क्रीनप्ले राइटिंग में एक साल का पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रदान करता है। टेलीविजन पाठ्यक्रम में निर्देशन, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमेटोग्राफी, वीडियो संपादन, साउंड रिकॉर्डिंग और टीवी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ टेलीविज़न में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं।

o"kZ dk nkjku çeq[k xfrfofèk;k

- पहली बार वर्ष 2018 में एफटीआईआई, पुणे और एसआरएफटीआई, कोलकाता दोनों के पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित 21 केंद्रों पर आयोजित संयुक्त और अखिल भारतीय स्तर की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी।
- 120 कोर्स जैसे फ़िल्म अभिमूल्यन, अभिनय, डिजिटल सिनेमेटोग्राफी, टेलिविजन के लिए लेखन, फ़िल्म बोध, स्टिल फोटोग्राफी, भारतीय गीतों की सराहना, एनिमेशन एंड वीएफएक्स (विज़ुअल इफ़ेक्ट्स) बच्चों के लिए समान्य एक्टिंग वर्कशॉप, डिजिटल फ़िल्म प्रोडक्शन का संचालन किया गया। जिसमें 5,250 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।
- 7 दिसंबर, 2018 को फ़िल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) पुणे के बढ़ते बुनियादी ढांचे के अंतर्गत अत्याधुनिक क्लासरूम थियेटर (सीआरटी) जोड़े गए। प्रसिद्ध फ़िल्म निर्माता और एफटीआईआई के पूर्व छात्र श्रीराम राघवन, जिनकी नवीनतम हिंदी थ्रिलर फ़िल्म 'अंधाधुन' काफी सराही गई है ने औपचारिक रूप से परिसर खोला।
- एफटीआईआई, पुणे में ग्रष्मिकालीन फ़िल्म प्रशंसा (एफए) पाठ्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें देश के 15 राज्यों और नेपाल और कनाडा से 90 प्रतिभागियों (31 महिलाओं, 59 पुरुषों) ने भाग लिया। एफटीआईआई परिसर में चार बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तमिल फ़िल्म निर्माता, पटकथा लेखक और निर्माता वेट्री मारन ने फ़िल्म प्रशंसा पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया।
- 7–22 दिसंबर, 2018 से एनएफएआई फेस–2 ऑडिटोरियम, कोथ्रुद, पुणे में दूसरा 2 शीतकालीन फ़िल्म प्रशंसा पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम का आयोजन भारत के राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार, पुणे के समन्वय में किया जा रहा है। कोर्स में कुल 65 प्रतिभागियों ने दाखिला लिया था। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता

नई दिल्ली में 3 मई, 2018 को 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए ए. आर. रहमान को रजत कमल प्रदान करते हुए माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द। इस अवसर पर टेक्सटाइल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्रीमती स्मृति ईरानी तथा युवा मामले एवं खेल और सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी उपस्थित थे

फ़िल्म निर्माता और एफटीआईआई की पूर्व छात्र सुश्री अरुणराजे पाटिल द्वारा संचालित किया गया था।

- एफटीआईआई के छात्रों की तीन फ़िल्में अरुण कुप्पुस्वामी (निर्देशक : मन्डे), मेधप्रणव पोवार (निर्देशक : हैप्पी बर्थडे) और स्वप्निल कपूर (निर्देशक : भर दुपहरी) को 3 मई, 2018 को नई दिल्ली में 65 वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार समारोह में गैर फ़ीचर फ़िल्म श्रेणी में सम्मान मिला।
- एफटीआईआई के कला निर्देशन विभाग ने महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एफटीआईआई मेन गेट पर साबरमती आश्रम, अहमदाबाद की प्रतिकृति स्थापित की। स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी 15 अगस्त, 2018 को सार्वजनिक रूप से प्रतिकृति को रखा गया था।
- महाराष्ट्र के ज़ादीपट्टी क्षेत्र (गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरोली, भंडारा) के कलाकारों के लिए विभिन्न कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एफटीआईआई और डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसके अंतर्गत 20 अगस्त, 2018 से 13 सितंबर, 2018 तक एक्टिंग का प्रथम फाउंडेशन कोर्स आयोजित किया गया।
- एफटीआईआई ने 11 से 12 अगस्त, 2018 को ओपन डेज आयोजित किया, जिसमें लोगों को फ़िल्म निर्माण प्रक्रियाओं, बुनियादी ढांचे और संस्थान की समृद्ध विरासत को जानने हेतु सक्षम बनाने के लिए यात्रा संचालित की गई। एफटीआईआई में 3,800 से अधिक दर्शकों के आगमन की सुविधा के साथ इसके कर्मचारियों और विभाग द्वारा पुणे में समुदाय के साथ एक पुल के निर्माण में मदद की।
- एफटीआईआई ने स्वतंत्रता दिवस, 2018 को चिह्नित करने के लिए "फिटनेस" विषय पर एक संगीत वीडियो जारी किया। शारीरिक स्वस्थता विषय पर बना और संगीतबद्ध किया गया यह वीडियो विभाग की अपनी प्रस्तुति है। वीडियो 15 अगस्त को संस्थान के सोशल मीडिया खातों पर जारी किया गया था।
- एफटीआईआई के प्रांगण में एफटीआईआई के कर्मचारियों के 19 से 20 अप्रैल, 2018 तक 'क्रिएटिंग ए न्यू पैराडिग्म' पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मजागरुकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के जरिए प्रदर्शन और कार्यक्षमता में सुधार था। इस कार्यशाला में संवादात्मक–अभ्यास शामिल था, जिसमें प्रतिभागी आत्मखोज की एक प्रक्रिया से गुज़र कर स्वयं की इंसानी बनावट के बारे में जागरूक हो सके।
- एफटीआईआई में जिम सुविधा का उद्घाटन 23 अप्रैल, 2018 को माननीय संसद सदस्य श्री अनिल शिरोले के कर–कमलों द्वारा किया गया।
- योग कक्षा शिक्षक, सुश्री शैलजा भट्ट द्वारा 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के एक भाग के रूप में एफटीआईआई में 21 जून, 2018 को प्रातः 7:30 बजे से 8:30 बजे तक योग की एक विशेष कक्षा आयोजित की गई।
- कैनन इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ काजुतादा कोबायाशी ने अपनी टीम के साथ 8 जून, 2018 को एफटीआईआई का दौरा किया। एफटीआईआई टीम ने परिसर के दौरे के बाद फ़िल्म और टेलीविजन पहल (एसकेआईएफटी) कार्यक्रम में एफटीआईआई के स्किलिंग इंडिया की प्रगति पर चर्चा की। कैनन एसकेआईएफटी का प्रौद्योगिकी भागीदार हैं।
- एफटीआईआई मार्च 2019 में अपने छठे ओपन डे का अनुपालन करेगा। संस्थान ओपन डे के दौरान आगंतुकों को निर्देशित दौरा मुहैया करवाएगा। इस दौरे में विजडम ट्री, स्टूडियो एक साउंड विभाग, पुनर्वसन चैंबर, प्रभात संग्रहालय, शांताराम तालाब और टीवी स्टूडियो जैसे स्पॉट्स शामिल होंगे। प्रत्येक दौरा डेढ़ से दो घंटे की अवधि का होगा। पहले दिन स्कूली बच्चे, दिव्यांग बच्चे, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे जबकि दूसरे दिन, सामान्य जनता को संस्थान का दौरा करने की अनुमति दी जाएगी।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, विभिन्न विषयों पर एफटीआईआई में कई अतिथि व्याख्यान/कार्यशाला/सेमिनार/मास्टर कक्षाएं आयोजित की गईं।
- एफटीआईआई के मुख्य थियेटर में 2017 के एक्टिंग बैच द्वारा संगीतमय नाटक 'दुविधा' का प्रदर्शन किया गया।

fQYe lekjkg e ,QVhvkÃvkÃ fQYek dh Hkkxhnkjh

- 16 से 23 जून, 2018 को ईरान में नाहल स्टूडेंट शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल तेहरान का 15वां संस्करण।
- 2018 बाफ्टा छात्र फ़िल्म पुरस्कार, लॉस एंजिल्स 12 जुलाई 2018 को आयोजित किया गया।
- पोस्टिरा सीसाइड फ़िल्म फेस्टिवल पोस्टारिया, क्रोएशिया का 8वां संस्करण 24 से 28 जुलाई, 2018 को आयोजित किया गया।
- 21वां अंतरराष्ट्रीय वीडियो महोत्सव विडियोमेडिजा, सर्बिया 31 अगस्त से 2 सितंबर, 2018 तक आयोजित किया गया।
- 16वां प्योंगयांग अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव प्योंगयांग,

उत्तर कोरिया 19 से 28 सितंबर, 2018 को आयोजित किया गया।

- बीजिंग फ़िल्म अकादमी (आईएसएफवीएफ), बीजिंग, चीन के 16वें अंतरराष्ट्रीय छात्र फ़िल्म और वीडियो महोत्सव 21 से 28 अक्तूबर, 2018 तक आयोजित।
- अक्तूबर, 2018 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, कैलिफोर्निया, यूएसए द्वारा छात्र अकादमी पुरस्कार।
- 16वां एशियाई अंतरराष्ट्रीय लघु फ़िल्म महोत्सव, दक्षिण कोरिया में 1 से 6 नवंबर, 2018 को आयोजित किया गया।
- 21वां अंतरराष्ट्रीय कुर्ज़फ़िल्मेट विंटरथुर स्विट्ज़रलैंड का लघु फ़िल्म समारोह, 6 से 11 नवंबर, 2018 को आयोजित किया गया।
- 7 और 8 नवंबर, 2018 को वैश्विक चीनी विश्वविद्यालय छात्र फ़िल्म और टीवी महोत्सव, चीन आयोजित हुआ।
- 10–17 नवंबर, 2018 को पोलैंड की आर्ट ऑफ़ सिनेमैटोग्राफी ब्यडगोस्ज़कज़ का कैमरिमेज 25वां अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह आयोजित हुआ।
- 33ई एन्ट्रेवल्स बेलफोर्ट फेस्टिवल अंतरराष्ट्रीय ड्यू फ़िल्म, पेरिस, फ्रांस 17 से 25 नवंबर, 2018 तक।
- भारत का 48वां अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, 20 से 28 नवंबर, 2018 तक गोवा।
- क्योटो अंतरराष्ट्रीय छात्र फ़िल्म और वीडियो महोत्सव 2018, नवंबर 2018।
- 30 नवंबर और 7 दिसंबर, 2018 से पोयटर्स फ़िल्म फेस्टिवल, फ्रांस।
- 22वां सिनेमाइबिट अंतरराष्ट्रीय छात्र फ़िल्म महोत्सव, बुचारेस्ट, 4 से 8 दिसंबर, 2018।
- 6 से 11 दिसंबर, 2018 तक 18वीं नदी से नदी फ्लोरेंस भारतीय फ़िल्म महोत्सव, इटालिया।
- 13वां पुंटो डे विस्टा फ़िल्म फेस्टिवल, 11 से 16 मार्च 2019 तक न वारा, स्पेन।

,QVhvkÃvkbZ fQYek dk çkIr iqjLdkj

Øa-la-	fnukad	fQYe	iqjLdkj
		Hkkjrh;	
1.	मई 2018	भर दुपहरी	निर्देशक स्वप्निल कपूर ने 65वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन पुरस्कार प्राप्त किया।
2.	मई 2018	हैप्पी बर्थडे	65वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार समारोह में रजत कमल के साथ पारिवारिक मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार श्री मेधप्रणव पोवार ने जीता
3.	मई 2018	मंडे	65वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार समारोह में रजत कमल के साथ स्पेशल जूरी पुरस्कार श्री अरुण कुप्पूस्वामी ने जीता
4.	जून 2018	हैप्पी बर्थडे	कश्मीर वर्ल्ड फ़िल्म समारोह की विद्यार्थी प्रतियोगिता क्षेणी में निर्देशक श्री मेधप्रणव पोवार ने पुरस्कार जीता।
		fons'kh	
5.	मई 2018	एकांत	निर्देशक सार्थक भसीन ने ”एएमआईआरएएनआई” 2018 के तब्लीसी अंतरराष्ट्रीय छात्र फ़िल्म महोत्सव, जॉर्जिया ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिक्शन पुरस्कार जीता।
6.	अगस्त 2018	थिया (लेबर अड्डा)	निर्देशक स्वप्निल कपूर की फ़िल्म ने ’द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ़ फ़िल्म एंड टेलीविज़न स्कूल, सीआईएलईसीती, बुल्गारिया में कापा सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार जीता।

fo|kFkÊ vknku&çnku dk;Øe

- yk Qfeal ,Dlpsat çksxzke % 4 फरवरी–1 मार्च, 2019 तक ला फेमिस ने अपने कला निर्देशन संकाय से चार विद्यार्थी आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत एफटीआईआई के कला निर्देशन विभाग को भेजे गएं। छात्रों ने एफटीआईआई के छात्रों की परियोजनाओं पर काम किया और भारतीय फ़िल्म निर्माण में कला निर्देशन की बारीकियों को सीखा।
- vkÃ,Q,l] dksyu fo|kFkÊ vknku&çnku dk;Øe% आईएफएस, कोलन, जर्मनी ने अपने निर्देशन संकाय से एक विद्यार्थी को विद्यार्थी आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत एफटीआईआई के कला विभाग को सौंपा। 7 फरवरी–15 मार्च, 2019 तक इन छात्रों ने एफटीआईआई की छात्र परियोजना का काम करेगा और भारतीय फ़िल्म निर्माण में दिशा और कहानी की बारीकियों को सीखा।
- xqfQFk fo'ofo|ky; ds Nk= vknku&çnku

dk;Øe % ग्रिफिथ विश्वविद्यालय, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया ने 20 फरवरी–2 मार्च, 2019 से एफटीआईआई के बदले छात्रों और संकाय सदस्यों को भेजा। इस आदान–प्रदान में ग्रिफिथ विश्वविद्यालय के छात्रों और एफटीआईआई के छात्रों द्वारा महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों में लघु वृत्तचित्र निर्माण किया गया। छात्रों को 4–5 समूहों में विभाजित किया गया और स्थानीय मुद्दों पर वृत्तचित्र बनाने और शोध करने के लिए विभिन्न स्थानों पर भेजा गया। समूहों और संकाय सदस्यों के बीच एक संयुक्त स्क्रीनिंग और आपसी संवाद–सत्र आयोजित किया गया।

lR;ftr js fQYe vkSj Vsyhfotu laLFkku

सत्यजीत रे फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई) की स्थापना 1995 में एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में की गई थी और इसे पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत किया गया है। प्रसिद्ध फ़िल्म उस्ताद सत्यजीत रे के नाम पर, संस्थान 3 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करता है। छह विशेषताओं में पाठ्यक्रम–(1) निर्देशन और पटकथा लेखन (2) छायांकन (3) संपादन (4) साउंड रिकॉर्डिंग और डिज़ाइन, (5) फ़िल्म और टेलीविजन के लिए निर्माण और (6) एनिमेशन सिनेमा प्रदान करता है।

एसआरएफटीआई ने 14.08.2017 से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल मीडिया (ई एंड डीएम) पर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किया है। पाठ्यक्रमों का विवरण (1) इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए लेखन (2) इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्रबंधन (3) इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए वीडियोग्राफी (4) इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए उत्पादन (5) इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए संपादन (6) इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए ध्वनि।

o"kZ dh xfrfof/k;k

- सत्यजित रे फ़िल्म एवं टेलीविजन संस्थान ने फेडरेशन ऑफ फ़िल्म सोसायटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एसआरएफटीआई में 10 अप्रैल, 2018 को पहली दक्षिण एशियाई लघु फ़िल्म महोत्सव के पुरस्कार विजेता फ़िल्मों की स्क्रीनिंग का आयोजन किया था।
- 2018 में पहली बार, एफटीआईआई, पुणे और एसआरएफटीआई, कोलकाता दोनों के पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 21 केंद्रों पर एक संयुक्त और अखिल भारतीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया गया।
- 20 सप्ताह के स्व–वित्तपोषित लघु अवधि के लिए स्क्रीन एक्टिंग कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। 27 अप्रैल, 2018 को छात्रों को प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए।
- इस संस्थान के 11वे बैच के छात्रों के लिए 8वें दीक्षांत समारोह 2 मई, 2018 को प्रसिद्ध फ़िल्म उस्ताद सत्यजीत रे की 97वीं जयंती के दिन आयोजित किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फ़िल्म–निर्माता श्री सईद अख्तर मिर्ज़ा, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और 8वें दीक्षांत समारोह में अतिथि के रूप में प्रख्यात फ़िल्म निर्देशक श्री कुमार शाहनी मौजूद रहे।
- एसआरएफटीआई की 14वीं बैच की एनीमेशन सिनेमा की छात्रा मिस सूचना साहा को 5 से 24 जुलाई, 2018 तक मोओएससीओडब्लू और क्रास्नोडार में आयोजित द वीजीआईके इंटरनेशनल समर स्कूल में भाग लेने के लिए चुना गया।
- एसआरएफटीआई ने फ़िल्म महोत्सव निदेशालय के साथ मिलकर 23 से 29 जुलाई, 2018 तक यूरोपीय संघ फ़िल्म महोत्सव–2018 का आयोजन किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कोलकाता में इटली के महावाणिज्य दूत श्री दामियानो फ्रान्कोविघ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
- एसआरएफटीआई ने पश्चिम बंगाल के जिलों में आउटरीच कार्यक्रमों के रूप में 28 जुलाई, 2018 से डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, सिनेमैटोग्राफी, एडिटिंग और साउंड डिजाइन में फ़िल्म एक्टिंग और डिजिटल फ़िल्म निर्माण पर दो महीने के बुनियादी कोर्स की श्रृंखला शुरू की।
- एसआरएफटीआई को मानव संसाधन विकास के प्रौद्योगिकी संवर्धित अध्ययन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, (एनपीटीईएल) 'स्वयं' (स्टडी वेब्स ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड के लिए स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम) को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करते हुए प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है।
- अमेरिकी लाइब्रेरी कांग्रेस, एसआरएफटीआई के छात्रों की फ़िल्मों को संग्रहित कर रही है, जिनका उपयोग विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों और आईवीवाई लीग इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के बीच शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
- संस्थान ने 9 जुलाई से 31 अगस्त, 2018 तक बीएनए, लखनऊ के छात्रों के लिए 56 दिवसीय फ़िल्म बोध पाठ्यक्रम का सफल आयोजन किया।
- एसआरएफटीआई और ढाका विश्वविद्यालय के फ़िल्म, टेलीविजन और फोटोग्राफी विभाग ने 25 सितंबर, 2018

को छात्रों के आदान–प्रदान कार्यक्रम के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन (एमएसटीसी) लिमिटेड ने एसआरएफटीआई को 'स्वच्छ भारत मिशन' पर फ़िल्म और एक अन्य प्रचार फ़िल्म के लिए सम्मानित किया।
- सत्यजीत रे फ़िल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ने अलाइड आर्ट्स के सहयोग से 29 अक्तूबर से आधुनिक यूरोपीय सिनेमा पर 29 अक्तूबर से 2 नवंबर, 2018 तक एक सत्र आयोजित किया जहां विभिन्न देशों के यूरोपीय संघ की पांच फ़िल्मों की स्क्रीनिंग की गई।
- एसआरएफटीआई संकाय नवंबर 2018 से दूरदर्शन, कोलकाता के लिए डिजिटल प्रलेखन की वीटिंग प्रक्रिया में लगे हुए हैं।
- एसआरएफटीआई ने संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की एक परियोजना, वाराणसी के मन मंदिर में वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम में स्क्रीनिंग के लिए एक द्विभाषी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म 'बनारस परिचय' का निर्माण किया।
- 1 दिसंबर, 2018 को एसआरएफटीआई ने परबो कगाज के साथ मिलकर फ़िल्म और टेलीविजन के लिए निर्माण संबंधित दूसरा राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रख्यात फ़िल्म निर्देशक राहुल रवैल ने मुख्य भाषण दिया।
- एसआरएफटीआई ने जादवपुर विश्वविद्यालय के साथ 7 दिसंबर, 2018 को यूजीसी से संबद्ध कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए चौथे ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया।
- एसआरएफटीआई, पीयरलेस ग्रुप और रामकृष्ण मिशन के सहयोग से फ़िल्म निर्माण और संबंधित व्यावसायिक विषयों के क्षेत्र में कौशल भारत पहल शुरू करेगा।
- विदेशी पेशेवरों के लिए एसआरएफटीआई ने 21 जनवरी से 16 मार्च, 2019 तक आईटीईसी–एमईएम (विदेश मंत्रालय) कार्यक्रम के तहत 'परिचय और सिनेमा के सौंदर्यशास्त्र' पर 8 सप्ताह के लघु पाठ्यक्रम का आयोजन किया।
- एसआरएफटीआई 16 से 31 जनवरी, 2019 तक गणतंत्र दिवस और स्वच्छ भारत पखवाड़ा का आयोजन किया।

fo|kFk;k }kjk cukÃ xÃ fQYek dk fQYekRlok vkj i|jLdkjk d fy, p;u

Øe la-	MkD;qesVªh fQYe dk uke	funs'kd	fQYe lekjksg esa iqjLdkj ds fy, p;fur
1.	अम्माकाय	अशिता नायर	अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र और लघु फिल्म समारोह में चयनित
2.	भूमि	मिथुन चंद्रन	
3.	जीआई	कुंजिला मस्किलमणि	
4.	चौकाथ	मोइनक गुहा	
5.	नवाबी बालूचरी	तृषा बनर्जी	"रूट्स ऑफ यूरोप इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल" स्पेन के आधिकारिक एजेंडे के लिए चयनित।
6.	अस्तित्व	शरद उइके	एनीमेशन सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा 'एनिफेस्ट, मुंबई' के लिए चुना गया
7	मां तुकी	सुहाना साहा	एनिफेस्ट, मुंबई में दो पुरस्कार जीते और 38वें वीजीआईके अंतरराष्ट्रीय छात्र फ़िल्म समारोह में पुरस्कृत किया गया।
8	डिस्सेंटिंग रिज़ेस	अचुतनकुट्टी ए अच्युतन	38वें वीजीआईके अंतरराष्ट्रीय छात्र फ़िल्म समारोह में पुरस्कृत।
9	नवाबी बालूचरी	तृषा बनर्जी	पोर्टलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में ओरेगन सिनेमा कला फ़िल्म महोत्सव में चयनित।
10	फाइंड मी मदर	सूचना साहा	मास्को,रूस के ग्रासनाद्र में वीजीआईके इंटरनेशनल समर स्कूल के अंतरराष्ट्रीय चयन में प्रदर्शित।
11.	ईथर वरुम्बुकल	अचुतन कुट्टी	
12	फॉर द मदर इनसाइड	अशिथा नायर	स्माइल इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ (एसआईएफएफसीवाई), दिल्ली में स्क्रीनिंग के लिए चयनित।
13	इनसाइड	रेमीया राजीव	
14	लुक एट द स्काई	अशोक वैलो	24वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव– 2018 में सर्वश्रेष्ठ लघु फ़िल्म के लिए पुरस्कृत।

15	छुटकी	निधि तनेजा	16वें कल्पनिर्झर फ़िल्म महोत्सव– 2018, कोलकाता में स्क्रीनिंग के लिए चयनित।
16	भगवती	आकाश निगम	

v#.kkpy çn'k e fQYe vkj Vyhfotu lLFkku ¼iokUkj {k=½

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास और फ़िल्म और टेलीविजन क्षेत्र में उत्तर पूर्व के युवाओं के बीच प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की पहल के एक हिस्से के रूप में, मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में से किसी एक में फ़िल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे (एफटीआईआई) और सत्यजीत रे फ़िल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई) के तर्ज़ पर फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया।

वर्तमान में, एक अस्थायी परिसर में फ़िल्म और टेलीविजन क्षेत्र से संबंधित लघु अवधि के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

fo|kFk;k dk vknku&çnku dk;Øe

25 सितंबर, 2018 को एसआरएफटीआई और ढाका विश्वविद्यालय के फ़िल्म, टेलीविजन और फोटोग्राफी विभाग ने छात्रों के आदान–प्रदान कार्यक्रम के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

Hkkjr dk jk"Vªh; fQYe vfHkys[kkxkj ,d >yd

फ़िल्म को कला और ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में संरक्षित करने की आवश्यकता को पूरे विश्व में मान्यता दी गई है। सिनेमा को उसके सभी विविध अभिव्यक्तियों और रूपों में संरक्षित करने का काम एक राष्ट्रीय संगठन को सौंपा गया है जिसके पास पर्याप्त संसाधन, एक स्थायी सेटअप और स्थानीय फ़िल्म उद्योग में आस्था है। इस प्रकार, भारत के राष्ट्रीय फ़िल्म पुरालेख को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र मीडिया इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। नेशनल फ़िल्म आर्काइव ऑफ़ इंडिया, सरकार के इस अहसास का नतीजा है कि फ़िल्में, किताबों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेज़ों की तरह ही मूल्यवान हैं और देश की फ़िल्म विरासत को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने की ज़रूरत है।

भारतीय सिनेमा की विरासत को प्राप्त करने और संरक्षित करने के प्राथमिक चार्टर के अलावा, यह भी पुरालेख के घोषित उद्देश्यों में से एक है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक उपस्थिति दुनियाभर में और अधिक बढ़े।

हर सोसाइटी की चल रही छवि धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण है और इसकी सांस्कृतिक विरासत का निश्चय ही हिस्सा है। चलायमान छवि विरासत का संरक्षण ज्यादातर देशों में सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। चलायमान छवि धरोहर की सुरक्षा के लिए यूनेस्को जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा दिया जा रहा समर्थन सदस्य देशों की गतिविधि के महत्व का प्रमाण है। भारत में एनएफएआई एकमात्र संगठन है जिसे भारत की समृद्ध और विविध सिनेमाई विरासत को प्राप्त करने और संरक्षित करने का काम सौंपा गया है।

राष्ट्रीय फ़िल्म पुरालेख को फरवरी 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक मीडिया इकाई के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. भावी पीढ़ी के राष्ट्रीय सिनेमा की धरोहर का पता लगाने, उसे हासिल और संरक्षित करना और विश्व सिनेमा और राष्ट्रीय सिनेमा का प्रतिनिधि संग्रह तैयार करना।
2. फ़िल्म से संबंधित आकड़ों का वर्गीकरण और प्रलेखन और सिनेमा पर शोध संकलित और प्रोत्साहित करना और प्रकाशित कर उन्हें वितरित करना।
3. देश में फ़िल्म संस्कृति के संप्रेषण के लिए एक केंद्र के रूप में काम करना और विदेशों में भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक मौजूदगी सुनिश्चित करना।

,u,Q,vkÃ dh fQYe lxg.k uhfr

- भारत में फ़िल्मों के लिए राज्य पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों में पुरस्कार एवं गुणवत्ता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने वाली फ़िल्में।
- अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों के भारतीय पैनोरमा खंड में दिखाई जाने वाली फ़िल्में।
- बॉक्स ऑफिस पर लोकप्रियता हासिल करने वाली फ़िल्में और भारत और विदेश में बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करने वाली फ़िल्में।
- भारतीय और विदेशी, दोनों तरह की जानी–मानी सहित्यिक कृतियों का फ़िल्म रूपांतरण।
- भारतीय और विदेशी स्थानीय परिवेश में शूट की गई तथा भारतीय अथवा विदेशी निर्माताओं द्वारा बनाई गई फ़िल्में ।
- एनएफडीसी और अन्य सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित/निर्मित सभी फ़िल्में।

- बेहतरीन बाल फ़िल्मों के विशिष्ट नमूने।
- भारतीय और विदेशी फ़िल्म निर्माताओं द्वारा की गई समाचार कवरेज में दर्ज़ यथार्थ सामग्री वाली फ़िल्में।
- सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक महत्व के वृत्तचित्र।

t ;dj cxyk

पुणे में लॉ कॉलेज रोड पर एनएफएआई के मुख्य परिसर में स्थित, बैरिस्टर मुकुल आर. जयकर के निवास "जयकर बंगला" को एक धरोहर इमारत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैरिस्टर मुकुल आर. जयकर जाने–माने शिक्षाविद और विधि विशेषज्ञ थे, जो पुणे विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बने और उन्होंने पुणे की समृद्ध विरासत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लकड़ी की सीढ़ियों और खिड़कियों के साथ इमारत के पत्थर में एक सभ्य ठोस संरचना का समावेश है।

1964 में भारतीय फ़िल्म संस्थान, पुणे के परिसर में अस्थायी कमरों के लघु शेडों में हुई सामान्य शुरुआत के बाद मई 1974 में एनएफएआई का कार्यालय जयकर बंगले में स्थानांतरित किया गया। एनएफएआई ने मार्च 1981 में दो एकड़ भूमि के साथ इंडियन लॉ सोसायटी से जयकार बंगला अधिग्रहीत किया था। जयकर बंगले में एनएफएआई ने अपना कार्यालय जनवरी 1994 तक रखा। उसके बाद एनएफएआई को उसी परिसर में अपना एक नया भवन मिला, जहां फ़िल्म कक्षों का डिज़ाइन अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म संस्थान मानकों के साथ तैयार किया गया है, उपयुक्त रूप से सुसज्जित संरक्षण विभाग हैं, काफी मात्रा में किताबें हैं और पत्र–पत्रिकाओं का पुस्तकालय है और एक कैटलॉग, अनुसंधान और प्रलेखन केंद्र है, जिसमें सिनेमा पोस्टर, अचल चित्रों और अन्य अनुषंगी सामग्री का एक अनमोल संग्रहालय भी है। अभिलेखागार में 3 सिनेमा ऑडिटोरियम हैं, जहां वह अपने संग्रह से जनता के लिए फ़िल्मों का प्रदर्शन भी करता है।

धरोहर होने के कारण जयकर बंगले का ऐतिहासिक मूल्य है और इसे भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर स्थिति में संरक्षित रखने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने जयकर बंगले के संरक्षण कार्य और डिजिटल पुस्तकालय के लिए अपेक्षित ढांचे की स्थापना हेतु 9 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

gky d fnuk e egRoi.k vfèkxg.k

वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण प्रतिष्ठित आर. के. स्टूडियो के 21 फ़िल्मों के निगेटिव्स को जोड़ना था।

(1) बॉबी (2) धरम करम (3) सत्यम शिवम सुंदरम (4) बीवी ओ बीवी (5) प्रेम रोग (6) राम तेरी गंगा मैली (7) आग (8) बरसात (9) आवारा (10) आह (11) बूट पॉलिश (12) श्री 420 (13) जागते रहो (14) एक दिन रात्रि (बंगाली) (15) जिस देश में गंगा बहती है (16) संगम (17) मेरा नाम जोकर (18) हीना (19) प्रेम ग्रंथ (20) आ अब लौट चल (21) कल आज और कल।

egku lxhrdkj 'kdj dk 0;fäxr fi;kuk अब एनएफएआई संग्रह का हिस्सा है! शंकर के पोते श्री संतोष कुमार ने पियानो एनएफएआई को उपहार स्वरूप दिया।

विभिन्न नंबरों के 89 नंबर वीएचएस/युएमएटीआईसी/बीटा टेप एम/एस हाइफ़न फ़िल्म लंदन (नसरीन मुन्नी कबीर) द्वारा प्राप्त हुए।

(i) 35 मिमी में 10 फ़िल्में और 16 मिमी में 22 लघु फ़िल्में चंदन फ़िल्म कोलार, कर्नाटक से (रेडीमेड खरीद समिति द्वारा अनुमोदित)।

(ii) 16 मिमी में एक फ़िल्म "सती सावित्री" (मराठी), अमर फ़िल्म (पी) लिमिटेड, मुंबई (समिति द्वारा अनुमोदित रेडीमेड खरीद) से।

(iii) 10 शीर्षक–फ़िल्म लैब प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से 35 मिमी में रिलीज़ प्रिंट, पिक्चर निगेटिव और साउंड निगेटिव (हमारे मास्टर प्रिंट से प्राप्त आदेश के अनुसार)।

ç"kd%&जयराज पुनतार एम/एस अजीत पिक्चर्स मुंबई (संभावित रेडीमेड खरीद के रूप में)।

(i) श्री राम अवतार–16 मिमी

(ii) चालबाज़–16 मिमी

(iii) पैसा हाय पैसा–16 मिमी

(iv) एआईसीसी–1938 फैजपुर कांग्रेस – 35 मिमी

(v) आज का अर्जुन–35 मिमी

(vi) डेकरिना मांडव–35 मिमी (गुजराती)

Jh vrqy [kkjc }kjk lkisi x, iqjkus fMLd fjd,M

ये रिकॉर्ड 78 आरपीएम, एलपी प्रकारों में हैं। इसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, धार्मिक संगीत, गैर–शास्त्रीय संगीत, फ़िल्म संगीत, मराठी फ़िल्में और थियेटर आदि शामिल हैं।

iqjkus v,fM;k dlsV1 ,i- 1000] स्वर्गीय श्री भालचंद्र वानी की बेटी अमृता वानी द्वारा सौपें गए।

इस संग्रह में ज्यादातर मराठी शास्त्रीय संगीत और बॉलीवुड फ़िल्मी गाने शामिल हैं।

vkfny tqlkokyk% 70 vkj 80 d n'kd dh iqjkuh

Ýklhlh if=dk,¡A

एनएफएआई ने 121 पुरानी फ्रांसीसी फ़िल्म पत्रिकाओं का एक संग्रह प्राप्त किया है। संग्रह में ला रिव्यू डु सिनेमा, इक्रान और ले नोव्यू सिनेमा के मुद्दे शामिल हैं। भव्य कवर से सुसज्जित और विश्व सिनेमा के सितारों को कैथरीन डेनेव्वे से लेकर अल पचीनो से तकाशी शिमुरा तक, ये पत्रिकाएं सिनेमा की जादुई दुनिया में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। भले ही ये सभी मुद्दे 70 और 80 के दशक में प्रकाशित किए गए थे, लेकिन इनमें पुराने क्लासिक्स पर लेखन शामिल हैं, जिनमें अन चिएन एंडालॉ (1929), मैन विथ एक मूवी कैमरा (1929) और आईकीरू (1952) शामिल हैं। यह संग्रह प्रसिद्ध भारतीय कवि और संपादक आदिल जुसावाला के सौजन्य से एनएफएआई द्वारा अधिग्रहित किया गया था।

fQYe HkaMkj.k@laj{k.k

एनएफएआई लगभग 27 अत्याधुनिक, फ़िल्म संरक्षण सुविधाओं/अभिलेखागार मानकों और विनिर्देशों के साथ वाल्ट को आश्रय देता है। इन वॉल्ट्स में लगभग 2 लाख फ़िल्म रीलों के भंडारण की क्षमता है। ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्मों, रंगीन फ़िल्मों और नाइट्रेट आधारित फ़िल्मों के लिए निम्न तापमान के साथ फ़िल्म वाल्ट्स बनाए रखे जाते हैं:–

fQYeksa dk çdkj	rkieku	lkisf{k vknzZrk
नाइट्रेट फ़िल्म	10 डिग्री–12 डिग्री	सी 40 फीसदी
ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्में	10 डिग्री– 12 डिग्री C	40 प्रतिशत +/–5
रंगीन फ़िल्में	2 डिग्री–4 डिग्री C	30 प्रतिशत +/–5

fQYe lekjksg esa Hkkxhnkjh

16oka iq.ks varjjk"Vªh; fQYe egksRlo ¼ihvkÃ,Q,Q½ 2018 % 11 से 18 जून, 2018 तक आयोजित किया गया और मुख्य थियेटर में प्रतिदिन तीन स्क्रीनिंग आयोजित की गईं।

पीआईएफएफ 2018 के अवसर पर आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी

थीम L=h ए ट्रिब्यूट टू वूमनहुड इन इंडियन सिनेमा पर 11 जनवरी से 17 जनवरी, 2018 तक सिटी प्राइड, कोथ्रुड, पुणे में 60 प्रदर्शनियों का प्रदर्शन किया गया। कई गणमान्य व्यक्ति, फ़िल्म उद्योग के सदस्य, प्रतिनिधियों और फ़िल्म प्रेमियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

एमआईएफएफ 2018– एनएफएआई ने 15वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (एमआईएफएफ 2018) में 30 जनवरी से 3 फरवरी, 2018 तक कैलेंडर, पोस्टर, ग्रीटिंग कार्ड आदि की बिक्री के लिए फ़िल्म्स डिवीजन परिसर में एक स्टॉल लगाया।

u,Fkh ÃLV fQYe QsfLVoy 2018

हिमालयन क्लब ने 1 अप्रैल, 2018 को मुख्य थियेटर एनएफएआई में अपना वार्षिक फ़िल्म कार्यक्रम आयोजित किया। यह आम जनता के लिए खुला था।

बौद्ध अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव नागपुर बौद्ध केंद्र द्वारा एनएफएआई मेन के साथ 28 और 29 अप्रैल, 2018 को एक बौद्ध अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव का आयोजन किया जिसने इस अवसर पर लगभग 10 फ़िल्मों को प्रदर्शित किया। यह समारोह सभी के लिए सुलभ था।

ejkBh fQYe egksRlo% अक्षय फ़िल्म क्लब और सांवद, पुणे के सहयोग से बालगंधरवा रंगमंदिर में मराठी फ़िल्मों की प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें 1 मई से 5 मई, 2018 तक 35 प्रदर्शनी प्रदर्शित की गई।

dksfj;kÃ fQYe egksRlo एनएफएआई के सहयोग से कोरियाई दूतावास द्वारा आयोजित कोरियाई फ़िल्म महोत्सव का आयोजन 07 और 8 जून, 2018 को किया गया था। दो सत्रों में भारतीय फ़िल्मों को पुणे के दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया, जिन्हें अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

;jksih; ;wfu;u fQYe QsfLVoy (ईयूएफएफ–2018) 6 से 12 जुलाई, 2018 को आयोजित किया गया। फेस्टिवल का उद्‌घाटन मिस्टर उज्ज्वल निर्गुडकर एसएमपीईटी के चेयरमैन (भारत) के हाथों किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे मुंबई में बेल्जियम के महावाणिज्य दूत (मिशन के प्रमुख) श्री पीटर ह्यहेबैबर्ट, डगलस बोसवेल, समापन फ़िल्म "लबैरिन्थुस" के निर्देशक और बेल्जियम के अभिनेता ब्रैम स्पुरेन उपस्थित थे। 23 देशों की 24 फ़िल्में मेन थियेटर, एनएफएआई, पुणे में उत्सव के दौरान प्रदर्शित की गईं।

,u,Q,vkbZ us eSDl eqyj Hkou iq.ks ds lg≶ksx ls teZu fQYe QsfLVoy 'kf"kZd tuuDLLV 10.0 fQYe QsfLVoy dh 25 से 27 जुलाई, 2018 तक मेन थियेटर मेज़बानी की। एनएफएआई (दो शो की चार फ़िल्में प्रतिदिन) पुणे के स्कूली छात्रों के लिए प्रदर्शित की गईं जो जर्मन भाषा सीखते हैं।

एनएफएआई ने पुणे इंटरनेशनल सेंटर (पीआईसी) के सहयोग से, 10 से 13 अगस्त, 2018 तक श्रीलंकन फ़िल्म फेस्टिवल का आयोजन किया। पुणे के दर्शकों के लिए उत्सव के दौरान, मुख्य थियेटर एनएफएआई में प्रतिदिन कुल 11 फ़िल्में प्रदर्शित की गईं।

bfM;k gkml xyjh] i.k ने 24 और 25 अगस्त, 2018 को मेन थियेटर, एनएफएआई में दो दिनों के लिए पहली बार आर्किटेक्चर एंड अर्बनिज़्म पर एक अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव का आयोजन किया। विभिन्न देशों की सात फ़िल्मों को पुणे की जनता के लिए प्रदर्शित किया गया।

पुणे के एक निजी संगठन Þcgjxß ने एनएफएआई मुख्य रंगमंच में 9 सितंबर, 2018 को "आदिवासी फ़िल्म महोत्सव" का आयोजन किया।

xV elt इंडिया इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल", पुणे में एक निजी संगठन, ने छात्रों और अन्य आमंत्रितों के लिए, 22 सितंबर, 2018 को एनएफएआई चरण II में एक लघु फ़िल्म समारोह का आयोजन किया।

likfFkd VLV ने 6 अक्तूबर, 2018 को मेन थियेटर एनएफएआई में अद्वैत क्वेर फ़िल्म फेस्टिवल (एलजीबीटीआई) का आयोजन किया।

एनएफएआई के साथ मिलकर ,yk;l Ýdbl ने एनएफएआई मेन थियेटर में 12 अक्तूबर, 2018 को फ्रेंच एनिमेशन फ़िल्म फेस्टिवल का आयोजन किया। स्क्रीनिंग 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए खुली थी।

एक निजी संगठन fVfeVh VLV ने 23 नवबंर, 2018 को ÞfFk;Vj v,Q fn ekbM Ldki eVy gYFk fQYe QfLVoyß का आयोजन किया।

एनएफएआई पीआईसी के साथ सहयोग में 6 दिसंबर, 2018 से 9 दिसंबर, 2018 तक Þbtjk;y fQYe QfLVoyÞ का एनएफएआई मेन थियेटर में आयोजन किया गया। कुल 13 फ़िल्मों की स्क्रीनिंग की गई। कार्यक्रम सभी के लिए सुलभ था।

ih,e 'kkg QkmM'ku] i.k ने जनता के लिए एनएफएआई मेन थियेटर में 21 और 22 दिसंबर, 2018 को ÞvkjkX; fQYe egkRloÞ का आयोजन किया।

N=ifr f'kokth fQYe QfLVoy] i.k में एक निजी पार्टी ने ÞfQYe QfLVoyÞ का आयोजन 29 दिसंबर, 2018 को एनएफएआई थियेटर फेज II में किया।

fVfeVh VLV i.k ¼,uthvk½ ने 23 दिसंबर 2018 को एनएफएआई मुख्य रंगमंच पर Þekufld LokLF; fQYe egkRloÞ का आयोजन किया।

fo'k"k dk;Øe %

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक–लेखक सुमित्रा भावे के 75वें जन्मदिन के अवसर पर, vkjHkV fQYe Dyc के सहयोग से नेशनल फ़िल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। सुमित्रा भावे और सुनील सुकथनकर द्वारा निर्देशित फ़िल्म 'वास्तुपुरुष' 12 जनवरी कोथरूड, एनएफएआई को प्रदर्शित की गई।

एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन और फ़िल्म शो Þi.k l gEcx d fy, dkj MkbofViÞ एक निजी पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था जो 15 फरवरी, 2018 को मेन थियेटर में सभी के लिए खुला था। यह श्री चारुचंद्र श्रोती द्वारा स्वयं द्वारा शूट किया गया यह एक स्व–चालित अनुभव था।

एक निजी आयोजक सपत्सुर ने 22 फरवरी, 2018 को मेन थियेटर में गुजरे जमाने की vfHku=h eekckyk को श्रद्धांजलि स्वरूप एक ऑडियो–विजुअल कार्यक्रम का आयोजन किया।

सेंटर फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च इन जियोसाइंसेज ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे फ़िल्म शो का आयोजन कियाः–ए थर्सटी वर्ल्ड थियेटर ऐम इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री 22 मार्च को एनएफएआई के मुख्य थियेटर में प्रदर्शित की गई। यह जनता के लिए खुला था।

श्रीविद्या और शंकर जयकिशन फाउंडेशन ने 12 अप्रैल 2018 को 'kdj t;fd'ku ij v,fM;k&ohfM;k dk;Øe का आयोजन किया। यह कार्यक्रम एनएफएआई मुख्य थियेटर में सभी के लिए खुला था।

jkVjh Dyc v,Q 'kfuokjokMk i.k] ने "फिर जिंदगी' नामक एक कार्यक्रम/फ़िल्म शो का आयोजन किया, जो विशेष रूप से अंगदान पर तैयार किया गया और इसके बाद 15 अप्रैल, 2018 को एनएफएआई मुख्य थियेटर में आयोजित होने वाले डॉक्टर्स, काउंसलर और लाभार्थियों द्वारा इस विषय पर चर्चा की गई, यह कार्यक्रम आम जनता क लिए खुला था।

एनएफएआई ने 20 से 22 अप्रैल तक पुणे के फ़िल्म प्रेमियों के लिए djy pyfp= vdkneh d leUo; e ledkyhu ey;kye fQYek के पुरस्कार प्राप्ति के उत्सव की मेजबानी की। इस समारोह का उद्घाटन पुरस्कार विजेता कलाकार और फ़िल्म ÞVd v,QÞ की मुख्य अभिनेत्री पार्वती टी.के. ने किया। एनएफएआई के मुख्य थियेटर में इसके निर्देशक महेश नारायणन हैं।

lokn पुणे ने 5 और 6 मई को एनएफएआई मेन थियेटर में मराठी चित्रपट सम्मेलन का आयोजन किया। यह एनएफएआई और अक्षय फ़िल्म क्लब का एक संयुक्त उद्यम था, और जनता के लिए खुला था।

मूवी Þdk lkCyknkßÞ की स्क्रीनिंग 9 जून, 2018 को एनएफएआई, मेन थियेटर में संयुक्त रूप से v{k; fQYe Dyc i.k और jkVjh Dyc i.k द्वारा आयोजित की गई थी।

ÞbEeVfj;yÞ एक निजी संगठन ने एनएफएआई, मेन थियेटर में 10 जून, 2018 को वृत्तचित्र (nhnh d,UVDVj–बिल्डिंग से विवाह करने वाली पृथ्वी) + स्क्रीन रिलीज़ की स्क्रीनिंग की व्यवस्था की।

lIrlj] नासिक के एक संगीत संगठन ने देवानंद को श्रद्धांजलि के रूप में एक ऑडियो–विजुअल कार्यक्रम Þjxhyk nokunÞ का आयोजन किया। यह 14 जून, 2018 को एनएफएआई, मेन थियेटर में आयोजित किया गया था, सभागार में उपस्थित अनेक दर्शकों ने अपने मन्तव्य व्यक्त किये।

एनएफएआई और vjckr fQYe Dyc i.k और कला प्रयोग पुणे ने वृत्तचित्र फ़िल्म क्लब स्क्रीनिंग का आयोजन किया। (4 वें संस्करण) अरुण खोपकर की 5 फ़िल्में (नारायण गंगाराम सर्वेक्षण, रसिकप्रिया, लोकप्रिया, सांचारी, विचार के आंकड़े–सभी 35 मिमी में) 29 जुलाई, 2018 को मुख्य रंगमंच, एनएफएआई में प्रदर्शित की गईं।

uekfo;k 62 i.k] (1962 के नूतन मराठी विद्यालय–पुणे छात्रों के बैच के स्कूली छात्रों का पुनर्मिलन) पुरुषोत्तम आप्टे की अगुवाई वाली टीम ने एनएफएआई प्रिंट "उमराव जान" (हिंदी) की स्क्रीनिंग की व्यवस्था 2 अगस्त, 2018 को मेन थियेटर, एनएफएआई में की।

okÃMh th fQYe i.k] (श्री गोसावी) एक निजी प्रोडक्शन हाउस ने 3 अगस्त 2018 को अपनी फ़िल्म Þl,jhÞ की प्रीव्यू स्क्रीनिंग मेन थियेटर, एनएफएआई में अपने तकनीकी कलाकारों और चालक दल के सदस्यों के लिए आयोजित की। फ़िल्म के मुख्य कलाकार बातचीत/चर्चा के लिए मौजूद थे।

एक निजी पार्टी Jhfo|k ,Vjçkbtst ,M 'kdj t;fd'ku QkmUMs'ku ने में 9 मई, 2018 को मुख्य थियेटर, एनएफएआई में गुजरे जमाने की अभिनेत्रियों मीना कुमारी और मधुबाला पर एक निःशुल्क संगीतमय दृश्य श्रव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जो सभी के लिए खुला था एवं पुणे के दर्शकों ने हार्दिक स्वीकृति दी।

VkYlMk bLVhV;V i.k] एक निजी पार्टी ने अपनी फ़िल्म ÞcD'kh'kÞ की स्क्रीनिंग का आयोजन 16 अगस्त, 2018 को शाम 6 बजे से 8.00 बजे तक मेन थियेटर, एनएफएआई में अपने तकनीकी कलाकारों और चालक दल के सदस्यों के लिए किया।

एक निजी संगठन eMkfyu yol ने पुणे में संगीतमय दृश्य–श्रव्य कार्यक्रम को 6 सितंबर, 2018 को मेन थियेटर, एनएफएआई में आयोजन किया।

एनएफएआई के सहसंयोजन से पुणे में bMkk dkfj;u dYpj xqi ने बनाना ग्रुप चिल्ड्रन के लिए एनएफएआई मेन थियेटर में 14 सितंबर, 2018 को कोरियन फ़िल्म "सिंगिंग विद द एंग्री बर्ड" की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया।

jhtuy vkmVjhp C;jks] सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन, (सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत के प्रसारण) पुणे ने पंजीकृत सांस्कृतिक मंडलों के लिए पोषण अभियन पर कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 27 सितंबर, 2018 को एनएफएआई चरण II, थियेटर में आयोजित किया गया था।

एक निजी संस्था ÞLojxaxk vkVZ QkmUMs'kuß पुणे, ने एनएफएआई के मुख्य रंगमंच पर 27 सितंबर, 2018 को (लता मंगेशकर पर) एक संगीत दृश्य श्रव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम पुणे की जनता के लिए खुला था।

एक वरिष्ठ नागरिक श्री संतोष कोठड़िया ने अपने कुछ संगीत प्रेमी मित्रो के साथ, 25 अक्तूबर, 2018 को मेन थियेटर एनएफएआई में चियर एंड ट्रिब्यूट गुजरे ज़माने की अभिनेत्रियों से संबंधित एक विशेष दृश्य श्रव्य कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम सभी दर्शकों के लिए खुला था।

एनएफएआई मुख्य क्लब में 18 से 20 नवंबर, 2018 को अक्षय फ़िल्म क्लब पुणे के सह संयोजन से एनएफएआई ने 100 lky 'krkCnh i;yLro ¼i-y-n'kikM½ का आयोजन किया। फ़िल्म की स्क्रीनिंग और फ़िल्म पर चर्चा हुई। यह कार्यक्रम सभी दर्शकों के लिए खुला था।

एक निजी पार्टी श्रीविद्या इन्टरप्राइज़ेज ने संगीतज्ञ द्वय ^'kdj t;fd'ku ,oa mudh vej vfHkusf=;k^ नामक संगीतमय दृश्य श्रव्य कार्यक्रम का आयोजन एनएफएआई मुख्य थियेटर में 22 नवम्बर, 2018 को किया।

परिवर्तन इवेन्ट्स पुणे, एक निजी संस्थान ने एनएफएआई के सह–संयोजन से ^furh'k Hkkj}kt ds lkFk ,d n'; J0; okrkZ dk;Øe^ ¼Vh-oh- /kkjkokfgd egkHkkjr ds 30 o"kZ iwjs gksus ds miy{; eas½ का आयोजन एनएफएआई मुख्य थियेटर में 30 नव्रबर, 2018 को किया। श्री भरद्वाज ने महाभारत धारावाहिक के विभिन्न पक्षों को उजागर करते हुए लोगों से संवाद किया।

vk'k; fQYe Dyc] i.k ने एनएफएआई के सह–सेयोजन में ^,f'k;kbZ fQYe egksRlo^ का आयोजन 24–30 दिसंबर, 2018 तक एनएफएआई मुख्य थियेटर में किया। यह कार्यक्रम सभी के निःशुल्क था।

,u,Q,vkÃ }kjk vk;ksftr fofHkUu dk;Øeksa vkj fofHkUu dk;Øeksa ds fy, fQYeksa dh vkiwfrZ %

भारत में फ़िल्म संस्कृति के प्रसार संबंधित एनएफएआई की गतिविधियों में 25 सक्रिय फ़िल्म क्लब/सदस्यों के साथ वितरण लायब्रेरी, भारत में होने वाले विभिन्न स्क्रीनिंग कार्यक्रमों और फ़िल्मोत्सवों के लिए फ़िल्मों की आपूर्ति करना शामिल है। वर्ष के दौरान एनएफएआई ने फ़िल्मों की आपूर्ति की और अन्य संगठनों के सहयोग से विभिन्न फ़िल्म समारोहों का आयोजन किया।

एनएफएआई, अरभात फ़िल्म क्लब और राजू सुतार ने मिलकर वृत्तचित्र फ़िल्मों पर विशेष रूप से केंद्रित एक फ़िल्म क्लब प्रारंभ किया। फ़िल्म क्लब हर महीने एक वृत्तचित्र फ़िल्म का प्रदर्शन करेगा, साथ ही फ़िल्म निर्माताओं और फ़िल्म के साथ परस्पर संवादात्मक सत्र भी करेगा। अरभात एंड आर्ट एक्सपेरिमेंट द्वारा 7 अक्तूबर, 2018 को एनएफएआई मुख्य थियेटर में वृत्तचित्र फ़िल्म क्लब कार्यक्रम के तहत वृत्तचित्र फ़िल्म "मालेगांव के सुपरस्टार" का आयोजन किया गया। एनएफएआई/अरभात द्वारा वृत्तचित्र फ़िल्म क्लब स्क्रीनिंग कार्यक्रम के तहत, मणि कौल की फ़िल्म "चित्रकथी" के प्रदर्शन के बाद चर्चा आयोजित की गई थी। यह कार्यक्रम 13 मई (रविवार) को जनता के लिए खुला था।

एनएफएआई/एआरबीएएटी के सह–संयोजन से 28 जुलाई, 2018 को फेज दो में चिल्ड्रन फ़िल्म क्लब स्क्रीनिंग के अंतर्गत 28 जुलाई को मार्क ओसबोर्न की 'द लिटिल प्रिंस' और एक फ्रेंच एनिमेटेड थ्री डी फंतासी एडवेंचर, वाले पारिवारिक नाटक की व्यवस्था की।

एएफएआईएन ने एनएफएआई के सह–संयोजन से मराठी पुस्तक "सिनेमा डायरी" के प्रकाशन के बाद फ़िल्म स्क्रीनिंग 27 मई, 2018 को की गई। इस कार्यक्रम में काफी दर्शक उपस्थित थे।

हैबिटेट फ़िल्म क्लब–दिल्ली–डीवीडी, "ग़ज़्ज़ेपूजे," माज़े बल" "इंटरव्यू" (बंगाली), "भवानीभावई" (गुजराती), "आदिमगल" (मलयालम), "बाजी" (हिंदी), "फायरिंगोटी" (असमिया) "नीम अन्नपूर्णा" (बंगाली) को एनएफएआई संग्रह से जारी किया गया।

बिमल रॉय के जन्म शताब्दी समारोह के भाग के रूप में हैदराबाद फ़िल्म क्लब में स्क्रीनिंग के लिए–"यहूदी" (हिंदी) का एक बीआरडी जारी किया गया था। 10 फ़िल्में (169 रीलें) फ़िल्म लैब मुंबई में प्रतियों के लिए जारी की गई।

भारत का अंतराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (आईएफएफआई) गोवा, 2018 का 49वां संस्करण (i) अचनाक (35 मिमी)–5 डी (ii) मलाईकलां (35 मिमी)–18 (रील) (iii) शक (हिंदी) (35 मिमी)–7 डी फ़िल्में जारी की गईं।

कश्मीर फ़िल्म समारोह के लिए छह डीवीडी जारी की गई।

1) मुग़ल ए आज़म 2) पाकीज़ा 3) जागते रहो 4) श्री 420 5) नया दौर 6) काला पानी

फ़िल्म फेस्टिवल भुवनेश्वर, ओडिशा के लिए, निम्नलिखित चार डीवीडी जारी की गई।

(i) राजा हरिश्चंद्र, (मूक) 1913, (ii) कुममट्टी, (मलयालम) जी अरविंदन, 1979 (iii) सुवर्णरेखा, (बंगाली) ऋत्विक घटक, 1962, (iv) गोपी गायने बाघा बायने, (बंगाली) 1969 सत्यजीत रे,

एनएफएआई में एशियाई फ़िल्म महोत्सव के लिए 3 फ़िल्में (1 (डीवीडी) + 2 (35 मिमी) जारी की गईं।

vrjjk"Vªh; fQYeksRloksa ds fy, Hkkjrh xÃ fQYesa

इंडो–जर्मन वीक 2018 बेबीलोन, बर्लिन में स्क्रीनिंग के लिए "शिराज" (मूक) की एक डीवीडी भेजी गई।

इंडिया पवेलियन वीडियासिट्टा, इटली में एक डीवीडी स्क्रीनिंग के लिए भेजी गई जिसमें तीन फ़िल्में (राजा हरीशचंद्र, कालियामर्दन, जमाईबाबू) शामिल थी।

fQYe cks/k ikB~;Øe

43वां फ़िल्म बोध पाठ्यक्रम 7 मई, 2018 में शुरू हुआ और इसका उद्घाटन विख्यात फ़िल्म निर्माता श्री वेत्रिमरन द्वारा किया गया। 84 प्रतिभागियों को भागीदारी प्रमाण–पत्र से सम्मानित किया गया। ये प्रतिभागी भारत के 17 राज्यों से और 2 प्रतिभागी नेपाल से थे। इस पाठ्यक्रम का समापन 2 जून, 2018 को हुआ और प्रसिद्ध फ़िल्म निर्माता श्री नीरज पांडे ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

ejkBh esa fQYe cks/k ikB~;Øe

इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन एफटीआईआई के निर्देशक श्री भूपेंद्र कनथोला ने किया। इस साल महाराष्ट्र के सभी कोनों से 76 प्रतिभागियों ने कोर्स में भाग लिया। यह कोर्स 30 सितंबर, 2018 से 6 अक्तूबर, 2018 तक आयोजित किया गया।

nljk 'khrdkyhu fQYe cks/k ikB~;Øe 2018

7 दिसंबर, 2018 से एनएफएआई के द्वितीय चरण परिसर में 22 दिसंबर, 2018 को एफटीआईआई के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन जाने–माने फ़िल्म निर्माता श्री राम राघवन ने किया था। पाठ्यक्रम में भारत के सभी हिस्सों के 47 और सिंगापुर के 1 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह अनेक पुरस्कृत फ़िल्म निर्माता सुश्री अरुणा राजे पाटिल द्वारा आयोजित किया गया था।

ikLVj çn'kZuh

,evkÃ,Q,Q 2018 % एनएफएआई ने 15वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (एमआईएफएफ 2018) में 30

जनवरी से 3 फरवरी, 2018 तक कैलेंडर, पोस्टर, मग, ग्रीटिंग कार्ड आदि की बिक्री के लिए फ़िल्म डिवीजन परिसर में एक स्टॉल लगाया।

ukfld bVju'kuy fQYe QfLVoy 2018 % श्री शशि कपूर के जीवन और कार्य (38 प्रदर्शन) पर नासिक में 22 मार्च से 25 मार्च, 2018 तक एक प्रदर्शनी आयोजित की गई।

lhch,Qlh fQYe QfLVoy % सीबीएफसी, मुंबई में 50 पोस्टरों की प्रदर्शनी भेजी गई

fcey j,; ij çn'kuh % बिमल रॉय की 52वीं पुण्यतिथि के अवसर पर "बिमल रॉय–द मैन इन द पिक्चर्स" और "स्टोरी बिहाइंड मधुमती" शीर्षक से एक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसका विमोचन मुख्य थियेटर में 6 जनवरी, 2018 को एनएफएआई समारोह में किया गया। बिमल रॉय पर 14 प्रदर्शनीय वस्तु और उनके द्वारा काम को एनएफएआई की लॉबी में प्रदर्शित किया गया था।

dkyck] Jhydk में आयोजित होने वाली एक प्रदर्शनी के लिए 150 प्रदर्शनी (सॉफ्ट कॉपी) भारत और श्रीलंका @70 समारोह में भाग लेने के लिए भेजी गई थीं।

rgjku e Hkkjrh; fluek ij çn'kuh% 45 प्रदर्शनी (सॉफ्ट कॉपी) ईरान, तेहरान में भारतीय दूतावास को भेजी गईं।

,QVhvkÃvkÃ vkiu M% 11 और 12 अगस्त, 2018 भारतीय सिनेमा में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित 12 प्रदर्शन दिखाए गए।

lY;ykbM ij egkRek% 2 अक्तूबर, 2018 को यरवदा जेल के कैदियों के लिए 20 प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन सांसद श्री अनिल शिरोले ने किया।

इसी तरह की 25 प्रदर्शनियां मुंबई के राजभवन में एनएफएआई द्वारा आयोजित की गईं जिनका उद्घाटन माननीय सी. विद्यासागर राव, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 2 अक्तूबर 2018 को किया।

40 वें प्रदर्शनियों की प्रदर्शनी 25 वें अक्तूबर से 30 अक्तूबर, 2018 तक II गुवाहाटी अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में आयोजित की गई थी।

27-10-2018 dk oYM v,fM;k&fo t;vy fnol मनाने के लिए एनएफएआई में इसी प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया गया था।

lY;ykbM ij egkRek % एनएफएआई द्वारा आईएफएफआई 2018 के एक हिस्से के रूप में नई दिल्ली में ब्यूरो ऑफ़ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के सहयोग से 21

नवंबर से 28 नवंबर 2018 तक एक मल्टी–मीडिया प्रदर्शनी आयोजित की गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कई गणमान्य व्यक्तियों और मशहूर हस्तियों ने प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में उपस्थिति अच्छी रही और इसे सराहा गया। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने भी प्रदर्शनी का दौरा किया क्योंकि यह प्रदर्शनी प्रतिनिधियों और जनता के लिए खुली हुई थी। एनएफएआई ने 2019 के लिए एक पुस्तिका (प्रदर्शनी पर महात्मा विषय से संबंधित 70 फ़िल्मों की जानकारी प्रदर्शित करता है) प्रदर्शित की और साथ ही टेबल कैलेंडर का विमोचन किया।

lY;ykbM ij egkRek % द भुवनेश्वर आर्ट ट्रेल 2018 के सहयोग से एनएफएआई ने 20 प्रदर्शनियां लगाईं। जिनका उद्घाटन 3 दिसंबर को पूर्व राजदूत श्री अबसरा बेउरिया द्वारा किया गया था और प्रदर्शनी को 10 दिसंबर, 2018 तक दर्शकों के लिए खुला रखा गया था।

lY;ykbM ij egkRek % एनएफएआई ने एरीज टेलीकास्टिंग द्वारा आयोजित इंडी वुड 2018 के सहयोग से, कोचीन में 1 से 5 दिसंबर, 2018 तक हैदराबाद में इस प्रदर्शनी की 40 प्रदर्शनियां लगाई थी। व्यवसायी और निर्देशक सोहन रॉय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।

le>krk Kkiu

एक नई पहल के अंतर्गत एनएफएआई ने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (एसपीपीयू) के साथ भारतीय फ़िल्म अध्ययन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फ़िल्म प्रस्तुति के एक घटक पाठ्यक्रम के रूप में यह पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा और इस पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए एनएफएआई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

एनएफएआई ने गांधीवादी अध्ययन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय, jk"Vªh; çk—frd fpfdRlk lLFkku ¼,uvkÃ,u½ पुणे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन के एक भाग के रूप में, एनएफएआई संग्रह से महात्मा गांधी पर दृश्य सामग्री को एनआईएन के शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

;kstuk vkSj xSj&;kstuk dk;Øe

;kstuk dh ykxr

एनएफएआई के पास दो योजनाओं के लिए 2018–19 के दौरान 5.50 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है। नई योजना यानी राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) के लिए 2018–19 के दौरान कुल 11.05 करोड़ रुपये की लागत है।

2018–19 के दौरान योजना के निष्पादन को दर्शाने वाला एक विज्ञापन अनुलग्नक– C पर संलग्न है।

mÙkj iwoZ {ks= vkSj tEew vkSj d'ehj ds fy, ctV çkoèkku

एनएफएआई की गतिविधियों की प्रकृति को देखते हुए इसे उत्तर–पूर्व क्षेत्र और जम्मू–कश्मीर के लिए कोई बजट प्रावधान प्रदान करना संभव नहीं माना गया।

श्रेणी I–स्थापना व्यय और श्रेणी II–केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के लिए बजट दर्शाने वाला वक्तव्य नीचे दिया गया है:

ctV vuqeku 2018&19

(रु. करोड़ में)

fooj.k	Js.kh I& LFkkiuk 0;;	Js.kh II&dsaæh; {ks= dh ;kstuk,a		dqy
		vfHkys[kh; fQYe vkSj fQYe lkexh ¼,u,Q,vkÃ½ dk vfèkxzg.k vkSj ,u,Q,vkÃ ds cfu;knh <kaps dk mUu;u	,u,Q,p,e	
प्रमुख अध्यक्ष "2220" सूचना और प्रचार	5.55	5.50	57.78	68.83
dqy	5-55	5-50	57-78	68-83

la'kksfèkr vuqeku 2018&19

(रूपये करोड़ में)

fooj.k	Js.kh I&LFkkiuk 0;;	Js.kh II&dsaæh; {ks= dh ;kstuk,a		dqy
		vfHkys[kh; fQYe vkSj fQYe lkexh ¼,u,Q,vkÃ½ dk vfèkxzg.k	,u,Q,p,e	
प्रमुख अध्यक्ष "2220" सूचना और प्रचार	5.71	5.50	15.00	26.21
dqy	5-71	5-50	15-00	26-21

'kklu çcaèk

laxBukRed LFkkiuk

एनएफएआई का पुणे में मुख्यालय होने के साथ के बंगलुरु, कोलकाता और तिरुअनंतपुरम में तीन क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य रूप से फ़िल्म समाज, शैक्षणिक संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में फ़िल्म संस्कृति के प्रचार–प्रसार के काम में लगे हुए हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज की देखरेख निदेशक, एनएफएआई द्वारा की जाती है। एनएफएआई के तीन क्षेत्रीय कार्यालयों को मिलाकर कर्मचारियों की संख्या (प्रशासनिक विंग में 22 और तकनीकी विंग में 27) है।

vtk vkj vttk d fy, tutkrh; mi&;ktuk@ fo'k"k ?kVd ;ktuk d lcèk e ctV çkoèkkuA

एनएफएआई की गतिविधियों के स्वरुप को ध्यान में रखते हुए अजा और अजजा के लिए जनजातीय उप–योजना/विशेष घटक योजना के संबंध में बजट प्रावधान प्रदान करना संभव नहीं माना गया।

,QvkÃ,,Q

एनएफएआई मई, 1969 से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फ़िल्म अभिलेखागार का सदस्य रहा है। एफआईएएफ की सदस्यता एनएफएआई को विशेषज्ञ सलाह, संरक्षण तकनीक, प्रलेखन, ग्रंथ सूची इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। अन्य अभिलेखागारों के साथ दुर्लभ फ़िल्मों के आदान–प्रदान के साथ अभिलेखीय विनिमय कार्यक्रमों के तहत सुविधा भी देता है।

vtk@vttk@vfio d dY;k.k grq

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए लाभ और कल्याण प्रदान करने के लिए समय–समय पर संशोधित मानदंडों के अनुसार ध्यान दिया जाता है।

jktHkk"kk d :i e fgnh dk ç;kx

हिंदी पखवाड़ा (दो सप्ताह) 14.09.2018 से 28.09.2018 तक मनाया गया। जिसके अंतर्गत दीक्षा, स्वच्छता अभियान पर श्रुतलेख, स्लोगन और अंताक्षरी से संबंधित प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें एनएफएआई के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। 19.9.2017 को श्री राजेंद्र कुमार वर्मा, सहायक निदेशक (मौखिक), हिंदी शिक्षण योजना, पुणे द्वारा दैनंदिन के कार्यों के लिए हिंदी के प्रभावी उपयोग हेतु आईटी उपकरणों के उपयोग पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

foHkkxh; y[kk

एनएफएआई 1976 में शुरू की गई विभागीय लेखा प्रणाली का अनुसरण करता है। इस व्यवस्था के तहत एनएफएआई का वेतन और लेखा पीएओ, एफडी और मुंबई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निदेशक, एनएफएआई को विभागाध्यक्ष के रूप में डीडीओ के रूप में नामित किया गया है और इन अधिकारों को प्रशासनिक अधिकारी, एनएफएआई को सौंप दिया गया है।

ylcr v,fMV vkifÙk;k

महानिदेशक लेखा परीक्षा (मध्य), मुंबई ने एनएफएआई के खातों का दिनांक 03.10.2017 से 18.10.2017 तक ऑडिट किया।

fu;fä@çfrfufèk eMy

एनएफएआई निदेशक ने–

1) दूसरे सिनेमा रित्रोवतो फ़िल्म महोत्सव के 31वें संस्करण के लिए बोलोग्ना, इटली में 28 और 29 जून, 2017 2 दिन की अवधि के लिए भाग लिया।

2) 73वें एफआईएएफ कांग्रेस और संगोष्ठी एवं महासभा 28 अप्रैल–3 मई, 2017 में भाग लिया।

3) सिनेमैथे फ्रैंकेइस, पेरिस, फ्रांस के आई फ़िल्म संस्थान एम्स्टर्डम में 6.03.2017 से 10.03.2017 तक अध्ययन यात्रा की। इस दौरे का सफल कार्यान्वयन विशेष रूप से एनएफएआई के राष्ट्रीय फ़िल्म धरोहर मिशन के मद्देनजर प्रौद्योगिकी के डिजिटलीकरण और फ़िल्मों की नवीनीकरण के बारे में हालिया प्रगति को जानने के लिए किया गया था। ये बहुत पूर्वावस्था की प्राप्ति के लिए जानकारीपूर्ण और लाभकारी दौरे थे।

lh,Vh d fu.kZ;@vkns'kk dk dk;kZUo;u

रिपोर्ट के तहत इस संदर्भ में एनएफएआई के संबंध में जानकारी को कृपया शून्य माना जाए। जैसा कि ऐसा कोई कैट के निर्णय/आदेश एनएफएआई को प्राप्त नहीं हुए।

vkjVhvkÃ vfèkfu;e&2005

एनफीएआई ने भारत के सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 को सरकार द्वारा अधिसूचना के रूप में लागू किया है।। एनएफएआई द्वारा 1 अप्रैल, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 की अवधि के दौरान 37 आवेदन लिए प्राप्त किए थे और नियमानुसार आवेदकों को आवश्यक जानकारी प्रदान की गई थी। इस अधिनियम ने संगठन के कामकाज में पारदर्शिता लाने का काम किया है।

f'kdk;r çdk"B

एनएफएआई के निदेशक, को विभागाध्यक्ष के रूप में शिकायत अधिकारी नामित किया गया है। सभी शिकायतों का निवारण सरकारी नियमों और मानदंडों के अनुसार किया गया है।

ukxfjd pkVj

एनएफएआई की वेबसाइट पर नागरिकों के लिए चार्टर है। नागरिक हमारी वेबसाइट (www.nfaipune.gov.in) पर जा सकते हैं और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकों के चार्टर की जानकारी समय–समय पर दी जाती है।

dk;l;ktuk dk dk;kZUo;u

नई परियोजना स्कीम के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में एसएफसी की मंजूरी "जयकर बंगला सहित एनएफएआई के

बुनियादी ढांचे का उन्नयन और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना" 14.6.2013 को प्राप्त हुई थी जिसका कार्यान्वयन अभी होना है। एनएफएआई के चरण–II में सुरक्षा बाड़ लगाने और आंतरिक सड़क पूरी हो गई है, डॉल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम को लगाना, चरण–I अंतर्गत सभागार में कुर्सियां और कालीन लगाना और डीजी सेट का काम पूरा हो गया और बिजली का काम जैसे वाल्टों के लिए एयर कंडीशनिंग के प्रतिस्थापन, सभागार, अग्निशमन प्रणाली शुरू हो गई है और उसका काम प्रगति पर है। घरोहर स्मारक, जयकर बंगले की बहाली का काम प्रगति पर है।

vkèkfudhdj.k] dI;Vjhdj.k vkSj Ã&xous'l@Ã&d,el

एनएफएआई देश में फ़िल्म संस्कृति के प्रसार के लिए एक केंद्र के रूप में काम करते हुए भारतीय सिनेमा की विरासत हासिल करने और उसे संरक्षित करने के कार्य संलग्न है। अभिलेखागार की वेबसाइट के जरिए देश के विभिन्न भागों और समूचे विश्व के सामान्य जान, सिनेमा के गंभीर अध्येता और अनुसंधानकरता अभिलेखागार में संगृहीत वस्तुओं और अभिलेखागार की सेवाओं तक पहुंच कायम कर सकते हैं, फ़िल्म बोध पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्रपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। लोगों के प्रश्नों के उत्तर आमतौर पर ई–मेल (nfaipune@gmail.com) के माध्यम से दिए जाते हैं। एनएफएआई में इंटरनेट, फैक्स और स्कैनिंग की सुविधा है। एनएफएआई के आधिकारिक फेसबुक और ट्विटर अकाउंट चालू हैं और सक्रिय रूप से उपयोग किए जा रहे हैं।

lrdZrk xfrfofèk;k

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान सतर्कता गतिविधियों के बारे में जानकारी निम्नानुसार है :

1. मुख्यालय में और क्षेत्रीय कार्यालयों में संगठन के गठन की सतर्कता का विवरण :

   इस कार्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद नहीं है और इस कारण निदेशक को विभाग प्रमुख के सतर्कता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

2. इस अवधि के दौरान निरोधक सतर्कता गतिविधियां :
   - i इस अवधि में किए गए नियमित निरीक्षणों की संख्या : बारह
   - ii इस अवधि में किए गए औचक निरीक्षण की संख्या : बारह

3. अवधि के दौरान निगरानी और पता लगाने की गतिविधियां:
   - i निगरानी रखने के लिए चुने गए क्षेत्रों का विवरण : फ़िल्मों की सुरक्षा और नकल।
   - ii निगरानी में रखे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या : शून्य

4. दंडात्मक गतिविधियां संख्या (1) से (x) इंगित होनी चाहिए जहां नियुक्ति प्राधिकारी राष्ट्रपति के अलावा कोई अन्य होगा।
   - i. अवधि के दौरान
   - ii. उन मामलों की संख्या जिनमें प्रारंभिक जांच की गई थी : शून्य
   - iii. उन मामलों की संख्या जहां प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई थी : शून्य
   - iv. उन मामलों की संख्या जिनमें प्रमुख दंड के लिए आरोप पत्र जारी किए गए थे : शून्य
   - v. मामूली जुर्माना के लिए आरोप पत्र जारी करने वाले मामलों की संख्या : शून्य
   - vi. उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर भारी जुर्माना लगाया गया था : शून्य
   - vii. ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन पर मामूली जुर्माना लगाया गया था : शून्य
   - viii. निलंबन के तहत रखे गए व्यक्तियों की संख्या : शून्य
   - ix. उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई जैसे चेतावनी जारी करना आदि लिया गया था : शून्य
   - x. नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत समय से पहले सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संख्या : शून्य

jk"Vªh; fQYe èkjkgj fe'ku ¼,u,Q,p,e½

भारत की फ़िल्म धरोहर को बहाल करने और उसके संरक्षण के लिए 597.41 करोड़ रूपये की "राष्ट्रीय फ़िल्म धरोहर मिशन" परियोजना मंजूर की गई थी। फ़िल्म धरोहर मिशन (एनएफएचएम) के अंतर्गत बनायी गई उच्च स्तरीय समिति की आई एंड बी मंत्रालय, सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी। भारत की फ़िल्म विरासत को पुनर्स्थापित करने और संरक्षित करने के लिए नवंबर, 2014 में वित्त मंत्रालय के माध्यम से यह योजना शरू की गई। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का एक हिस्सा है, जो योजना परिव्यय के वर्षवार आवंटन के अनुसार 13 वीं पंचवर्षीय योजना तक फैला रहेगा। फ़िल्म उद्योग द्वारा इस पहल की काफी सराहना की जाएगी। इस नई योजना योजना में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फ़िल्म विंग के तहत NFAI के साथ–साथ अन्य मीडिया इकाइयों के साथ उपलब्ध फ़िल्मों के डिजिटलीकरण/बहाली का ख्याल रखा गया है। योजना का कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म पुरालेख, पुणे को दिया जाता है। राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) के अंतर्गत बनायी गई उच्च स्तरीय समिति की कुल छह बैठकें मिशन के कार्यान्वयन पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुईं। एएस एंड एफए, जेएस (फ़िल्म), डीजी (एफडी), श्री जाह्नु बरुआ और राजीव

मेहरोत्रा, एसआरएफटीआई, कोलकाता के निदेशक ने बैठकों में भाग लिया। राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) की विभिन्न गतिविधियों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को सूचीबद्ध करने के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है।

jk"Vh; fQYe ekjkgj ¼,u,Q,p,e½ d y{;

i) फ़िल्म संग्रह में फ़िल्म की स्थिति का मूल्यांकन करना और किसी फ़िल्म के शेष बचे जीवन का पता लगाना।

ii) 1,32,000 फ़िल्म रीलों के निवारक संरक्षण।

iii) भारतीय सिनेमा की 1086 ऐतिहासिक फ़ीचर फ़िल्मों और 1152 लघु फ़िल्मों की 2के/4के पिक्चर एवं ध्वनि बहाली करना तथा प्रत्येक फ़िल्म की नई पिक्चर और साउंड इंटर नेगेटिव की रिकॉर्डिंग।

iv) 1160 फ़ीचर फ़िल्मों और लघु फ़िल्मों का डिजिटलीकरण।

v) एनएफएआई परिसर, पुणे में एनएफएआई के अंतर्गत बहाल की गई सामग्री को धूल मुक्त, न्यूनतम आर्द्रता और कम तापमान की स्थिति में सामग्री के संरक्षण सुविधाओं का निर्माण।

vi) अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में संरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाएं और पाठ्यक्रमों का आयोजन।

fFk;Vj lfoekk,

एनएफएआई के तीन बहु–प्रयोजनीय थियेटर हैं। इनमें मुख्य परिसर में 35 सीटों का एक प्री–यू थियेटर और 300 सीटों का मुख्य थियेटर तहत कोथर्ड में 200 सीटों का एक कला थियेटर शामिल है। इसके अलावा अन्य थियेटरों में पुणे में मैक्स मूलर भवन, एलाइंस और ब्रिटिश काउंसिल परिसर में स्वयं के लिए और एनएफएआई फ़िल्म सर्कल सदस्यों के थियेटर को 311 कार्यक्रमों के लिए किराए पर दिया गया।

fuekrkvk@d,ihjkbV ekfydk dk lfoekk,

एनएफएआई निर्माताओं/कॉपीराइट धारकों को उनके मूल नेगटिव्स की मरम्मत करने, डुप्लीकेट प्रतियां तैयार करने और टेलीकास्ट प्रयोजनों के लिए वीडियो कॉपी करने जैसे कार्यों में सेवाएं प्रदान करता है। एनएफएआई के संग्रह से राष्ट्रीय और उपग्रह नेटवर्कों पर अनेक सेल्युलॉयड क्लासिक्स टेलीकास्ट किये जाते हैं।

vuyXud&d

रिपोर्ट के तहत अभिलेखीय प्राप्ति में जोड़े गए कुछ महत्वपूर्ण नए शीर्षक :

महल	35मिमी	हिंदी	
दर्द	35मिमी	हिंदी	
चमन	35मिमी	पंजाबी	
श्री राम अवतार	16मिमी		
चाल बाज़	16मिमी		
पैसा ही पैसा	16मिमी		
ए आईसीसी–1938 फैज़पुर कांग्रेस	35मिमी		
आज का अर्जुन	35मिमी		
डीकारिणा मंडावा	35मिमी	गुजराती	
हांगलू वेशा	35मिमी	कन्नड़	
आधुरी	35मिमी	कन्नड़	
अमृता गालीज़	35मिमी	कन्नड़	
ऑनडू मुठिना काथे	35मिमी	कन्नड़	
उल्टा पुल्टा	35मिमी	कन्नड़	
नंजुंडी कल्याण	35मिमी	कन्नड़	
मुसांजे माथु	35मिमी	कन्नड़	
जूगुला	35मिमी	कन्नड़	
धर्म देवथे	35मिमी	कन्नड़	
चीगुरिडा कानसू	35मिमी	कन्नड़	रीलस
स्पीडिंग अहेड	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस
अंतरा	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस

कंगल हनुमंतहिआ	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस
होसा ची गुरु	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस
वन मैन वॉर	35मिमी	कन्नड़	1रीलस
अंडमान एंड निकोबार	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस
जनरल करिअप्पा	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस
सुगम दारी	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस
समानथे	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस
नेमादिया बड़कू	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस
डॉ. निरंजन	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस
ज़ी. वी. जी गुंडप्पा	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस
नया निनदु नीरू नामदू	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस
भूकंप	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस
डॉ. शिवराम कारंथ	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस
साधना आराधने	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस
दलित कासु	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस
राष्ट्र कवि कुवेम्पु	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस
महात्मा गांधी जीवन दर्शन	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस
विवेकानंद	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस
नेताजी	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस
नगालैंड मुन्नाडा	35मिमी	कन्नड़	1 रीलस
स्त्री सावित्री	16मिमी	मराठी	
चमन	35मिमी	हिंदी	17रीलस
दर्द	35मिमी	हिंदी	13रीलस
चरित्र	35मिमी	हिंदी	12रीलस
धरम करम	35मिमी	हिंदी	18रीलस
प्रेम ग्रन्थ	35मिमी	हिंदी	18रीलस
आ अब लौट चले	35मिमी	हिंदी	
बड़ी मां	35मिमी	हिंदी	13रीलस
मीनार	35मिमी	हिंदी	13रीलस
नदिया के पार	35मिमी	हिंदी	13रीलस
			14रीलस
कोरा कागज़	35मिमी	हिंदी	1 रील
संत रविदास की अमर कहानी	35मिमी	हिंदी	15रीलस

vuqyXud&[k

31 दिसंबर, 2018 को अभिलेखीय प्राप्ति दिखाने वाला वर्णन

en	31-03-2018 dk	1-4-2016 l= 31-12-2018	31-12-2018 l=
फ़िल्में	21224	53	21277
वीडियो कैसेट्स	3348	339	3687
डीवीडी	3140	12	3152
पुस्तकें	5949	451	6400
पटकथाएं	42625	183	42808

पहले से रिकॉर्डिड ऑडियो कैसेट्स	1098	—	1098
अचल चित्र (स्टिल्स)	180666	6516	187182
वाल पोस्टर्स	32637	3721	36358
गीतों की पुस्तिकाएं	4512	2667	7179
ऑडियो टेप्स (वाचिक परंपरा)	191	—	191
प्रेस क्लिपिंग्स	227624	—	227624
पंफ्लेट्स/फ़ोल्डर्स	9906	278	10184
स्लाइड्स	8576	—	8576
डिस्क रिकाड्र्स	3214	35	3249
ऑडियो कम्पैक्ट डिस्क	155	—	155
अनुषंगी फ़िल्म सामग्री का डिजिटलीकरण	3,70,220	13291	383511

vuqyXud&x

;kstuk dk;Z 2018&19

dk;Øe@;kstuk	, l-ch-t h- 2018&19	vkj-Ã 2018&19	25-02-2019 rd okLrfod 0;;
नई योजनाएं			
1) अभिलेखीय फ़िल्मों और फ़िल्म सामग्री का अधिग्रहण।	2.50	2.50	1.39
2) जयकर बंगला सहित एनएफएआई के बुनियादी ढांचे का उन्नयन और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	3.00	3.00	1.24
3) राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम)	57.78	15.00	7.40

vuqyXud&?k

एनएफएआई की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में आंकड़े

jhyk@fQYek dh l[;k	16,e,e	35,e,e
1. फ़िल्मों की व्यापक जाँच	—	13
2. फ़िल्मों की नियमित जाँच	—	578
3. रीलों की नियमित जाँच	—	6941

fQYe lL—fr dk lç"k.k	
1. वितरक पुस्तकालय सदस्य	301
2. वितरक पुस्तकालय सदस्यों को आपूर्ति की गई फ़िल्मों की संख्या	—
3. विशेष अवसरों पर आपूर्ति की गई फ़िल्में	39
4. संयुक्त स्क्रीनिंग	90
5. फ़िल्म बोध पाठ्यक्रम के लिए आपूर्ति की गई फ़िल्में	27
6. अनुसंधान कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई फ़िल्म देखने की सुविधाएं	124
7. शैक्षणिक स्क्रीनिंग के लिए एफटीआईआई को आपूर्ति की गई फ़िल्में	105
8. एनएफएआई में दिखाई गई फ़िल्मों की संख्या	681
9. पुस्तकालय सेवा का लाभ प्राप्त करने वाले पाठकों की संख्या	882

10. अनुसंधानकर्ताओं की संख्या, जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन अनुभाग की सेवाएं प्राप्त की — 500
    प्रलेखन अनुभाग की सेवाओं की
11. एनएफएआई की स्क्रीनिंग पर उपस्थित दर्शकों की संख्या — 50479

fQYe lekjkg funs'kky;

ifjp;

फ़िल्म समारोह निदेशालय के माध्यम से मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान कई फ़िल्म समारोह आयोजित किए गए। मंत्रालय ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों में भी भाग लिया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :

65ok jk"Vªh; fQYe iqjLdkj

नई दिल्ली में 65वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का आयोजन भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी; सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री, श्री राज्यवर्धन राठौड़ और तत्कालीन सचिव, सूचना और प्रसारण, श्री एन के सिंहा की उपस्थिति में किया गया।

दिवंगत अदाकारा श्रीदेवी को फ़िल्म 'मॉम' (हिंदी) के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रिद्धि सेन को नागर कीर्तन (बंगाली) के लिए मिला।

रीमा दास द्वारा सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म विलेज रॉकस्टार्स (असमिया) ने सर्वश्रेष्ठ संपादन, सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार पुरस्कार जीता। गैर–फ़ीचर श्रेणी में नागराज मंजुले ने सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन की श्रेणी में पावसाचा निबन्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार प्राप्त किया,गिरिधर झा ने सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म क्रिटिक का पुरस्कार प्राप्त किया।

3 मई, 2018 को नई दिल्ली में, केन्द्रीय कपड़ा तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्रीमती स्मृति ईरानी, 65वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार समारोह के अवसर पर अभिनेत्री श्रीमती दिव्या दत्ता को हिन्दी फ़िल्म 'इरादा' के लिए (सर्वश्रेष्ठ सह–अभिनेत्री) रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित करते हुए। इस अवसर पर युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी थे

lkd fQYe egksRlo] dksyacks

फ़िल्म समारोह निदेशालय, डीएफएफ ने कोलंबो में 22 से 27 मई, 2018 तक आयोजित होने वाले सार्क फ़िल्म महोत्सव के लिए विभिन्न वर्गों में पांच भारतीय पैनोरमा को चुना। फ़ीचर फ़िल्म क्षितिज–ए होराइजन (मराठी) को

दिवंगत अदाकारा श्रीदेवी को फ़िल्म मॉम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री–वैष्णवी तांगड़े और विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया–मनोज कदाम (भारत), पूर्णा (हिंदी) को सर्वश्रेष्ठ पटकथा–प्रशांत पांडे और श्रेया देव वर्मा को फ़ीचर प्रतियोगिता खंड में सम्मानित किया गया। जीआई (मलयालम) को सर्वश्रेष्ठ लघु फ़िल्म का सम्मान दिया गया। वाटरफॉल (अंग्रेजी) को गैर–फ़ीचर फ़िल्म के लिए प्रतिस्पर्धी खंड के लिए चुना गया था। मास्टर फ़िल्म गैर–प्रतिस्पर्धात्मक अनुभाग के लिए बेसरजॉन (बंगाली) को नामांकित किया गया था।

vkfl;ku&Hkkjr fQYe lekjksg

आसियान–भारत फ़िल्म महोत्सव 25 मई से 30 मई, 2018 तक नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। यह 25 साल के आसियान और भारत के संबंधों की याद में घटनाओं की श्रृंखला के भाग के रूप में विदेश मंत्रालय (आसियान बहुपक्षीय प्रभाग) के सहयोग से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फ़िल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित किया गया था। राज्योत्सव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने महोत्सव का उद्घाटन किया।

इस गैर–प्रतिस्पर्धी फ़िल्म समारोह स्लोगन "फ़िल्मों के माध्यम से दोस्ती" था। भारत सहित 11 देशों की लगभग 31 फ़िल्मों को छह दिनों के त्योहार के दौरान प्रदर्शित किया गया था।

,llhvks fQYe QfLVoy] 2018

फ़िल्म समारोह निदेशालय, डीएफएफ ने चीन के किंडाओ में 13 से 17 जून, 2018 तक आयोजित एससीओ फ़िल्म महोत्सव के लिए विभिन्न वर्गों में पांच भारतीय पैनोरमा और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फ़िल्मों का नामांकन किया। जबकि दो भारतीय फ़िल्मों को प्रतियोगिता खंड–टेक ऑफ और विलेज रॉकस्टार के लिए नामांकित किया गया था, तीन फ़िल्में सैराट, दंगल और वेसरजोन इसका हिस्सा थीं।

फ़िल्म समारोह ने भारत की फ़िल्मी हस्तियों को भी आमंत्रित किया। फ़िल्म टेक ऑफ के लिए–श्री महेश नारायण (निर्देशक) श्री एंटो जोसेफ, (निर्माता); सैराट–श्री नागराज मंजुले (निर्देशक), श्री सुधाकर रेड्डी, (छायाकार), सुश्री रिंकू राजगुरु, (अभिनेत्री); बेसरजोन–सुपर्नाकंती करति (निर्माता), श्यामल दत्ता (अभिनेता)।

;jksih; l?k fQYe egkRlo] 2018

18 जून से 24 जून, 2018 तक नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में यूरोपीय संघ फ़िल्म महोत्सव आयोजित किया गया। इसका आयोजन यूरोपियन यूनियन द्वारा फ़िल्म फेस्टिवल्स, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निदेशालय के सहयोग से किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राज्यवर्धन राठौड़ की उपस्थिति में महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री अमित खरे, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल से भारत और दूतावासों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। फेस्टिवल में शुरुआती फ़िल्म स्लोवाकिया से fyfVy gkcj थी।

माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ यूरोपीय फ़िल्म महोत्सव का उद्घाटन करते हुए

rhljk fczDl fQYe lekjksg

फ़िल्म उत्सव निदेशालय ने डरबन में 22–27 जुलाई, 2018 से ब्रिक्स फ़िल्म महोत्सव के तीसरे खंड में भाग लिया। जबकि विलेज रॉकस्टार्स (असमिया) और न्यूटन (हिंदी) ने प्रतियोगिता खंड सिंजर (जसारी) भयाणकम (मलयालम) और बाहुबली–2 (तेलुगू) में भाग लिया था। फ़िल्म न्यूटन ने सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म पुरस्कार जीता और विलेज रॉकस्टार्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और विशेष जूरी पुरस्कार दो पुरस्कार मिले।

फ़िल्म उत्सव निदेशालय ने नई दिल्ली में सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 14–15 जुलाई, 2018 को एफटीआईआई, पुणे के सहयोग से सांग पिक्चराइजेशन पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

ueLr FkkÃyM fQYe egkRlo

थाईलैंड उच्चायोग के सहयोग से फ़िल्म समारोह निदेशालय ने 31 से 2 सितंबर, 2018 तक सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में तीन दिवसीय नमस्ते थाईलैंड फ़िल्म महोत्सव का आयोजन किया। यह उत्सव 2017 फ़िल्म बैड जीनियस के साथ खुला। अन्य फ़िल्मों की स्क्रीनिंग 4बीआईए, मलीलाः द फेयरवेल फ्लावर, ब्रदर ऑफ द ईयर, याक–द जाइंट किंग, पी मैक, बाकी प्रदर्शित फ़िल्मों के पैकेज के साथ प्रदर्शित की गईं। मलीलाः द फेयरवेल फ्लावर, फ़िल्म के बाद फ़िल्म निर्माताओं और विशेषज्ञों के साथ परस्पर संवाद का आयोजन हुआ।

Hkkjrh; iukjek fQYe egkRlo] iÌpjh

पुद्दुचेरी सरकार के सूचना और प्रचार विभाग के सहयोग से फ़िल्म समारोह निदेशालय ने पुद्दुचेरी में 7 से 11 सितंबर, 2018 तक पांच दिवसीय फ़िल्म महोत्सव का आयोजन किया।

कल्याण मंत्री श्री एम. कंदासामी ने मुग्गा थियेटर में महोत्सव का उद्घाटन किया और श्री शंकरदास स्वामीगल सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म पुरस्कार अमान कुमार द्वारा निर्देशित मानुसंगदा (तमिल) को दिया गया। इस महोत्सव में चार और भारतीय पैनोरमा की चुनिंदा फ़िल्में बिसेरजोन (बंगाली), टेक ऑफ़ (मलयालम), न्यूटन (हिंदी), रेलवे चिल्ड्रन (कन्नड़) प्रदर्शित हुईं।

Hkkjr bMh fQYe QfLVoy] Lisu] efMM

भारत के दूतावास, मैड्रिड, स्पेन के सहयोग से फ़िल्म समारोह निदेशालय ने 10–14 सितंबर, 2018 को एकेडमी ऑफ आर्ट्स और स्पेन के सिनेमैटोग्राफिक विज्ञान और सिनेटेक मैटाडेरो में पांच दिवसीय फ़िल्म समारोह का आयोजन किया। तीन भारतीय पैनोरमा चयनित फ़िल्मों में न्यूटन (हिंदी), विलेज रॉकस्टार्स (असमिया), जूजे (कोंकणी) शामिल थीं।

QfLVoy v,Q bfM;k] fl;ky] dkfj;k

भारतीय दूतावास, सियोल और कोरिया गणराज्य के सहयोग से फ़िल्म समारोह निदेशालय ने 14–15 सितंबर, 2018 को सियोल के बुसान सिनेमा केंद्र में तीन दिवसीय फ़िल्म समारोह का आयोजन किया।

इस फेस्टिवल में चार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और भारतीय पैनोरमा की चुनिंदा फ़िल्में न्यूटन, टू लेट, द गाज़ी अटैक और सिंजर प्रदर्शित हुईं।

समारोह में द रूद्राक्ष डांस कंपनी और यू. राजेश द्वारा कर्नाटक संगीत जैसे ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जैसी कई अन्य गतिविधियां प्रस्तुत की गईं।

egkRek xkèkh dh 150oÈ t;rh

जिला प्रशासन, नौगांव के सहयोग से फ़िल्म समारोह, निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा 29 से 30 सितंबर, 2018 तक खगेन महंत सभागार, नौगांव में दो दिवसीय "150वीं जयंती" का आयोजन किया गया।

फ़िल्मों के पैकेज में मेकिंग ऑफ महात्मा (ओपनिंग फ़िल्म), ईशु, लगे रहो मुन्ना भाई और गांधी (क्लोजिंग फ़िल्म) शामिल थीं। इस समारोह ने स्वच्छ भारत एक्शन प्लान के तत्वावधान में "स्वच्छ भारत फ़िल्म" पुरस्कार जीता।

"महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 1 अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 2018 तक पोर्ट ब्लेयर में आयोजित "महात्मा गांधी की 150वीं जयंती" का आयोजन अंडमान और निकोबार के द्वीपों के सभी शैक्षिक संस्थानों को कवर करने वाले जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के सहयोग से फ़िल्म फेस्टिवल, नई दिल्ली निदेशालय द्वारा किया गया था। फ़िल्मों के पैकेज में द मेकिंग ऑफ महात्मा (ओपनिंग), गांधी, लगे रहो मुन्ना भाई, वीर सावरकर, सिंजर (समापन) शामिल थे। साथ ही फेस्टिवल ने स्वच्छ भारत एक्शन प्लान के तत्वावधान में "स्वच्छ भारत फ़िल्म" पुरस्कार जीता।

ohfM;kfl êk v,fM;kfotvy fQYe QfLVoy

19 से 28 अक्तूबर, 2018 तक रोम, इटली में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की 70वीं वर्षगांठ पर भारत के साथ सहयोग से वीडियोसिट्टा ऑडियोविजुअल फ़िल्म समारोह आयोजित किया गया। दस दिवसीय उत्सव में इस साल की रोम फ़िल्म समारोह के साथ साझेदारी में रोम के आसपास के 42 स्थानों में 60 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किये गए। फ़िल्म फेस्टिवल निदेशालय द्वारा भेजी गई फ़िल्मों में–विलेज रॉकस्टार्स (असमिया), सिंजर (जसारी), मॉम (हिंदी), टेक ऑफ (मलयालम), न्यूटन (हिंदी), सैराट (मराठी), लद्दाख चले रिक्शावाला, जॉली एल.एल.बी. 2 (हिंदी), पुष्कर पुराण फ़िल्में शामिल थीं।

dkFkt fQYe lekjkg

फ़िल्म समारोह निदेशालय, डीएफएफ ने ट्यूनिशिया में 3 से 10 नवंबर, 2018 तक आयोजित कार्थेज फ़िल्म महोत्सव के लिए दो भारतीय पैनोरमा चयनित फ़िल्मों को नामित किया। दो भारतीय फ़िल्मों–न्यूटन (हिंदी) और लोकतक लायरेम्बी

(मणिपुरी) की स्क्रीनिंग की गई। निदेशालय ने उस्ताद फ़िल्म निर्माता सत्यजीत रे की दो बंगाली फ़िल्मों–जोई बाबा फेलुनाथ और चारुलता द्वारा की स्क्रीनिंग की सुविधा भी दी।

vUrjjk"Vªh; fQYe QfLVoy v,Q bfM;k] xkok

20 वें से 28 नवंबर, 2018 तक गोवा के फ़िल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) द्वारा गोवा के पणजी में गोवा में 49वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (आईएफएफआई) का आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, समारोह केलिडोस्कोप और विश्व पैनोरमा पर वर्गों के तहत आईएफएफआई 2018 में 67 से अधिक देशों की 220 से अधिक फ़िल्मों का प्रदर्शन किया गया। इजरायल केंद्रीय देश था और पहली बार, आईएफएफआई 2018 में एक राज्य फोकस अनुभाग प्रदर्शित किया गया, जिसमें इस वर्ष झारखंड राज्य फोकस के रूप में शामिल है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म उद्योग के अक्षय कुमार, करण जौहर, रणधीर कपूर, अनिल कपूर, जूलियन लैंडियास, डायना पेंटी, चित्रांगदा सिंह, अरबाज खान, राकेश ओमप्रकाश मेहरा, कबीर बेदी जैसे कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन के मौके पर मौजूद थे जिन्होंने समापन समारोह के ऑडियो विजुअल प्रदर्शन भी देखे। समारोह के लिए उद्घाटन और समापन फ़िल्मों के वर्ल्ड प्रीमियर्स से किया गया और फ़िल्म के प्रति उत्साही लोगों से असाधारण प्रतिक्रिया मिली।

49वें आईएफएफआई के उद्घाटन समारोह में श्री करण जौहर माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री (स्वंतत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ तथा श्री अक्षय कुमार की मेजबानी करते हुए

माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री (एचएमएसआईबी), कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाई और माननीय पर्यटन मंत्री श्री के.जे. अल्फोंस ने समापन समारोह में शिरकत की, साथ ही राजनीतिक और सिनेमाई परिदृश्य के गणमान्य लोगों की मेजबानी भी की। एचएमएसआईबी ने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) के सहयोग से भारत के राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) द्वारा आयोजित 'सेल्युलॉइड पर महात्मा' मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया, जिसका प्रकाशन पब्लिकेशन डिवीजन (डीपीडी) और एनएफएआई ने किया। भारतीय

आईएफएफआई 2018 को विदाई देते गणमान्य अतिथि एवं फ़िल्म जगत की मशहूर हस्तियां

सिनेमा 'और अमेज़न एलेक्सा स्पीकर पर प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) का "आईएफएफआई 2018 फ्लैश ब्रीफिंग कौशल" का प्रमोशन किया।

इफ्फी–2018 में कई नवाचार हुए जिनमें 6 भरतीय स्पोटर्स बायोपिक की स्क्रीनिंग का एक नया खण्ड 'खेलो इंडिया पहल' के तहत शामिल थे। 'मास्टरक्लासेस' एवं 'वार्ता में' खण्ड में फिल्म जगत की मशहूर हस्तियों एवं डेलीगेट्स के साथ उनकी वार्ता शामिल थी। 'ए स्केच आन स्क्रीन' नामक एनीमेशन फिल्म पैकेज भी इस बार से इफ्फी में शामिल किया गया। ए फिल्में शोले और हिचकी का प्रर्दशन दृष्टि विकलांग जनों के लिए विशेष रूप से दिखाई गईं। इन्गमार बर्गमैन की जन्मशती समारोह से जुड़ा पुर्न वलोकन खण्ड इफ्फी की एक और प्रभुखता रही।

आईएफएफआई 2018 में, वयोवृद्ध इज़राइली फ़िल्म निर्माता डैन वोलमैन को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईएफएफ़आई स्पेशल अवार्ड सलीम खान को सिनेमा में उनके आजीवन के योगदान के लिए दिया गया है। आईसीएफटी–यूनेस्को गांधी मेडल को लद्दाखी मूवी वॉकिंग विद द विंड से सम्मानित किया गया।

कलाकार सलीम खान को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया

Hkkjr&phu fQYe egkRlo] 2018

विदेश मंत्रालय के सहयोग से फ़िल्म समारोह निदेशालय और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दूतावास ने नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 22 से 24 दिसंबर, 2018 तक तीन दिवसीय फ़िल्म समारोह का आयोजन किया। महोत्सव का आयोजन भारत–चीन उच्चस्तरीय तंत्र पर सांस्कृतिक और लोगों के परस्पर आदान–प्रदान के लिए किया गया। उत्सव का एक प्रतीकात्मक उद्घाटन 21 दिसंबर, 2018 को प्रवासी भारतीय केंद्र में सांस्कृतिक पर्व के दौरान किया गया। इस अवसर में श्रीमती सुषमा स्वराज, विदेश मंत्रालय और एच.ई. श्री वांग यी, स्टेट काउंसिलर और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विदेश मामलों के मंत्री उपस्थित थे।

इस समारोह में चार चीनी फ़िल्में 'सीजेड12' जिन्हें चाईनीज़ ज़ोडिएक प्रदर्शित की गयी वुल्फ टोटेम, ब्रदरहुड ऑफ ब्लेड्स, लॉस्ट इन थाईलैंड के नाम से भी जानी जाती हैं। साथ ही, तीन भारतीय फ़िल्में दंगल (हिंदी), माचेर झोल (बंगाली) और वेंटिलेटर (मराठी) का प्रदर्शन किया गया।

Hkkjrh; iukjek fQYe egkRlo

फ़िल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित भारतीय पैनोरमा फ़िल्म महोत्सव नई दिल्ली में 4 जनवरी, 2019 को शाम 5.30 बजे सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम II, नई दिल्ली में शुरू होगा।

भारतीय पैनोरमा, 2018 में भारत के 49वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव के हिस्से के रूप में चयनित सभी फ़िल्मों को महोत्सव के दौरान दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। 10 दिनों के त्योहार के दौरान 26 फ़ीचर फ़िल्में और 21 नॉन फ़ीचर फ़िल्में दिखाई गईं।

श्री आदित्य सुहास जम्भले द्वारा निर्देशित लघु फ़िल्म "खारवास" और श्री शाजी एन करुण द्वारा प्रदर्शित निर्देशित मलयालम फ़ीचर फ़िल्म "ओलू" के अवलोकन के लिए आम दर्शक भी आमंत्रित थे।

इस महोत्सव का उद्घाटन मलयालम फ़ीचर फ़िल्म 'ओलू' के निर्देशक श्री शाजी एन करुण की उपस्थिति में किया गया था, शुरुआत गैर फ़ीचर फ़िल्म खारवास निर्देशक श्री आदित्य सुहास जम्भले से हुई।

dæh; fQYe çek.ku ckM

Hkfedk

1. फ़िल्म निर्माण और फ़िल्मों के प्रदर्शन का संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये कला के सर्वाधिक व्यापक और लोकतांत्रिक माध्यम समझे गए हैं। जनमत तैयार करने, ज्ञान प्रदान करने और विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति एवं लोक परंपराओं को समझने में फ़िल्मों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में फ़ीचर फ़िल्मों का निर्माण अधिकतर निजी क्षेत्र में किया जा रहा है।

2. हमारा संविधान भाषण और अभियक्ति की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है ; परंतु यह स्वतंत्रता " भारत की सार्वभौमिकता और अखंडता, राष्ट्र

की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार और नैतिकता तथा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने जैसे मामले को ध्यान में रख कर तर्कसंगत प्रतिबंधों" के अधीन है।" संविधान के इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फ़िल्म प्रमाणन में बोर्ड का मार्गदर्शन करने वाले बुनियादी सिद्धांत सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त फ़िल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए अधिनियम की धारा 5बी(2) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

3. सार्वजानिक प्रदर्शन के लिए फ़िल्मों की मंजूरी देने के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 3 के अंतर्गत फ़िल्म सेंसर बोर्ड का गठन किया, जिसे 1 जून 1983 से नया नाम, केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणनबोर्ड दिया गया। वर्तमान बोर्ड में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

4. बोर्ड मुंबई में अपने मुख्यालय और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम, दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में नौ क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ काम करता है। क्षेत्रीय कार्यालयों का नेतृत्व क्षेत्रीय अधिकारी/एडीएल द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय अधिकारी और फ़िल्मों की परीक्षा में सलाहकार पैनल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। बोर्ड और सलाहकार पैनल के सदस्य समाज के एक क्रॉस–सेक्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं और शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गृहिणियों, फ़िल्मी हस्तियों, डॉक्टरों, पत्रकारों आदि जैसे सभी क्षेत्रों के लोगों को शामिल करते हैं।

5. बे–रोकटोक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली फ़िल्मों को "यू" प्रमाण–पत्र दिया जाता है। ऐसी फ़िल्में जो बे–रोकटोक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त समझी गई, लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए माता–पिता के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखती है, उन्हें "यूए" प्रमाण–पत्र दिया जाता है, साथ ही माता–पिता के लिए इस आशय की चेतावनी दे दी जाती है। गैर–वयस्कों के लिए अनुपयुक्त, परन्तु डॉक्टरों आदि विशेषज्ञतापूर्ण दर्शकों के समक्ष प्रदर्शन के लिए उपयुक्त फ़िल्मों को "एस" प्रमाण–पत्र दिया जाता है। सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त समझी गई प्रमाण–पत्र नहीं किया जाता।

fQYe çek.ku

6. भारत विश्व के प्रमुख फ़िल्म निर्माता देशों में से एक है। वर्ष के दौरान प्रमाणित गई भारतीय फ़ीचर फ़िल्मों की संख्या में संतुलित वृद्धि हुई। अप्रैल, 2018 से दिसंबर, 2018 के दौरान बोर्ड ने कुल 17014 प्रमाण–पत्र जारी किए, जिसमें से एक प्रमाण–पत्र सेल्यूलॉइड फ़िल्मों, 'निल 'सीईआरटी' प्रमाण–पत्र जारी किए गए, वीडियो फ़िल्मों को 6122 प्रमाण–पत्र और डिजिटल फ़िल्मों को 10892 प्रमाण–पत्र जारी किए गए।

fMft Vy

अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 के दौरान 10892 डिजिटल फ़िल्मों को कुल प्रमाण–पत्र जारी किए गए। इनमें से 1843 प्रमाण–पत्र भारतीय फ़ीचर फ़िल्मों को, 221 विदेशी फ़ीचर फ़िल्मों को, 8423 भारतीय लघु फ़िल्मों को और 405 विदेशी फ़िल्मों को दिए गए।

ohfM;k

इसी प्रकार 6122 प्रमाण–पत्रों में से, 591 प्रमाण–पत्र भारतीय फ़ीचर फ़िल्मों को जारी किए गए, 485 विदेशी फ़ीचर फ़िल्मों को, 4849 भारतीय लघु फ़िल्मों को और 197 विदेशी लघु फ़िल्मों को जारी किये गए।

lsY;qykbM

सेल्युलाइड फॉर्मेट में केवल एक 'निल' प्रमाण–पत्र जारी किया गया।

अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 की अवधि में प्रमाणित फ़िल्मों के प्रमाण–पत्रवार और श्रेणीवार ब्योरा अनुलग्नक–I में दिया गया।

7. अनुलग्नक–VI में भारतीय सेल्युलाइड फ़िल्मों के क्षेत्रवार और विषयवार वर्गीकरण दिया गया है। अनुलग्नक–IV में भारतीय डिजिटल फ़िल्मों का क्षेत्रवार और भाषावार ब्योरा है। सबसे अधिक फ़िल्में हिंदी भाषा में बनीं और उसके बाद तेलुगू, कन्नड़ और तमिल का स्थान है। अनुलग्नक–V में भारतीय डिजिटल फ़िल्मों का विषयवार वर्गीकरण है। अनुलग्नक–VI में विदेशी डिजिटल फ़िल्मों की क्षेत्रवार और राष्ट्रवार जानकारी दी गई है और अनुलग्नक अनुबंध VII में विदेशी फ़ीचर डिजिटल फ़िल्मों के विषयगत वर्गीकरण डेटा हैं।

ckM cBd@{ks=h; vfèkdkfj;ksa dh cBd

8. इस दौरान, 2 बोर्ड बैठकें एवं सह–कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं, जिनका ब्योरा आगे दिया गया है :

i) 145वीं बोर्ड बैठक एवं कार्यशाला मुंबई में 21 सितंबर, 2018 को बीकेसी के होटल ट्राइडेंट में आयोजित की गई थी। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता सीबीएफसी के अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी ने की।

ii) क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक 21 सितंबर, 2018 को होटल ट्राइडेंट, बीकेसी, मुंबई में आयोजित की गई।

सीबीएफसी के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बोर्ड के सदस्य और श्री प्रसून जोशी

egRoi.k xfrfof/k;k

9.) i) सलाहकार पैनल के सदस्यों के लिए कार्यशाला, 20 सितंबर, 2018 को होटल ट्राइडेंट, बीकेसी, मुंबई में आयोजित की गई थी। कार्यशाला की अध्यक्षता सीबीएफसी के अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी ने की। कार्यशाला में सीबीएफसी के बोर्ड के सदस्यों ने भी भाग लिया।

श्री प्रसून जोशी, अध्यक्ष, सीबीएफसी, सलाहकार पैनल के सदस्यों को संबोधित करते हुए

ii) 20 सितंबर, 2018 को मुंबई के बीकेसी के होटल ट्राइडेंट में फ़िल्म उद्योग के साथ एक बातचीत हुई। इस बातचीत की अध्यक्षता सीबीएफसी के अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी ने की।

श्री प्रसून जोशी, अध्यक्ष सीबीएफसी एवं बोर्ड के सदस्यों के साथ मुंबई क्षेत्र के सलाहकार पैनल के सदस्य

f'kdk;r

10. सीबीएफसी को फ़िल्मों के प्रमाणन को लेकर जनता से निरंतर शिकायतें मिलती रहीं। ये शिकायतें लिंग, धर्म, पर्दे पर हिंसा आदि से संबंधित थीं। अधिकतर शिकायतें सामान्य किस्म की थीं।

lljf'ki mYy?ku

11. अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 के दौरान, फ़िल्मों के प्रदर्शन के सेंसरशिप उल्लंघन का कोई मामला सामने नहीं आया। परंतु उल्लंघन के ज्यादातर मामले फ़िल्मों अंतरवेषण से संबंधित थे। फ़िल्म उद्योग के वर्गों द्वारा लगाए गए सेंसरशिप के उल्लंघन मोटे तौर पर पाँच प्रकार के हैं।

क) सार्वजनिक प्रदर्शनी के दौरान सीबीएफसी द्वारा फ़िल्मों में हटाए गए अंशों की प्रविष्टि

ख) प्रमाणित फ़िल्म को बोर्ड को नहीं दिखाया जाना

ग) प्रमाणित फ़िल्म में अंश (बिट्स) की प्रविष्टि

घ) जाली प्रमाण–पत्रों के साथ बिना संसर फ़िल्मों को दिखाना और

ई) सेंसर सर्टिफिकेट के बिना फ़िल्मों का प्रदर्शन।

फ़िल्मों में प्रक्षेप के मामले आमतौर पर विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं और यदि ऐसे मामलों का पता लग जाता है, तो इन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु सक्षम अधिकारियों

को भेजा जाता है। इस अवधि के दौरान, मुंबई क्षेत्र में प्रक्षेप का एक मामला था और फ़िल्म का शीर्षक एन सेंट नेरी मराठी मीडियम (मराठी) था। उक्त फ़िल्म को जाली सीबीएफसी प्रमाण–पत्र के साथ प्रदर्शित किया जा रहा था। यह मामला मुंबई पुलिस को सूचित किया गया था और वर्तमान में अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

çek.khdj.k 'kYd

12. प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में रु. 10,12,28,930 वसूल किए गए।

13. मंत्रालय के आदेश संख्या 807/3/2007 दिनांक 24 सितंबर, 2007 के तहत कुछ श्रेणियों की फ़िल्मों के प्रमाणन से संबंधित प्रावधान से छूट दी गई है।

egRoi.kZ ifji=

14.) i) एक महत्वपूर्ण परिपत्र संख्या 15 दिनांक 25 मई, 2018 सीबीएफसी प्रमाण–पत्र के प्रदर्शन की अवधि के बारे में जारी किया गया।

ii) धूम्रपान के दृश्य वाली फ़िल्मों में नए स्वास्थ्य स्थान (धूम्रपान और विरोधी तंबाकू) की प्रविष्टि के बारे में 26–11–2018 को एक परिपत्र जारी किया गया था।

vuqyXud&I

1&4&2018 ls 31&12&2018 rd dh vof/k esa ckM }kjk fQYek dk çek.k nrk gvk lefdr fooj.k

lsY;qyksbM									
	;w	;w *	;w ,	;w , *	,	, *	,l	,l *	dqy
भारतीय फ़ीचर फ़िल्में	–	–	–	–	–	–	–	–	–
विदेशी फ़ीचर फ़िल्में	–	–	–	–	–	–	–	–	–
भारतीय लघु फ़िल्में	–	–	–	–	–	–	–	–	–
विदेशी लघु फ़िल्में	–	–	–	–	–	–	–	–	–
फ़ीचर के अलावा भारतीय फ़ीचर फ़िल्में	–	–	–	–	–	–	–	–	–
फ़ीचर के अलावा दूसरी विदेशी फ़ीचर फ़िल्में	–	–	–	–	–	–	–	–	–
dqy ¼,½	&	&	&	&	&	&	&	&	&

ohfM;ks									
	;w	;w *	;w ,	;w , *	,	, *	,l	,l *	dqy
भारतीय फ़ीचर फ़िल्में	89	71	98	318	5	10	–	–	591
विदेशी फ़ीचर फ़िल्में	62	37	145	227	5	9	–	–	485
भारतीय लघु फ़िल्में	3284	105	1267	128	62	3	–	–	4849
विदेशी लघु फ़िल्में	69	1	115	8	2	2	–	–	197
फ़ीचर के अलावा भारतीय फ़ीचर फ़िल्में	–	–	–	–	–	–	–	–	–
फ़ीचर के अलावा दूसरी विदेशी फ़ीचर फ़िल्में	–	–	–	–	–	–	–	–	–
dqy ¼ch½	3504	214	1625	681	74	24	&	&	6122

fMf t Vy									
	;	; *	;	;, *	,	, *	, l	, l *	dy
भारतीय फ़ीचर फ़िल्में	405	294	229	666	64	184	–	1	1843
विदेशी फ़ीचर फ़िल्में	22	8	62	66	18	45	–	–	221
भारतीय लघु फ़िल्में	7118	129	927	153	82	14	–	–	8423
विदेशी लघु फ़िल्में	109	1	278	9	8	–	–	–	405
फ़ीचर के अलावा भारतीय फ़ीचर फ़िल्में	–	–	–	–	–	–	–	–	–
फ़ीचर के अलावा दूसरी विदेशी फ़ीचर फ़िल्में	–	–	–	–	–	–	–	–	–
dy ¼lh½	7654	432	1496	894	172	243	&	1	10892
dy tkM ¼,chlh½	11158	646	3121	1575	246	267	&	1	17014

* कटौती के साथ

vuyXud&II

1&4&2018 ls 31&12&2018 rd ckM }kjk çekf.kr dh xÃ Hkkjrh; fQYeksa dk lefdr fooj.k

{ks=okj&Hkk"kkokj

¼lsY;qykbM½

Øe-	Hkk"kk	ecÃ	psUuÃ	dksydkrk	csxy#	gnjkckn	fr#vuariqje	fnYyh	dVd	xqokgVh	dy
शून्य											
शून्य											

vuyXud&III

1&4&2018 ls 31&12&2018 rd ckM }kjk çekf.kr dh xÃ Hkkjrh; fQYeksa dk lefdr fooj.k

fo"k;okj oxÊdj.k

¼lsY;qykbM½

Øe-	Hkk"kk	ecÃ	psUuÃ	dksydkrk	csxy#	gnjkckn	fr#vuariqje	fnYyh	dVd	xqokgVh	dy
शून्य											
शून्य											

1-4-2018 से 31-12-2018 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित की गई भारतीय फिल्मों का समेकित विवरण
{क्षेत्रवार-भाषावार वर्गीकरण (डिजिटल)}

क्रम.	भाषा/क्षेत्र	मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	बंगलुरु	हैदराबाद	तिरुअनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहटी	कुल
1	हिंदी	315	1	9	1	2	—	37	—	1	366
2	कन्नड़	1	3	—	244	—	—	—	—	—	248
3	तेलुगू	3	29	—	9	171	5	—	—	—	217
4	मलयालम	2	6	—	1	6	161	1	—	—	177
5	तमिल	5	157	—	5	7	2	—	—	—	176
6	बांग्ला	9	—	138	—	—	—	1	2	—	150
7	मराठी	124	—	—	—	—	—	—	—	—	124
8	भोजपुरी	58	—	4	—	—	—	5	—	—	67
9	गुजराती	56	—	—	—	—	—	2	—	—	58
10	पंजाबी	30	—	—	—	—	—	19	—	—	49
11	उड़िया	1	—	—	—	—	—	—	33	—	34
12	असमिया	—	—	—	—	—	—	—	—	32	32
13	अंग्रेजी	11	1	2	—	2	3	—	—	1	20
14	मणिपुरी	1	—	—	—	—	—	—	—	13	14
15	टुलु	—	—	—	13	—	—	—	—	—	13
16	छत्तीगढ़ी	11	—	—	—	—	—	—	1	—	12
17	नगामीज़	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11
18	मिज़ो	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10
19	कोंकणी	8	—	—	—	—	—	—	—	—	8
20	राजस्थानी	3	—	—	—	—	—	3	—	—	6
21	उर्दू	2	—	—	—	2	—	1	—	—	5
22	सिंधी	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5
23	खासी	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
24	नागपुरी	2	—	2	—	—	—	—	—	—	4
25	बंजारा	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3
26	हिंदी आंशिक अंग्रेजी	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
27	हिंगलिश	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2
28	मगही	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
29	मैथिली	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
30	अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
31	बोड़ो	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1

32	बृजभाषा	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
33	दखिनी	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
34	अंग्रेजी आंशिक हिंदी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
35	गढ़वाली	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
36	गारो	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
37	हरियाणवी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
38	हिंदी आंशिक उर्दू	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
39	हो	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
40	अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ इरुला	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
41	खांडेशी अहिरानी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
42	खोरठा	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
43	अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ कोडव	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
44	लंबनी	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
45	पंग्चेंपा	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
47	सादरी	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
48	शेरदुकपेन	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
49	अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ सिक्किमी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
50	मूक	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
51	अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ तांगखुल	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	कुल जोड़	658	197	157	280	191	172	71	38	79	1843

vuyXud&V

1&4&2018 ls 31&12&2018 ckM }kjk çekf.kr dh xÃ Hkkjrh; fQYeksa dk lefdr fooj.k fo"k;okj oxÊdj.k ¼fMftVy½

Ø- l-	fo"k;okj oxÊdj.k	eqcÃ	pUuÃ	dksy-dÙkk	cxyq#	gnjk-ckn	fr#vuariqje	fnYyh	dVd	xqokgVh	dqy
1	सामाजिक	628	196	154	261	188	165	70	36	41	1739
2	बाल फ़िल्में	26	–	–	19	3	3	–	–	38	89
3	शैक्षिक	–	–	2	–	–	–	–	1	–	3
4	अन्य	4	1	1	–	–	4	1	1	–	12
	dqy tksM+	658	197	157	280	191	172	71	38	79	1843

1–4–2018 से 31–12–2018 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित गई विदेशी फ़िल्मों का समेकित विवरण

{k=okj&jk"Vªokj ¼fMf tVy½

Ø- l-	mnxe n'k@ {k=	e|cÃ	p|UuÃ	dky- dkrk	c|xy|#	g|njk- ckn	fr#vu| rije	fnYyh	dVd	x|okgVh	d|y tkM-
1	अमरीका	110	17	–	–	–	–	3	–	–	130
2	कोसोवो	30	1	–	–	–	–	1	–	–	32
3	संयुक्त अरब अमीरात	15	–	–	–	–	–	–	–	–	15
4	फ्रांस	10	–	–	–	–	–	–	–	–	10
5	यूके	9	–	–	–	–	–	–	–	–	9
6	बांग्लादेश	2	–	2	–	–	–	–	–	–	4
7	होंगकोंग	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4
8	पेरू	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4
9	यूक्रेन	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4
10	कनाडा	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
11	चिली	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
12	चीन	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
13	सायप्रस	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
14	कोसोवो	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
15	अन्य	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
16	रूस	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
17	ताईवान	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
18	ऑस्ट्रेलिया	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	कुल जोड़	196	18	2	0	0	0	5	0	0	221

vu|yXud&VII

1&4&2018 l| 31&12&2018 rd ckM }kjk çekf.kr dh xÃ fon|'kh fQYek dk lefdr fooj.k

{k=okj&jk"Vªokj oxÊdj.k ¼ohfM;k½

Ø- l-	Hkk"kk	e|cÃ	p|UuÃ	dky- dÙkk	c|xy|#	g|njk- ckn	fr#vu| rije	fnYyh	dVd	x|okgVh	d|y tkM-
1	हिंदी	301	2	–	–	–	–	41	–	–	344
2	भोजपुरी	59	–	1	–	–	–	2	–	–	62
3	कन्नड़	–	–	–	36	–	–	–	–	–	36
4	तमिल	1	24	–	2	–	1	–	–	–	28
5	मणिपुरी	–	–	–	–	–	–	–	–	25	25
6	बंगाली	3	–	18	–	–	–	–	–	–	21
7	गुजराती	–	–	–	–	–	–	19	–	–	19
8	मलयालम	–	13	–	–	–	4	–	–	–	17

9	तेलुगू	—	2	—	1	11	—	—	—	—	14
10	अंग्रेजी	6	—	—	—	—	—	1	—	—	7
11	मराठी	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6
12	उड़िया	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
13	अंग्रेजी आंशिक हिंदी	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
14	हरियाणवी	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15	हिंदी आंशिक अंग्रेजी	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16	हिमाचली	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17	हिंगलिश	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
18	पंजाबी	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	कुल जोड़	381	41	19	39	11	5	65	5	25	591

vuqyXud&VIII

1&4&2018 ls 31&12&2018 rd ckM }kjk çekf.kr dh xÃ fons'kh fQYeksa lef"dr fooj.k {ks=okj&jk"Vªokj oxÊdj.k¼ohfM;ks½

Ø-l-	mnxe ns'k	eqcÃ	pUuÃ	dksy-dÙkk	cxyq#	gSnjk-ckn	fr#vuUriqje	fnYyh	dVd	xqok-gkVh	dqy tksM
1	अमेरिका	327	18	10	—	1	—	6	—	—	362
2	यू के	22	—	3	—	—	—	1	—	—	26
3	जापान	20	—	—	—	—	—	—	—	—	20
4	हंगरी	13	—	1	—	—	—	—	—	—	14
5	कनाडा	9	—	—	—	—	—	4	—	—	13
6	फ्रांस	12	—	—	—	—	—	—	—	—	12
7	होंगकोंग	7	—	2	—	—	—	—	—	—	9
8	संयुक्त राष्ट्र अमीरात	7	—	1	—	—	—	—	—	—	8
9	ऑस्ट्रेलिया	4	1	—	—	—	—	—	—	—	5
10	थाईलैंड	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3
11	नीदरलैंड	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
12	चीन	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
13	डेनमार्क	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
14	फ़िनलैंड	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15	जर्मनी	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
16	कोसोवो	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17	लेबनान	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
18	बांग्लादेश	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
19	रोमानिया	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
20	दक्षिण कोरिया	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21	वेनेजुएला	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22	वर्जिन आइलैंड	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	dqy tksM	436	19	17	0	1	0	12	0	0	485

ckM dh foÙk 0;oLFkk

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधान के अंतर्गत, केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड फ़िल्मों एक सांविधिक निकाय है, जो फ़िल्मों के सार्वजानिक प्रदर्शन का नियमन करता है. परंतु प्रशासनिक प्रयोजन के लिए बोर्ड को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय समझा जाता है।

बोर्ड को राजस्व सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 में निर्दिष्ट अनुसार प्रमाणन शुल्क की वसूली से प्राप्त होती है। बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय में फ़िल्मों की स्क्रीनिंग के संदर्भ में प्रोजेक्शन प्रभार भी लगाता है। 1 अप्रैल, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 की अवधि के दौरान अर्जित कुल आय रु. 10,12,28,930/–है। वसूल किया गया राजस्व भारत के समेकित निधि में जमा किया जाता है। बोर्ड इस संबंध में कोई बैंक खाता संचालित नहीं करता।

व्यय के साथ–साथ राजस्व के लिए खातों को बनाए रखने के उद्देश्य से, बोर्ड वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रणाली का पालन करता है। बोर्ड को मंत्रालय से विभिन्न मदों के लिए गैर–योजना व्यय के अंतर्गत अनुदान प्राप्त होता है। 1–4–2018 से 31–12–2018 तक इन मदों के अंतर्गत खर्च की राशि का ब्योरा नीचे दिया गया है।

ctV vkoVu vkj 0;;

(लाख रु. में)

	xj&;ktuk ch-b ¼2018&19½	31 fnlcj] 2018 rd 0;;
वेतन	560.00	402.99
चिकित्सा	10.00	3.39
डीटीई	21.00	13.65
ओई	102.00	57.07
पीपीएसएस	180.00	176.66
किराया दरें और कर	16.00	7.59
अन्य प्रशासनिक व्यय	08.00	4.15
सूचना प्रौद्योगिकी	05.00	0.49
एसएपी	02.00	1.15
कुल	904.00	667.14

1- ;ktuk 0;; % सीबीएफसी और प्रमाणन प्रक्रिया का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार

2018 से 2019 की योजना अवधि के तहत सीबीएफसी की प्रस्तावित योजना "सीबीएफसी और प्रमाणन प्रक्रिया का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार" के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों के लिए 2.50 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए रु. 50 करोड़ की राशि (बीई के अंतर्गत) आवंटित की गई थी।

(1) फ़िल्म अनुप्रयोग और प्रमाणन वेबसाइट की ऑनलाइन इन प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर विकास।

(2) सीबीएफसी के सभी कार्यालयों के लिए डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम और डिजिटल थियेटर।

(3) सीबीएफसी और मुख्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त कार्यालय स्थान की आवश्यकता। एसएफसी ने अनुमोदन नहीं दिया है, अतः कोई व्यय नहीं किया गया।

Øe l	ch-Ã- 2018&19 dk fy, ¼yk[k #- e½	31&12&2018 rd 0;; ¼yk[k #- e½
1	250.00	65.61

2- ;ktuk dk;Øe % मानव संसाधन और विकास के लिए प्रशिक्षण।

सीबीएफसी "मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण" कार्यक्रम 2018–19 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों संचालित कर रहा है :

(क) क्षेत्रीय कार्यालयों और मुम्बई में बोर्ड के सदस्यों और

क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए कार्यशाला/सेमिनार/संवाद।

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में परामर्शी पैनल सदस्यों के लिए प्रशिक्षण/कार्यशालाओं।

(ग) समूह 'क', ख 'और ग' का कर्मचारियों को प्रशासन लेखा और बजट प्रक्रिया, ई–गवर्नेंस, आईटी कौशल, सतर्कता और आरटीआई के मामलों का प्रशिक्षण।

एसबीजी : 2018–19 : रु. 25.00 (लाख)।

31–12–2018 : 09.86 (लाख) पर व्यय।

jk"Vªh; fQYe fodkl fuxe ¼,u,QMhlh½

वर्ष 1975 में राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम लिमिटेड की स्थापना भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित राष्ट्रीय आर्थिक नीति और उद्देश्यों के अनुसार भारतीय फ़िल्म उद्योग में सम्मिलित एक एकीकृत और कुशल विकास की योजना, प्रचार और आयोजन के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की थी। एनएफडीसी को विलय किया गया था फ़िल्म वित्त निगम (एफएफसी) और इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (आईएमपीईसी) के साथ विलय करके 1980 में पुनः स्थापित किया गया था। स्थापना के बाद से, एनएफडीसी ने 21 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में 300 से अधिक फ़िल्मों को वित्त पोषित/निर्मित किया है, जिनमें से कई ने व्यापक प्रशंसा अर्जित की है और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। स्थापना के बाद से,एनएफडीसी ने 21 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में 300 से अधिक फ़िल्मों को वित्त पोषित/निर्मित किया है, जिनमें से कई ने व्यापक प्रशंसा अर्जित की है और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं।

एनएफडीसी सरकारी एजेंसियों के लिए 360 डिग्री एकीकृत विपणन समाधान भी प्रदान करता है और विज्ञापन, वृत्तचित्र, लघु फ़िल्में, टीवी शृंखला, वेब विज्ञापन, रेडियो शृंखला और विषयगत संगीत प्रतिमाओं का उत्पादन करता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एनएफडीसी ने मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के विभिन्न वर्टिकल्स में भारत के ब्रांड सिनेमाघरों के तहत फ़िल्मों के उत्पादन और वितरण को कवर करने, विज्ञापन के उत्पादन, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के लिए लघु और कॉरपोरेट फ़िल्मों, फ़िल्म प्रदर्शन, के लिए अपनी बाइट को जारी रखना जारी रखा। बहाली, फ़िल्म बाज़ार, डिजिटल नॉन–लीनियर एडिटिंग, सिनेमैटोग्राफी, सबटाइटलिंग आदि में प्रशिक्षण।

फ़िल्म विकास एजेंसी के रूप में, एनएफडीसी फ़िल्म उद्योग के ऐसे क्षेत्रों/खंडों के विकास में मदद करने के लिए भी जिम्मेदार है, जो सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हों और ऐसे क्षेत्र जो निजी उद्यमियों द्वारा वाणिज्यिक मजबूरियों के कारण, शुरू न किए जा सकते हों तथा जिससे संतुलित विकास हो सके। हालांकि, भले ही भारतीय फ़िल्म उद्योग में इसकी भूमिका काफी हद तक विकासात्मक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में, एनएफडीसी के पास एक कॉरपोरेट जनादेश भी है और जो एक स्वस्थ बैलेंस शीट बनाने के लिए जिम्मेदार होता है।

mRiknu

फ़िल्म प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत "विभिन्न भारतीय भाषाओं में फ़िल्मों का उत्पादन" शीर्षक से भारतीय सिनेमा में विविधता को दर्शाने वाली/सह–निर्मित फ़ीचर फ़िल्मों का निर्माण किया। उक्त योजना के तहत, एनएफडीसी फ़िल्म निर्माण के लिए अपने मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत फ़िल्मों का निर्माण और सह–निर्माण करता है, जिससे यह पहली फ़िल्म के 100% उत्पादन और निजी खिलाड़ियों के साथ साझेदारी में भारत और विदेश में अच्छी गुणवत्ता की फ़िल्मों के सह–उत्पादन का काम करके नवोदित फ़िल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करता है।

- 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत एनएफडीसी द्वारा पान नलिन द्वारा निर्देशित फ़ीचर 'बियॉन्ड द नोन वर्ल्ड, पहली आधिकारिक इंडो–न्यूज़ीलैंड सह–उत्पादन है, अभी निर्माणाधीन है। यह कॉर्पोरेशन उन बहुमुखी और उभरते फ़िल्म निर्माताओं के समुदाय के समर्थन के सहयोग के प्रयास को दर्शाता है, जो विविधता, नवाचार और विशिष्टता को मूर्त रूप देते हैं।
- एनएफडीसी द्वारा गैप फाइनेंसिंग में फ़िल्म "अंग्रेजी में कहते हैं" का सह–निर्माण एक अनूठा प्रयोग था। इसके डिजिटल प्रीमियर का नाट्यकीय रूप 18 मई, 2018 को पैन इंडिया के आधार पर अमेज़ॅन पर जारी किया गया था।

forj.k

एनएफडीसी का वितरण विभाग पारंपरिक प्लेटफार्मों (थियेट्रिकल, टेलीविजन, होम वीडियो और एयरलाइंस) और तेजी से उभरते प्लेटफार्मों (वीडियो–ऑन–डिमांड, डीटीएच और मोबाइल) पर एक फ़िल्म की रिलीज के लिए जिम्मेदार है।

- **ukV;&lcekh forj.k**

एनएफडीसी के पास उन योग्य परियोजनाओं पर एक नजर होगी जो वार्षिक फ़िल्म बाज़ार के कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में काम कर सकती हैं क्योंकि ये परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं और वित्तीय या कलात्मक सहायता, नाट्य संबंधी समर्थन, फ़िल्म समारोह, वितरण आदि की जरूरत है। इस विभाग ने कुछ परियोजनाओं को चिंहित किया है जो प्रोडक्शन जनादेश के साथ संरेखण में हो सकती हैं।

- **ohfM;k v,u fMekM Iy\VQ,e % cinemasofindia.com**

एनएफडीसी 2012 में लॉन्च किया गया, एनएफडीसी के आधिकारिक वीओडी प्लेटफ़ॉर्म के लिए सुचारु इस्तेमालकर्ता के अनुभव को सृजित करने के लिए पूरे साल सब्सक्रिप्शन के आधार पर खिताब हासिल किया। आने वाले वर्ष में, नए शीर्षकों के साथ एक सुचारु के विपणन से वीओडी रिलीज़ देखेंगे। वीओडी प्लेटफ़ॉर्म इंस्टीट्यूशनल प्रमाणिकरण पर केंद्रित है जो दुनिया भर के संस्थानों को दिया जाता है, जिसमें सब्सक्राइबर्स को संस्थानों और विश्वविद्यालयों के शुल्क के लिए दुनिया भर में कहीं से भी फ़िल्में उपलब्ध होंगी।

- **legu ¼Çl fMd'ku½**

टेलीविजन–एनएफडीसी फ़िल्मों के प्रदर्शन/प्रसारण के लिए भागीदार चैनलों/प्रसारकों (ज़ी, स्टार और अन्य) के साथ एनएफडीसी भागीदारी को बनाए रखेगा।

डिजिटल/डीटीएच–एनएफडीसी शीर्षक सभी प्रमुख प्लेटफार्मों जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, जियो सिनेमा पर उपलब्ध हैं और मौजूदा कंपनियों के साथ संबंधों को मजबूत करने और अन्य उभरते/स्थापित मंच के साथ नए रिश्ते बनाने की योजना है।

- **gke ohfM;k**

भारत की अग्रणी एमएंडई कंपनी में से एक, शेमारू एंटरटेनमेंट के साथ कार्यनीतिक भागीदारी को जारी रखते हुए एनएफडीसी इसे नवीनीकृत करेगा। इससे पहले, 98+ शीर्षकों को शेमारू के सहयोग से जारी किया गया था।

- **vrjjk"Vh; fQYe ck tkj vkj fcØh**

वितरण विभाग दुनिया भर के सभी प्रमुख फ़िल्म बाज़ारों में अपना प्रतिनिधित्व कायम रखे हुए है और वेनिस, कान्स, एएफएम, ईएफएम, एचकेटीडीसी आदि जैसे सभी प्रसिद्ध बाज़ारों में ब्रांड एनएफडीसी का निर्माण करता है और ए–लिस्ट फेस्टिवल प्रोग्रामर, अंतराष्ट्रीय बिक्री एजेंटों/वितरकों और प्रतिष्ठित पत्रकारों के साथ सुदृढ़ संबंध कायम करने में मदद करता है। अंतरराष्ट्रीय वितरकों, चैनलों, टेलीविज़न फर्मों और टीवी चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग करने वाले एनएफडीसी के विचार इसके शीर्षक को टीवी, वीओडी और अन्य पर मुद्रीकृत करने की योजना करता है।

çhO; fFk;Vj

एनएफडीसी मुम्बई स्थित अपने 81 सीट प्रीव्यू थियेटर और चेन्नई स्थित 100 सीटों के प्रीव्यू थियेटर को फ़िल्मों की प्रदर्शनी के लिए विभिन्न सरकारी/गैर–सरकारी ग्राहकों किराए पर देता है। ये थियेटर 3 डी प्रक्षेपण सुविधाओं सहित एनालॉग और डिजिटल प्लेटफार्मों में फ़िल्में दिखाने के लिए नवीनतम तकनीक से लैस हैं। टैगोर फ़िल्म सेंटर में आयोजित हालिया फ़िल्म समारोह में रूसी, जापानी और कोरियाई फ़िल्म समारोह हुए हैं। दिसंबर 2018 में, चेन्नई इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल को इंडो सिने एप्रिसिएशन फाउंडेशन (आईसीएएफ) के साथ जोड़ा जा रहा है। एनएफडीसी फ़िल्म समारोहों/दूतावासों के साथ नियमित रूप से फ़िल्म समारोह आयोजित करने के लिए संबद्ध कर रहा है।

- **vkV gkml fFk;Vj vkj fQYe lL—fr dæ] ckæk**

कला और फ़िल्म समुदाय के लिए भारत के पहले सिनेमैथिक एनएफडीसी के आर्ट हाउस थियेटर और फ़िल्म कल्चर सेंटर के रूप में सिनेमा के लिए एक केंद्र के रूप में इरादा है। आर्ट हाउस थियेटर और फ़िल्म संस्कृति केंद्र, बांद्रा में यह एकसाथ कई लोगों के देखने, अनुसंधान करने, शिक्षाविदों और सिनेमा के संरक्षण के लिए प्रस्तावित है।

lekjkg vkj vkmVjhp ¼vkxs c<uk½

- पूरे वर्ष में कई कार्यक्रमों में एनएफडीसी फ़िल्मों की स्क्रीनिंग की सुविधा सहित, कोर्टिसन फ़िल्म फेस्टिवल, गेन्ट बेल्जियम, निबंध इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, लंदन, इंडियन हैबिटेट सेंटर, आईआईटी मद्रास, किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट, बिहार स्टेट फ़िल्म डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, केरल साहित्य महोत्सव, 1018एमबी. कॉम के साथ सहयोग किया।
- प्रीमियर नाइट्स के लिए रेडियो नाशा के साथ टाई–इन–'जाने भी दो यारों' की स्क्रीनिंग में ब्रांडिंग और प्रोत्साहन के अवसर पर कुंदन शाह और ओम पुरी को श्रद्धांजलि में रेडियो नाशा के साथ साझेदारी में स्क्रीनिंग की गई। इस अवसर पर मौजूद अतिथियों में श्रीमती कुंदन शाह, सतीश शाह, सतीश कौशिक, सुधीर मिश्रा, नंदिता पुरी और ईशान पुरी, राजेश पुरी तथा अन्य हस्तियां शामिल थीं।

fon'kk e loèku vkj foi.ku

विदेश विभाग अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों और बाज़ारों में भारतीय सिनेमा की उपस्थिति दर्ज़ करने की दिशा में काम करता है। अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समुदाय की भारतीय सिनेमा में बढ़ती रुचि को देखते हुए एनएफडीसी मुख्य रूप से भारत के सिनेमा और भारतीय प्रतिभा को अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों और बाज़ारों में बढ़ावा देने और प्रदर्शन करने, विश्व भर में निजी और सरकारी फ़िल्म संस्थानों के साथ साझेदारी सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रभाग ने दुनिया भर से निजी और सरकारी फ़िल्म संस्थानों के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया है। रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान, एनएफडीसी ने कान फ़िल्म महोत्सव, फ्रांस, अमेरिकी फ़िल्म बाज़ार और संयुक्त राज्य अमेरिका में भाग लिया।

fQYe ckt kj

- एनएफडीसी ने 20 नवंबर से 24 नवंबर, 2018 के दौरान गोवा में फ़िल्म बाज़ार–2018 आयोजित किया। गोआ में फ़िल्म बाज़ार एक ऐसा मंच है, जिसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय और दक्षिण एशियाई फ़िल्म समुदाय के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसमें फ़िल्म–सृजन, निर्माण और वितरण के क्षेत्र में दक्षिण एशियाई विषयवस्तु और प्रतिभा की खोज करने, उसे बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह बाज़ार विश्वभर के फ़िल्म क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए एक मंच का काम करता है। फ़िल्म बाज़ार का लक्ष्य विश्व सिनेमा की दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बिक्री में सहायता करना भी है।

- फ़िल्म बाज़ार अब दक्षिण एशियाई फ़िल्म निर्माताओं के लिए अपनी कहानियों को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू फ़िल्म समुदाय के लिए प्रस्तुत करने का केंद्र स्थल बन गया है। इसके अलावा, यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय बिक्री एजेंटों, उत्पादकों, वितरकों, फ़िल्म फेस्टिवल प्रोग्रामरस और फ़िल्म फंड के वार्षिक कैलेंडर में शामिल होना चाहिए; अंतिम लेकिन कम से कम, यह एक घटना भी बन रही है जहां उद्योग के पेशेवर व्यवसाय में भविष्य के रुझानों के बारे में जानने के लिए आ रहे हैं और अगली बड़ी फ़िल्म/फ़िल्म निर्माता के साथ पहचान करने और साझेदार बनने के लिए भी।

- वर्ष 2018 में वर्क–इन–प्रोग्रेस लैब्स के लिए प्रस्तुत सह–उत्पादन परियोजनाओं के लिए यूएसए, जर्मनी, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, चीन के फ़िल्म निर्माताओं/निर्माताओं के साथ एक बहुत ही रोमांचक लाइन–अप देखा गया।

- फ़िल्म बाज़ार में पांच फ़िल्मों को सम्मानित किया गया। तीन फ़िल्मों को प्रसाद पोस्ट प्रोडक्शन और मूवीबफ एप्रिसिएशन अवार्ड (डीआई + डीसीपी अवार्ड) दिया गया–सौरव राय द्वारा निर्देशित निमटोह (निमंत्रण), जदु महंता द्वारा निर्देशित रुक्नी कोइना (द होली ब्राइड), किस्लय द्वारा निर्देशित, अजीब बूढ़ी स्त्री (स्ट्रेंज ओल्ड लेडी) जबकि दो फ़िल्मों भास्कर हजारिका द्वारा निर्देशित 'आमिस' (रावेनिंग) प्रेटेक वत्स और द्वारा निर्देशित 'ईब अलाय ऊ' ने फेसबुक पुरस्कार जीता।

çf'k{k.k vkj fodkl

- एनएफडीसी ने 2012 में एक प्रशिक्षण और विकास विभाग की स्थापना की, जिसे फ़िल्म क्षेत्र में मध्य–कैरियर प्रशिक्षण के अवसरों के क्षेत्र में अंतर को संबोधित करने के लिए तैयार किया गया है। यह भारतीय फ़िल्म समुदाय के लिए एक प्रमुख उत्पादन देने के लिए ब्रांड एनएफडीसी लैब्स के तहत स्थापित किया गया है। पेशेवर फ़िल्म निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण, मुख्य विषयों में कार्यशालाओं और मास्टर कक्षाएं प्रदान करना–निर्देशन, लेखन, संपादन, छायांकन और निर्माण।

,u,QMhlh yCl

एनएफडीसी ने फ़िल्म क्षेत्र में लगे व्यवसायियों में प्रशिक्षण अंतराल दूर करने के लिए 2012 में बाज़ार–2012 में एनएफडीसी लैब्स ब्रैंड के अंतर्गत प्रशिक्षण और विकास विभाग की स्थापना की थी। इसका लक्ष्य भारतीय फ़िल्म समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण निर्माण बिंदु रूप में काम करना, संबंधित मूलभूत विषयों–निर्देशन, लेखन, संपादन, सिनेमेटोग्राफी और निर्माण में कार्यशालाओं और प्रमुख कक्षाओं का प्रबंध करना है।

iVdFkk y[kdk dh yc

- पटकथा विकास प्रयोगशाला लेखकों, पटकथा और चरित्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि लेखकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद से उनकी पटकथा लेखन तकनीक को बढ़ाया जा सके। प्रयोगशाला को 6 महीने की अवधि में 3 भाग के सत्र में डिज़ाइन किया गया है ताकि प्रत्येक परियोजना के समग्र रचनात्मक विकास के लिए स्वस्थ निर्माणपूर्व अवधि की अनुमति दी जा सके। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आकाओं के साथ 6 लेखकों के साथ प्रयोगशाला के पहले सत्र को निष्पादित किया गया है और शेष 2 सत्र जनवरी 2019 और मार्च, 2019 के महीने में आयोजित किए गए।

dk'ky fodkl çf'k{k.k

- स्किल इंडिया मिशन के तहत चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय में प्रशिक्षण प्रभाग दक्षिणी राज्यों में बेरोज़गार युवाओं के लिए विभिन्न मीडिया से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जहाँ इसने एनीमेशन के क्षेत्र में 14000 से अधिक युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किए हैं। कैमरा, एडिटिंग, मल्टीमीडिया, फोटोग्राफी और ऑडियो इंजीनियरिंग। यह अनुमान है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरने वाले लगभग 70 प्रतिशत युवाओं ने रोज़गार पाया है।
- एससी/एसटी और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों को शामिल करने के लिए कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है, और मीडिया और मनोरंजन उद्योग में विभिन्न प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को पर्याप्त रोज़गार के अवसर प्रदान किये जाते हैं। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों को राष्ट्रीय उत्थान शिक्षा अभियान (रूसा), एक केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से मीडिया में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- राज्य प्रायोजित योजना के तहत, एनएफसीडी ने वित्त वर्ष 2018–19 (नवंबर 2018 तक) के लिए 1593 उम्मीदवारों के लिए मीडिया में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया है।

ehfM;k vfHk;ku

एनएफडीसी को वर्ष 2015 से मंत्रालयों/विभागों के ऑडियो–विजुअल मीडिया अभियानों को इकट्ठा करने के लिए एक एजेंसी के रूप में फिर से अधिसूचित किया गया है।

एनएफडीसी के निरंतर प्रयास और समय पर सेवाओं ने कई मंत्रालयों/विभागों को अपने मीडिया प्रचार अभियानों के लिए अपनी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर दिया है।

- ehfM;k lqpkyu dk fMftVyhdj.k

एनएफडीसी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नीति के अनुसार मीडिया नियोजन और मीडिया संबंधी गतिविधियों में पारदर्शिता, दक्षता और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मीडिया ऑपरेशन विनियोग को लागू किया है।

पूर्णतः त्रुटिमुक्त समाधान प्रदान करने के लिए इस मीडिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी योजना, बिलिंग और भुगतान प्रक्रिया को एकीकृत किया गया है।

इससे रिलीज़ ऑर्डर, बिल सत्यापन, भुगतान आदि जारी करने की मैनुअल प्रक्रिया को समाप्त करने में मदद मिली है और वादार्थी मंत्रालयों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एजेंसियों के लिए वितरण में सरल, तेज और कुशल हो गया है।

यह मीडिया एजेंसियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा बशर्ते कि वादार्थी मंत्रालयों से राशि समय पर प्राप्त हो।

हाल ही में, एनएफडीसी ने बीएआरसी के साथ मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की एक श्रृंखला के माध्यम से क्लाइंट के विज्ञापन बजट के प्रभाव को अधिकतम करने और टीवी स्पॉट के प्रसारण के तृतीय पक्ष सत्यापन के संचालन के लिए एक समझौता किया है।

fQYe lqfoèkk dk;kZy; ¼,Q,Qvk½

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नवंबर 2015 में राष्ट्रीय फ़िल्म विकास नियम (एफएफओ) में फ़िल्म सुविधा कार्यालय की स्थापना की थी। इसका लक्ष्य भारत में विदेशी फ़िल्म निर्माताओं को फ़िल्म शूटिंग हेतु प्रोत्साहित करना और तत्संबंधी सुविधाएं प्रदान करना है। फ़िल्म सुविधा कार्यालय द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार अब भारतीय फ़िल्म निर्माताओं के लिए भी किया गया है।

यह कार्यालय एक ही स्थान पर सुविधाएं मंजूर करने के व्यवस्था के रूप में काम कर रहा है। इससे भारत में फ़िल्म निर्माण में आसानी होती है और साथ एक फ़िल्म–अनुकूल वातावरण का निर्माण होता है, फ़िल्म निर्माण को लाभयुक्त क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

इसकी स्थापना देश में फ़िल्म अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए की गई है। इसके लिए निम्नांकित मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए–

गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आदि। इसके अलावा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों में भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए ताकि फ़िल्मों की शूटिंग में सुविधा प्रदान की जा सके। इस प्रकार, सरकारी तंत्र को फ़िल्म के अनुकूल इको–सिस्टम और नीतियां बनाने में मदद करने में सक्रिय भूमिका निभाता है।

- ,Q,Qvk oc ikVy dk 'kHkkjHk

अपने अधिकार–पत्र के हिस्से के रूप में और दुनिया भर की फ़िल्म बिरादरी तक पहुंचने के प्रयास में, एफएफओ ने अपना वेब पोर्टल प्रारंभ किया, जिसे सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री (स्वंतत्र प्रभार) माननीय कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

ने 20 नवंबर, 2018 को 49वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के उद्घाटन समारोह में प्रारंभ किया।

इस पोर्टल से न केवल अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म निर्माताओं को लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने में मदद मिलती है बल्कि भारत की सह–उत्पादन संधियों और प्रमुख केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लागू दिशानिर्देश भी दर्ज़ हैं।

एफएफओ पोर्टल का डिज़ाईन और इसका विकास देश की फ़िल्मांकन से संबंधित सारी जानकारी को एक ही स्थान पर रखाने हेतु किया गया है और इस प्रकार की सुगम सुलभता से देश में फ़िल्मांकन में आसानी होती है।

- Hkkjr e *fQYekdu dh lxerk* ij dfær nk fnolh; dk;l'kkyk

एफएफओ ने 21–नवंबर, 2018 को फ़िल्म बाज़ार–2018 में 'फ़िल्मांकन की सुगमता' पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में 11 राज्यों–आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक के प्रमुख उद्योग के हिस्सेदारों और नोडल अधिकारियों की भागीदारी शामिल थी। कार्यशाला में भाग लेने के लिए विशेष रूप से लक्षद्वीप, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ–साथ असम और ओडिशा से आए भी प्रतिभागी थे।

- of'od çn'kuh e lokvk ij Hkkxhnkjh

एफएफओ ने मुंबई में आयोजित 15 से 18 मई 2018 तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक भाग के रूप में सेवाओं (जीईएस) पर वैश्विक प्रदर्शनी में भाग लिया। एक वैश्विक मंच, जीईएस, जो भारत की सेवाओं को प्रदर्शित करता है, ने वैश्विक मीडिया और मनोरंजन उद्योग के कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल और प्रतिभागियों की उपस्थिति दर्ज की जो जीईएस में एक चैंपियन क्षेत्र था। भारत में फ़िल्मांकन को बढ़ावा देने के प्रयास में, एफएफओ ने 'देश में फ़िल्म के गुणक प्रभाव पर फ़िल्म' का प्रदर्शन किया, साथ ही भारत की सह–उत्पादन संधियों और भारतीय राज्यों द्वारा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन के बारे में जानकारी का प्रसार किया। भारत के मनोरंजन उद्योग–ए ग्लोबल पावर हाउस' पर एक सत्र आयोजित किया गया जिसमें श्री जी.सी. आरोन, निदेशक (फ़िल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में फ़िल्मांकन में सरकार की वह पहल साझा की, जिसे एफएफओ के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

- çe[k dæh; e=ky;k d lkFk cBd

एफएफओ ने पिछले कुछ महीनों में निम्नलिखित हितधारक मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों के साथ मुलाकात की, एफएफओ वेब पोर्टल के लिए डेटा और जानकारी एकत्र करने के साथ–साथ फ़िल्म निर्माताओं द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में फ़िल्म निर्माण के दौरान आने वाले मुद्दों पर विचार–विमर्श किया, ताकि फ़िल्मांकन की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके।

- ,,QlhvkÃ d fluikfl;e 2018 e ,Q,Qvk

एसोसिएशन ऑफ़ इंटरनेशनल फ़िल्म कमिश्नर्स (एएफसीआई) का सदस्य बनने के लिए फ़िल्म सुविधा कार्यालय ने 20 सितंबर से 22 सितंबर, 2018 के बीच आयोजित एएफसीआई की वार्षिक तीन दिवसीय प्रमुख उद्योग कार्यशाला में भाग लिया, जिसमें एक बदलते उद्योग के साथ संवादात्मक और शैक्षिक सेमिनारों की एक श्रृंखला भी शामिल थी जिसके एक सत्र में फ़िल्म उद्योग से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के इरादे के बारे में फ़िल्म शूटिंग से संबंधित लोगों को दिया गया। इस यात्रा ने एफएफओ को वार्नर ब्रदर्स, एचबीओ, सीएए, पैरामाउंट स्टूडियोज, एंटरटेनमेंट पार्टनर्स, फाइनल ड्राफ्ट, कोडक जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर के कई वैश्विक खिलाड़ियों के साथ मुलाकात करने और भारत सरकार की पहल पर उनके साथ वेब पोर्टल और फ़िल्म पर चर्चा करने का मौका दिया।

- jkT; ukMy vfèkdkfj;k d lkFk lgHkkfxrk

राज्यों और स्थानों की जानकारी इकट्ठा करने के प्रयास में और जमीनी स्तर पर उन्हे फ़िल्मांकन में सुविधा के लिए राज्य एफएफओ के अधिकारियों ने विभिन्न नोडल अधिकारियों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, नगालैंड दक्षिणी राज्य हैदराबाद और तेलंगाना के साथ मुलाकात की। इसके अतिरिक्त, एफएफओ लक्षद्वीप के साथ लगातार अनुकूल फ़िल्म निर्माण के लिए दिशानिर्देश बनाने और उसमें विभिन्न स्थानों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है।

- fQYe ckt kj&2018 e Hkkxhnkjh

एफएफओ ने फ़िल्म बाज़ार में अपने संबंधित फ़िल्म कार्यालयों एवं 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, लक्षद्वीप, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ संगठित भागीदारी की। इस ज्ञानवर्धन श्रृंखला सत्र को एफएफओ के वेब पोर्टल में भी दिखाया गया।

एफएफओ शूजीत सिरकार, रमेश सिप्पी, ऋचा चड्ढा, शेल कुमार, रोनी लाहिड़ी, संजय सूरी, भुवन लल्ल, कनाडाई फ़िल्म निर्माता पियरे गिल, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सीईओ कुलमीत मक्कड़, इंटरनेशनल लाइन प्रोड्यूसर दिलीप

आईएफएफआई फ़िल्म बाज़ार में एनएफडीसी द्वारा आयोजित ज्ञान श्रृखंला

सिंह राठौड़ सहित निर्देशकों और निर्माताओं को एमपीए (भारत कार्यालय), उदय सिंह, विभिन्न राज्य फ़िल्म कार्यालयों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकों आदि की प्रदान करता है।

- vrjjk"Vh; fQYekRlo e çpkj

एफएफओ वैश्विक मंचों जैसे कान्स फ़िल्म फेस्टिवल (8–19 मई 2018), टोरंटो इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल (6–16 सितंबर 2018) और वीडियोसिट्टो फ़िल्म महोत्सव (19–28 अक्तूबर 2018 रोम, इटली में) पर भारतीय स्थलों, इसके प्रोत्साहनों और सह–उत्पादन की संधियों आदि को बढ़ावा देता रहा है।

- fQYe fuek.k lokfèkd vudy jkT; ijLdkj&2017

एक प्रतिष्ठित जूरी जिसमें प्रख्यात फ़िल्म निर्माता श्री रमेश सिप्पी, श्री नागराज मंजुले, श्री राजा कृष्ण मेनन, श्री विवेक अग्निहोत्री और अध्यक्ष श्री उदय सिंह, एमडी, मोशन पिक्चर एसोसिएशन (इंडिया ऑफिस) शामिल थे, 16 राज्यों से प्राप्त आवेदनों के विस्तृत विश्लेषण और चर्चा के बाद, जूरी ने सर्वसम्मति से "फ़िल्म निर्माण के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य पुरस्कार" मध्य प्रदेश को और उत्तराखंड को विशेष पुरस्कार का प्रमाण–पत्र प्रदान किया।

egkRek xkèkh d 150oÈ tUe'krkCnh dh LFkkiuk

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर के रूप में, एनएफडीसी, चेन्नई द्वारा छात्रों में सत्य और अहिंसा पर गांधी दर्शन के संदेश को फैलाने के लिए अक्तूबर, 2018 को 2 वर्षों के लिए स्कूल और टैगोर फ़िल्म सेंटर में गांधी (तमिल भाषा में) की स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर रहा है।

एनएफडीसी रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित प्रतिष्ठित फ़ीचर फ़िल्म गांधी के डीवीडी के विशेष संस्करण को लाने की योजना बना रहा है। ये डीवीडी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर वितरण और फुटकर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गांधीजी के 150 वर्षों का जश्न मनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में एनएफडीसी का यह प्रयास है कि भारत के युवाओं को एक लघु फ़िल्म प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस अवसर पर एक लघु फ़िल्म प्रतियोगिता, जो महात्मा गांधी के संदेशों की प्रासंगिकता को 21वीं सदी में प्रदर्शित करने के लिए " वे परिवर्तन जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं" पर लघु फ़िल्म निर्माण करने हेतु शौकीन फ़िल्म निर्माताओं (स्कूल/कॉलेज के छात्रों) को www.mygov.in प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया है। यह प्रतियोगिता https://www.mygov.in/task/be.change.which.you.want.see.world.short.film.competition/2 अक्तूबर और 31 दिसंबर 2018 के बीच आयोजित की गई थी।

flu vkfVLV l oyQ;j QM v,Q bfM;k

सिने आर्टिस्ट वेलफ़ेयर फ़ंड ऑफ़ इंडिया (सीएडब्लूएफआई), एक ट्रस्ट है जो 1991 से एनएफडीसी व्यवस्थित करता है। बीते दिनों के सिने कलाकार लॉर्ड रिचर्ड एटनबरो, जिन्होंने फ़िल्म गांधी बनाई थी ने ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए फ़िल्म द्वारा अर्जित लाभ के 5% का उपयोग करते हुए कॉर्पस फ़ंड की स्थापना की। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य 50 साल से ऊपर के पुराने सिने कलाकारों या जो बुरे समय का सामना कर रहे हैं और कोई भी उनकी सहायता के लिए नहीं है को वित्तीय सहायता देना है। वर्तमान में सिने कलाकारों के लिए मासिक सहायता के रूप में रु. 3000/–की राशि दी जाती है। वर्ष 2018–19 के लिए कुल 300 लाभार्थियों ने इस पेंशन का लाभ प्राप्त किया। सीएडब्लूएफआई पेंशनरों के आश्रितों को सीएडब्लूएफआई योजना के तहत मीडिया में कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया था। अब तक 68 उम्मीदवारों ने रु. 3000/–के वजीफे के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

पणजी, गोवा में 20 नवंबर, 2018 को 49वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (इफ्फी–2018) के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित गोवा की गर्वनर श्रीमती मृदुला सिन्हा, युवा मामले एवं खेल तथा सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, अभिनेता श्री अक्षय कुमार एवं अन्य गणमान्य अतिथि

नई दिल्ली में 17 सितंबर, 2018 को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के फेडरल चांसलर की राज्यमंत्री तथा संस्कृति एवं मीडिया की फेडरल गवर्नमेंट कमिश्नर प्रो. (श्रीमती) मोनिका ग्रटर्स ने युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ से मुलाकात की

7 varjjk"Vªh; lg;ksx

Hkkjr vkSj ;wusLdks

भारत, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक, यूनेस्को के संस्थापक सदस्यों में से है। यूनेस्को का मुख्य लक्ष्य शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और जन–संचार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। विकासशील देशों की संचार क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए, 1981 में यूनेस्को के महासम्मेलन के 21वें सत्र में संचार के विकास के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) की स्थापना को मंजूरी दी गई। भारत ने इसकी अवधारणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आईपीडीसी और इसकी अंतर सरकारी परिषद का सदस्य रहा है। इसके महासम्मेलन के 35वें सत्र में भारत को मौखिक मतदान के जरिए 2009–2013 की अवधि के लिए आईजीसी का सदस्य चुना गया था।

संचार के बारे में यूनेस्को उपायोग के साथ सहयोग के लिए 11 अक्तूबर, 2018 को, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय आयोग की बैठक हुई। बैठक का एजेंडा था :

(i) मीडिया तथा सूचना साक्षरता (एमआईएल) को बढ़ावा देना और उसे संसाधन आवंटित करना।

(ii) ऑनलाइन और ऑफलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पत्रकारों की सुरक्षा, स्वतंत्र मीडिया का समर्थन।

(iii) ज्ञान समाज का निर्माण, सूचना पहुंचाना और सभी के लिए ज्ञान।

varjjk"Vªh; ehfM;k dk;ZØe

यह, मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही नई योजना 'मानव संसाधन विकास' के अंतर्गत आने वाले घटकों में से एक है। इस घटक के अंतर्गत वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए 45 लाख रु. का परिव्यय आवंटित किया गया है, जिसमें से 15 लाख रु. वित्त वर्ष 2018–19 के लिए रखे गए। इस कार्यक्रम में सूचना तथा फ़िल्म क्षेत्र में मीडिया आदान–प्रदान कार्यक्रम, संयुक्त कार्यसमूह तथा समझौते और अंतरराष्ट्रीय मीडिया सेमिनार/कार्यशालाएं शामिल हैं। कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- मीडियाकर्मियों के बीच अधिक संवाद के माध्यम से देशों के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और एक–दूसरे के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना।
- समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों और सहिष्णुता को बढ़ावा देने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना।
- इस योजना का व्यापक उद्देश्य सूचना और मास मीडिया के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ निकट संबंध स्थापित करने और विकसित करने की समान इच्छा से प्रेरित होकर सूचना और प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में बेहतर समझ को बढ़ावा देकर विभिन्न देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करना है।
- भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना।
- मास मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और फ़िल्म क्षेत्र में भारत तथा अन्य देशों के बीच विचारों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना।
- उच्च श्रेणी का मीडिया प्रशिक्षण
- संकट के समय संचार
- सोशल और मल्टीमीडिया प्रशिक्षण

'kk?kkbZ lg;ksx laxBu

मंत्रालय ने ''मास मीडिया में सहयोग'' के लिए शंघाई सहयोग संगठन समझौते पर हस्ताक्षर करने की दृष्टि से, 2018 में बीजिंग में आयोजित दो विशेष स्तरीय बैठकों में भाग लिया। हालांकि, समझौते के मसौदे पर अभी चर्चा जारी है। 'मीडिया क्षेत्र में सहयोग' के समझौते पर 2019 के दौरान हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

ns'kksa ds lkFk lkaL—frd vknku&inku dk;ZØe ¼lhbZih½

सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम/समझौतों पर भारत सरकार की ओर से संस्कृति मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों/समझौतों का उद्देश्य संबंधों को मजबूत करना है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संदर्भ में, ये कार्यक्रम/समझौते मास मीडिया, प्रसारण और फ़िल्मों के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच विचारों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देते हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान, भारत और अन्य देशों जैसे रवांडा, सेशेल्स, युगांडा और ग्रीस के साथ कई सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, गुयाना और म्यामां के साथ भी कई सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों को सक्रियता से लागू किया जा रहा है। भारत और क्रोएशिया के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम पर मंत्रालय में सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

■ ■ ■

मुंबई में 19 जनवरी, 2019 को भारतीय सिनेमा संग्रहालय के उद्घाटन अवसर पर युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, वरिष्ठ गायिका श्रीमती आशा भोंसले का स्वागत करते हुए

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 21 जनवरी, 2019 को 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारतीय युवा प्रवासियों से संवाद सत्र के दौरान युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

8 vu|lfpr tkfr;k@vu|lfpr tutkfr;k vkj vU; fiNMk oxl ds fy, vkj{k.k

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में जारी किए गए आदेशों/निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार सभी प्रयास किए गए हैं। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों द्वारा पद आधारित सूचियां बनाई जाती हैं।

2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण और अन्य लाभों के बारे में दिशानिर्देशों और निर्देशों का, सख्ती से अनुपालन करने के लिए सभी मीडिया इकाइयों को भेजा जाता है।

3. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में 1 जनवरी, 2018 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी DOP&T की वेबसाइट 'rrcps.nic.in' पर अपलोड की जा चुकी है।

4. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत और कर्मचारियों की कुल संख्या 1 जनवरी, 2018 तक निम्नानुसार थी :

J.kh	d|y de|pkjh	vu|lfpr tkfr ¼ifrfuf/kRo %½	vu|lfpr tutkfr ¼ifrfuf/kRo %½	vU; fiNMk ox ¼ifrfuf/kRo %½	vU; ¼ifrfuf/kRo %½
क	537	92 (17.13)	34 (6.33)	34 (6.33)	377 (70.20)
ख	781	126 (16.13)	42 (5.37)	124 (15.88)	489 (62.61)
ग (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	1716	508 (29.60)	312 (18.18)	357 (20.80)	539 (31.41)
ग (सफाई कर्मचारी)	12	12 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
d|y	3]046	738 ¼24-22½	388 ¼12-74½	515 ¼16-91½	1]405 ¼46-13½

■ ■ ■

नई दिल्ली में 02 अक्तूबर, 2018 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

9 e=ky; dh lokvksa esa fn0;kax tuksa dk ifrfuf/kRo

नोडल मंत्रालय/विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के संबंध में समय–समय पर सभी मीडिया इकाइयों तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालयों को कड़े तौर पर अमल में लाने के लिए आदेश तथा दिशानिर्देश जारी किए जाते रहे हैं। मुख्य सचिवालय में दिव्यांगजनों के हितों की देखभाल के लिए एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है।

डीओपीटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर मंत्रालय में दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों को भरने की विशेष भर्ती प्रक्रिया जारी है। मंत्रालय में वार्षिक आधार पर दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व का लेखा–जोखा तैयार कर डीओपीटी को प्रेषित किया जाता है। इस दिशा में 01/01/2019 को मंत्रालय में दिव्यांगजनों का समग्र प्रतिनिधित्व और सीधी भर्तियां एवं तरक्की कोटा नीचे दिया गया है :–

ihMCY;Mh fjikV&1

dk;{k= e fn0;kax tuksa dk ifrfuf/kRo n'kkrh okf"kd lph

(वर्ष 2018 के लिए, 01/01/2019 तक)

Ekk=ky;@foHkkx % lpuk ,oa izlkj.k e=ky;

Lkeg	depkfj;ksa dh l[;k				
	dy	fpfUgr in	Okh,p	,p,p	vk,p
1	2	3	4	5	6
समूह क	1690	643	02	01	06
समूह ख	4448	679	08	09	40
समूह ग एवं घ	10544	354	22	22	87
dy	**18088**	**1676**	**32**	**32**	**123**

नोट :– (1) वीएच का अर्थ विजुअली हैंडिकैप्ड (नेत्रहीन अथवा कमजोर दृष्टि क्षमता वाले व्यक्ति)।

(2) एचएच का अर्थ हीयरिंग हैंडीकैप्ड (बधिर व्यक्ति)।

(3) ओएच का अर्थ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड (चलन अंगों या प्रमस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति)।

ihMCY;Mh fjikV & II

कैलेंडर वर्ष के दौरान नियुक्त दिव्यांगजनों की संख्या दर्शाने वाली सूची

वर्ष 2018 के लिए (01/01/2019 तक)

समूह	पीडब्ल्यूडी के लिए सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत आरक्षित रिक्त पद			सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत नियुक्तियों की संख्या					पीडब्ल्यूडी के लिए प्रोमोशन कोटा के अंतर्गत आरक्षित रिक्त पद			प्रोमोशन कोटा के अंतर्गत नियुक्तियों की संख्या				
	वीएच	एचएच	ओएच	कुल नियुक्तियां	पीडब्ल्यूडी के लिए चिन्हित पदों पर कुल नियुक्तियां	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल नियुक्तियां	पीडब्ल्यूडी के लिए चिन्हित पदों पर कुल नियुक्तियां	वीएच	एचएच	ओएच
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
समूह क	00	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	02	00	00	00	00
समूह ख	00	06	06	02	00	00	01	00	00	00	00	16	00	00	00	00
समूह ग एवं घ	04	12	11	84	08	01	01	07	02	01	01	29	01	00	00	01
कुल	04	18	21	94	08	01	02	07	02	01	01	47	01	00	00	01

नोट :– (1) वीएच का अर्थ विजुअली हैंडिकैप्ड (नेत्रहीन अथवा कमजोर दृष्टि क्षमता वाले व्यक्ति)।

(2) एचएच का अर्थ हीयरिंग हैंडिकैप्ड (बधिर व्यक्ति)।

(3) ओएच का अर्थ ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड (चलन अंग पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति)

(4) समूह क और ख के पदों में तरक्की के लिए दिव्यांगजनों के लिए कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है। हालांकि, इन पदों पर दिव्यांगजनों को उस मामले में तरक्की के बाद नियुक्ति मिल सकती है यदि उक्त पद दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमता के अनुरूप कार्य हो।

नई दिल्ली में 12 अप्रैल, 2018 को 65वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों के ज्यूरी सदस्यों के साथ ज्यूरी प्रमुख श्री शेखर कपूर, तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्रीमती स्मृति ईरानी को ज्यूरी रिपोर्ट सौंपते हुए

जयपुर में 12 अगस्त, 2018 को रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा आयोजित चित्र प्रदर्शनी ''साफ नीयत सही विकास'' का दीप जलाकर शुभारंभ करते युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

10

jktHkk"kk d :i e
fgnh dk i;kx

हिंदी भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा है। हिंदी को आधिकारिक कामकाज में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाए जाने के लिए भारत सरकार की सुनियोजित नीति भी है। मंत्रालय भारत सरकार की आधिकारिक योजना नीति के अंतर्गत हिंदी को इस्तेमाल में लाए जाने पर जोर दे रहा है। केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) मंत्रालय का प्रमुख सचिवालय है जो अपने यहां और संबंधित तथा अधीन कार्यालयों में हिंदी के व्यापक इस्तेमाल से जुड़े कार्य देखता है। मंत्रालय तथा उससे संबंधित मीडिया इकाइयों/संस्थानों में हिंदी के व्यापक इस्तेमाल की देखरेख के लिए केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वन समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनके अंतर्गत राजभाषा विभाग के अधीन आधिकारिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग तथा विस्तार की दिशा में निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु चल रहे प्रयासों की समीक्षा की जाती है।

2. आधिकारिक भाषा के लिए भारत सरकार की राजभाषा नीति तथा अनुवाद, कार्यान्वयन एवं जांच को जरूरी सहयोग के लिए मंत्रालय के प्रमुख सचिवालय को एक निदेशक (ओएल), एक उप–निदेशक (ओएल), दो सहायक निदेशक (ओएल), दो वरिष्ठ हिंदी अनुवादक एवं दो जूनियर हिंदी अनुवादकों की क्षमता प्राप्त है।

3. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत सभी पत्रों/दस्तावेजों को द्विभाषिक फॉर्म में और हिंदी में प्राप्त एवं हस्ताक्षरित पत्रों के हिंदी में उत्तर देने के लिए प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। साथ ही, विभिन्न संभागों एवं मीडिया इकाइयों से प्राप्त त्रैमासिक प्रगति–पत्रों का आकलन किया जाता है और राजभाषा नीति के अनुरूप योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उचित कार्रवाइयां एवं सुझावों पर अमल किया जाता है।

4. भूतपूर्व माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्रीमती स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के इस्तेमाल में वृद्धि के लिए 20.04.2018 को हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया था। इस बैठक के दौरान माननीय मंत्री ने दूरदर्शन समाचार, डीजी : ऑल इंडिया रेडियो, डीजी दूरदर्शन एवं प्रकाशन विभाग को मिलाकर एक उप–समिति गठित करने का निर्देश दिया ताकि इन संस्थानों द्वारा तैयार किए जाने वाले सभी ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रमों को हिंदी के प्रयोग के साथ एक मंच पर लाया जा सके जिससे आम जनता में हिंदी की पहुंच में व्यापक विस्तार हो।

5. मॉरीशस में इस वर्ष जीओआई और जीओएम द्वारा 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। हिंदी को विश्वव्यापी पहचान दिलाने की मंत्रालय की नीति के अनुसार, इस सम्मेलन में प्रमुख सचिवालय से संयुक्त निदेशक (ओएल), डीडी न्यूज़ के निदेशक एवं प्रकाशन विभाग के संयुक्त निदेशक सम्मिलित हुए जिन्होंने सम्मेलन के विभिन्न अकादमिक सत्रों में व्यापक योगदान किया।

6. आधिकारिक कार्य में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्रालय में 14–28 सितंबर, 2018 तक 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया गया। इस दौरान, निबंध लेखन, काव्य पाठ, टिप्पणी/आलेखन, श्रुतलेख, अनुवाद, टंकण, स्टेनोग्राफी एवं वाद–विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें 71 कर्मचारियों ने भाग लिया।

7. गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार वहां के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौलिक टिप्पणी–आलेखन एवं श्रुतलेख से जुड़ी दो उत्प्रेरक योजनाएं भी कार्यरत हैं। गत वर्ष मीडिया इकाइयों एवं मंत्रालय के अनुभागों के लिए एक नई प्रेरक योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विजेता मीडिया प्रमुखों एवं मंत्रालय के अनुभागों को उनके आधिकारिक कार्य में हिंदी के इस्तेमाल के आधार पर उनके वार्षिक प्रदर्शन पर पुरस्कारों/प्रतीकचिह्न की सिफारिश की गई। अधिकारियों को हिंदी के इस्तेमाल में सुविधासंपन्न करने के लिए, उनके संस्थानों में संबंधित विभागों में ओएलआईसी गोष्ठियों, हिंदी वर्कशॉप, हिंदी पखवाड़ा एवं अन्य बैठकों का आयोजन किया गया।

8. राजभाषा पर संसदीय समिति की दूसरी उप–समिति ने वर्षभर मंत्रालय के अंतर्गत 17 विभागों का निरीक्षण किया। इसके बाद समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया और राजभाषा के बेहतर इस्तेमाल हेतु कई सुधारात्मक अभियानों की शुरुआत की गई।

नई दिल्ली में 14 दिसंबर, 2018 को डीडी किसान के रियलिटी शो 'महिला किसान अवाड्र्स' के शुभारंभ अवसर पर दीप प्रज्ज्वलित करते प्रसार भारती के चेयरमैन डॉ. ए. सूर्य प्रकाश। साथ में हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव, सुश्री जयश्री मुखर्जी, प्रसार भारती के सीईओ श्री शशि एस. वेम्पती, दूरदर्शन की महानिदेशक श्रीमती सुप्रिया साहु और एनएसडी–एआईआर की महानिदेशक श्रीमती ईरा जोशी

11 Ekfgyk dY;k.k lc/kh xfrfof/k;k

- राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार महिलाओं के लिए चल रही विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए मंत्रालय ने 1992 में एक विशेष महिला सेल का गठन किया था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार 16 मई, 2002 को इस सेल को पुनर्गठित किया गया जिसके अंतर्गत इसे कार्यस्थलों पर यौन शोषण से जुड़े मामलों की शिकायत समिति के अधिकार दिए गए। 13 जनवरी, 2006 को वाईडब्ल्यूसीए से एक बाह्य विशेषज्ञ को महिला सेल के गैर–आधिकारिक सदस्य के तौर पर शामिल किया गया।
- बाद को, सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों और राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों के आधार पर 25.10.2013 को महिला सेल का नाम बदलकर 'आंतरिक शिकायत समिति' कर दिया गया था।
- पिछली बार 03.07.2017 को सर्कुलर नं. बी–11020/17/2011–एड.–III (खंड–II) के आधार पर समिति का पुनर्गठन किया गया था। सुश्री अंजु निगम, संयुक्त सचिव (बी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आईसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, सुश्री कल्पना डेविड, राष्ट्रीय सचिव प्रशासन को भारत की वाईडब्ल्यूसीए की ओर से समिति की गैर–आधिकारिक सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया। मंत्रालय की तीन अन्य महिला सदस्य एवं एक पुरुष सदस्य समिति के आधिकारिक सदस्य होते हैं।
- आंतरिक शिकायत समितियां भी मंत्रालय से संबंधित/अधीन एवं स्वायत्त इकाइयों के तौर पर कार्यरत हैं। समय–समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन शोषण से जुड़ी घटनाओं की रोकथाम के लिए केंद्रीय लोक सेवा (संहिता) नियम, 1964 द्वारा जारी दिशानिर्देशों को मंत्रालय द्वारा विमर्श हेतु सभी मीडिया इकाइयों को प्रेषित किया जाता है।

...

नई दिल्ली में 27 दिसंबर, 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रशासनिक विवरणिका के लोकार्पण के अवसर पर युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। साथ में हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे, पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक श्री सीतांशु आर. कार एवं अन्य गणमान्य अतिथि

12 lrdrk lcf/kh ekeys

मंत्रालय का सतर्कता विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव की समग्र देखरेख में काम करता है। मंत्रालय के सतर्कता विभाग की कमान संयुक्त सचिव स्तर के एक प्रमुख सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पास होती है जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की अनुशंसा से मंत्रालय के एक ब्यूरो प्रमुख में से की जाती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सीवीओ के अधीन एक निदेशक (सतर्कता), एक सह–सचिव (सतर्कता) एवं सतर्कता विभाग होता है। मंत्रालय का सीवीओ मंत्रालय एवं उसके अधीन/संबंधित कार्यालय तथा सीवीसी के साथ–साथ सीबीआई के बीच की कड़ी का कार्य करता है। मंत्रालय के अधीन/संबंधित और स्वायत्त कार्यालयों में, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों और पंजीकृत सोसाइटियों में भी, पृथक सतर्कता विभाग होते हैं। मंत्रालय का सीवीओ संबंधित एवं अधीनस्थ कार्यालयों, मंत्रालय की सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार सतर्कता गतिविधियों का संचालन करता है।

2. भ्रष्टाचार के मामलों में कमी लाने के लिए संयुक्त प्रयास किए गए हैं। संवेदनशील पदों पर कर्मचारियों का समयोचित तबादले के प्रयास भी किए जाते हैं। नियमों एवं पद्धतियों के सुचारू संचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित एवं औचक निरीक्षण भी किया जाता है। 1 अप्रैल, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 तक, 32 नियमित एवं 26 औचक निरीक्षण किए गए। वहीं विभिन्न मीडिया इकाइयों एवं मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में निगरानी के अधीन रखे जाने के लिए 20 क्षेत्रों एवं 78 व्यक्तियों को सूचीबद्ध किया गया। 29 अक्तूबर से 3 नवंबर, 2018 तक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं उसकी मीडिया इकाइयों द्वारा एक सप्ताह तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

3. 1 अप्रैल, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 तक मंत्रालय एवं उसकी मीडिया इकाइयों को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से 217 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों की जांच हुई और इनमें से 19 मामलों में शुरुआती जांच के आदेश दिए गए। इसके अलावा, इस दौरान 39 मामलों (नए एवं पुराने) से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट भी प्राप्त की गई। इनमें से 8 मामलों में निर्धारित विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत बड़ा जुर्माना एवं 5 मामलों में छोटे जुर्माने की शुरुआत की गई। इस दौरान 5 मामलों में बड़ा एवं 6 मामलों में छोटे जुर्माने की सजा तय की गई। इसी दौरान 7 मामलों में प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई और 1 अधिकारी को प्रासंगिक नियमन प्रावधानों के आधार पर समयपूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया।

■■■

नई दिल्ली में 02 अक्तूबर, 2018 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर प्रकाशित सामग्री का लोकार्पण करते हुए युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे

13 ukxfjd pkVj vkj f'kdk;r fuokj.k r=

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का 'नागरिक/उपभोक्ता' घोषणा–पत्र मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mib.gov.in पर मौजूद है। मंत्रालय द्वारा अपने साझीदारों को दी जाने वाली निम्न 12 प्रमुख सेवाएं घोषणा–पत्र में शामिल की गई हैं :

(i) भावी लाइसेंस धारक को डीटीएच सेवाओं के लिए लाइसेंस वितरित करना ;

(ii) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स को लाइसेंस वितरित करना ;

(iii) भावी लाइसेंस धारक को एचआईटीएस सेवाओं के लिए लाइसेंस वितरित करना ;

(iv) भारत में टेलिविजन रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) एजेंसियों का पंजीकरण ;

(v) अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए टीवी चैनलों द्वारा टेलिपोर्ट्स की स्थापना ;

(vi) भारत से अपलिंक्ड किए गए टीवी चैनलों के लिए अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए मंजूरी प्रदान करना ;

(vii) विदेशों से अपलिंक्ड टीवी चैनलों को डाउनलिंकिंग की मंजूरी प्रदान करना ;

(viii) गैर–सरकारी संस्थाओं (एनजीओ), शिक्षण संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों/संस्थानों के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना ;

(ix) विदेशी पत्रिकाओं/जर्नलों/नियतकालिक पत्रों/नई पत्रिकाओं को विशेष/तकनीकी/वैज्ञानिक श्रेणी में प्रकाशन के लिए विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त संस्थाओं को स्वीकृति–पत्र वितरित करना ;

(x) समाचार और समसामयिक घटनाओं/समाचार–पत्रों के भारतीय संस्करण प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं की अधिकार प्राप्त संस्थाओं को मंजूरी–पत्र प्रदान करना जिनके पास विदेशी निवेश होने/न होने के बावजूद विदेशी समाचार–पत्र के विदेशी निवेश/प्रतिलिपि संस्करण हैं ;

(xi) शिकायत निवारण तंत्र ; और

(xii) टीवी/सिनेमा और रियलिटी शो/कमर्शियल टीवी धारावाहिक बनाने वाले विदेशी निर्माताओं को स्वीकृति–पत्र प्रदान करना।

f'kdk;r fuokj.k r=

मंत्रालय को प्राप्त होने वाली शिकायत याचिकाओं को कंप्यूटरीकृत केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) में पंजीकृत कर संसाधित किया जाता है। प्राप्त सभी याचिकाओं को नियमों के अनुसार स्वीकार किया जाता है और पावती सूचना में शिकायत संख्या, उसके निपटान का अनुमानित समय और जांचकर्ता का संपर्क ब्योरा लिखा होता है। शिकायत याचिकाएं संबंधित मीडिया इकाइयों/दफ्तरों/विभागों को शिकायत पर कार्य करने हेतु भेजी जाती हैं, साथ ही, नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता को उचित उत्तर भी भेजा जाता है। इन याचिकाओं पर निरंतर कार्य होता है जिसके अंतर्गत संबंधित विभागों/प्रखंडों को स्मरण–पत्र भेजना और समीक्षात्मक बैठकें आदि करना शामिल होता है। मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी मीडिया यूनिटों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कम–से–कम एक कनिष्ठ प्रशासनिक दर्जे के अधिकारी को उस इकाई का लोक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जाता है। महत्वपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में, संबंधित मीडिया इकाइयों/कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी मामले के निपटान के संबंध में बात कर सकते हैं। याचिकाओं पर अंतिम निर्णय को याचिकाकर्ता को डाक या सीपीजीआरएएमएस के जरिए भेजा जाता है।

जन शिकायतों के निपटान के लिए जन शिकायत/कार्यकारी तंत्र को दिशानिर्देश प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग आदि से प्राप्त होते हैं जिन्हें मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य कर रही सभी मीडिया इकाइयों/स्वायत्त निकायों आदि को वितरित किया जाता है। जन शिकायतों के निवारण को मंत्रालय के सबसे शीर्ष स्तर पर और मासिक 'प्रगति' बैठकों में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी देखा जाता है।

f'kdk;r fuokj.k d fy, iLrkfor le; lhek

Øe l[;k	fo"k;	Lke;
1.	शिकायतकर्ता को प्राप्ति/अंतरिम उत्तर जारी करना	3 दिन
2.	संबंधित प्रशासनिक खंड/उत्तरदायी केंद्र तक शिकायत याचिका स्थानांतरण में लगने वाला समय	7 दिन
3.	शिकायतकर्ता से शिकायत प्राप्ति या स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना, जो भी बाद में प्राप्त हो, की तिथि के बाद उसको दिए जाने वाले अंतिम उत्तर में लगने वाला समय।	2 माह

01&04&2018 l 26&10&2018 rd e=ky; dh f'kdk;r fLFkfr

01@04@2018 rd ikIr	ikIr f'kdk;r ¼01@04@2018 l 26@10@2018 rd½	dy f'kdk;r	f'kdk;r fuiVku ¼01@04@2018 l 26@10@2018 rd½	Ykfcr f'kdk;r 26@10@2018 rd
535	4,482	5,017	3,936	1,081

Ek=ky; dk ikIr vf/kdk'k f'kdk;r fuEu Jf.k;k e gkrh g

Øe l[;k	f'kdk;r J.kh	01&04&2018 l 26&10&2018 rd ikIr f'kdk;rk dh nj
1	डीटीएच ऑपरेटरों एलसीओ/एमएसओ के खिलाफ शिकायतें	31%
2	अन्य मंत्रालयों के विषय में याचिकाएं	20%
3	मिश्रित	14%
4	सलाह एवं प्रश्न	5%
5	विषय–समाचार एवं गैर–समाचार कार्यक्रम प्रसारण	5%
6	सेवा मामले–अस्थायी कर्मचारी	4%
7	प्रेस–पत्रकारिता मामले	3%
8	भ्रष्टाचार एवं कदाचार	3%
9	सेवा मामले–स्थायी कर्मचारी	3%
10	पेंशन मामले–पेंशन एवं अन्य भत्तों के निर्गमन में विलंब	2%
11	प्रसारण विषय–विज्ञापन	2%
12	फ़िल्म विषयक मामले	1%
13	पेंशन मामले–पेंशन का पुनःनिर्धारण	1%
14	प्रेस–कंटेंट मामले	1%
15	सदाशयी नियुक्तियां	1%
16	सदस्यता/प्रकाशन विभाग की पत्रिकाओं का प्रकाशन	1%
17	शोषण और दुर्व्यवहार	1%
18	पेंशन मामले – पेंशन की गलत स्थिरता	1%
19	पंजीकरण और शीर्षक सत्यापन	0.5%
20	विज्ञापन और प्रचार मामले	0.4%
21	यौन शोषण	0.1%

नई दिल्ली में 04 जनवरी, 2019 को फ़िल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित भारतीय पैनोरामा फ़िल्म समारोह के उद्घाटन अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे

नई दिल्ली में 28 सितंबर, 2018 को भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश पर आयोजित पीएचडी चैम्बर के 113वें वार्षिक सत्र के अवसर पर उपस्थित युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

14 lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 l lcf/kr ekey

Lkpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 dk dk;kUo;u

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) 2005, प्रत्येक नागरिक को, जन प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले लोकहित से जुड़े मामलों से संबंधित सूचना प्राप्त करने की सुविधा देती है ताकि प्रशासनिक कार्यों में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहन दिया जा सके। यानी ऐसे मामलों में जो सीधे आमजन से संबंधित या प्रासंगिक हों। सूचना के अधिकार का अर्थ है, इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्ति जो किसी लोक प्राधिकरण के अधीन हो और इसमें निम्न अधिकार निहित हों –

1. कार्य, दस्तावेज एवं रिकॉर्डों का निरीक्षण ;
2. दस्तावेजों या रिकॉर्डों से नोट, उद्धरण या आधिकारिक प्रतियां प्राप्त करना ;
3. कार्य की प्रमाणीकृत बानगियां प्राप्त करना ;
4. यदि सूचना कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण में मौजूद है तो उसे सीडी या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक विधि अथवा प्रिंट से प्राप्त करना।

Ek[; lfpoky; e vkjVhvkbZ vf/kfu;e dk dk;kUo;u %

मंत्रालय के आरटीआई सेल की स्थापना 4 जुलाई, 1997 को सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के आदेश के बाद हुई थी।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मंत्रालय, उसके संबंधित कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों एवं स्वायत्त निकायों से संबंधित सभी प्रार्थना पत्र, अपीलें और निर्णय आरटीआई सेल के पास पहुंचती हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी अपीलों पर निर्णय लेने और सूचना उपलब्ध कराने के लिए 27 सीपीआईओ एवं 13 अपीलीय प्राधिकरणों (एए) की स्थापना की है। सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकरणों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mib.gov.in पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदन एवं अपीलें तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्योरा आगे दिया गया है :

o"k	ikIr vkonu ,o vihy rFkk dh xbZ dkjZokbZ
2015	2114
2016	2034
2017	1733

01.01.2018 से 09.11.2018 तक आरटीआई सेल में 1,234 आवेदन–पत्र एवं 152 अपीलें प्राप्त की गई थीं और सभी आवेदनकर्ताओं को उचित जवाब दिया गया। अप्रैल 2013 को https://rtionline.gov.in नामक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया। एमआईबी को 683 ऑनलाइन आवेदन और 92 अपीलें प्राप्त हुई थी। डाक के जरिए प्राप्त होने वाले आरटीआई आवेदनों को भी आरटीआई वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। 01.01.2018 से 09.11.2018 के अरसे के दौरान आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क/निरीक्षण शुल्क के तौर पर 10,459 रुपये प्राप्त हुए थे। इसके अलावा, आरटीआई सेल देश के विभिन्न राज्यों के आगंतुकों से प्राप्त आरटीआई संबंधित प्रश्नों को भी देखता है।

आरटीआई सेल संस्थान के उपभोक्ताओं/ग्राहकों को निम्न सेवाएं भी प्रदान करता है :

(क) ब्रॉशरों, फोल्डरों के माध्यम से संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सहयोगी कार्यक्रमों, योजनाओं तथा प्रासंगिक नियमों और कार्यविधियों से जुड़ी सूचना प्रदान करना ;

(ख) ग्राहकों/उपभोक्ताओं को संस्थान की सेवाओं का त्वरित, समयोचित, सुचारू तथा पारदर्शी तरीके से लाभ उठाने में सहयोग प्रदान करना तथा जन इस्तेमाल के लिए फॉर्म आदि उपलब्ध कराना ;

(ग) संस्थान द्वारा विकसित सेवा तथा समय से जुड़े गुणवत्ता मानक संबंधित सूचना जो संस्थान की सेवाओं/योजनाओं/कार्यप्रणाली से संबद्ध होती है ; और

(घ) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एक सूचना पुस्तिका को संशोधित किया गया था।

vkjVhvkbl vkonuk ij dk;l dju dh fof/k

आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों का अध्ययन किया जाता है और जो आवेदन इस मंत्रालय से संबद्ध नहीं होते, उन्हें संबंधित मंत्रालय के सीपीआईओ को भेज दिया जाता है। शेष आवेदनों को मंत्रालय के संबंधित सीपीआईओ को सौंप दिया जाता है।

लंबित आवेदनों पर कार्य करने के लिए, सीपीआईओ को 15 तथा 25 दिनों के पश्चात क्रमशः नीले एवं गुलाबी रंगों वाले पत्रों पर स्मरण–पत्र भेजे जाते हैं ताकि आवेदक को निर्धारित 30 दिनों के भीतर सूचना भेजे जाने में कोई रुकावट न आए।

आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों और अपीलों को ऑनलाइन ही मंत्रालय के सीपीआईओ/एए को भेज दिया जाता है। सभी सीपीआईओ एवं एए को आवेदनों/अपीलों पर की जाने वाली कार्रवाइयों को देखने और ऑनलाइन उत्तर भेजने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं।

vkjVhvkbl vf/kfu;e] 2005 dh /kkjk 4 dk dk;kU;ou

मंत्रालय ने धारा 4(बी)(I) और 4(बी)(II) के अंतर्गत अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए अपनी वेबसाइट के जरिए जन प्राधिकरण के अधीन आने वाली समस्त सूचना को आमजन के लिए प्रदर्शित करने का फैसला लिया है। मंत्रालय द्वारा वेबसाइट पर आरटीआई आवेदन, अपील और उनके उत्तर भी अपलोड किए गए हैं। प्राप्त, रद्द, स्थानांतरित आवेदनों/अपीलों के आंकड़े दर्शाने वाली त्रैमासिक रिपोर्ट भी सीआईसी की वेबसाइट पर लगातार अपलोड की जाती हैं।

vkjVhvkbl vf/kfu;e dk e=ky; d lcf/kr@v/khu dk;ky;k e ifjikyu

मंत्रालय के अंतर्गत सभी संबंधित/अधीनस्थ/सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों एवं स्वायत्त निकायों में सीपीआईओ एवं अपीलीय प्राधिकरणों को नियुक्त किया जा चुका है। यह सभी इस संबंध में डीओपीटी से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं।

गुवाहाटी में 18 सितम्बर, 2018 को आर्य विद्यापीठ हाई स्कूल के छात्र 'स्वच्छ भारत' पर क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम के लिए रैली निकालते हुए

गोवा में 28 नवंबर, 2018 को 49वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के समापन अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम

15 y[kkdu vkj vkrfjd y[kk ijh{kk

lpuk vkj çlkj.k e=ky; dk y[kk lxBu

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव, मुख्य लेखा अधिकारी के तौर पर मुख्य लेखा नियंत्रक और वित्तीय सलाहकार की सहायता से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं।

2. जीएफआर 2017 के नियम 70 के अनुसार मंत्रालय/विभाग के सचिव, जो मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी हैं–

   i. अपने मंत्रालय या विभाग के वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होंगे।

   ii. यह सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रालय को विनियोजित सार्वजानिक निधियों का उपयोग जिस उद्देश्य के लिए वह आवांटित हैं के लिए किया जाता है।

   iii. संबंधित मंत्रालय के उक्त परियोजना उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रदर्शन मानकों का पालन करते हुए मंत्रालय के संसाधनों का प्रभावी, कुशल, किफायती और पारदर्शी उपयोग के लिए जिम्मेदार रहेंगे।

   iv. लोक लेखा समिति तथा अन्य संसदीय समिति के समक्ष निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

   v. अधोलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति निर्धारित करने के लिए अपने मंत्रालय को सौंपे गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा और निगरानी करेंगे।

   vi. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नियमों, दिशा निर्देशों या हिदायतों के अनुसार अपने मंत्रालय से संबंधित व्यय और अन्य विवरण की तैयारी के लिए जिम्मेदार रहेंगे।

   vii. यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय वित्तीय लेन–देन का पूर्ण और उचित रिकॉर्ड रखता है और प्रणालियों और प्रक्रियाओं को ग्रहण करता है जो हर समय आंतरिक नियंत्रण रखते हैं।

   viii. यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय कार्यों के निष्पादन, साथ ही साथ सेवाओं और आपूर्ति की खरीद के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया का पालन करता है और इसे निष्पक्ष, न्यायसंगत, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत मूल्य पर लागू करता है।

   ix. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी और उपयुक्त कदम उठायेंगे कि उनका मंत्रालय/विभाग :

      (ए) सरकार के लिये सभी देय राशि एकत्रित करता है; और

      (बी) अनाधिकृत, अनियमित और व्यर्थ व्यय से बचता है।

3. नागरिक लेखा नियमावली के अनुच्छेद 1.3. के अनुसार, मुख्य लेखा नियंत्रक की ओर से मुख्य लेखा अधिकारी जिम्मेदार हैं:

   क) वेतन और लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से सभी भुगतानों को व्यवस्थित करने उसके आलावा, जहां आहरण और वितरण अधिकारी निश्चिय तरह के भुगतान करने के लिए अधिकृत हैं।

   ख) मंत्रालय/विभाग के खातों का संकलन और एकत्रीकरण और निर्धारित प्रारूप में उनको लेखा महानियंत्रक को प्रस्तुत करने, अपने मंत्रालय/विभाग के लिये अनुदान की मांग के लिये वार्षिक विनियोग खाते तैयार करने, और उन्हें मुख्य लेखा प्राधिकरण द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करवाकर लेखा–परीक्षण और सीजीए को विधिवत प्रस्तुत करना।

   ग) विभाग की विभिन्न अधीनस्थ संरचनाओं द्वारा वेतन एवं लेखा कार्यालयों के भुगतान और खातों के अभिलेखों के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बनाए गए सरकारी मंत्रालयों/विभागों के लेन–देन से संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करना।

4. सूचना और प्रसारण मंत्रालय का मुख्य लेखा नियंत्रक अपने कर्तव्यों को नियंत्रक/उपनियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक, 03 प्रा. मुख्यालय में लेखा अधिकारी और चौदह वेतन और लेखा कार्यालयों की सहायता से, जिनमें जीपीएफ/पेंशन के उद्देश्य से प्रसार भारती के साथ संलग्न 06 कार्यालय भी शामिल हैं। जोनल आतंरिक लेखा परीक्षा दल चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में तैनात किए गए हैं, जिनके कार्यों को मुख्यालय में आतंरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है।

5. सिविल लेखा नियमावली के पैरा 1.2.3 के अनुसार, मुख्यालय के प्रधान लेखा कार्यालय में एक प्रधान लेखा अधिकारी की जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं :

क) सीजीए द्वारा निर्धारित तरीके से मंत्रालय/विभाग के खातों का संचयन;

ख) मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित अनुदानों की मांगों के वार्षिक विनियोग खातों की तैयारी, केंद्रीय लेन–देन का विवरण प्रस्तुत करना और नियंत्रक महालेखाकार को केंद्र सरकार (नागरिक) के वित्त खाते के लिए सामग्री उपलब्ध कराना;

ग) भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार को ऋण और अनुदान का भुगतान और जहां भी इस कार्यालय का कोई आहरण खाता है, केंद्र शासित प्रदेश सरकार/प्रशासनों को भुगतान करना;

घ) प्रबंधन लेखा प्रणाली के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैनुअल तैयार करना और वेतन और लेखा कार्यालयों को तकनीकी सलाह प्रदान करने के लिए, सीजीए के कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना और लेखांकन मामलों में समग्र समन्वय और नियंत्रण को प्रभावित करना;

ङ) मंत्रालय/विभाग द्वारा संचालित विभिन्न अनुदानों के तहत व्यय की प्रगति को देखने के लिए मंत्रालय/विभाग के लिए समग्र रूप से विनियोग लेखा परीक्षा रजिस्टर बनाना;

प्रधान लेखा कार्यालय/अधिकारी लेखा संगठन के सभी प्रशासनिक और समन्वय कार्य भी करते हैं और आवश्यक वित्तीय, तकनीकी, लेखांकन सलाह को विभाग के साथ–साथ स्थानीय वेतन और लेखा कार्यालयों और आउट स्टेशन पे एंड एकाउंट्स कार्यालयों को प्रदान करते हैं।

6. लोक लेखा मैनुअल के नियमानुसार सभी वेतन और लेखा कार्यालय संबंधित मंत्रालय/विभाग के भुगतान करते हैं और विशेष परिस्थितियों में अधिकृत विभागीय आहरण और भुगतान अधिकारी भी उक्त मंत्रालय/विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक की शाखाओं/कार्यालयों से आहरित किए जा सकने योग्य चेकों द्वारा भुगतान करते हैं। ये भुगतान संबंधित मंत्रालय/विभाग के वेतन और लेखा कार्यालय में पृथक श्रेणी में उल्लिखित किए जाते हैं।

प्रत्येक वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और भुगतान अधिकारी जो चेक द्वारा अथवा ई–भुगतान के लिए अधिकृत हैं वे केवल उसी मान्यताप्राप्त बैंक के शाखा विशेष द्वारा ही आहरण करेगें जोकि संबंधित वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और वितरण अधिकारी से संबद्ध/अधिसूचित है। इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैं :

- नॉन–चेक ड्राइंग डीडीओ द्वारा प्रस्तुत ऋण और अनुदान सहायता सहित सभी बिलों की पूर्व जांच और भुगतान।
- निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप निधारित समय पर उपयुक्त भुगतान।
- प्राप्तियों की समय पर वसूली।
- चेक आहरण करने वाले डीडीओ के लिए त्रैमासिक साख पत्र जारी करना एवं उपने वाउचरों और बिलों की जांच करना।
- प्राप्तियों और व्यय के मासिक खातों का संचयन करके चेक आहरण डीडीओ खातों के साथ उन्हें शामिल करना।
- एकीकृत किए गए डीडीओ और सेवानिवृत्ति लाभों के प्राधिकरण के अलावा जीपीएफ खातों का रखरखाव।
- सभी डीडीआर प्रमुखों का रखरखाव।
- बैंकिंग व्यवस्था की ई–भुगतान शैली के माध्यम से मंत्रालय/विभाग को कुशल सेवा प्रदान करना।
- निर्धारित लेखा मानकों, नियमों और सिद्धांतों का पालन।
- समय पर, सटीक, व्यापक, प्रासंगिक और उपयोगी वित्तीय रिपोर्टिंग।

7. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में विभागीय लेखा संगठन की समग्र जिम्मेदारियां हैं:–

- मंत्रालय के मासिक खातों का एकीकरण और उसे सीजीए को प्रस्तुत करना।
- वार्षिक विनियोग खाते
- केंद्रीय लेन–देन का विवरण
- 'एक नजर में खाता' की तैयारी
- केंद्रीय वित्त खाते जो सीजीए, वित्त मंत्रालय और लेखा परीक्षण के प्रमुख निदेशक को प्रस्तुत किये जाते हैं।
- अनुदान संस्थाओं और स्वायत्त निकायों को अनुदान सहायता प्रदान करना

- यदि आवश्यक हो तो डीओपीटी, वित्त मंत्रालय और सीजीए आदि जैसे अन्य संगठनों के साथ परामर्श करके; सभी पीएओ और मंत्रालय को तकनीकी सलाह प्रदान करना।
- प्राप्ति बजट की तैयारी
- पेंशन बजट की तैयारी
- वेतन एवं लेखा कार्यालय/चेक आहरण डीडीओ की ओर से चेक बुक प्राप्त करना और आपूर्ति करना।

  लेखांकन मामलों और मान्यता प्राप्त बैंक में समग्र समन्वय और नियंत्रण को प्रभावी करने के लिए लेखा कार्यालय के नियंत्रक जनरल के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना।
- मान्यताप्राप्त बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से किए गए सभी प्राप्तियों और भुगतान को सत्यापित करना।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखना और नकदी शेष राशि का मिलान करना।
- शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना।
- पेंशन/भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का त्वरित समाधान।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन मंत्रालय, अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों और उसके अनुदेयी संस्थाएं, स्वायत्त निकाय आदि का आंतरिक लेखा परीक्षण।
- सभी संबंधित प्राधिकरणों/प्रभागों को लेखांकन जानकारी उपलब्ध कराना।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय का बजट समन्वय कार्य।
- समय–समय पर नई पेंशन योजना की निगरानी और पेंशन मामलों का संशोधन।
- लेखा और ई–भुगतान का कंप्यूटरीकरण।
- लेखा संगठन के प्रशासनिक और समन्वय कार्य।
- केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत अनुदेयी संस्थानों सहित पीएफएमएस का रोल आउट।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय में गैर–कर प्राप्ति पोर्टल(एनटीआरपी)।

8. प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की सुविधा के लिए वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा प्राधिकरण को लेखांकन जानकारी और डेटा भी प्रदान किया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदान के विभिन्न उप–प्रमुखों/विषय–प्रमुखों के तहत मासिक और प्रगतिशील व्यय के आंकड़ें, संयुक्त सचिव सहित मंत्रालय के बजट अनुभाग से मीडिया प्रभाग को प्रदत्त बजट प्रावधानों के तहत किये गए खर्च की प्रगति भी सचिव और अपर–सचिव तथा वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की बेहतर निगरानी के प्रयोजनों के लिए अनुदान को नियंत्रित करने वाले सचिव और वित्तीय सलाहकार और मंत्रालय के प्रमुखों को सप्ताहवार प्रस्तुत की जाती है।

9. लेखा संगठन मंत्रालय के कर्मचारियों के हाउस बिल्डिंग एडवांस, मोटर कार एडवांस और जीपीएफ खातों जैसे लंबी अवधि के अग्रिमों के खातों को भी बनाए रखता है।

10. अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन अधिकारों के सत्यापन और प्राधिकरण का भुगतान वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा सेवा विशेष और पेंशन कार्यालयों के आधार पर किया जाता है। सभी सेवानिवृत्ति लाभ और भुगतान जैसे– ग्रेच्युटी, छुट्टियों के वेतन के साथ–साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना के तहत भुगतान; डीडीओ से प्रासंगिक जानकारी/बिल प्राप्त होने पर वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा सामान्य भविष्य निधि आदि जारी किए जाते हैं।

vkrfjd y[kk ijh{k.k [kM

क. आंतरिक लेखा परीक्षण खंड मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के खातों के लेखा–परीक्षा का काम करता है वह सुनिश्चित करता है कि इन ऑफिसों में नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं को दिन–प्रतिदिन के कामकाज में पालन किया जाए। आंतरिक ऑडिटिंग एक स्वतंत्र गतिविधि है जिसका मूल उद्देश्य मूल्यांकन के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण लेकर अपने उद्देश्यों को पूरा करना और जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और प्रशासन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता में सुधार लाने में संगठन की मदद करना है।

यह मूल्य संवर्धन एवं प्रभावी बदलाव से युक्त एवं प्रशासन के विकास का विश्वास और सलाह देने के साथ ही, जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण उपायों और बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही यह प्रक्रियात्मक गलतियों/कमियों के सुधार हेतु बहुमूल्य जानकारी भी प्रदान करते हुए प्रबंधन, के लिए मददगार

साबित होता है। किसी विभाग/अनुभाग के लेखा की बारंबारता उसकी प्रकृति, कार्य के प्रकार और अनुदान की मात्रा पर निर्भर करता है।

ख. मुख्य लेखा अधिकारी और वित्तीय सलाहकार के समग्र मार्गदर्शन के तहत काम कर रहे आंतरिक लेखा परीक्षण खंड ने एक प्रभावी और आंतरिक लेखा परीक्षा अभ्यास को सुनिश्चित करने के लिए उचित तरीके से प्रशासन संरचनाओं, क्षमता निर्माण और तकनीक को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

ग. लेखा विभाग के महा लेखाधिकारी का पालन करते हुए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, ओएम नं. जी. 25014/33/2015–16/एमएफ सीजीए आईएडी/306–53 दिनांक– 15.05.17 और ओ/ओ सीजीए द्वारा जारी जेनेरिक इंटरनल ऑडिट मैनुअल (संस्करण 1.0) में निहित प्रावधानों के अनुसार, ऑडिट समिति का गठन एएस एंड एफए (आई–बी) के सचिव (आई–बी) और आंतरिक लेखा परीक्षा समिति की शर्तों के संदर्भ तहत इस मंत्रालय ओ/ओ सीसीए ओएम सं. प्रधान एओ/आई–बी/आईडब्ल्यू (मुख्यालय)/एन जेड/17–18/1016–1065 दिनांक 27.07.2017 में परिभाषित किया गया है।

मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के तहत पूरे भारत में 643 इकाइयां (प्रसार भारती–552 और गैर–प्रसार भारती–91) स्थित हैं, जो देश की लंबाई और चौड़ाई में फैली हुई हैं, जो आंतरिक लेखा परीक्षा के पूर्वावलोकन में आती हैं।

घ. वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, 363 चिन्हित इकाइयों में से 79 कार्यालयों का ऑडिट किया गया। ऑडिट का मकसद 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण का पता लगाना था। वर्ष 2017–18 के दौरान एक सौ छासठ (166) पैरा (संदर्भ) जुटाए गए।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती में 31 मार्च, 2018 को उत्कृष्ट आंतरिक लेखा परीक्षा की उपलब्धता की स्थिति नीचे दी जा रही है:–

I. çlkj Hkkjrh					
{k=	31-03-2018 rd cdk;k ijk	01-04-2018 ls 31-10-18 ijk c<k;k x;k	31-10-18 rd dy cdk;k ijk	01-04-18 ls 31-10-18 dh nkjku gVk;s x, ijk	31-10-2018 dk dy cdk;k ijk
दक्षिणी क्षेत्र (चेन्नई)	711	10	721	39	682
पश्चिमी क्षेत्र (मुंबई)	550	0	550	466	84
उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली)	456	0	456	210	246
पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता)	268	65	333	12	321
dy ¼I½	**1985**	**75**	**2060**	**727**	**1333**
II. xj çlkj Hkkjrh					
{k=	31-03-2018 rd cdk;k ijk	01-04-2018 ls 31-10-18 rd ijk c<k;k x;k	31-10-18 rd dy cdk;k ijk	01-04-18 ls 31-10-18 dh nkjku gVk;s x, ijk	31-10-2018 dk dy cdk;k ijk
दक्षिणी क्षेत्र (चेन्नई)	573	70	643	39	604
पश्चिमी क्षेत्र (मुंबई)	458	13	471	22	449
उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली)	423	52	475	50	425
उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली)	281	21	302	27	275
dy ¼II½	**1735**	**156**	**1891**	**138**	**1753**
dy ;kx ¼I $ II½	**3720**	**231**	**3951**	**865**	**3086**

vkÃvkj,y, ¼O;fäxr fØ;k'khy ystj ys[kk ç.kkyh½

वेतन एवं लेखा कार्यालय (आईआरएलए) अन्य मंत्रालयों के अन्य विभागीय वेतन एवं लेखा कार्यालयों के साथ अस्तित्व में आया है। आईआरएलए प्रणाली (समूह–ए अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत क्रियाशील लेजर लेखा) का विचार एक केंद्रीय प्रणाली में सभी सेवा और भुगतान विवरण रखने से उत्पन्न हुआ ताकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के मीडिया इकाइयों के अधिकारी, जिनके पास एक अखिल भारतीय हस्तांतरण देयता है, अपना वेतन सरलतापूर्वक निकाल सकते हैं। वेतन एवं लेखा कार्यालय (आईआरएलए) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों की सेवा और वेतन रिकॉर्ड और देशभर में विभिन्न शहरों में स्थित प्रसार भारती (दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो) के कार्यालयों का रखरखाव कर रहा है। पीएओ (आईआरएलए) जुलाई 2018 में एक नई वेबसाइट (https://iis.mib.gov.in/irla/) के लॉन्च के साथ डिजिटल प्लेटफार्म पर ऑन–बोर्ड किया गया है, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एनआईसी प्रकोष्ठ के परामर्श से विकसित किया गया है । .यह समूह–ए अधिकारियों को ऑनलाइन सेवाएं जैसे कि सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स फॉर्म–16 और जीपीएफ स्टेटमेंट आदि प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। आने वाले समय में इस वेबसाइट पर और अधिक ऑनलाइन सेवाओं को जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है।

cSad O;oLFkk

भारतीय स्टेट बैंक सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पीएओ और उसके क्षेत्र कार्यालयों के लिए मान्यता प्राप्त बैंक है। पीएओ/सीडीडीओ द्वारा जारी चेक भुगतान के लिए मान्यता प्राप्त बैंक की नामित शाखा को प्रस्तुत किए जाते हैं। गैर–कर–रसीद पोर्टल (एनटीआरपी) के अलावा संबंधित पीएओ/सीडीडीओ द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकों को भी रसीदें दी जाती हैं। मान्यता प्राप्त बैंक में किसी भी बदलाव के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, लेखा महानियंत्रक की विशेष स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

प्रधान लेखा कार्यालय में प्रसार भारती से जुड़े 06 पीएओ सहित 14 (चौदह) वेतन और लेखा कार्यालय हैं। पांच पीएओ नई दिल्ली में, दो प्रत्येक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में और एक–एक नागपुर, लखनऊ और गुवाहाटी में स्थित हैं। विभाग/मंत्रालय से संबंधित सभी भुगतान पीएओ/सीडीडीओ के माध्यम से संबंधित पीएओ के साथ किए जाते हैं। आहरण और संवितरण अधिकारी नामित पीएओ/सीडीडीओ को उनके दावे/बिल पेश करते हैं, जो समय समय पर सिविल लेखा नियमावली, रसीद और भुगतान नियमों और सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य आदेशों के अनुसार आवश्यक जांच के बाद ई–भुगतान जारी करते हैं।

[kkrksa dk dEI;wVjhdj.k

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभागीय लेखा संगठन में खातों के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया वित्त मंत्रालय के लेखा/महालेखाकार द्वारा लेखा समारोह के कंप्यूटरीकरण के साथ शुरू हुई। प्रिंसिपल लेखा कार्यालयों में मासिक खातों के एकत्रीकरण के लिए 'कांटेक्ट' नाम के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इस मंत्रालय में सभी पीएओ ने वाउचर स्तर पर इंप्रूव कंप्यूटरीकरण का उपयोग किया। प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा ऑनलाइन स्वीकृति के साथ विवरण के माध्यम से पुट के पीएओ वार समायोजन के बाद नवंबर, 2008 के महीने से मासिक खाते को ओ/ओ सीजीए के लिए प्रस्तुत किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल जैसे विंडो आधारित एप्लिकेशन का उपयोग शीर्षवार विनियोग खातों की तैयारी, केंद्रीय सरकार के वित्त खाते की सामग्री (सिविल) और मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए मासिक व्यय और रसीद विवरणों के लिए भी किया जाता है।

d,EiSDV ¼osru vkSj ys[kk 2000½

मौजूदा इंप्रूव सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए वेतन और लेखा कार्यालय स्तर पर उपयोग के लिए एक बहु उपयोगी सॉफ्टवेयर शामिल किया गया था। यह सॉफ्टवेयर सभी वेतन और लेखा कार्यालयों में कार्य का कंप्यूटरीकरण करने की दृष्टि से विकसित किया गया था। इस सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित विशेषताएं थीं:–

1. पूर्व–जांच (एकीकृत भुगतान और लेखा कार्य और स्वचालित चेक मुद्रण)
2. इलेक्ट्रॉनिक बैंक पुनर्समाधान
3. सामान्य भविष्य निधि
4. खातों का संकलन
5. पेंशन मामलों का निपटान
6. व्यय बनाम बजट नियंत्रण

Ã&isesaV miØe

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी वेतन और लेखा कार्यालयों में ई–भुगतान प्रणाली 2011 से सफलतापूर्वक लागू की गई थी।

Ã&isesaV ç.kkyh

चूंकि, आईटी अधिनियम, 2000 डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों या डिजिटल तरीके से प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों अथवा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे दस्तावेजों अथवा रिकॉर्डों को प्रमाणित/सत्यापित करता है, इसलिए खातों के नियंत्रक जनरल ने

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक परामर्श के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (ई–भुगतान) करने के लिए कॉम्पेक्ट में एक सुविधा विकसित की थी जिसने भुगतान की मौजूदा प्रणाली को बदल दिया।

विकसित ई–भुगतान प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं की एक पूरी तरह से सुरक्षित वेब आधारित प्रणाली थी जो सरकारी भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता का परिचय देती है। इस प्रणाली के अंतर्गत देय राशि का भुगतान सरकार द्वारा धनराशि के क्रेडिट कॉम्पेक्ट से प्राप्त डिजिटल स्वामित्व वाली ई–परामर्श के माध्यम से एक सुरक्षित संचार चैनल पर 'सरकारी ई–भुगतान गेटवे (जीईपीजी)' द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में किया जाता था। इसे समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्यात्मक और सुरक्षा प्रमाण–पत्र एस टीक्यूसी निदेशालय से प्राप्त किए गए थे। सभी केंद्र सरकार के सिविल मंत्रालयों/विभागों में इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया था।

जीईपीजी को आगे पीएफएमएस प्रणाली में अपग्रेड किया गया है, जो अनुमोदन की तैयारी, बिल प्रसंस्करण, भुगतान, रसीद प्रबंधन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, निधि प्रवाह प्रबंधन और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए खातों के नियंत्रक जनरल की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है।

fMftVy gLrk{kj dk iathdj.k% वेतन और लेखा अधिकारी एनआईसी प्रमाणकर्ता प्राधिकरण से डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करता है। एनआईसी प्रमाणकर्ता प्राधिकरण से प्राप्त डिजिटल हस्ताक्षर एक यूएसबी टोकन में स्टोर किए जाते हैं जिसे आई–की कहा जाता है। पीएओ संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से पीएफएमएस पोर्टल के साथ डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत करता है। संबंधित बैंक पीएफएमएस पोर्टल से पीएओ डिजिटल हस्ताक्षर डाउनलोड करते हैं। बैंकों द्वारा पीएओ को प्रदान किए गए ई–भुगतान स्क्रॉल के प्रमाणीकरण के लिए संबंधित बैंकों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के डिजिटल हस्ताक्षर भी पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं।

fcy tek djuk% आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) ई–भुगतान के लिए बिल के साथ भुगतानकर्ता का अधिकृतपत्र और अनिवार्य विवरण जैसे कि बैंक शाखा का आईएफएससी कोड खाता नंबर, नाम, पता आदि वेतन और लेखा अधिकारी (पीएओ) के पास जमा करता है। उस समय कॉम्पेक्ट से एक टोकन नंबर प्राप्त होता है जो डीडीओ को सूचित किया जाता है।

fcy cukus dk dke% वेतन और लेखा कार्यालय के कम्पैक्ट सिस्टम में बिल बनाने का काम किया जाता है।

fMftVy gLrk{kj% पीएओ द्वारा बिल पास होने के बाद, आई–की का उपयोग करके यह सुरक्षित रूप से हस्ताक्षरित होता है और सिस्टम द्वारा ई–भुगतान प्राधिकरण तैयार किया जाता है।

ih,Q,e,l ij vfèkdkj&i= viyksM djuk% ई–भुगतान प्राधिकरण फ़ाइल (ई–परामर्श) पीएफएमएस पर सुरक्षित वातावरण में अपलोड की जाती है। संबंधित बैंक पीएफएमएस से ई–परामर्श डाउनलोड करते हैं और डिजिटल हस्ताक्षर आदि के आवश्यक सत्यापन के बाद, बैंक लाभार्थियों के खाते को सीबीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस का उपयोग करते हुए लागू करते हैं।

Ã&LØ,Yl% सभी सफल ई–भुगतानों के लिए बैंक द्वारा जेपीजीपी पर एक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक स्क्रॉल जनरेट और अपलोड किया जाता है। पुनर्समाधान और अन्य एमआईएस प्रयोजनों के लिए पीओएस द्वारा ई–स्क्रॉल डाउनलोड किए जाते हैं और कॉम्पैक्ट सिस्टम में शामिल किए जाते हैं।

Ã&Hkqxrku ds Qk;ns

- डिजिटली हस्ताक्षरित विशिष्ट ई–प्राधिकरण आईडी का उपयोग करके ऑनलाइन निधि ट्रांसफर के कारण समय और मेहनत की बचत।
- भुगतान का सुरक्षित तरीका।
- भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता।
- भौतिक चेकों और उनके मैनुअल संचालन का उन्मूलन।
- प्राप्तकर्ता द्वारा बैंक खाते में चेक के मैनुअल जमा करने की बाधाओं का उन्मूलन।
- समग्र भुगतान प्रसंस्करण दक्षता में वृद्धि।
- भुगतानों का ऑनलाइन स्वतः–मिलान।
- खातों का कुशल संकलन।
- सभी स्तरों पर लेन–देन का पूरा लेखा सत्यापन।

lkoZtfud foÙkh; çcèku ç.kkyh ¼ih,Q,e,l½

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) शुरुआत में 2008–09 में तत्कालीन योजना आयोग की सीपीएसएमएस नामक योजना व्यवस्था के रूप में शुरू की गई। यह योजना पायलट योजना के रूप में चार राज्य मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और मिजोरम में चार फ्लैगशिप योजनाओं जैसे एमजीएनआरईजीएस, एनआरएचएम, एसएसए और पीएमजीएसवाई के लिए एक पायलट (मार्गदर्शक) योजना, के रूप में शुरू की गई। मंत्रालयों/विभागों में एक नेटवर्क स्थापित करने के प्रारंभिक चरण के बाद, केंद्र, राज्य सरकारों और राज्य सरकारों की एजेंसियों के वित्तीय नेटवर्क को जोड़ने के लिए सीपीएसएमएस (पीएफएमएस) का राष्ट्रीय रोल–आउट करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना को भूतपूर्व योजना आयोग एवं वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में 12वीं योजना के नवाचार प्रयोग के रूप में शामिल किया गया। वर्तमान में पीएफएमएस, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की योजना है और महालेखा नियंत्रक अधिकारी के आदेशानुसार पूरे देश में लागू की गई है।

2. एमओएफ, डीओआई ओएम नंबर 66 (29) पीफ–II/2016 दिनांक 15/07/2016 के अनुसार, माननीय प्रधानमंत्री ने केंद्रीय योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बेहतर वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि पैसा निर्धारित समय पर जारी हो और समय–समय पर योजनाओं के धन के उपयोग और उनकी सूचना प्रणाली (पीएफएमएस) व्यय विभाग में महालेख नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रशासित किया जाता है जो प्रसंस्करण भुगतान, ट्रैकिंग, निगरानी, लेखा, सुलह और रिपोर्टिंग के लिए एक अनंतिम समाधान है। यह योजना प्रबंधकों को रिलीज के ट्रैकिंग और उनके अनंतिम उपयोग की निगरानी के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है।

3. जस्ट–इन–टाइम रिलीज़ को लागू करने और फंड के अंतिम उपयोग की निगरानी के निर्देशों का पालन करने के लिए, वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत सभी लेनदेन/भुगतानों को कवर करने के लिए पीएफएमएस के उपयोग को सार्वभौमिक बनाने का निर्णय लिया गया है। इन योजनाओं की पूरी निगरानी के लिए पीएफएमएस पर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईएएस) के अनिवार्य पंजीकरण और इनके द्वारा पीएफएमएस के व्यय, अग्रिम और हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल का अनिवार्य उपयोग आवश्यक है। कार्यान्वयन योजना में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का पूरा ब्रह्मांड शामिल है, जिसके लिए अंतरमंत्रालयी स्तर पर प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है :

(i) सभी केंद्रीय योजनाओं का खाका तैयार करने/आकार देने और पीएफएमएस प्लेटफॉर्म पर लाया जाना है।

(ii) धनराशि प्राप्त करने और उसका उपयोग करने वाली सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को पीएफएमएस पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए।

(iii) सभी पंजीकृत एजेंसियों को भुगतान, अग्रिम और स्थानान्तरण करने के लिए पीएफएमएस मॉड्यूल का उपयोग अनिवार्य किया जाना है।

(iv) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के संबंध में व्यय करने वाली सभी विभागीय एजेंसियों को रजिस्टर करना होगा और अनिवार्य रूप से पीएफएमएस मॉड्यूल का उपयोग करना होगा।

(v) केंद्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली सभी संस्थाओं भुगतान/स्थानांतरण/अग्रिम करने के लिए पीएफएमएस मॉड्यूल अपनाना होता है। ऐसा करने पर वे केंद्र सरकार से फंड लेने के लिए उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सकेंगी।

(vi) मंत्रालय को अपने संबंधित सिस्टम/एप्लिकेशन को पीएफएमएस के साथ एकीकृत करने के लिए कदम उठाना होगा।

vkn'k&i= ykx dju d fy, e,M;y

केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार हितधारकों के लिए पीएफएमएस द्वारा विकसित/अविकसित मॉड्यूल निम्नानुसार हैं:

I- dk"k iokg dh fuxjkuh

- एजेंसी पंजीकरण
- पीएफएमएस ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से व्यय प्रबंधन और फंड का उपयोग
- पंजीकृत एजेंसियों के लिए लेखांकन मॉड्यूल
- ट्रेजरी इंटरफ़ेस
- पीएफएमएस–पीआरआई फंड प्रवाह और उपयोग इंटरफ़ेस
- राज्य योजनाओं के फंड ट्रैकिंग के लिए राज्य सरकारों के लिए क्रियाविधि
- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की निगरानी (ईएपी)

II- çR;{k ykHk gLrkarj.k ¼MhchVh½ e,M;wy

- लाभार्थी से पीएओ
- लाभार्थी से एजेंसी
- लाभार्थी से राज्य कोष

III- cSadx d fy, bVjQsl

- सीबीएस (कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस)
- इंडिया पोस्ट
- आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक)
- नाबार्ड और सहकारी बैंक

lkoZfekr vkns'k&i= ykxw djus d fy, e,M;wy

1. पीएओ कंप्यूटरीकरण–ऑनलाइन भुगतान, भारत सरकार की प्राप्तियां और सरकार का लेखा।
    - प्रोग्राम डिवीजन मॉड्यूल
    - डीडीओ मॉड्यूल
    - पीएओ मॉड्यूल
    - पेंशन मॉड्यूल
    - जीपीएफ और एचआर मॉड्यूल
    - जीएसटीएन सहित रसीदें
    - वार्षिक वित्तीय विवरण
    - नकदी प्रवाह प्रबंधन
    - गैर–नागरिक मंत्रालयों के साथ इंटरफेस
2. गैर–कर रसीद पोर्टल।

vU; foHkkxh; igy

पीएफएमएस की क्षमता का लाभ उठाने के लिए, कई अन्य विभागों ने अपने विभागों के लिए आवश्यकतानुसार उपयोगिताओं का लाभ लेने के लिए पीएफएमएस से संपर्क किया है:–

(i) एफसी आरए के तहत फंड प्राप्त करने वाली एजेंसियों की निगरानी के लिए एमएचए (फॉरेनर्स डिवीजन) की निगरानी

(ii) सीबीडीटी पैन सत्यापन

(iii) जीएसटीएन बैंक खाता सत्यापन

dk;kZUo;u j.kuhfr

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा एक कार्ययोजना तैयार और अनुमोदित की गई है।

cgrj foÙkh; çcèku d ekè;e l

- ➢ जस्ट इन टाइम में (जेआईटी) धनराशि जारी
- ➢ अंतिम उपयोग सहित निधियों के उपयोग की निगरानी

j.kuhfr

- ➢ पीएफएमएस का सार्वभौमिक रोल–आउट जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ शामिल है
    - पीएफएमएस पर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) का अनिवार्य पंजीकरण और
    - सभी आईएएस द्वारा पीएफएमएस के अग्रिम व्ययऔर अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल का अनिवार्य उपयोग।

I- dsæh; {k= ¼lh,l½ dh ;kstukvk@yHkkFkhZ d fy, dk;kZUo;u j.kuhfr

जिन गतिविधियों को पूरा करना है

- ➢ आईए द्वारा अनिवार्य पंजीकरण और ईएटी मॉड्यूल का उपयोग
- ➢ योजनाओं की सभी प्रासंगिक सूचनाओं का मानचित्रण
- ➢ पीएफएमएस पर प्रत्येक योजना का बजट अपलोड करना
- ➢ प्रत्येक योजना के कार्यान्वयन पदानुक्रम की पहचान करना
- ➢ पीएफएमएस के साथ नरेगासॉफ्ट, आवाससॉफ्ट जैसी विशिष्ट योजनाओं के सिस्टम इंटरफेस का एकीकरण
- ➢ प्रशिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण

II- dsæh; lgk;d jkT; ;kstuk ¼lh,,lih½ d fy, dk;kZUo;u j.kuhfr

राज्यों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां

- ➢ पीएफएमएस के साथ राज्य खजाना एकीकरण

- ➢ (पीएफएमएस) पर सभी एसआईए का पंजीकरण (प्रथम स्तर और नीचे)
- ➢ संबंधित केंद्रीय योजनाओं के साथ राज्य योजनाओं का मानचित्रण
- ➢ पीएफएमएस पर राज्य योजनाओं का विन्यास
  - राज्य योजनाओं के घटकों का विन्यास करना
  - प्रत्येक राज्य योजना के पदानुक्रम को पहचानें और विन्यास करें
- ➢ योजना आधारित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के साथ पीएफएमएस का एकीकरण
- ➢ प्रशिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण
- ➢ कार्यान्वयन के लिए निरंतर समर्थन

वर्तमान में, सभी चौदह (14) पे एंड एकाउंट्स कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय जीपीएफ और पेंशन के लिए प्रसार भारती से जुड़े छह (06) पीएओ पीएफएमएस पर सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। सभी भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किए जाते हैं और ई–भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं।

I- ih,Q,e,l deipkjh lpuk ç.kkyh ¼ÃvkÃ,l½ e,M;y

कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) केंद्रीकृत है; कार्मिक सूचना और पेरोल के लिए एकीकृत (पीएफएमएस के साथ) वेब आधारित प्रणाली/पैकेज है। यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के लिए काम करने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लिए व्यापक संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करता है।

यह दोहरे उपयोगकर्ता यानी 'डीडीओ मेकर' और 'डीडीओ चेकर' की अवधारणा पर काम करता है और आहरण एवं संवितरण अधिकारी दोनों के डोमेन के तहत पंजीकृत है। डीडीओ निर्माता का कार्य विवरणों को इनपुट करना और सभी प्रकार के ई–वे बिल तैयार करना है और डीडीओ चेकर का काम भुगतान की आगे की प्रक्रिया के लिए पीएओ को सत्यापित और जमा करना है।

ईआईएस वेतन का ई–वे बिल और जीपीएफ के लिए आवश्यक कार्यक्रम, आयकर, और एचबीए, एमसीए और ओएमसीए आदि ब्याज सहित अग्रिम बनाता है।

ईआईएस मॉड्यूल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में लागू किया गया है

II- ih,Q,e,l dk lhMhMhvk e,M;y

केंद्र सरकार के सभी लेनदेन/भुगतान को कवर करने के लिए पीएफएमएस के उपयोग को सार्वभौमिक बनाने के लिए। लेखा महानियंत्रक कार्यालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ने पीएफएमएस के सीडीडीओ मॉड्यूल के माध्यम से फील्ड संरचनाओं में चेक ड्राइंग और डिसबर्सिंग अधिकारियों (सीडीडीओ) को डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से ई–भुगतान करने की कार्यक्षमता को बढ़ाया है।

इस मॉड्यूल का उपयोग करते हुए, फील्ड फॉर्मेशन में सीडीडीओ को सरकारी खातों (ई–लेखा) और पीएफएमएस में खर्च की वास्तविक समय बुकिंग के साथ ई–मोड (एनईएफटी/आरटीजीएस) के माध्यम से वेंडर/लाभार्थी के बैंक खाते में राशि का वितरण करने का अधिकार दिया गया है।

पीएफएमएस के सीडीडीओ मॉड्यूल को सभी बीस (20) चेक डिसबर्सिंग सूचना और प्रसारण के आधुनिकता वाले कार्यालयों में रोल आउट किया गया है।

III- xj dj jlhn ikVy ¼,u Vhvkjih½@ Bharatkosh(https://bharatkosh.gov.in/)

- ➢ गैर–कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) का उद्देश्य भारत सरकार (जीओआई) को देय गैर–कर राजस्व का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नागरिकों/कॉरपोरेट/अन्य उपयोगकर्ताओं को एक–स्टॉप विंडो प्रदान करना है।
- ➢ भारत सरकार के गैर–कर राजस्व में विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा एकत्रित प्राप्तियों का एक बड़ा समूह शामिल है। मुख्य रूप से ये प्राप्तियां/रसीद लाभांश, ब्याज रसीदें, स्पेक्ट्रम शुल्क, आरटीआई आवेदन शुल्क, छात्रों द्वारा प्रपत्र/पत्रिकाओं की खरीद और नागरिकों/कॉरपोरेट/अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा इस तरह के अन्य भुगतान से आती हैं।
- ➢ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आईटी वातावरण में पूरी तरह से सुरक्षित सुविधा है यह आम लोगों/नागरिकों को ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंकों में जाने के कष्ट से बचाता है और फिर सरकारी कार्यालयों में सेवाओं का लाभ उठाने के लिए साधन जमा करने में मदद करता है। यह प्रेषण में परिहार्य देरी को रोकने में भी मदद करता है। सरकारी

खातों में उपकरण के साथ–साथ बैंक खातों में इन उपकरणों के विलंबित जमा में अवांछनीय बाधाओं को समाप्त किया जाता है।

- ➢ एनटीआरपी ऑनलाइन भुगतान प्रौद्योगिकियों जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके पारदर्शी वातावरण में तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।
- ➢ एनटीआर पोर्टल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से 01 नवंबर, 2016 से कार्यात्मक रहा है।
- ➢ 01.04.2018 से 31.10.2018 तक की अवधि के लिए चालू वित्त वर्ष (2018–19) में मंत्रालय के गैर–कर राजस्व का संग्रह 1259.52 करोड़ है और इसमें से भारतकोश के माध्यम से 1223.46 करोड़ का संग्रह केवल एनटीआर ई–पोर्टल द्वारा किया गया है।

IV- ih,Q,e,l dk 0;;] vfxze vkSj LFkkukarj.k ¼Ã,Vh½ e,M;wy

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने सरकार के सभी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। सभी लाभार्थी/स्वायत्त निकायों को अंतिम लाभार्थी तक ई–मोड (एनईएफटी/आरटीजीएस/पीपीए) के माध्यम से ग्रांट–इन–एड के संवितरण के लिए पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल का उपयोग करना अनिवार्य है।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के व्यय, अग्रिम और हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल का उद्देश्य कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को धन के हस्तांतरण, अग्रिमों और इसके निपटान में व्यय करने में सहायता करना है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी छह (06) स्वायत्त निकाय पीएफएमएस के व्यय अग्रिम हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल पर निर्भर हो गए हैं।

V- dæh–r v,uykbu thih,Q e,M;wy jksy vkmV

पीएफएमएस का जीपीएफ मॉड्यूल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को विशिष्ट कर्मचारी आईडी प्रदान करता है, जिससे कर्मचारी के वर्तमान जीपीएफ शेष के लिए ऑनलाइन पहुंच के साथ अग्रिम जीपीएफ और निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलती है। पहले चरण में, इसे पीएओ में लागू किया गया, जिनके सभी डीडीओ वेतन बिलों के लिए पीएफएमएस के ईआईएस मॉड्यूल का उपयोग कर रहे हैं। इस मॉड्यूल के ऑन–बोर्डिंग में सूचना और प्रसारण मंत्रालय चल रहा है।

VI- rhu ehfM;k bdkb;ksa Mh,ohih] Mh,Qih vkSj ,l ,.M MhMh dk foy;@,dhdj.k

डीएवीपी, डीएफपी और एस एंड डी डी का ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन (बीओसी) और रीजनल आउटरीच ब्यूरो (आरओबी), पे एंड एकाउंट्स ऑफिस (डीएवीपी आदि) में विलय/एकीकरण के परिणामस्वरूप नई दिल्ली में 1.04. 2018 से पहले और तत्कालीन डीएवीपी, एस एंड डी डी और डीएफपी के फील्ड कार्यालयों (डीडीओ) को 23 क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो (आरओबी–17 चेक ड्रॉइंग डीडीओ और 06 नॉन चेक ड्रॉइंग डीडीओ) को नए बनाए गए 17 के पक्ष में चेक ड्रॉइंग शक्तियों के नए प्रतिनिधिमंडल के साथ रसीद एवं भुगतान नियमों के नियम–11 और सिविल लेखा नियमावली के पैरा 3.1 के संदर्भ में चेक ड्रॉइंग आरओबी बनाया और सम्मिलित किया गया तथा फिर से नामित किया गया है।

VII- u, lftr vkjvkch esa 21 ofj"B ys[kk vf/kdkjh ds fy, inksa dk l`tu

डीएवीपी, एस एंड डीडी और डीएफपी के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) और क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो (आरओबी) में एकीकरण और विलय के परिणामस्वरूप, केंद्रीय नागरिक लेखा सेवा (सीसीएएस) में लेवल–10 (आरपी नियम–2016) में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के इक्कीस पद संबंधित एडीजी (क्षेत्र) को आरेखण और संवितरण अधिकारी और आईफए के रूप में पदनाम/नामांकन क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो (आरओबी) के लिए बचत के आधार पर मिलान करके तत्कालीन सृजित और नामित किये गए।

VIII- isa'ku vnkyr dk vk;kstu

पेंशनरों की शिकायतों के त्वरित और शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से, तालिकाओं के पार सभी संबंधित हितधारकों की उपस्थिति में मौजूदा नीति दिशानिर्देशों के ढांचे के भीतर पे फिक्सेशन एंड पेंशन प्रोसेसिंग के प्रभारी अधिकारी, पीपीओ जारी करने वाली शाखा, वेतन और लेखा कार्यालय के साथ–साथ संबंधित बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी, पेंशनधारकों को पेंशन अदालत के समय और स्थल के बारे में एक नोटिस जारी किया गया था कि वह या उनका प्रतिनिधि उनके मामले की पैरवी करने के लिए उपस्थित हो सकता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 18 सितंबर, 2018 को विभिन्न स्थानों पर पेंशन आदालत का आयोजन किया है, जिसमें पैंतीस (35) मामलों की रिपोर्ट की गई है और उन पर विचार किया गया है और इनमें से, इकतीस (31) मामलों को पेंशन अदालत में हल किया गया है।

IX- ih,vks vkj MhMhvks dh funsf'kdk

डीएफपी, एस एंड डीडी और डीएवीपी के एकीकृत और विलय के बाद ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) में क्षेत्रीय इकाई स्तर पर ड्राइंग और डिसबर्सिंग कार्यालयों की एक संशोधित निर्देशिका की आवश्यकता महसूस की गई है। इसलिए, सभी हितधारकों के लिए सितंबर, 2018 में सूचना और प्रसारण के तहत पीएओ/सीडीडीओ/एनसीडीडीओ की व्यापक निर्देशिका का दूसरा संस्करण प्रकाशित किया गया है।

X- thÃ,e iksVZy ds ekè;e ls [kjhn

सरकार के ई मार्केट प्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से संबंधित प्रावधान जीओआई द्वारा जीएफआर 2017 के नियम 149 में किए गए हैं। जीएफआर 2017 के नियम 149 के प्रावधानों के अनुसार "मंत्रालयों या विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, जीईएम पर उपलब्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए अनिवार्य होगी"।

XI- fMftVy isesaV dks c<kok

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटी) ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए चार प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए भीम कैशबैक योजना, व्यापारियों के लिए भीम प्रोत्साहन योजना, भीम आधार व्यापारी प्रोत्साहन योजना और डेबिट कार्ड/भीम–यूपीआई/आधार पे के लिए एमडीआर मूल्य माफी में ₹ 2000 से कम या बराबर लेनदेन। इस मंत्रालय के सभी ग्रांटी संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग, फ़िल्म और सूचना क्षेत्र के प्रभारी सचिव शामिल हैं, जो सब्सक्राइबरों ग्राहकों, लाइसेंस ऑपरेटरों, छात्रों और आम जनता सहित सभी हितधारकों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इन प्रोत्साहन योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित करते हैं।

XII- vkarfjd ys[kkijh{kk lfefr dk xBu

एएस एण्ड एफए (आई एण्ड बी) की अध्यक्षता में आज्ञा–पत्र के साथ एक आंतरिक ऑडिट समिति गठित की गई जिसका काम समय–समय पर आतंरिक ऑडिट के कामों और प्रदर्शन की समीक्षा और उन नीतियों और जोखिम के क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने के लिए जिनके तहत आंतरिक ऑडिट को काम करना चाहिए।

XIII- 2016 ls iwoZ ds isa'ku ekeyksa esa la'kksèku

7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, लगभग 25,682 पेंशन मामलों को अंतिम रूप देकर 10.09. 2018 तक केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) को भेज दिया गया है।

मंत्रालय का लेखा संगठन

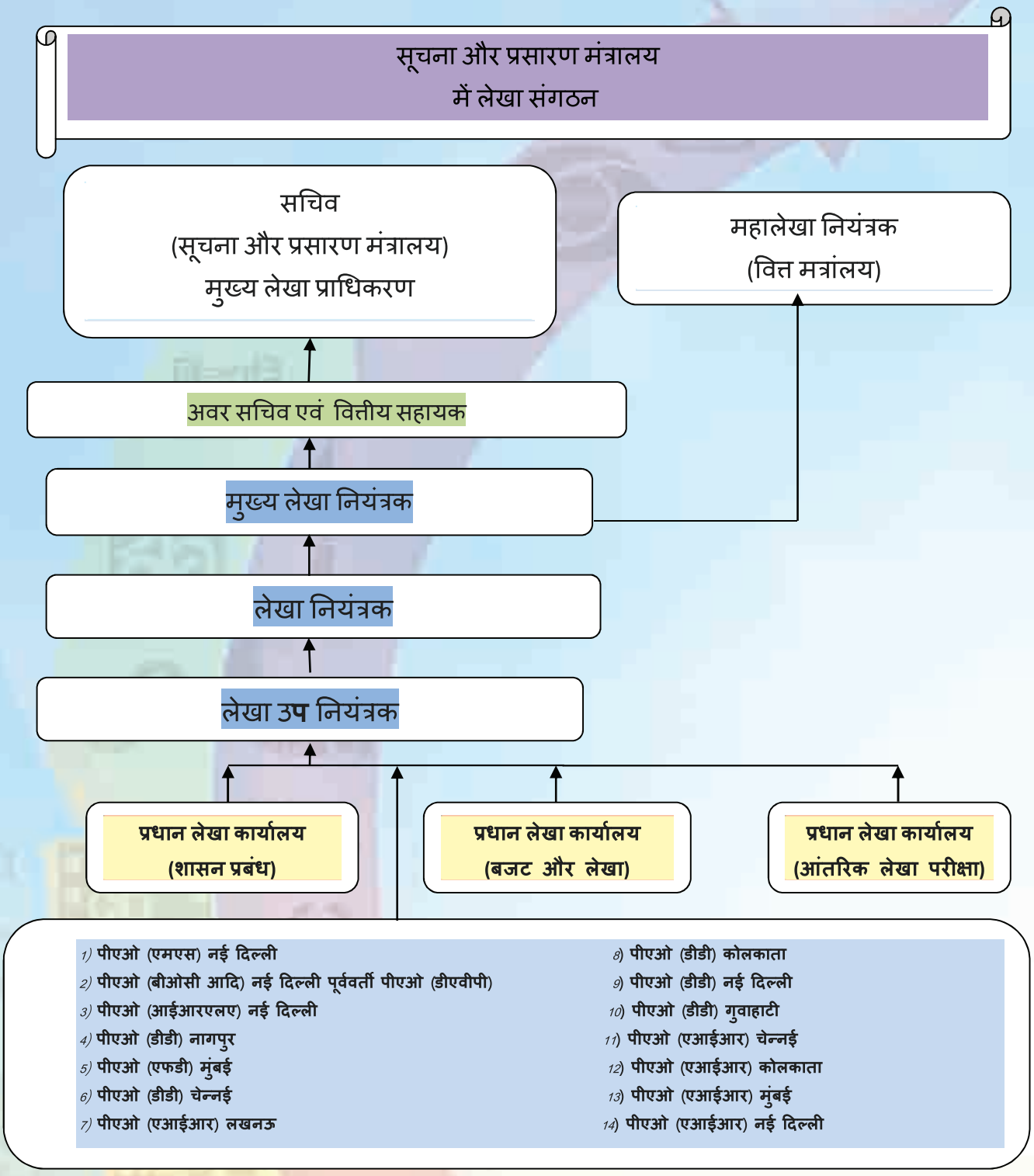

06 दिसंबर, 2018 को आयोजित ''ईटी इमर्जिंग मीडिया सम्मेलन–2018'' को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे

नई दिल्ली में 07 दिसंबर, 2018 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (आईआईएमसी) के 51वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर लोकसभा की स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन। साथ में हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे तथा अन्य गणमान्य अतिथि

16 y[kk ijk

[d] fu;=d vkj egky[kk ijh{kd dh fVIif.k;k

Ø- l-	fjikVZ l- vkj o"k	ijk l-	fo"k; dk C;kjk	dh xbZ dk;Zokgh
1.	2018 का 4 (अनुपालन लेखा परीक्षण)	13.1	सुपर पावर ट्रांसमिशन (एसपीटी), ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर), बंगलुरु – बिजली शुल्क पर परिहार्य भुगतान, एसपीटी, बंगलुरु को बिजली आपूर्ति के लिए बैंगलौर बिजली आपूर्ति कंपनी (बेस्कॉम) के साथ 5,200 केवीए की अनुबंध मांग थी। ऑडिट आकलन से पता चला है कि वास्तविक खपत अप्रैल 2008 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान अनुबंध की मांग की तुलना में 26 से 54 प्रतिशत कम थी, जिसके परिणामस्वरूप नौ साल के लिए 1.24 करोड़ रुपये का भुगतान परिहार्य था।	ब्रॉडकास्टिंग विंग ने 19.12.2018 को पैरा के निपटान के लिए अंतिम एटीएन को ऑडिट के लिए भेजा। प्रसारण शाखा ने पैरा के निपटान के लिए अंतिम एटीएन 19.12.2018 को लोक लेखा समिति को ऑडिट के लिए भेजा। एटीएन, आडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल (एपीएमएस) पर उपलब्ध स्थिति के अनुसार पैरा का निपटान 11.01.2019 को कर लिया गया।
2.	2018 का 4 अनुपालन लेखा परीक्षण)	13.2	[वाणिज्यिक प्रसारण सेवा (सीबीएस), ऑल इंडिया रेडियो, मुंबई– निर्धारित भुगतान प्रक्रिया का अनुपालन न करने वाला] सीबीएस मुंबई ने उन छह गैर–मान्यता प्राप्त एजेंसियों का भुगतान एकत्र नहीं किया था जिनकी सामग्री विज्ञापनों का प्रसारण 1995–2005 के दौरान हुआ था। इसके परिणामस्वरूप 1.12 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई। यह भी उल्लेखनीय है कि सीबीएस ने इनकी सामग्री का प्रसारण जारी रखा, हालांकि उन्होंने पहले के प्रसारण के लिए भुगतान नहीं किया था। इसके अलावा, बकाया राशि की वसूली के लिए सीबीएस की ओर से कोई प्रभावी प्रयास नहीं किया गया था। सीबीएस ने भी भुगतान में चूक करने वाली एजेंसियों के पते और ठिकाने की अद्यतन जानकारी नहीं रखी थी, जिससे इस बारे में उनके अनैच्छिक दृष्टिकोण का पता चलता है।	इस पैरा को लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा 2018–19 के दौरान परीक्षा के लिए चुना गया है। ब्रॉडकास्टिंग विंग ने 19.12.2018 को पैरा के निपटान के लिए अंतिम एटीएन को लोक लेखा समिति को ऑडिट के लिए भेजा था। ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (एपीएमएस) पोर्टल पर उपलब्ध स्थिति के अनुसार, पैरा का 09.10.2018 का निपटारा कर दिया गया है।

[[k] tu y[kk lfefr ¼ih,lh½ dh fVIif.k;k

Ø- l-	fjikV l- vkj o"k	fo"k;	lpuk ,o i lkj.k e=ky; l lcf/kr fl Qkfj'k	dh xbl dk;okgh
1.	74वीं रिपोर्ट (16वीं लोक सभा) 2017	XIX राष्ट्रमंडल खेल, 2010	6	इन सिफारिशों पर पुनरीक्षण के लिए 16 अगस्त, 2018 को ऑडिट हेतु एटीएस भेजा गया। इसके बाद मंत्रालय को पुनरीक्षण संबंधित टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी हैं जिनके आधार पर अंतिम एटीएन तैयार किए जा रहें हैं।
2.	94वीं रिपोर्ट (16वीं लोक सभा) 2018	2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान सीबीएफसी की कार्यकारी और एसआरएफटीआई, कोलकाता की अकादमिक गतिविधियां	14	एपीएमएस पोर्टल की जानकारी के अनुसार अंतिम एटीआर 09/11/2018 को लोक सभा सचिवालय में पीएसी को भेज दी गई।
3.	121वीं रिपोर्ट (16वीं लोक सभा) 2018	2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान सीबीएफसी की कार्यकारी और एसआरएफटीआई, कोलकाता की अकादमिक गतिविधियां	6	प्रथम एटीएन निर्माणाधीन हैं।

dx ,o ih,lh dh lLrfr ij dk;okgh fd;s ukVl ¼,Vh,u½ dh okLrfod fLFkfr vuyXud e foLrkj l nh xbl gA

vuyXud

y[kk voykdu leh{kk d vulkj ,Vh,u dh fLFkfr

Ø- l-	o"k	vkfMV d ckn ykdy[kk lfefr dk lki x, ijk@ij fjikVl dh l[;k ftu ij ,vh,u Hkt x,	ijk dk foLrkj@ih, fjikVl ij vk/kkfjr		
			igyh ckj e=ky; }kjk ugh Hkt tku oky ,Vh,u dh l[;k	voykdu mijkr Hkt x, ijr ykV vk, ,Vh,u dh l[;k ftl dh e=ky; }kjk iu% iLrfrdj.k dh y[kk dk ifr{kk g	vkMj }kjk iujh{k.k fd, x, ,Vh,u dh l[;k ijr ftUg& e=ky; u ykd y[kk lfefr dk ugh Hkt k g
1.	2017	1	शून्य	6	शून्य
2.	2018	16*	6	शून्य	शून्य

* 31.03.2019 के आधार पर

गोवा के पणजी में 20 नवंबर, 2018 को भारत के 49वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (आईएफएफआई 2018) के उद्घाटन अवसर पर युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

नई दिल्ली में 11 मई, 2018 को 15वें एशिया मीडिया समिट के समापन सत्र के अवसर पर 'इमिग्रेशन और माइग्रेशन' विषय पर सर्वश्रेष्ठ टीवी वृत्तचित्र 2018 का वर्ल्ड टेलिविजन पुरस्कार प्रदान करते हुए युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

17 dSV ds QSlyk@vkns'kksa ij vey

वर्ष 2017–18 के लिए मंत्रालय के प्रमुख सचिवालय और विभिन्न मीडिया इकाइयों के सीएटी मामलों से संबंधित निर्णयों/आदेशों के कार्यान्वयन संबंधी सूचना निम्न है :

क्रम संख्या	ehfM;k bdkb;k	o"kZ 2017&18 ds fy, lh,Vh ls izkIr funsZ'kksa dh la[;k	o"kZ 2017&18 ds fy, dk;kZfUor fu.kZ;ksa@funsZ'kksa dh la[;k
1	प्रमुख सचिवालय	4	2
2	बीओसी	5	5
3	डीपीडी	0	0
4	पीआईबी	0	0
5	आरएनआई	0	0
6	फोटो विभाग	0	0
7	न्यू मीडिया विंग	0	0
8	पीसीआई	0	0
9	आईआईएमसी	0	0
10	डीजी : एआईआर (सीसीडब्ल्यू सहित)	68	36
11	डीजी : डीडी	40	27
12	बीईसीआईएल	0	0
13	सीबीएफसी	3	3
14	एसआरएफटीआई	0	0
15	एफटीआईआई	0	0
16	फ़िल्म प्रभाग	0	0
17	एनएफडीसी	0	0
18	एनएफएआई	0	0
19	सीएफएसआई	0	0
20	डीएफएफ	0	0
21	पीएओ	0	0
22	ईएमएमसी	0	0
	dqy	120	73

प्रमुख सचिवालय से संबंधित सूचना में एमयूसी–II/आईआईएस/टीवी–इनसैट/बीए–ई/बीए–पी/एफ(एफ)/एफ(सी)/एफ(आई) डेस्क्स/सेक्शन्स शामिल नहीं हैं।

नई दिल्ली में 17 सितंबर, 2018 को रूस के पत्रकारों/संपादकों से बात करते हुए युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

18 ;kstuk ifj0;;

ctV vuqeku (2018–19)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में 2018–19 के लिए परिव्यय 735.05 करोड़ रुपये था।

(रु. करोड़ में)

Ø- la	{ks=	Tkhch, l
1	सूचना क्षेत्र	228.51
2	फ़िल्म क्षेत्र	165.84
3	प्रसारण क्षेत्र	340.70
	dqy	735-05

2. केंद्रीय क्षेत्र योजना 2018.19 का योजनावार अलग–अलग विवरण संलग्न है।

3. 74.34 करोड़ रुपये के साथ पूर्वोत्तर घटक 735.05 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय क्षेत्र योजना व्यय के 10.11 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्वोत्तर घटक का अलग–अलग विवरण निम्न प्रकार है :

(रु. करोड़ में)

Lkpuk {ks=	
पीआईबी	0.67
बीओसी	20.43
आईआईएमसी	2.00
फोटो प्रभाग	0.05
fQYe {ks=	
मुख्य सचिवालय (फिल्म विंग स्कीम)	5.00
izlkj.k {ks=	
Ek- lfp- ¼izlkj.k½	
1. भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता	0.20
izlkj Hkkjrh	
1. आकाशवाणी	17.00
2. दूरदर्शन	28.99
dqy izlkj.k	46-19
dqy lpuk vkj izlkj.k ea=ky;	74-34

Lkpuk vkj izlkj.k ea=ky;
ctV vuqeku dk fooj.k 2018&19 ¼;kstukokj½

¼#- djksM+ esa½

Ø- la	;kstuk dk uke	dqy ;kstuk izko/kku 2018&19	iokŸkj {ks= 2018&19 ds fy, fu/kkZfjr izko/kku	ctV vuqeku 2018&19 ds fooj.k esa n'kk;k x;k izko/kku
1	2	3	4	5
	सूचना क्षेत्र			
d	Tkkjh ;kstuk,a			
1	अंतरराष्ट्रीय मानकों (रु. करोड़ में) आईआईएमसी आईआईएमसी) के अनुरूप का उन्नयन (आईआईएमसी)	3.00	0.00	3.00
	dqy	3-00	0-00	3-00
[k	ubZ ;kstuk,a			
2	मीडिया आधारभूत ढांचा विकास कार्यक्रम			
2.1	कुल एमआईडीपी आईआईएमसी को छोड़ कर	23.83	0.05	23.78
2.2	आईआईएमसी के नये क्षेत्रीय केंद्र खोलना(आईआईएमसी)	13.00	2.00	11.00
	dqy	36-83	2-05	34-78

Ø- l	;kstuk dk uke	dqy ;kstuk iko/kku 2018&19	iokÿkj {k= 2018&19 ds fy, fu/kkfjr iko/kku	ctV vuqeku 2018&19 ds fooj.k esa n'kk, x, iko/kku
3	fodkl Lkpkj vkj lpuk iilkj	182.00	21.10	160.90
	dqy	182-00	21-10	160-90
4	मानव संसाधन विकास			
4.1	मानव संसाधन के लिए प्रशिक्षण (प्रसार भारती को छोड़कर) (मुख्य सचिवालय)	4.50	0.00	4.50
4.2	अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम (मुख्य सचिवालय)	0.15	0.00	0.15
4.3	तीनों क्षेत्रों (प्रसार भारती को छोड़कर) के लिए नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि (मुख्य सचिवालय)	0.53	0.00	0.53
4.4	फ़िल्म मीडिया इकाइयों का मानव संसाधन विकास (मुख्य सचिवालय)	1.00	0.00	1.00
4.5	पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान (मुख्य सचिवालय)	0.50	0.00	0.50
	dqy	6-68	0-00	6-68
	dqy tkM+ ¼lpuk {k=½	228-51	23-15	205-36
	dqy tkjh ;kstuk,a	3-00	0-00	3-00
	dqy ubZ ;kstuk,a	225-51	23-15	20236
	fQYe {k=			
d	Tkkjh ;kstuk,a			
5	राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय (एफडी)	0.00	0.00	0.00
	dqy	0-00	0-00	0-00
[k	ubZ ;kstuk,a			
6	फ़िल्म क्षेत्र से संबंधित ढांचागत विकास कार्यक्रम			
6.1	सीबीएफसी और प्रमाणन प्रक्रिया का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार (सीबीएफसी)	2.50	0.00	2.50
6.2	सिरीफोर्ट परिसर का उन्नयन (डीएफएफ)	1.00	0.00	1.00
6.3	फ़िल्म प्रभाग के भवन बुनियादी ढांचे का उन्नयन (एफडी)		0.00	
6.4	जयकर बंगला सहित एनएफएआई के बुनियादी ढांचे का उन्नयन और डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना (एनएफएआई)	3.00	0.00	3.00
6.5	एफटीआईआई के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए अनुदान सहायता (एफटीआईआई)	22.00	0.00	22.00
6.6	एसआरएफटीआई में बुनियादी ढांचा विकास (एसआरएफटीआइ)	14.00	2.00	42.20
	dqy	44-20	2-00	12-00
7.	fQYeh lkexh ds tulapkj dk fodkl vkj iilkj			
7.1	भारत तथा विदेश में फ़िल्म महोत्सवों और फ़िल्म विक्रय के जरिए भारतीय सिनेमा का संवर्धन (मुख्य सचिवालय)	30.24	2.00	28.24
7.2	विभिन्न भारतीय भाषाओं में फ़िल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण (मुख्य सचिवालय)	27.50	1.00	26.50

Ø- l|	;kstuk dk uke	d|y ;kstuk i|o/kku 2018&19	i|okŸkj {k= 2018&19 d| fy, fu/kkfjr i|o/kku	ctV vu|eku 2018&19 d| fooj.k e| n'kk;, x, i|o/kku
7.3	फ़िल्म अभिलेखागार की वेबकास्टिंग (एफडी)	0.50	0.00	0.50
7.4	पुरालेखीय फ़िल्मों और फ़िल्म सामग्री का अधिग्रहण (एनएफएआई)	2.50	0.00	2.50
	d|y		0-00	
	vfHk;ku fo'k"k ifj;kstuk,|	60-74	3-00	57-74
8	राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत मिशन(मुख्य सचिवालय)	57.78	0.00	57.78
9	पायरेसीरोधी पहल (मुख्य सचिवालय)	1.00	0.00	1.00
10	एनिमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना (मुख्य सचिवालय)	2.12	0.00	2.12
	d|y	60-90	0-00	60-90
	d|y tkM| ¼fQYe {k=½	165-84	5-00	160-84
	d|y tkjh ;kstuk,|	0-00	0-00	0-00
	d|y ubl ;kstuk,|	165-84	5-00	160-84
	उक्त क्र. सं. 10.2 के तहत विलय यथा 12वीं योजना में विभिन्न भारतीय भाषाओं (मुख्य सचिवालय) में फ़िल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण			
	i|lkj.k {k=			
d	Ekk[; lfpoky;			
11	इलेक्टॉनिक मीडिया मॉनटिरिंग सेंटर (ईएमएमसी) को सुदृढ़ करना	18.10	0.00	18.10
12	भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता	4.00	0.20	3.80
13	मंत्रालय में बुनियादी ढांचा सहायता सेल का नाम बदलकर डिजिटलीकरण मिशन किया गया	2.00	0.00	2.00
14	प्रसारण विंग का स्वचालन	0.90	0.00	0.90
	d|y	25-00	0-20	24-80
[k	i|lkj Hkkjrh			
15	प्रसार भारती को अनुदान सहायता	260.00	36.00	224.00
16	प्रसार भारती को किसान चैनल के लिए अनुदान सहायता	51.70	6.00	45.70
17	प्रसार भारती को अरुण प्रभा चैनल के लिए अनुदान सहायता	4.00	3.99	0.01
	d|y i|lkj Hkkjrh	315-70	45-99	269-71
	d|y i|lkj.k {k=	340-70	46-19	294-51
	ctVh; lgk;rk dk d|y tkM| ¼l|puk] fQYe] i|lkj.k½	735-05	74-34	660-71

नई दिल्ली में 13 फरवरी, 2019 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन अवसर के दौरान युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे और पत्र सूचना विभाग के प्रधान महानिदेशक श्री सीतांशु आर. कार भी उपस्थित थे

19 ehfM;k bdkbl&okj ctV

ekx l- 59 lpuk vkj ilkj.k e=ky;

			रु. हजार में
ehfM;k bdkbl@xfrfof/k dk uke	chbl 2018-19	vkjbl 2018-19	chbl 2019-20
राजस्व अनुभाग			
श्रेणी 1 केंद्र का स्थापना व्यय (गैर–योजना व्यय)			
मुख्य शीर्ष 2251 सचिवालय सामाजिक सेवाएं			
मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	**638500**	**666055**	**686800**
मुख्य शीर्ष 2252 कला एवं संस्कृति			
सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सिनेमैटोग्राफिक फ़िल्मों का प्रमाणन			
फ़िल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण	5100	3000	4100
केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड	90400	97400	104800
कुल मुख्य शीर्ष 2205	**95500**	**100400**	**108900**
मुख्य शीर्ष 2220 सूचना और प्रचार			
फ़िल्म प्रभाग	487200	492760	529600
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार	55500	57100	61300
फ़िल्म समारोह निदेशालय	129800	132300	138600
न्यू मीडिया विंग (पूर्व में अनुसंधान, संदर्भ एवं प्रशिक्षण विभाग)	23200	21995	23200
ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन (बीओसी)	1742900	1742900	1817400
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)(*)	693500	754321	893200
भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक	85300	87600	86500
फोटो प्रभाग (*)	46100	42100	0
प्रकाशन विभाग	350100	382650	398000
रोज़गार समाचार	143600	158150	173781
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)	8050	9750	11500
संचार विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों को वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान (आईपीडीसी)	2100	2100	2100
प्रसारण विकास के लिए एशिया प्रशांत संस्थानों को योगदान (एआईबीडी)	2600	2869	2869
एसोसिएशन ऑफ मूविंग इमेजिस आर्किविस्ट्स को वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान (एनएफएआई)	40	40	40
एनएफएआई द्वारा अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता के लिए योगदान	210	210	210
निजी एफएम रेडियो स्टेशन	44800	129600	20500
dy e[; 'kh"kl ^2220^	**3815000**	**4016445**	**4158800**
dy dni dk LFkkiuk 0;;	**4549000**	**4782900**	**4954500**
¼*½ foYk o"kl 2019&20 ls QkVks iHkkx dk i=&lpuk C;jks es foy; dj fn;k x;k			

रु. हजार में			
ehfM;k bdkb@xfrfof/k dk uke	chbl 2018-19	vkjbl 2018-19	chbl 2019-20
J.kh 2 dnh; {k= ;ktuk, ¼fo'k"k 0;;½			
lpuk {k=			
भारतीय जन–संचार संस्थान (आईआईएमसी) का उन्नयन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार करना	30000	2000	15000
(आईआईएमसी) के नए क्षेत्रीय केंद्र खोलना	130000	52400	95000
मीडिया बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी)	238300	187800	210000
संचार और सूचना प्रसार विकास (डीसीआईडी)	1820000	2200000	2000000
मानव संसाधन विकास	66800	61300	60000
dy ¼lpuk {k=½	**2285100**	**2503500**	**2380000**
fQYe {k=			
भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय (फ़िल्म प्रभाग)	0	42700	0
फ़िल्म क्षेत्र से संबंधित बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम (आईडीपीएफएस)	442000	343400	681500
संचार विकास और फ़िल्म सामग्री का प्रसार (*)	607400	557200	538700
राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत मिशन	577800	150000	224800
पायरेसी निरोधी अभियान (*)	10000	10000	0
एनिमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स के उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना	21200	16300	205000
dy ¼fQYe {k=½	**1658400**	**1119600**	**1650000**
iljk.k {k=			
भारत में सामुदायिक रेडियो को सहायता	40000	26000	38000
इलेक्टॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर को मजबूत करना (ईएमएमसी)	181000	167100	173000
मंत्रालय में बुनियादी ढांचा सहायता प्रकोष्ठ का नाम बदलकर डिजिटलीकरण मिशन किया गया।	20000	34000	20000
ब्रॉडकास्टिंग विंग का ऑटोमेशन	9000	9000	9000
प्रसार भारती के लिए अनुदान सहायता	2600000	2178500	0
किसान चैनल के लिए प्रसार भारती को अनुदान सहायता	517000	488900	0
अरुणप्रभा चैनल के लिए प्रसार भारती को अनुदान सहायता	40000	600000	0
प्रसारण बुनियादी ढांचा नेटवर्क विकास	0	0	4730000
dy ¼iljk.k {k=½	**3407000**	**3503500**	**4970000**
dy dnh; {k= ;ktuk,	**7350500**	**7126600**	**9000000**
bue ls ,ubl vkoVu	**743400**	**1222100**	**1626500**
LrHk'kh"k d rgr vkoVu	**234000**	**116100**	**135400**

(*) वर्ष 2019–20 से पायरेसी निरोधी पहल को विकास संचार और फ़िल्म सामग्री के प्रसार में अम्ब्रेला नामक योजना में विलय कर दिया गया है।

वित्त वर्ष 2019–20 से प्रसार भारती की तीन योजनाओं– प्रसार भारती को अनुदान सहायता, किसान चैनल के लिए प्रसार भारती को अनुदान सहायता और अरुणप्रभा चैनल के लिए प्रसार भारती को अनुदान सहायता ''प्रसारण बुनियादी ढांचा नेटवर्क विकास'' इस नए नाम के तहत में विलय कर दिया गया।

			रु. हजार में
ehfM;k bdkbl xfrfof/k dk uke	chbl 2018-19	vkjbl 2018-19	chbl 2019-20
Js.kh 3 vU; dsnh; 0;; Lok;Ùk fudk; xSj&;ktuk 0;;			
भारतीय जन–संचार संस्थान (आईआईएमसी) को अनुदान सहायता	203900	188900	264900
भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता (पीसीआई)	67300	67300	74500
भारतीय बाल फ़िल्म सोसायटी (सीएफएसआई) को अनुदान सहायता	36000	36000	39000
भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) को अनुदान सहायता	312900	307900	328500
फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान, (एसआरएफटीआई) कोलकाता को अनुदान सहायता	164600	174600	197100
प्रसार भारती को अनुदान सहायता	28205600	28205600	28893600
dqy vU; dsnh; 0;; ¼Lok;Ùk fudk;½	**28990300**	**28980300**	**29797600**
dqy ekax l- 59	**40889800**	**40889800**	**43752100**

मुंबई में 12 मार्च, 2019 को 'फिक्की फ्रेम्स 2019' के उद्घाटन अवसर पर 'फ्रेम्स@20ः ग्लोबल गोज़ इंडिया' विषय पर आयोजित तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दौरान 'सिरिल अमरचंद मंगलदास लॉ बुक' का लोकार्पण करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री अमित खरे

20

lpuk vkj ilkj.k e=ky; dk lkxBfud pkV

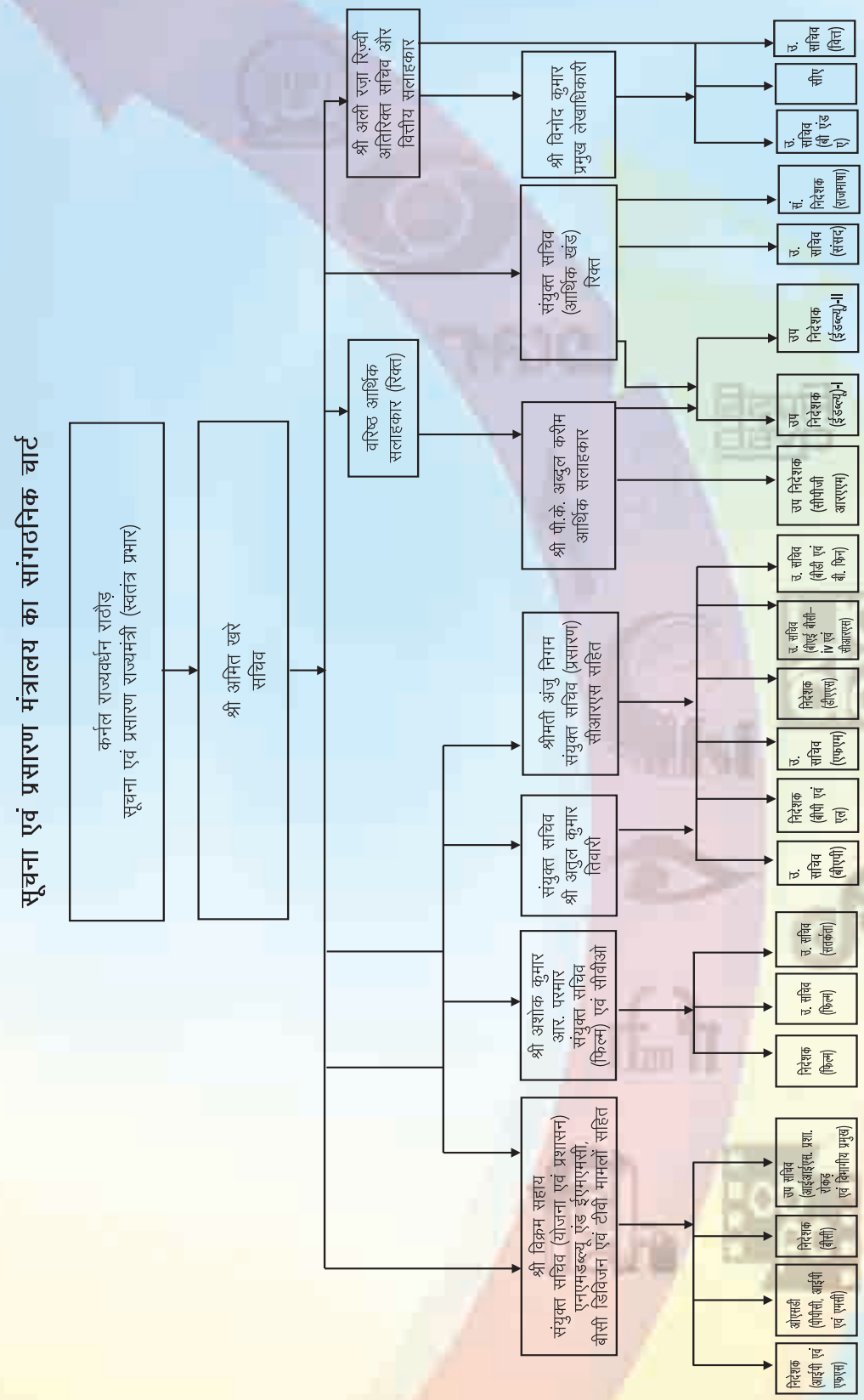

ए.एस/एस.एस.	अतिरिक्त सचिव अस्थाई एएसी द्वारा वर्तमान पदधारी के पद पर पदोन्नयन
ए.एस. और एफ.ए	और वित्तीय सलाहकार
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
जे. एस. (पी एण्ड ए)	संयुक्त सचिव (नीति और प्रशासन)
जे. एस. (बी)	संयुक्त सचिव (प्रसारण – 1)
जे. एस. (एफ)	संयुक्त सचिव (फ़िल्म)
जे. एस. (ईडब्ल्यू)	संयुक्त सचिव (आर्थिक स्कंध)
आर्थिक सलाहकार	आर्थिक सलाहकार
सीसीए	मुख्य लेखा नियंत्रक
निदेशक (आईपी एण्ड एमयूसी)	निदेशक (सूचना नीति और मीडिया इकाई समन्वय)
निदेशक (फ़िल्म – 1)	निदेशक (फ़िल्म – 1)
निदेशक (फ़िल्म – 2)	(फ़िल्म – 2)
निदेशक (बीसी)	निदेशक (प्रसारण सामग्री)
निदेशक/संयुक्त निदेशक (ओएल)	निदेशक / संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
निदेशक(बीपी एंड एल एंड बीए–पी(1)	निदेशक (प्रसारण, नीति और कानून/प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम – 1)
निदेशक (वित्त)	निदेशक (वित्त)
निदेशक (बी एण्ड ए)	निदेशक (बजट और लेखा)
डीएस (बीडी एण्ड बी वित्त)	उप सचिव (प्रसारण विकास और प्रसारण वित्त)
डीएस (प्रशासन, रोकड़, एच ओ डी एण्ड बीएपी–2)	उप सचिव (प्रशासन, रोकड़, विभागाध्यक्ष और प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम –2)
डीएस (डीएएस)	उप सचिव (डिजिटल एडरेसेबल प्रणाली)
डीएस (एफएम)	उप सचिव (फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन)
डीएस (सतर्कता और संसद)	उप सचिव (सतर्कता और संसद)
डीएस (बीए – ई + बीसी – 4)	उप सचिव (प्रसारण प्रशासन इंजीनियरिंग) + प्रसारण . सामग्री. 4
ओएसडी (सी एण्ड पीपीसी एण्ड आईपी एण्ड एमसी)	ऑफिसर ऑन स्पेशल डयूटी (समन्वय, नीति आयोजन सैल, सूचना नीति और मीडिया समन्वय)
सी. ए	लेखा नियंत्रक
यूएस (प्रशासन I, II, III, IV और एचओओ)	अंडर सचिव (प्रशासन 1,2,3,4) और हैड ऑफ आफिस
यूएस (आईआईएस)	अपर सचिव (भारतीय सूचना सेवा)
यूएस (एमयूसी 1)	अपर सचिव (मीडिया इकाई समन्वयन 1)
यूएस (एमयूसी 2)	अपर सचिव (मीडिया इकाई समन्वयन 2)
यूएस (प्रेस)	अपर सचिव (प्रेस)
यूएस (सतर्कता)	अपर सचिव (सतर्कता)
यूएस (रोकड और संसद)	अपर सचिव (रोकड़ और संसद)

यूएस (एनएमसी + एनएमडब्ल्यू)	अपर सचिव (न्यू मीडिया प्रकोष्ठ, न्यू मीडिया विंग)
यूएस (पीपीसी एण्ड आईपी एण्ड एमसी)	अपर सचिव (नीति आयोजन प्रकोष्ठ और सूचना नीति और मीडिया समन्वयक)
यूएस (बीसी 1,2,3)	अपर सचिव (प्रसारण सामग्री 1,2,3)
यूएस (इन्सैट)	अपर सचिव (भारतीय उपग्रह टेलिविजन)
यूएस (डीएएस)	अपर सचिव (डिजिटल एडरेसेबल सिस्टम)
यूएस (बीपी एण्ड एल)	अपर सचिव (प्रसारण, नीति और कानून)
यूएस (बीडी एण्ड बी फिन)	अपर सचिव (प्रसारण विकास और प्रसारण वित्त)
यूएस (बीएपी 1)	अपर सचिव (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम 1)
यूएस (बीएपी 2)	अपर सचिव (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम 2)
यूएस (बीए ई)	अपर सचिव (प्रसारण प्रशासन इंजीनियरिंग)
यूएस (बीसी 4)	अपर सचिव (प्रसारण सामग्री 4)
यूएस (एफ 1 और 3)	अपर सचिव (वित्त 1 और वित्त 3)
यूएस (फिन. 2)	अपर सचिव (बजट और लेखा)
यूएस (बी एण्ड ए)	अपर सचिव (वित्त 2)
यूएस एफ (एफ) +एफ (1) 1+ एफ	अपर सचिव (फ़िल्म समारोह फ़िल्म उद्योग और फ़िल्म प्रमाणन)
यूएस (एफ(ए) + एफ (पीएसयू)+एफ (एफटीआई)	अपर सचिव (फ़िल्म प्रशासन और फ़िल्म सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और एफटीआई)
डीडी (ओएल)	उप निदेशक (राजभाषा)
डीडी (ईडब्ल्यू 1) एण्ड आईएफसी	उप निदेशक (आर्थिक प्रकोष्ठ 1) और आईएफसी
डीडी (ईडब्ल्यू 1) एण्ड आईएफसी	उप निदेशक (आर्थिक प्रकोष्ठ 1) और आईएफसी
डीडी (सीआरएस)	उप निदेशक (सामुदायिक रेडियो स्टेशन)
डीसीए	लेखा उप नियंत्रक
ए.डी. (ओएल 1)	सहायक निदेशक (राजभाषा 1)
ए.डी. (ओएल 2)	सहायक निदेशक (राजभाषा 2)
एस. ओ. (प्रशा. 1)	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन 1)
एस. ओ. (प्रशा. 2)	अनुभाग अधिकारी(प्रशासन 2)
एस. ओ. (प्रशा. 3)	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन 3)
एस. ओ. (प्रशा. 4)	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन 4)
एस. ओ. (रोकड़)	अनुभाग अधिकारी (रोकड़)
एस. ओ. (संसद)	अनुभाग अधिकारी (संसद)
एस. ओ. (एमयूसी 1)	अनुभाग अधिकारी (मीडिया इकाई प्रकोष्ठ 1)
एस. ओ. (एमयूसी 2)	अनुभाग अधिकारी (मीडिया इकाई प्रकोष्ठ 2)
एस. ओ. (सतर्कता)	अनुभाग अधिकारी (सतर्कता)
एस. ओ. (आईपी एण्ड एमसी)	अनुभाग अधिकारी (सूचना नीति और मीडिया समन्वयक)
एस. ओ. (पीपी प्रकोष्ठ)	अनुभाग अधिकारी (नीति आयोजन प्रकोष्ठ)

एस. ओ. (प्रेस)	अनुभाग अधिकारी (प्रेस)
एस. ओ. (आई आई एस)	अनुभाग अधिकारी (भारतीय सूचना सेवा)
एस. ओ. (आई आई एस)	अनुभाग अधिकारी (भारतीय सूचना सेवा))
एस. ओ. एफ (एफ)	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म समारोह)
एस. ओ. एफ. (एफटीआई)	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म [फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान])
एस. ओ. एफ. (ए)	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म [प्रशासन])
एस. ओ. (सी)	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म [प्रमाणन])
एस. ओ. (1)	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म [उद्योग])
एस. ओ. एफ. (पीएसयू)	अनुभाग अधिकारी (एफ [पीएसयू फ़िल्म सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में])
एस. ओ. (बीसी 1)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री 1)
एस. ओ. (बीसी 2)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री 2)
एस. ओ. (बीसी 3)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री 3)
एस. ओ. (बीसी 4)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री 4)
एस. ओ. बी (डी)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री विकास)
एस. ओ. बी (वि.)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण वित्त)
एस. ओ. (बीपी एण्ड एल)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण नीति और कानून)
एस. ओ. (बीए पी)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण प्रशासन और कार्यक्रम)
एस. ओ. (बीए ई)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण प्रशासन और इंजीनियरिंग)
एस. ओ. (एफएम प्रकोष्ठ)	अनुभाग अधिकारी (फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रकोष्ठ)
एस. ओ. (सीआरएस प्रकोष्ठ)	अनुभाग अधिकारी (सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रकोष्ठ)
एस. ओ. (इन्सैट टीवी)	अनुभाग अधिकारी (भारतीय उपग्रह टेलिविजन)
एस. ओ. (वि. 1 एण्ड 3)	अनुभाग अधिकारी (वित्त 1 और 3)
एस. ओ. (वि. 2)	अनुभाग अधिकारी (वित्त 2)
एस. ओ.(पीसी प्रकोष्ठ)	अनुभाग अधिकारी (योजना समन्वयन प्रकोष्ठ)
एस. ओ. (बी एण्ड ए)	अनुभाग अधिकारी (बजट और लेखा)
एस. ओ. (पीएमएस)	अनुभाग अधिकारी (निष्पादन प्रबंधन अनुभाग)
एस. ओ. (एनएमसी)	अनुभाग अधिकारी (न्यू मीडिया सेल)
एस. ओ.(आईएफसी)	अनुभाग अधिकारी (सूचना सुविधा काउंटर)
पी एण्ड ए ओ	वेतन और लेखा अधिकारी

Lkpuk vkj ilkj.k e=ky; l lcf/kr egRoi.k oclkbV fyd

lxBu dk uke	oclkbV ;vkj,y
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	https://mib.gov.in
ब्यूरो ऑफ आउटरीच और संचार	https://davp.nic.in
केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड	https://www.cbfcindia.gov.in
फ़िल्म समारोह निदेशालय	https://diff.nic.in https://iffgoa.org
फ़िल्म डिवीजन	https://filmsdivision.org
भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार	https://www.nfai.gov.in
न्यू मीडिया विंग	https://mib.gov.in/information/new-media-wing
पत्र सूचना कार्यालय	https://pib.nic.in
प्रकाशन विभाग	https://www.publicationsdivision.nic.in
भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक	https://rni.nic.in
आकाशवाणी	https://allindiaradio.gov.in https://www.newsonair.com
ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कन्सलटेंट इंडिया लि.	https://www.becil.com
भारतीय बाल फ़िल्म समिति	https://www.cfsindia.org
दूरदर्शन	https://doordarshan.gov.in
प्रसार भारती	https://prasarbharti.gov.in
भारतीय फ़िल्म और टेलिविजन संस्थान	https://www.ftindia.com
फ़िल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण	https://mib.gov.in/film/film-certification-appellate-tribunal
भारतीय दूरसंचार संस्थान	https://iimc.nic.in
भारतीय फ़िल्म विकास निगम	https://www.nfdcindia.com
भारतीय प्रेस परिषद	https://presscouncil.nic.in
सत्यजित रे फ़िल्म और टेलिविजन संस्थान	https://srfti.ac.in
फ़िल्म सुविधा कार्यालय	https://ffo.gov.in

lpuk ,o ilkj.k e=ky; dh okf"kd fjikV d [kM&2 dk
idk'ku jkdk tkuk

ykdlHkk lfpoky; d vk-,e- l[;k 61@2@blh@2009
fnukd 18-12-2009 }kjk lfpr llnh; ikDdyu lfefr dh
vu'klkvk d vuljk.k e lpuk ,o ilkj.k e=ky; dh
okf"kd fjikV d [kM&2 dk idk'ku o"k 2009&10 l
cn dj fn;k x;k gA

gkykfd ;g e=ky; dh oclkbV **www.mib.gov.in** ;k
www.mib.nic.in ij mlh ik:i e miyC/k g] tls fd lpuk
,o ilkj.k e=ky; dh okf"kd fjikV d [kM&2 e
igyl idkf'kr fd;k tkrk FkkA

मुद्रक : जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि., नई दिल्ली